वार्षिक रिपोर्ट

2010 - 2011

विदेश मंत्रालय

भारत सरकार

द्वारा प्रकाशित:
नीति नियोजन और अनुसंधान विभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

यह वार्षिक रिपोर्ट इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
www.mea.gov.in

रूपरेखा एवं मुद्रण:
साइबरआर्ट इनफारमेशंस प्रा. लि.
1517 हेमकुन्ट चैम्बरस, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110 019
ईमेल: cyberart.mail@gmail.com
वैबसाइट: www.cyberart.co.in / 0120-4231676

विषय सूची

प्रस्तावना और सारांश

1	भारत के पड़ोसी देश	1
2	दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत	18
3	पूर्वी एशिया	26
4	यूरेशिया	32
5	खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका	41
6	अफ्रीका (सहारा से दक्षिण)	50
7	यूरोप और यूरोपीय संघ	66
8	अमेरिका	88
9	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन	105
10	निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले	120
11	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	125
12	सार्क	128
13	तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास भागीदारी	131
14	निवेश और तकनीकी संवर्धन	134
15	ऊर्जा सुरक्षा	136
16	नीति नियोजन और अनुसंधान	137
17	प्रोतोकोल	140
18	कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं	147
19	प्रशासन एवं स्थापना	150
20	सूचना का अधिकार एवं मुख्य लोक सूचना अधिकारी	153
21	ई-शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी	154
22	समन्वय	155
23	विदेश प्रचार	156
24	लोक राजनय	158
25	विदेश सेवा संस्थान	165
26	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार	167
27	मिशन प्रमुखों का तीसरा सम्मेलन	170
28	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	171
29	भारतीय विश्व कार्य परिषद	176
30	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली	180
31	पुस्तकालय	183

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I: वर्ष 2010 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत की गयी संधियां/अभिसमय/करार 187

परिशिष्ट-II: 1 जनवरी, 2010 से दिसंबर 2010 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज 198

परिशिष्ट-III: 1 जनवरी, 2010 से दिसंबर 2010 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन/अधिमिलन 200

परिशिष्ट-IV: आइटेक भागीदार देशों की सूची 202

परिशिष्ट-V: पैनल में शामिल आइटेक/स्कैप संस्थानों की सूची लेखा, वित्त और लेखा-परीक्षा पाठ्यक्रम 204

परिशिष्ट-VI: 2010-2011 की अवधि के दौरान नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्तपोषित की गई संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित/आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठियां/अध्ययन परियोजनाएं 206

परिशिष्ट-VII: 1 जनवरी-30 नवंबर 2010 तक पासपोर्ट कार्यालयों में प्राप्त और जारी पासपोर्टों की संख्या, प्राप्त विविध आवेदन, दी गई सेवाएं, जारी पासपोर्टों की संख्या और तत्काल स्कीम के अंतर्गत प्राप्त राजस्व और पासपोर्ट कायालर्यों के कुल राजस्व और व्यय को दर्शाने वाला विवरण 207

परिशिष्ट-VIII: वर्ष 2010-2011 के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में संवर्ग संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय के बजट से प्रदान किए गए पद और संवर्ग बाह्य पद इत्यादि शामिल हैं) 208

परिशिष्ट-IX: विदेश मंत्रालय में अप्रैल 2010-नवंबर 2010 तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ की गई भर्ती संबंधी आंकड़े 209

परिशिष्ट-X: विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्या 210

परिशिष्ट-XI: वर्ष 2010-2011 में विदेश मंत्रालय का व्यय 211

परिशिष्ट-XII: वर्ष 2010-2011 में मुख्य क्षेत्रवार आबंटन (संशोधित अनुमान) 212

परिशिष्ट-XIII: भारत के तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के मुख्य गंतव्य 214

परिशिष्ट-XIV: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लम्बित लेखा परीक्षा पैरा की स्थिति 215

परिशिष्ट-XV: संगोष्ठियां/सम्मेलन/व्याख्यान/बैठकेः अप्रैल 2010-जनवरी 2011 216

परिशिष्ट-XVI: आरआईएस द्वारा आयोजित संगोष्ठियां, आरआईएस प्रकाशन 219

संक्षिप्तियाँ 220

प्रस्तावना और सार

इस वैश्विक एवं अंतर्निर्भर विश्व में भारत की विदेश नीति सुरक्षा एवं विकास प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। इसमें सतत विकास एवं समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास जैसी घरेलू प्राथमिकताओं के संरक्षण के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार जैसी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना शामिल है। हम अपने घरेलू लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु भारत के लिए उपलब्ध अवसरों को देखते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें वैश्विक मामलों में तेजी से बदलते परिवेश और उदीयमान सुरक्षा एवं आर्थिक रूपरेखा के साथ अपनी गतिशील भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों का विकास कर रहा है। भारत ने हमेशा से पड़ोस की विचारधारा को ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है, जिसके क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समानताओं की मध्य धुरी के इर्द-गिर्द निरन्तर विकास हो।

भारत भूटान के सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्रयासों में भूटान को सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल के साथ हमारे विलक्षण संबंधों के अनुसरण में सीमा पार संपर्क अवसंरचना को बढ़ावा दिये जाने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की गति में तेजी आने के साथ ही इस देश के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है। भारत ने नेपाल की शांति प्रक्रिया को समर्थन और बहुदलीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नेपाल और वहां की राजनैतिक पार्टियों के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखा। बंगलादेश के नेताओं के साथ विभिन्न स्तरों पर हुए सतत और लाभकारी सम्पर्कों से बंगलादेश के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। बंगलादेश की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बंगलादेश को दी गई एक बिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षे की भारत की दो यात्राओं तथा उच्च स्तर पर निरन्तर हुए सम्पर्कों से श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों को संवेग मिला। भारत ने उत्तरी प्रांत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में अनेक विकास परियोजनाओं के जरिए श्रीलंका सरकार को मदद देना जारी रखा है।

सर्वोच्च स्तरों पर नियमित वार्ता के आधार पर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों का निरन्तर विस्तार होता रहा है जिसे अप्रैल 2010 में राष्ट्रपति करजई की भारत यात्रा से बल मिला। उस देश के साथ हमारी विकास भागीदारी के पारस्परिक लाभकारी कार्यान्वयन से हमारे संबंधों को स्पष्ट एवं सार्थक सार मिला है।

भारत आतंकवाद और हिंसा मुक्त परिवेश में द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, यदि बातचीत की इस प्रक्रिया को व्यापक, गंभीर और स्थाई बनाना है, तो पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकवाद को हवा देने के लिए अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्रों का उपयोग नहीं करने देने संबंधी अपनी घोषित वचनबद्धता को पूरा करना होगा। अप्रैल 2010 में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच थिम्पू में हुई बैठक के उपरान्त दिए गए अधिदेश के अनुसरण में जुलाई 2010 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने तथा दोनों देशों के बीच आस्था और विश्वास बहाल करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद में बैठक हुई। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 6 फरवरी, 2011 को थिम्पू में एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच हुई थिम्पु बैठक की भावना में सभी मुद्दों पर बातचीत बहाल करने पर सहमति हुई।

दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध कायम रखने के अतिरिक्त भारत ने सार्क को क्षेत्रीय सहयोग का एक सार्थक और गतिशील वाहन बनाने के लिए असमान एवं गैर-पारस्परिक तरीके से भी योगदान देना जारी रखा।

चीन के साथ हमारे संबंधों में पारस्परिक सम्मान और एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है। वर्ष 2010 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। मई 2010 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की चीन यात्रा तथा दिसंबर 2010 में चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। भारत और चीन ने जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक वित्तीय स्थिति जैसे वैश्विक मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देना जारी रखा।

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच के संबंध साझे मूल्यों, उतरोत्तर समान हो रहे हितों, आपसी लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग

की असीम संभावनाओं और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए मिलकर कार्य करने की साझी वचनबद्धता पर आधारित हैं। ये बातें नवंबर 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान स्पष्ट हुईं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को गहन बनाने और सामरिक संबंधों में समान भागीदारों के रूप में संबंधों को गहन बनाने और सामरिक संबंधों में समान भागीदारों के रूप में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की जिससे विश्व शांति, स्थायित्व और प्रगति पर सकारात्मक और निर्णायक प्रभाव पड़ेगा।

रूस के साथ भारत की विशेष सामरिक भागीदारी है जो पिछले पांच दशकों के दौरान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। दोनों पक्षों द्वारा 'विशिष्ट भागीदारी' के रूप में स्वीकृत इस संबंध को वर्ष 2010 में रूस के प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति श्री दिमित्री मेदवेदेव के भारत दौरे से प्रोत्साहन मिला। इन यात्राओं से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नया स्वरूप मिला, हमारे संबंधों के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग गहन हुए तथा अगले दशक के लिए ब्लूप्रिंट का विकास हुआ।

जुलाई 2010 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री डेविड केमरून ने भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी सामरिक भागीदारी को भविष्य के लिए संवर्धित भागीदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने दिसंबर 2010 में भारत का दौरा किया। नेतृत्व के स्तर पर हुई ठोस वार्ता और अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग से वर्ष 1998 में फ्रांस के साथ स्थापित हमारी सामरिक भागीदारी और सुदृढ़ हुई।

यूरोप के साथ भारत का संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद एवं मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित है, इसलिए सुदृढ़ और समृद्ध यूरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता और संतुलन के लिए अनिवार्य है। यूरोपीय संघ भारत की विकास जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 11वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक में भाग लेने के लिए दिसंबर 2010 में बेल्जियम का दौरा किया। लिस्बन संधि के लागू होने के पश्चात यह पहली शिखर बैठक थी जिससे भागीदारी के क्षेत्रों की पहचान करने और उनका विस्तार करने का अवसर मिला।

दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत का संबंध हमारी 'पूर्वोन्मुख' नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसकी शुरुआत वर्ष 1992 में पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के गतिशील क्षेत्रों के साथ उत्कृष्ट सहक्रिया और सभ्यतामूलक संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2010 में जापान का दौरा किया। भारत की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में जापान की सक्रिय भागीदारी तथा द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर चल रही वार्ता के समापन की पहचान हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में की गई।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्व एशियाई भागीदारों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ उतरोत्तर समेकित होती जा रही है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने सितंबर 2010 में लाओस और कम्बोडिया का दौरा किया। आसियान के साथ भारत के घनिष्ठ एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लाओस और कम्बोडिया महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अक्तूबर 2010 में 8वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वियतनाम का और 5वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया का दौरा किया जो आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। नवंबर 2010 में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कोरिया गणराज्य में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुसिलो बामबंग युधोयोनो 26 जनवरी, 2010 को भारत के गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोहों के मुख्य अतिथि थे।

इस अवधि के दौरान खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए। भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 29 नवंबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित फिलीस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर फिलीस्तीनी लोगों के प्रति भारत के अटल समर्थन को दोहराया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने नवंबर 2010 में सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात का राजकीय दौरा किया। खाड़ी क्षेत्र भारत का एक महत्पवूर्ण व्यापार भागीदार बना हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात एक महत्वपूर्ण व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा भागीदार तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।

मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध गहन एवं विविधतापूर्ण बने रहे। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बेरदीमुहामेदोव ने मई 2010 में भारत का राजकीय दौरा किया। इस वर्ष तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइप लाइन परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटेक) कार्यक्रम के जरिए मध्य एशिया के सभी देशों के साथ भारत के विकास अनुभवों को बांटा गया। आतंकवाद एवं कट्टरवाद की साझी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञ स्तर पर आतंकवादरोधी संवाद जारी रहे।

भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना जारी रखा। इन संबंधों की गतिशीलता विभिन्न उच्चस्तरीय दौरों से जारी रही। सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, मोजाम्बिक और मलावी के राष्ट्रपतियों तथा केन्या के प्रधान मंत्रियों ने इस अवधि के दौरान भारत का दौरा किया। 40 देशों में पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना कार्यान्वित किए जाने के अतिरिक्त अनेक अफ्रीकी देशों को ऋण श्रृंखलाएं एवं सहायता अनुदान दिए गए।

इस अवधि के दौरान लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों में गतिशीलता बनी रही। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इब्सा एवं ब्रिक शिखर बैठकों के लिए अप्रैल 2010 में ब्राजील का दौरा किया। इस क्षेत्र के साथ भारत

का व्यापार 17 बिलियन अमरीकी डालर के प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच गया है और इन क्षेत्रों में हमने लगभग 13 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बहुपक्षीय आर्थिक कार्यकलापों का और विस्तार किया गया। उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 8वें आसियान तथा 5वें एशिया-यूरोप सम्मेलन (एसेम) में भाग लिया तथा प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिक, इब्सा, भारत-आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। प्रधान मंत्री जी ने टोरेंटो (जून) और सियोल (नवंबर) 2010 में आयोजित चौथे और पांचवे जी-20 शिखर बैठकों में भी भाग लिया। भारत की मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2010 में यमन, साना में आयोजित हिन्द महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर-एआरसी) की 10वीं बैठक और नवंबर 2010 में तेहरान में आयोजित एशियाई सहयोग वार्ता (एसीडी) की 9वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत वर्ष 2011 में आईओआर-एआरसी का अध्यक्ष बनने वाला है।

पिछले वर्षों की भांति वर्ष 2010 में भी वित्तीय एवं आर्थिक संकट एवं जलवायु परिवर्तन पर गहन चर्चा जारी रही। वित्तीय संकट के प्रभावों का सामना करने में भारत ने अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र प्रगति करने वाले देशों में एक बना रहा। जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत का दृष्टिकोण भारत की प्रगति और देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की अनिवार्यता से निर्देशित होता है। भारत ने नवंबर-दिसंबर 2010 के दौरान कानकुन, मैक्सिको में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने कानकुन सम्मेलन से पूर्व बेसिक समूह के भाग के रूप में चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने प्रयासों का घनिष्ठ समन्वयन भी किया।

वर्ष 2011-2012 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में डाले गए 192 मतों में से 187 मत प्राप्त करते हुए अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के चयन से विश्व मंच पर भारत की विश्वसनीयता के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन का महत्वपूर्ण संकेत मिला है। इस अवधि के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई एवं अस्थाई श्रेणियों सहित समग्र संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाने के प्रयास जारी रखे ताकि इस निकाय को और भी प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके तथा इसकी प्रभाविता और वैधता में वृद्धि हो।

पड़ोसी देश

अगस्त 2010 में नई दिल्ली में मिशन प्रमुखों के तीसरे सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने पड़ोस में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की आवश्यकता पर बल दिया। पड़ोसी देशों के साथ भारत के सक्रिय कार्यकलापों के अंतर्गत नेपाल, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका के राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा हुई। साथ ही भूटान नरेश, भूटान के प्रधान मंत्री, बंगलादेश की प्रधान मंत्री और म्यामां के राज्याध्यक्ष ने भी भारत का दौरा किया। मई माह में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील और चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ ने दिसंबर माह में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्रमशः चीन और भारत का राजकीय दौरा किया। भारत के विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने काठमांडू, बीजिंग, थिम्पू, तेहरान, इस्लामाबाद, काबुल, यांगून और कोलंबो का सरकारी दौरा किया। उन्होंने श्रीलंका के जाफना और हम्बनटोटा में भारत के प्रधान कोंसलावासों का उद्घाटन किया।

अफगानिस्तानः भारत और अफगानिस्तान के बीच सहस्त्राब्दियों से ऐतिहासिक संबंध है। इस वर्ष भी उच्चस्तरीय यात्राओं का क्रम जारी रहा जिसमें राष्ट्रपति करजई (अप्रैल 2010), विदेश मंत्री (जनवरी 2011) तथा अन्य उच्चाधिकारियों की यात्राओं का उल्लेख किया जा सकता है। शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं वाणिज्य तथा क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में जीवन्त आदान-प्रदान हुए। निरन्तर हो रहे हमलों के बावजूद भारत ने शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, बहुलवादी एवं समृद्ध अफगानिस्तान का निर्माण करने में अफगानिस्तान की सरकार और जनता को सहायता प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। अफगानिस्तान के एक सामरिक भागीदार तथा नजदीकी पड़ोसी देश के रूप में भारत अफगानिस्तान की सरकार और जनता को समर्थन देने के लिए कटिबद्ध है।

बंगलादेशः जनवरी 2010 में बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना की उल्लेखनीय यात्रा के पश्चात जारी प्रेस विज्ञप्ति में सन्निहित निर्णयों के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति हुई है। अगस्त, 2010 में वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की ढाका यात्रा के दौरान बंगलादेश के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण श्रृंखला करार पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में दाहाग्राम एवं अंगारपोटा का विद्युतीकरण करना, बंगलादेश में आसूगंज और भारत में सिलघट को नए पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में नामित करना, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, आसूगंज के जरिए बृहत खेपों के परिवहन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, तीस्ता एवं फेनी नदियों के जल के बंटवारे पर चर्चाओं में तेजी लाना, संयुक्त सीमा कार्यदल की बैठकें आयोजित करना, मेघालय सीमा पर दो सीमावर्ती हाट खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, भारतीय सहायता से निर्मित की जा रही अखौरा-अगरतला रेलवे लाइन के लिए एलाइनमेंट फिक्स करना, द्विपक्षीय व्यापार केंद्र के रूप में फुलवारी बांग्लाबंदा को खोला जाना, नेपाली ट्रकों को 200 मीटर तक बंगलादेश की सीमा में प्रवेश देने से संबंधित समझौता ज्ञापन को लागू करना, विद्युत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, आंतरिक जल परिवहन संधि का 2012 तक विस्तार करना, सद्भावना प्रदर्शन के रूप में निर्यातों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देते हुए बंगलादेश को 3 लाख टन चावल और दो लाख टन गेहूं का निर्यात करना शामिल है।

भूटानः भारत और भूटान के बीच विलक्षण और विशेष संबंध हैं, जो पारस्परिक विश्वास और समझबूझ पर आधारित हैं। नियमित आधार पर होने वाली उच्चस्तरीय यात्राएं, घनिष्ठ विचार-विमर्श तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग भूटान के साथ हमारे संबंधों की आधारशिला हैं। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 16वें सार्क शिखर सम्मेलन के लिए 28-30 अप्रैल, 2010 को भूटान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भूटान के महामहिम नरेश और भूटान के महामहिम चतुर्थ ड्रक ग्याल्पो एवं भूटान के प्रधान मंत्री से मुलाकात की और पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। महमहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक ने 5-7 अक्तूबर, 2010 तक कोलकाता का दौरा किया जिसके दौरान उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टरेट ऑफ लॉ की मानद उपाधि दी गई। महामहिम नरेश ने राष्ट्रीय रक्षा कालेज के स्वर्ण जयंती समारोहों के अवसर पर विशिष्ट सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 20-29 अक्तूबर, 2010 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान महामहिम नरेश ने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील, प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा, वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव से मुलाकात की। भूटान के प्रधान मंत्री ल्योन्छेन जिग्मी वाय थिनले ने महाबोधि सोसायटी की 113वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए 24-29 सितंबर, 2010 तक बोध गया, बिहार का दौरा किया, जहां उन्होंने इस सोसायटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। भूटान के प्रधान मंत्री ने सार्क के वर्तमान अध्यक्ष की हैसियत से 30 अक्तूबर-3 नवंबर 2010 तक नई दिल्ली का दौरा किया। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 24-26 मई, 2010 तक भूटान का दौरा किया। यह भारत के किसी लोक सभा अध्यक्ष की भूटान की पहली यात्रा थी। लोक सभा अध्यक्ष महोदया ने भूटान की संसद के 5वें सत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इसके संयुक्त सत्र को संबोधित किया। वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीना ने सार्क वित्त मंत्रियों की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए 22-24 अगस्त, 2010 तक भूटान का दौरा किया। थल सेना अध्यक्ष जनरल बी. के. सिंह ने 7-11 जून, 2010 तक भूटान का दौरा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन और विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने 13-14 अगस्त, 2010 तक भूटान का दौरा किया। भारत भूटान के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार बना हुआ है। जल विद्युत विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार होने से दोनों देशों के बीच संबंधों को और गति मिली। दो पनबिजली परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सार्क मंत्रिपरिषद की अगली अंतर-सत्रीय बैठक का आयोजन 8 और 9 फरवरी को किया गया जिसके दौरान विदेश मंत्री ने महामहिम भूटान नरेश और भूटान के प्रधान मंत्री से मुलाकात की।

चीनः चीन के साथ हमारा संबंध भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकता है। दोनों देशों ने वर्ष 2005 में शांति एवं समृद्धि के लिए सामरिक और सहकारी भागीदारी की स्थापना की थी। भारत और चीन ने 'भारत गणराज्य तथा चीन लोक गणराज्य के बीच 21वीं सदी के साझे विजन' पर एक संयुक्त दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के हितों की समानता तथा इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने की हमारी इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष, 2010 में भारत गणराज्य और चीन लोक गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान पूरे वर्ष भारत में चीन महोत्सव तथा चीन में भारत महोत्सव सहित अन्य सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दोनों देशों ने नियमित रूप से उच्चस्तरीय सम्पर्क बनाए रखे हैं। 26-31 मई, 2010 तक राष्ट्रपति जी की चीन यात्रा तथा 15-17 दिसंबर, 2010 तक चीन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिला। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए स्थापित व्यापक वार्ता रूपरेखा के अंतर्गत चर्चाएं जारी रखीं। दोनों पक्ष शांतिपूर्ण वार्ताओं के आधार पर न्यायसंगत, उपयुक्त, आपसी स्वीकार्य एवं सक्रिय तरीके से सामरिक उद्देश्य के रूप में भारत-चीन सीमा प्रश्न सहित अन्य सभी अनसुलझे मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया है कि सीमा प्रश्न का स्थाई समाधान प्राप्त होने तक वर्ष 1993, 1996 और 2005 में हस्ताक्षरित प्रासंगिक करारों के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन-चैन कायम रखा जाना चाहिए। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक 29-30 नवंबर, 2010 को हुई।

ईरानः जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री द्वारा मई 2010 में की गई ईरान यात्रा से उच्चस्तरीय यात्राओं का क्रम जारी रहा। भारत-ईरान संयुक्त आयोग के 16वें सत्र, जिसकी सहअध्यक्षता विदेश मंत्री और ईरान के आर्थिक एवं वित्त मंत्री द्वारा की गई, का आयोजन 20 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में किया गया। विदेश सचिव तथा ईरान के उप विदेश मंत्री स्तर पर विदेश कार्यालय परामर्शों का आयोजन अगस्त 2010 में किया गया। वर्ष 2010-2011 अवधि के दौरान ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, मीडिया एवं प्रसारण इत्यादि जैसे अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान जारी रहे और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किए गए जिससे द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता बनी रही।

मालदीवः भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध और भी प्रगाढ़ हुए। मालदीव के राष्ट्रपति ने अक्तूबर 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से समुद्रीय एवं तटीय निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया तथा रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का विस्तार किया गया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री ब्यालार रवि

ने नंवबर 2010 में मालदीव का आधिकारिक दौरा किया। भारत मालदीव के विकास प्रयासों में निरन्तर सहायता करता रहा है। इनमें आवास निर्माण के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला तथा एनआईआईटी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण परियोजना के लिए 5.3 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान शामिल है। नागर विमानन, शिक्षा, गैर-पारम्परिक ऊर्जा, बुनियादी संरचना इत्यादि सहित अन्य क्षेत्रों में व्यावसायिक एवं व्यापारिक सम्पर्कों का विस्तार हुआ।

म्यामां: म्यामां संघ की स्टेट पीस एवं डेवलपमेंट कौंसिल के अध्यक्ष सीनियर जनरल थान श्वे की जुलाई 2010 की भारत की राजकीय यात्रा से म्यामां के साथ हमारे धनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध और सुदृढ़ हुए। कलादान मल्टी-मॉडल पारगमन परियोजना का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह दिसंबर 2010 में आयोजित किया गया और 20 मिलियन अमरीकी डालर की भारतीय ऋण श्रृंखला की सहायता से हैवी ड्यूटी ट्रक परियोजना का उद्घाटन अगस्त 2010 में किया गया। इस अवधि के दौरान ऊर्जा, व्यापार, व्यवसाय और उद्योग, संस्कृति, मीडिया तथा प्रसारण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विनिमय हुए जिससे द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता बनी रही।

नेपाल: नियमित कार्यकलापों एवं उच्चस्तरीय यात्राओं से द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए। राष्ट्रपति रामबरन यादव ने 27 जनवरी-5 फरवरी 2011 तक भारत का सरकारी दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने भारत की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संप्रग अध्यक्षा, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। नेपाल की उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्रीमती सुजाता कोइराला ने भारत के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं के साथ बैठकें करने के लिए 5-6 जनवरी, 2011 को भारत का दौरा किया। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अप्रैल 2010 में थिम्पू में आयोजित 16वीं सार्क शिखर बैठक के दौरान प्रधान मंत्री माधव कुमार नेपाल से मुलाकात की। नेपाल के युवा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल की पहली भारत यात्रा नवंबर 2010 में हुई। विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने 18-20 जनवरी, 2011 तक नेपाल का दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग एवं प्रगति की समीक्षा की। एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध देश के रूप में नेपाल के परिवर्तन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने नेपाल सरकार तथा वहां की प्रमुख राजनैतिक पार्टियों के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखा।

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश तथा पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। भारत ने नेपाल में विकास गतिविधियों को समर्थन देना जारी रखा। फिलहाल भारत-नेपाल, आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तत्वावधान में 400 से अधिक लघु एवं बृहत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत समन्वित सीमा चौकियों, सीमापार रेल सम्पर्कों तथा नेपाल के तराई क्षेत्र मे फीडर एवं लैटरल सड़कों का निर्माण करने के जरिए भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। इससे नेपाल के तराई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा इसके आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

पाकिस्तान: प्रधान मंत्री ने 29 अप्रैल को थिम्पू में आयोजित सार्क शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यदि दक्षिण एशिया को शांति, प्रगति एवं समृद्धि के अपने स्वप्न को मूर्त रूप देना है, तो दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने दोनों विदेश मंत्रियों और विदेश सचिवों को संबंधों में आस्था एवं भरोसा बहाल करने के लिए तौर-तरीकों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी, ताकि पारस्परिक हित के मुद्दों पर ठोस चर्चा का मार्ग प्रशस्त हो सके।

अप्रैल 2010 में दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विदेश मंत्री ने 15 जुलाई, 2010 को इस्लामाबाद का दौरा किया। अपनी बैठक में दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की और आस्था एवं विश्वास बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। भारत ने पारस्परिक हित के सभी मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए कदम दर कदम और प्रगतिशील नजरिए की वकालत की है। पाकिस्तान के वदेश मंत्री ने उपयुक्त तिथियों को भारत आने के विदेश मंत्री के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तिथियों का निर्णय राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिया जाएगा।

अप्रैल 2010 में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच थिम्पू में हुई बैठक के उपरान्त दिए गए अधिदेश तथा जुलाई 2010 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच इस्लामाबाद में हुई बैठक के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में आगे का मार्ग निकालने के लिए 6 फरवरी, 2011 को थिम्पू में एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों विदेश सचिवों ने सभी अनसुलझे मुद्दों का समाधान करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक बातचीत किए जाने की आवश्यकता पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता की पुष्टि की। बैठक के पश्चात दोनों पक्षों ने सभी मुद्दों पर बातचीत बहाल करने पर सहमति व्यक्त की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने समकक्ष के साथ वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए जुलाई 2011 में भारत का दौरा किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा से पूर्व आतंकवाद का मुकाबला (मुम्बई अभियोजन में हुई प्रगति सहित); मानवीय मुद्दे; विश्वासोत्पादक उपायों सहित समग्र शांति और सुरक्षा; जम्मू और कश्मीर; मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान का संवर्धन; और सरक्रीक (अपर सचिव/ महासर्वेक्षक स्तर) पर संबंधित सचिवों के स्तर पर बैठकें होंगी।

भारत आतंकवाद और हिंसा मुक्त परिवेश में द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, यदि बातचीत की इस प्रक्रिया

को व्यापक, गंभीर और स्थाई बनाना है, तो पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकवाद को हवा देने के लिए अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्रों का उपयोग नहीं करने देने संबंधी अपनी महत्वपूर्ण वचनबद्धता को पूरा करना होगा।

श्रीलंका: भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सभ्यतामूलक संबंध हैं। जुलाई 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे की राजकीय यात्रा से भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला। इस अवसर के दौरान जारी संयुक्त घोषणा में कोलम्बो-तूतीकोरन तथा तलाईमन्नार-रामेश्वरम के बीच फेरी सेवाओं को बहाल करने; त्रिंकोमाली में संयुक्त उद्यम के रूप में 500 मेगावाट तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना करने सहित आर्थिक कार्यकलाप एवं घनिष्ठ विकास सहयोग को बढ़ावा देने; श्रीलंका के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में आंतरिक रूप से विस्थापित (आईडीपी) लोगों के लिए भारत की पुनर्वास सहायता जारी रखने और लोगों से लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने इत्यादि के जरिए सहयोग का विस्तार करने की पुष्टि की गई। भारत ने श्रीलंका द्वारा समझ-बूझ की भावना में सभी अनसुलझे मुद्दों का समाधान करने और वास्तविक राष्ट्रीय सुलह की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता संप्रेषित की। भारत ने अस्थाई समाधान प्राप्त करने के लिए सार्थक हस्तांतरण पैकेज की आवश्यकता पर बल दिया और श्रीलंका सरकार तथा तमिल एवं अन्य अल्पसंख्यक पार्टियों के बीच निर्धारित बातचीत किए जाने का आह्वान किया। भारत ने आंतरिक रूप से विस्थापितों के पुनर्वास और उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका के पुनर्निर्माण में पर्याप्त योगदान दिया। वर्तमान में अनेक विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत ने उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका में 50,000 घरों का निर्माण किए जाने संबंधी पहल की घोषणा की। भारत ने देहात क्षेत्रों में भी भारतीय मूल के तमिलों के लिए सहायता कार्यक्रम चलाना जारी रखा।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने अक्तूबर 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भाग लिया। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 25-28 नवंबर, 2010 तक श्रीलंका का दौरा किया। भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक की सहअध्यक्षता करने के अतिरिक्त उन्होंने जाफना और हम्बनटोटा में भारत के प्रधान कोंसलावासों का उद्घाटन किया और 800 मिलियन अमरीकी डालर की भारतीय ऋण श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित की जाने वाली रेलवे परियोजना के ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह में भाग लिया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर 19 नवंबर, 2010 को राष्ट्रपति राजपक्षे के दूसरे कार्यकाल के शपथग्रहण समरोह में भाग लेने के लिए कोलम्बो में थीं।

दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत

हाल के वर्षो में दक्षिण-पूर्व एशिया तथा प्रशांत एक गतिशील और तेजी से प्रगति करने वाला क्षेत्र रहा है। शेष विश्व के साथ हमारे आर्थिक कार्यकलापों के विस्तार की संभावना को देखते हुए इस क्षेत्र के देश हमारे स्वाभाविक भागीदार हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के कुछ देशों के साथ हमारा संबंध सामरिक स्तरों तक उन्नयित हुआ जबकि कुछ अन्य देशों के साथ हमारी 'पूर्वोन्मुख नीति' के अनुरूप हमारे संबंधों में विविधता आई। मिशन प्रमुखों, शासनाध्यक्षों एवं विदेश मंत्रियों के स्तर पर हुए उच्चस्तरीय कार्यकलापों से इन देशों के साथ हमारे कार्यकलापों में गतिशीलता आई।

भारत तथा आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा, वर्ष 2009-2010 में 44 बिलियन अमरीकी डालर (18 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात तथा 26 बिलियन अमरीकी डालर का आयात) तक पहुंच गया है। वर्ष 2003-2004 में द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 13.25 बिलियन अमरीकी डालर का था। प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2012 तक 70 बिलियन डालर का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे कमजोर वैश्विक आर्थिक सुधार के बावजूद प्राप्त किया जा सकता है।

मुक्त व्यापार करार के पहले भाग के रूप में अगस्त 2009 में बैंकाक में हस्ताक्षरित भारत-आसियान सेवा व्यापार करार 1 जनवरी, 2010 को लागू हुआ। यह आसियान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में हम लोगों से लोगों के बीच सम्पर्कों, धार्मिक पर्यटन, उच्च शैक्षिक संस्थाओं के बीच सम्पर्कों तथा साझे हित के मुद्दों पर दूर संचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इस क्षेत्र के देशों के साथ क्षेत्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। इन क्षेत्रों में हमारा सहयोग हमारे सभ्यतामूलक सम्पर्कों की निरन्तरता पर आधारित है। अगस्त 2010 में, 'अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण एवं उत्कृष्टता संस्थान' के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक को पारित किया जाना, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

हमारी संसदीय संस्थाओं और आसियान संसदों के बीच कार्यकलापों को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण मुहिम के अंतर्गत हमें हनोई में हाल में आयोजित आसियान अंतर्संसदीय असेंबली में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।

इस क्षेत्र के देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत ने कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस को अनुदानों, रियायती ऋणों एवं ऋण श्रृंखलाओं के जरिए सहायता प्रदान करना जारी रखा। इसके साथ ही आईटेक योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी पेशकश की गई। प्रशांत द्वीप मंच (पीआईएफ) देशों के वार्ता भागीदार के रूप में भारत क्षमता निर्माण तथा सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों एवं सतत विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशांत द्वीप के देशों के साथ भी विविध कार्यकलापों में शामिल रहा है। इसके आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी, राष्ट्रमंडल, असैनिक परमाणु सहयोग इत्यादि जैसे मुद्दों पर भारत के लिए इस क्षेत्र के अधिकांश देशों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा है।

26 जनवरी, 2011 को गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुसिलो बाम्बंग युधोयोनो की उपस्थिति से भारत और इंडोनेशिया के बीच विद्यमान सामरिक भागीदारी और मजबूत हुई।

जनवरी 2011 में आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री श्री केविन रूड के साथ रूपरेखा वार्ता के सातवें दौर में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा की आस्ट्रेलिया यात्रा से भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हितों एवं संदर्शों की समानता प्रतिबिम्बित हुई। आस्ट्रेलिया के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 22 बिलियन अमरीकी डालर (2 बि.अ.डा. का निर्यात और 20 बि.अ.डा. का आयात) के आंकड़े से आगे पहुंच गया है।

भारत के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रभाव के कारण दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश आसियान, ईएएस, बिम्स्टेक, एमजीसी तथा एआरएफ जैसे क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर भारत के साथ बेहतर कार्यकलाप करने की दिशा में आकर्षित हुए हैं।

पूर्व एशिया

वर्ष 2010 के दौरान पूर्व एशिया के साथ आर्थिक, राजनैतिक एवं सुरक्षा सम्पर्कों का पर्याप्त विस्तार हुआ। अनेक उच्चस्तरीय यात्राओं तथा महत्वपूर्ण करारों से संबंधों की गतिशीलता को कायम रखने में मदद मिली। इस अवधि की मुख्य बातों में भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह की जापान यात्रा के दौरान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) को अंतिम रूप दिया जाना तथा असैनिक परमाणु सहयोग करार पर भारत-जापान वार्ता का आरंभ होना शामिल है। वर्ष 2009 में संपन्न भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक भागीदारी करार भी वर्ष 2010 में लागू हो गया। भारत-मंगोलिया संबंधों में सौहार्द और विकास की झलक मिलती रही।

जापानः जापान के साथ हमारा संबंध भारत की 'पूर्वोन्मुख नीति' का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2010-2011 में उच्चस्तरीय यात्राओं, सहयोग के नए क्षेत्रों, बातचीत के नए तंत्रों, संयुक्त परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन तथा रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग के जरिए द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति जारी रही। (इन यात्राओं से भारत-जापान संबंधों की प्रगति को कायम रखनेमें मदद मिली।) इस वर्ष के दौरान जापान के साथ भारत के संबंधों की एक प्रमुख बात जापान के प्रधान मंत्री श्री नवोतो कान के साथ वार्षिक शिखर बैठक करने के लिए 24-26 अक्तूबर, 2010 तक प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह की जापान यात्रा रही। दोनों प्रधान मंत्रियों ने दो निम्नलिखित दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किएः ''अगले दशक में भारत-जापान सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी का विजन'' और ''व्यापक आर्थिक भागीदारी करार संपन्न किए जाने पर भारत और जापान के नेताओं के बीच संयुक्त घोषणा।'' इसके अतिरिक्त भारत और जापान के बीच वीजा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधान मंत्री जी ने जापान के प्रधान मंत्री के साथ व्यापक चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री श्री तोशिमी किताजावा ने 30 अप्रैल-1 मई 2010 तक भारत का दौरा किया और रक्षा मंत्री के साथ व्यापक बातचीत की। 15 जून, 2010 को जापान सरकार ने असैनिक परमाणु सहयोग के लिए भारत के साथ बातचीत आरंभ करने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा की। प्रथम दो प्लस दो वार्ता का आयोजन 6 जुलाई, 2010 को भारत के विदेश सचिव एवं रक्षा सचिव और जापान के उप विदेश मंत्री एवं प्रशासनिक उपमंत्री के बीच किया गया। संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 जनवरी-2 फरवरी 2010 को जापान का सद्भावना दौरा किया। भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर टोक्यो में 16 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए।

कोरिया गणराज्यः हाल के वर्षों में भारत-कोरिया गणराज्य संबंधों में तीव्र प्रगति हुई है और हितों की समानता तथा पारस्परिक सद्भावना के कारण ये बहुफलकीय बन गए हैं। अगस्त 2009 में व्यापक आर्थिक भागीदार करार पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी जीवन्त एवं गतिशील बन गए। सीईपीए, जो 1 जनवरी, 2010 से लागू हुआ, ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में खासा योगदान दिया है। कोरिया गणराज्य के व्यापार मंत्री महामहिम श्री किम जांग हुन ने व्यापार मंत्रियों के नेतृत्व में संयुक्त समिति की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए जनवरी में भारत का दौरा किया। इसमें सीईपीए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की गई। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा की 17-19 जून, 2010 तक कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोगों से लोगों के बीच सम्पर्कों में वृद्धि किए जाने के महत्व का पता चला। उन्होंने कोरिया गणराज्य के विदेश और व्यापार मंत्री श्री यू म्युंग ह्वान के साथ भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता भी की। रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी ने 3 सितंबर, 2010 को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की और रक्षा क्षेत्र से संबद्ध दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जिससे सुदृढ़ भावी संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अक्तूबर 2010 में सियोल में द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए गए जिससे मूल लोगों की बेहतर आवाजाही का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मंगोलियाः भारत उच्च शिक्षा, कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में मंगोलिया को तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग देता आ रहा है। मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है जबकि भारत ने मंगोलिया को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का समर्थन किया है। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने 26-30 जून, 2010 तक मंगोलिया का दौरा किया। स्टेट ग्रेट हुराल ऑफ मंगोलिया (मंगोलियाई संसद) के अध्यक्ष श्री डी. डेम्बेरल ने लोक सभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर 8-14 दिसंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया।

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके)
भारत तथा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, जो कि मानवीय व मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थे। वर्ष 2010-2012 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही वर्ष 2010 के दौरान संस्कृति, खेल व शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान में प्रगति जारी रही।

यूरेशिया

रूसः रूस के साथ भारत के संबंध स्थाई हैं तथा समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं; वे भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। गहन हो रहे द्विपक्षीय संबंधों की विलक्षण ताकत और परिपक्वता को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों ने इन्हें इस वर्ष 'विशेष एवं विशेषीकृत भागीदारी'का नाम दिया। रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा एवं हाइड्रो कार्बन्स समेत ऊर्जा के क्षेत्रों में घनिष्ठ राजनीतिक समन्वय एवं गहन भागीदारी हमारी सामाजिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं। हाल के वर्षों में, हमने व्यापार एवं निवेश संबंधों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है; दोनों देश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध बने हुए हैं कि आर्थिक संबंध सामरिक साझेदारी के एक अतिरिक्त स्तंभ के रूप में विकसित हो।

2009 में उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों में जो गहनता थी वह 2010 में भी वर्षभर जारी रही। वास्तव में, इस दृष्टि से यह एक अनोखा वर्ष था कि हमने रूस के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष दोनों की अगवानी की - मार्च 2010 में प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमीर पुतिन की तथा दिसम्बर 2010 में राष्ट्रपति श्री दामित्री मेदवेदेव की। इन दो यात्राओं ने दोनों देशों को न केवल हमारी सामरिक साझेदारी के पहले दशक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया, अपितु अगले दशक में हमारे संबंधों के लिए पहले से भी अधिक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार करने का भी अवसर प्रदान किया।

मध्य एशियाः मध्य एशिया जो हमारे विस्तारित पड़ोस का अंग है, के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक एवं मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत ने मध्य एशिया के पांचों देशों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोग संबंध दृढ़ता से विकसित किया है। मध्य एशिया के पांच देशों में से तीन देशों अर्थात तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उजबेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमाएं लगती हैं और अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में सामरिक कार्यकलापों का स्थानांतरण होने के साथ ही इस क्षेत्र का बूराजनैतिक महत्व बढ़ गया है। कैस्पियन घाटी में ऊर्जा के भंडारों समेत अपने भौगोलिक अवस्थान एवं व्यापक प्राकृतिक संसाधनों के कारण मध्य एशिया के गणतंत्र भारत के लिए भू-सामरिक एवं भू-आर्थिक रूचि के क्षेत्र हैं। मध्य एशिया की प्रगति में एक भागीदार के रूप में भारत क्षमता निर्माण और विकास की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। भारत मध्य एशिया के देशों का मित्र एवं साझेदार है तथा उनके साथ इसकी परम्परागत सदाशयता है जिसकी झलक आईटी और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं तथा भारतीय फिल्मों और संस्कृति के लिए इस क्षेत्र में विद्यमान प्रेम में मिलती है। उच्चस्तरीय राजनैतिक वार्ता के अतिरिक्त इस वर्ष इस क्षेत्र के साथ कार्यकलापों पर विशेष बल दिया जाता रहा। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति श्री गुरबांगुली बेर्दिमुहामेदेव ने मई 2010 में भारत का राजकीय दौरा किया। अप्रैल 2010 में वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नजरबायेव से मुलाकात की। अन्य उच्चस्तीय यात्राओं में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने मई एवं जून में क्रमशः कजाकिस्तान एवं उजबेकिस्तान का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने अंतर्सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करने के लिए ने फरवरी 2010 में तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया।

काकेससः काकेसस क्षेत्र के देशों, अर्थात आर्मेनिया, अजरबैजान एवं जार्जिया के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं। हम इन देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने तथा उनके साथ अपनी आर्थिक भागीदारी भढ़ाने को बहुत महत्व देते हैं। भारत ने इन देशों को क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करके तथा व्यापार एवं निवेश संबंधों में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके मंत्री एवं अधिकारी स्तरीय दौरों के माध्यम से नियमित संपर्क बनाए रखा। अर्मेनिया के विदेश मंत्री श्री एडवर्ड नेलबंडियन ने नवम्बर 2010 में भारत का दौरा किया।

उक्रेन एवं बेलारूसः उक्रेन एवं बेलारूस के साथ हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता जारी रही। 22 सितम्बर 2010 को सचिव (पूर्व) सुश्री विजय लता रेड्डी के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के 8वें दौर के लिए उक्रेन के उप विदेश मंत्री श्री विक्टर मायको ने नई दिल्ली का दौरा किया। परामर्श के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को जीवंत बनाने का निर्णय लिया गया। अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बेलारूस के पहले उप प्रधानमंत्री श्री व्लादिमीर सेमाक्षो ने भारत का दौरा किया। श्री व्लादिमीर सेमाक्षो ने मई 2010 में जी-15 शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में तेहरान में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा से मुलाकात की।

संघाई सहयोग संगठन (एससीओ): भारत संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को काफी महत्व देता है, जिसके अधिकांश सदस्य हमारे विस्तारित पड़ोसी देश हैं। भारत प्रेक्षक राज्य के रूप में एससीओ में रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा एससीओ मंच पर विस्तारित एवं अधिक सार्थक भूमिका निभाने की अपनी इच्छा को लगातार व्यक्त किया है। भारत अपने क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता एवं विकास लाने में एससीओ की भूमिका को महत्व देता है तथा इस संगठन में और अधिक योगदान करने के लिए तैयार हैं। एससीओ की राज्य परिषद के प्रमुखों की

बैठक में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा की सहभागिता तथा 25 नवम्बर, 2010 को दुशान्बे में सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की परिषद की शिखर बैठक में विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे की सहभागिता इस संगठन में सार्थक योगदान करने की हमारी अभिलाषा को अभिव्यक्त करते हैं।

भारत-रूस-चीन (आईआरसी): भारत-रूस-चीन (आईआरसी) त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक प्रमुख क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों के स्पष्ट आदान-प्रदान के लिए तीन उभरती एवं प्रभावशाली वैश्विक शक्तियों के विदेश मंत्रियों के लिए एक अनोखा मंच है। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने भारत, रूस एवं चीन के विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक के लिए 14-15 नवम्बर, 2010 को वुहान, चीन का दौरा किया। तीनों विदेश मंत्रियों ने आपदा प्रबंधन, कृषि एवं स्वास्थ्य देखभाल में त्रिपक्षीय क्षेत्रगत सहयोग की समीक्षा की तथा संयुक्त राष्ट्र सुधार, वैश्विक आर्थिक वास्तुशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटना, उभरते बाजारों में सहयोग, जलवायु परिवर्तन, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, एससीओ, तथा अफगानिस्तान, ईरान एवं कोरिया प्रायद्वीप की स्थिति समेत अनेक क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का विस्तारित आदान-प्रदान किया।

खाड़ी, पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका

भारत ने खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक एवं परम्परागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं सहयोग को बनाए रखा। तेल एवं गैस के बढ़ते आयात तथा व्यापार एवं निवेश के बढ़ते अवसरों के समानान्तर, इस संबंध को सुदृढ़ करने एवं विस्तारित करने के लिए वर्ष 2010 में इस क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर सक्रिय कदम उठाए गए। इस वर्ष के दौरान अनेक द्विपक्षीय उच्च स्तरीय दौरों का आयोजन हुआ।

खाड़ी क्षेत्र भारत का एक प्रमुख व्यापार साझेदार है। 2009-2010 के दौरान कुल दो तरफा व्यापार लगभग 107 बिलियन अमेरिकी डालर था जिससे खाड़ी क्षेत्र वर्ष के लिए सबसे भड़ा व्यापार साझेदार बन गया। सभी खाड़ी देश मिलकर हमारे कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 70 प्रतिशत पूरा करते हैं तथा हमारी ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकरीबन 6 मिलियन भारतीय खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तथा काम करते हैं। हर वर्ष 30 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक धन बेजने वाले ये भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सहारा हैं। नवंबर 2010 में भारत की राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण संवेग मिला।

अनेक उच्च स्तरीय दौरों एवं विचार विनिमयों ने भारत तथा पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों के मध्य विद्यमान मजबूत संबंध को प्रगाढ़ बनाने में सहायता की। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आदान-प्रदान में से प्रमुख भारत के राष्ट्रपति का सीरिया दौरा था जो 26-29 नवम्बर, 2010 तक सम्पन्न हुआ। भारत ने 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयार्क में आयोजित फिलिस्तीन पर मंत्री स्तरीय बैठकों में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा की सहभागिता के माध्यम से फिलिस्तीनियों के उद्देश्य के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता एवं समर्थन को दोहराया तथा निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) में एक मिलियन अमेरिकी डालर का अपना वार्षिक अंशदान किया। मिश्र, लीबिया, जिबूती तथा सोमालिया के मंत्रियों समेत अफ्रीका के 12 देशों के मंत्रियों के साथ विचारों का सीधे आदान-प्रदान करते हुए विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 16 अगस्त, 2010 को अखिल अफ्रीका ई-नेटवर्क के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सीरिया के प्रधान मंत्री द्वारा 29 दिसम्बर, 2010 को भारत-सीरिया सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 12 जुलाई, 2010 को अपने पीएसएलवी-सी15 लांच वाहन के माध्यम से अल्जीरिया के उपग्रह अलसैट-2ए को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया।

अफ्रीका

वर्ष 2010 द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय स्तरों पर भारत अफ्रीकी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पूर्व एवं दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र के बीस देशों के साथ भारत के संबंध अनेक उच्चस्तरीय यात्राओं एवं अनेक करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने से सुदृढ़ हुए। मार्च 2010 में भारत यात्रा पर आए अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस), 2008 के अंतर्गत भारत-अफ्रीका सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने के उपरान्त प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा शिखर सम्मेलन में व्यक्त वचनबद्धताओं का कार्यान्वयन आरंभ करने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए। संबंधित मंत्रालयों एवं संस्थानों की सहायता से अनेक क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया जिनमें से कुछ की शुरुआत कर दी गई है। इनमें कृषि क्षेत्र में 50 स्नात्कोत्तर और 25 डाक्टोरल छात्रवृत्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। अफ्रीकी संघ आयोग के परामर्श से 19 क्षमता निर्माण संस्थाओं की स्थापना जैसी अनेक महत्वपूर्ण वचनबद्धताएं कार्यान्वयन के चरण में पहुंच गई हैं। अफ्रीका में क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के प्रयास किए गए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2010 में क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया। इन सभी को इस प्रक्रिया में शामिल करने की पहल की गई, ताकि भारत-अफ्रीका सहयोग कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की जा सके और कार्यान्वयन प्रक्रियाएं तय की जा सकें।

अनेक महत्वपूर्ण यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सम्मेलनों के दौरान अतिरिक्त समय में हुई बैठकों से वर्ष 2010 के दौरान पश्चिम अफ्रीका के 25 देशों के साथ भारत के संबंधों का निरन्तर विकास होता रहा। इस वर्ष के दौरान मंत्रालय की अग्रणी पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का कार्यान्वयन 12 से अधिक देशों में किया गया जिसके फलस्वरूप इस परियोजना में शामिल अफ्रीकी देशों की संख्या 43 हो गई है।

बुनियादी ढांचे का विकास करने तथा प्राकृतिक आपदाओं के उपरान्त पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए पश्चिम अफ्रीका के देशों को अनेक ऋण श्रृंखलाएं और सहायता अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2009-2010 के दौरान भारत और पश्चिम अफ्रीका के बीच 18.04 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ; अर्थात, पिछले वर्ष की तुलना में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

यूरोप

अनेक राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों, मंत्रियों और अधिकारियों की यात्रा से पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हमारे संबंध संवर्धित हुए। इस वर्ष के दौरान रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित अन्य विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विकास हुआ। उच्च स्तरीय यात्राओं के अतिरिक्त नियमित संवाद के जरिए संस्थागत सम्पर्क भी कायम रखे गए।

प्रधान मंत्री जी ने 11वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 2010 में बेल्जियम का दौरा किया। लिस्बन संधि लागू होने के उपरान्त यह उनकी पहली यात्रा थी। बेल्जियम के साथ ब्रसेल्स में एक द्विपक्षीय शिखर बैठक का भी आयोजन किया गया। प्रधान मंत्री जी राष्ट्रपति क्रिश्चियन उल्फ और चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बैठकें करने के लिए जर्मनी में भी रुके।

वर्ष 2010 के दौरान अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भारत का भी दौरा किया। बेल्जियम के युवराज फिलिप ने 350 से अधिक सदस्यों वाले आर्थिक मिशन के प्रमुख के रूप में 20-27 मार्च, 2010 तक भारत का दौरा किया। उनके प्रतिनिधिमंडल में बेल्जियम की अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों की 60 कंपनियों के प्रतिनिधि थे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को और गहन बनाना था। युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री डेविड कैमरून ने 27-29 जुलाई, 2010 तक भारत का दौरा किया। प्रधान मंत्री जी के साथ व्यवसाइयों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं खिलाड़ियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था। इस यात्रा के दौरान न सिर्फ प्रधान मंत्री स्तर पर अपितु विभिन्न मंत्रियों के साथ भी आपसी हित के प्रासंगिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस चार्ल्स अर्ल ऑफ वेसेक्स, प्रिंस एडवर्ड तथा मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट-II ने भी राष्ट्रमंडल खेलों के सिलसिले में अक्तूबर 2010 में भारत का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी ने 4-7 दिसंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया और पारस्परिक हित के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर हमारे प्रधान मंत्री जी के साथ चर्चा की। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सामरिक सहभागिता को बढ़ावा मिला।

प्रधान मंत्री जी ने जून 2010 में टोरंटो में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी अतिरिक्त समय में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी और ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात की थी। उन्होंने नवंबर 2010 में सियोल में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी अतिरिक्त समय में ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात की थी। अप्रैल 2010 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बैठकें की। पूरे वर्ष भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान और सभ्य समाज संवाद जारी रहे।

मध्य यूरोप के देशों और नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंध पारम्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इस क्षेत्र के देशों ने भारत की उत्तरोत्तर विकसित हो रही अर्थव्यवस्था और इसके विशाल बाजार में उपलब्ध अवसरों की पहचान कर ली है और ये देश विद्यमान संबंधों का लाभ उठाने और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए उत्सुक हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में आई सामान्य मंदी के बावजूद आर्थिक विकास की उच्च दर कायम रखने में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदर्शित लोचनीयता के कारण भी भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की इच्छा को बल मिला।

नियमित राजनैतिकि आदान-प्रदानों के जरिए विद्यमान संबंधों के संवर्धन, समानताओं एवं संपूरकताओं का पता लगाने के जरिए आर्थिक संबंधों के विस्तार, संस्थागत संपर्कों एवं संवादों के संवर्धन तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए हम इन देशों के साथ अपने कार्यकलापों का विस्तार करना चाहते हैं। जिन क्षेत्रों में उपयोगी कार्यकलाप हुए हैं, उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा एवं पर्यावरण से संबंध प्रौद्योगिकियां इत्यादि शामिल हैं। इन देशों के साथ सामानों एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश प्रवाहों में वृद्धि करना भी भारत की प्राथमिकता है।

इनमें से अनेक देशों के साथ रक्षा, संस्कृति, आर्थिक निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पर्यटन सहित अनेक क्षेत्रों में करार संपन्न किए गए हैं अथवा इन पर बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों के निरन्तर पहुंचने से अनेक देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों एवं श्रम गतिशीलता भागीदारियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा अनेक देशों के साथ इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।

इस अवधि के दौरान मध्य यूरोपीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैंः भारत के उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी की चेक गणराज्य और क्रोएशिया यात्रा (6-11 जून, 2010); विदेश राज्य मंत्री की रोमानिया (9-10 अप्रैल, 2010), हंगरी (1-3 नवंबर, 2010) और स्लोवेनिया एवं आइसलैंड (30 अगस्त-3 सितंबर 2010) यात्रा। इस क्षेत्र से हुई भारत की यात्राओं में, पोलैंड के प्रधान मंत्री (6-8 सितंबर, 2010); लेच्टेंस्टिन के राजकुमार (14-20 नवंबर, 2010); डेनमार्क के उप प्रधान मंत्री (14-15 दिसंबर, 2010); फिनलैंड के विदेश मंत्री (3-5 मई, 2010); और स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री (30 अगस्त, 2010) की यात्राएं शामिल हैं।

भारत और यूरोपीय संघ सामरिक भागीदार हैं जिनके संबंध लोकतंत्र के साझे मूल्यों और सिद्धांतों, विधिसम्मत शासन तथा मानवाधिकार और मूलभूत आजादियों के प्रति सम्मान पर आधारित हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सर्वोच्च स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किए गए। भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य योजना, जिसे 2005 में पारित किया गया और 2008 में जिसकी समीक्षा की गई थी, में भारत-यूरोपीय संघ के बीच विद्यमान संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। 10 दिसंबर, 2010 को ब्रसेल्स में आयोजित 11वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक लिस्बन संधि के लागू होने के बाद पहली शिखर बैठक थी। इससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक भागीदारी को नया संवेग मिला।

आज यूरोपीय संघ हमारे सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के प्रभावशाली लोग रहते हैं। व्यापार और निवेश हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है परन्तु समग्र द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आया है जिसका संकेत नई और उदीयमान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए साझे नजरिए का विकास करने के हमारे द्विपक्षीय प्रयासों से मिलता है। दोनों पक्षों के बीच मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, कोंसली एवं वीजा सेवा, सुरक्षा एवं आतंकवाद का मुकाबला इत्यादि जैसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमरीका: नवंबर 2009 में प्रधान मंत्री जी की वाशिंगटन डीसी की राजकीय यात्रा और नवंबर 2010 में अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के साथ ही भारत-अमरीका सामरिक भागीदारी नए स्तर तक पहुंच गई। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि भारत-अमरीका भागीदारी न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि 21वीं सदी में वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए अपरिहार्य है। राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा की आधारशिला पहली मंत्रिस्तरीय भारत-अमरीका सामरिक वार्ता के दौरान रखी गई जिसकी सहअध्यक्षता विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन द्वारा जून 2010 में वाशिंगटन डीसी में की गई।

इस वर्ष के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में शामिल हैं: असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करार को कार्यान्वित करने के लिए दोनों सरकारों द्वारा शेष उपायों को पूरा किया जाना; विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के भारत के दावे को अमरीका द्वारा समर्थन दिए जाने संबंधी राष्ट्रपति ओबामा की घोषणा; भारत के लिए निर्यात नियंत्रणों में ढील देने संबंधी अमरीकी निर्णय; चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए अमरीकी समर्थन की घोषणा; पूर्व एशिया वार्ता सहित विस्तारित रणनीति परामर्श; जुलाई 2010 में हस्ताक्षरित आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग से संबंधित पहल; नई होमलैंड सुरक्षा वार्ता; मार्च 2010 में संपन्न कृषि एवं खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; अप्रैल 2010 में वित्तीय एवं आर्थिक भागीदारी की शुरुआत; भारत द्वारा स्थापित किए जा रहे वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अनेक नई पहलकदमियां तथा राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान लोकतंत्र एवं विकास के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की शुरुआत करना।

कनाडा: विश्व की आधुनिकतम अर्थव्यवस्थाओं में से एक तथा जी-20 के एक सदस्य देश कनाडा के साथ संबंधों के आर्थिक आयाम को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिए जाने के साथ कनाडा के साथ भारत के संबंधों को नई गतिशीलता मिली। टोरंटो, वाशिंगटन डीसी और सियोल में कनाडाई प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर के साथ हुई हमारे प्रधान मंत्री जी की बैठकों के साथ-साथ अनेक द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय और आधिकारिक बैठकें भी हुईं। दोनों सरकारों ने जून 2010 में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए; सितंबर 2010 में व्यापार और निवेश पर पहले मंत्रिस्तरीय संवाद का शुभारंभ किया; नवंबर 2010 में व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर बातचीत की शुरुआत की और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार पर बातचीत को आगे बढ़ाया। दोनों सरकारें निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल से संबद्ध कार्यकारी दल गठित करने पर सहमत हुए जिसमें मुख्य तौर पर बुनियादी ढांचे, ऊर्जा एवं खनन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा पर बल दिया जाएगा।

लैटिन अमरीका और कैरेबिया

लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों में गतिशीलता जारी रही। सभी स्तरों पर कार्यकलापों में गहनता आई जिससे इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को और सुदृढ़ और गहन बनाने में मदद मिली। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अप्रैल 2010 में इब्सा एवं ब्रिक शिखर बैठकों के लिए ब्राजील का दौरा किया और राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधान मंत्री जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और मैक्सिको के राष्ट्रपति श्री काल्डेरोन से नवंबर 2010 में सियोल में आयोजित जी-20 शिखर बैठक के दौरान भी मुलाकात की।

भारत के विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने सितंबर 2010 में न्यूयार्क में आयोजित 65वें संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरा अतिरिक्त समय में भारत-सीका संवाद में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री ने न्यूयार्क में गयाना के राष्ट्रपति श्री भरत जगदेव से भी मुलाकात की। मैक्सिको और कोस्टारिका के विदेश मंत्रियों ने भारत का दौरा किया जिनके साथ विदेश मंत्री जी की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। मई 2010 में विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने मई क्रांति के 200 वर्ष होने पर आयोजित समारोहों में भाग लेने के लिए अर्जेन्टीना का दौरा किया। उन्होंने अलायंस ऑफ सिवलिजेशंस की बैठक में भाग लेने के लिए रियो का भी दौरा किया।

इस क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार 17 बिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े तक पहुंच गया है और इस क्षेत्र में हमने लगभग

13 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। इस वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के देशों के साथ छः द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ कर सूचना आदान-प्रदान कार्यक्रमों (टीआईईए) को भी अंतिम रूप दिया गया है। भारत-मर्कोसुर (स्पेनिशः मर्काडो कोमुन डेल सुर, अंग्रेजीः दक्षिणी साझा बाजार) अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) पर संयुक्त प्रशासन समिति की दूसरी बैठक का आयोजन 15-16 जून, 2010 तक नई दिल्ली में किया गया। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र के देशों को कुल 428 आईटेक सीटें आवंटित की गईं। अल-सल्वाडोर और निकारागुआ की सरकारों के अनुरोध पर इन देशों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों का विस्तार एक और वर्ष के लिए कर दिया गया। हमने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों, विशेष रूप से जमैका, सेंट लूसिया, कोस्टारिका, चिली, हैती, कोलम्बिया और वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान की। मैक्सिकों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र प्रचालित हो गया और आईसीसीआर की अनेक मंडलियों ने इस क्षेत्र में अपनी प्रस्तुतियां दी। अर्जेन्टीना, उरुग्वे और पराग्वे में भारत महोत्सवों का आयोजन किया गया।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

वर्ष 2010 संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा। भारत को 1 जनवरी, 2011 से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया। अक्तूबर 2010 में आयोजित चुनावों में भारत को कुल 190 वैध मतों में 187 मत प्राप्त हुए, जो सुरक्षा परिषद में चुने गए देशों को प्राप्त सर्वाधिक मत हैं। भारत ने जुलाई 2010 में यूएन एन्टिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन (यूएन वुमेन) के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए भारत और जी-4 के अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने के एक उपाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर पाठ आधारित वार्ताओं के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल का नेतृत्व किया। अनुवर्ती पाठ आधारित वार्ताओं में संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थाई एवं अस्थाई दोनों श्रेणियों का विस्तार किए जाने और परिषद के कार्य करने के तौर तरीकों में सुधार लाए जाने की इच्छा व्यक्त की।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सक्रिय बनाने तथा संयुक्त राष्ट्र के विकास प्रयासों में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इकोसॉस) को सुदृढ़ बनाए जाने के संबंध में हुई चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने मानवाधिकारों एवं सामाजिक मुद्दों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संगठनों के कार्यकलापों में सकारात्मक तरीके से भाग लिया, जो सहिष्णुता तथा मानवाधिकारों एवं मानवीय मूल्यों के सम्मान की हमारी ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप है। भारत के उम्मीदवार चंद्रशेखर दासगुप्ता को 27 अप्रैल, 2010 को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इकोसॉस) की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध समिति के लिए सर्वाधिक मतों से चुना गया। भारत ने डब्ल्यूआईपीओ के साथ अपना सकारात्मक कार्यकलाप जारी रखा और इसने बौद्धिक सम्पदा एवं विकास, कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकारों, व्यापार चिह्नों, औद्योगिक डिजाइनों एवं भौगोलिक संकेतों, पारम्परिक ज्ञान, लोकगीत एवं जेनेरिक संसाधनों पर अंतर्सरकारी समितियों एवं प्रवर्तन से संबद्ध परामर्शी समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा। भारत को गैर सरकारी संगठनों से संबद्ध समिति, एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध आयोग के लिए भी ध्वनिमत से चुना गया। भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) के प्रारूप पर बातचीत में प्रगति करने तथा इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए दबाव बनाए रखा। भारत, जो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों में लगभग 9,000 सैनिकों की तैनाती के साथ सैनिकों से योगदान करने वाले तीन सबसे बड़े योगदानकर्ता देशों में है, ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में अपने योगदान और सहभागिता को जारी रखा।

इसके अतिरिक्त भारत ने गैर संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय संगठनों एवं समूहों, यथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम), राष्ट्रमंडल तथा सोमालिया तट पर समुद्री डकैती से संबद्ध सम्पर्क समूह (सीजीपीसीएस) में भी अपनी भागीदारी को बढ़ावा दिया। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने सितंबर 2010 में आयोजित 65 संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान अतिरिक्त समय में नैम समन्वय ब्यूरो की मंत्रिस्तरीय बैठक तथा राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) की रजत जयंती के दौरान भारत ने सार्क को क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के एक गतिशील वाहन में परिवर्तित करने की दिशा में अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत ने असमान एवं गैर पारस्परिक तरीके से सार्क में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जारी रखा। क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने में योगदान देने के अतिरिक्त इसने सार्क के अन्य सदस्य देशों को क्षेत्रीय परियोजनाओं पर पहलकदमियां करने के लिए भी प्रेरित किया। वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) और सार्क विकास कोष (एसडीएफ) जैसी अग्रणी परियाजनाओं के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति हुई। अगस्त 2010 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों का आरंभ होना तथा विश्वविद्यालय के प्रचालन हेतु शेष प्रक्रियाओं का अनुमोदन किया जाना सार्क के दीर्घावधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सदस्य देशों द्वारा मिलकर कार्य करने की इच्छा का प्रतीक है। अप्रैल माह में थिम्पू में सचिवालय की स्थापना के साथ सार्क विकास कोष को पूर्ण रूप से प्रचालित किए जाने तथा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से दक्षिण एशिया के लोगों के लिए सामाजिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने की दिशा में इस

संगठन को पर्याप्त संवेग प्राप्त हुआ। सार्क को और सक्रिय बनाने के प्रयासों में प्रगति हुई है, हालांकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सुविधा के क्षेत्र में पूर्ण क्षमताएं अभी प्राप्त नहीं की जा सकी हैं। हम सार्क को सुदृढ़ एवं पुष्पित-पल्लवित करने के प्रयास जारी रखेंगे जिसका उद्देश्य सार्क चार्टर में सन्निहित प्रधान लक्ष्यों के अनुरूप दक्षिण एशिया की जनता के हित कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले (डीसा)

भारत ने वैश्विक, निष्पक्ष एवं सत्यापनीय परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों को अपना समर्थन देना जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा के वक्तव्य और 24 सितंबर, 2010 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आहूत निरस्त्रीकरण पर उच्चस्तरीय सम्मेलन में उनकी भागीदारी के जरिए भी इस तथ्य को रेखांकित किया गया। प्रधान मंत्री ने 12-13 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया और वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की। भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन तथा कतिपय पारम्परिक हथियारों से संबद्ध सम्मेलन में भी भाग लिया। भारत ने हेग में रासायनिक हथियारों पर राज्य पक्षकारों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और रासायनिक हथियारों को नष्ट किए जाने सहित रासायनिक हथियार अभिसमय के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत ने जिनेवा में आयोजित जैविक हथियार अभिसमय के राज्य पक्षकारों की वार्षिक बैठक में भी भाग लिया जिसमें जैविक अथवा विषैले हथियारों के तथाकथित उपयोग के मामले में सहायता और समन्वय तथा राष्ट्रीय क्षमताओं में सुधार लाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। भारत ने इस वर्ष के दौरान आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक तथा एशिया में कार्यकलापों एवं विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध शिखर बैठक में भी अपने विचार रखे।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

भारत ने अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने तथा आर्थिक एवं वित्तीय संकट, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा जैसी समसामयिक वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत करने और इनका समाधान ढूंढ़ने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय आर्थिक समूहों में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना जारी रखा। भारत ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत-आसियान, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, इब्सा, एसीडी, एसेम, जी-15, आईओआर-एआरसी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूहों के साथ अपने कार्यकलापों को जारी रखा और इसे सुदृढ़ बनाया।

भारत के उप राष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अक्तूबर 2010 में आयोजित आठवें एसेम (एशिया-यूरोप बैठक) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बेल्जियम गया। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतनिधिमंडल ने अप्रैल 2010 में चौथी इब्सा शिखर बैठक तथा दूसरी ब्रिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील का दौरा किया। चौथी इब्सा शिखर बैठक में ब्राजीलिया घोषणा के अतिरिक्त दो दस्तावेजों और दो समझौता ज्ञापनों को अंगीकार किया गया। दूसरी ब्रिक शिखर बैठक में एक संयुक्त वक्तव्य पारित किया गया तथा ब्रिक विकास बैंकों के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। अक्तूबर 2010 में वियतनाम में आयोजित आठवीं भारत-आसियान बैठक तथा पांचवे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंउल का नेतृत्व करते हुए प्रधान मंत्री जी ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आसियान सहयोग के लिए नई पहलकदमियों की घोषणा की।

इस अवधि के दौरान भारत ने विभिन्न मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लिया। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने सर्विया में आयोजित समूह पंद्रह (जी-15) के 14वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिक एवं इब्सा व्यवसाय मंच के संयुक्त सत्र में भाग लिया। ब्रिक विदेश मंत्रियों ने सितंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान न्यूयार्क में बैठक की। मानव संसाधन विकास मंत्री डा. डी. पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यमन में आईओआर-एआरसी की मंत्रिस्तरीय परिषद की 10वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के उपरान्त एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डा. डी. पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में भारतीय प्रतनिधिमंडल ने तेहरान में आयोजित 9वें एशिया सहयोग संवाद में भाग लेने के लिए नवंबर 2010 में तेहरान का दौरा किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिसंबर 2010 में श्रीलंका में बिम्स्टेक स्थाई सचिवालय की स्थापना पर संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक और नवंबर 2010 में कैंडी में कृषि सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की तीसरी बैठक में भाग लिया।

जी-20

भारत में जी-20 बैठकों में सक्रिय भागीदारी करनी जारी रखी। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने ''सुधार और नई शुरुआत'' विषय पर टोरंटो, कनाडा में 26-27 जून, 2010 तक आयोजित चौथे जी-20 शिखर सम्मेलन और ''आर्थिक संकट के उपरान्त साझा विकास'' विषय पर सियोल, दक्षिण कोरिया में 11-12 नवंबर, 2010 तक आयोजित जी-20 के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत ठोस, सतत एवं संतुलित विकास; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सुधार; वित्तीय नियामक सुधार; तथा जी-20 की विकास कार्यसूची सहित जी-20 शिखर सम्मेलन में लिए गए सभी निर्णयों के कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण मानता है।

तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग और विकास भागीदारी

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटेक) कार्यक्रम, अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (इस्केप), तथा कोलम्बो योजना के अंतर्गत तकनीकी सहयोग स्कीम (टीसीएस) विकासशील विश्व के साथ भारत की विकास भागीदारी और सहयोग के महत्वपूर्ण घटक हैं। मांग आधारित एवं अनुक्रियान्मुख ये कार्यक्रम दक्षिण-दक्षिण सहयोग की रूपरेखा के अंतर्गत भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण एवं गतिशील अंग हैं जिनका उद्देश्य क्षमता निर्माण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। विभिन्न देशों में इन सहकारी कार्यकलापों की उपयोगिता और प्रासंगिकता इस बात से प्रतिबिंबित होती है कि इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इसने वस्तुतः विकासशील विश्व में एक ब्रांड का नाम प्राप्त कर लिया है।

वर्ष 2010-2011 के दौरान आईटेक/स्केप के अंतर्गत 5,500 असैनिक प्रशिक्षण स्लाट्स 159 विकासशील देशों को आवंटित किए गए। ये स्लाट्स उनकी रुचि के क्षेत्रों में उनके लाभार्थ प्रदान किए गए। कोलम्बो योजना की टीसीएस के अंतर्गत कोलम्बो योजना की टीसीएस के सदस्य देशों में से 18 सहभागी देशों को लगभग 500 असैनिक प्रशिक्षण स्लाट्स आवंटित किए गए। अनेक आईटेक भागीदार देशों के 800 से अधिक रक्षा कार्मिकों को भारत के विभिन्न रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण स्लाट्स आवंटित किए गए। रक्षा सेवा तथा असैनिक क्षेत्र के अनेक विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति कम्बोडिया, इथोपिया, फिजी, ग्रेनाडा, गयाना, लाओस, लेसोथो, मारीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, नामीबिया सेशल्स, उगांडा, जाम्बिया इत्यादि जैसे देशों में की गई। मुख्यतः पुरातत्व संरक्षण, सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी तथा लघु एवं मझोले उपक्रमों के क्षेत्र में बुरुंडी, कम्बोडिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनकन गणराज्य, इक्वाडोर, अल-सल्वाडोर, फिजी, ग्रेनाडा, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, निकारागुआ, सीरिया, वियतनाम और जिम्बाब्वे जैसे देशों में अनेक द्विपक्षीय परियोजनाएं चलाई गईं। आपदा राहत सहायता के अंतर्गत चिली, लाइबेरिया, माल्दोवा, म्यामां, नाइजर, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों को नकद दान के रूप में सहायता प्रदान की गई। गयाना और मोंटीनिग्रो में व्यवहार्यता अध्ययन किए गए।

निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी)

भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र उदारीकरण तथा शेष विश्व के साथ इसके बढ़ते एकीकरण के कारण हाल के वर्षों में विदेशों में भारत के आर्थिक और व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता रहा है। विदेश स्थित अपने मिशनों के जरिए विदेश मंत्रालय भारत के विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। वर्ष 2010-2011 के दौरान हमारे मिशनों को उदीयमान अवसरों का लाभ उठाने के लिए 8.50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। भारतीय मिशन बाजार, सर्वेक्षण, सेमिनारों, कार्यशालाओं, क्रेता-बिक्रेता बैठकों तथा औद्योगिक कार्यकलापों जैसे प्रचारात्मक कार्य करते हैं।

मंत्रालय ने निवेश और व्यापार से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलजुलकर कार्य किया और विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ सम्पर्क जारी रखते हुए उन्हें उनके विदेशी कार्यकलापों में सहायता प्रदान की। आईटीपी प्रभाग की वेबसाइट www.indiabusiness.nic.in का नाम और इसके वार्षिक प्रकाशन 'इंडिया-डायनामिक बिजनेस पार्टनर' के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

ऋण श्रृंखलाएं अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमरीका में हमारी आर्थिक रणनीति के महत्वपूर्ण घटक बनी रही। वर्ष 2010-2011 के दौरान 2548.33 मिलियन अमरीकी डालर की 16 ऋण श्रृंखलाएं दी गईं जिनमें अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बंगलादेश को दी गई। एक बिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला, रेलवे परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को दी गई 382.37 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला, अवसंरचना विकास के लिए नेपाल को दी गई 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला, चीनी उद्योग के लिए इथोपिया को दी गई 213.3 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला, विद्युत परियोजना के लिए लाओ पीडीआर को दी गई 72.55 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला और विद्युत पारेषण लाइनों के लिए केन्या को दी गई 61.6 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला शामिल हैं।

ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा आयातों पर देश की उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को दिए जा रहे महत्व के कारण वर्ष 2009 में ऊर्जा सुरक्षा एकक को एक पूर्ण प्रभाग के रूप में उन्नयित करने का निर्णय लिया गया था। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों के लिए विदेश मंत्रालय में नोडल केंद्र के रूप में ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने ऊर्जा से जुड़े सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रभागों के साथ निकट समन्वय बनाए रखा और ऊर्जा मुद्दों पर उनके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) में भारत के शामिल होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसकी स्थापना 26 जनवरी, 2009 को की गई थी। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने तकनीकी कार्यबल तथा प्रस्तावित तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन की संचालन समिति की बैठकों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप 11 दिसंबर, 2010 को अश्गाबाद में आयोजित टीएपीआई शिखर बैठक में टीएपीआई अंतर्सरकारी करार और गैस पाइप लाइन रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा सुरक्षा के अतिरिक्त ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग को खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का भी अधिदेश दिया गया है। यह प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परामर्शों के लिए विभिन्न एजेंसियों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों की अनुक्रियाओं का समन्वयन करता है।

प्रोतोकोल

अप्रैल-दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान राज्याध्यक्ष, उप राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष और विदेश मंत्री स्तरीय भारत की 45 यात्राएं हुईं जबकि इन्हीं स्तरों की 24 विदेश यात्राएं हुईं। यात्राओं की बड़ी संख्या इनके भौगोलिक आकार तथा कार्यकलापों की गहनता से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विश्व के साथ भारत के व्यापक कार्यकलाप प्रतिबिंबित हुए। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि सभी पी-5 देशों के राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों ने छह माह की लघु अवधि अर्थात जुलाई और दिसंबर 2010 के बीच भारत का दौरा किया। वर्ष 2010 में पांच नए आवासी मिशन खोले गए जिससे नई दिल्ली में विदेशी मिशनों की कुल संख्या 145 हो गई। स्विटजरलैंड और न्यूजीलैंड द्वारा क्रमशः बेंगलुरु और नई दिल्ली में प्रधान कोंसलावास भी खोले गए। इसके अतिरिक्त 14 देशों ने नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु और कोलाकाता में नए मानद कोंसलावास खोले।

कोंसलर, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं

जनवरी से दिसंबर 2010 के दौरान हमारे 37 पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 52.51 लाख पासपोर्ट जारी किए गए और 6.76 लाख विविध सेवाएं प्रदान की गईं। इस अवधि के दौरान 55.02 लाख पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए, जो एक वर्ष में प्राप्त आवेदनों की सबसे बड़ी संख्या है। इस अवधि के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों के जरिए कुल 679.11 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। इन पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 100.98 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल और त्वरित बनाने की दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में जिला पासपोर्ट केंद्रों के जरिए विकेंद्रीकरण, विदेशों में गैर कम्प्यूटरीकृत मिशनों के लिए पासपोर्टों की केंद्रीय प्रिंटिंग, लोक शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, सुविधा काउंटरों एवं सहायता डेस्कों की स्थापना करना, शिकायतों का निवारण करने के लिए पासपोर्ट अदालतें लगाना और आरटीआई अधिनियम का सजग कार्यान्वयन करना शामिल है। नवंबर 2010 में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए एक कार्य योजना की पहल की गई। जनवरी, फरवरी और मार्च 2011 में विशेष पासपोर्ट अदालतों का आयोजन किया गया।

मई 2010 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु के अंतर्गत चार पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने के साथ कर्नाटक में पासपोर्ट सेवा परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया। अगस्त 2010 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़ के अंतर्गत, पंजाब में तीन पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए। सभी 77 केंद्रों के प्रचालन का कार्य 2011 में समाप्त किया जाना निर्धारित है।

इस अवधि के दौरान 2,610 राजनयिक तथा 24,646 सरकारी पासपोर्ट जारी किए गए तथा विदेशी राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों को 7026 वीजा जारी किए गए। कुल 3,15,146 व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक दस्तावेज तथा 3,04,301 वाणिज्यिक दस्तावेजों को सत्यापित किया गया। विदेशों में उपयोग किए जाने के लिए 1,64,872 दस्तावेज भी सत्यापित किए गए।

पासपोर्ट सेवा परियोजना के अतिरिक्त नई परियोजनाओं में शामिल हैं, ई-पासपोर्ट जारी करना, वीजा कार्यों की आउटसोर्सिंग तथा 'अपोस्टाइल कन्वेंशन परियोजना' की शुरुआत।

समन्वय प्रभाग

समन्वय प्रभाग संसद से जुड़े सभी कार्यों तथा विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों, स्वायत्तशासी निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य निजी संस्थाओं के बीच होने वाले कार्यकलापों का समन्वय करता है। यह स्व-वित्तपोषित विदेशी छात्र योजना के अंतर्गत भारत में विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मैत्रीपूर्ण, पड़ोसी एवं विकासशील देशों के छात्रों के चयन, नामांकन एवं प्रवेश से जुड़े मुद्दे को देखता है।

प्रशासन और स्थापना

वर्तमान में विदेशों में भारत के 176 मिशन और केंद्र हैं। भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास में विदेशों में भारत की राजनयिक उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए जाफना और हम्बनटोटा (दोनों श्रीलंका) में दो नए केंद्र खोले गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ही ग्वाटेमाला सिटी में मिशन खोला गया। प्रशासन ने नीति-निर्माण का विकेंद्रीकरण करने तथा नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास जारी रखा। इन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्मिकों से संबंधित मुद्दों का समाधान सहानुभूतिपूर्वक किया गया।

पिछले वर्षों की भांति सचल सम्पत्तियों की आपूर्ति एवं रख-रखाव से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई में प्रभाविता लाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाने के प्रयास किए गए। अनेक मिशनों/केंद्रों के लिए किराए की अधिकतम राशि में संशोधन किया गया तथा किराए एवं अनुरक्षण से जुड़े प्रस्तावों का शीघ्रता से निस्तारण किया गया। दो हॉस्टलों का नवीनीकरण, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के आवासीय परिसर में सुधार तथा विदेश मंत्रालय आवासीय परिसर, द्वारका में पाइप्ड गैस का प्रावधान किया गया। इस अवधि के दौरान निरीक्षकों की उच्च स्तरीय टीम ने आठ मिशनों/केंद्रों का दोरा किया गया और उनकी रिपोर्टों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई। जवाहरलाल नेहरू भवन के लिए सचल सम्पत्तियों की खरीद की गई और उन्हें प्रतिस्थापित किया गया। इसके साथ ही इन सम्पत्तियों तथा परिसर के रख-रखाव का कार्य भी आरंभ किया गया।

मंत्रालय ने विदेशों में और भारत में निर्माण और निर्मित संपत्तियों की खरीद की दोनों नीतियों का पालन किया। तदनुरूप विदेशों

में तीन केंद्रों में निर्माण कार्य अपेक्षा के अनुरूप पूरा कर लिया गया और छह केंद्रों में कार्य चल रहा है। इसी प्रकार अन्य केंद्रों में भी सम्पत्तियों से जुड़ी योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत में जवाहरलाल नेहरू भवन तथा दो पारगमन आवास सुविधाओं का कार्य पूरा होने वाला है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को शामिल करते हुए विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से हिन्दी में कार्य करने के लिए विदेश स्थित लगभग 70 मिशनों/केंद्रों को हिन्दी शिक्षण सामग्रियां और साफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए और 100 मिशनों को हिन्दी पत्रिकाएं दी गईं। मंत्रालय ने हिन्दी से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारतीय मिशनों/केंद्रों के जरिए विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को सहायता भी प्रदान की। प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से चार मिशनों/केंद्रों को विविध अनुदान दिए गए। केंद्रीय हिन्दी संस्थान आगरा में अध्ययन करने के लिए 82 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं जिसका समन्वय कार्य विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया, हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने इसी प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पुणे, तिरुअनंतपुरम और कोच्ची का दौरा किया।

लोक राजनय

लोक राजनय प्रभाग ने भारत और विदेशों में भारत और इसकी विदेश नीति के उद्देश्यों के प्रति बेहतर समझबूझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया। विविध समूहों के साथ मंत्रालय के कार्यकलापों का विस्तार करने और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर बौद्धिक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई गतिविधियां की गईं। लोक राजनय की नई वेबसाइट तथा फेसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब पर चैनलों के माध्यम से 2.0 टूल्स का उपयोग किए जाने के कारण लोक राजनय प्रभाग को सरकार में सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिया गया। भारत की विदेश नीति पर आयोजित व्याख्यान माला के कारण पूर्व राजदूतों को पूरे भारत के 27 विश्वविद्यालयों और आईआईटी परिसरों में विशिष्ट मुद्दों पर व्याख्यान देने का अवसर मिला। भारत यात्रा कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और इस सिलसिले में इस प्रभाग ने प्रमुख देशों के सांसदों, विचारकों, युवा राजनैतिक नेताओं और अन्य लोगों की आगवानी की। विश्वविद्यालयों, विचार मंचों, व्यावसायिक संघों एवं निजी संस्थानों के साथ स्थापित भागीदारी से दावोस में विश्व आर्थिक मंच और जयपुर साहित्य महोत्सव जैसे विविध मंचों पर भारत और भारत की विदेश नीति को प्रस्तुत करने का प्लेटफार्म उपलब्ध हुआ। इसके अतिरिक्त प्रभाग ने वृत्तचित्र फिल्मों के निर्माण और कॉफी टेबल पुस्तकों तथा भारत सन्दर्श के प्रकाशन जैसे पारम्परिक कार्यों को नई दिशा प्रदान की।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंध से जुड़ी नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन करने के अपने घोषित लक्ष्यों एवं अधिदेशों के अनुसरण में भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया। आईसीसीआर विदेशों में दो उपकेंद्रों सहित 28 भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों का संचालन कर रहा है। आईसीसीआर ने नेहरू-वांग्चुक सांस्कृतिक केंद्र के नाम से थिम्पू (भूटान) में एक नया सांस्कृतिक केंद्र खोला है और इसने मैक्सिको सिटी, दारेस्लाम (तंजानिया), बुडापेस्ट (हंगरी), यांगून (म्यामां) और प्राग (चेक गणराज्य) में नए सांस्कृतिक केंद्रों में कार्य भी आरंभ किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आईसीसीआर ने विदेशी छात्रों को 2,350 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की। आईसीसीआर के 15 क्षेत्रीय केंद्रों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके इसने आईसीसीआर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भारत में अध्ययन करने वाले लगभग 4,700 विदेशी छात्रों की स्थिति में सुधार तथा उनके हित कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपायों को कार्यान्वित किया। आईसीसीआर ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार और आईसीसीआर की विस्तार योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 28 अतिरिक्त पीठों की स्थापना की जिससे इन पीठों की कुल संख्या 70 हो गई है। अध्येयतावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त 6 अध्येयताओं ने अपना कार्य पूरा कर लिया, 12 ने अपने कार्य जारी रखे हैं तथा 8 और आने वाले हैं। 11 नवंबर, 2010 को आईसीसीआर की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। आईसीसीआर ने भारत में 31 विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों की मेजबानी की। आईसीसीआर ने 54 विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया । आईसीसीआर ने विदेशों में दो आवक्ष प्रतिमाओं, 34 देशों में 23 प्रदर्शनियों, कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 16 कलाकारों तथा 85 सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को प्रायोजित किया। 'होराइजन सिरीज' के तहत भारत में भी 37 प्रदर्शनियों का प्रायोजन किया गया। चीन, फ्रांस और अर्जेन्टीना में भारत महोत्सवों का आयोजन किया गया। भारत से 44 प्रसिद्ध विद्वानों को विदेश भेजा गया जबकि 15 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने आईसीसीआर के विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दौरा किया।

भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए)

एक प्रमुख विचार मंच, सुविधा प्रदाता तथा भारत के विदेश संबंधों पर संवाद और चर्चाओं के आयोजक के रूप में भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2010-2011 के दौरान आईसीडब्ल्यूए की गतिविधियों से इस तथ्य को बल भी मिला जिसके तहत 15 व्याख्यानों, 9 सेमिनारों, 14 द्विपक्षीय सामरिक संवादों, 3 पैनल चर्चाओं/ पृष्ठभूमि वार्ताओं तथा तीन अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 'भारत एवं जीसीसी देश ईरान और इराकः उदीयमान सुरक्षा संदर्श' विषय पर नवंबर 2010 में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय

सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विश्व के प्रमुख नेताओं एवं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने आईसीडब्ल्यूए में अपना संबोधन दिया। इनमें चीन के प्रधान मंत्री, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति, बेलारूस के पहले उप प्रधान मंत्री इथोपिया के उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री, फिनलैंड के विदेश मंत्री, आर्मेनिया के विदेश मंत्री तथा उक्रेन के उप विदेश मंत्री शामिल हैं। अपने आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में आईसीडब्ल्यूए ने कोलकाता विश्वविद्यालय के विदेश नीति अध्ययन संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन और पेरू, इथोपिया, दक्षिण कोरिया, तुर्की और नेपाल के संस्थानों के साथ पांच समझौता ज्ञापन संपन्न किए। आईसीडब्ल्यूए ने एशिया प्रशांत सुरक्षा सहयोग परिषद (सीएससीएपी) द्वारा आयोजित चार बैठकों में भी भाग लिया और एस्केप की भारत शाखा के लिए सचिवालय उपलब्ध कराया।

आईसीडब्ल्यूए के पुस्तकालय की पुस्तकों, जर्नलों एवं संयुक्त राष्ट्र तथा यूरोपीय संघ से संबंधित दस्तावेजों और प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन से संबंधित दस्तावेजों को ऑटोमेटेड किया गया और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्च करने योग्य बना दिया गया। पाठकों के लिए दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह, समाचार-पत्रों के संकलनों और कतरनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इसका राजस्व भी कई गुना बढ़ गया है।

आईसीडब्ल्यूए मुख्यतः पड़ोसी देशों को केंद्रित करते हुए अनुसंधान एवं प्रकाशन कार्यों में भी लगा हुआ है। इसके अनेक कार्य प्रत्यक्ष तौर पर अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष आईसीडब्ल्यूए शोध अध्येयताओं ने चीन, जापान, नेपाल, फारस की खाड़ी और रूस/मध्य एशिया क्षेत्र की राजनैतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक प्रवृत्तियों पर अध्ययन और अनुसंधान किए।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली विदेश मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली स्थित एक स्वायत्तशासी विचार मंच है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों एवं विकास सहयोग में विशेषज्ञता है। आरआईएस को बहुपक्षीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर सरकार के लिए एक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करने का अधिदेश प्राप्त है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरआईएस ने अन्य के साथ-साथ जी-20 और विश्व व्यापार संगठन की वार्ता प्रक्रियाओं में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान अध्ययन किए। आरआईएस पूर्व एशिया में व्यापक आर्थिक भागीदारी (सीईपीईए) के ट्रैक-II अध्ययन दल सहित अनेक क्षेत्रीय पहलकदमियों की ट्रैक-II प्रक्रियाओं में भी शामिल है। आरआईएस विचार मंचों के क्षेत्रीय नेटवर्क में भी सक्रिय भागीदारी करता रहा है जिसमें इसे भारत के केंद्रबिंदु के रूप में नामित किया गया है। इनमें आसियान और पूर्व एशिया आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) और विचार मंचों का बिम्स्टेक नेटवर्क शामिल है। आरआईएस ने अनेक नीतिगत संवादों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया। आरआईएस द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सार्क के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसके तहत दक्षिण एशिया के प्रमुख नीति अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एकीकरण को गहन और व्यापक बनाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक मंच पर आ सके।

विदेश प्रचार

विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग (एक्सपीडी) ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के विचारों और नजरिए को अभिव्यक्त करना जारी रखा। साथ ही इस प्रभाग ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की विदेश नीति की सफलताओं और प्राथमिकताओं का प्रचार-प्रसार भी किया। ऐसा नियमित और विशेष प्रेस वार्ताओं, वक्तव्यों तथा पृष्ठभूमि कार्यकलापों और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए किया गया, जिसे नया कलेवर दिया गया है। वेबसाइट पर लगने वाली सामग्रियों का अरबी भाषा में अनुवाद भी शुरु किया गया। विदेश प्रचार प्रभाग ने मुख्य रूप से अपने निकटस्थ एवं विस्तारित देशों तथा विश्व के प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने पर मुख्य बल दिया। प्रभाग ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री जी के साथ विदेश यात्रा पर जाने वाले तथा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत आने वाले मीडिया कर्मियों को भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। पूरे विश्व के सम्पादकों/वरिष्ठ पत्रकारों के समूहों को भारत की परिचय यात्राओं के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया गया है।

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग

इस प्रभाग को अनेक कार्य दिए गए हैं जिनमें सबसे महत्पूर्ण हैं, अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्रवाई करना और विदेश मंत्रालय के लिए प्रासंगिक अध्ययन करना, इनके लिए धन उपलब्ध कराना और इनका मानीटरन करना; सेमिनारों का प्रायोजन (प्रभाग ने इस अवधि के दौरान तीन सेमिनारों, एक सम्मेलन और एक कार्यशाला के आयोजन का वित्तपोषण) किया; विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और इसके संबद्ध अंगों तथा विश्व के विभिन्न भागों पर अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करना; मंत्रिमंडल के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का मासिक सार तैयार करना; मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशन विभाग के भारत वार्षिकी अंक में 'भारत और विदेश' अध्याय के लिए सामग्रियों का संग्रहण और संकलन करना।

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय के विदेश नीति अध्ययन संस्थान के साथ समन्वय करता है और इसे निधियां उपलब्ध कराता है और यह रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली की अनुसंधान परियोजना 'भारत के पड़ोसी देशः अगले दो दशकों की चुनौतियां'

के साथ सहयोजित है। इस प्रभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विदेश मंत्रालय-आईडीएसए सामरिक एवं संदर्श योजना अनुसंधान दल का भी गठन किया गया।

चुनिंदा मिशनों/केंद्रों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं की व्यवस्था करना इस प्रभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है तथा समीक्षाधीन अवधि के दौरान तीन मिशनों को यह सुविधा प्रदान की गई। साउथ ब्लाक में स्थिति कक्ष का संचालन भी इस प्रभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। स्थिति कक्ष का उपयोग विदेश मंत्रालय तथा मिशनों और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य देशों में उनके समकक्षों के बीच महत्वपूर्ण वीडियो कांफ्रेंसों का आयोजन करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगस्त 2010 में लेह में भारी हिमपात और फरवरी 2011 में मध्यपूर्व के घटनाक्रमों के दौरान इसका उपयोग चौबीसों घंटे कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष के रूप में भी किया गया।

भारतीय मिशन प्रमुखों का सम्मेलन

भारतीय मिशन प्रमुखों का तीसरा सम्मेलन 27-29 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने किया। संपूर्ण विश्व के भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों से 119 मिशन प्रमुखों ने इसमें भाग लिया।

इन मिशन प्रमुखों ने भारत की राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, आईसीसीआर के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव ने उन्हें संबोधित किया। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना है। उन्होंने भारत की प्रगति, आर्थिक विकास और इसकी वैश्विक प्राथमिकताओं के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के सृजन को सुविधाजनक बनाने में भारतीय राजनियकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

मिशन प्रमुखों ने हमारे पड़ोस और विस्तारित पड़ोस के घटनाक्रमों, प्रमुख राष्ट्रों और क्षेत्रों के साथ संबंधों तथा भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और महत्वपूर्ण मुद्दों सहित विदेश नीति से जुड़े व्यापक मुद्दों पर आयोजित अनेक सत्रों में भी भाग लिया। सीआईआई तथा फिक्की के सहयोग से श्रीमती इंदिरा नूई और श्री गुरचरणदास सहित व्यवसाय और उद्योग जगत की अन्य विशिष्ट हस्तियों के साथ भी संवाद का आयोजन किया गया।

विदेश सेवा संस्थान

विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों तथा विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना जारी रखा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक स्तरीय अधिकारियों के लिए ई-मेल आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए तीसरे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मई 2011 में किया जाएगा जिसमें तीन बैचों के अधिकारी शामिल होंगे। विदेश सेवा संस्थान ने वर्ष 2009 में की गई पहल के उपरांत संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तरीय अधिकारियों के लिए मीडिया कार्यकलापों के संदर्भ में भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। फरवरी 2011 में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार पर एक अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

आसियान राजनयिकों के लिए पांचवें विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन भी इस वर्ष किया गया। वर्ष 2010 कैलेंडर वर्ष में अफगानिस्तान के राजनयिकों के लिए दूसरे विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पहली बार आईओआर-एआरसी सदस्य देशों के राजनयिकों के लिए भी एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। एक अन्य पहल के अंतर्गत फिजी में प्रशांत द्वीप मंच के सदस्य देशों के राजनयिकों के लिए भी विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। जून 2010 में विदेश सेवा संस्थान और दक्षिण अफ्रीकी राजनयिक अकादमी के बीच सहयोग की संस्थागत रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया।

■■

भारत के पड़ोसी देश 1

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति, हामिद करजई ने प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर 26 अप्रैल, 2010 को भारत की सरकारी यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति करजई ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से चर्चा की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच लगातार हुए उच्च स्तरीय विचार-विमर्शों के आदान-प्रदान का प्रतीक बनी और यह भारत और अफगानिस्तान के बीच नियमित परामर्शों की परम्परा की अभिव्यक्ति थी।

राष्ट्रपति करजई और प्रधान मंत्री के बीच हुई चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझीदारी के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और अपने संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात को नोट किया कि इन संबंधों की जड़ें ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधी संबंधों में समाई हुई हैं और इन संबंधों से न सिर्फ दोनों देशों के हित सधते हैं एवं उनका कल्याण होता है बल्कि ये क्षेत्र में शांति, स्थायित्व एवं समृद्धि में भी सहायक है। प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत एक मजबूत, स्थाई और समृद्ध अफगानिस्तान देखना चाहता है, जो कि शांतिप्रिय हो। भारत अफगानिस्तान के लोगों की इच्छाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने विकासात्मक प्रयासों में अफगानिस्तान की सहायता करने के लिए वचनबद्ध रहा। राष्ट्रपति करजई ने अफगानिस्तान की सरकार एवं लोगों के पुनर्निर्माण एवं विकास संबंधी प्रयासों के लिए भारतीय सहायता की सराहना की।

अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं के अतिरिक्त विदेश मंत्री ने काबुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20 जुलाई, 2010 को भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जिसकी सह-अध्यक्षता राष्ट्रपति हामिद करजई और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मार्च 2010 में काबुल की यात्रा की और अन्यों के अतिरिक्त राष्ट्रपति करजई से मुलाकात की। अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री हकीमी ने विदेश कार्यालय परामर्श के लिए जुलाई 2010 में भारत की यात्रा की। सांसदों सहित अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी कई यात्राएं की गई।

विदेश मंत्री, श्री एस. एम. कृष्णा ने अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री श्री जलमई रसूल के निमंत्रण पर 8-9 जनवरी, 2011 के दौरान अफगानिस्तान की यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय विचार-विमर्श का भाग थी और यह भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता और समझ की अभिव्यक्ति थी। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति करजई, विदेश मंत्री रसूल, एन. एस. ए. स्पांटा, भूतपूर्व राष्ट्रपति रब्बानी (उच्च शांति परिषद का अध्यक्ष) और अन्य वरिष्ठ अफगानी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में भारत की सकारात्मक भूमिका की पुनः सराहना की। भारत ने अफगानिस्तान और इसके स्थायित्व और विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक वचनबद्धता दोहराई।

अफगानिस्तान के साथ भारत की विकासात्मक साझीदारी का उद्देश्य उस देश में स्थायित्व लाने के साधन के रूप में इस देश के पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता करना है। हमारी सहायता अब 1.3 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गई है जो पूरे अफगानिस्तान में फैल चुकी है और इस सहायता में आर्थिक और सामाजिक विकासात्मक क्रियाकलापों के लगभग संपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। भारत की विकास संबंधी साझीदारी अब अवस्थापना विकास, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, खाद्य सहायता और लघु विकास परियोजनाओं पर केन्द्रित है जिनसे सबसे गरीब लोगों को तत्काल लाभ पहुंचता है। लगातार हमलों के बावजूद भारत ने सरकार और अफगानिस्तान के लोगों की सहायता करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है क्योंकि वे एक शांतिपूर्ण, प्रजातांत्रिक, बहुलबादी और समृद्ध देश का निर्माण कर रहे हैं।

अफगानिस्तान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2009-2010 में 588.74 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। अफगानिस्तान में किए गए निर्यात का मूल्य 463.55 मिलियन अमरीकी डालर तथा आयात का मूल्य 125.19 मिलियन डालर था। भारत अपने वृहत एवं उभरते बाजार के साथ कृषि उत्पादों सहित अफगानी वस्तुओं के लिए एक प्रमुख केन्द्र और क्षमतावान बाजार है।

अफगानिस्तान के विकास की कुंजी के रूप में कृषि के महत्व को समझते हुए भारत ने अगले पांच वर्षों में अफगानी लोगों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में 200 नये स्नातकों के लिए डिग्री कार्यक्रम चलाने के लिए प्रति वर्ष 100 छात्रवृति प्रदान करने की वचनबद्धता दी है। भारत ने अफगान राष्ट्रीय संस्था निर्माण परियोजना को सहायता सहित देशी अफगान क्षमताओं और संस्थानों का निर्माण करने के लिए अपनी ओर से सतत सहायता के बारे में भी सूचित कर दिया है।

बंगलादेश

दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 29 अप्रैल, 2010 को थिम्पु में 16 वें सार्क सम्मेलन के दौरान बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने संयुक्त विज्ञप्ति के क्रियान्वयन सहित दोनों पक्षों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। न्यूयार्क में यू.एन.जी.ए. सम्मेलन के अतिरिक्त समय में विदेश मंत्री ने 23 सितम्बर, 2010 को बंगलादेश के अपने समकक्ष डा. दिपु मोनी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की।

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट करार पर हस्ताक्षर करने के लिए 7 अगस्त, 2010 को ढ़ाका की सरकारी यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना, वित्त मंत्री डा. दिपु मोनी से मुलाकात की। चर्चा के दौरान संयुक्त विज्ञप्ति के क्रियान्वयन सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

बंगलादेश के वाणिज्य मंत्री कर्नल(सेवानिवृत) फारूक खान ने 21-23 अक्तूबर, 2010 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित व्यवसाय बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुलाकात की। बंगलादेश के साथ लगती मेघालय की सीमा पर दो सीमा हाट स्थापित करने के लिए एक करार और एक दूसरे के क्षेत्र में 200 मीटर तक ट्रकों की आवाजाही के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये गए। बंगलादेश में मीनि ट्रक्स को एसैंबल एवं विनिर्माण करने और बंगलादेश में स्पेयर पार्टस बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए टाटा मोटर्स, इंडिया और बंगलादेश के उत्तरा मोटर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक सरकार के निमंत्रण पर बंगलादेश के विदेश मंत्री डा. दिपु मोनी ने 10-11 नवम्बर, 2010 को त्रिपुरा की यात्रा की। इस अवसर पर त्रिपुरा में छोटा खोला में एक 'भारत-बंगलादेश ' मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया। बंगलादेश के प्रधानमंत्री के आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और उर्जा कार्य संबंधी सलाहकार ने भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय मुद्दों पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा की।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री के सलाहकार डा. मुशिउर रहमान और डा. गौहर रिजवी, ने द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा करने के लिए 22-25 दिसम्बर, 2010 के दौरान भारत की यात्रा की और जनवरी 2010 में प्रधान मंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्ति में लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन बी. चावला ने 'दक्षिण एशिया क्षेत्र के चुनाव आयुक्तों के बीच सहयोग' विषय पर बैठक में भाग लेने के लिए 28-31 मई, 2010 को ढ़ाका की यात्रा की और महालेखा नियंत्रक ने एशिया के एकाउंटिंग एसोसिएशन के सदस्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28-29 मई, 2010 को ढ़ाका की यात्रा की। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के निमंत्रण पर श्री शेख मुहम्मद वहीद उज जमां, सचिव, बंगलादेश जल संसाधन मंत्रालय के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल के जल संसाधन क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले भारतीय संस्थानों और इच्छामत्ती नदी पर तलकर्षण स्थान का दौरा करने के लिए 2-9 जून, 2010 को भारत की यात्रा की। श्री जवाहर सरकार, सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने 19-22 दिसम्बर, 2010 के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के 150 वें वर्षगांठ के संयुक्त समारोह के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए एक आठ सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

मानव तस्करी संबंधी कार्यबल की पहली बैठक 18-19 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के अतिरिक्त कार्यबल ने इस संकट के विरूद्ध समन्वित कार्रवाई करने के लिए अपनी सहमति जताई। बी.एस.एफ. और बंगलादेश राइफल्स (बी.डी.आर.) के बीच 32वां डी.जी. स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 22-27 सितम्बर, 2010 को ढ़ाका में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सीमा पर अपराध रोकने के संयुक्त प्रयासों को सुदृढ़ करने पर सहमति जताई। चौथे संयुक्त सीमा कार्यकारी समूह (जे.बी.डब्लू.जी.) की 10-11 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में बैठक हुई और इसने व्यापक स्तर पर समाधान करने की दृष्टि से सभी बकाया भूमि मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सभी विदेशी अन्तःक्षेत्रों में ज्वाईंट हेड काउन्ट प्रारंभ करने और भारत-बंगलादेश सीमा से लगे विपरीत कब्जे वाले क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण करने के लिए सहमति जताई।

आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में ठोस परिणाम हासिल करने के लिए बातचीत की गई है। सी.आई.आई. व्यवसाय शिष्टमंडल ने 10-13 अप्रैल, 2010 को बंगलादेश की यात्रा की। बंगलादेश में भारतीय निवेशों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यमों के अवसरों की पहचान करने के लिए दोनों देशों के व्यवसाय संघों के बीच एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टस आर्गेनाइजेशन (एफ.आई.ई.ओ.), कोलकाता के एक 32 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 22-24 जून, 2010 को ढाका की यात्रा की और एक मल्टी-प्रोडक्ट बायर-सेलर मीट (बी.एस.एम.) में भाग लिया। बंगलादेश में विद्युत, मुर्गी पालन, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, संचार अवसंरचना विकास, मृत्तिक शिल्प, औषधि, प्लास्टिक और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के अवसरों का पता लगाने के लिए बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (बी.एन.सी.सी.आई.) के एक 14 सदस्यीय व्यवसाय शिष्टमंडल ने जून में ढाका की यात्रा की। श्री मणिशंकर अय्यर, संसद संदस्य (राज्य सभा) के नेतृत्व में मर्चेंटस चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के एक 30 सदस्यीय व्यवसाय शिष्टमंडल ने 10-14 जुलाई, 2010 को बंगलादेश की यात्रा की। एम.सी.सी.आई. और भारत बंगलादेश चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 26 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस सम्मेलन में अफगानिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति श्री हामिद करजई के साथ।

29 अप्रैल, 2009 को थिम्पु, भूटान में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम शेख हसीना। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन भी उपस्थित हैं।

इंडस्ट्रीज (आई.बी.सी.सी.आई.) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गए जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार के विकास, निवेश, अवसंरचना और सामान्य आर्थिक सहयोग के प्रति उनकी परस्पर वचनबद्धता की घोषणा की गई है।

बंगलादेश के वाणिज्य मंत्री ले.कर्नल(सेवानिवृत) मुहम्मद फारूक खान ने कोलकाता में 24-27 दिसम्बर, 2010 के दौरान आयोजित 24वें औद्योगिक व्यापार मेले में भाग लेने के लिए एक 12 सदस्यीय व्यवसाय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

व्यापार संबंधी भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यकारी समूह की सातवीं बैठक और विद्युत क्षेत्र में सहयोग संबंधी संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक क्रमशः ढाका (मई) और नई दिल्ली (जून) में आयोजित की गई। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) और बंगलादेश पावर डिवलपमेंट बोर्ड (बी.पी.डी.बी.) ने 26 जुलाई, 2010 को ढाका में एक 35 वर्षीय पावर पारेषण करार पर हस्ताक्षर किये। इन्लैंड वाटर ट्रांजिट एण्ड ट्रेड संबंधी प्रोटोकाल के तहत स्थाई समिति की 12वीं बैठक अगस्त में ढाका में आयोजित की गई। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) और बंगलादेश पावर डिवलपमेंट (बी.पी.डी.बी.) ने 30 अगस्त को संयुक्त उद्यम के तहत चटगांव और खुकना में 1,320 मेगावाट के दो कोल फायर्ड पावर प्लांट स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के दल ने बंगलादेश मानक जांच संस्थान (बी.एस.टी.टी.) के खाद्य जांच प्रयोगशालाओं और सीमेंट जांच प्रयोगशालाओं के उन्नयन के संबंध में अगस्त में ढाका की यात्रा की। 30 नवम्बर, 2010 को बंगलादेश सरकार ने त्रिपुरा में पलटाक पावर प्रोजेक्ट के लिए आशुगंज के माध्यम से आवेर डाइमेंशनल कंसाइनमेंट्स की ट्रांस-शिपमेंट की अनुमति के लिए ओ.एन.जी.सी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

11 मार्च, 2010 को ढाका में इन्दिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्र (आई.जी.सी.सी.) की स्थापना के पश्चात दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यकलापों में ओर तेजी आई है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमे पुस्तक विमोचन, चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम, विशेष रूप से भारतीय फिल्में दिखाना और कला प्रदर्शनी और व्याख्यान सहित सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यकलाप शामिल किये गए हैं। सांस्कृतिक केन्द्र में भारत के शिक्षक योग, नृत्य, और शास्त्रीय संगीत में कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। वर्ष 2011 में गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने की तैयारी जारी है। बंगलादेश के कई सहभागियों ने आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम और कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया है। मिशन ने 18 जुलाई को सभी देशों के राष्ट्रिकों को ऑन लाइन वीजा आवेदन प्रस्तुत करने की शुरूआत की है। बंगलादेश में 26 नवम्बर-3 दिसम्बर 2010 के बीच 'आंनद जाग्या' शीर्षक पर भारत महोत्सव का आयोजन किया गया।

डा. मुशिउर रहमान और डा. गौहर रिजवी, बंगलादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 22-25 दिसम्बर, 2010 को भारत की यात्रा की और जनवरी 2010 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्ति में लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

10 जनवरी, 2011 को ढाका में जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। श्री ध्रुव विजय सिंह, सचिव (जल संसाधन) ने दोनों देशों के बीच जल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

भूटान

भारत और भूटान के बीच प्रगाढ़ और मित्रवत संबंध है जोकि परस्पर विश्वास और समझ पर आधारित है। वर्ष के दौरान नियमित रूप से उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान से और द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने से इन संबंधों में और मजबूती आई है। आज की द्विपक्षीय चर्चा में जल विद्युत परिवहन, संचार, अवसरंचना, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और शिक्षा जैसे दोनों देशों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 16वें सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28-30 अप्रैल, 2010 को भूटान की यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भूटान नरेश और भूटान के चौथे ड्रक ग्याल्पो और भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात शामिल थी जिसके दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की गई। यात्रा के दौरान आर्थिक कार्यमंत्री ल्योनपो खांडु वांग्चुक और विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा द्वारा दोनों देशों के प्रधान मंत्रीयों की मौजूदगी में पुनातसांग्चु-II और मांगदेचु हाड्रो इल्लेक्ट्रिक प्रोजेक्टस (एच.ई.पी.एस.) के कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों प्रधान मंत्रियों ने इन दो एच.ई.पी.एस. और भूटान आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए आधारशिला का अनावरण किया और सूचना संचार प्रौद्योगिकी परियोजना 'चिपेन रिगफेल' अथवा 'टोटल सोल्यूशन्स प्रोजेक्ट' की शुरूआत की।

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने 26-29 मई, 2010 को भूटान में एक 14 सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जिसमें नेता, प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज शामिल थी। यह किसी भारतीय लोकसभा अध्यक्ष की भूटान की प्रथम यात्रा की। लोकसभा अध्यक्ष के भूटानी संसद के पांचवें सत्र के स्वागत भाषण में भाग लिया और इसके संयुक्त सत्र को संबोधित किया।

वित्त राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीणा ने 22-24 अगस्त, 2010 को वित्त मंत्रियों की सार्क बैठक में भाग लेने के लिए भूटान की यात्रा की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वी. के. सिंह ने 7-11 जून, 2010 को भूटान की यात्रा की। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय ने 30 जुलाई-2 अगस्त 2010 के दौरान भूटान की यात्रा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन और विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव ने 13-14 अगस्त, 2010 को भूटान की यात्रा की।

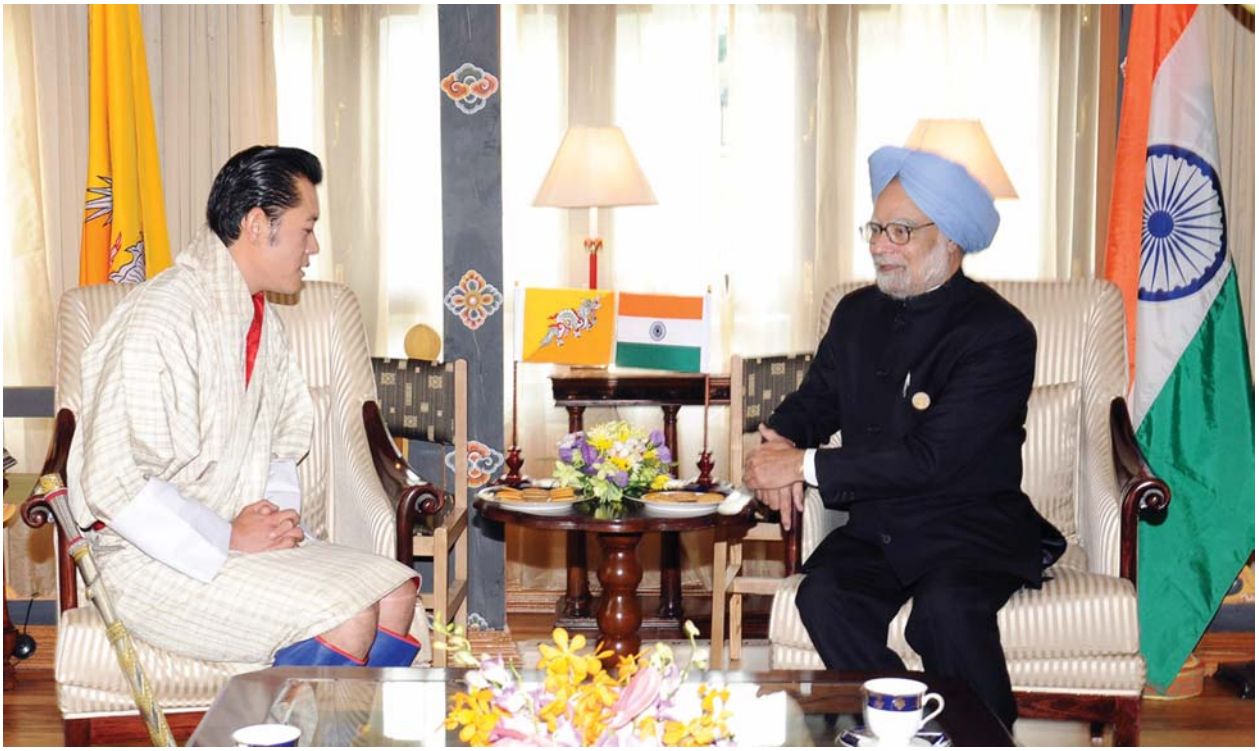

29 अप्रैल, 2009 को थिम्पु, भूटान में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक।

थिम्पू, भूटान में आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 28 अप्रैल, 2010 को मालदीव के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नाशीद के साथ मुलाकात करते हुए।

भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक ने 5-7 अक्तूबर, 2010 को कोलकाता की यात्रा की जिसके दौरान कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें मानद अपाधि से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नरेश से मुलाकात की।

भूटान नरेश ने राष्ट्रीय रक्षा कालेज के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 20-29 अक्तूबर, 2010 को भारत की यात्रा की। इस समारोह में वे मुख्य अतिथि थे। यात्रा के दौरान भूटान नरेश ने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री श्री एस.एम.कृष्णा, वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव से बातचीत की।

भूटान के प्रधानमंत्री ल्यान्छेन जिग्मी वाई. थिनले ने महाबोधि सोसाइटी की 113वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए 24-29 सितम्बर, 2010 को बोध गया, बिहार की यात्रा की जहां पर उन्होंने सोसाइटी की अध्यक्षता ग्रहण की। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भूटान के प्रधानमंत्री ने सार्क के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 30 अक्तूबर-3 नवम्बर 2010 को नई दिल्ली की यात्रा की।

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास साझेदार बना हुआ है। 2009 में भारत से भूटान को किया जाने वाला निर्यात इसके कुल आयात का 80 प्रतिशत था और भारत को किया जाने वाला निर्यात इसके कुल निर्यात का 94 प्रतिशत है।

महत्वपूर्ण और परस्पर लाभकारी जलविद्युत क्षेत्र में भूटान के साथ जारी सहयोग के संबंध में नियमित बैठकें आयोजित की गई जिसमें कार्य की प्रगति, विशेषकर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन तीन चार योजनाओं की समीक्षा की गई और समय पर इसे पूरा करने के लिए नोट किया गया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के वृहत दायरे में विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों की नियमित बैठकें की गई। लघु विकास परियोजना स्कीम के तहत 1,259 परियोजनाएं कर्यान्वयन के विभिन्न चरण में हैं।

इंडिया भूटान फाउंडेशन के तत्वावधान में भारत के 35 विख्यात लेखकों एवं कवियों ने 17-20 मई, 2010 को साहित्यिक समारोह 'माउंटेन इकोज' में भाग लिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डा. करण सिंह और भूटान के गृह एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री मिनजुर दोरजी द्वारा 21 सितम्बर, 2010 को थिम्पु स्थित नेहरू-वांग्चुक सांस्कृतिक केन्द्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया ।

मानव संसाधन के विकास में भूटान को सहायता करने के प्रति भारत की वचनबद्धता के भाग के रूप में भारत सरकार ने 60 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्लॉटों के अतिरिक्त भूटानी छात्रों को पूर्वस्नातक स्तर पर 85 स्लॉट और स्नातकोत्तर स्तर पर 77 स्लॉट, कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम और एम्बेस्डर स्कालरशिप स्कीम के तहत 50 स्लॉट प्रदान किये। नेहरू-वांग्चुक स्कालरशिप की इस वर्ष शुरूआत की गई।

सार्क अन्तर-सत्र मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 8-9 फरवरी, 2011 को थिम्पु में आयोजित की जाएगी जिस दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

चीन

भारत-चीन संबंधों के मामले में यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि यह वर्ष भारत गणराज्य और चीन के लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत-चीन संबंधों में कई घटनाक्रम हुए। यह वर्ष कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय घटनाक्रमों का साक्षी रहा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के अवसरों पर नियमित उच्च स्तरीय बातचीत और विभिन्न क्षेत्रों में विचारों के सतत आदान-प्रदान होते रहे। दोनों देश जलवायु परिवर्तन ओर वैश्विक वित्तीय स्थिति जैसे वैश्विक मुद्दों पर क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर भी आगे सहयोग बढाते रहे हैं।

एक दशक के अंतराल में तथा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की जनवरी 2008 में चीन यात्रा के पश्चात भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील की 26-31 मई, 2010 के दौरान चीन की एक सफल यात्रा रही। उनकी चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति महोदया की चीन के शीर्षस्थ नेतोओं से सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने चीन के हेनान प्रांत स्थित लूयांग में भारतीय शैली के बौध मंदिर का उद्घाटन कर इसे समर्पित किया। विदेश मंत्री ने 5-8 अप्रैल, 2010 को चीन की द्विपक्षीय यात्रा की। उनकी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच एक डायरेक्ट सेक्योर टेलीफोन लिंक की स्थापना करने के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किये। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 3-6 जुलाई, 2010 को चीन की यात्रा की। चीन की ओर से उप प्रधानमंत्री श्री ह्यू लियांग्यू ने 25-29 मार्च, 2010 को भारत की यात्रा की और श्री झाऊ योंगकांग, सदस्य, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलित ब्यूरो की स्थाई समिति, ने दोनों देशों के बीच पार्टी-दर-पार्टी आदान-प्रदान के भाग के रूप में 31 अक्तूबर से 2 नवम्बर 2010 के दौरान भारत की यात्रा की।

दोनों देशों के नेताओं ने भी अन्य बहुपक्षीय शिखर बैठक के दौरान हुई बैठकों में विचारों का सार्थक आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक शिखर बैठक के अवसर पर 15 अप्रैल, 2010 का ब्रासीलिया में चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री की 29 अक्तूबर, 2010 को पूर्वी एशिया आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर हनोई, वियतनाम में बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने 14 नवम्बर, 2010 को भारत-रूस-चीन विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक के अवसर पर युवान, चीन में चीन के विदेश मंत्री यांग जियेची से मुलाकात की।

भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर श्री बेन जियाबाओ, चीनी लोकतांत्रिक गणराजय के स्टेट कांउसिल के प्रधानमंत्री ने

प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह 16 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में चीन के प्रधान मंत्री श्री वेन जियाबाओ से मुलाकात करते हुए।

थिम्पू, भूटान में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 29 अप्रैल, 2010 को अपने पाकिस्तानी समकक्षी श्री युसुफ रजा गिलानी के साथ।

15-17 दिसम्बर, 2010 को भारत की राजकीय यात्रा की। यह भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ का उपयुक्त अवसर था। प्रधानमंत्री वेन ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ शिष्टमंडल स्तरीय बातचीत की और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील से मुलाकात की। उन्होंने यू.पी.ए. अध्यक्षा ओर नेता, प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक एवं दोस्ताना माहौल में विचारों का आदान-प्रदान किया और इस पर व्यापक सहमति व्यक्त की। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 15 दिसम्बर, 2010 को भारत-चीन व्यावसायिक शिखर बैठक को संबोधित किया और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का दौरा किया। उन्होंने भारतीय विश्व कार्य परिषद (आई.सी.डब्लयू.ए.) में भारत-चीन संबंध पर एक व्याख्यान दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 16 दिसम्बर, 2010 को चीन में भारत महोत्सव के समापन्न समारोह में भी भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संस्कृति, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मीडिया आदान-प्रदान, जल संसाधन और बैंकिंग सहयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए छः समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किये। यात्रा के दौरान एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई।

आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों पक्ष बृहत आर्थिक नीति समन्वय बढ़ाने, आदान-प्रदान एवं तालमेल को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में आने वाले मुद्दों एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नीतिगत आर्थिक वार्ता तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए। 2015 तक 100 बिलियन अमरीकी डालर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करते हुए दोनों पक्ष भारत के व्यापार घाटे को कम करने की दृष्टि से चीन में अधिक से अधिक भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय करने पर सहमत हुए। वे व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा करने और व्यापार और निवेश सहयोग के विस्तार की सिफारिश करने के लिए भारत-चीन सी.ई.ओ. मंच का गठन करने पर भी सहमत हुए।

संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने 2011 को 'भारत-चीन आदान-प्रदान का वर्ष' घोषित किया। शैक्षिक सहयोग के क्षेत्र में चीन ने सी.बी.एस.ई. के स्कूल पाठ्यक्रम में चीनी भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने का स्वागत किया और चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को सहायता देने एवं चीनी भाषा से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने इंडिया-चाइना आउटस्टैंडिंग कालेज स्टूडेंटस एक्सचेंज प्रोग्राम के आयोजन की घोषणा की।

विशेष प्रतिनिधिमंडल वार्ता का 14वां दौर 29-30 नवम्बर, 2010 को बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया। दोनों विशेष प्रतिनिधिमंडल ने सीमा प्रश्न के समाधान के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा जारी रखी। दोनों देशों के नेताओं ने विभिन्न अवसरों पर उपयुक्त तार्किक और आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधमंडल द्वारा की जा रही प्रगति पर संतोष जताया। दोनों पक्षों ने यह घोषणा की कि सीमा प्रश्न के शीघ्र समाधान से दोनों देशों के मूलभूत हित सधेंगे और इस प्रकार राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसी बीच, 1993, 1996 और 2005 में हस्ताक्षरित संगत करारों के अनुरूप सीमा क्षेत्रों में शांति भी बरकरार रही जिसके परिणामस्वरूप सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान पर चर्चा में प्रगति करने के लिए माहौल बना।

चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 2009 में 43.27 बिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार हुआ जिसमें व्यापार घाटा 15.87 बिलियन अमरीकी डालर रहा। वैश्विक आर्थिक संकट के कारण विगत वर्ष की तुलना में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 16.54 प्रतिशत का घाटा दर्ज हुआ। 2010 के प्रथम दस महीनों में 15.90 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे सहित दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 49.84 बिलियन अमरीकी डालर (जोकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 45.29 प्रतिशत की वृद्धि है) तक पहुँच गया। चीन के साथ व्यापार घाटे में यह वृद्धि सरकार के लिए चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों द्वारा उनके चीनी समकक्ष के साथ बैठक के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया। चीन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि वे यह कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक भारतीय उत्पाद चीन आयें। भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह की 8वीं मंत्रालय स्तरीय बैठक 19 जनवरी, 2010 को बीजिंग में आयोजित की गई। द्विपक्षीय व्यापार, संगरोधन आवश्यकताओं या सहयोग आई.टी. और आई.टी.एस. सेवाओं, फर्मास्यूटिकल नियति, अंतर बैंक संबंध, व्यापार निकायों द्वारा वीजा प्रक्रिया, अवसंरचना परियोजनओं और प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों के सरलीकरण को शामिल करते हुए व्यापार और आर्थिक सहयोग के विस्तार संबंधी एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गए। चीन में भारतीय उत्पादों को भेजने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से आई.टी., फर्मास्यूटिकल्स, इंजिनियरिग और कृषि उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित 18 चीनी नगरों में व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किये गए।

भारत और चीन के बीच विभिन्न वार्ता तंत्रों ने भी धीमी प्रगति दर्शायी। दोनों देशों की बीच कोंसली स्तरीय वार्ता का तीसरा दौर 23 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों पक्षों ने विभिन्न कोंसली और वीजा संबंधी मामलों पर चर्चा की। दोनों देशों ने सितम्बर 2010 में बीजिंग में आयोजित नीति आयोजन वार्ता के तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मामले पर विचारों का सार्थक आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने सीमापार नदियों पर भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की चौथी बैठक के दौरान सीमापार नदियों के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। यह बैठक 26-27 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने चीन द्वारा भारत को सतलज नदी के बारे में जलवैज्ञानिक सूचना प्रदान करने संबंधी कार्यान्वयन योजना (आई.पी.) पर भी हस्ताक्षर किये।

भारत-चीन सैन्य सहयोग भी जारी रहा; तीसरी भारत-चीन वार्षिक रक्षा वार्ता 6 जनवरी, 2010 को हुई। 16 नवम्बर, 2010 को चौथी भारत-चीन राजनीतिक वार्ता हुई जिसमें दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से रचनात्मक चर्चा की गई।

भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में लोगों के आपसी संपर्क में भी इजाफा हुआ है। इस वर्ष, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव मनाने की दृष्टि से चीन में 'भारत महोत्वस' और भारत में 'चीन महोत्सव' का आयोजन किया गया। चीन में भारत महोत्सव का 7 अप्रैल, 2010 को बीजिंग में विदेश मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। महोत्स्व के दौरान इस वर्ष भारत की मंचीय कला 33 चीन शहरों में प्रदर्शित की गई। श्री सुन जियाजेंग, चीन के लोकतांत्रिक राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन के उपाध्यक्ष द्वारा 20 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में भारत में चीन महोत्सव का उद्घाटन किया गया। भारत महोत्सव का समापन समारोह 24 अक्तूबर, 2010 को चेंगदु, सिचुअन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डा. करण सिंह मुख्य अतिथि थे। भारत में चीन महोत्सव का समापन समारोह दिसम्बर 2010 में आयोजित किया गया। भारत ने 'सिटिजन ऑफ हारमनी' विषय पर 4000 वर्ग मीटर मे राष्ट्रीय पविलियन के साथ 1 मई से 3 अक्तूबर 2010 के दौरान शंघाई में विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया। इस वर्ष भारत और चीन के बीच पांचवा वार्षिक युवा आदान-प्रदान भी किया गया। खेल एवं युवा काय मंत्री के नेतृत्व में भारतीय युवा शिष्टमंडल ने 17-29 अगस्त, 2010 को चीन की यात्रा की और चीनी युवा शिष्टमंडल ने 16-25 नवम्बर, 2010 को भारत की यात्रा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इस वर्ष उत्तराखण्ड के पिथौड़ागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के पार जून से सितम्बर 2010 तक बहुत सहजता से आगे बढ़ी।

दोनों देशों ने कार्यात्मक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाये हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 11-16 सितम्बर, 2010 को चीन की यात्रा की और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के संबंध में अपने चीनी समकक्ष से सार्थक चर्चा की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने 14-16 सितम्बर, 2010 को चीन की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत में अवसंरचना विकास के क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग पर चर्चा की।

दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रचनात्मक ढ़ंग से बातचीत की। दोनों पक्ष व्यापार, जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं, वैश्विक वित्तीय संकट आदि जैसे प्रमुख हितों के मुद्दों पर आगे कार्य करने के लिए सहमत हुए। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री ने मूलभूत रूपरेखा के भीतर जलवायु परिवर्तन पर भारत-चीन सहयोग बढ़ाने के बारे में आगे चर्चा करने के लिए मई और अक्तूबर 2010 में चीन की यात्रा की। दोनों पक्षों ने पूर्व एशिया शिखर बैठक, आसियान, आर.आई.सी. एवं एस.सी.ओ. जैसे विभिन्न मंचों पर भी पर्यवेक्षक एवं सदस्य के रूप में चर्चा की।

मालदीव

भारत और मालदीव दोनों देशों ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ और मित्रवत संबंध बनाने में मिलकर कार्य किया। मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री मुहम्मद नशीद ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए 2-5 अक्तूबर, 2010 को भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति नशीद ने 4 अक्तूबर, 2010 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

इससे पहले प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिहं और मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद दोनों ने 28-29 अप्रैल, 2010 के दौरान थिम्पु में आयोजित सार्क बैठक के अवसर पर 28 अप्रैल, 2010 को भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की थी और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया था।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री, श्री व्यालार रवि ने 4-7 नवम्बर, 2010 को मालदीव की सरकारी यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान श्री व्यालार रवि ने 4 नवम्बर, 2010 को मालदीव के राष्ट्रपति और मानव संसाधन, युवा एवं खेल मंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय हित के मामलों पर चर्चा की।

मालदीव के राष्ट्रपति के विशेष दूत, श्री इब्राहिम हुसैन जकी ने 20-22 दिसम्बर, 2010 को भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, श्री जकी ने विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। पूर्व में, श्री जकी ने अगस्त 2010 में भी भारत की यात्रा की थी। श्री हसन लतीफ, मालदीव गणराज्य के मानव संसाधन, खेल एवं युवा मंत्री ने भी 19वें राष्ट्रमंडल खेल एवं पांचवी राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री के निमंत्रण पर भारत की यात्रा की।

अपर सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने 17-19 जनवरी, 2011 को मालदीव की यात्रा की और पुलिस से संबंधित मामलों में सहयोग बढ़ाने पर मालदीव के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की।

भारत और मालदीव ने 23 जनवरी, 2011 को दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बारे में हस्ताक्षर किये जिसके अंतर्गत भारत प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा क्षमता निर्माण के संबंध में अपनी परियोजना के लिए मालदीव को 23 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

भारत और मालदीव दोनों ने मालदीव के विकास प्रयासों में अपना सहयोग जारी रखा। मालदीव सरकार को सहायता के रूप में 1 करोड़ रूपये की दवाईयां प्रदान की गई। मालदीव को उनके देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास स्वरूप भारत ने 64 लाख रूपये की खेल सामग्री भेंट की। भारत ने मालदीव में आवास इकाइयों का निर्माण करने के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर की एक ऋण श्रृंखला भी प्रदान

की है। भारत ने सिविल एवं सुरक्षा दोनों से जुड़े क्षेत्रों में मालदीव के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना जारी रखा।

मालदीव गणराज्य के कार्यवाहक विदेश मंत्री, श्री मोहम्मद असलम नई दिल्ली में 18-19 फरवरी, 2011 को आयोजित होने वाली अल्प विकसित देशों (एल.डी.सी.एस.) के विकास के लिए दक्षिण-एशिया सहयोग के सकारात्मक योगदान का उपयोग करने संबंधी भारत-एल.डी.सी मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए भारत आयेंगे।

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री मोहम्मद नशीद 24-26 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में एस.ए.सी.ई.पी.एस. ओर आर.आई.एस. द्वारा आयोजित किये जाने वाले दक्षिण एशिया का निर्माण, प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय और स्थाई विकास से संबंधित विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए फरवरी 2011 में भारत की यात्रा करेंगे।

म्यामां

भारत और म्यामां अन्य बातों के साथ-साथ सभ्यता मूलक बंधन, भौगोलिक निकटता, संस्कृति, इतिहास और धर्म की दृष्टि से प्रगाढ़ और मित्रवत पड़ोसी हैं। इसकी सीमा जो 1,640 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है और जिसकी सीमाएं भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों से लगी हुई है, के अतिरिक्त भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या म्यामां में रहती है। हमारे द्विपक्षीय संबंध इन बहुविध एंव पारम्परिक संबंधों को प्रतिबिम्बित करते हैं। इसके अतिरिक्त, म्यामां जिसकी सीमा भारत से लगती है, एक मात्र आसियान देश होने के नाते, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक महत्वूपर्ण संपर्क सेतु भी है।

इस वर्ष के दौरान द्विपक्षीय बातचीत और यात्रा जारी रही। सीनियर जनरल थान श्वे, चेयनमैन ऑफ द स्टेट पीस एण्ड डिवलपमेंट काउंसिल ऑफ द यूनियन ऑफ म्यामां ने 25-29 जुलाई, 2010 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील के निमंत्रण पर भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की और उसके बाद शिष्टमंडल स्तरीय बातचीत की गई। विभिन्न बैठकों में दोनों पक्ष सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक व्यवस्था, संपर्क, अवसंरचना विकास, तेल और प्राकृतिक गैस, कृषि, रेल, विद्युत, संस्कृति आदि क्षेत्रों सहित बहुआयामी संबंध को और सुदृढ़ एवं विस्तार करने पर सहमत हुए। निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये गए:-

- आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता;
- सूचना सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर करार;
- लघु विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन;
- बगान में आनंद मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर समझौता ज्ञापन;
- रेल अवसंरचना परियोजना के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला के लिए करार।

सिविल सेवा चयन एवं प्रशिक्षण के अध्यक्ष, श्री यू. क्वा थू के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल ने 26 सितम्बर-1 अक्तूबर 2010 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य सिविल सेवा चयन प्रक्रिया के सुधार में भारत के अनुभव से लाभ प्राप्त करना था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यू.पी.एस.सी. के अध्यक्ष तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और विदेश सेवा संस्थान के प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एल.बी.एस.एन.ए.ए.), मसूरी का भी दौरा किया।

द्विपक्षीय यात्राओं और म्यामां सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में सहयोग और आदान-प्रदान कार्यक्रम जारी रहा। कुल 11 भारतीय सशस्त्र सेना शिष्टमंडल और तीन भारतीय नौ-सैनिक/तट रक्षक पोत 2010 के दौरान म्यामां आए। 2010 के दौरान म्यामां सशस्त्र बल के कुल नौ शिष्टमंडलों ने भारत की यात्रा की।

भारत म्यामां की विकास सहायता जारी रखने के लिए वचनबद्ध है। वे परियोजनाएं जो वर्तमान में इस प्रकार की सहायता के अंतर्गत जारी हैं, उनमें रेल, सड़क और जलमार्ग विकास, विद्युत, स्वास्थ्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, दूरसंचार आदि शामिल हैं।

भारत ने विकास सहायता के भाग के रूप में म्यामां को कई ऋण श्रृंखलाए प्रदान की हैं। इनमें (क) मैसर्स राइट्स द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले रेल उपस्करों की खरीद के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला (एल.ओ.सी.), (ख) टाटा मोटर्स द्वारा मैगवे डिविजन स्थित ट्रक एसेंबली प्लांट, जिसका उद्घाटन 31 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तावित है, की स्थापना के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला, (ग) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए दी गई 64.07 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला, (घ) थनण्याकन पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को 20 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला शामिल हैं। चर्चाधीन लघु विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत अन्य परियोजनाएं यांगून चिल्ड्रेन्स हॉस्पीटल और सितवे हॉस्पीटल का उन्नयन एवं राइस सिलोस के निर्माण से संबंधित हैं। चक्रवात 'नरगिस' प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के भाग के रूप में यंगून प्रभाग में संस्थापन हेतु, 16 ट्रांसफोर्मर और 20 बायो-मास गैसोलियर्स भी सौंपे गए थे।

कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 19 दिसम्बर, 2010 को भूमि पूजन समारोह

आयोजित किया गया। बंदरगाह विकास और अंतर्देशीय जलमार्ग का ठेका मैसर्स एस्सार लिमिटेड को दिया गया है।

एन.एच.पी.सी. वर्तमान में डी.पी.आर. तैयार करने में जुटा हुआ है और यह चिंदविन नदी घाटी, म्यामां में तमंथी और श्वेजाए जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अन्वेषण भी कर रहा है।

पक्कोकी, म्यामां में भारत-म्यामां औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.एम.आई.टी.सी.) का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह केन्द्र म्यामां पक्ष को सौंप दिया गया था और म्यामां के प्रधानमंत्री द्वारा 30 मार्च, 2010 को इस केन्द्र का उद्घाटन किया गया था। केन्द्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पहला बैच जुलाई 2010 में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी प्रशिक्षण संबंधी म्यामां-भारत केन्द्र (एम.आई.सी.ई.एल.टी.) भी पूरी तरह से कार्य कर रहा है और नियमित पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

2009-2010 में द्विपक्षीय व्यापार ने एक बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य पार करके 2009-2010 में 1,207.56 मिलियन अमरीकी डालर के व्यापार कारोबार का लक्ष्य प्राप्त किया। चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान, लगभग 422.37 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ। कई भारतीय कंपनियां म्यामां में निवेश की संभावनाओं का भी पता लगा रही हैं। ओ.वी.एल. और गैल ने 2010 के दौरान म्यामां में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की घोषणा की।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स, कोलकाता के सरकारी प्रतिनिधियों और व्यवसायियों वाले एक शिष्टमंडल ने 13-16 सितम्बर, 2010 को म्यामां (यंगून और मांडले) की यात्रा की। इस शिष्टमंडल में श्री मणिशंकर अय्यर, संसद सदस्य, राज्य सभा और श्री एल. आर. सेलो, व्यापार और वाणिज्य मंत्री, मिजोरम सरकार और 35 व्यवसायी शामिल थे। म्यामां के लगभग 100 रत्न एवं आभूषण व्यवसायी ने 14-27 नवम्बर, 2010 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली का दौरा किया।

भारत ने कोलंबो योजना के आई.टी.ई.सी., टी.सी.एस. और आई.सी.सी.आर. के जी.सी.एस.एस. के तहत म्यामां को क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए सहायता देना जारी रखा। स्लोटों का उपयोग उत्कृष्ट रहा और वर्ष-दर-वर्ष उनमें वृद्धि हुई है। 2010-2011 में म्यामां के प्रशिक्षुओं के लिए स्लॉट निम्नानुसार थेः आई.टी.ई.सी. 140, टी.सी.एस. कोलंबो योजना-70 और आई.सी.सी.आर. का जी.सी.एस.एस.-10।

भारत और म्यामां के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत की बौद्ध विरासत के कारण बौद्ध समुदाय विशेष के बीच बन्धुत्व की गहरी भावना परिलक्षित होती है। विभिन्न सांस्कृतिक मंडलियों ने 2010 में यात्राओं का आदान-प्रदान किया और दोनों देशों में प्रस्तुतियाँ दीं। आई.सी.सी.आर. और एन.जी.ओ. 'सेहर' ने मार्च 2010 में सप्ताह भर चलने वाले शिविर 'पुडुचेरी बल्यू' का आयोजन किया जिसमें 9 दक्षिण एशियाई देशों के 32 कलाकार शामिल हुए। यांगून में 17-23 नवम्बर, 2010 के दौरान इस शिविर के दौरान कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया।

27-31 दिसम्बर, 2010 को नई दिल्ली में भारत और म्यामां के बीच 16वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक (एन.एल.एम.) का आयोजन किया गया। श्री जी.के. पिल्लै, गृह सचिव ने भारत के और यू.फोन स्वे, म्यामां के उप गृह मंत्री ने म्यामां शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में सुरक्षा, सीमा व्यापार और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

31 दिसम्बर, 2010 को म्यामां के प्रधानमंत्री श्री थेन सेन ने म्यामां ऑटोमोबाइल और डीजल इंजन इंडस्ट्रीज (एमू.ए.डी.आई.) की हैवी टर्बो ट्रक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री की स्थापना भारत सरकार द्वारा म्यामां को दी गई 20 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला (एल.ओ.सी.) के तहत टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा की गई थी। मध्य म्यामां के मैग्वे शहर में स्थापित ट्रक आटोमोबाइल प्लांट में प्रतिवर्ष 1,000 ट्रक का उत्पादन करने की क्षमता है, जिसे प्रतिवर्ष 5,000 ट्रक के उत्पादन तक बढ़ाया जा सकता है।

विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, श्रीमती प्रनित कौर ने 20-22 जनवरी, 2011 को म्यामां में आयोजित 13वीं बिम्सटेक मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच एक विशेष और अनोखा संबंध है जो दोनों देशों की विरासत, सभ्यता और रीति-रिवाजों में समाहित है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है और विदेशी निवेश और पर्यटकों के आगमन का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत ने एक प्रजातांत्रिक, स्थाई, शांतिपूर्ण और समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में नेपाल में परिवर्तन का समर्थन करने की दृष्टि से नेपाल सरकार और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखा। भारत नेपाल के साथ अपना आर्थिक, वाणिज्यिक और अवसंरचना संबंधों का विस्तार करने के लिए वचनबद्ध है जिससे नेपाल का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा तथा भारत को ऐसी किसी भी प्रकार की सहायता देने में खुशी होगी जिसे नेपाल सरकार भारत सरकार से लेना चाहेगी।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अप्रैल 2010 में थिम्पु में आयोजित 16वें सार्क शिखर बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री माधव कुमार नेपाल से मुलाकात की। दोनों प्रधान मंत्रियों ने नेपाल और भारत के बीच पुराने, घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंधों पर संतोष व्यक्त किया और दोनों पक्ष इन संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आई.सी.आई.एम.ओ.डी.) द्वारा आयोजित 'बेनिफिटिंग फ्रॉम अर्थ आब्जर्वेशनः ब्रिजिंग द डाटा गैप फॉर एडप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इन द हिन्दुकुश हिमालयन

रीजन' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 3-6 अक्तूबर, 2010 को नेपाल की यात्रा की। उन्होंने पर्यावरण मंत्री और वन एवं मृदा संरक्षण मंत्री, नेपाल सरकार के साथ, द्विपक्षीय बैठकें की और पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन अध्ययन के क्षेत्र में नेपाल को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

हमारी संसद और नेपाल के संविधान सभा और विधायी संसद के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के प्रयासों के भाग के रूप में नेपाल में सात राजनयिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 युवा सांसदों के एक शिष्टमंडल ने 21-27 नवम्बर, 2010 को भारत की यात्रा की।

विदेश सचिव ने 18-20 जनवरी, 2011 को नेपाल की यात्रा की। यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति, उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री, उप प्रधान मंत्री एवं फिजिकल प्लानिंग एण्ड वर्क्स मंत्री तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबधों और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध बढ़ाने एवं उसे और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। विदेश सचिव ने सभी नेताओं से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत नेपाल को एक प्रजातांत्रिक, स्थाई और समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है और उन्होंने नेपाल में बहुपक्षीय प्रजातंत्र को सुदृढ़ करते हुए तथा नेपाली नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भी संविधान के प्रारूप की प्रक्रिया में भारत की ओर से उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। विदेश सचिव ने विभिन्न संस्थागत तंत्रों की शीघ्र बैठकें बुलाने की अपील की और उन्होंने भारत सरकार की सहायता से नेपाल में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नेपाल सरकार के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रपति डा. राम बरन यादव ने 27 जनवरी-5 फरवरी 2011 के दौरान भारत की सरकारी यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यू.पी.ए. अध्यक्षा, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। वे मेडिकल कालेज, कोलकाता और पोस्ट ग्रेजूएट इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल एडुकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ के दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि थे।

इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार में काफी तेजी देखी गई। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा और नेपाल का लगभग 60 प्रतिशत विदेशी व्यापार भारत के साथ ही हुआ। भारत विदेशी निवेश के मामले में नेपाल का सबसे बड़ा स्रोत रहा जो कि नेपाल में कुल विदेशी निवेश वचनबद्धताओं का 44 प्रतिशत है।

भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देते हुए लघु विकास परियोजना (एस.डी.पी.एस.) कार्यक्रम को बुनियादी स्तर पर अपनी सहायता जारी रखी। नेपाल के सभी 75 जिलों में अब तक 400 से अधिक परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारत नेपाल के तराई क्षेत्रों में एकीकृत चेक पोस्टों, सीमापार रेल संपर्क एवं फीडर और शाखा सड़कों के विकास के माध्यम से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी अवसंरचना का विकास करने के लिए भी नेपाल की सहायता कर रहा है। इससे नेपाल के तराई क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी जिससे आर्थिक विकास होगा।

नेपाल को इसके मानव संसाधान विकास के लिए भारत की ओर से निरंतर सहायता के भाग के रूप में भारत सरकार ने भारत और नेपाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेपाली छात्रों को लगभग 1,800 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, 23 जुलाई, 2010 को त्रिभुवन विश्वविद्यालय में दो वर्षों की शुरूआती अवधि के लिए आई.सी.सी.आर. भारतीय पीठ की स्थापना की गई थी।

नेपाल सरकार ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया कि नेपाल अपने क्षेत्र में भारत के विरूद्ध निर्देशित गतिविधियाँ चलाने की अनुमति नहीं देगा।

पाकिस्तान

अप्रैल 2010 में भूटान में आयोजित सार्क शिखर बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री स्तरीय वार्ता सहित कई अवसरों पर पाकिस्तान को भारत की चिंताओं एवं आकांक्षाओं से अवगत करा दिया गया है। विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव ने 24 जून, 2010 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ चर्चा की। गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 26 जून, 2010 को सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा की। विदेश मंत्री ने 15 जुलाई, 2010 को इस्लामाबाद की यात्रा की। इन बैठकों का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना एवं दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ाना था।

पाकिस्तान में चल रहे मुंबई के आतंकवादी हमलों के मुकदमे और जांच के संबंध में पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाई तो की है परन्तु बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार ने 25 नवम्बर, 2010 को पाकिस्तान सरकार को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है कि मुंबई आतंकवादी हमले के संबंध में पाकिस्तान में चल रहे मुकदमे और जांच के संबंध में पाकिस्तान के उच्च स्तरीय नेतृत्व द्वारा बार-बार दिये गए आश्वासनों और भारत द्वारा दिये गए व्यापक सहयोग के बावजूद घृणात्मक हमले के साजिशकर्ताओं को दंडित करने की दिशा में काफी प्रगति नहीं हुई है। सरकार ने पाकिस्तान को मुंबई आतंकवादी हमलों के साजिशकर्ताओं को दंडित करने एवं इन हमलों के पीछे रची गई बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए अपनी

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्षे 9 जून, 2010 को प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के दौरान।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा, श्रीलंका के विदेश मंत्री प्रोफेसर जी. एल. पेइरिस तथा विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव 28 नवंबर, 2010 को हमबनटोटा में प्रधान कोंसलावास कार्यालय का उद्घाटन करते हुए।

कथित वचनबद्धता पूरी करने का आह्वान किया। सरकार ने इस बात पर बल दिया कि पाकिस्तान की कथित वचनबद्धताओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने से न केवल दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ेगा बल्कि इसमें आतंकवाद का व्यापक रूप से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की वचनबद्धता भी परिलक्षित होगी।

मुंबई हमलों के बावजूद लोगों से लोगों के बीच संपर्क जारी रहा। समग्र वार्ता के पिछले दौर में बहाल की गई परिवहन संपर्क व्यवस्था सफलतापूर्वक जारी रही जिससे लोगों की आवाजाही और द्विपक्षीय व्यापार में सुविधा हुई।

केन्द्रीय जनसंख्या कल्याण मंत्री, डा. फिरदौस आशिक अवान ने 16-21 अप्रैल, 2010 को भारत की यात्रा की। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की।

टाइम्स ऑफ इंडिया और जंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान ने 1 जनवरी, 2010 को 'अमन की आशा' अभियान चलाया। पूरे वर्ष चले इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षिक चर्चा की गई। 'अमन की आशा' पहल के तहत 18-19 मई, 2010 को नई दिल्ली में भारत-पाकिस्तान व्यावसायिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वागत भाषण दिया।

पाकिस्तान सीनेट के उपाध्यक्ष तथा पाकिस्तान के प्रोविंसियल एसेंबली के अध्यक्षों एवं सदस्यों वाले एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल ने 25-29 अक्तूबर, 2010 को रायपुर में चौथे भारत और एशिया क्षेत्र के सी.पी.ए. सम्मेलन में भाग लिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री, श्री मखदूम शहाबुद्दीन ने 'पार्टनर्स फोरम' में भाग लेने के लिए 13-14 नवम्बर, 2010 को भारत की यात्रा की।

एफ.आई.सी.सी.आई. ने 24 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में भारत-पाकिस्तान आर्थिक संबंधः संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें भारत और पाकिस्तान के इंडस्ट्री एण्ड चैम्बर ऑफ कामर्स के सहभागियों ने भाग लिया। विदेश सचिव ने इसमें उद्घाटन भाषण दिया। इस कार्यक्रम के दौरान भारत-पाकिस्तान आर्थिक संबंध बढ़ाने पर पैनल चर्चा भी की गई।

काफी संख्या में भारतीय कैदी, मछुआरे और नौकाएं पाकिस्तानी कब्जे में हैं। पाकिस्तान को भारत के जेलों में पड़े उसके राष्ट्रिकों के बारे में भी चिंता है। कैदियों एवं मछुआरों संबंधी भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति की सिफारीशों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे की हिरासत में पड़े कैदियों एवं मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया गया।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 170 भारतीय मछुआरे और 445 नौकाएं पाकिस्तान के कब्जे में हैं। भारत ने 101 मछुआरों की राष्ट्रीयता की पुष्टि की है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। 6 मछुआरों की राष्ट्रीयता की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है और पाकिस्तान द्वारा 75 मछुआरों तक कोंसली संपर्क प्रदान किया जाना शेष है। पाकिस्तान ने 2006 में 143, 2007 में 265, 2008 में 230, 2009 में 100 और 2010 से आज की तारीख तक 442 मछुआरों को रिहा किया है। पाकिस्तान ने 14 दिसम्बर, 2010 से 12 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है।

2009-2010 के दौरान कुल 1.849 बिलियन के व्यापार में से भारत के निर्यातों का मूल्य 1.573 बिलियन डालर था जबकि पाकिस्तान के निर्यातों का मूल्य .275 बिलियन डालर था। 2009-2010 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा कुल 2.17 प्रतिशत तक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ जबकि पाकिस्तान के लिए भारतीय निर्यात में 9.27 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई लेकिन पाकिस्तान से आयातों में 25.45 प्रतिशत तक की कमी हुई। विकासशील देशों के माध्यम से किये जाने वाले गैर-सरकारी व्यापार का भी महत्व है और पाकिस्तान में अंतिम उपभोक्ता के लिए व्यापार लागत में कमी आई है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को एम.एफ.एन. का दर्जा दिया है जबकि पाकिस्तान ने 1934 मदों की सकारात्मक सूची में से भारत से आयात की मदों को सीमित करना जारी रखा है। साफ्ता के अंतर्गत पाकिस्तान ने भारत की सकारात्मक सूची में से मदों को वार्ता सम्मत शुल्क रियायत देने से इन्कार कर दिया है जिसके चलते करार को धक्का लगा है क्योंकि निर्यात सकारात्मक सूची की मदों तक सीमित हैं।

पाकिस्तान प्रचंड बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि बाढ़ से जान व माल का काफी नुकसान पहुँचा है। भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में आई प्रचण्ड बाढ़ की वजह से गई जान पर शोक एवं संवेदना व्यक्त करने के लिए 19 अगस्त, 2010 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री युसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। पाकिस्तान में प्रचण्ड बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ हमदर्दी की भावना से भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 25 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता दी है।

श्रीलंका

साझी सांस्कृतिक एवं सभ्यतापरक विरासत सहित भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मित्रवत संबंधों को और सुदृढ़ किया गया। इस अवधि में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे ने जनवरी 2010 मं हुए राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की और सत्ता गठबंधन ने अप्रैल 2010 में हुए संसदीय चुनाव में आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। उन्होंने नवम्बर 2010 में दूसरी दफा श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला।

सभी स्तरों पर नियमित द्विपक्षीय आदान-प्रदान किये गए जिससे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों में इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2010 में भूटान में 16वीं सार्क शिखर बैठक के अवसर पर राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने भी इस शिखर बैठक के दौरान अपने श्रीलंकाई समकक्ष प्रो. जी. एल. पेयरिस से मुलाकात की।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने 8-11 जून, 2010 को भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक संयुक्त घोषणा जारी की गई जिसमें श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों के सभी पहलू शामिल थे। दोनों पक्ष संपर्क बढ़ाने, आर्थिक समाकलन और निकट विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्ध थे। भारत और श्रीलंका जाफना और हंबनटोटा में भारत का प्रधान कौंसलावास स्थापित करने पर सहमत हुए। दोनों देश कोलंबो और तुतीकोरिन तथा तलाइमन्नार और रामेश्वरम के बीच नौका सेवा प्रारंभ करने पर सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गएः

1 भारत और श्रीलंका के बीच लघु विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता संबंधी समझौता ज्ञापन का नवीकरण;

2 सजायाफ्ता कैदियों के स्थानांतरण संबंधी समझौता ज्ञापन;

3 आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर संधि;

4 बट्टिकलोवा में महिला व्यापार सुविधा केन्द्र एवं सामुदायिक शिक्षण केन्द्र की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन;

5 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सी.ई.पी.) का नवीकरण;

6 अंतर संबंध विद्युत ग्रिड संबंधी समझौता ज्ञापन;

विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव ने 31 अगस्त-2 सितम्बर 2010 को श्रीलंका की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तरी श्रीलंका का व्यापक दौरा किया और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आई.डी.पी.एस.) के पुनर्स्थापना में हुई प्रगति का मुआयना करने के लिए मलयतिवु, त्रिनकोमाली, वावुनिया, क्रिलीनोची और जाफना की यात्रा की और भारत सरकार की सहायता से चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पूर्वी प्रांत में त्रिनकोमाली की भी यात्रा की और पूर्वी प्रांत के गवर्नर से मुलाकात की और उनसे पूर्वी प्रांत में भारत सरकार की सहायता से चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करने के लिए उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा श्रीलंका सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की।

राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने 19वें राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भाग लेने के लिए 14-15 अक्तूबर, 2010 को पुनः नई दिल्ली की यात्रा की। प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने जून 2010 में राष्ट्रपति राजपक्षे द्वारा पहले की गई यात्रा के दौरान संपन्न की गई संयुक्त घोषणा के निष्कर्षों और उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ श्रीलंका के विदेश मंत्री प्रो. जी. एल. पेयरिस भी आये और उन्होनें भारत के गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने 'ग्रोथ, एक्विटी एण्ड सेक्यूरिटीः कंस्टीट्यूशनल इंपरेटिव्स फॉर साउथ एशिया' विषय पर आर. के. मिश्रा मेमोरियल लेक्चर भी दिया।

विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनित कौर ने राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के दूसरी बार सत्ता में आने पर कोलंबो में 19 नवम्बर, 2010 को आयोजित उद्घाटन समारोह और शपथ-ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 25-28 नवम्बर, 2010 को श्रीलंका की यात्रा की। उन्होंने कोलंबो में 26 नवम्बर, 2010 को श्रीलंका के विदेश मंत्री प्रो. जी. एल. पेयरिस के साथ बैठक की सहअध्यक्षता की। संयुक्त आयोग ने राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की जून 2010 में भारत की यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में विकास की समीक्षा की और इस बात पर संतोष जताया कि इस यात्रा के जरिए भारत-श्रीलंका संबंधों के भावी विकास के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी गई। अपनी यात्रा के दौरान जाफना और हंबनटोटा में भारत के प्रधान कौंसलावासों का उद्घाटन किया, जाफना के निकट अरियलई में 1,000 घरों वाली एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की और उत्तरी रेल के पुनरूद्धार की परियोजना के लिए मेदावाचिया में भूमि पूजन भी किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के 416.39 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रंखला के तहत किया जा रहा है। यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात भी की और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

श्रीलंका द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में, आर्थिक विकास मंत्री बेसिल राजपक्षे, राष्ट्रपति के सचिव गोटाभाया राजपक्षे ने 26 अगस्त, 2010 को त्रोइका वार्ता में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

भारत और श्रीलंका दोनों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग जारी रखा। भारत अपने देश में उनके सशस्त्र बलों और पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए श्रीलंका को सहायता करता रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंध के सुरक्षा और रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता को आगे बढ़ाने और उच्च-स्तरीय सैन्य आदान-प्रदान में वृद्धि करने और दोनों सरकारों के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता की शुरूआत करने पर सहमत हुए।

इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच दोनों देशों के रक्षा बलों द्वारा कई उच्च-स्तरीय यात्राएं की गईं। भारतीय नौसेना प्रमुख ने

27 जून-2 जुलाई 2010 को श्रीलंका की यात्रा की। उन्होंने श्रीलंका के हीरक जयंती समारोह में भाग लेने के लिए दिसम्बर में श्रीलंका की पुनः यात्रा की। सितम्बर 2010 में भारतीय सेना प्रमुख ने श्रीलंका की यात्रा की। भारत के रक्षा सचिव ने भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए दिसम्बर 2010 में श्रीलंका की यात्रा की। श्रीलंका के नौसेना प्रमुख ने भी अक्तूबर 2010 में भारत की यात्रा की।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार जारी रहा। भारत अब श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आई.एस.एल.एफ.टी.ए.) से प्राप्त गति से पिछले वर्षों के दौरान द्विपक्षीय कारोबार में स्थाई और तीव्र वृद्धि से जारी रही। आई.एस.एल.एफ.टी.ए. के लागू होने के बाद समग्र व्यापार कारोबार में पांच गुणा वृद्धि हुई और 2007 में पहली बार इसने 3 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर लिया। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत और श्रीलंका के बीच 2009 में द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा लुढ़क कर 2.035 बिलियन अमरीकी डालर तक पहँच गया और उसके बाद पुनः इसमें तेजी आई। जनवरी-अक्तूबर 2010 के दौरान भारत-श्रीलंका व्यापार वर्ष 2009 में उसी अवधि में 1.29 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.356 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया। श्रीलंका को भारतीय निर्यात 2009 में उसी अवधि में 1.10 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1.983 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया। भारत को श्रीलंका की तरफ से निर्यात वर्ष 2009 में उसी अवधि में 193.07 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में .373 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया। भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में चार सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत में श्रीलंका के निवेश में भी हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है।

श्रीलंका के लिए विकास सहायता श्रीलंका के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण फलक है। मई 2009 में सशस्त्र संघर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद भारत ने इस क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनी दखल बढ़ा दी थी।

जून 2009 में प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह ने श्रीलंका के लिए 500 करोड़ रूपये के एक राहत, पुनर्वास और पुननिर्माण पैकेज की घोषणा की। शुरू-शुरू में भारत ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आई.डी.पी.एस.) के लिए तत्काल मानवीय सहायता देने पर जोर दिया। तत्काल राहत उपाय के रूप में पिछले वर्ष राहत सहायता भेजी गई थी और आपातकालीन क्षेत्र अस्पताल की तैनाती की गई थी। भारत ने इन आई.डी.पी.एस. की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास में श्रीलंका सरकार को सहायता जारी रखी। इस संबंध में भारत ने आई.डी.पी.एस., जिन्हें जयपुर फूट की आवश्यकता थी, के लिए उत्तरी श्रीलंका में महीने भर चलने वाली कृत्रिम लिंब फिटिंग कैंप लगाने के लिए भारतीय एन.जी.ओ. की तैनाती की थी। विस्थापितों की शीघ्र पुनर्स्थापना के लिए इस क्षेत्र को सुरक्षित करने में सहायता करने के लिए उत्तरी श्रीलंका में बारूदी सुरंगों का हटाने वाले सात दलों का विस्तार किया गया है। आई.डी.पी. परिवारों की तत्काल पुनर्स्थापना में सहायता करने और उनके क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत करने में सहायता करने के लिए भारत ने 7,800 टन राहत सामग्री भेजी है तथा 4 लाख सीमेंट की बोरियां दी हैं। 2,600 टन की राहत सामग्री की दूसरी खेप शीघ्र भेजी जाएगी। भारत ने उत्तरी, पूर्वी और मध्य प्रांतों को 55 बसें भी दी हैं।

भारत पुनर्स्थापित आई.डी.पी. परिवारों की आजीविका गतिविधियों को पुनरूज्जीवित करने के लिए कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त सहायता भी प्रदान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के एक शिष्टमंडल ने उत्तरी श्रीलंका में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में अपेक्षित सहायता की संभावना का आकलन करने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। इस संबंध में तात्कालिक उपाय के रूप में सितम्बर 2009 से 95,000 एग्रीकल्चरल सटार्टर पैक का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुदान सहायता के रूप में उत्तरी प्रांत में किसानों के लाभ के लिए भारत ने कृषि सेवा केन्द्रों को कृषि उपकरण सहित 500 ट्रैक्टर दिये हैं। खेती फसलों के लिए बीज के रूप में एग्रीकल्चरल इंपुट्स भी श्रीलंका सरकार को प्रदान कर दी गई है।

भारत श्रीलंका के उत्तरी, पूर्वी और मध्य प्रांतों में आई.डी.पी.एस. के लिए 50,000 घरों का निर्माण कराने के लिए भी वचनबद्ध है। 27 नवम्बर, 2010 को विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा की यात्रा के दौरान जाफना में अरियालई में 1,000 घरों के निर्माण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की गई थी।

राहत और पुनर्वास के उपरांत पुनर्निमाण एवं विकास पर जोर देने के लिए उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में भारत की सहायता से कई परियोजनाएं भी प्रारंभ की जा रही हैं। इनमें उत्तरी रेल लाइनों का पुनरूद्धार, के.के. एस. हार्बर का पुनर्वास, त्रिंकोमाली में 500 मेगावाट के साथ तापीय विद्युत संयंत्र के लिए एन.टी.पी.सी. और सी.ई.बी. के बीच संयुक्त उद्यम, जाफना में सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण, दुरय्यप्पा स्टेडियम का पुनरूद्धार, व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना आदि तथा लघु विकास परियोजना स्कीम के तहत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। भारत ने रेल परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को लगभग 800 मिलियन अमरीकी डालर की रियायत युक्त ऋण श्रृखंला प्रदान की है।

भारत शिक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन और क्षमता निर्माण में श्रीलंका की सहायता कर रहा है। इस संबंध में भारत ने आई.सी.सी.आर. स्कीमों, कोलंबो योजना, कॉमनवेल्थ, आई.ओ.आर.-ए.आर.सी. एवं सार्क फेलोशिप प्रोग्रामों के अंतर्गत और साथ ही भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीलंकाई छात्रों के लिए कई स्कालरशिप प्रोग्राम जारी रखा है। जून 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका 'भारत-श्रीलंका नालेज इनिशियेटिव' पर

सहमत हुए। इस पहल के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता से कोलंबो विश्वविद्यालय में भारतीय समसामयिक अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में मई 2010 में लिवनेल वेंट गैलरी, कोलंबो में 'कल्पना' शीर्षक से पेंटिग की प्रदर्शनी और 'रिलिजन्स ऑफ इंडिया' शीर्षक से एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जून 2010 में भारत और श्रीलंका ने 2010-2013 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये। अगस्त 2010 में 64वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान श्रीमती शर्मीला बिस्वास के नेतृत्व में एक ओडिसी नृत्य मंडली ने कोलंबो, कैण्डी और नुवेरा इलिया में अपना प्रदर्शन दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व वाले दल ने तिरूकेतीस्वरम मंदिर के जिर्णोद्धार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रारंभ करने के लिए अगस्त 2010 में श्रीलंका की यात्रा की। विदेश मंत्रालय ने सारनाथ से लाई गई 5वीं सदी की गुप्तकालीन महात्मा बुद्ध की मूर्ति सौंपी है जिसे कैंडी, श्रीलंका में श्री दलाडा मलीगावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय में एक इंडियन गैलरी भी स्थापित की जा रही है। मई-जून 2010 के दौरान श्रीलंका में आयोजित वेसाक 2010 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध फिल्म समारोह में दो भारतीय फिल्में (त्रिसंगी और द लैंड ऑफ बुद्धा) दिखाई गई। कोलंबो विश्वविद्यालय में समकालीन भारतीय अध्ययन में एक अल्पावधिक रोटेटिंग आई.सी.सी.आर. पीठ की स्थापना की गई। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र ने 5 मई, 2010 को जाफना में 'अभिज्ञान शाकुंतलम' तमिल में एक म्यूजिकल डांस-ड्रामा के रूप में एक प्रसिद्ध संस्कृत ड्रामा के प्रस्तुतिकरण में सहायता की। आई.सी.सी.आर. द्वारा दिल्ली में 12–14 दिसम्बर, 2010 के दोरान दिल्ली हाट, पीतमपुरा में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान इंटरनेशनल कल्चरल फीयेस्टा में श्रीलंका के चित्रसेन नृत्य समूह का अभिनय प्रदर्शित किया गया और साउथ एशियन बैंड फेस्टीवल में श्रीलंका के रॉक बैंड ने भाग लिया। श्रीलंका की प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रख्यात संपादकों की भारत की परिचय यात्रा हुई।

■■

2 दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया के साथ विविध क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों का विकास होना जारी रहा। आस्ट्रेलिया, खासकर मेलबोर्न में भारतीय छात्रों और भारतीय समुदाय से जुड़ी घटनाओं, जो वर्ष 2009 के मध्य में और वर्ष 2010 के आरंभ में अपनी चरमसीमा पर थीं, में इस वर्ष के दौरान धीरे-धीरे कमी आती गई। भारत सरकार ने इस मुद्दे को संघीय और प्रान्तीय दोनों स्तरों पर आस्ट्रेलिय सरकार के साथ उठाया। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से काफी हद तक इन घटनाओं की रोकथाम करना संभव हो सका।

वर्ष 2009-2010 में भारत और आस्ट्रेलिया केक बीच सामानों और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 22.40 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर के आंकड़े तक पहुंच गया जिसमें 19.89 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का भारत को निर्यात किया गया जबकि 2.51 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का आस्ट्रेलिया को भारत से निर्यात किया गया। भारत आस्ट्रेलिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा जबकि आस्ट्रेलिया भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंदशर्मा तथा आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री श्री सामइन क्रीन ने मई 2010 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की 12वीं बैठक की सहअध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत-आस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार करार संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन दल की रिपोर्ट का लोकार्पण किया जिसने व्यापक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार पर चर्चा किए जाने की अनुशंसा की है। विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जून 2010 में पर्थ में आयोजित आस्ट्रेलिया-भारत ऊर्जा एवं खनिज मंच की पहली बैठक में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया का दौरा किया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री ब्यालार रवि ने जून 2010 मे आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

खेल मंत्री सिनेटर मार्क आर्बिब और विक्टोरिया के गवर्नर प्रो. डेविड डी क्रेटसर ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। संसद सदस्य सुश्री मेलिसा पार्के के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें पश्चिमी आस्ट्रेलिया के एक एमएलए और विभिन्न राजनैतिक दलों के चार अधिकारी भी शामिल थे, ने युवा राजनैतिक नेताओं के आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक भारत का दौरान किया। विदेश और व्यापार विभाग के सचिव श्री डेनिश रिचर्डसन ने वरिष्ठ अधिकारी बैठक तथा सामरिक वार्ता के लिए दिसंबर 2010 में भारत का दौरा किया।

आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 4,50,000 है, जिसमें मुख्यतः शिक्षक, इंजीनियर, लेखाकार, डाक्टर और आईटी परामर्शदाता शामिल हैं।

ब्रूनेई

ब्रूनेई के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हैं। हिन्दू और बौद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं की ब्रूनेई की विरासत को आज भी इसकी भाषा, कला और सामाजिक लोकाचारों इत्यादि में देखा जा सकता है। द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना 1984 में हुई थी जबकि आवासीय राजनयिक मिशन 1993 में खोला गया।

वर्ष 2009-2010 में भारत द्वारा 24.40 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात जबकि 428.65 मिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया।

ब्रूनेई में भारतीय समुदाय की अनुमानित संख्या 6,000 है जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, व्यवसायी, निर्माण कामगार, दूकान और घरेलू सहायक इत्यादि शामिल हैं।

कम्बोडिया

भारत और कम्बोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। हमारे द्विपक्षीय सहयोग में मुख्य तौर पर मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण से संबंधित कार्यकलापों पर बल दिया जाना जारी रहा।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने सांस्कृतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 13-18 सितंबर, 2010 तक कम्बोडिया की छह दिवसीय राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दो करारों अर्थात (1) भारत के सी एंड एजी तथा कम्बोडिया के नेशनल ऑडिट अथारिटी के बीच सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन; और (2) एक्जिम बैंक तथा कम्बोडियाई आर्थिक वित्त मंत्रालय के बीच 15 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला (स्टंग तशाल जल विकास परियोजना के लिए) से संबंधित करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान काम्पोंग चैम प्रान्त में भारत-कम्बोडिया मैत्री स्कूल के लिए 2,46,000 अमरीकी डालर का दान दिया गया और सियाम रीप स्थित एमजीसी एशियाई पारम्परिक वस्त्र

संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। जल संसाधन एवं संसदीय मामले मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने 7-9 जून, 2010 तक कम्बोडिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान वैपकास लिमिटेड द्वारा जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया।

विदेश मामलों से संबद्ध नेशनल असेम्बली कमीशन के अध्यक्ष श्री चियांग उन के नेतृत्व में दस सदस्यीय बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 22-28 अगस्त, 2010 तक भारत का परिचय दौरा किया।

वर्ष 2009-2010 के दौरान कुल 50.60 मिलियन अमरीकी डालर (भारत का निर्यात 45.54 मिलियन डालर और आयात 5.05 मिलियन अमरीकी डालर) का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ताप्रोम मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों में काफी प्रगति हुई है। गृह मंत्रालय द्वारा भारत में दो विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमोंः (1) ''साइबर अपराध एवं नेटवर्क पाठ्यक्रम'' (10 कम्बोडियाई पुलिस अधिकारियों के लिए); और (2) ''बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच'' (12 कम्बोडियाई पुलिस अधिकारियों के लिए) का आयोजन किया गया। ''कृषि क्षेत्र में भारत और कम्बोडिया के बीच कार्य योजना'' के अंतर्गत पांच कम्बोडियाई वैज्ञानिकों के लिए विशेष कृषि पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के प्रस्ताव पर आईसीएआर द्वारा विचार किया जा रहा है।

रक्षा सहयोग के अंतर्गत भारतीय सेना के दो अधिकारियों ने जुलाई 2010 में कमांड पोस्ट अभियान में आब्जर्वर के रूप ने 'अंकोर सेंटीनल-10' नामक बहुराष्ट्रीय शांति समर्थन अभियान में भाग लिया। अगस्त, 2010 में भारत ने (1) उन्नत डिमाइनिंग तथा (2) संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान में नोमपेन्ह में आरसीएएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा वन अनुसंधान संस्थान के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 8-9 जून, 2010 को सियाम रीप में आयोजित अंकोरवाट टेम्पल के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की तकनीकी बैठक में भाग लिया।

कम्बोडिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए हमारी उम्मीदवारी सहित अन्य सभी मुद्दों पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न भारतीय पहलकदमियों का लगातार समर्थन करता रहा है। कम्बोडिया ने वर्ष 2011-2012 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता के लिए हमारी उम्मीदवारी का भी समर्थन किया। कम्बोडिया ने 2013-2014 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता की अपनी उम्मीदवारी के लिए भारत का समर्थन मांगा है। हमारी पूर्वोन्मुख नीति तथा आसियान के संदर्भ में कम्बोडिया एक महत्वपूर्ण वार्ताकार और अच्छा भागीदार है। फिलहाल कम्बोडिया आसियान में भारत के लिए समन्वयक राष्ट्र है।

आईटेक के अंतर्गत प्रशिक्षण स्लाट्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आईटेक स्लाट्स की संख्या को वर्ष 2009-2010 में 75 से बढ़ाकर 85 कर दिया गया है। अलग से एमजीसी के अंतर्गत 10 शैक्षणिक छात्रवृत्तियों तथा सीईपी/सीजीएसएस के तहत चार (प्रत्येक दो) छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया गया है। अब तक आईटेक के अंतर्गत विभिन्न विधाओं में 790 कम्बोडियाई राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। सियाम रीप में अप्सरा प्राधिकार की सहायता के लिए आईटेक के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए जल प्रबंधन से जुड़े एक भारतीय विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की गई है।

फिजी

भारत ने फिजी द्वीपों के साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास क्षेत्रों में सहयोग और सहायता का विस्तार किया और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा।

सितंबर 2010 में भारत और फिजी ने फिजी द्वीप में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए भारत शिक्षक, हार्डवेयर तथा पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 500 छात्रों को लाभ होगा।

भारत ने फिजी के 125 से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए जल टैंकों की आपूर्ति करने तथा मंत्रालय के स्वास्थ्य आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के अंतर्गत फिजी द्वीप के सब-डिवीजनल अस्पतालों के लिए 5 नए एम्बुलेंसों की खरीद के लिए फिजी के शिक्षा मंत्रालय को सहायता अनुदान दिया।

जुलाई-सितंबर 2010 के दौरान फिजी के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जयपुर फुट आर्गनाइजेशन (भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति) में प्रोस्थेटिक प्रशिक्षण दिया गया। तदुपरान्त फरवरी 2010 में नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य से संबंध पहले संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक में इस पर चर्चा भी की गई।

साउथ पैसिफिक विश्वविद्यालय के एक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मंडल ने भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक भागीदारी स्थापित करने के उद्देश्य से भारत का दौरा किया। इसके उपरान्त संयुक्त एशियाई विकास बैंक-भारत सरकार मिशन का दौरा भी हुआ जिसने फरवरी-मार्च 2010 में फिजी द्वीप का दौरा किया। इस दौरे में एशियाई विकास बैंक के तकनीकी सहायता कोष के जरिए यूएसपी को भारत द्वारा दी गई एक मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से चलाई जा रही परियोजना की प्रगति का आकलन भी किया गया।

इंडोनेशिया

वर्ष 2010 में भी इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध उत्कृष्ट बने रहे। राजनैतिक, सुरक्षा, रक्षा, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे संबंधों का त्वरित विकास होने से हमारी सामरिक भागीदारी और सुदृढ़ हुई।

भारत के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री कमलनाथ ने अप्रैल 2010 में अवसंरचना विकास 2010 के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आयोजित एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जकार्ता का दौरा किया। जल संसाधन मंत्री श्री पी. के. बंसल ने सिंचाई एवं जल व्ययन से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय आयोग के छठे एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2010 में योगयाकार्ता का दौरा किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने जनसंख्या एवं विकास भागीदार सम्मेलन तथा पीडी कार्यकारी परिषद एवं बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2010 में योगयाकार्ता का दौरा किया।

फिलहाल इंडोनेशिया आसियान में दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वर्ष 2009-2010 में 11.72 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। पारम्परिक दवा निर्माता आठ कम्पनियों वाले फिक्की के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2010 में इंडोनेशिया का दौरा किया।

उच्च स्तरीय यात्राओं, पोत यात्राओं, दोनों देशों के स्टाफ कालेज में पढ़ने वाले छात्रों के आदान-प्रदान तथा संयुक्त समन्वय गश्तियों के जरिए रक्षा सहयोग में अबाध प्रगति होती रही। द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक का आयोजन जून 2010 में नई दिल्ली में हुआ।

इस वर्ष के दौरान संगीत एवं नृत्य के 20 बड़े कार्यक्रमों तथा विशिष्ट आगंतुकों की चर्चाओं एवं इंडोनेशियाई मंडलियों के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंडोनेशिया में एक वर्ष तक चलने वाले भारत महोत्सव का समापन अक्तूबर 2010 में 'भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध' पर आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्री सेमिनार के साथ हुआ। इस सेमिनार में विभिन्न आसियान देशों के 14 विद्वानों ने भाग लिया।

इंडोनेशिया को आईटेक के अंतर्गत 75 प्रशिक्षण स्लाट्स, कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम (टीसीएस) के अंतर्गत 35 प्रशिक्षण स्लाट्स, सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जीसीएसएस) के अंतर्गत 20 स्लाट्स और हिन्दी अध्ययन के लिए दो एकवर्षीय पाठ्यक्रम छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

लाओ पीडीआर

लाओस ने पूरे देश में अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करके अपनी जनता के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं बेहतरी पर विशेष बल देना जारी रखा।

लाओस ने वर्ष 2011-2015 के लिए 7वीं राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास योजना का शुभारंभ किया है। वर्ष 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा वर्ष 2020 तक देश को अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी से ऊपर उठाना राष्ट्रीय नीतियों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दक्षिण-पूर्व एशिया में लाओस की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अलग-अलग तथा समूहिक तौर पर इस क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

लाओस के साथ भारत के संबंध विकास सहयोग पर आधारित हैं। भारत लाओस के आठ सबसे महत्वपूर्ण विकास भागीदारों में से एक है तथा ऋण के जरिए अवसंरचना विकास परियोजनओं के लिए हमारी प्रतिबद्धता 162 मिलियन अमरीकी डालर की है। मानव संसाधन विकास, जल विद्युत, पारेषण लाइनों तथा सिंचाई इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। सितंबर 2010 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की यात्रा 1959 के बाद किसी राष्ट्रपति की लाओस की दूसरी यात्रा थी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2011-2013 और एक्जिम बैंक तथा लाओस के बीच 72.55 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। संसदीय मामले एवं जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल की जून 2010 की यात्रा के दौरान जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (वैपकॉस) तथा लाओस के कृषि एवं वन मंत्रालय के सिंचाई विभाग के बीच एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

लाओपीडीआर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता के भारत के दावे सहित क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर भारत का समर्थक रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सत्र में लाओ के प्रतिनिधिमंडल के नेता उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री सोमसावत लेंग्सावद ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल किए जाने के लिए लाओ पीडीआर का समर्थन अभिव्यक्त किया। जहां तक लाओपीडीआर के क्षेत्रीय संघ का संबंध है, इसका विभिन्न मुद्दों पर पूरा समर्थन प्रदान करते हुए क्षेत्रीय संगठनों में तीसरे देश को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सहकारी नजरिया है।

मलेशिया

पारम्परिक मैत्री एवं सौहार्द भारत-मलेशिया संबंधों की विशेषता रही। दोनों देशों द्वारा सामरिक भागीदारी की रूपरेखा पर निर्णय लिए जाने के साथ ही इस वर्ष के दौरान हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए।

दोनों देशों के नेताओं के बीच नियमित रूप से यात्राओं का आदान-प्रदान होता रहा है इसमें अक्तूबर 2010 में प्रधान मंत्री जी की मलेशिया यात्रा भी शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति ने अक्तूबर 2010 में ब्रसेल्स में आयोजित एसेम शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में मलेशिया के प्रधान मंत्री से मुलाकात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने जुलाई 2010 में मलेशिया का आधिकारिक दौरा किया।

प्रधान मंत्री जी की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सामरिक भागीदारी की एक रूपरेखा की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान छह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, नामतः भारत और मलेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार को

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील, इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि डा. एच. सुसिलो बामबंग युधोयोनो, उपराष्ट्रपति, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी तथा प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह 26 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 62वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 'ऐट होम' के दौरान।

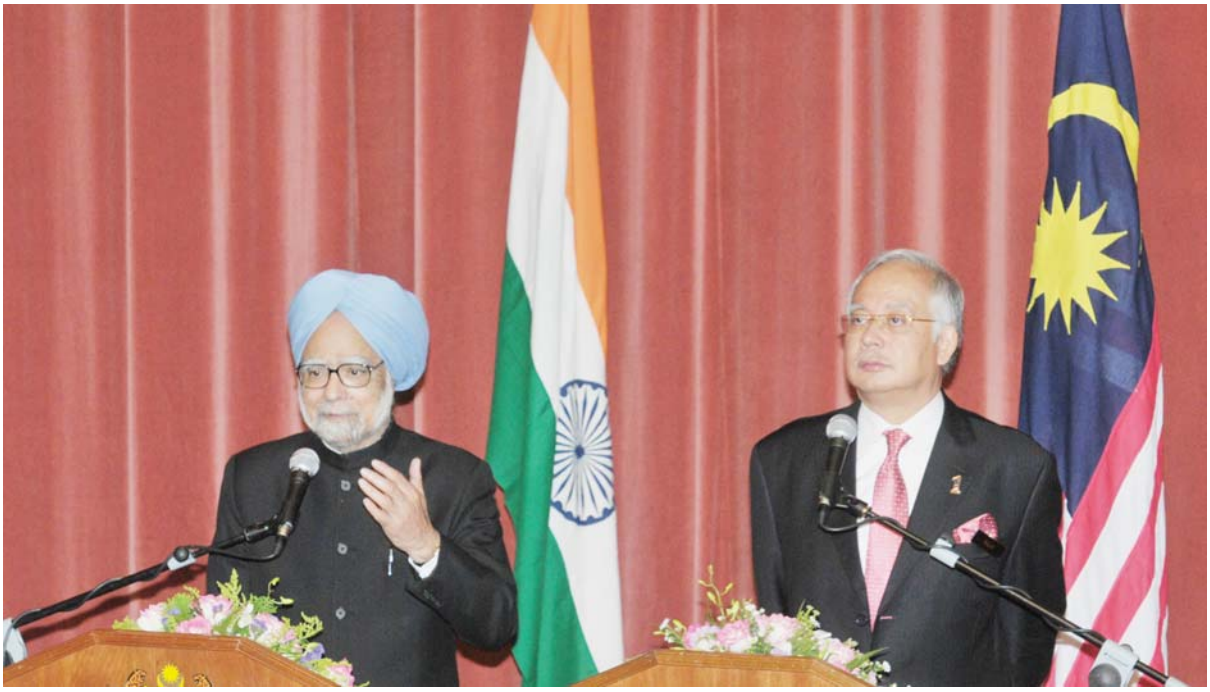

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और मलेशिया के प्रधान मंत्री दातो श्री मोहम्मद नजीब बिन तुन अब्दुल रज्जाक 27 अक्तूबर, 2010 को पुत्रजया, प्रधान मंत्री कार्यालय, मलेशिया में हस्ताक्षर समारोह के उपरांत संयुक्त प्रेस सम्मेलन में।

कार्यान्वित किए जाने की दिशा में करार; पारम्परिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; आईटी एवं सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम; तथा भारत के सीएसआईआर एवं मलेशिया के यूएनआईके के बीच करार। दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना किए जाने पर भी सहमति व्यक्त की।

पिछले वर्षों के दौरान भारत-मलेशिया रक्षा संबंधों में सतत प्रगति हुई है। मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग बैठकों का आयोजन नियमित आधार पर किया जाता रहा है। मिडकॉम की आठवीं बैठक का आयोजन मार्च 2010 में किया गया। दोनों देशों के सेवा प्रमुखों की भी नियमित रूप से यात्राएं होती रही हैं। फरवरी 2008 में मलेशिया में तैनात भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण टीम ने एसयू-30 एसकेएम विमान के मलेशियाई पायलटों को प्रशिक्षित करने का कार्य सितंबर 2010 में पूरा कर लिया।

जनवरी-सितंबर 2010 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 6.84 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, अर्थात वर्ष 2009 में इसी अवधि की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मलेशिया 1 जनवरी, 2010 को सामानों के क्षेत्र में आसियान-भारत मुक्त व्यापार का अनुसमर्थन करने वाला पहला देश बन गया। प्रथम भारत-मलेशिया मुख्य कार्यकारी मंच जिसमें दोनों पक्षों के 18 मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं, का शुभारंभ अक्तूबर 2010 में भारत और मलेशिया के प्रधान मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

भारतीय कम्पनियों ने मलेशिया में लगभग दो बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है जिसके आधार पर भारत मलेशिया में 7वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। मलेशियाई प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त आईसीटी प्रतिभा विकास परामर्शी समिति का गठन करने पर सहमति व्यक्त की थी। यह समिति आईटी कौशल प्रशिक्षण, प्रतिभा विकास एवं मलेशिया में भारतीय आईटी कम्पनियों की बेहतर भागीदारी के संदर्भ में दोनों देशों को विशेष अनुशंसाएं देगी।

भारत के छह बड़े गंतव्यों के लिए सीटों की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि किए जाने हेतु वर्ष 2007 में सम्पन्न द्विपक्षीय करार के उपरान्त हवाई सम्पर्कों में पर्याप्त सुधार आया है।

रोजगार एवं कामगारों के कल्याण से संबद्ध द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के जरिए भारतीय कामगारों से जुड़े मामलों का समाधान करने के लिए एक संस्थागत रूपरेखा उपलब्ध हुई है। संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक अप्रैल 2010 में हुई जिसमें मलेशिया में कानूनी रूप से भर्ती किए गए लगभग डेढ़ लाख भारतीय कामगारों के लिए कल्याण उपायों को विनियमित एवं सुव्यवस्थित बनाने पर विचार किया गया। आईटी, निर्माण, बैंकिंग इत्यादि क्षेत्रों में वहां लगभग 10,000 प्रवासी नियुक्त हैं। मिशन ने भारतीय समुदाय विकास कोष के अंतर्गत मार्च 2010 में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए दो अलग-अलग सलाह सह-आश्रय केंद्रों का प्रचालन आरंभ कर दिया।

मलेशियाई प्रधान मंत्री श्री नजीब की जनवरी 2010 में हुई भारत यात्रा के दौरान उच्च शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया था। मलेशिया में लगभग 2,000 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं जबकि एक अनुमान के अनुसार 3,000 मलेशियाई छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। फरवरी 2010 में क्वालालम्पुर में एक नया सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। भारत आईटेक के अंतर्गत लगभग 30 स्लाट्स और कोलम्बो योजना के अंतर्गत 25 स्लाट्स का प्रस्ताव करता है।

मलेशिया में विश्व में भारतीय मूल के लोगों के सबसे बड़े समुदायों में से एक रहता है जिनकी संख्या लगभग दो मिलियन (मलेशिया की जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत) है।

न्यूजीलैंड

भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंध पारम्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण यात्राएं हुईं: मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने अप्रैल 2010 में न्यूजीलैंड का दौरा किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्रालय के बीच शिक्षा सहयोग करार को अगले पांच वर्षों के लिए नवीकृत किया; प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री ब्यालार रवि ने जून 2010 में न्यूजीलैंड का दौरा किया तथा भारतीय समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की; एडमिरल निर्मल वर्मा, सीएनएस ने नवंबर 2010 में न्यूजीलैंड का दौरा किया। आईडीएसए-एशिया न्यूजीलैंड ट्रैक-2 वार्ता का दूसरा दौर सितंबर 2010 में बेलिंगटन में आयोजित किया गया। आईडीएसए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डाक्टर अरविंद गुप्ता, अपर सचिव लालबहादुर शास्त्री पीठ, आईडीएसए द्वारा किया गया।

गवर्नर जनरल परम माननीय सर आनन्द सत्यानंद ने श्रीमती सुसान सत्यानंद तथा विदेश, खेल, मनोरंजन एवं रग्वी विश्वकप मामलों के मंत्री मरे मैकुले के साथ 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए अक्तूबर 2010 में नई दिल्ली का दौरा किया।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार करार वाताओं के पहले दौर का आयोजन अप्रैल 2010 में बेलिंगटन में किया गया जिसके बाद अगस्त 2010 में नई दिल्ली दूसरे दौर की बैठक हुई। तीसरे दौर की बैठक अक्तूबर 2010 में हुई।

आईसीसीआर और बेलिंगटन के विक्टोरिया विश्वविद्यालय के बीच विक्टोरिया विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन की लघु आवधिक पीठ स्थापित किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन सितंबर 2010 में हस्ताक्षर किए गए।

भारत-न्यूजीलैंड विदेश कार्यालय परामर्शों का आयोजन 29 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव पूर्व सुश्री लता रेड्डी ने और न्यूजीलैंड के

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व न्यूजीलैंड के विदेश एवं व्यापार मंत्रालय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री जॉन एलेन ने किया।

पापुआ न्यूगिनी

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2010 में पोर्टविला में पश्च मंच वार्ता में भाग लेने के लिए वनवातू का दौरा किया। पापुआ न्यूगिनी के शिक्षा और कार्यकारी खेल मंत्री श्री जेम्स मरापे ने राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक और राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली, 2010 में भाग लिया।

भारत ने प्रशांत द्वीप के देशों के लिए भारत सरकार की क्षेत्रीय सहायता पहल के अंतर्गत पापुआ न्यूगिनी को 1,25,000 अमरीकी डालर का सहायता अनुदान दिया। इस सहायता के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक आईटी उत्कृष्टता केंद्र तथा तीन होल इन दि वाल शिक्षण स्टेशनों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

पापुआ न्यूगिनी में भारतीय सामुदायिक शिक्षा अनुसंधान और विकास परिषद (आईसीआरडीसीई), चेन्नै के सहयोग से वहां के वंचित वर्गों के लिए 13 प्रशिक्षण कालेज स्थापित किए जाने की प्रक्रिया के भाग के रूप में पापुआ न्यूगिनी के विभिन्न भागों में अवस्थित स्कूलों से 33 शिक्षकों को आईसीआरडीसीई, चेन्नै में अपेक्षित प्रशिक्षण दिया गया।

जारी आईटेक कार्यक्रम के तहत वर्ष 2010-2011 के लिए पापुआ न्यूगिनी को आवंटित 25 प्रशिक्षण स्लाट्स का उपयोग पापुआ न्यूगिनी सरकार द्वारा कर लिया गया। कोलम्बो योजना की टीसीएस के अंतर्गत प्रस्तावित चार अन्य स्लाट्स का उपयोग अभी नहीं किया जा सका है।

पापुआ न्यूगिनी तकनीकी विश्वविद्यालय (यूनीटेक) द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से पापुआ न्यूगिनी में दूरस्थ शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी एक परियोजना की परिकल्पना की गई है। इग्नू के सुझावों के अनुरूप पापुआ न्यूगिनी में इग्नू के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए इग्नू और यूनीटेक के बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

फिलीपींस

इस वर्ष लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए फिलीपींस में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और 30 जून, 2010 को राष्ट्रपति बनिग्नो एस. एक्विनो ने राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया। फिलीपींस की नई सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने 2011-2012 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थाई सदस्यता को भी अपना समर्थन दिया है।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डा. फारूख अब्दुल्ला ने एशिया में पवन ऊर्जा पर एडीबी सेमिनार को संबोधित करने के लिए जून 2010 में फिलीपींस का दौरा किया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री ब्यालार रवि ने जुलाई 2010 में मनीला का दौरा किया और उत्प्रवासन मुद्दों पर फिलीपींस सरकार के साथ चर्चा की।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2009-2010 के दौरान 1061.84 मिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ जिसमें भारतीय निर्यात 748.77 मिलियन अमरीकी डालर का और फिलीपींस का निर्यात 313.17 मिलियन अमरीकी डालर का था। सहयोग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बीपीओ है, जिसमें भारतीय आईटी कम्पनियों की मजबूत उपस्थिति है। फिलीपींस की प्रमुख कम्पनियों, अर्थात पीएलडीटी (दूर-संचार), अयाला (रीयल इस्टेट) तथा डेल मोंटे (खाद्य प्रसंस्करण) की उपस्थिति भारत में भी है।

12 सदस्यीय रायल छऊ नृत्य मंडली ने जून 2010 में मनीला का दौरा किया। प्रसिद्ध लेखक और कवयित्री प्रोफेसर मेरली अलुनान ने सितंबर-अक्तूबर 2010 के दौरान प्रसिद्ध भारतीय लेखकों से मिलने-जुलने तथा कविता पाठ करने के लिए साहित्य अकादमी के निमंत्रण पर आनन्द कुमार स्वामी फेलोशिप के अंतर्गत भारत का दौरा किया।

लोगों से लोगों के बीच उत्तरोत्तर बढ़ते सम्पर्कों और हमारे घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री जी ने अक्तूबर 2010 में हनोई में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में घोषणा की कि फिलीस्तीन के राष्ट्रिकों को भी 1 जनवरी, 2011 से आगमन उपरान्त पर्यटक वीजा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

सिंगापुर

इस वर्ष उच्चस्तरीय कार्यकलाप, व्यापक आर्थिक सहयोग करार की दूसरी समीक्षा का शुभारंभ तथा द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की मुख्य विशेषता रही। इस वर्ष सामरिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में गहन और व्यापक कार्यकलापों से द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए।

प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अक्तूबर 2010 में हनोई में आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन तथा आठवें भारत-आसियान सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में प्रधान मंत्री ली सीन लुंग से मुलाकात की। वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग ने मार्च 2010 में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, विपक्ष में लोक सभा की नेता और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। सिंगापुर राष्ट्रीय ओलम्पिक परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री श्री तियो ची हीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली आया और उन्होंने रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय कार्यकलापों के भाग के रूप में विदेश मंत्री ने मार्च 2010 में सिंगापुर का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री ली सीन लुंग, मिनिस्टर मेंटर ली क्वान येव, वरिष्ठ मंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध समन्वय मंत्री प्रोफेसर एस. जय कुमार, उप

प्रधान एवं रक्षा मंत्री तियो ची हीन से मुलाकात की और विदेश मंत्री जार्ज एयो के साथ चर्चा की। सिंगापुर के विदेश मंत्री जार्ज एयो ने कार्यकारी दौरे के लिए तथा नालंदा मेंटर ग्रुप की छठी बैठक में भाग लेने के लिए अगस्त 2010 में नई दिल्ली का दौरा किया। 6-9 मई, 2010 तक उन्होंने तमिलनाडु का आधिकारिक दौरा भी किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन सांगरी-ला डायलॉग में भाग लेने के लिए जून 2010 में सिंगापुर का दौरा किया। 9वें भारत-सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्शों और राष्ट्रीय सुरक्षा गोलमेज की दूसरी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वार्षिक भारत-सिंगापुर सामरिक वार्ता का आयोजन 18-19 फरवरी, 2010 को किया गया।

वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2009 में द्विपक्षीय व्यापार घटकर 21.58 सिंगापुर डालर का रह गया। वर्ष 2010 में सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में ठोस सुधार आने से द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष-दर-वर्ष 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और जनवरी-अक्तूबर 2010 के दौरान यह 24.99 बिलियन सिंगापुर डालर तक पहुंच गई। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा 18.23 बिलियन सिंगापुर डालर का था। अप्रैल 2000-सितंबर 2010 की अवधि में सिंगापुर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह 11.32 बिलियन (समग्र) अमरीकी डालर का रहा।

व्यापक आर्थिक सहयोग करार की दूसरी समीक्षा का शुभारंभ मई 2010 में नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा तथा सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री लिम हंग क्यांग द्वारा किया गया। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय आर्थिक मार्ग पर अपनी सहमति व्यक्त की जिसमें अन्य के साथ-साथ वर्ष 2015 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य शामिल है। सीईसीए की दूसरी समीक्षा के पहले दौर की बैठक का आयोजन 3 अगस्त, 2010 को सिंगापुर में किया गया।

तमिलनाडु सरकार तथा सिंगापुर सहयोग उपक्रम (एससीई) ने चेन्नै में नदियों एवं जल निकायों के जीर्णोद्धार पर एक समझौता ज्ञापन मार्च 2010 में संपन्न किया। कूम नदी का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं प्रबंधन एससीई एवं चेन्नै रिवर्स रेस्टोरेशन ट्रस्ट के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पहली परियोजना होगी। केरल सरकार तथा सिंगापुर सहयोग उपक्रम (एससीई) ने केरल सरकार के साथ शहरी शासन एवं प्रबंधन का अनुभव बांटने के लिए 3 मई, 2010 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया।

रक्षा कार्यदल की 5वीं बैठक अगस्त 2010 में नई दिल्ली में हुई। रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी डीआरडीओ के बीच भारत सिंगापुर रक्षा प्रौद्योगिकी संचालन समिति की छठी बैठक सितंबर 2010 में हुई।

आईसीसीआर एवं सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस) के बीच एनयूएस में दक्षिण एशियाई अध्ययन कार्यक्रम में भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञपन 12 मार्च, 2010 को संपन्न किया गया। यह पीठ कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, एनएसयू के तत्वावधान में दक्षिण एशियाई अध्ययन कार्यक्रम के तहत कार्य करेगा। जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजपे को भारतीय अध्ययन के लिए आईसीसीआर का पहला अतिथि प्राध्यापक चुना गया।

थाईलैंड

थाईलैंड के साथ हमारे संबंध बहुफलकीय हैं और पिछले वर्षों के दौरान ये संवर्धित हुए हैं।

युवराज महावजिरालांगकॉर्न, राजकुमारी श्रीरश्मि और पुत्र युवराज दीपांगकॉर्न रश्मिज्योति तथा शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पवित्र बौद्ध स्थलों की तीर्थ यात्रा के लिए थाईलैंड के विशेष विमान से नवंबर 2010 में भारत आए।

भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार करार की रूपरेखा पर अक्तूबर 2003 में बैंकाक में हस्ताक्षर किए गए। व्यापक मुक्त व्यापार करार पर बातचीत चल रही है जिसका समापन किया जाना है। थाईलैंड के प्राधिकारी आशा व्यक्त करते रहे हैं कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार पर शीघ्र हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। थाईलैंड के उप वाणिज्य मंत्री एलांगकॉर्न पोनलाबूत ने मई 2010 में भारत का दौरा किया और उन्होंने वाणिज्य राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री कमलनाथ के साथ थाईलैंड-भारत मुक्त व्यापार करार सहित अन्य द्विपक्षीय व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा की।

जनवरी-अक्तूबर 2010 के व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि 5.46 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, अर्थात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में थाईलैंड का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रैल 2000-नवंबर 2008 के दौरान 44 मिलियन अमरीकी डालर का रहा है।

भारतीय नौसैनिक एवं तटरक्षक पोतों ने कार्यात्मक यात्राओं एवं पासिंग अभियानों (पासेक्स) के लिए नियमित रूप से थाईलैंड का दौरा किया। मई 2005 में भारतीय नौसेना एवं रॉयल थाई नौसेना के बीच समन्वित गश्ती (कोर्पट) के लिए एक करार संपन्न किया गया था। तब से 11 समन्वय गश्तियां चलाई जा चुकी हैं। पिछली गश्ती 22 नवंबर, 2010 को फुकेट में अभियानों के पूर्ण होने के उपरान्त 15-22 नवंबर, 2010 में आयोजित की गई थी।

थाईलैंड के लगभग 5,000 छात्र (स्कूल और कॉलेज) भारत में हैं।

दोनों देशों के बीच पर्यटकों की पर्याप्त आवाजाही हो रही है। पिछले वर्ष 5.3 लाख भारतीयों ने थाईलैंड का दौरा किया जबकि थाईलैंड के लगभग 40,000 पर्यटक भारत आए जिनमें से अधिकांश ने बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा।

प्रशांत द्वीप

भारत ने पोर्ट विला, वनवातू में आयोजित 41वें प्रशांत द्वीप मंच (पीआईएफ) की बैठक के उपरान्त यहीं 6 अगस्त, 2010 को आयोजत पश्च मंच वार्ता (पीएफडी) भागीदारों की 22वीं बैठक में भाग लिया। पीएफडी के दौरान विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक कार्यसूची में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके विकासशील देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। विकासशील देशों के लिए यह सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है बल्कि यह उनकी विकास आकांक्षाओं एवं उत्तरजीविता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

भारत को प्रशांत द्वीपों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी है और उन्होंने प्रशांत द्वीप के देशों के आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ उनके बेहतर समेकन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने घोषणा की कि जिन देशों ने पिछले वर्षों के दौरान प्रभावित 1,25,000 अमरीकी डालर के सहायता अनुदान का उपयोग नहीं किया, वे देश इस बार किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

नूई

लिकु विलेज पास्टर्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के नवीनीकरण को वित्तपोषित करने के लिए नूई सरकार के लिए 71,000 अमरीकी डालर का सहायता अनुदान जारी किया गया। साथ ही नूई खेल, प्रशिक्षण एवं मनोरंज केंद्र में छत का दोबारा निर्माण करने और इसके नवीनीकरण के लिए 29,000 अमरीकी डालर दिया गया।

नौरू

नौरू गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मार्कस स्टिफन ने श्रीमती अमांडा स्टीफन तथा नौरू सरकार में खेल मंत्री श्री मैथ्यू बत्सीयूआ और उनकी पत्नी श्रीमती ट्रिशिया बत्सीयूआ के साथ 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 1-5 अक्तूबर, 2010 तक नई दिल्ली का दौरा किया।

पलाऊ, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य

पलाऊ, मार्शल द्वीप तथा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे और अगस्त 2003 में आयोजित प्रशांत द्वीप मंच (पीआईएफ) की पहली वार्ता बैठक में भारत की भागीदारी के बाद से ही इनके साथ हमारे कार्यकलापों में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

उन्होंने 2011-2012 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित 10 सीटों में से मार्शल द्वीप के छात्रों को 5, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों को 3 तथा पलाऊ गणराज्य को 2 सीटें आवंटित की जाएंगी। वर्तमान वर्ष के दौरान 30 नवंबर तक मार्शल द्वीप तथा पलाऊ गणराज्य द्वारा एक-एक प्रशिक्षण स्लाट का उपयोग किया गया है।

प्रशांत द्वीप मंच के सदस्य देशों की विकास परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान देने की भारत सरकार की वचनबद्धता को कार्यान्वित करते हुए अब तक मार्शल द्वीप द्वारा 1,00,000 अमरीकी डालर (सौर स्ट्रीट लाइटिंग), माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों द्वारा 73,145 अमरीकी डालर (नारियल विकास प्राधिकरण से मशीनों की खरीद) और पलाऊ गणराज्य द्वारा 1,00,000 अमरीकी डालर (एक नौका एवं दो पिकअप ट्रक) का उपयोग किया गया है।

सोलमन द्वीप तथा वनुआतू

वर्ष 2010-2011 से आईटेक के अंतर्गत प्रशिक्षण स्लाट्स की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है।

भारत ने पापुआ न्यूगिनी, सोलोमन द्वीप और वनुआतू को प्रशांत द्वीप देशों के लिए भारत सरकार की क्षेत्रीय सहायता पहल के अंतर्गत प्रति देश 1,25,000 अमरीकी डालर का नया सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव किया है।

■■

3 पूर्व एशिया

जापान

'भारत-जापान रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी' की स्थापना होने और प्रधान मंत्री की दिसंबर 2006 में हुई जापान की यात्रा के दौरान वार्षिक शिखर बैठक की परंपरा से हाल के वर्षों में जापान के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। वर्ष 2010-2011 में हुए कई उच्च स्तरीय दौरों, सहयोग के नए क्षेत्रों एवं वार्ता की नई व्यवस्थाओं, आर्थिक सहभागिता गहन होने, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैगशिप परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन तथा रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग होने से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार आना जारी रहा।

वर्ष 2010-2011 में जापान के साथ भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जापान के प्रधान मंत्री, नाओतो कॉन के साथ वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 24-26 अक्तूबर, 2010 तक प्रधान मंत्री की जापान यात्रा थी। दोनों प्रधान मंत्री ने दो दस्तावेज नामतः 'अगले दशक में भारत-जापान रणनीतिक एवं वैश्विक सहभागिता के दृष्टिकोण' पर एक संयुक्त वक्तव्य और 'व्यापक आर्थिक सहभागिता करार के निष्पादन पर भारत और जापान के नेताओं द्वारा संयुक्त घोषणा-पत्र ' पर हस्ताक्षर किये। इसके अलावा, यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच वीजा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। प्रधान मंत्री की जापान के प्रधान मंत्री के साथ सीमित-सत्र और प्रतिनिधि स्तरीय, दोनों वार्ताओं में गहन चर्चा हुई। इस यात्रा से भारत-जापान संबंधों को बेहतर बनाने की प्रवृति और इन बढ़ते महत्वपूर्ण संबंधों में शिखर बैठक स्तरीय प्रतिबद्धताओं को कायम रखने में मदद मिली।

भारत और जापान के पास राजनीतिक संवाद के लिए एक संतुलित ढांचा मौजूद है। जापान के प्रधान मंत्री के रूप में श्री कॉन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के अन्दर दोनों प्रधान मंत्रियों ने 27 जून, 2010 को टोरंटो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में संक्षिप्त मुलाकात की; दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को आकार देने की सतत इच्छा व्यक्त की। भारत और जापान ने वर्ष 2007 से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित की है। जापान के तत्कालीन विदेश मंत्री काटसुया ओकाडा ने इस वार्ता के चौथे दौर के लिए 21 अगस्त, 2010 को भारत की यात्रा की। मंत्रिस्तरीय वार्ता के अन्य तंत्रों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और जापान के एमईटीआई (अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय) मंत्री स्तर की और योजना आयोग के उपाध्यक्ष और एमईटीआई के मंत्री के बीच उच्च स्तरीय उर्जा वार्ता जापान-भारत नीति वार्ता में शामिल हैं। इन दोनों वार्ता का अंतिम दौर तत्कालीन एमईटीआई मंत्री मासायुकी नाओशिमा की यात्रा के दौरान 30 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दोनों देशों ने वर्ष 2009 से दोनों रक्षा मंत्रियों के द्वारा होने वाले वार्षिक दौरे की भी शुरूआत की है। इसके परिणामस्वरूप, जापान के रक्षा मंत्री श्री तोशिमी किताजावा ने 30 अप्रैल-1 मई 2010 को भारत की यात्रा की और रक्षा मंत्री के साथ गहन विचार-विमर्श किया। अक्तूबर 2010 को वार्षिक शिखर बैठक के दौरान दोनों देश क्षेत्रीय एवं वैश्विक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए और अवसंरचना विकास एवं वित्तपोषण सहित परस्पर-विरोधी स्वरूप के आर्थिक मसलों का समन्वय करने के लिए अपने-अपने द्विपक्षीय आर्थिक क्रियाकलापों के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीति का निर्धारण करने के लिए एक मंत्री-स्तरीय आर्थिक वार्ता-तंत्र स्थापित करने पर सिद्धांततः सहमत हुए।

दोनों देशों के सरकारी मंत्रियों, संसद-सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के एक-दूसरे देशों में नियमित दौरे हुए हैं। ऊपर बताए गए नियमित मंत्रिस्तरीय वार्ता तंत्रों के अलावा, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रियों ने वर्ष 2010-2011 में जापान की यात्रा कीः वित्त राज्य मंत्री (22-25 जुलाई, 2010) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (2-7 अक्तूबर, 2010)। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने 15-20 जनवरी, 2011 तक जापान की यात्रा की, जबकि संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री ने 27 जनवरी-2 फरवरी 2011 तक जापान में सद्भावना यात्रा पर संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत और जापान में सभी स्तरों पर व्यापक अधिकारी स्तरीय वार्ता तंत्र मौजूद है और इनमें से अधिकांश वार्ता तंत्र की बैठकें नियमित रूप से वर्ष 2010-2011 में आयोजित हुई। द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा, इन वार्ताओं में क्षेत्रीय एवं वैश्विक रूप से और अन्य जी-4 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और जी-4 देशों के विदेश मंत्रियों ने सितंबर 2010 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की। वर्ष 2010-2011 में शुरू हुई वार्ताओं में अफ्रीका पर वार्ता शामिल है, जिसकी पहली बैठक 4-6 अक्तूबर, 2010 को टोक्यो में हुई।

भारत-जापान संबंधों में आर्थिक सहयोग की काफी संभावना है। दोनों देशों ने सितंबर 2010 में व्यापक आर्थिक भागीदारी करार संपन्न करने के लिए बातचीत पूरी कर ली है। इसकी औपचारिक

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, 30 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में
जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए।
जापान के रक्षा मंत्री श्री तोशिमी किताजावा और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री नासायुकी नाओशिमा भी साथ में है।

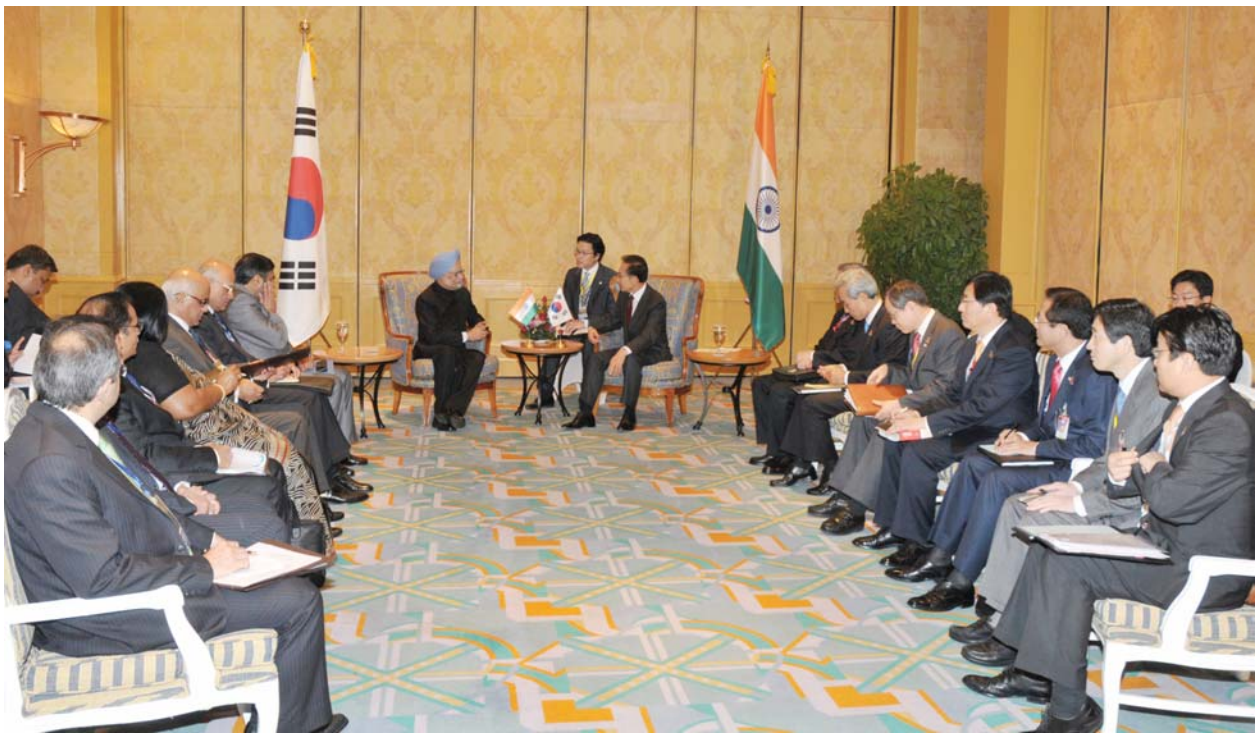

हनोई, वियतनाम में 29 अक्तूबर, 2010 को आयोजित 17वें आसियान शिखर सम्मेलन और अन्य संबंधित बैठकों के दौरान
अतिरिक्त समय में प्रधान मत्री डॉ. मनमोहन सिंह और
दक्षिण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री ली म्यूंग-बाक के बीच द्विपक्षीय बैठक।

घोषणा अक्तूबर 2010 में वार्षिक शिखर बैठक के दौरान की गई। यह करार भारत द्वारा अभी तक निष्पादित इस प्रकार के करारों से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार, विस्तृत सेवाएं, निवेश, आई पी आर, सीमा शुल्क और व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दे शामिल है। सी ई पी ए पर औपचारिक रूप से फरवरा 2011 में मंत्रिस्तरीय बैठक में हस्ताक्षर होने की आशा है। वर्ष 2010-2011 में भारत लगातार सातवें वर्ष जापान से ओ डी ए का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। भारत के लिए अभी तक (जुलाई 2010 तक) जापानी ओ डी ए की संचित प्रतिबद्धता 3.3 ट्रिलीयन येन की है। वर्ष 2010 में जापान सरकार के आकड़ों के अनुसार पहले 11 माह में व्यापार में निरन्तर प्रगति होती रही और यह बढ़कर 13.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। 8.08 बिलियन अमरीकी डालर के पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान भारत के लिए जापान के निर्यात में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत से जापान का आयात 57 प्रतिशत बढ़कर 5.22 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्तमान में जापान, भारत के 3.62 प्रतिशत के कुल एफ डी आई प्रवाह के साथ भारत के संचित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह का छठा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2006 की विशेष आर्थिक भागीदारी पहल के अन्तर्गत भारत और जापान ने समर्पित फ्रेट-कॉरीडोरी (डीएफसी) और दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजनाओं जैसी फ्लैगशिप परियोजनाएं शुरू की हैं, जो कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। डी एफ सी के चरण-I के करार पर मार्च 2010 के अंतिम सप्ताह में हस्ताक्षर हुए, जबकि परियोजना के चरण-II के इंजीनियरींग सेवा ऋण पर 26 जुलाई, 2010 के हस्ताक्षर किये गए। डीएमआईसी के साथ-साथ 'स्मार्ट कम्यूनिटीज एंड इको-फ्रेंडली सिटीज' के निर्माण में शामिल चार जापानी कंसोर्टियम ने चार संबंधित राज्य सरकारों के साथ 30 अप्रैल, 2010 को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के डी एम आई सी राज्यों में स्थित जापान की पांच प्रारंभिक परियोजनाएं (ई बी पी) वर्तमान में कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है, जबकि जापानी पक्ष द्वारा छठी परियोजना की घोषणा जून 2010 में की गई है। भारत और जपान के बीच सामाजिक सुरक्षा करार संपन्न करने के लिए 12-15 जनवरी, 2011 तक वार्ता का प्रारंभिक दौर संपन्न हुआ।

भारत और जापान के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में गहन सहयोग रहा है, जिसमें जापान भारत को कोयला और नई एवं पुनर्नवीकरण ऊर्जा जैसे और प्रशिक्षण एवं मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा प्रभाविकता बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। नई दिल्ली में 30 अप्रैल, 2010 को संपन्न चतुर्थ भारत-जापान ऊर्जा वार्ता की समाप्ति पर भारत के योजना आयोग और जापान के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्री के बीच ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र को दर्शाते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। जापान सरकार ने भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग के लिए वार्ता शुरू करने के अपने निर्णय की घोषणा 25 जून, 2010 को की। इस संबंध में दोनों देशों के बीच वार्ता के तीन दौर आयोजित किये गए हैं।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग क्रमिक रूप से जापान के साथ हमारी सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरा है और इसे दोनों पक्षों द्वारा एशिया और विश्व में शांति और समृद्धि के लिए लाभकारी रूप में स्वीकार किया गया है। अक्तूबर 2008 की भारत-जापान सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा की रूपरेखा, जोकि भारत द्वारा किसी अन्य देश के साथ हस्ताक्षरित पहला ऐसा दस्तावेज था, के अन्दर एक ठोस कार्रवाई योजना दिसंबर 2009 में जारी की गई। सहयोग में समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री डकैती एवं सीमा-पार अपराधों के विरूद्ध युद्ध, परिवहन सुरक्षा, समुद्री माहौल की सुरक्षा एवं एशिया की बहुपक्षीय रूपरेखा में परामर्श एवं सहयोग के व्यापक मुद्दे शामिल हैं। वर्ष 2010-2011 में रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, दो समहत दस्तावेज तथा रक्षा आदान-प्रदान के वार्षिक कैलेंडर के आधार पर आगे बढ़े हैं। वर्ष के दौरान शुरू हुई दो वार्ताओं में नई दिल्ली में 6 जुलाई, 2010 को भारत के विदेश एवं रक्षा सचिव तथा जापान के उप विदेश मंत्री तथा प्रशासनिक वाइस मिनिस्टर के बीच पहली बार आयोजित 'टु-प्लस-टु' वार्ता शामिल है। वर्ष 2010 में ग्राउंड-टु-ग्राउंड स्टाफ वार्ता शुरू हुई। दोनों देशों के तट-रक्षक बलों के महानिदेशकों के बीच 29 नवंबर-3 दिसंबर 2010 तक कोबे में आयोजित 10वीं उच्च-स्तरीय बैठक के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक जहाज 'विश्वस्त' ने जापानी तटरक्षक के साथ संयुक्त अभ्यास किया।

कोरिया गणराज्य (आर ओ के)

कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति रोह म्यून-ह्वान की वर्ष 2004 में हुई भारत की यात्रा के दौरान कोरिया गणराज्य और भारत के बीच स्थापित 'दीर्घकालिक सहयोगी भागीदारी' भारत-कोरिया गणराज्य द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है। यह भागीदारी हाल के वर्षों में और अधिक सघन एवं विस्तृत हुई है और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली म्यूंग-बाक की जनवरी 2010 में हुई भारत की यात्रा के दौरान यह 'रणनीतिक भागीदारी' के स्तर तक पहुंच गई। वर्ष के दौरान कई उच्च स्तरीय दौरे, करार, संवर्धित आर्थिक एवं वाणिज्यिक तालमेल और कला व संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ते आदान-प्रदान भारत-कोरिया गणराज्य के द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण बिन्दु रहे हैं।

शिखर बैठक स्तर पर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली म्यूंग-बाक की जनवरी 2010 में हुई यात्रा के पश्चात प्रधान मंत्री और कोरिया गणराज्य राष्ट्रपति पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में 29 अक्तूबर, 2010 को हनोई में मिले। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ली ने जी-20 में लिये गए निर्णयों का सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने की आवश्यकता बतायी। प्रधान मंत्री ने 10-12 नवंबर, 2010 तक जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोरिया गणराज्य की यात्रा की। इस

सम्मेलन के दौरान उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की जनवरी 2010 में हुई यात्रा के पश्चात कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के दौरे हुए। भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की छठी बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 17-19 जून, 2010 तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की। संयुक्त आयोग की बैठकों की सह-अध्यक्षता करने के अलावा, विदेश मंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी में एक बैठक को भी संबोधित किया। यात्रा के दौरान निम्नलिखित तीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये गएः (i) लघु एवं मध्य उद्यम के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के लघु एवं मध्यम व्यापार प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन; (ii) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और कोरिया फाउंडेशन के बीच सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन; और (iii) भारतीय विश्व कार्य परिषद् (आई.सी.डब्ल्यू.ए.) और कोरिया गणराज्य के इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी के बीच सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जी-20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 21-24 अक्तूबर, 2010 तक ग्योंग्जु, कोरिया गणराज्य में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि ने अक्तूबर 2010 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा करार पर 19 अक्तूबर, 2010 को हस्ताक्षर किये गए। यह करार दोनों देशों के बीच व्यावसायिकों की आवाजाही को बढ़ाएगा और व्यापार एवं निवेश को मजबूती प्रदान करेगा। विद्युत राज्य मंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी ने 11-14 मई, 2010 तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की। विद्युत राज्य मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान वहां के नॉलेज इकोनॉमी मंत्री डा. चोइ क्यूंग-ह्वान से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री श्री मुलापल्ली रामाचन्द्रन ने इंचियोन, कोरिया गणराज्य में आयोजित आपदा जोखिम कमी पर चतुर्थ एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25-29 अक्तूबर, 2010 तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की।

वर्ष के दौरान भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग निर्बाध रूप से जारी रहा। रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटोनी ने 2-4 सितम्बर, 2010 तक द्विपक्षीय यात्रा पर कोरिया गणराज्य की यात्रा की। यात्रा के दौरान दो करारः (i) रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन; और (ii) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन (डी.ए.पी.ए.) के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर समझौता ज्ञापन।

कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की अक्तूबर 2004 में हुई भारत की यात्रा के दौरान घोषित भारत-कोरिया गणराज्य विदेश नीति एवं सुरक्षा वार्ता (एफ पी एस डी) की वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष नियमित बैठकें हुई हैं। एफ पी एस डी का चौथा दौर सचिव/उप-मंत्री स्तर पर 9 अप्रैल, 2010 को सियोल, कोरिया गणराज्य में आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सचिव (पूर्वी) विजया लता रेड्डी ने किया। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की जनवरी 2010 में हुई भारत की यात्रा के दौरान लिये गए निर्णय के अनुसरण में इस वार्ता के स्तर को संयुक्त सचिव/महानिदेशक स्तर से बढ़ा कर सचिव/उप-मंत्री स्तर का कर दिया गया। इसमें भारत-कोरिया गणराज्य रक्षा सहयोग और आतंकवाद एवं अप्रसार सहित क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई।

भारत-कोरिया गणराज्य रक्षा उद्योग एवं संभार-तंत्र पर संयुक्त समिति की सचिव/उप-मंत्री स्तर की तृतीय बैठक 15-16 अप्रैल, 2010 को आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री अजय आचार्या ने किया। भारतीय तट-रक्षक और कोरिया तट-रक्षक के बीच उप महानिदेशक स्तरीय पांचवीं द्विपक्षीय उच्च-स्तरीय बैठक 10 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में खोज एवं बचाव, समुद्री प्रदूषण, संयुक्त अभ्यास, भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और गश्ती पोतों पर कार्मिकों के परस्पर आदान-प्रदान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। छठीं उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2011 में दक्षिण कोरिया में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

पृथ्वी विज्ञान एवं सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए कोरिया गणराज्य के कोरियाई मौसम विज्ञान प्रशासन और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 29 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गए। भारत के केआईआईटी विश्वविद्यालय और कोरिया गणराज्य के हांसियो विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 15 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षर किये गए।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और कोरिया एयरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (कारी) के बीच बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग करने में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के पश्चात इसरो के विशेषज्ञों के एक दल ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का पता लगाने के लिए जनवरी 2011 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की।

दोनों देशों के बीच जनवरी 2010 में सीईपीए के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भारत-कोरिया गणराज्य द्विपक्षीय व्यापार में इस वर्ष के पहले नौ माह में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार 12.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की जनवरी 2010 में हुई यात्रा के दौरान वर्ष 2014 तक प्राप्त करने के लिए 30 बिलियन अमरीकी डालर का एक नया व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सीईपीए ने अपने कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाने में सहयोग किया है। सीईपीए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए व्यापार मंत्री श्री किम जोंग-हून ने 20 जनवरी, 2011 को दोनों देशों के व्यापार मंत्री के नेतृत्व में संयुक्त समिति की पहली बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की।

दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कोरिया गणराज्य के रणनीति एवं वित्त मंत्री श्री यून जियुंग ह्यून ने नई दिल्ली में 17 जनवरी, 2011 को आयोजित द्वितीय कोरिया-भारत वित्त मंत्रियों की बैठक में कोरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की जनवरी 2010 में हुई यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2011 में कोरिया गणराज्य में 'भारत वर्ष' और भारत में 'कोरिया वर्ष' का आयोजन किया जाए। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय समकालीन कला संग्रहालय में 'रियलिज्म इन एशियन आर्ट' प्रदर्शनी आयोजित की गई। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल इत्यादि के भारतीय प्रदर्शों की प्रदर्शनी लगायी गईं। कत्थक गुरू पदम विभूषण पंडित बिरजु महाराज ने भा.सां.सं.परि. द्वारा प्रायोजित एक 22 सदस्यीय दल ऋतु-संसर का नेतृत्व किया। उन्होंने 1-13 अक्तूबर, 2010 तक कोरिया गणराज्य में जियोन्जु सोरी महोत्सव, नामी महाद्वीप और राष्ट्रीय संग्रहालय और बाक्जे महोत्सव में प्रदर्शन किया।

मंगोलिया

भारत और मंगोलिया दोनों ने अपनी सदियों पूरानी मैत्री के आधार पर सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाए रखे। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर और मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री साखियाजीइन एल्बेग्दोर्ज की वर्ष 2009 में हुई यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को बल मिला। दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, मानव संसाधन विकास और संसदीय आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करते हुए नाभिकीय ऊर्जा, खनन एवं सांख्यिकी जैसे कई नए क्षेत्रों में सहयोग करार संपन्न किए हैं। यद्यपि, वर्ष के दौरान कोई उच्च स्तरीय यात्रा नहीं हुई, फिर भी दोनों देशों ने वर्ष 2009 में दोनों देशों के बीच संपन्न करारों को कार्यान्वित करने के प्रयास किए।

लोक सभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार ने 26-30 जून, 2010 तक मंगोलिया की यात्रा की। लोकसभा अध्यक्षा ने अपने समकक्ष स्टेट ग्रेट हुराल के अध्यक्ष श्री डामदीन डेम्बेरेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें उन्होंने दोनों संसदों के बीच सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री अधीर रंजन चौधुरी (लोकसभा सदस्य) की अध्यक्षता में भारतीय संसद में एक भारत-मंगोलिया संसदीय दल का गठन किया गया। दोनों सचिवालयों के बीच मैत्री संबंधों एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लोक सभा सचिवालय और मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल ने एक प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष संसदीय कानूनों, विधिक दस्तावेजों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का परस्पर आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए।

खनन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां भारत और मंगोलिया के हितों की समानता है। खनन, खनिज एवं भू-विज्ञान क्षेत्र पर प्रथम संयुक्त कार्य दल की बैठक में भाग लेने के लिए श्रीमती शांता शीला नायर, सचिव (खनन) के नेतृत्व में भारतीय परतिनिधिमंडल (जिसमें इस क्षेत्र के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि थे) ने 6-10 जून, 2010 तक मंगोलिया की यात्रा की। भारत खाना बनाने के कोयले, थर्मल कोयले, यूरेनियम और फ्लोरस्पार जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का इच्छुक है। मंगोलियाई पक्ष ने खनिज प्रसंस्करण, प्रयोगशाला स्केल अध्ययन एवं प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकृत अयस्क बॉडी मोडेलिंग, उपग्रह आधारित नक्शा तैयार करने और लक्षित सर्वेक्षण एवं अध्ययन के क्षेत्रों में विदेशी निवेश एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की है।

मंगोलिया की राष्ट्रीय विकास एवं नवाचार समिति (एनडीआईसी) जो कि हमारे योजना आयोग के समकक्ष एक निकाय है, के अध्यक्ष श्री चुलून्डोर्ज खासचुलून ने 7 सितम्बर, 2010 को नई दिल्ली में सचिव (खनन) के साथ बैठक की और एनडीआईसी द्वारा तैयार 'दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज 26 इंवेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स' नामक एक दस्तावेज सौंपा। उन्होंने कहा कि मंगोलियाई प्राधिकारी विशिष्ट रूप से भारतीय कंपनियों के लिए एक औद्योगिकी पार्क का डिजाइन तैयार करने के इच्छुक होंगे, यदि सौंपी गई 26 परियोजनाओं की सूची में से किसी परियोना में रूचि प्रदर्शित की जाती है। भारतीय पक्ष प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। कईं भारतीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (जैसे नालको, सेल, तामीन और जीएमडीसी) और निजी क्षेत्र (जैसे टेगा उद्योग, मेस्को स्टील, मोहन एनर्जी और स्टील वर्क्स गुजरात) की कंपिनियों ने मंगोलिया के खनन क्षेत्र में रूचि दिखायी है और दोनों देशों के बीच सहयोग से लाभान्वित होने की आशा है। भारतीय रूचि मुख्यतः कोयला, लौह अयस्क, उर्वरक से संबंधित खनिज, यूरेनियम और रेयर अर्थ में है। श्री खासचुलून की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत के योजना आयोग और मंगोलिया के राष्ट्रीय विकास एवं नवाचार समिति के बीच समझौता ज्ञापन के पाठ को अंतिम रूप दिया।

भारत और मंगोलिया ने नाभिकीय ऊर्जा और रेडियोधर्मी सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। दोनों पक्ष संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक मुम्बई में आयोजित करने पर सहमत हुए। भारत ने मंगोलिया के नाभिकीय विशेषज्ञों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) में प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। भारत ने मंगोलिया को एक विनियामक रेडियेशन सुरक्षा ढांचा स्थापित करने में सहायता करने की भी पेशकश की है। भारतीय सरकारी क्षेत्र की कंपनी नालको-एन पी सी आई एल मंगोलिया में यूरेनियम खनन करने की इच्छुक हैं।

सीमा सुरक्षा सहयोग का एक अन्य क्षेत्र है, जिसमें दोनों पक्षों ने काफी प्रगति की है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक

श्री रमण श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पांच-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 16-19 जून, 2010 तक मंगोलिया की यात्रा की। दोनों पक्ष विशेष बल संचालन पर मंगोलिया के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था तैयार करने पर सहमत हुए। सीमा सुरक्षा बल ने मंगोलिया की सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मानव संसाधान प्रबंधन साफ्टवेयर तैयार किया है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के लिए तृतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 दिसंबर 2010-2012 फरवरी 2011 तक बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर में आयोजित किया गया। सात सप्ताह के पाठ्यक्रम में मौलिक अंग्रेजी, दुर्गम क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन, विशेष अभियान, अनुदेशक प्रोफाइन और दो सप्ताह का सीमा अध्ययन दौरा शामिल है।

भारत और मंगोलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आपसी हित के मुद्दों पर वार्षिक वार्ता आयोजित की। इसकी अंतिम वार्ता 1-2 सितंबर, 2010 को उलानबातार में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त आसूचना समिति के अध्यक्ष श्री एच. उपाध्याय ने की। मंगोलिया पक्ष ने 'राष्ट्रीय घुसपैठ सूचक एवं निषेधक नेटवर्क मानीटरिंग केन्द्र' और 'सूचना सुरक्षा प्रशिक्षण प्रयोगशाला' स्थापित करने में भारत से सहायता देने का अनुरोध किया। इस संबंध में मंगोलिया के सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के एक दल ने दिसंबर 2010 में भारत की यात्रा की।

मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल के अध्यक्ष (मंगोलियाई संसद) श्री डी. डेम्बेरेल ने लोकसभा अध्यक्षा के निमंत्रण पर 8-14 दिसबर, 2010 तक भारत की यात्रा की। नई दिल्ली में श्री डेम्बेरेल ने उप राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्षा और विपक्षी दल के नेता, विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य और इस्पात मंत्री से मुलाकात की। सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग ने उनसे मुलाकात की। भारत के योजना आयोग और मंगोलिया की राष्ट्रीय विकास एवं नवाचार समिति के बीच सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर 9 दिसंबर, 2010 को आद्यक्षर किये गए। भारत गणराज्य की लोकसभा और मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल के बीच सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर 9 दिसंबर, 2010 को हस्ताक्षर किये गए।

'नोमाडिक एलीफैन्ट' नामक एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग अभ्यास 6-19 दिसंबर, 2010 को बेलगांव में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना के 50 अधिकारियों और कार्मिकों के साथ मंगोलिया सशस्त्र बलों के कुल 30 सदस्यों, जिनमें कि 28 सेवाकर्मी और दो पर्यवेक्षक शामिल हैं, ने भाग लिया।

मंगोलिया आइटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख लाभप्राप्तकर्ता देशों में से एक बन गया है। अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंधन, लघु व्यापार, कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, तेल एवं गैस परिमापन, फ्लोर मिलींग प्रौद्योगिकी, मौसम विज्ञान, वस्त्र अनुसंधान, मानकीकरण, पत्रकारिता एवं जन संचार और अनुप्रयुक्त मानवशक्ति सहित विभिन्न विषयों में मंगोलिया के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए मंगोलिया ने आइटेक स्लॉट का उपयोग किया है। आइटेक/स्केप 2010-2011 के अन्तर्गत रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मंगोलिया को 11 स्लॉट आवंटित किये गए हैं।

मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारतीय दावेदारी का समर्थन करता है। उसने वर्ष 2011-2012 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारतीय दावेदारी का भी समर्थन किया है।

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके)

भारत और डीपीआरके के बीच संबंध मानवीय एवं मानव संसाधन विकास सहायता पर केन्द्रित होते हुए सौहार्द्रपूर्ण बने रहे। संस्कृति, खेल-कूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान में प्रगति होना जारी रहा। डीपीआरके में मानव संसाधन विकास के लिए हमारी सहायता जारी रही। गत वर्ष की भाति वर्ष 2010-2011 के लिए डीपीआरके को आइटेक के अंतर्गत 18 स्लॉट आवंटित किये गए। संयुक्त राष्ट्र के निकायों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत और डीपीआरके ने सहयोग करना जारी रखा।

■■

4 यूरेशिया

रूसी परिसंघ

रूस के साथ संबंध भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता बनी हुई है और यह एक 'विशेष और विशेषाधिकृत' सामरिक भागीदारी है। पिछले वर्षों के दौरान रूसी परिसंघ के साथ भारत के कार्यकलापों में आई तेजी वर्ष 2010-2011 के दौरान भी जारी रही। रूस के प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमीर पुतिन ने 12 मार्च, 2010 को तथा राष्ट्रपति श्री दिमित्री मेदवेदेव ने 11वीं वार्षिक शिखर बैठक के लिए 21-22 दिसंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया। अनेक मंत्रिस्तरीय एवं आधिकारिक यात्राओं के अतिरिक्त सैन्य तकनीकी सहयोग (एमटीसी), और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग (टीईसी) से संबद्ध भारत-रूस अंतर्सरकारी आयोगों की बैठकों का आयोजन क्रमशः अक्तूबर एवं नवंबर, माह में किया गया। अतः पूरे वर्ष हमारे द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र का विस्तार होता रहा और इसमें गहनता आती रही।

प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर 12 मार्च, 2010 को भारत का कार्यकारी का दौरा किया। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था जिसमें अनेक मंत्री तथा रूस के रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्ति शामिल थे। अपनी यात्रा के दौरान रूस के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह से बातचीत की और उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से भी मुलाकात की। उन्होंने एक रूसी टेलिकॉम कम्पनी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अन्य नगरों की प्रमुख व्यावसायिक हस्तियों, बुद्धिजीवियों और छात्रों से बात की। यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए गएः (i) शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किए जाने के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच करार; (ii) भारत गणराज्य में रूसी डिजाइन वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के क्रमिक निर्माण का रोड मैप; (iii) इसरो और रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच असैनिक उपयोग के लिए उपग्रह नौवहन उपकरण के निर्माण एवं सेवाओं के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन; (iv) भारत गणराज्य के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा रूसी परिसंघ के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के बीच उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; और (v) भारत के इफको तथा आईपीएल (इंडियन पोटास लिमिटेड) और रूस के फोसाग्रो के बीच डीएपी उर्वरकों के आयात से संबंधित करार की रूपरेखा। इस यात्रा के दौरान ही अनेक व्यावसायिक करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रपति मेदवेदेव ने भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ होने वाली 11वीं वार्षिक शिखर बैठक के लिए 21-22 दिसंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया। भारत-रूस सामरिक भागीदारी का एक दशक पूरा होने के कारण इस शिखर बैठक का ऐतिहासिक महत्व है जिसके दौरान हमारे संबंध 'विशेष और विशेषाधिकृत' बन गए हैं। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की और वे राष्ट्रपति जी से मिलने गए जिन्होंने उनके सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया गया था। उन्होंने आगरा और मुम्बई का भी दौरा किया। मुम्बई में आयोजित उनके कार्यक्रमों में आईआईटी, मुम्बई के छात्रों और भारतीय फिल्म उद्योग के साथ बातचीत शामिल थी। भारत और रूस के प्रधान मंत्रियों की उपस्थिति में निम्नलिखित ग्यारह करारों पर हस्ताक्षर किए गएः (1) भारत के निर्वाचन आयोग और रूसी परिसंघ के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच चुनाव के क्षेत्र में पारस्परिक समझबूझ और सहयोग पर ज्ञापन; (2) भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के राष्ट्रिकों की कतिपय श्रेणियों के लिए यात्रा दस्तावेजों के पारस्परिक सरलीकरण पर करार; (3) आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर करार; (4) तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्सरकारी करार; (5) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में समेकित दीर्घावधिक सहयोग कार्यक्रम; (6) भारत गणराज्य की सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा रूसी परिसंघ के शिक्षा एवं विज्ञान मंत्रालय के बीच भारत-रूस वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हेतु संयुक्त कार्यकारी दस्तावेज; (7) स्टेट परमाणु ऊर्जा सहयोग 'रोसाटोम' तथा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन; (8) अनियमित उत्प्रवासन की रोकथाम करने के संबंध में पारस्परिक सहमति ज्ञापन; (9) भारत गणराज्य के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) और रूसी परिसंघ के दूर संचार एवं जन संचार मंत्रालय के बीच सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (10) भेषज क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (11) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड तथा जेएसएफसी सिस्टेमा के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध रूपरेखा करार। शिखर बैठक के अन्त में 'भारत रूस सामरिक भागीदारी का दशक और इससे आगे' शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य भी

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री दिमित्री ए. मेदवेदेव 21 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस सम्मेलन में।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 11 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नजरबायेव के साथ मुलाकात करते हुए।

पारित किया गया। इसके अतिरिक्त शिखर बैठक के पार्श्व में सरकारी और निजी क्षेत्र में लगभग बीस अन्य संविदाएं भी संपन्न की गईं। ये संविदाएं रक्षा, बैंकिंग, व्यापार, भेषज, रसायन और पेट्रोरसायन तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संपन्न की गईं।

उपर्युक्त दो यात्राओं के अतिरिक्त इस वर्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राएं भी हुईं:

- ब्राजील-रूस-भारत-चीन (ब्रिक) कृषि मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने 24-27 मार्च, 2010 तक मास्को का दौरा किया। उन्होंने अपने रूसी समकक्ष सुश्री एलेना स्क्रिनिक के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

- उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री आलोक प्रसाद ने अपने रूसी समकक्ष श्री वी. पी. नजारोव के साथ संयुक्त समन्वय समूह की बैठक में भाग लेने के लिए मास्को का दौरा किया। इन दोनों के बीच बैठकों का अगला दौर 24-25 नवंबर, 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 18-19 जून, 2010 तक मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री की सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एसपीआईईएफ) में भाग लेने के लिए एक उच्चस्तरीय भारतीय व्यापारिक शिष्टमंडल भी गया था। मास्को में मंत्री महोदय ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की।

- उद्योग और व्यापार उपमंत्री श्री जी. वी. कलामानोव ने भेषज क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए 20-21 जुलाई, 2010 तक भारत का दौरा किया।

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलाई पातरूशेव के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद में भाग लेने के लिए 17-18 अगस्त, 2010 तक रूस का दौरा किया। सुरक्षा से संबद्ध उच्च प्रतिनिधियों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में उन्होंने अक्तूबर 2010 में अपने रूसी समकक्ष के साथ सोच्ची में दूसरी द्विपक्षीय बैठक की।

- रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री श्री वी. बी. क्रिस्टेन्को ने 15-19 फरवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान रूस के मंत्री महोदय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा से मुलाकात की और उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। बाद में श्री क्रिस्टेन्को ने मिग-29के को वायुसेना में शामिल किए जाने के अवसर पर गोवा में आयोजित समारोह में भी भाग लिया, जहां रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी भी उपस्थित थे। श्री क्रिस्टेन्को ने 29 सितंबर-1 अक्तूबर 2010 तक दोबारा भारत का दौरा किया और वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान भेषज क्षेत्र में सहयोग पर गोलमेज चर्चा का भी आयोजन किया गया।

- रूसी रक्षा मंत्री श्री अनातोली ई. सर्डियुकोव ने 7 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित सैन्य तकनीकी सहयोग से संबद्ध भारत-रूस अंतर्सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) की 10वीं बैठक की सहअध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी के साथ करने के लिए भारत का दौरा किया।

- पूर्व संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए. राजा ने अपने रूसी समकक्ष श्री आइगोर सेगेलोव के निमंत्रण पर 10-15 अक्तूबर, 2010 तक रूस का दौरा किया।

- रूस के उप प्रधान मंत्री श्री सर्गेई इवानोव ने आईआरआईजीसी-टेक के 16वें सत्र में भाग लेने के लिए 18 नंवबर को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के साथ इसकी सहअध्यक्षता की। श्री इवानोव ने प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की और वे रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी, प्रधान मंत्री जी के प्रधान सचिव श्री टी. के. ए. नायर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन से भी मिले। आईआरआईजीसी-टेक बैठक से पूर्व अंतर्सरकारी आयोग के तहत विभिन्न कार्यकारी दलों की बैठकें हुईं जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। इनमें शामिल थे, पर्यटन और संस्कृति से संबद्ध कार्यकारी दल (मास्को, 14 मई, 2010); व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध कार्यकारी दल (नई दिल्ली, 5-6 अक्तूबर, 2010); निज्नी नोवगोरोद में बैंकिंग औ वित्तीय मामलों से संबद्ध उपसमूह (7-9 जून, 2010); विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबद्ध कार्यकारी दल (नई दिल्ली); और पारस्परिक वित्तीय दायित्वों से संबद्ध कार्यबल (नई दिल्ली)।

- विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए 29 नवंबर को भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री जी से भी मुलाकात की। यात्रा के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों द्वारा 2011-2012 के लिए विदेश कार्यालय परामर्शों से संबद्ध प्रोतोकोल पर भी हस्ताक्षर किए गए।

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 12-16 दिसंबर, 2010 तक रूस का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की नई गवेषण एवं लाइसेंसिंग नीति पर वार्ता के 9वें दौर में भारत में उपलब्ध अवसरों पर निवेशकों की बैठक का उद्घाटन भी किया।

- विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने रूस के प्रथम उप विदेश मंत्री श्री आंद्रेई देशीनोव के साथ विदेश कार्यालय परामर्शों में भाग लेने के लिए 2-3 अगस्त, 2010 तक मास्को का दौरा किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने उप प्रधान मंत्री श्री सर्गेई सोब्यानिन से भी मुलाकात की और उप विदेश मंत्री श्री अलेक्सी बोरोदाकिन के साथ बातचीत की। इसके अतिरिक्त दोनों विदेश कार्यालयों के बीच इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर भी परामर्श किए गए: (1) मध्य-पूर्व एवं खाड़ी (मास्को, जनवरी 2010); (2) कोंसली मुद्दे (फरवरी और अक्तूबर 2010); (3) राजनयिक संपत्तियां (नई दिल्ली, जून 2010); (4) ईरान और अफगानिस्तान (मास्को, अगस्त 2010); (5) मध्य एशिया (मास्को, अगस्त 2010); और (6) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला (मास्को, नवंबर 2010)।
- प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव श्री टी. के. ए. नायर के नेतृत्व में भारतीय आईटी एवं भेषज व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने 31 जनवरी-1 फरवरी 2011 तक रूस का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गोलमेज बैठकों के साथ-साथ एक व्यावसायिक बैठक का भी आयोजन किया गया। श्री नायर ने आईआरआईजीसी के सहअध्यक्ष और उप प्रधान मंत्री सर्गेई बी. इवानोव सहित अन्य वरिष्ठ रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात की।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आर्थिक सहयोग का संवर्धन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता का विषय बना रहा। तदनुरूप व्यापार विकास लक्ष्य प्राप्त किया गया और अनेक बड़े निवेश सौदों/भागीदारियों की घोषणा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिष्ठित सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एसपीआईईएफ) में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया। एसपीआईईएफ की रूपरेखा के अंतर्गत ही इस अवसर पर प्रथम भारत-रूस व्यावसायिक संवाद का आयोजन किया गया। सीआईआई तथा एसपीआईईएफ प्रतिष्ठान ने दोनों देशों के व्यवसायों के बीच कार्यकलापों एवं आदान-प्रदानों को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया। आईआरआईजीसी-टेक के 16वें सत्र का आयोजन 18 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में किया गया जिसमें व्यावसायिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के अगले उपायों की पहचान की गई। 20 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित व्यापार और निवेश पर भारत-रूस मंच के चौथे सत्र में दोनों पक्षों से भारी संख्या में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

इस वर्ष के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि जारी रही। 2009 में 7.46 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ और वर्ष 2010 के पहले दस महीनों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 19.69 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष आधार) की वृद्धि दर्ज की गई।

आर्मेनिया

भारत और आर्मेनिया के बीच पारम्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंध रहे हैं। पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारस्परिक समझबूझ और विचारों में समानता रही है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री श्री एडवर्ड नलबंदियान ने 9-13 नवंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इन्हें विस्तारित करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। आर्मेनिया के विदेश मंत्री भारत के उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी से मिले और उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री एम. के. नारायणन से कोलकाता में मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर एक कार्यकारी कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत आर्मेनिया द्वारा अवसंरचना विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में लगातार योगदान देता रहा है। विभिन्न स्तरों पर इस तथ्य को स्वीकार किया गया है और इसकी सराहना की गई है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सितंबर 2010 में लगभग 2,15,000 अमरीकी डालर की भारतीय सहायता से एक ग्रामीण विकास परियोजना को पूरा किया गया। येरेवान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत-आर्मेनिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना में भी प्रगति दर्ज की गई। आर्मेनिया के कुशल प्रशिक्षकों के दो बैचों को सेंटर फॉर डवेलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक) में प्रशिक्षण के लिए भारत भेजा गया। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटेक) के अंतर्गत आर्मेनिया के तीस राष्ट्रिकों ने भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। अप्रैल 2010 में नई दिल्ली और येरेवान के बीच सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित होने के साथ ही व्यापार और पर्यटन को और बढ़ावा दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वर्ष 2011 की पहली तिमाही में निर्धारित महत्वपूर्ण यात्राओं में आर्मेनियाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव की नई दिल्ली यात्रा (1-5 मार्च, 2011) शामिल हैं।

अजरबैजान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान अजरबैजान के साथ भारत के संबंध और भी सुदृढ़ एवं मजबूत हुए।

प्रस्तावित असैनिक, वाणिज्यिक एवं आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार और प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत को अंतिम रूप दिया गया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक करार को भी अंतिम रूप दिया गया है। आशा है कि निकट भविष्य में ही इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

जनवरी-सितंबर 2010 के दौरान अजरबैजान के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो अभी 327.32 मिलियन अमरीकी डालर का है। वर्ष 2009 में इसी अवधि के दौरान 302.37 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ था। यह वृद्धि मुख्य तौर पर भारतीय तेल शोधकों द्वारा अजेरी से कच्चा तेल प्राप्त किए जाने, भारत से बाक्साइट अयस्क का निर्यात आरंभ किए जाने और अजरबैजान द्वारा इलेक्ट्रानिक कार्ड, इंजीनियरिग सामान, कार एवं मोबाइल टेलीफोन इत्यादि जैसी नई मदों का आयात किए जाने के कारण हुई। भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट और भारत के तीन टूर ऑपरेटरों ने पहली बार अप्रैल 2010 में बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में भाग लिया। पंजाब के कृषि मंत्री के नेतृत्व में एक कृषि प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर 2010 में बाकू का दौरा किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित 'हिन्दी पीठ' का उद्घाटन अक्तूबर 2010 में बाकू में अजरबैजान युनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेज में किया गया। 11 जनवरी, 2011 को अजरबैजान युनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेज में विश्व हिन्दी दिवस समारो का आयोजन किया गया।

बेलारूस

दोनों पक्षों की ओर से हुई अनेक द्विपक्षीय यात्राओं के आधार पर बेलारूस के साथ भारत के पारम्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध और सुदृढ़ हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री के. जी. बालकृष्णन ने अधिकारियों के न्यायिक संरक्षण की समस्या से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मंच में भाग लेने के लिए 10 अप्रैल, 2010 को मिन्स्क का दौरा किया। बेलारूस के प्रथम उप प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमिर सेमांस्को ने नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2010 में नई दिल्ली का दौरा किया। उनके साथ बेलारूस के उद्योग मंत्री श्री एलेकजेंडर रेदेविच और उप विदेश मंत्री श्री सर्गेई अलेनिक भी आए थे। इस यात्रा के दौरान श्री सेमांस्को ने उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर से मुलाकात की। इन यात्राओं के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों पर भी संपर्क स्थापित किए गए। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने जुलाई 2010 में जिनेवा में आयोजित संसद अध्यक्षों के तीसरे सम्मेलन के दौरान बेलारूस गणराज्य की परिषद के अध्यक्ष श्री अनातोली रूबीनोव के साथ मुलाकात की। बेलारूस के पहले उप प्रधान मंत्री श्री ब्लादिमिर सेमांस्को ने मई 2010 में आयोजित जी-15 शिखर बैठक के पार्श्व में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा से मुलाकात की।

इस वर्ष आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों में निरन्तर प्रगति होती रही। जनवरी-सितंबर 2010 के दौरान लगभग 378 मिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत के एक्जिम बैंक और ग्रोडनोनेर्गो के बीच अप्रैल 2010 में ग्रोडनो-2 विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार की 56 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। बेलारूस की कंपनी बेलाज ने बेलारूस के डम्प ट्रकों की सर्विसिंग हेतु एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना करने के लिए भारतीय कंपनी अल्ट्रामेक्स के साथ अक्तूबर 2010 में एक करार संपन्न किया। आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध भारत-बेलारूस अंतर्सरकारी आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन मिंस्क में जनवरी 2011 में होने की संभावना है। कृषि क्षेत्र में बेलारूस के साथ जून 2008 में हस्ताक्षरित कार्य योजना को वर्ष, 2010-2012 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

रक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों में अबाध प्रगति हुई। सैन्य तकनीकी सहयोग से संबद्ध भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक का आयोजन 8-10 दिसंबर, 2010 तक मिंस्क में किया गया।

मिंस्क में भारत द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी पार्क में स्थापित किए जा रहे डिजिटल शिक्षण केंद्र का स्थापन इसी वर्ष किया जाना है। इसका नामकरण पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नाम पर किया जाएगा।

बेलारूस के संदर्भ में आईटेक कार्यक्रम काफी सफल रहा है और यहां इसकी काफी सराहना भी की जाती रही है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2010-2011 के लिए आईटेक स्लाट्स की संख्या को 15 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान अच्छा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग किया गया है। मिंस्क स्थित भारतीय दूतावास ने प्रतिष्ठित बेलारूसी स्टेट अकादमी ऑफ म्यूजिक में भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए अप्रैल 2010 में 'रंगोली' नामक भारतीय शास्त्रीय एवं आधुनिक नृत्य के एक कंसर्ट का आयोजन किया गया। मई 2010 में गोमेल में भारतीय फिल्म सप्ताह का आयोजन किया गया। आईसीसीआर से प्राप्त प्रदर्शनी 'कल्पना-मास्टरपीसेज ऑफ फिगरेटिव इंडियन कंटेम्परेरी पेंटिंग्स' का आयोजन सितंबर 2010 में गोमेल के प्रतिष्ठित कला दीर्घा जी वासेनको कला दीर्घा में किया गया। रोरिक पैक्ट की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन 'भारत और बेलारूस की महान सांस्कृतिक विरासत' का आयोजन 17 सितंबर, 2010 को रोरिक्स अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बेलारूस स्टेट विश्वविद्यालय, बेलारूस इंडिया फ्रेंडशिप सोसायटी और बेलारूस की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सहयोग से किया गया। विदेश मंत्रालय के लोक राजनय प्रभाग की सहायता से बेलारूस की एक प्रमुख साहित्यिक पत्रिका 'नेमान' ने अक्तूबर 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की वर्षगांठ पर भारत पर एक विशेष संस्करण निकाला।

सैन्य तकनीकी सहयोग से संबद्ध भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक का आयोजन मिंस्क में 8-10 दिसंबर, 2010 को किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग में अपर सचिव श्री वी. सोमसुन्दरम ने किया।

जार्जिया

इस वर्ष जार्जिया के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। जार्जिया ने वर्ष 2010 के आरंभ में नई दिल्ली में अपना आवासीय मिशन खोला। आर्मीनिया में भारत के राजदूत, जिन्हें जार्जिया के लिए भी सहप्रत्यायित किया गया है, ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आयामों से जुड़े मुद्दों पर पारस्परिक समझबूझ को बढ़ावा देने के लिए बातचीत जारी रखी। 30 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श किए गए जिससे द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लेने का अवसर मिला। अंतर्सरकारी आयोग की स्थापना करने से संबद्ध करार और संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर दो करार भी संपन्न किए गए। क्षमता निर्माण में जार्जिया की सहायता करने की हमारी वचनबद्धता की भाग के रूप में आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत जार्जिया के अनेक राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया।

शंघाई से टिबिलसी जाते समय जार्जिया के प्रधान मंत्री श्री निका गिलौरी निजी दौरे पर मुम्बई आए थे, जहां उन्होंने 1 नवंबर, 2010 को फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा आयोजित 'इन्वेस्ट जार्जिया' व्यावसायिक मंच को संबोधित किया। द्विपक्षीय व्यापार में सतत वृद्धि दर्ज की गई। टिबिलसी और बटूमी में भारतीय उपभोक्ता सामानों की दो प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

कजाकिस्तान

भारत-कजाक संबंध परिपक्व हुए हैं और इनमें सर्वोच्च स्तरों पर विविधता आई है। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 11 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में राष्ट्रपति श्री नूर सुल्तान नजरवायेव से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संवर्धन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय संबधों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा सीआईआई के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 11-13 मई, 2010 तक अस्ताना का दौरा किया। राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरवायेव और प्रधान मंत्री श्री करीम मसीमोव और विदेश मंत्री श्री कनात सौदाबायेव के साथ विशेषकर आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान भारत-कजाकिस्तान व्यावसायिक मंच को भी संबोधित किया।

सचिव (पूर्व) सुश्री लता रेड्डी ने 13-14 मई, 2010 तक अल्माता में आयोजित मध्य एशियाई मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन के दौरान मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के कार्यकलापों का विस्तार किए जाने पर चर्चा की।

चर्म निर्यात संवर्धन परिषद और एसोचैम के दो व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों ने क्रमशः 25-29 मई और 1-4 सितंबर, 2010 तक कजाकिस्तान का दौरा किया। पंजाब के कृषि मंत्री के नेतृत्व में कृषि निर्यात से जुड़ी कम्पनियों के प्रतिनिधिमंडल ने 9-12 अक्तूबर, 2010 तक कजाकिस्तान का दौरा किया।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध भारत-कजाकिस्तान अंतर्सरकारी आयोग की 8वीं बैठक का आयोजन 6 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में किया गया। इस अंतर्सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा और कजाकिस्तान के ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री श्री सनत मिनबायेव द्वारा की गई। इसके दौरान दोनों पक्षों ने मार्च 2009 में अस्ताना में आयोजित अंतर्सरकारी आयोग की 7वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक के अंत में दोनों पक्षों द्वारा एक प्रोतोकोल पर भी हस्ताक्षर किए गए। व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध प्रथम संयुक्त दल की बैठक 13-14 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में हुई।

किर्गीस्तान गणराज्य

संशोधित संविधान के अंतर्गत किर्गीस्तान में पहले संसदीय चुनावों का आयोजन 10 अक्तूबर, 2010 को हुआ। मंत्रालय ने चुनावों के सफल आयोजन पर किर्गीस्तान की जनता को मुबारकबाददेते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए भारत ने चुनावों के सुचारु संचालन में सहायता करने के लिए किर्गीस्तान के निर्वाचन आयोग को भेंट स्वरूप कंप्यूटर प्रदान किए। दिसंबर माह के अंत में एक गठबंधन सरकार गठित की गई जिसमें किर्गीस्तान के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के श्री एतमबायेव अल्माजबेक को प्रधान मंत्री नियुक्त किया किया गया।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग पर भारत-किर्गीस्तान अंतर्सरकारी आयोग के 5वें सत्र का आयोजन 4 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में किया गया। किर्गीस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री कापर कुर्मानालियेव और भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। दोनों देशों के बीच खनिज गवेषण एवं विकास, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, शिक्षा, खेल और संस्कृति क्षेत्र में पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने पर एक प्रोतोकोल भी हस्ताक्षरित किया गया।

जून 2010 में दक्षिणी किर्गीस्तान में जातीय हिंसा की घटनाओं के आलोक में भारत ने किर्गीस्तान को लगभग 1 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 60 टन मानवीय सहायता प्रदान की जिसमें खाद्य सामग्रियां, दवाएं और तम्बू शामिल थे। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा विशकेक के भारत-किर्गीस्तान सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में दिया जा रहा अपेक्षित प्रशिक्षण अक्तूबर 2010 में पूरा हो गया। फिलहाल यह केंद्र लघु

आईटी पाठ्यक्रम चला रहा है और इसने अब किर्गीस्तान में 600 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।

किर्गीस्तान में आलू प्रसंस्करण संयंत्र कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है। भारत से सभी उपकरणों को किर्गीस्तान में संयंत्र स्थल तक पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। भारत सरकार तू आसू पास में पर्वतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने के लिए भी किर्गीस्तान सरकारी की सहायता कर रही है। नई दिल्ली के शरीर विज्ञान एवं संबद्ध सेवा रक्षा संस्थान (डीआईपीएएस) द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना का सिविल कार्य और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद और संस्थापना संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। निकट भविष्य में ही इस केंद्र का प्रचालन आरंभ हो जाने की आशा है।

आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेषकर मानव संसाधन विकास क्षेत्र में सहयोग किर्गीस्तान के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी की विशेषता है। आईटेक के अंतर्गत किर्गीस्तान को प्रतिवर्ष नागरिक प्रशिक्षण के 80 स्लाट्स उपलब्ध कराए जाते हैं।

ताजिकिस्तान

विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए 24-25 नवंबर, 2010 तक दुशान्बे का दौरा किया। सम्मेलन में दिए गए अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा, स्थायित्व एवं विकास लाकर एससीओ मंच पर और भी रचनात्मक एवं सार्थक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद तथा स्वापकों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने की भारत की इच्छा भी व्यक्त की।

थल सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह ने ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल शेराली खाइरूलोयेव के साथ मुलाकात करने के लिए 10-13 नवंबर, 2010 तक ताजिकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति श्री इमोमाली रहमान से भी मुलाकात की। जनरल सिंह ने कुलोव का भी दौरा किया और वहां उन्होंने गवर्नर से बातचीत की।

जल संसाधन मंत्रालय में सचिव श्री यू. एन. पंजियार ने 8-10 जून, 2010 तक दुशान्बे में जल पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

भारतीय विश्व कार्य परिषद के महानिदेशक श्री सुधीर देवड़े के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-ताजिकिस्तान संबंधों पर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन आईसीडब्ल्यूए और ताजिकिस्तान विज्ञान अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से दुशान्बे में 29 जून, 2010 को किया गया था।

भारत ने नवंबर 2010 में ताजिकिस्तान में चलाए जा रहे पोलियो टीकाकरण अभियान के छठे और अन्तिम दौर के लिए पोलियो बैक्सीन की दो मिलियन खुराकों का योगदान दिया। भारत सरकार ने खतलोन प्रान्त में मई 2010 में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए दो लाख अमरीकी डालर की मानवीय सहायता भी दी।

भारत और ताजिकिस्तान ने 7 अक्तूबर, 2010 को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर एक करार संपन्न किया।

वर्ष 2010 में ताजिकिस्तान के 32 छात्रों को भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आईसीसीआर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। वर्ष 1995-96 तक कुल 246 ताजिक छात्रों को आईसीसीआर की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। आईटेक के अंतर्गत वर्ष 2010-2011 के लिए ताजिकिस्तान को 100 स्लाट्स आमंत्रित किए गए हैं।

3 दिसंबर को दूतावास में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का आयोजन किया गया जिसमें आईसीसीआर छात्रवृत्ति के तहत भारत में अध्ययन करने वाले 60 ताजिक छात्रों और पेशेवरों ने भाग लिया। उसी दिन भारत के राजदूत ने ताजिकिस्तान के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय द्वारा ताजिक नेशनल लाइब्रेरी के लिए भेजी गई 200 पुस्तकें भेंट की। इस कार्यक्रम में ताजिकिस्तान के उप संस्कृति मंत्री ने भी भाग लिया जिन्होंने इस उदार योगदान के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।

तुर्कमेनिस्तान

तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति श्री गुरबांगुली बेर्डीमुहामेदोब ने 24-26 मई, 2010 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील से मुलाकात की और प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत में भाग लिया। उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा तथा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने यात्रा पर आए तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए: (1) राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच करार; (2) भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम; (3) भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार; (4) भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार; (5) भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच 2010-2012 अवधि के लिए विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, कला, पर्यटन, खेल तथा मीडिया क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रम; और (6) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) तथा तुर्कमेनिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग संघ के बीच समझौता ज्ञापन।

तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना के सफल कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण

घटनाक्रम के रूप में राष्ट्रपति गुरबांगुली बेर्डीमुहामेदोब की मेजबानी में अश्गाबाद में 11 दिसंबर, 2010 को टीएपीआई शिखर बैठक का आयोजन किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने भारतीय पक्ष से इस शिखर बैठक में भाग लिया। सभी चारों पक्षों ने इस गैस पाइपलाइन परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। टीएपीआई शिखर बैठक के दौरान अंतर्सरकारी करार तथा गैस पाइपलाइन रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस पाइपलाइन के पूरा होने के उपरान्त योजना के अनुसार भारत को तीस वर्ष तक टीएपीआई गैस पाइपलाइन से प्रति दिन 38 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस मिलेगी। इससे पूर्व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 20 सितंबर, 2010 को अश्गाबाद में टीएपीआई संचालन समिति की बैठक में भाग लिया।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने अंतर्सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करने के लिए 7-9 फरवरी, 2010 तक अश्गाबाद का दोरा किया। यात्रा के दौरान भारत द्वारा तुर्कमेनिस्तान में एक आईटी कार्यक्रम की स्थापना करने पर समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए सीडैक इंडिया द्वारा छह महीने की अवधि के लिए तुर्कमेनिस्तान के 10 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैत्रीपूर्ण सद्भावना प्रदर्शन के रूप में भारत अश्गाबाद में एक आईटी केंद्र का निर्माण भी करेगा।

उक्रेन

उक्रेन के उप विदेश मंत्री श्री विक्टर माइको ने सुश्री विजय लता रेड्डी, सचिव (पूर्व) के साथ विदेश कार्यालय परामर्शों के आठवें दौर में भाग लने के लिए 22 सितंबर, 2010 को भारत का दौरा किया। इन परामर्शों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के संवर्धन तथा पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

वर्ष 2009-2010 के दौरान लगभग 1.882 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत का निर्यात 289.03 मिलियन अमरीकी डालर का और आयात 1593.52 मिलियन अमरीकी डालर का रहा। पंजाब के कृषि मंत्री श्री सुच्चा सिंह लांघा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय कृषि प्रतिनिधिमंडल ने फलों, सब्जियों, संसाधिक खाद्य, अनुबंध कृषि इत्यादि की संभावना का पता लगाने के लिए 2016-10 अक्तूबर, 2010 तक के लिए कीव का दौरा किया। उक्रेन के भारतीय प्रतिनिधमंडल ने उक्रेन के उप कृषि मंत्री के साथ व्यापक चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने उक्रेन के कृषि विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय जीवन एवं पर्यावरण विज्ञान विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। भारतीय पर्यटन फ्रैंकफर्ट कार्यालय स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड तथा भारतीय काफी बोर्ड ने उक्रेन में आयोजित विश्व खाद्य महोत्सव में तथा हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद ने कीव में आयोजित एम्बियंस उक्रेन प्रदर्शनी में भाग लिया।

उक्रेन के सैन्य बलों के वायु सेना कमाण्डर ले. जनरल सेर्हली ओनिस्चेन्को के नेतृत्व में एक सैनिक प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 अक्तूबर, 2010 तक भारत का दौरा किया और भारतीय रक्षा अधिकारियों के साथ सैन्य सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने नौसेना प्रमुख तथा वायुसेना प्रमुख के साथ भी बैठकें की, जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख भी हैं।

भारतीय दूतावास कीव ने उक्रेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा सीख रहे छात्रों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करके विश्व हिन्द दिवस (10 जनवरी) मनाया जिसमें विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं हिन्दी पुस्तकें वितरित की गईं।

उज्बेकिस्तान

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने एशियाई विकास बैंक की 43वीं बैठक में भाग लेने के लिए 1-4 मई, 2010 तक ताशकंद का दौरा किया। अतिरिक्त समय में, उन्होंने उज्बेकिस्तान के प्रधान मंत्री शवकत मिर्जियायेव तथा उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री श्री रुस्तम अजीमोव के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने एससीओ राज्य परिषद प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के लिए 10-11 जून, 2010 तक ताशकंद का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री इस्लाम करीमोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

उज्बेकिस्तान के लघु उद्योगों के अध्यक्ष श्री इल्खाम खैदारोव ने सितंबर 2010 के पहले हफ्ते में भारत का दौरा किया और उन्होंने वस्त्र क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग से जुड़े मुद्दे पर वस्त्र मंत्री दयानिधि मारन के साथ चर्चा की।

इस वर्ष के दौरान उज्बेकिस्तान के 81 राष्ट्रिकों ने भारत सरकार के आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लघु आवधिक पाठ्यक्रमों में भाग लिया। अनेक उज्बेकी छात्रों ने आईसीसीआर के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भी भारत के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकन कराया है।

भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय सहयोग

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने भारत, रूस, चीन, रूस के विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक में भाग लेने 14-15 नवंबर, 2010 तक वुहान, चीन का दौरा किया। तीनों विदेश मंत्रियों ने आपदा प्रबंधन, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और संयुक्त राष्ट्र सुधार, वैश्विक वित्तीय रूपरेखा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला, उदीयमान बाजारों के बीच सहयोग, जलवायु परिवर्तन, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, संघाई सहयोग संगठन तथा अफगानिस्तान, ईरान और कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति सहित विभिन्न वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किए। चर्चा के परिणाम के रूप में बैठक के उपरान्त एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। अतिरिक्त समय में विदेश मंत्री ने अपने रूसी और चीनी समकक्षों श्री सर्गेई लावरोव और श्री यांग जियेची के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। विदेश मंत्रियों

की बैठक के पूर्व आपदा प्रबंधन से संबद्ध विशेषज्ञ समूह (नई दिल्ली, नवंबर 2010) की बैठक और त्रिपक्षीय शैक्षिक सेमिनार (मास्को, सितंबर 2010) का आयोजन किया गया था।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के साथ अपने कार्यकलापों को गहन बनाया। विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने 25 नवंबर, 2010 को सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने एससीओ राज्याध्यक्ष परिषद की बैठक में प्रधान मंत्री जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10-11 जून, 2010 तक ताशकंद का दौरा किया।

एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी रूपरेखा के निदेशक श्री जेनिस बेक एम. जुमनाबेकोव ने 7-9 सितंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन तथा सचिव (पूर्व) सुश्री विजय लता रेड्डी से मुलाकात करके अफगानिस्तान तथा इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के मुद्दों पर सूचना का आदान-प्रदान करने और एसीओ द्वारा लिए गए प्रासंगिक निर्णयों के आधार पर भावी सहयोग कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

भारत के महा न्यायाधिकर्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने 22 अक्तूबर, 2010 को जिआमेन, चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के महा अभियोजकों के सम्मेलन में भाग लिया।

■■

खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका 5

बहरीन

भारत और बहरीन के बीच प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबध है, जिसकी जड़े सिंधु घाटी और दिलमन की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हैं। बहरीन की कुल 1.04 मिलियन की आबादी में भारतीय राष्ट्रिकों की जनसंख्या लगभग 4,00,000 है, जो वहां प्रवासियों का सबसे बड़ा समुदाय है और पहली प्रमुखता पाने वाला समुदाय समझा जाता है।

वर्ष के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस) द्वारा आयोजित बहरीन वैश्विक मंच (भू-आर्थिक रणनीति शिखर बैठक) में हिस्सा लेने के लिए 14-15 मई, 2010 तक बहरीन की यात्रा की। वह इस अवसर पर एक प्रमुख प्रवक्ता थे।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने आर्थिक बोर्ड द्वारा आयोजित 'बहरीन शिक्षा परियोजना 2010' सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 8-10 अक्तूबर, 2010 तक बहरीन की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने श्रम मंत्री डॉ. मजीद अल अलावी से मुलाकात की और शिक्षा तथा व्यासायिक प्रशिक्षण में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

ईरान

विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने अपने समकक्षी ईरान इस्लामी गणराज्य के एशिया और ओसियानिया के उप विदेश मंत्री डॉ. मोहम्मद अली फथोल्लाही के निमंत्रण पर विदेश कार्यालय परामर्श/सामरिक वार्ता के सातवें दौर के लिए 2-3 फरवरी, 2010 तक तेहरान की यात्रा की। तेहरान में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री श्री मनोचेहर मोत्ताकी, अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री डॉ. सैयद शमशुद्दीन हुसैनी और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. सईद जलीली से मुलाकात की। विदेश सचिव ने अपने ईरानी वार्ताकारों से द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा की। यह सहमति हुई कि भारत-ईरान संयुक्त आयोग की अगली बैठक शीघ्र ही नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। उन्होंने अफगानिस्तान, सीमापार आतंकवाद के संकट समेत क्षेत्रीय स्थितियों तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व के अन्य मसलों पर ईरानी पक्ष के साथ विचारों का आदान-प्रदान भी किया।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने मई 2010 में तेहरान में आयोजित 14वें जी-15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। 17 मई को दिए अपने भाषण में विदेश मंत्री ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन दो दशक पहले जी-15 की स्थापना से इसके द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि जी-15 ने विकाससशील देशों के हितों से जुड़े मुद्दों को वैश्विक एजेंड़े में शामिल कराने और इसकी चिंताओं को हल करने संबंधी परिणामों की मांग करने के लिए सामूहिक प्रयास किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि जी-15 को न केवल दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए बल्कि व्यापार, धन और वित्त, समतापूर्ण विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि के क्षेत्रों में वैश्विक वार्ता में नीति-निर्धारण के लिए भी एक प्रभावी मंच बनाया जाना चाहिए। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति डॉ. महमूद अहमदीनेजाद तथा मजलिस के अध्यक्ष डॉ. अली लारीजानी से मुलाकात की और विदेश मंत्री श्री मनोचेहर मोत्ताकी से मुलाकात की। ईरानी प्रतिनिधियों से अपनी वार्ता के दौरान विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय मुद्दों तथा परस्पर हितों के क्षेत्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का अदान-प्रदान किया।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग के 16वें सत्र का आयोजन 8-9 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में किया गया। सत्र की ईरानी पक्ष की ओर से ईरानी इस्लामिक गणराज्य के आर्थिक मामले और वित्त मंत्री श्री सैयद शामशेद्दीन होसीनी द्वारा और भारतीय पक्ष की ओर से विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा द्वारा सहअध्यक्षता की गई। संयुक्त आयोग की बैठक ने द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा का अवसर प्रदान किया। यह सहमति हुई कि संयुक्त आयोग के अगले सत्र का आयोजन तेहरान में किया जाएगा। संयुक्त आयोग की बैठक में निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गएः

1 हवाई सेवा करार;

2 साजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांरण संबधी करार;

3 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन;

4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एसएसआईसी) और ईरानी लघु उद्योग और औद्योगिक पार्क संगठन (आईएसआईपीओ) के बीच लघु उद्योग और औद्योगिक पार्क संगठन (आईएसआईपीओ) के बीच लघु उद्योग पर सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन;

5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग का कार्यक्रम; तथा

6 केंद्रीय भारतीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई) और जोरगन कृषि विज्ञान एवं प्राकृतिक

संसाधन विश्वविद्यालय (जीयूएएसएनआर) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

अपनी यात्रा के दौरान डॉ. सैयद शमसेद्दीन होसीनी ने प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन से भी मुलाकात की तथा 'ईरान में निवेश के अवसर' पर फिक्की द्वारा आयोजित व्यवसाय संगोष्ठी का उद्घघाटन किया। डॉ. होसीनी के साथ आए, कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ने एसोचेम और सीआईआई के साथ भी बैठकें की।

ईरान के एशिया और ओसियानिया उप विदेश मंत्री डॉ. मोहम्मद अली फथोल्लाही ने विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव के बुलावे पर विदेश कार्यालय परामर्श के आठवें दौर के लिए 5-8 अगस्त, 2010 तक नई दिल्ली की यात्रा की। दोनों पक्षों के बीच परस्पर हितों के विविध मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें अन्य के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय स्थिति में अफगानिस्तान, सीमापार आतंकवाद के संकट से जुड़े मुद्दे इत्यादि शामिल थे। अपनी यात्रा के दौरान डॉ. फथोल्लाही ने विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा से मुलाकात की।

अन्य मंत्रिस्तरीय दौरों में आवास और शहरी निर्धनता उपशमन तथा पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा (आवास और शहरी विकास के लिए एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की पांचवी ब्यूरो बैठक के लिए), जिसका आयोजन तेहरान में 23 फरवरी, 2010 को किया गया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. डी. पुरनदेश्वरी (तेहरान में 8–9 नवंबर, 2010 को आयोजित नवीं एशिया सहयोग वार्ता मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए) द्वारा की गई यात्राएं थीं।

भारत-ईरान वाणिज्यिक संबंध में भारत ईरानी कच्चे तेल के आयात का बर्चस्व है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के दौरान 63,443.00 करोड़ रुपए (13.394 बिलियन अमरीकी डालर) थी, जबकि अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 में यह 67,387.01 करोड़ रुपए (14.91 बिलियन अमरीकी डालर) थी। अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के दौरान भारत का ईरान को निर्यात 8,807.43 करोड़ रुपए (1,853.17 मिलियन अमरीकी डालर) का रहा। ईरान से भारत का आयात अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के दौरान 54635.56 करोड़ रुपए (11,540.85 मिलियन अमरीकी डालर) था। प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान भी हुआ और व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में एक-दूसरे के देश में भागीदारी भी की गई।

इराक

सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यताओं वाले देशों के रूप में भारत और इराक दोनों के बीच सदैव से प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे हैं। भारत ने एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, बहुलतावादी, संघीय और संयुक्त इराक का समर्थन किया है और आर्थिक पुनर्निर्माण की अनेक चुनौतियों से उबरने में इराक सरकार और लोगों की प्रत्यक्ष रूप से तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में दोनों तरह सहायता करने के लिए संकल्पबद्ध रहा है।

वर्ष 2010 के दौरान इराक ने अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को समन्वित किया। 325 सदस्यों वाले प्रतिनिधि परिषद के ऐतिहासिक चुनाव मार्च 2010 में सफलतापूर्व कराए गए। आठ माह बाद नई राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के लिए सभी दलों के बीच समझौता हुआ। जलाल तालाबानी फिर से राष्ट्रपति चुने गए और प्रधान मंत्री पद के दावेदार नूरी कमेल अल-मालिकी दूसरी लगातार अवधि के लिए अपने पद पर बने रहे। माननीय राष्ट्रपति जलाल तालाबानी और प्रधान मंत्री नूरी कमेल अल-मालिकी को अपना-अपना पद ग्रहण करने पर बधाई दी।

भारत ने मई 2010 में ईरान यात्रा के खिलाफ जारी परामर्शी को वापस करके रोजगार और यात्राओं के लिए भारतीय राष्ट्रिकों की ईरान यात्रा को सुगम बनाया।

भारत क्षमता निर्माण में इराक की मदद के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटेक) कार्यक्रम के तहत, भारत सैकड़ों इराकियों को तकनीकी शिक्षा के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है। इराक को दिए गए आईटक स्लाट को 2010-2011 में बढ़ाकर 120 किया गया है। इसी तरह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, छात्रवृत्ति स्कीम (सीईपीएसएस) और सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति स्कीम (जीसीएसएस) के अंतर्गत भारत ने इराकियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर भारत में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए 55 प्रति वर्ष कर दिया है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसी) ने इराक में तेल शोधन संयंत्र चलाने के लिए डाउनस्ट्रीम तेल सेक्टर से संबंधित विविध विषयों पर भारत में 200 से अधिक इराकी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

बगदाद में संयुक्त आयोग बैठक के आयोजन से संबंधित इराक से एक तैयारी दल की फरवरी 2011 में भारत यात्रा संभावित है। वित्तीय वर्ष 2009-2010 में भारत और इराक के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7.50 बिलियन अमरीकी डालर था।

भारत कम खर्च और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा इलाज, उच्च शिक्षा और पर्यटन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। जनवरी से दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान बगदाद स्थित भारतीय दूतावास ने इराकी राष्ट्रिकों को लगभग 27,848 वीजा जारी किए।

कुवैत

भारत और कुवैत के बीच प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की परंपरा रही है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सामान्य अवधारणा साझा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करते रहे हैं।

कुवैत के तेल मंत्री और सूचना मंत्री शेख अहमद अल-अब्दुल्ला अल-सबा ने 25-28 सितंबर, 2010 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने ओएनजीसी और आईओसी के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने जामिया

मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली स्थित भारत अरब सांस्कृतिक केंद्र में 'सबा सांस्कृतिक पुस्तकालय' का भी उद्घाटन किया, जो भारत में कुवैत की पहली और सबसे बड़ी सांस्कृतिक परियोजना है।

श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक जनवरी 2010 में कुवैत में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य रोजगार और जनशक्ति विकास से संबंधित मुद्दों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाना था।

रक्षा सेवा स्टॉफ कालेज, वेलिंगटन, भारत के कमाण्डेंट लेफ्टिनेंट एचपीएस क्लेयर की अगुवाई में भारतीय सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23-25 नवंबर, 2010 तक कुवैत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत स्टॉफ कालेज के कमांडेंट के साथ विचार-विमर्श किया और लैंड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस तथा एयर फोर्स के कमांडरों से मुलाकात की।

गोवा और कर्नाटक की राज्य सरकारों की ओर से वर्ष के दौरान कुवैत के कई मंत्रिस्तरीय दौरे किए गए।

कुवैत के प्रतिष्ठित अरबी और अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों के पत्रकारों के दो दल मई और नवंबर 2010 में केरल और गोवा आए। छः भारतीय पत्रकारों के एक दल ने 18-25 मई, 2010 को कुवैत की यात्रा की।

भारतीय तेल निगम ने कुवैत पेट्रोलियम निगम के साथ वर्ष 2010-2011 के दौरान 9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात के लिए कच्चा तेल आपूर्ति संविदा पर हस्ताक्षर किए।

भारत के भारती एयरटेल लिमिटेड ने लगभग 9 बिलियन अमरीकी डालर में जून 2010 में कुवैत की जैन टेलीकॉम कंपनी के अफ्रीका (दक्षिण सहारा) क्षेत्र की खरीद की। टेलिकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने अगस्त 2010 में कुवैत के लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क के रखरखाव के लिए कलपुर्जों और वैद्युत केबलों की आपूर्ति हेतु कुवैत के संचार मंत्रालय के साथ 10 मिलियन अमरीकी डालर की लागत के एक एक वर्ष की संविदा पर हस्ताक्षर किए।

नवंबर 2010 में कुवैत के खराफी समूह ने अपनी निवेश कंपनी अल केबला अल वत्य के माध्यम से कैल्स रिफायनरी, हल्दिया, भारत में 150मिलियन अमरीकी डालर निवेश करने का निर्णय लिया है।

विशेष कुवैत प्रकोष्ठ

विशेष कुवैत प्रकोष्ठ खाड़ी युद्ध (1990-1991) से वापस आने वालों के मुआवजा दावों पर कार्रवाई करता है। सभी वैध दावों को पहले ही निस्तारित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग (यूएनसीसी) ने अपना दावा भुगतान कार्य बंद कर दिया है और अब भारतीय दावेदारों को देय कोई दावा भुगतान के लिए शेष नहीं है। प्रकोष्ठ अब दावा लेखा की लेखापरीक्षा जैसे कतिपय शेष बचे मुद्दों का निस्तातरण कर रहा है। यह अनुभाग दावेदारों द्वारा आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारियां दे रहा है।

ओमान

भारत और ओमान के बीच विद्यमान प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंधों में मई 2010 में रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटोनी की ओमान यात्रा से और मजबूती आयी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने भारत-ओमान संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएन) के छठे सत्र की सहअध्यक्षता के लिए सितंबर 2010 में ओमान गए प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। परंपरा के अनुसार, इसके पार्श्व में संयुक्त व्यवसाय परिषद (जेसीएम) की बैठक भी आयोजित की गई। जेसीएम में लघु तथा मध्यम उपक्रमों में संयुक्त निवेश और सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही पहचान किए गए क्षेत्रों में आर्थिक और व्यापार सहयोग की समीक्षा भी की गई। अल्पसंख्यक और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सलमान खुर्शीद ने ओमान के राष्ट्रीय दिवस की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नवंबर 2010 में ओमान की यात्रा की। सुल्तान कबूज बिन सईद और ओमान के लोगों को बधाई संप्रेषित की। ओमान में लगभग 5,73,000 भारतीय रह रहे हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अपना योगदान किया है। वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार (तेल और गैस-तेल दोनों में) बढ़कर 4.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि 2008 में यह यह 2 बिलियन अमरीकी डालर था।

ओमान सल्तनत के विदेश मामलों के उत्तरदायी मंत्री श्री यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला अक्तूबर 2010 में एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में भारत आए। विदेश मंत्री और ओमानी विदेश मंत्री की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताएं आयोजित की गयीं, जिनमें परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों को साझा करने के साथ-साथ मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मंत्री और ओमान के वित्तीय मामले और ऊर्जा संसाधन परिषद के उपाध्यक्ष श्री अहमद बिन अब्दुलनबी मक्की की जुलाई 2010 में भारत यात्रा से आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में और मजबूती आई। यात्रा के दौरान संयुक्त जोखिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। जल और विद्युत संबंधी सार्वजनिक प्राधिकरण, ओमान के अध्यक्ष मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-महरूकी की अगुवाई में एक चार सदस्यों वाले ओमानी प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर 2010 में 'दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन (डीआईआरईसी-2010 में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने दोनों देशों के बीच पहचान किए गए क्षेत्रों में विद्यमान सामरिक भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए दिसंबर 2010 में ओमान की यात्रा की। ओमान पक्ष की ओर से रिपोर्ट पर सुल्तान के सलाहकार श्री मोहम्मद बिन अल जुबैर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

कतर

कतर के साथ भारत के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बहुआयामी संपर्कों और लोगों के साथ घनिष्ठ संपर्कों के साथ बढ़ते रहे।

कतर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री डॉ. खालिद अल अतियाह की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी 2010 में द्वितीय भारत-अरब निवेश परियोजना कान्क्लैव में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान कतर के मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुलाकात की और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की, जिनके साथ उन्होंने भारत-कतर उच्चस्तरीय अनुवीक्षण तंत्र (एचएलएमएम) की सहअध्यक्षता की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला ने मार्च 2010 में कतर की यात्रा की और कतर के उप प्रधान मंत्री एवं ऊर्जा और उद्योग मंत्री अब्दुल्ला अल अतियाह के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की।

कतर के उप प्रधान मंत्री और ऊर्जा तथा उद्योग मंत्री अब्दुल्ला अल अतियाह ने मार्च 2010 में भारत की तीन दिवसीय यात्रा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ मुलाकात के अतिरिक्त उन्होंने प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की और विदेश मंत्री के साथ अलग से एक बैठक की। कतर के उद्योग और ऊर्जा राज्य मंत्री मोहम्मद अल सदा ने 27-29 अक्तूबर, 2010 को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में कतर के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। भारत-कतर उच्चस्तरीय अन्वीक्षण तंत्र (एचएलएमएन) की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 13-14 जनवरी, 2011 को आयोजित की गई। दोनों पक्ष पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, विद्युत, बैंकिंग और वित्त सेक्टर, सिविल उड्डयन और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और सघन बनाने के लिए विशिष्ट उपाय करने के लिए सहमत हुए।

कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2009-2010 के दौरान 5.18 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया।

अरब विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में दोहा का नामांकन किए जाने पर समारोह मनाने के लिए सितंबर 2010 में दोहा में 'भारतीय सांस्कृतिक दिवसों' का आयोजन किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित तीन मंडलियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 5,00,000 का विशाल भारतीय समुदाय परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

सऊदी अरब

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की 27 फरवरी से 1 मार्च, 2010 की तीन दिवसीय यात्रा से भारत के सऊदी अरब के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। प्रधान मंत्री और किंग अब्दुल्ला ने 'रियाद घोषणा' पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच 'सामरिक भागीदारी के एक नए युग' का आरंभ हुआ। सऊदी के विदेश मंत्री, पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की। यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें प्रत्यर्पण संधि, सजाप्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार, सांस्कृतिक सहयोग संबंधी करार और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग संबंधी करार शामिल थे।

पूर्व विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने हज करार पर हस्ताक्षर के लिए मार्च 2010 में जद्दा की यात्रा की। सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलावे पर अप्रैल 2010 में भारत की यात्रा की। प्रिंस सलमान ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और राज्य सभा के उप सभापति के साथ बैठकें की। पिंस सलमान और उनके साथ आए कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ने फिक्की, सीआईआई और एसोचैम द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में भारतीय कारोबारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री वयालार रवि ने सितंबर 2010 में सउदी अरब की यात्रा की और कार्यवाहक श्रम मंत्री डॉ. अब्दुलवाहिद बिन खालिद एवं रियाद के कार्यवाहक गवर्नर प्रिंस सत्तम बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। सऊदी वाणिज्य और उद्योग मंत्री अब्दुल्ला जैनल अलिरेजा ने नवंबर 2010 में भारत की तीन दिनों की यात्रा की। उन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और वित्त एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों के साथ बैठकें की।

भारत-सऊदी संयुक्त आयोग की पहली समीक्षा बैठक अक्तूबर 2010 में रियाद में संपन्न की गई और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई। योजना आयोग के सदस्य श्री बी. के. चतुर्वेदी ने अक्तूबर 2010 में जी-20 ऊर्जा सुरक्षा कार्यशाला में तीन सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

इस वर्ष के दौरान कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान से आर्थिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई। प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान एक 36 सदस्यों वाले भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी वाणिज्य एवं उद्योग संघों की परिषद में सऊदी कारोबारियों से विचार-विमर्श किया। बाद में भारत के साल्वेंट एक्ट्रैक्टर्स संघ (एसईए) के एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मई 2010 में रियाद में आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया। उर्वरक विभाग के अपर सचिव की अगुवाई में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2010 में सऊदी अरब का दौरा किया। रियाद, दम्माम और जद्दा में एक बहु-सेक्टर कैटलॉग प्रदर्शनी, भारतीय केटेक्स-2010 आयोजित की गई। भारतीय कंपनियों को सऊदी अरब में रेलवे, ऑटोमोबाइल, अभियांत्रिकी और बुनियादी सुविधाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी संविदाएं प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2009-2010 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 21 बिलियन अमरीकी डालर का था।

सऊदी कमांड और स्टॉफ कालेज से एक 16 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने जून 2010 में भारत की यात्रा की। इस वर्ष के दौरान अनेक सऊदी प्रतिरक्षा कर्मियों ने रक्षा सेवा स्टॉफ कालेज, वैलिंगटन और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, गोवा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया। सऊदी अरब में बसी दो मिलियन से भी अधिक भारतीय आबादी वहां सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध परंपरागत रूप से प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं और ये राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और भारत गैर-तेल सामग्री व्यापार की दृष्टि से एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, जिनका द्विपक्षीय व्यापार (कच्चे माल का आयात सहित) 43 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का है। भारत संयुक्त अरब अमीरात के उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। संयुक्त अरब अमीरात में 1.75 मिलियन से अधिक प्रवासी हैं, जो भिन्न-भिन्न आर्थिक उत्पादन कार्यकलापों में लगे हुए हैं।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने नवंबर 2010 में संयुक्त अरब अमीरात की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा की। उनके साथ विद्युत राज्य मंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी, संसद सदस्य, कारोबारी और मीडिया के शिष्टमंडल भी गए थे। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिना जायेद अल नहयान तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठकें की और उनके साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए खासतौर से निवेश, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने आबू धाबी में वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ संघ से मुलाकात की और दुबई में भारतीय श्रमिक संसाधन केंद्र (आईडब्ल्यूआरसी) का उद्घाटन भी किया।

संयुक्त अरब अमीरात के उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मार्च 2010 में भारत की यात्रा की।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2010 में अबू धाबी में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्रीमती विजय लता रेड्डी और संयुक्त अरब अमीरात पक्ष से विदेश मामलों के राज्य मंत्री डॉ. अनवर मोहम्मद गारगश ने बैठक की अगुवाई की। दोनों पक्षों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों और परस्पर हितों के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। भारतीय निर्यात संघ परिसंघ (एफआईईओ) के समन्वयन से जून 2010 में दुबई स्थित दुबई कंवेशन और इक्जीवीशन सेंटर में इंडिया शो, 2010 का आयोजन किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने शो में हिस्सा लिया।

वर्ष के दौरान कई मंत्रिस्तरीय दौरों का आदान-प्रदान हुआ। कारपोरेट मामले और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सलमान खुर्शीद ने अप्रैल 2010 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने मई 2010 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने मई 2010 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। भारतीय प्रवासी मामलों के मंत्री श्री वयालार रवि ने भी मई 2010 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। विदेश राज्य मंत्री प्रनीत कौर ने संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान द्वारा नवंबर 2010 में दुबई में आयोजित प्रथम अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन (एआईआईसी) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नौसेना प्रमुख ने मई 2010 में अबू धाबी में आयोजित द्वितीय भारतीय समुद्री नौसेना संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की।

यमन

भारत और यमन के बीच प्राचीन काल से संबंध है। संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएस) के सातवें सत्र का आयोजन मार्च 2010 में साना में किया गया। भारतीय पक्ष की अगुवाई सचिव (पूर्व) श्रीमती लता रेड्डी ने और यमन पक्ष की अगुवाई योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उप मंत्री इंजीनियर हिशाम शर्राफ अब्दुल्ला ने की। संयुक्त आयोग बैठक के अंत में जारी सहमत कार्यवृत्त में द्विपक्षीय मुद्दों के सभी विषयों को शामिल किया गया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. डी. पुरनदेश्वरी ने हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर-एआरसी) के मंत्रियों के दसवें परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में अगस्त 2010 में साना की यात्रा की। भारत, 2011 में हिंद महासागर परिधि-क्षेत्रीय सहयोग संघ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

यमन के तेल और खनिज मंत्री श्री अमीर सलेम अल-एदरूस ने पेट्रोटेक 2010 में हिस्सा लेने के लिए अक्तूबर 2010 में भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए सार्वजनिक और निजी भारतीय पेट्रोकैमिकल्स कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया। यमन के विद्युत और ऊर्जा मंत्री श्री अवध अल सोकोत्री ने अक्तूबर 2010 में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन (डीआईआरईसी) के संबंध में भारत की यात्रा की।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मई 2010 में यमन की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यमन के सरकारी अधिकारियों और यमन वाणिज्य और उद्योग संघ परिसंघ के सदस्यों से भी मुलाकात की। यह प्रतिनिधिमंडल अदेन भी गया और अदेन के वाणिज्य और उद्योग संघ परिसंघ के सदस्यों से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत और यमन के बीच सहयोग के कोर क्षेत्रों के रूप में व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं की पहचान की। भारतीय सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियां यमन में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सक्रिय हैं।

यमन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2009-2010 में 2-3 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया।

भारत-अरब निवेश परियोजना कान्क्लेव

द्वितीय भारत-अरब निवेश परियोजना कान्क्लेव का आयोजन फरवरी 2010 में नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन

विदेश मंत्रालय, अरब राज्य लीग, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ परिसंघ (फिक्की) और अरब व्यापार, उद्योग और कृषि परिसंघों के सामान्य संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बैठक में अरब राज्य लीग के 21-सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें वाणिज्य और उद्योग विभाग के कई मंत्री शामिल थे। कान्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने किया।

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका

इस अवधि के दौरान उच्च स्तरीय दौरों के आदान-प्रदान और द्विपक्षीय सहयोग के जरिए भारत के पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र के देशों के साथ संबंध और सुदृढ़ हुए।

अल्जीरिया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 12 जुलाई, 2010 को अपने पीएसएलवीसी-15 यान के माध्यम से एक अल्जीरियाई उपग्रह एएसएसएटी 2ए को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।

केपक्सिल के तत्वावधान में एक 13 सदस्यों वाले कारोबारी शिष्टमंडल ने 21-22 जुलाई, 2010 तक अल्जीरिया की यात्रा की और एक क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया।

सितंबर से दिसंबर 2010 तक अल्जीयर्स में एक भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था।

मिस्त्र

भारत और मिस्त्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का आठवां दौर काहिरा में सचिव (पूर्व) के दौरे के दौरान 5 अगस्त, 2010 को आयोजित किया गया। वार्ता में द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की गई। सचिव (पूर्व ने मिस्त्र के विदेश मंत्री श्री अबुल घेत से भी मुलाकात की और राष्ट्रपति के सचिव एवं राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता के साथ भी बैठकें की।

तीसरी संयुक्त रक्षा समिति की बैठक काहिरा में 9-13 अप्रैल, 2010 को आयोजित की गई। भारतीय शिष्टमंडल की अगुवाई रक्षा मत्रालय के अपर सचिव द्वारा की गयी थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा की और एक-दूसरे देश में प्रशिक्षण दौरे जारी रखने की सहमति हुई।

कई भारतीय कंपनियों ने मिस्त्र के तीन मेलों - प्लास्टेक्स 2010 (13-16 मई) में भारत के प्लास्टिक प्रोसेसरों का संघ, मैक्टेक 2010 (25-28 नवंबर) में इलेक्ट्रिक्स 2010 (4-7 दिसंबर) ईईपीसी और इलैक्ट्रिक और साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी)- में हिस्सा लिया। क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन मिस्त्र में फिक्की के शिष्टमंडल के लिए 17-20 अप्रैल को, मुंबई फार्मास्युटिकल एसोसिएशन के शिष्टमंडल के लिए 21-23 अप्रैल को, सोल्वेंट इक्स्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन के शिष्टमंडल के लिए 29 अप्रैल-2 मई केमेक्सिल के लिए 16-17 जून, केपेक्सिल के लिए 24-29 जुलाई, टेक्सप्रोसिल के लिए 23-26 अक्तूबर और ईएससी के शिष्टमंडल के लिए 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किए गए। भारत में आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के लिए मिस्त्र के कारोबारियों और पत्रकारों ने कैमेक्सिल (मई और अक्तूबर में) भारतीय हथकरघा और उपहार मेला (अक्तूबर में) और केपिक्सिल (नवंबर में) आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (गेल) ने काहिरा में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया।

मिस्त्र में 26 सितंबर-4 अक्तूबर 2010 तक एक भारतीय संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की मणिपुरी, ओडिसी, गुजराती लोक नृत्यों और विलय संगीत मंडलियों ने मिस्त्र के काहिरा; पोर्ट सईद, एलेक्जेंड्रिया और बेनी सऊफ नगरों में अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। भारतीय संस्कृति सप्ताह के दौरान चार स्त्री कलाकारों द्वारा समकालिक कला की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। इस कार्यक्रम के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक ने भी मिस्त्र की यात्रा की थी। छह भारतीय फिल्मों ने 34वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (30 नवंबर-9 दिसंबर 2010) में हिस्सा लिया, जिसमें कुछ भारतीय कलाकारों को जूरी का सदस्य बनाया गया था।

इजराइल

भारत की ओर से छह सदस्यों वाले एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2010 में इजराइल की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति पेरेज, नेसेट अध्यक्ष रिवेन खिलिन और प्रतिपक्ष के नेता ट्विपी लिवनी से मुलाकात की।

विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने 65वें संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान 22 सितंबर, 2010 को न्यूयार्क में इजराइल के उप विदेश मंत्री श्री डेनियल आयालोन से मुलाकात की।

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आईएमएफ की बैठक के दौरान 8 अक्तूबर, 2010 को वाशिंगटन डीसी में इजराइल के वित्त मंत्री श्री युवल स्टीननिट्ज से मुलाकात की।

इजराइली पक्ष से भारत-इजराइल संसदीय मैत्री लीग के उपाध्यक्ष श्री राचेल अदातो ने अप्रैल 2010 में भारत की यात्रा की और विदेश मामलों की मंत्री सुश्री रुथ कहनोफ, डीडीजी (एशिया और प्रशांत) ने जून 2010 में भारत की यात्रा की।

हरियाणा के कृषि राज्य मंत्री श्री सुखवीर सिंह ने भारत-इजराइल परियोजना के अधीन साइट्रस, जैतून और आम की फसलों के लिए फसल प्रौद्योगिकी और फसल बाद प्रबंधन के अध्ययन के लिए 1-6 अगस्त, 2010 तक इजराइल में एक आठ सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

मिजोरम विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री जॉन रोतलालियाना ने अध्ययन दौरे पर 10-13 सितंबर, 2010 तक इजराइल की यात्रा की।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 12 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान मोरक्को के प्रधान मंत्री श्री अब्बास अल फास्सी से मुलाकात करते हुए।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 27 नवंबर, 2010 को दमिश्क, सीरिया के प्रधान मंत्री कार्यालय में सीरिया के प्रधान मंत्री श्री मुहम्मद नाजी-अल-ओत्री के साथ।

इस अवधि के दौरान रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण दौरों में नौसेना प्रमुख एडमिरल निर्मल शर्मा की 10-15 अक्तूबर, 2010 तक की यात्रा शामिल थी। रक्षा उत्पादन, खरीद और विकास संबंधी पांचवे उप कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी डीपीपीडी) की बैठक 1-7 मई, 2010 को इजराइल में आयोजित की गयी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई डीजी, (अभिप्राप्ति) श्री शशिकांत शर्मा ने की थी। पांचवी वायु सेना स्टॉफ से वायु सेना स्टॉफ वार्ताएं 31 अक्तूबर–4 नवंबर 2010 तक इजराइल में आयोजित की गई। छठी सेना स्टाफ से सेना स्टाफ वार्ताएं 28 नवंबर-2 दिसंबर 2010 तक इजराइल में आयोजित की गयी थीं।

वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव, श्री अनिल मुकिम ने रत्न और रत्नाभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के सरकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों वाले छह सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में 21-24 जून, 2010 तक इजराइल की यात्रा की।

भारतीय उद्योग परिसंघ और तेल अवीव विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तृतीय भारत इजराइल मंच का आयोजन नई दिल्ली में 1-2 नवंबर, 2010 को किया गया। मंच में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें जैव प्रौद्योगिकी, जैव औषधि, जल प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक ऊर्जा और पारिस्थितिकी के क्षेत्र भी शामिल थे, में कारोबारी सहयोग और प्रौद्योगिकीय सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गयी।

कैप्टन अमन सिंह बहादुर (हाईफा युद्ध में शहीद हुए भारतीय योद्धाओं में एक) के पौत्र कर्नल एम. एस. जोधा की अगुवाई में एक दो सदस्यों वाले सैनिक प्रतिनिधिमंडल ने 22 सितंबर, 2010 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाईफा की मुक्ति में भारतीय योद्धाओं के बलिदान को याद करने के लिए आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए इजराइल की यात्रा की।

उस्ताद इकबाल अहमद खान की अगुवाई में एक पांच सदस्यों वाले हिंदुस्तानी स्वर संगीत समूह ने कॉनफेडरेशन हाउस द्वारा जेरुसलम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय औद उत्सव में प्रस्तुति देने 21-24 नवंबर, 2010 तक इजराइल की यात्रा की। श्री राजकुमार भट्ट के नेतृत्व में छह सदस्यीय एक कठपुतली दल ने 2-8 अगस्त, 2010 तक 35वें अंतर्राष्ट्रीय कला एवं शिल्प मेले में प्रदर्शन किया।

जोर्डन

50वें एनडीसी पाठ्यक्रम के विदेशों के अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में एक 14 सदस्यों वाले राष्ट्रीय रक्षा कालेज (एनडीसी) प्रतिनिधिमंडल ने 9–15 मई, 2010 तक जोर्डन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जोर्डन के प्रधान मंत्री और वरिष्ठ स्थानीय नेताओं से मुलाकात की।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सचिव (एसई और एल) श्रीमती अंशू वैश की अगुवाई में एक दो सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय नीति वार्ता मंच में हिस्सा लेने के लिए अम्मान की यात्रा की।

नैसकॉम के अध्यक्ष श्री सोम मित्तल की अगुवाई में प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के सदस्यों के एक 10 सदस्यों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल 10-11 अक्तूबर, 2010 तक अम्मान में आयोजित द्विवर्षीय मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच, 2010 (मेना-आईसीटी मंच, 2010) में हिस्सा लिया। मंच के दौरान जोर्डन सूचना प्रौद्योगिक संघ और नैसकॉम और जोर्डन तथा भारत के आईसीटी उद्योगों के बीच भी संयुक्त सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए।

लीबिया

लीबिया के अफ्रीकी मामलों के पूर्व मंत्री डॉ. अली अब्दुस्सलाम अल-त्रेकी, जिन्होंने अप्रैल 2008 में नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका मंच शिखर बैठक के लिए लीबियाई प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी, ने अप्रैल 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में भारत की यात्रा की।

मोरक्को

भारत के प्रधान मत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक के दौरान अप्रैल 2010 में वाशिंगटन में मोरक्को के प्रधान मंत्री श्री अब्बास एल फैसी से मुलाकात की और दोनों देशों के हितों के द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

मोरक्को के विदेश मत्री श्री तईब फैसी फिहरी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र के दौरान सितंबर 2010 में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा से मुलाकात की और परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्तूबर 2010 में मोरोक्को की यात्रा की और मराकेश, मोरक्को में आयोजित मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका संबंधी विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लिया। मंच की बैठक के दौरान उन्होंने मोरक्को के विदेश वाणिज्य मंत्री श्री अब्देल्लतीफ माजौज से मुलाकात की और आर्थिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की।

वर्ष के दौरान कई सदस्यों वाले कारोबारी और निर्यात संवर्धन प्रतिनिधिमंडल ने मोरक्को की और मोरक्को के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की।

फिलीस्तीन

भारत ने फिलीस्तीन के लोगों के अपने स्वयं की मातृभूमि को प्राप्त करने के न्यायसंगत अधिकार को अपना अटल सहयोग जारी रखा। विदेश मंत्री श्री एस एम कृष्णा ने सितंबर 2010 में आयोजित 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयार्क में नैम मंत्रिस्तरीय और फिलीपींस पर आईबीएस + इंडोनेशिया + फिलीस्तीन में हिस्सा लिया, जिसमें भारत ने इजराइल और फिलीस्तीन के बीच 'सीधी वार्ता' का स्वागत किया।

भारत ने निकट पूर्व में फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी को 1 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान दिया।

विदेश मंत्री श्री एस एम कृष्णा ने 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान आयोजित सूडान पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। न्यूयार्क में 22 सितंबर, को सूडान के विदेश मंत्री अहमद अली कारती के साथ हुई अपनी द्विपक्षीय वार्ता में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, सूडान के घटनाक्रमों, आम सहमति के लिए तैयारी और दारफुर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की आशा व्यक्त की।

सूडान के पेट्रोलियम मंत्री डॉ. लुआल एक्यूक डेंग ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 31 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय तैल और गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी 'पेट्रोटेक 2010' में हिस्सा लिया।

सूडान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. इसा बुशरा मोहम्मद हामिद और विद्युत तथा बांध मंत्री, इल्साडिग मोहम्मद अली इल्शीख ने अपने दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27-29 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित 'दि दिल्ली इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी कांफरेंस (डीआईआरईसी 2010)' नामक नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी चौथे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया।

तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग पर भारत-सूडान संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक खारतूम में 29-30 नवंबर, 2010 को संपन्न हुई।

सूडान के उद्योग मंत्री श्री अवद अल जाज ने 2-3 नवंबर, 2010 तक भारत की यात्रा की और 3 नवंबर, 2010 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा से मुलाकात की।

सीरिया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने 26-29 नवंबर, 2010 तक सीरिया की राजकीय यात्रा की। उन्होंने सीरीया के राष्ट्रपति डॉ. बशर अल असद से मुलाकात की और विविध मुद्दों पर व्यापक चर्चा की, जिसके अंतर्गत सीरिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ाने को प्रमुखता दी गयी। उन्होंने प्रधान मंत्री मुहम्मद नाजी अल ओत्री और सीरिया एसेंबली के अध्यक्ष महमूद अल अबराश से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और सीरिया के कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों से भी विचार-विमर्श किया और भारत-सीरिया कारोबार शिखर बैठक में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारत-सीरिया कारोबार परिषद की शुरुआत की। दोनों देशों के बीच मीडिया और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति निशक्त बच्चों की संस्था - सीरियाई गैर सरकारी संगठन - 'आमल' भी देखने गई और आमल के कार्यकलापों के लिए 2 मिलियन सीरियाई पाउंड (लगभग 20 लाख रुपए) दान दिया। भारत ने सीरिया को 100 मिलियन अमरीकी डालर की एक नई ऋण श्रृंखला और आइटेक के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या को 45 से बढ़ाकर 90 करने की भी पेशकश की। पर्यटन पर भारत-सीरिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में मई 2010 में आयोजित की गयी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने जून 2010 में दमिश्क की यात्रा की और भारत-सीरिया संयुक्त आयोग बैठक की सहअध्यक्षता की। सचिव (उर्वरक) श्री शांतनु बहूरिया ने अक्तूबर 2010 में दमिश्क की यात्रा की, जहां फास्फेट क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ट्यूनीशिया

अंतर्राष्ट्रीय बोली के तहत मैसर्स केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने ट्रांसमिशन टावरों के निर्माण और अवस्थापना के लिए सरकारी स्वामित्व की विद्युत और गैस उत्पादन और संवितरण एजेंसी एसटीईजी से 93 मिलियन अमरीकी डालर की निविदा हासिल की। मैसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमि. भी एसटीईजी से 73 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी निविदा हासिल करने में सफल रही।

मगरेब क्षेत्र की यात्रा के हिस्से के रूप में फिक्की ने ट्रैक्टर और दूसरे कृषि उपकरण, कंप्यूटर साफ्टवेयर, टायर, कपड़ा, एसोर्टेड विद्युत उपकरण, तंबाकू, मसाले और विविध उपभोक्ता सामग्रियों से जुड़ी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक 17 सदस्यों वाले बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल को प्रायोजित किया। एक अतिथि प्रतिनिधिमंडल ने 4-5 अक्तूबर, 2010 को ट्यूनिश में आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया।

भारत और ट्यूनिशिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित भारत के 14 उत्कृष्ट कलाकारों की चित्रकला की प्रदर्शनी 'कल्पना' का आयोजन 13 अप्रैल-22 मई 2010 को सोस, स्फैक्स और ट्यूनिश शहरों में किया गया। ट्यूनिशिया सरकार, संस्कृति मंत्रालय ने क्रमशः दिल्ली और चंडीगढ़ में 18-20 मई, 2010 को आयोजित अफ्रीका महोत्सव में प्रस्तुति के लिए 11-सदस्यों वाली सांस्कृतिक मंडली 'इफ्रीगा' को भारत भेजा।

अरब लीग

भारत-अरब लीग राजनैतिक परामर्श के पांचवे दौर का आयोजन सचिव (पूर्व) और अरब लीग के महसचिव के मंत्रिमंडल के प्रमुख के बीच 8 अगस्त, 2010 को काहिरा में किया गया। विचार-विमर्श साझा हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और अरब-भारत सहयोग मंच (एआईसीएफ) के कार्यकलापों की समीक्षा पर केंद्रित रहा। सचिव (पूर्व) ने अरब लीग के महासचिव से भी मुलाकात की।

■■

6 अफ्रीका (सहारा से दक्षिण)

पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र के 20 देशों के साथ भारत के संबंध दोनों पक्षों से कई उच्च स्तरीय यात्राओं के आयोजन व कई करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षरों के परिणामस्वरूप और सुदृढ़ हुए हैं।

भारत ने इस क्षेत्र से कई उच्च स्तरीय यात्राओं की मेजबानी कीः

- सेशल्स के राष्ट्रपति श्री जेम्स एलिक्स माइकल ने 1-3 जून, 2010 को भारत की सरकारी यात्रा की।
- दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, श्री जैकब जी. जुमा ने 2-5 जून, 2010 को भारत की सरकारी यात्रा की। बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति ले. जनरल मामपती एस मेराफहे ने 16-19 जून, 2010 को भारत की यात्रा की।
- बुरुण्डी के राष्ट्रपति श्री पीयर कुरंजिज ने 13-22 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली की गैर सरकारी यात्रा की।
- मोजाम्बिक के राष्ट्रपति अरमाण्डो गुएबुजा ने 29 सितंबर-4 अक्तूबर 2010 को भारत की यात्रा की।
- मॉरीशस के उप-प्रधानमंत्री, ऊर्जा एवं लोक उपयोगिता मंत्री डा. अहमद रशीद बीबीजाउन ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन, 2010 (डीआईआरईसी) में भाग लेने के लिए 26-29 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली की यात्रा की।
- मालावी के राष्ट्रपति प्रो. बिंगु वा मुथरायका ने 2-7 नवंबर, 2010 को भारत की यात्रा की।
- कीनिया के प्रधानमंत्री श्री रेला ओडिंगा ने 14-17 नवंबर, 2010 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।
- इथियोपिया के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेशी मंत्री ने 30 नवंबर-3 दिसंबर 2010 को प्रथम संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के लिए वित्त एवं आर्थिक विकास मंत्री और व्यापार राज्य मंत्री सहित 13 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने 11 नवंबर, 2010 को सियोल में जी-20 की बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात की तथा दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय, व्यापार व निवेश संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए विचार-विमर्श किया।
- योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री की सह-अध्यक्षता में आयोजित जलवायु परिवर्तन वित्त व्यवस्था पर यूएनएसजी के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की तीसरी व अंतिम बैठक में भाग लेने के लिए 12 अक्तूबर, 2010 को अदिस अबाबा की यात्रा की।

वर्ष के दौरान भारत की अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- तंजानिया के सूचना, खेल व संस्कृति मंत्री (अक्तूबर 2010)
- मॉरीशस के उद्योग व वाणिज्य मंत्री (जून-जुलाई 2010)
- मॉरीशस के तृतीयक शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी मंत्री (जुलाई 2010)
- जाम्बिया के वित्त एवं राष्ट्रीय आयोजना उपमंत्री, श्री डेविड फिरी तथा वाणिज्य, व्यापार व उद्योग उप मंत्री श्री ल्विपा पुमा ने जुलाई 2010 में भारत की यात्रा की।
- मॉरीशस के युवा एवं खेल मंत्री (अक्तूबर 2010)
- मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री एवं ऊर्जा व लोक उपयोगिता मंत्री (अक्तूबर 2010)
- मॉरीशस के उद्योग एवं राज्य वाणिज्य मंत्री (अक्तूबर-नवंबर 2010)

भारत की ओर से महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सचिव (पश्चिम) ने सेशल्स की यात्रा की (मई 2010)
- विदेश मंत्री ने मॉरीशस, मोजाम्बिक और सेशल्स की यात्रा की (जुलाई 2010)
- विदेश राज्य मंत्री ने जुलाई 2010 में नामीबिया की यात्रा की
- रक्षा मंत्री ने सेशल्स की यात्रा की (जुलाई 2010)
- सचिव (पश्चिम) ने अफ्रीकी संघ सम्मेलन में भाग लेने के

दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. जैकब जुमा और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 4 जून, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस सम्मेलन में।

लिए कम्पाला में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया (जुलाई 2010)

- सचिव (पश्चिम) ने आदिस अबाबा की यात्रा की (सितंबर 2010)
- लोकसभा अध्यक्ष ने कीनिया की यात्रा की (सितंबर 2010)
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने केनया की यात्रा की (अक्तूबर 2010)
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री गुरुदास कामत ने आदिस अबाबा में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया (दिसंबर 2010)

बुरुण्डी

बुरुण्डी के साथ भारत के सम्बंध प्रगाढ़ व सौहार्दपूर्ण बने रहे। बुरुण्डी भारत को लोकतंत्र एवं विकास के लिए सफल आदर्श के रूप में देखता है। बुरुण्डी के आर्थिक विकास में हमारी सहायता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई है तथा भारत की उपलब्धियों की सराहना हुई है।

बुरुण्डी सरकार द्वारा किए गए विशेष अनुरोध के आधार पर बुरुण्डी के शरणार्थी शिविरों में वितरण के लिए जून व जुलाई 2010 में बुरुण्डी को आवश्यक दवाओं की 2 खेप भेजी गई थी।

जुलाई 2010 में सचिव (पश्चिम) ने कम्पाला में बुरुण्डी के विदेश मत्री से मुलाकात की जहां उन्होंने अफ्रीकी संघ सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। दोनों पक्षों ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था।

बुरुण्डी के राष्ट्रपति ने 13-19 सितंबर, 2010 को चिकित्सिय उपचार के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। उनके साथ एक विदेश मंत्री सहित एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी था। सचिव (पश्चिम) ने बुरुण्डी के राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात की तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

विदेश मंत्री ने बुरुण्डी के विदेश मंत्री के साथ 16 अगस्त, 2010 को बुजुम्बरा में स्थापित पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।

बुरुण्डी के ऊर्जा व खान मंत्री श्री मायस बुकुमी ने 27-29 अक्तूबर, 2010 को दिल्ली में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर चौथे संयुक्त मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

बोत्सवाना

बोत्सवाना के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ एवं मैत्रीपूर्ण रहे हैं। बोत्सवाना लोकतांत्रिक स्वरूप वाला एक विकासशील देश है तथा दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय का एक सक्रिय सदस्य है। भारत ने 1966 में बोत्सवाना की स्वतंत्रता के तत्काल बाद इसके साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए तथा 1987 में गैबोरोन में अपना राजनयिक मिशन खोला। वर्ष 1990 में रंगभेद संघर्ष के दौरान भारत व बोत्सवाना ने बहुसंख्यक दक्षिण अफ्रीकियों के हितों की रक्षा करने के लिए मिलकर कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार सहित विभिन्न मुद्दों पर उनकी अवधारणा समान है तथा उन्होंने विश्व व्यापार संघटन, एफएडीपी तथा दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ में एक-दूसरे के साथ सहयोग भी किया था।

बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति ले. जनरल मामपती एस मराफहे ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जून 2010 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर करारों तथा एमएसएमई/एसएमएमई पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) तथा बोत्सवाना स्थानीय उद्यम प्राधिकरण (एलईए) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मत्री ने 16 अगस्त, 2010 को बोत्सवाना से संबंधित पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का उद्घाटन किया।

कोमोरोस

भारत व कोमोरोस के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत कोमोरोस के विकास में सहायता करने की इच्छा व्यक्त करता रहा है। पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क ने सितंबर 2010 में कोमोरोस में अपने प्रचालन शुरू किए। कोमोरोस के विदेश मंत्री श्री फाहमी सईद इब्राहिम ने 2 नवंबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारत के लिए कामरोस के समर्थन की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि भारत की जनसांख्यिकी, भूगोल, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र तथा वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए योगदान की दृष्टि से भारत इस सम्मान का पात्र है।

जिबुती

जिबुती ने 600 टीपीडी अली साबी सीमेंट संयंत्र परियोजना पूरी करने के लिए एक्जिम बैंक से अतिरिक्त राशि के रूप में 14 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला प्राप्त की।

जिबुती अपने बंदरगाह पर प्रचालनात्मक परिवर्तन के लिए आने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों को भव्य स्वागत व आतिथ्य प्रदान करता है। दस्यु-रोधी अभियान पर आईएनएस इन्वेस्टिगेटर 12-14 दिसंबर, 2010 तक जिबुती के बंदरगाह पर रहा।

जिबुती गणराज्य के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री मोहम्मद अली युसूफ द्वारा 18-19 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में अल्प विकसित देशों के मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए भारत यात्रा की संभावना है।

इरीट्रिया

भारत इरीट्रिया के नागरिकों को भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए आइटेक के अंतर्गत प्रति वर्ष 15 स्लॉटों का प्रस्ताव जारी रखा।

इथियोपिया

भारत तथा इथियोपिया ने संयुक्त मंत्रालयी आयोग की सर्वप्रथम बैठक आयोजित करके वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों के लिए सशक्त संस्थागत आधारशिला का निर्माण करना जारी रखा। भारत के विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री श्री हेलीमेरियम ने भारत व इथियोपिया के बीच 30 नवंबर-3 दिसंबर 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित प्रथम संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए 13 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इथियोपिया के व्यापार राज्य मंत्री श्री अहमद तुसा तथा वित्त व आर्थिक विकास राज्य मंत्री श्री अहमद शिदे भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

राजनैतिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में भारत इथियोपिया के प्रगाढ़ व सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों की समग्र संरचना में मुख्य रूप से गैर सरकारी क्षेत्र का निवेश, ऋण श्रृंखला तथा अवस्थापना संबंधी कई परियोजनाओं में लगी हुई भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जबकि व्यापार अपेक्षाकृत छोटा परंतु प्रगतिशील क्षेत्र है।

संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की व पिछले 5 वर्षों में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा दोनों पक्षों के हित से जुड़े क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इथियोपिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। चीनी विकास में सहायता के लिए 213.31 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता जारी करने के तीसरे चरण के लिए एक्जिम बैंक व इथियोपिया सरकार के बीच 1 दिसंबर, 2010 को करार सम्पन्न किया गया था। विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग संवर्धित करने के लिए 1 दिसंबर, 2010 को विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इथियोपिया पक्ष ने उल्लेख किया था कि भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन एक अद्वितीय पहल है तथा यह अफ्रीकी विकास में सहायक है।

यात्रा के दौरान इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री ने भारत के वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा से भी मुलाकात की।

15-17 सितंबर, 2010 को अदामा में आयोजित इथियोपिया के सत्ताधारी मोर्चे की 8वीं संगठनात्मक कांग्रेस में प्रधानमंत्री मेलेस जेनावी ने भारत के स्वयं के सामने आने वाली समान चुनौतियों के बावजूद इथियोपिया के लोगों के लिए भारत सरकार की सहायता की सराहना की। इथियोपिया में पिछले आम चुनाव मई-जून 2010 में सम्पन्न किए गए थे तथा इथियोपियाई जनवादी क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चे के सत्ताधारी गठबंधन की भारी जीत हुई थी। सत्ताधारी गठबंधन ने 547 सीटों में से 545 सीटें प्राप्त की। नए मंत्रिमंडल का गठन सितंबर 2010 में किया गया था तथा प्रधानमंत्री मेलेस जेनावी को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया था।

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री गुरदास कामत के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 13-16 दिसंबर, 2010 को आदिस अबाबा में आयोजित संघवाद पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। राज्य मंत्री (संचार व सूचना प्रौद्योगिकी) सम्मेलन के एक सत्र में बीज व्याख्यान दिया; इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं तथा 0.5 मिलियन अमरीकी डालर के चिकित्सा उपस्कर सौंपे, जोकि भारत की ओर से दान के रूप में दूर चिकित्सा परीक्षणार्थ परियोजना का भाग था। इथियोपिया के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री केबेडे वारकु ने उपस्कर प्राप्त किए तथा इस महान संभावना प्रदर्शन के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया।

सचिव (पश्चिम) ने इथियोपियाई नेताओं तथा अफ्रीकी संघ आयोग के साथ बातचीत के लिए 12-13 सितंबर को आदिस अबाबा की यात्रा की। उन्होंने इथियोपिया के विदेश राज्य मंत्री तथा अफ्रीका संघ आयोग (एयूसी) के अध्यक्ष श्री जीन पिंग से मुलाकात की।

भारत के सेना उप प्रमुख ले. जनरल वी. एस. टोंक ने भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कार्यकलापों के पर्यावलोकन के लिए जून 2010 में इथियोपिया की यात्रा की तथा इथियोपिया के सेनाध्यक्ष और इथियोपिया के रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

इथियोपियाई सेनाध्यक्ष ने भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीम (आईएटीटी) भेजने के लिए अपने देश की ओर से भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। इथियोपियाई नेता भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते रहे हैं।

इथियोपियाई सिविल सेवा महाविद्यालय तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के बीच सिविल सेवा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2010 में द्विपक्षीय वाणिज्यिक, आर्थिक व निवेश संबंध सुदृढ़ बने रहे। भारत 4.7 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक वास्तविक निवेश के साथ इथियोपिया में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। दो तरफा व्यापार भी बढ़कर लगभग 600 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया तथा दोनों देश 2015 तक इसको लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। 21 सितंबर को आदिस अबाबा में पूर्व एशिया के लिए एक्जिम बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, जो कि अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

इस वर्ष के दौरान कई भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने आदिस अबाबा की यात्रा की, जिसमें जुलाई 2010 में भारत की एक अग्रणी अवस्थापना विकास व वित्त कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईएलएण्डएस) के नेतृत्व में विविध क्षेत्रों से उद्योग प्रतिनिधियों सहित 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल; 15-16 नवंबर, 2010 को पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल; 15-16 नवंबर को फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स

ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के नेतृत्व में 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल तथा 2-4 दिसंबर, 2010 को इलैक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल (ईएससी) के नेतृत्व में 16 कंपनियों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल था।

भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों के बहुसदस्यीय दल ने इथियोपियाई राजस्व एवं सीमाशुल्क प्राधिकरण को विश्व व्यापार संगठन सीमाशुल्क मूल्यांकन में परामर्श देने के लिए इथियोपिया की कई यात्राएं कीं। इथियोपिया के नेताओं ने इस दल के साथ-साथ सेन्ट्रल लैदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट तथा फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवेल्पमेंट इन्स्टीट्यूट से चमड़ा व्यावसायिकों के 40 सदस्यीय दल द्वारा किए गए कार्य की सराहना की जोकि इथियोपिया सरकार द्वारा हस्ताक्षरित वाणिज्यिक संविदा पर वहां थे।

वर्ष के पहले 8 महीनों में इथियोपिया को आबंटित 90 स्लॉटों के उपयोग के साथ ही आईटीईसी कार्यक्रम के लिए उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया रही है। इसके परिमाणस्वरूप भारत सरकार ने प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 120 कर दी है। वर्तमान वर्ष के दौरान इथियोपिया ने भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन के अंतर्गत 40 आईसीसीआर प्रशिक्षण स्लॉटों, 6 विशेष कृषि छात्रवृत्तियों तथा 8 सी वी रमन छात्रवृत्तियों का उपयोग किया। भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार भारत सरकार इथियोपिया में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेगी।

श्री सुभाष गोयल तथा श्रीमती अंजू गोयल के नेतृत्व में 13 सदस्यीय भारतीय लोक संगीत एवं नृत्य मंडली ने 5-12 नवंबर, 2010 को इथियोपिया की यात्रा की तथा आदिस अबाबा में 2 प्रस्तुतियों के अलावा दीरेदावा, आम्बो विश्वविद्यालय, हेलम फार्मा सैनिक अकादमी, होलेटा में प्रस्तुति दिए। अक्तूबर-दिसंबर 2010 में भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से 2 अक्तूबर, 2010 को गांधी पर आयोजित फिल्म शो के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई।

विदेश राज्यमंत्री (प्रनीत कौर) के नेतृत्व में सचिव (पश्चिम) सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने अफ्रीकी संघ के 18वें आम सत्र में भाग लेने के लिए 26-28 जनवरी, 2011 तक आदिस अबाबा की यात्रा की तथा इथियोपियाई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

इथियोपिया के वित्त एवं आर्थिक विकास मंत्री, श्री सुफियन अहमद ने 3-4 फरवरी, 2011 में नई दिल्ली की यात्रा की तथा विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया।

द्विपक्षीय कृषि सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर, नई दिल्ली ने इथियोपियाई कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सहयोग प्रस्ताव के आधार पर सहयोग की संभावनाओं तथा सहयोग के ठोस ढांचे के विकास का आंकलन करने के उद्देश्य से 9-16 फरवरी, 2011 के दौरान डा. एस अय्यपन, डी जी, आईसीएआर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए सहमति दी है। इथियोपियाई कृषि अनुसंधान संस्थान ने अनुभव यात्रा के आदान-प्रदान के लिए अलग से इथियोपियाई वैज्ञानिकों के 2 प्रतिनिधिमंडल आईसीएआर में भेजे हैं।

इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री हेलमेरियम देसालेन द्वारा 18-19 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली एलडीसी की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक के लिए भारत यात्रा की संभावना है।

कीनिया

भारत और कीनिया के बीच प्रगाढ़ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस वर्ष अध्यक्ष (लोकसभा) व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की कीनिया यात्रा तथा कीनिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से इसमें और प्रगाढ़ता आई है। भारत सरकार ने विद्युत पारेषण लाइनों के लिए 61.60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला अनुमोदित की है।

भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस गंगा तथा आईएनएस आदित्य ने 23-26 अगस्त से मोम्बासा बंदरगाह पर सौहार्द यात्रा की। कीनिया के विदेश मंत्री मासिज वेटनगुला ने मोम्बासा में इन जहाजों को देखा।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने 10-19 सितंबर से नैरोबी में आयोजित 56वें राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य विधान मंडलों के कई पीठासीन अधिकारी शामिल हैं।

कीनिया ने 3-14 अक्तूबर तक नई दिल्ली में आयोजित 19वीं राष्ट्रमण्डल खेलों में अपना सबसे बड़ा दल भेजा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (सीआईएम) श्री आनंद शर्मा ने 12-13 अक्तूबर से नैरोबी में आयोजित भारत-कीनिया संयुक्त व्यापार समिति के छठे सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कीनिया पक्ष का नेतृत्व कीनिया के व्यापार मंत्री श्री चिराऊ अली वाकवेयर ने की। विस्तृत क्षेत्रों में भारत-कीनिया सहयोग पर चर्चा की गई थी, जिसमें अवस्थापना, कृषि, वस्त्र, आईसीटी, भेषज, पर्यटन, नागरिक उड्डयन विधुत व ऊर्जा, सड़कें, द्रुत परिवहन, रेलवे, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, एसएमई, ईपीजेड व एसईजेड शामिल हैं। सीआईएम ने वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से फिक्की द्वारा 14-15 अक्तूबर, 2010 को नैरोबी में आयोजित व्यापार उत्सव 'नमस्कार अफ्रीका' का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय उत्सव में 9 पूर्व अफ्रीकी देशों से व्यापारियों की सहभागिता सहित 'भारतीय प्रदर्शनी' और 'भारत-पूर्व अफ्रीका व्यापार मंच' शामिल थे। इस मंच में भारत की ओर से एक बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, सिकंदाबाद से 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्तूबर-6 नवंबर तक कीनिया की यात्रा की।

कीनिया के प्रधानमंत्री महामहिम रेला आडिंगा ने विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14-17 नवंबर तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आडिंगा ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। उपरोक्त यात्रा के दौरान विद्युत पारेषण परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा कीनिया सरकार को प्रस्तावित 61.6 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला प्रदान करने से संबंधित करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

लेसोथो

वर्ष 1996 से प्रिटोरिया उच्चायोग का अतिरिक्त प्रभार लेसोथो को दिया गया है। अगस्त 2003 में प्रधानमंत्री मासिसिलि की भारत यात्रा के बाद लेसोथो ने नई दिल्ली में अपना आवासीय मिशन खोला। श्री शबीर पीरभाई को भारत में लेसोथो का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था।

जून 2001 से लेसोथो में तैनात भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मई 2001 में सैन्य प्रशिक्षण सहयोग पर अंतरसरकारी सहयोग करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात 17 सदस्यीय भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल जून 2001 में लेसोथो भेजा गया था। भारत सरकार लेसोथो में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल की तैनाती की अवधि को 2011 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई थी। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में लेसोथो सरकार के अनुरोध पर भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया है।

मालावी

मालावी के राष्ट्रपति प्रो. बिंगु मुथारिका ने 2-7 नवंबर, 2010 से भारत की सरकारी यात्रा की। प्रो. मुथरिका के साथ उनकी पत्नी मादाम कालिस्टा मुथारिका व 6 मंत्री तथा 45 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी था। इस यात्रा के दौरान प्रो. मुथारिका ने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ सार्थक विचार-विमर्श किया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय तथा साथ ही क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान भारत तथा मालावी ने निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किएः सामान्य सहयोग करार, खनिज संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

प्रधानमंत्री ने लघु उद्योग इंक्यूबेटर के विनिर्माण सहित विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा भी कि लिलांग्वे में भारतीय मिशन पुनः खोला जाएगा।

चांसलर कॉलेज जोम्बा, मालावी ने 16 अगस्त, 2010 को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया था।

मेडागास्कर

आइटेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण के क्षेत्र में मेडागास्कर के साथ बातचीत जारी है। इसी प्रकार दूर-शिक्षा तथा दूर-चिकित्सा कार्यक्रमों सहित पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना कार्यक्रम भी चल रहा है।

मॉरीशस

साझा संबंधों के आधार पर भारत व मॉरीशस के बीच संबंध ऐतिहासिक व समय की कसौटी पर खरे रहे हैं। ये व्यापक, बहुआयामी व आपसी लाभों के लिए हैं। राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी, रक्षा व सुरक्षा क्षेत्र तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत व मॉरीशस के बीच व्यापक सहभागिता और सुदृढ़ हुई है तथा उसमें विस्तार हुआ है।

विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने 2-4 जुलाई, 2010 को मॉरीशस की सरकारी यात्रा की। उन्होंने मॉरीशस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, क्षेत्रीय एकीकरण व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री तथा मॉरीशस के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान 5 करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस वर्ष के दौरान मॉरीशस के कई मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के अन्य उपायों पर चर्चा करने के लिए भारत की यात्रा की। भारत मॉरीशस के लिए आयातों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। मॉरीशस भारत के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नौसेना के जहाजों की सौहार्द यात्रा के माध्यम से मॉरीशस के साथ रक्षा व सुरक्षा सहयोग जारी रहे। हमारे जहाजों ने ईईजेड निगरानी तथा जलदस्युता-विरोधी अभियान भी संचालित किए हैं। भारतीय नौसेना ने मॉरीशस में जल विज्ञान संबंधी कार्यकलाप करने में भी सहायता की है। असैनिक रक्षा श्रेणी में आईटीईसी कार्यक्रमों की अधिक से अधिक मांग हुई। मॉरीशस के विद्यार्थियों ने आईसीसीआर तथा भारत सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाना जारी रखा। सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत सहयोग जारी है। मॉरीशस यूरो जोन संकट का प्रभाव महसूस करने के बाद व्यापार व आर्थिक सहभागियों के रूप में अधिक से अधिक भारत तथा पूर्वी देशों की ओर देख रहा है। पर्यटन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक है।

मॉरीशस के चुनाव आयोग के आमंत्रण पर तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला के साथ भारतीय चुनाव आयोग के विधिक परामर्शदाता 2-6 मई, 2010 को मॉरीशस में थे। संयोगवश 5 मई, 2010 को मॉरीशस में आम चुनाव थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मॉरीशस के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा नैशनल असेम्बली के अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की।

मॉरीशस के उद्योग व वाणिज्य मंत्री शोकुताली सूदन ने 27 जून-2 जुलाई 2010 तक मैंगलोर व नई दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान मैंगलोर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.

ने वर्ष 2010-2013 की अवधि के लिए मॉरीशस की स्ट्रेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए संविदा नवीकरण करार पर 1 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 2-4 जुलाई, 2010 को मॉरीशस की सरकारी यात्रा की। उन्होंने मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरीशस के प्रधानमंत्री एवं वित्त व आर्थिक विकास मंत्री श्री प्रबिन्द कुमार जगन्नाथ तथा विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा क्षेत्रीय सहयोग मंत्री डा. अर्विन बुलेल से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अपने वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। इस यात्रा के दौरान 5 करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें अपतटीय पैट्रोल जहाजों की आपूर्ति, 2010-2013 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम; तटीय बाधायेरू के लिए पूर्व-चेतावनी सहयोग, सूचना सुरक्षा में सहयोग तथा महात्मा गांधी संस्थान में संस्कृत व भारतीय दर्शनशास्त्र की पीठ स्थापित करना शामिल है।

मॉरीशस की तृतीयक शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी मंत्री डा. राजेश्वर जीता ने नई दिल्ली में टाइम्स एजुकेशन बूटीक में भाग लिया। उन्होंने 5 जुलाई, 2010 को मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल तथा 6 जुलाई, 2010 को तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात की।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय से सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ श्री आलोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 सितंबर, 2010 को अध्ययन दौरे पर मॉरीशस की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने 21 सितंबर, 2010 को मॉरीशस के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

युवा व खेल मंत्री श्री सत्यप्रकाश रितू ने राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने 5 अक्तूबर, 2010 को युवा मामले व खेल मंत्री डा. एम. एस. गिल से मुलाकात की। मॉरीशस ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में एथलिटों तथा कर्मचारियों का 89 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भेजा।

पश्चिमी बेड़े के कमांडिंग फ्लैग आफिसर, रियर एडमिरल आर. के. पटनायक ने आईएनएस मैसूर पर 6-8 अक्तूबर, 2010 को मॉरीशस की यात्रा की। उन्होंने मॉरीशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ, विभिन्न मंत्रियों तथा अधिकारियों से मुलाकात की।

मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री तथा ऊर्जा एवं लोक उपयोगिता डा. राशीद बीबीजुआन ने 26-29 अक्तूबर, 2010 को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन, 2010 (डीआईआरईपी, 2010) में भाग लिया। उन्होंने भारत के उप राष्ट्रपति डा. हामीद अंसारी, नवीन एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, डा. फारुख अबदुल्ला तथा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की।

मॉरीशस के उद्योग एवं वाणिज्यि मंत्री श्री शोकुताली सूधुन ने 31 अक्तूबर-3 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में आयोजित पेट्रोटेक, 2010 सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कृषि मंत्री श्री शरद पवार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा से मुलाकात की।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत-मॉरीशस संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक 4 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

मॉरीशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के साथ श्रीमती सरोजिनी जगन्नाथ 14-28 नवंबर, 2010 को भारत की निजी यात्रा की थी। उन्होंने भुवनेश्वर, रांची, पटना, फैजाबाद, लखनऊ, उदयपुर, रोहतक तथा नई दिल्ली की यात्रा की।

भारतीय नौसैनिक जहाज, आईएनएस निर्देशक ने 26 मार्च-27 अप्रैल 2010 को मॉरीशस समुद्र तट के आस-पास जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। सेंट ब्रेडन द्वीप के दक्षिणी भाग एवं ग्राण्ड पोर्ट के दक्षिण जलमार्ग से संबंधित उपयुक्त सर्वेक्षण शीट, बांदी मिट्रिक सर्वेक्षण और भूमि आधारित महासागरीय उद्योग के विकास के लिए फ्लाई एन फ्लैक क्षेत्र में डिजिटल चार्ट तथा सेंट ब्रेंडेन द्वीप के उत्तरी भाग के सर्वेक्षण चार्ट मॉरीशस को भूमि एवं आवास मंत्री, डा. आबु तबालिव केंसनली को सौंपा गया था। भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस त्रिशुल को 23 मई-12 जून 2010 के दौरान मॉरीशस के समुद्री सीमा क्षेत्र में ईईजेड सर्वेक्षण तथा संयुक्त जलदस्युता अभियान चलाने के लिए मॉरीशस के समुद्री सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया था। आईएनएस मैसूर तथा आईएनएस तबर, 6-8 अक्तूबर, 2010 के दौरान मॉरीशस में थे तथा उन्होंने मॉरीशस के समुद्री सीमा क्षेत्र में ईईजेड सर्वेक्षण तथा दस्युता-विरोधी अभियान चलाए। जहाजों की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय तटरक्षक कार्मिकों के साथ संयुक्त अभ्यास किया गया। मई 2010 के दौरान भारतीय समुद्री कमाण्डो दल ने मॉरीशस के राष्ट्रीय तटरक्षकों को कमाण्डों अभियानों तथा गहरे समुद्र में गोताखोरी का प्रशिक्षण दिया। भारतीय नौसैनिक जहाजों ने अपनी यात्रा के दौरान आउटर आयरलैण्ड डेवेल्पमेंट कार्पोरेशन के कार्मिक तथा वस्तुएं अगालेगा भेजे।

सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों पर भारत-मॉरीशस तदर्थ दल की पहली बैठक 22-28 अगस्त, 2010 के दौरान मॉरीशस में आयोजित की गई थी।

वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान मॉरीशस को भारत से 453.43 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया, जबकि मॉरीशस से भारत में आयात की राशि 10.89 मिलियन अमरीकी डालर थी। वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान भारत मॉरीशस के आयातों का सबसे बड़ा स्रोत रहा। मॉरीशस के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी-सितंबर 2010 की अवधि के दौरान भारत से निर्यात का मूल्य

517.63 मिलियन अमरीकी डालर था, जोकि मॉरीशस के कुल आयात का 21.9 प्रतिशत था।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार वर्ष 2009-2010 के दौरान मॉरीशस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा एकल स्रोत रहा, जिसके माध्यम से भारत में 10.376 मिलियन अमरीकी डालर अथवा कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 42 प्रतिशत प्राप्त हुआ। अप्रैल 2000-मई 2010 तक मॉरीशस से भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से 48.534 बिलियन अमरीकी डालर अथवा 42.33 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई।

मॉरीशस बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-जुलाई 2010 के दौरान भारत ने मॉरीशस में 91.067 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया। उसी अवधि के दौरान मॉरीशस ने भारत में 0.267 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया।

इंडियन ऑयल मॉरीशस लि. ने सितंबर 2010 में मॉरीशस में सभी सरकारी वाहनों के लिए ईंधन की आपूर्ति के लिए संविदा प्राप्त की।

मॉरीशस ने मॉरीशस से भारत तथा भारत से मॉरीशस में विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करके आईटीईसी के महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाना जारी रखा। वर्ष 2010-2011 के दौरान मॉरीशस के लिए आईटीईसी के अंतर्गत प्रशिक्षण स्लॉटों को बढ़ाकर असैनिक पाठ्यक्रमों के लिए 125 तथा रक्षा पाठ्यक्रमों के लिए 46 कर दिया गया है। अब तक आईटीईसी कार्यक्रमों के अंतर्गत 79 असैनिक प्रशिक्षणार्थियों तथा 22 रक्षा प्रशिक्षणार्थियों इन ने पाठ्यक्रमों में भाग लिया। वर्ष के दौरान आईसीसीआर तथा अन्य कई योजनाओं के अंतर्गत मॉरीशस के विद्यार्थियों को 97 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी।

करार

1 अगस्त 2010-जुलाई 2013 के दौरान मेसर्स मैंगलोर रिफाइनरिज एण्ड पेट्रोलियम द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए संविदा के नवीकरण से संबंधित करार पर 1 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।

2 भारत सरकार द्वारा मॉरीशस सरकार को अपतटीय निगरानी जहाजों की आपूर्ति के लिए अंतर्सरकारी करार पर 3 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।

3 मानकीकरण, जांच व गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा मॉरीशस के नेशनल कम्प्यूटर्स बोर्ड के बीच सूचना सुरक्षा में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर 3 जुलाई, 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे।

4 भारतीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र तथा मॉरीशस की मौसम सेवा के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर 3 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।

5 भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद तथा महात्मा गांधी संस्थान के बीच संस्कृत एवं भारतीय दर्शनशास्त्र की अतिथि पीठ की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर 3 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मोजाम्बिक

मोजाम्बिक के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ व मैत्रीपूर्ण बने रहे। 29 सितंबर-4 अक्तूबर 2010 को मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की सरकारी यात्रा से भारत और मोजाम्बिक के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायता मिली है। मोजाम्बियन पक्ष ने भारत द्वारा अवस्थापना, ऊर्जा व कृषि क्षेत्रों में 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला प्रदान करने की पेशकश की काफी सराहना की है। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने जुलाई 2010 में मोजाम्बिक की यात्रा की तथा मोजाम्बियन पक्ष के साथ व्यापक बातचीत की।

मोजाम्बिक के राष्ट्रपति अरमांडो गुएबजा के साथ 5 मंत्रियों और एक बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 29 सितंबर-4 अक्तूबर 2010 को भारत की सरकारी यात्रा की। भारत के प्रधानमंत्री ने मोजाम्बिक के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान तीन करारों अर्थात दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए), खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने 2013 तक द्विपक्षीय व्यापार में 1 बिलियन अमरीकी डालर तक वृद्धि करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।

विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4-5 जुलाई, 2010 को मोजाम्बिक की यात्रा की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति गुएबुजा तथा प्रधानमंत्री आयरेस अली से मुलाकात की। उन्होंने विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री ओल्डीमिरो बालोई के साथ अलग से तथा प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत की तथा साझा हित के द्विपक्षीय एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की। भारत सरकार द्वारा प्रदान 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला के संबंध में एक्जिम बैंक व मोजाम्बिक सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह ऋण श्रृंखला ग्रामीण विद्युतिकरण परियोजना के लिए है। विदेश मंत्री ने मोजाम्बिक में कोयला क्षेत्र में एक प्रशिक्षण संस्थान तथा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता तथा स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा भी की। विदेश मंत्री ने मोजाम्बिक सहित 12 अफ्रीकी देशों में 16 अगस्त, 2010 को अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।

पश्चिमी बेड़े से आईएनएस मैसूर, आईएनएस तबर, आईएनएस आदित्य तथा आईएनएस गंगा नामक चार नौसैनिक जहाजों ने 5-8 सितंबर, 2010 को मपूतो की यात्रा की।

नामीबिया

वर्ष 2010 में भारत-नामीबिया द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ व मजबूत हुए। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने 21 सदस्यीय सीआईआई प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी 2010 पर 13वें सीआईआई, एक्जिम बैंक कनक्लेव के संबंध में जुलाई 2010 में नामीबिया की यात्रा की। विगत में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय यात्राएं सौहार्दपूर्ण व प्रगाढ़ संबंधों के दिए गए महत्व व मूल्यों को दर्शाती हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा कम है, फिर भी इसमें सतत रूप से वृद्धि हुई है। नामीबिया ने स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल तथा अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्टीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है, कई संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत का समर्थन किया है तथा विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। नामीबिया ने 2011-2012 में अस्थायी सीट के लिए भारत के सफल निर्वाचन का भी समर्थन किया था।

नामीबिया के राष्ट्रपति हिफिकेपुनिये ने 16-17 अगस्त, 2010 को आयोजित 30वें दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) जुबली सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एमएडीसी) के निवर्तमान अध्यक्ष, डी आर कांगो के राष्ट्रपति जोजक काबिला से इसकी अध्यक्षता भी ग्रहण की है।

रवाण्डा

भारत तथा रवाण्डा के बीच संबंध प्रगाढ़ व सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

रवाण्डा नेशनल बैलेट 'उरुकेरेज्जा' से 11 कलाकारों ने नई दिल्ली में अफ्रीकी महोत्सव में भाग लेने के लिए 18-20 मई, 2010 को भारत की यात्रा की।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने स्कूल ऑफ एण्ड बैंकिंग फाइनेंस के सहयोग से 16-26 नवंबर, 2010 के दौरान किगाली में 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रवाण्डा के विभिन्न संस्थानों से 35 सहभागियों ने भाग लिया।

रवाण्डा के निजी क्षेत्र फाउण्डेशन ने अक्तूबर 2010 में फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कर्नाटक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन तथा ऑल इण्डिया ग्रेनाइट एण्ड स्टोन एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सेशल्स

श्री विवेक काटजू, सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 7वें भारत सेशल्स संयुक्त आयोग की बैठक के लिए 10-12 मई, 2010 को सेशल्स की यात्रा की। भारत सरकार द्वारा एक्जिम बैंक के माध्यम से 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला प्रदान करने से संबंधित करार पर 11 मई, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।

राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स माइकल ने 1-3 जून, 2010 को भारत की सरकारी यात्रा की तथा राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय सहयोग तथा साझा हित के अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील को सेशल्स यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया। राष्ट्रपति माइकल ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए सेशल्स का समर्थन व्यक्त किया। भारत तथा सेशल्स के बीच द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा व संवर्धन करार पर 2 जून, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 5-6 जुलाई, 2010 को सेशल्स की यात्रा की तथा द्विपक्षीय सहयोग, हिन्द महासागर में सुरक्षा हित, जलदस्युता के विरुद्ध लड़ाई तथा आर्थिक विकास पर विचार-विमर्श किया।

रक्षामंत्री श्री ए के एंटोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स माइकल की भारत यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 18-20 जुलाई, 2010 को सेशल्स की यात्रा की। 19 जुलाई, 2010 को सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई थी कि सरकार निगरानी को बढ़ावा देने के लिए सेशल्स को तीन विमानों (एक डोर्नियर व 2 चेतक) का योगदान देगा। राष्ट्रपति माइकल ने इस संभावना प्रदर्शन की सराहना की।

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के राजनैतिक संघर्ष तथा एएनसी के नेतृत्व में रंगभेद नीति के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्पष्ट समर्थन से शुरू हमारे ऐतिहासिक अनुबंध तय सम्पर्कों पर आधारित है। 1994 के बाद, महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय यात्राओं की श्रृंखलाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे के विचारों की सराहना द्वारा प्रदर्शित अंतर्राष्ट्रीय संबंध भली-भांति विकसित हुए हैं जो कि आईवीएसए संरचना के माध्यम से और सुदृढ़ हुए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री जैकब जी. जुमा ने 2-5 जून, 2010 को भारत की सरकारी यात्रा की। राष्ट्रपति जुमा के प्रतिनिधिमंडल में उनके मंत्रिमंडल के सात मंत्री तथा 200 सदस्यों का विशाल प्रतिनिधिमंडल शामिल था। इस यात्रा के दौरान कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, वायु सेवा करार तथा भारत के विदेश सेवा संस्थान तथादक्षिण अफ्रीका की राजनयिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2012 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

स्वाजीलैण्ड

लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार के साथ लोक सभा महासचिव श्री पी. डी. टी. अचारी तथा लोकसभा सचिवालय के

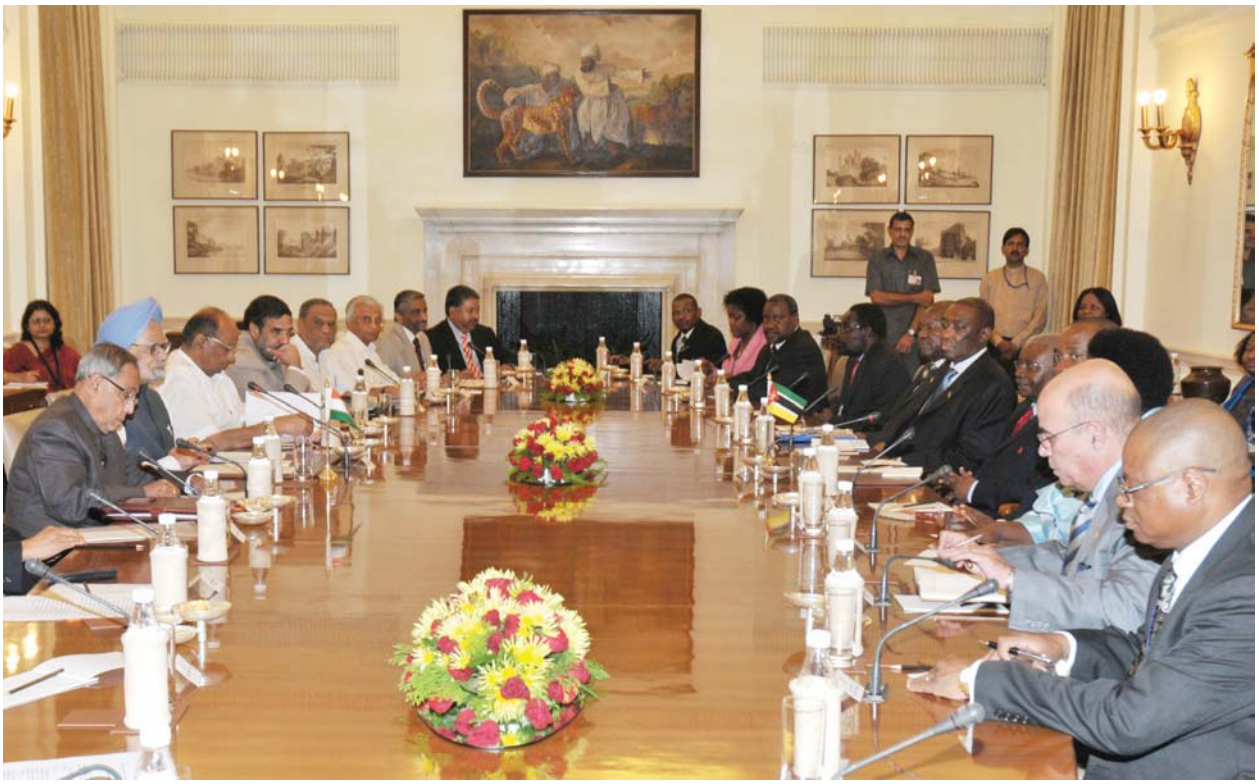

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और मोजांबिक के राष्ट्रपति श्री अर्मांडो इमिलो गुबेजा 30 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के दौरान।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सेशल्स के राष्ट्रपति श्री जेम्स एलिक्स माइकेल के साथ 2 जून, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित हस्ताक्षर समारोह में।

तीन अधिकारियों ने 8-13 मई, 2010 को स्वाजीलैण्ड में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (पीपीए) की मध्यवर्षीय कार्यपालक बैठक में भाग लेने के लिए स्वाजीलैण्ड की यात्रा की। सीपीए बैठक में भाग लेने के अलावा अध्यक्ष महोदया ने स्वाजी सम्राट मसबाती III से भेट की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री बर्नाबस सिबुसियो दलामिनी के साथ बैठक की तथा सीनेट के अध्यक्ष और नैशनल असेम्बली के स्पीकर व संसद के कई सदस्यों से बातचीत की।

टेलिकम्यूनिकेशन कंसलटेंटस इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ने स्वाजीलैण्ड में पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना स्थापित करने के लिए स्वाजीलैण्ड सरकार के साथ करार पर हस्ताक्षर किए।

तंजानिया

तंजानिया के साथ भारत के संबंध पारम्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक रहे हैं, जो और भी व्यापक एवं सुदृढ़ हुए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान तंजानिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बल मिला। तंजानिया ने संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से अस्थाई सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की उम्मीदवारी को समर्थन देकर हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता प्रदर्शित की है। भारत तंजानिया के आयातों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। क्षमता निर्णाण के क्षेत्र में सहयोग भी और प्रबलित हुआ। आईटीईसी तथा छात्रवृत्ति, जिसके लिए तंजानिया सबसे बड़े लाभार्थियों में एक है, के अंतर्गत प्रशिक्षण के अलावा 19 भारतीय प्रोफेसरों ने डोडामा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। तंजानिया के 16 पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध के संबंध में भारत में प्रशिक्षण दिया गया था। एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र भी स्थापित किया गया।

आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में सतत विकास होता रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट के बाद विदेश व्यापार में मंदी की स्थिति के बावजूद तंजानिया के साथ भारत का व्यापार 965 मिलियन अमरीकी डालर था जिससे भारत को तंजानिया के आयातों के सबसे बड़े स्रोत का दर्जा मिला। तंजानिया में भारतीय निवेश में भी वृद्धि होती रही, जोकि वर्ष 2009 तक 1.32 बिलियन अमरीकी डालर था, जिससे भारत को तंजानिया में दूसरे सबसे बड़े निवेशक का दर्जा मिला। फार्मेकसिल, कैपेक्सिल तथा एचसीजी हैल्थ ग्लोबल - चिकित्सा दल (दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा कैंसर देखरेख नेटवर्क) सहित कई निर्यात संवर्धन परिषदों ने तंजानिया की यात्रा की। इसी प्रकार तंजानिया ने भारत में आयोजित क्रेता-विक्रेता भेट में भी प्रतिनिधित्व किया।

भारत ने अक्तूबर 2010 में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले तंजानियाई राष्ट्रमंडल दल को खेल उपस्करों व मदों का उपहार भी दिया।

राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान तंजानिया के सूचना, खेल व संस्कृति मंत्री ने भारत की यात्रा की तथा राष्ट्रमण्डल खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

तंजानिया सरकार की 'किलिमो क्वांजा' पहल के लिए भारत का समर्थन प्रदर्शित करते हुए आईटीपीओ के तत्वावधान में 30 भारतीय कंपनियों ने दार-ए-स्लाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया।

रक्षा सहयोग के क्षेत्र में मेजर जनरल मकाकला के नेतृत्व में तंजानिया जन सुरक्षा बल से एक प्रतिनिधिमंडल ने हमारे अनुभवों का अध्ययन करने के लिए सितंबर 2010 में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की यात्रा की क्योंकि तंजानिया स्वयं अपना राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है। रियर एडमिरल आर के पटनायक वाई एस एम की कमान में चार भारतीय नौसैनिक जहाजों ने 28-31 अगस्त, 2010 को दार-ए-स्लाम की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत नौसेना ब्रास बैण्ड ने एक स्कूल में प्रस्तुतिकरण किया तथा अपने तंजानियाई समकक्षियों के साथ तकनीकी आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों की नौसैनिकों ने तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया।

उगाण्डा

उगाण्डा के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ व मैत्रीपूर्ण बने रहे। वर्ष के दौरान निम्नलिखित उच्चस्तरीय यात्राएं हुईं:

मई 2010 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कम्पाला में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया। देश के विभिन्न भागों से लिए गए 60 से अधिक सहभागियों ने इसमें भाग लिया। उगाण्डा के अधिकारियों के साथ-साथ सहभागी भी पाठ्यक्रमों से बहुत ही संतुष्ट थे।

मई 2010 में भारतीय कपास प्रतिनिधिमंडल ने कपास की खेती व प्रसंस्करण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग संवर्धित करने के लिए उगाण्डा की यात्रा की।

सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में भारतीय पर्यवेक्षक प्रतिनिधिमंडल ने 22-23 जुलाई, 2010 को एयू परिषद की बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय मुद्दों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के संबंध में 10 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें भी कीं।

उगाण्डा के संसदीय सेवा आयोग से 5 संसद सदस्यों ने लोक सभा सचिवालय के आमंत्रण पर तीन दिवसीय अध्ययन दौरे पर अप्रैल 2010 में नई दिल्ली की यात्रा की।

तृतीय उप प्रधानमंत्री एवं आंतरिक कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस बलों के आवास के लिए निजी क्षेत्र सहभागियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विपणण एवं संवर्धन पहल के संबंध में 19-21 जुलाई, 2010 को भारत की यात्रा की।

वित्त, नियोजन व आर्थिक विकास राज्य मंत्री ने श्री कजारा एस्टन पीटर्सन ने 14-16 जुलाई, 2010 को भारत में भिन्नों मैरीन प्रोजेक्ट लि. का दौरा किया।

सरकार के मुख्य सचेतक श्री दाऊदी माइग्रको के नेतृत्व में युगाण्डा संसद के 7 सदस्यों ने 24-31 जुलाई, 2010 को लोक सभा सचिवालय के अध्ययन दौरे पर नई दिल्ली की यात्रा की।

कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री सुश्री हाप वेस्गी ने टाटा सोलर एण्ड हिमालया नैचुरल हर्बल फार्मास्युटिकल्स समूह के साथ बैठक में भाग लेने के लिए 6-10 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली की यात्रा की।

ऊर्जा व खनिज विकास राज्य मंत्री श्री साइमन डी उजांगा ने पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन व पैट्रोटेक-2010 में भाग लेने के लिए 27-30 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली की यात्रा की।

जाम्बिया

जाम्बिया से सरकारी-गैर सरकारी सहभागिता (पीपीपी) प्रतिनिधिमंडल ने 28 जुलाई, 2010 को भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल में वित्त व राष्ट्रीय नियोजन उप मंत्री, श्री डेविड फिरी, वाणिज्य, संचार, कार्य व आपूर्ति, कृषि मंत्रालयों तथा जाम्बिया विकास एजेंसी के अधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने सचिव (पश्चिम) से बैठक की। उन्होंने एक संगोष्ठी भी आयोजित की, जिनका उद्घाटन जाम्बिया के शिक्षा मंत्री डोरा सिल्विया ने किया, जोकि पहले से भारत में थे।

किब्बे में मुलुवंशी विश्वविद्यालय में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 16 अगस्त, 2010 को जाम्बिया के लिए पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया था।

भारती एयरटेल ने 22 नवंबर, 2010 को जाम्बिया में एयरटेल जाम्बिया नामक अपना नया ब्राण्ड शुरू किया। एयरटेल के अध्यक्ष श्री सुनील मित्तल ने लुसाका में 22 नवंबर, 2010 को आयोजित प्रेस सम्मेलन में इसकी घोषणा की।

जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध सदैव प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत ने उनके स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया है तथा यह 1980 में इसकी स्वतंत्रता से ही जिम्बाब्वे के विकास में सहभागी रहा है। भारत ने दूर-संचार, विद्युत, परिवहन क्षेत्रों में जिम्बाब्वे की सहायता की तथा आईटीईसी कार्यक्रमों के माध्यम से इसके क्षमता निर्माण में सहायता की।

भारत तथा जिम्बाब्वे अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान विचार रखते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विश्व व्यापार संगठन व जी-15 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर निकट सहयोग करते हैं। जिम्बाब्वे सामान्यतः बहुपक्षीय मंचों पर अधिकांश चुनावों में और संयुक्त राष्ट्र में हमारे संकल्पों का समर्थन करता है। इस वर्ष के दौरान जिम्बाब्वे ने प्रशासनिक एवं बजटगत मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के चुनाव में भारत के उम्मीदवार का समर्थन किया। जिम्बाब्वे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए हमारी उम्मीदवारी का समर्थन भी किया।

पश्चिम अफ्रीका प्रभाग

अंगोला

पेट्रोलियम मंत्री जोस मारिया बोटेलहो डी वास्कोनसिलास ने 1-3 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित पेट्रोटेक, 2010 सम्मेलन में भाग लिया। तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग संवर्धित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर 1 नवंबर, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।

अंगोला के दूर-संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पैन-अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना के बारे में जानकारी हासिल करने तथा ई-शासन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ आदान-प्रदान करने के लिए 5-9 दिसंबर को भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्र ई-शासन के कार्यान्व्यन की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए भोपाल व इंदौर में सामान्य सेवा केन्द्र का दौरा भी किया।

भारतीय तेल क्षेत्र से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 12-14 सितंबर को अंगोला में रिफाइनरी परियोजना का दौरा किया। एमएमटीसी से एक 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 23-24 नवंबर को स्टेट डायमण्ड कंपनी, एण्डीआमा का दौरा किया।

भारत सरकार ने (i) औद्योगिक विकास पार्क (30 मिलियन अमरीकी डालर) तथा (ii) कॉटन स्पिनिंग एण्ड गिनिंग मिल (15 मिलियन अमरीकी डालर) स्थापित करने के लिए दो ऋण श्रृंखलाओं का अनुमोदन किया।

बेनिन

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने अनुदान के रूप में 60 एम्बुलेंस, 310 कम्प्यूटर व अनुषंगी कलपुर्जे तथा 4 वातानुकूलित बसें भेजी। बेनिन ने जुलाई में भारत में अपना आवासीय मिशन खोला तथा राजदूत एण्ड्रे सार्ना ने 18 अक्तूबर को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति बेनिन की ओर से की गई एक अपील के जवाब में भारत ने वहाँ आई बाढ़, जिससे देश के अधिकांश भाग ध्वस्त हो गए थे, के बाद पुनर्स्थापन प्रक्रिया में सहायता करने के लिए राहत सहायता के रूप में 5,00,000 मिलियन अमरीकी डालर का (दिसंबर 2010 में) नकद अनुदान भेजा।

कैमरून

भारत की ओर से एक राजस्थानी सांस्कृतिक मण्डली ने नवंबर में कैमरून में अपना प्रस्तुतिकरण दिया।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य

निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थेः

(i) बांगुई में आई टी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए (मार्च 2010)

(ii) होल इन द वाल शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 2 वर्क स्टेशन स्थापित करने के लिए (3 सितंबर)

(iii) विदेश कार्यालय परामर्श के लिए प्रोतोकाल (3 सितंबर)

चाड

चाड के विदेश राज्य मंत्री महामत बशीर ओकार्मी ने 4-8 सितंबर को भारत में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर के साथ सरकारी बातचीत की गई थी। विदेश कार्यालय परामर्श पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी)

भारत व डीआरसी के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन व सुरक्षा करार पर अप्रैल 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए 29-30 जून को किंशासा की यात्रा की। भारत सरकार ने काकाबोला जलविद्युत परियोजना तथा कारेण्डे जलविद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 42 मिलियन अमरीकी डालर तथा 168 मिलियन अमरीकी डालर की 2 ऋण श्रृंखलाएं अनुमोदित की। डीआरसी में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए 21 अक्तूबर, 2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नवंबर में निजी क्षेत्र की एक कंपनी काल्पा तास पावर ट्रांसमिशन लि. ने बास कांगो प्रान्त में 260 कि.मी. की दूरी तक विद्युत पारेषण लाइने स्थापित करने के लिए कांगलिय नेशनल इलैक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ 76.9 मिलियन अमरीकी डालर वाली संविदा पर हस्ताक्षर किए।

कांगो गणराज्य (आरओसी)

विदेश कार्य एवं सहयोग मंत्री श्री बेसिल इकोबे के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने 13-18 मार्च को भारत की यात्रा की। कांगलिज विदेश मत्री ने तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री डा. शशि थरूर के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के पूरा परिदृश्य शामिल था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार करने व उसे मजबूत बनाने के लिए विशेष क्षेत्रों की पहचान की। कांगो गणराज्य ने भारत को 2011-2012 की अवधि के लिए स्थायी सीट के लिए अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री डा. शशि थरूर तथा कांगो गणराज्य की ओर से विदेश कार्य एवं कारपोरेशन मंत्री श्री बेसाइल इकावे ने 17 मार्च को विदेश कार्यालय परामर्श से संबंधित प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए।

कांगो गणराज्य की प्रथम महिला मैडम एंटोनिटे ससोऊ एन गुएसो के साथ 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 22-27 नवंबर से रायपुर में सिकल सेल रोग पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया।

इक्वेटोरियल गिनी

इक्वेटोरियल गिनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने 22-27 नवंबर से रायपुर में सिकल सेल रोग पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया।

गाम्बिया गणराज्य

गाम्बिया के विदेश मंत्री डा. मामादऊ तंगारा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने 17-21 अगस्त को भारत की सरकारी यात्रा की। विदेश राज्य मत्री श्रीमती प्रनीत कौर के साथ 19 अगस्त को सरकारी स्तर पर बातचीत की गई। विदेश राज्य मंत्री (पी.के.) ने शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए 5,00,000 अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की। उन्होंने गाम्बिया में एक होल इन वाल वर्क स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत की पेशकश की। इस यात्रा के दौरान विदेश कार्यालय परामर्श पर एक प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए।

देश में अभूतपूर्व बारिश तथा उसके परिणामस्वरूप बाढ़ की स्थिति तथा अवस्थापना की क्षति के बाद बाढ़ राहत के रूप में 50,000 अमरीकी डालर की नकद सहायता दी गई।

घाना

घाना के उप-शिक्षा मंत्री डा. जोसेफ अन्नान ने 28 मार्च–4 अप्रैल 2010 तक भारत की यात्रा की। डा. अन्नान ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी तथा विदेश राज्य मंत्री डा. शशि थरूर से विचार-विमर्श किया। डा. अनान ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. तथा इंदिरा गांधी नैशनल ओपन युनिवर्सिटी के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

घाना में 1 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश से गैस आधारित उर्वरक संयंत्र संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रारंभिक समझौता ज्ञापन पर 6 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना द्वारा एक मिलियन टन यूरिया उत्पादन करने का अनुमान है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 2-3 सितंबर को अकरा की यात्रा की, जहां संयुक्त व्यापार समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी।

घाना के थल सेनाध्यक्ष मेजर जनरल जोसेफ नार आदिनकरा ने 28 जून-1 जुलाई को भारत की यात्रा की।

गिनी बिसाऊ

गिनी बिसाऊ को दवाइयों और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की आकस्मिक खरीद के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर की नकद अनुदान प्रदान किया गया था।

लाइबेरिया

अफ्रीकी देशों की सहायता करने के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत लाइबेरिया को उपहारस्वरूप 25 बसें भेजी गई थीं। जुलाई में 2 कार्य स्टेशनों के साथ होल इन दी वाल

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

माली

माली ने अपना आवासीय मिशन खोला तथा इसके राजदूत श्री ओसमानी तान्दिया ने 29 सितंबर को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया। कृषि मंत्री श्री अघातम एजी अलहसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 9-17 दिसंबर को विश्व के किसानों तथा हरित विकास सम्मेलन में भाग लिया।

मॉरीतानिया

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान 24 सितंबर को मॉरीतानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मॉरीतानिया के कृषि विकास के लिए भारतीय विशेषज्ञता की पेशकश की। मॉरीतानिया नई दिल्ली में अपना आवासीय मिशन खोलने की संभावना का पता लगा रहा है।

नाइजीरिया

कारपोरेट कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने नाइजीरिया की स्वतंत्रता की वर्षगांठ समारोह (30 सितंबर-2 अक्तूबर) में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया।

एक राजस्थानी लोकनृत्य मंडली ने नवंबर 2010 में नाइजीरिया की यात्रा की तथा अबूजा कार्निवल में प्रस्तुतिकरण दिया।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आठवें ई-9 मंत्रालयी समीक्षा बैठक (22-23 जून) में भाग लेने के लिए अबूजा की यात्रा की।

सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री प्रो. एम. के. अबुबाकर के नेतृत्व में एक नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल ने बंगलुरु स्पेस एक्सपो (25-28 अगस्त) में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

पेट्रोलियम मामलों पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार डा. इमैनुअल इग्बोगा ने नई दिल्ली में आयोजित पेट्रोटेक-2010 में नाइजीरिया प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के रूप में नवंबर में भारत की यात्रा की तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात की।

अन्य कंपनियों के अलावा रिलाइन्स, एस्सार व अदानी से प्रतिनिधियों को शामिल करके सीआईआई, गुजरात से 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 21-25 अगस्त के दौरान नाइजीरिया की यात्रा की।

कैपेक्सिल के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 7-9 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा की।

भारत सरकार ने नाइजीरिया में विद्युत परियोजनाओं के लिए सितंबर 2010 में 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला अनुमोदित की।

नाइजीरिया के खेल मंत्रालय के नेतृत्व में 104 सदस्यों वाले सशक्त नाइजीरियाई दल ने अक्तूबर में नई दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमण्डल खेलों में भाग लिया।

नाइजर

नाइजर में भारत के प्रथम आवासीय राजदूत ने 12 अक्तूबर को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया।

अगस्त 2010 में नाइजर सरकार को बाढ़ संकट से निपटने के लिए राहत सहायता के रूप में 1,00,000 अमरीकी डालर की नकद सहायता दी गई थी।

साओ तोम एण्ड प्रिंसिपे

भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 10 मिलियन ₹ के शिक्षा उपस्करों व दवाओं की आपूर्ति की गई थी।

टोगो

टोगो ने अक्तूबर 2010 में नई दिल्ली में अपना आवासीय मिशन खोला।

भारत सरकार ने (i) ग्रामीण विद्युतीकरण तथा (ii) खेती के यांत्रिकीकरण व फसलों की खेती के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर की एक-एक ऋण श्रृंखला का अनुदान किया।

अफ्रीकी संघ (एयू)

सचिव (पश्चिम) ने जुलाई 2010 में कम्पाला में आयोजित अफ्रीकी संघ सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने एयू आयोग के अध्यक्ष सहित उगाण्डा, तंजानिया, मालावी, चाड, इक्वेटोरियल गिनी, नाइजर, अंगोला, कोट डी आइवरी और गैबोन व इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की।

पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना की संचालन समिति की 7वीं बैठक 19-20 मई, 2010 को अदिस अबाबा में आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के राजदूत, जो अफ्रीकी संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी हैं तथा अफ्रीकी संघ के अवस्थापना कार्य आयुक्त डा. एल्हाम एम ए इब्राहिम ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डा. औसिक सैय्यद, संयुक्त सचिव (द. अफ्रीका) ने की, जिनके साथ टीसीआईएल, इगनऊ, एमिटि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि थे। 22 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया।

भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन की कार्ययोजना के अंतर्गत अफ्रीकी संघ ने 75 छात्रों के प्रथम बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किए,

जिन्हें कृषि व संबंधित क्षेत्रों में अपने उच्चाध्ययन एमएससी व पीएचडी जारी रखने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति पर भारत भेजा जाना था। अफ्रीकी संघ ने सी वी रमन छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए तथा 85 व्यक्तियों का चयन किया गया था।

भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन (आईएएफएस)

ऐतिहासिक संबंधों को सुरक्षित रखते हुए अफ्रीका के साथ हमारे संबंध विकास प्रक्रिया, विशेष रूप से क्षमता निर्माण, अवस्थापना विकास व व्यापार संवर्धन के क्षेत्र में अफ्रीकी आवश्यकताओं के आधार पर 21वीं सदी में निकट आर्थिक सहयोग शामिल करके और सुदृढ़ हुए हैं। अप्रैल 2009 में भारत ने प्रथम भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन (आईएएफएस) की मेजबानी की। इस सम्मेलन में भारत व अफ्रीका के बीच विद्यमान ऐतिहासिक संबंधों की आधारशिला का निर्माण हुआ तथा भारत व अफ्रीकी सहभागियों के बीच निर्धारित कार्यकलापों, आदान-प्रदान तथा सहयोग के लिए नया ढांचा का अभिकल्पन किया गया था। वर्ष 2008 में आयोजित सम्मेलन के अंत में पारित दिल्ली घोषणा तथा भारत-अफ्रीका अवसंरचना सहयोग अब आगामी वर्षों में अफ्रीका के साथ हमारे व्यवस्थित संबंधों की रूपरेखा के रूप में है। आईएएस ने महाद्वीपीय, क्षेत्रीय व द्विपक्षीय स्तरों पर आर्थिक सहयोग के लिए बहुआयामी प्रतिमान सृजित किए हैं।

आईएएफएस के निणर्यों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अफ्रीकी संघ ने भारत द्वारा अफ्रीका में 21 संस्थान स्थापित करने के लिए स्थानों को अंतिम रूप दे दिया है, जिनमें (i) भारत-अफ्रीका विदेश व्यापार संस्थान (ii) भारत-अफ्रीका हीरा संस्थान (iii) भारत-अफ्रीका शिक्षा नियोजन व प्रशासन संस्थान तथा (iv) भारत-अफ्रीका सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं।

स्थापित किए जाने वाले अन्य संस्थानों में 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कम लागत पर आवास प्रौद्योगिकी में सहायता करने वाले 5 मानव पुनर्वास संस्थान तथा 2 कोयला संस्थान शामिल हैं।

आईएएफएस के निर्णयों के बाद अफ्रीकी देशों के सहभागियों को वर्ष 2010-2011 के दौरान सी वी रमन छात्रवृत्ति के अंतर्गत 85 वैज्ञानिक छात्रवृत्तियां, 71 विशेष कृषि संबंधी छात्रवृत्तियां तथा 469 अल्पावधिक प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान किए गए थे।

वर्ष के दौरान भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन के निर्णयों के कार्यान्वयन के अंतर्गत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 239 सहभागियों के लिए 7 अफ्रीकी देशों अर्थात अंगोला, बोत्सवाना, नामिबीया, रवाण्डा, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका व उगाण्डा में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार' पर कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी सहभागियों द्वारा काफी सराहना की गई।

शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना के अंतर्गत 33 अफ्रीकी अल्प विकसित देशों में वे 18 देश पहले से ही इस योजना में शामिल हैं।

पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना

भारत द्वारा शुरू की गई एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना 53 अफ्रीकी देशों के लिए पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना थी। 47 अफ्रीकी देशों ने पहले ही करार पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा अब तक 34 देशों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा चुकी है। शेष 13 देश को उतरोत्तर इसके अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा।

यह परियोजना दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण था तथा अफ्रीकी संघ ने इसका उल्लेख हमारे सहयोग के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में किया है। पैन-ई अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत भारत अफ्रीका 53 राष्ट्रों को उपग्रह संपर्क, दूर-चिकित्सा व दूर शिक्षा प्रदान करने के लिए फाइबर-आपदिक नेटवर्क स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। भारत सरकार का एक उपक्रम, टीसीआईएल भारत सरकार की ओर से परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 16 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, जिसमें 12 देश शामिल थे। इन 12 देशों में बोत्सवाना, बुरुण्डी, कोर्ट डी आइवरी, जिबूती, मिस्र, इरीट्रिया, लिबिया, मालावी, मोजाम्बिक, सोमालिया, उगाण्डा तथा जाम्बिया शामिल थे। उद्घाटन के दौरान विदेश मंत्री ने नेटवर्क के माध्यम से 12 देशों के एक-एक वरिष्ठ मंत्री/प्रतिष्ठित व्यक्तियों से ऑनलाइन आदान-प्रदान किया। 11 देशों के लिए पहले चरण का उद्घाटन फरवरी 2009 में किया गया था।

आरईसी बैठक

भारत व अफ्रीका के बीच सतत संपर्क के भाग के रूप में तथा क्षेत्रीय स्तर पर संस्थागत आधार पर आईएएफएस के अंतर्गत हमारी प्रतिबद्धता की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारत व अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय (आरईसी) के बीच सर्वप्रथम बैठक 14-16 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अफ्रीकी संघ द्वारा मान्यता प्राप्त 8 क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों में से 6 समुदायों ने महासचिव अथवा अध्यक्ष स्तर पर भाग लिया। क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय से हमें अफ्रीका में क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के साथ नए संबंधों का निर्माण करने का अवसर मिला है।

पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा)

भारत ने फरवरी 2003 में कोमेसा के साथ दीर्घावधिक आर्थिक व तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत व अफ्रीका के बीच संस्थागत आधार पर सतत सम्पर्क के भाग के रूप में कामेसा सहित भारत-अफ्रीकी क्षेत्रीय समुदायों की सर्वप्रथम बैठक 14-16 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कामेसा के महासचिव ने इस बैठक में भाग लिया। कोमेसा नियमित आधार पर वार्ता में तेजी लाने तथा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए तत्पर है।

मानकों व कानूनों के एकीकरण के लिए अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के आंदोलन और साझा बाजार सृजित करने का भारत के व्यापार व निवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों की बैठक के दौरान भारतीय निवेशकों और उद्यमियों के कई वर्गों ने उनके देशों में अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कोमेसा राज्यों के व्यापक एकीकरण से भारतीय कंपनियों को कोमेसा द्वारा प्रवर्तित अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं में भाग लेने व इन देशों में वस्तुओं के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने तथा कोमेसा व सहारा के आस-पास स्थित अफ्रीकी राज्यों को निर्यात करने में सहायता मिलेगी। भारत-कोमेसा सहयोग कार्यक्रम में जैव-प्रौद्योगिकी, दूर-संचार परियोजना, बैंकिंग, कृषि, उर्वरक तथा सिंचाई से संबंधित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

पूर्व अफ्रीकी समुदाय (ईएसी)

पूर्व अफ्रीका समुदाय के महासचिव, राजदूत जुमा मवापाचू ने विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के महासचिवों की बैठक में भाग लेने के लिए 13-16 नवंबर, 2010 को भारत की यात्रा की। पूर्व अफ्रीकी समुदायों के महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत-पूर्व अफ्रीकी समुदाय सहयोग कार्यक्रमों के साथ-साथ भावी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई थी।

दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय (एसएडीसी)

भारत-एसएडीसी मंच की प्रथम बैठक 28 अप्रैल, 2006 को विंडहाक, नामीबिया में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री ने जुलाई 2008 में एसएडीसी सचिवालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए एक्जिम बैंक के माध्यम से 29.22 मिलियन अमरीकी डालर की रियायती ऋण श्रृंखला के प्रस्तावों का अनुमोदन कियाः छोटे स्तर के किसानों के लिए क्षेत्रीय सिंचाई व जल प्रबंधन पर जोर देते हुए शुष्क भूमि कृषि परियोजना, लघु व सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रदर्शन केन्द्र, विज्ञान व प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों (एसटीईपी) का अध्ययन, एसएडीसी में कांगो तट से जल दुलर्भ देशों को जल का हस्तांतरण। एसएडीसी सचिवालय इन परियोजनाओं पर विचार कर रहा है।

आईएएफएस के निर्णयों के अंतर्गत भारत ने एसएडीसी क्षेत्र में दो संस्थानों अर्थात शीर्ष नियोजन संगठन तथा शीर्ष प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया।

भारत तथा अफ्रीका के बीच संस्थागत आधार पर सतत संपर्कों के भाग के रूप में कोमेसा सहित भारत व अफ्रीकी आर्थिक विकास समुदायों के बीच प्रथम बैठक 14-16 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका विकास समुदायों के उप-कार्यपालक सचिव ने भाग लिया। एसएडीसी नियमित आधार पर वार्ता में तेजी लाने तथा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए तत्पर है।

इकोवास

भारत सरकार ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदायों के सदस्य देशों में अवस्थापना विकास परियोजनाएं चलाने के लिए इकोवास निवेश एवं विकास बैंक को 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला (जिसका संवितरण दो किश्तों अर्थात 100 मिलियन अमरीकी डालर तथा 150 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में किया जाएगा) का अनुमोदन किया।

इकोवास आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार द्वारा अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के साथ 15-17 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया।

■■

7 यूरोप और यूरोपीय यूनियन

मध्य यूरोप

अलबानिया

वर्ष के दौरान अलबानिया ने भारत में अपने प्रतिनिधित्व का राजदूत के स्तर तक उन्नयन किया तथा भारत में प्रथम अलबेनियाई राजदूत, श्री फातोस केरकिकु ने 18 अक्तूबर, 2010 को भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किया।

राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर अध्यक्षा श्रीमती जोजेफिना कोबा तोपाली के नेतृत्व में एक अलबेनियाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने मदर टेरेसा की 100वीं जन्म वर्षगांठ मनाने के लिए 18-22 दिसम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की। अलबेनियाई प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उप सभापति तथा विदेश राज्य मंत्री के साथ बैठकें की। अलबानिया के साथ यह प्रथम संसदीय विनिमय था।

आस्ट्रिया

भारत और आस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंध जोकि मैत्रीपूर्ण और सद्भावनापूर्ण थे, यात्राओं, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों तथा सांस्कृतिक दलों के आदान-प्रदान के जरिए वर्ष के दौरान और सुदृढ़ हुए। भारत और आस्ट्रिया ने 13 सितम्बर, 2010 को वियना में कृषि संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से आस्ट्रियाई आर्युवैदिक संघ तथा कैरीनथिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1-3 अक्तूबर, 2010 तक कलेगनफर्ट, आस्ट्रिया में आयुर्वेद पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री गांधीसेलवन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस कांग्रेस में भाग लिया। इस कांग्रेस ने यूरोप में संबंधित उत्पादों में व्यापार में वृद्धि करने के माध्यम के रूप में आयुर्वेद को विकसित करने के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध करवाया।

श्री एम. आर. के. पनीरसेलवम, स्वास्थ्य मंत्री, तमिलनाडु सरकार ने 18-23 जुलाई, 2010 तक वियना में XVIII अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में भाग लिया। श्री विनोद राय, भारत के नियत्रंक और महालेखा परीक्षक ने सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित 'लोक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने हेतु पायलट सम्मेलन' में भाग लेने के लिए 26-28 मई, 2010 तक आस्ट्रिया की यात्रा की। श्री तुलसी राम शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा श्री टांका बहादुर राय, अध्यक्ष, असम विधान सभा ने श्रीमती प्रणति फुकन, उपाध्यक्ष के साथ 56वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ पश्च-सम्मेलन अध्ययन भ्रमण करने के लिए 23-25 सितम्बर, 2010 तक वियना की यात्रा की।

भारत-आस्ट्रिया विदेश कार्यालय परामर्श के वियना में फरवरी 2011 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

बोसनिया और हरजेगोविना

भारत-बोसनिया संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। संचार और परिवहन मंत्री श्री रूडो विदोविक ने मई 2010 में भारत की यात्रा की तथा वायु सेवा करार पर हस्ताक्षर किए। प्रतिनिधिमंडल ने टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज तथा एन.आई.आई.टी की सुविधाओं का भी अवलोकन किया। मई 2010 में भारत-बोसनिया और हरजेगोविना मैत्री समिति का गठन किया गया।

बुलगारिया

वर्ष के दौरान भारत और बुलगारिया के बीच परम्परागत रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध निरन्तर बने रहे। आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-बुलगारिया संयुक्त आयोग का 16 वां सत्र 8-9 अप्रैल, 2010 तक सोफिया में आयोजित किया गया। संयुक्त आयोग ने खाद्य, वस्त्र, चमड़े, औषधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एस.एम.ई., उर्जा विशेषकर नई और नवीकरणीय उर्जा, इंजीनियरी वस्तुओं और पर्यटन, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि करने के लिए सहयोग पर चर्चा की। भारतीय पक्ष से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री तथा बुलगारियाई पक्ष से अर्थव्यवस्था, उर्जा और पर्यटन मंत्री श्री ट्रेचो ट्रेकोव द्वारा सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकीयों संबंधी बुलगारिया-भारत संयुक्त मंच की चौथी बैठक सोफिया में 14-15 जून को आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राकेश सिंह, अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा बुलगारियाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व परवन रूसीनोव, परिवहन उप मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार द्वारा किया गया। दोनों पक्षों ने आई.सी.टी. में संभावना को मान्यता प्रदान की, क्षेत्रों का पता लगाने के लिए

सहमति प्रकट की तथा आई.सी.टी क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु चर्चा आयोजित की।

भारत-बुलगारिया रक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त समिति की 15वीं बैठक 21-22 अक्तूबर, 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बुलगारियाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री एवगेनी एनगेलोव, अर्थव्यवस्था, उर्जा और पर्यटन उप मंत्री तथा भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री आर. के. माथुर, अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया।

अक्तूबर 2010 में सोफिया में एक भारतीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया। बुलगारियाई दर्शकों के उत्साहवर्धक स्वागत में नौ भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

क्रोएशिया

वर्ष के दौरान, सक्रिय राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था के जरिए क्रोशिया के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए। क्रोशिया के राष्ट्रपति इवो जोसिपोविक के निमंत्रण पर 9-11 जून, 2010 को उप राष्ट्रपति श्री एम.हामिद अंसारी ने क्रोशिया की यात्रा की, जोकि भारत से ऐसी प्रथम उच्च स्तरीय यात्रा थी। उप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि मंडल में श्री सचिन पायलट, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा तीन संसद सदस्य शामिल थे। उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति जोसिपोविक, अध्यक्ष बेबिक तथा क्रोशिया में प्रधानमंत्री कोसोर के साथ मुलाकात की तथा जगरेब विश्वविद्यालय के भारतविद्या केन्द्र को 25 कम्प्यूटर तथा हिन्दी सॉफ्टवेयर उपहार में दिए। यात्रा के दौरान 2010-2012 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य और औषधि में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

6-10 मार्च, 2010 तक अध्यक्ष लुका बेबिक के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय क्रोशियाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा की। प्रतिनिधि मंडल ने लोक सभा की अध्यक्षा तथा विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की। चर्चा दोनों देशों के बीच संसंदीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित थी।

जगरेब स्थित भारतीय दूतावास ने मार्च 2010 में स्थानीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 'भारत के साथ व्यापार कैसे करें' शीर्षक पर व्यापार सेमिनार आयोजित किया। क्रोशियाई इकोनोमी, लेबर और इन्टर-प्रेनियोरशिप मंत्रालय तथा क्रोशियन चैम्बर ऑफ इकोनोमी के सहयोग से 2 नवम्बर, 2010 को जगरेब में निवेश प्रोत्साहन पर एक और सेमिनार आयोजित किया गया। मिशन के सहयोग से एक क्रोशियाई गैर-सरकारी संगठन ने 21-29 मई, 2010 तक जगरेब में 'भारतीय संस्कृति के दिवस' कार्यक्रम आयोजित किया।

साइप्रस

भारत और साइप्रस के बीच संबंध परम्परागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं तथा वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय सम्पर्क बनाए रखे गए। साइप्रस के वाणिज्य, उद्योग और पर्यटन मंत्री श्री एनटोनिस फैशिलिडस ने अक्तूबर 2010 में भारत में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने फिक्की, साइप्रस इंडिया व्यापारिक एसोसिएशन तथा साइप्रस निवेश प्रोत्साहन एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से 26 अक्तूबर, 2010 को दिल्ली में आयोजित व्यापार मंच को सम्बोधित किया। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा तथा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एवं पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। 28 अक्तूबर, 2010 को मुम्बई में एक अन्य व्यापारिक फोरम आयोजित किया गया।

भारत-साइप्रस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-11 जून, 2010 तक सुश्री सुकन्या रामगोपाल के नेतृत्व में एक 5-सदस्यीय कर्नाटक संगीत समूह ने साइप्रस की यात्रा की। शान्ति अनुसंधान संस्थान, ओसलो जिसका निकोसिया में एक केंद्र है, के निमत्रण पर 11-14 मई, 2010 तक रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने साइप्रस की यात्रा की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा के फरवरी 2011 में साइप्रस की यात्रा करने की सम्भावना है।

चैक गणराज्य

6-9 जून, 2010 तक उप राष्ट्रपति की चैक गणराज्य की यात्रा के साथ भारत तथा चैक गणराज्य के बीच वर्ष के दौरान द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हुए। उन्होंने चैक राष्ट्रपति श्री वाकलाव क्लास से मुलाकात की तथा प्रधानमंत्री श्री जान फिशर और सीनेट के राष्ट्रपति श्री प्रेमस्यल सोबोटका से भी मुलाकात की। यात्रा के दौरान तीन महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर किए गएः (I) सामाजिक सुरक्षा करार, (II) बीआईपीपीए करार संबंधी संशोधन पर प्रोतोकाल, तथा (III) आर्थिक सहयोग पर करार। सितम्बर 2010 में सचिव (संस्कृति) की प्रेग की यात्रा के दौरान दोनों देशों के संस्कृति मंत्रालयों के बीच वर्ष 2010-2012 हेतु सहयोग के द्विपक्षीय कार्यक्रम पर आद्याक्षर किए गए।

चैक उद्योग और व्यापार उप मंत्री श्री मिलन होवोर्का ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बैठक में भाग लेने के लिए मई 2010 में तथा दुबारा दिसम्बर 2010 में 8 वें संयुक्त आर्थिक आयोग की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत की यात्रा की। दोनों अवसरों पर चैक उपमंत्री ने विभिन्न भारतीय मंत्रियों से बैठकें कीं।

डेनमार्क

डेनिस उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री सुश्री लेने एस्पर्सन ने भारत-डेनिस संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 14-15 दिसम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा से मुलाकात करने के अलावा उन्होंने वाणिज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की। भारतीय व्यापारिक भागीदारों

के साथ अवसरों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए डेनिश विदेश मंत्री के साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था।

डेनिश परिवहन मंत्री श्री हँस क्रिश्चियन स्कैमिडट ने कोपेनहेगन हवाई पत्तन पर एयर इंडिया के लिए एक पारगमन हब स्थापित करने सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए 18-22 जून, 2010 तक भारत के लिए एक 8-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से मुलाकात की।

श्रम गतिशीलता साझेदारी संबंधी भारत-डेनमार्क संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक 8-9 जून, 2010 तक कोपेनहेगन में आयोजित की गई। इसको मान्यता देते हुए कि आर्थिक मंदी के कारण डेनमार्क में वर्तमान नौकरी की संभावनाएं सीमित हैं, दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय उपायों के जरिए प्रारम्भिक कार्य जारी रखने पर सहमति प्रकट की। केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने सामान्यतः जल संसाधन के प्रबंधन में डेनिश अनुभवों से सीखने तथा विशेषकर निर्णय में सहायक प्रणालियों के इस्तेमाल के लिए 11-12 नवम्बर, 2010 को डेनमार्क के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज (नैसकॉम) की 14 भारतीय आईसीटी सदस्य कम्पनियों के प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए 3-4 मई, 2010 को डेनमार्क की यात्रा की। गुजरात सरकार के औद्योगिक विस्तार ब्यूरो के 10-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5वें वाइबरेन्ट गुजरात शिखर सम्मेलन, जोकि गुजरात में जनवरी 2011 में होना है, के प्रोत्साहन के लिए 3 सितम्बर, 2010 को डेनमार्क की यात्रा की। नयक्रेडिट ग्रुप, जोकि डेनमार्क में सबसे बड़ा मोर्टगेज लेन्डर तथा दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, के प्रतिनिधिमंडल ने 10-12 अक्तूबर, 2010 तक अध्ययन भ्रमण के लिए भारत की यात्रा की। ग्रुप ने विभिन्न पेंशन कम्पनियों, बीमा कम्पनियों और बैंकों का प्रतिनिधित्व किया तथा यात्रा का लक्ष्य डेनिश एफआईआई निवेशों पर विचार करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की भविष्य की संभावनाओं को समझना था।

अप्रैल 2010 में डेनिश सरकार ने 1995 के पुरुलिया आर्मस ड्राप केस में मुख्य अभियुक्त नीलस होलक उर्फ किम डेवी को भारत प्रत्यर्पित करने का निर्णय लिया। तथापि, शहरी न्यायालय ने नवम्बर 2010 में आदेश के विरुद्ध निर्णय दिया। डेनिश सरकार ने उच्चतर न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है।

डेनिश अर्थव्यवस्था और व्यापारिक कार्य मंत्री, श्री ब्रियान निक्कलसेन ने 6 जनवरी, 2011 को भारत की यात्रा की। उनके कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा के साथ बैठक शामिल थी। परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषद के 30-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के कोपेनहेगन अंतर्राष्ट्रीय फैशन मेले में भाग लेने के लिए 10-13 फरवरी, 2011 तक डेनमार्क की यात्रा करने की संभावना है।

एस्टोनिया

एस्टोनिया के साथ द्विपक्षीय संबंध निरंतर सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। एस्टोनियाई संसद के अध्यक्ष (स्पीकर) ने अप्रैल 2010 में भारत की यात्रा की। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत एस्टोनिया को 25 स्लॉट प्रदान किए गए और इनका पूर्णतः उपयोग किया गया।

फरवरी 2011 के अंत तक विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर के एस्टोनिया और अन्य बालटिक गणराज्यों की यात्रा करने की संभावना है।

फिनलैंड

वर्ष के दौरान भारत और फिनलैंड के बीच मंत्रालयी आदान-प्रदान होता रहा। फिनलैंड के रक्षा मंत्री श्री ज्यारी हकमीज ने विभिन्न फिनिश कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अप्रैल 2010 में भारत की यात्रा की। मंत्री हकमीज ने श्री ए. के. एंटनी, रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा रक्षा उद्योगों के सहयोग पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, मंत्री हकमीज ने वेस्टर्न एयर कमांड का दौरा किया, भारत-फिनलैंड रक्षा उद्योग गोलमेज में भाग लिया तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का दौरा किया।

फिनलैंड के विदेश मंत्री श्री एलैक्सैंडर स्टब ने मई 2010 में भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा के साथ वार्ता की तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन से भी मुलाकात की।

फिनलैंड के विदेश व्यापार तथा विकास मंत्री डॉ. पावो वायरेनेन ने 25-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2010 में भारत की यात्रा की। मंत्री वायरेनेन ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा विद्युत मंत्री के साथ मुलाकात की।

फिनलैंड की संचार मंत्री सुश्री सुवी लिनडैन ने दिसम्बर 2010 में भारत की यात्रा की। उनके साथ फिनिश आईटी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था तथा इसने टेलीकाम इंडिया, 2010 में भाग लिया। नई दिल्ली में सुश्री लिनडैन ने मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री कपिल सिब्बल के साथ चर्चा की, जोकि वर्तमान में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पद पर आसीन हैं। सुश्री लिनडैन ने श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सचिन पायलट, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा श्री नंदन निलकेनी, अध्यक्ष, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ भी मुलाकात की।

भारतीय पक्ष से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री कमल नाथ ने मई 2010 में हेलसिंकी की यात्रा की तथा

सड़क परिवहन क्षेत्र में सहयोग संबंधी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए।

फिनलैंड की माइग्रेशन और यूरोपियन कार्य मंत्री सुश्री एस्ट्रिड थोरस ने जनवरी 2010 के अंत में भारत की यात्रा की। फिनलैंड की पर्यावरण मंत्री सुश्री पाओला लेहतोमाकी के दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फरवरी 2011 में भारत की यात्रा करने की संभावना है। डॉ. फारुक अब्दुल्ला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के मार्च 2011 में फिनलैंड की यात्रा करने की संभावना है।

ग्रीस

ग्रीक प्रधानमंत्री जार्ज पपनद्रेव ने दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेने तथा प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष के साथ बातचीत करने के लिए फरवरी 2010 में भारत की यात्रा की।

श्री पवन कुमार बंसल, संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में सांसदों के 13-सदस्यीय भारतीय सदभावना प्रतिनिधिमंडल ने 18-20 जनवरी, 2010 को एथेंस की यात्रा की।

विदेश मंत्रालय के महासचिव श्री येनिस एलक्सिस जेपोस के नेतृत्व में ग्रीक प्रतिनिधिमंडल तथा सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में भारतीय पक्ष के साथ 27 अक्तूबर, 2010 तक नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर आयोजित किया गया।

त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल के अध्यक्षों स्पीकरों ने 21-24 सितम्बर, 2010 तक एथेंस की यात्रा की तथा हैलेनिक संसद के राष्ट्रपति फिलिपोस पेटसलनिकोस से शिष्टाचार मुलाकात की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3-5 नवम्बर, 2010 तक प्रथम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए एथेंस की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए जोकि पारस्परिक हित के कई क्षेत्रों में सहयोग आरंभ करेगा।

एक 10-सदस्यीय भारतीय सेना मोटरसाइकिल अभियान दल ने उन भारतीय सैनिकों का स्मरोणोत्सव मनाने के लिए 29 अगस्त-2 सितम्बर 2010 को ग्रीस की यात्रा की, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में अपना जीवन बलिदान किया था। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित उड़ीसा के 10-सदस्यीय लोक नृत्यदल ने 21-29 अगस्त, 2010 तक लेफकादा में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए ग्रीस की यात्रा की। हस्तशिल्प, रत्न और जवाहारात, वस्त्र क्षेत्र की 50 भारतीय कंपनियों ने 11-19 सितम्बर, 2010 तक थैसलोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया।

हंगरी

लोक सभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार ने उच्च-स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जून 2010 में हंगरी की सरकारी यात्रा की। यात्रा के दौरान हंगरी की संसद ने भारत-हंगरी संसदीय मैत्री समूह स्थापित किया। गोआ विधान सभा के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह रावजी राणे ने भी सितम्बर 2010 में हंगरी की दो दिवसीय यात्रा की।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने नवम्बर 2010 के प्रथम सप्ताह में हंगरी की यात्रा की। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन सहित नए निर्वाचित हंगरी के नेताओं के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करने के अलावा उन्होंने बुडापेस्ट स्थित भारतीय दूतावास की एनेक्सी का भी उद्घाटन किया। रक्षा संबंधी संयुक्त कार्य समूह ने 21-23 अक्तूबर, 2010 तक बुडापेस्ट में बैठक की।

70 से अधिक भारतीय कंपनियों ने सितम्बर 2010 में बुडापेस्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। वर्ष के दौरान, भारत से दो व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों नामतः पूर्वोत्तर लघु उद्योग संघ तथा कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने हंगरी की यात्रा की, जबकि हंगरी के चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत हेतु व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

आइसलैंड

आइसलैंड के साथ भारत के संबंध निरंतर घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बने रहे तथा व्यापार और निवेश संबंध व्यापक और विविध हुए हैं। भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी के क्षेत्र में आइसलैंड की कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है।

राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने 1-4 सितम्बर, 2010 तक आइसलैंड की सरकारी यात्रा की तथा आइसलैंड के राष्ट्रपति सहित आइसलैंड के विदेश मंत्री के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने के तरीकों तथा द्विपक्षीय संबंधों की समग्र परिधि पर चर्चा की। यात्रा के दौरान राज्यमंत्री ने रेयकजाविक में भारत के दूतावास का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्हेंने आइसलैंड के उत्तर में अकुरयेरी की भी यात्रा की।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, डॉ. फारुक अब्दुल्ला ने आइसलैंड के उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री के निमंत्रण पर 26-29 सितम्बर, 2010 तक आइसलैंड की सरकारी यात्रा की। यात्रा का मुख्य केन्द्र बिंदु भूतापीय ऊर्जा के अनुसंधान और अन्वेषण सहित इसके अनुवर्ती अनुप्रयोगों पर था।

सुश्री केटरीन जुलियसडोटिर, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री ने डॉ. फारुख अब्दुल्ला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के निमंत्रण पर द्विपक्षीय वार्तालाप सहित डीआईआरईसी-2010 में भाग लेने के लिए 27-31 अक्तूबर, 2010 तक भारत की यात्रा की। उनकी यात्रा के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर

भारत-आइसलैंड संयुक्त समिति की प्रथम बैठक 30 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।

लात्विया

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर फरवरी 2011 के अंत में लातविया की यात्रा करेंगी।

लिचेनस्टीन

वर्ष के दौरान उपराष्ट्रपति के निमंत्रण पर लिचेनस्टीन के वंशानुगत राजकुमार एलोइस ने 14-20 नवम्बर, 2010 तक भारत की प्रथम यात्रा की। उनके साथ उनकी पत्नी राजकुमारी सोफी, विदेश मंत्री सुश्री ओरेलिया फ्रिक, एक 11-सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल तथा एक 10-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था। राजकुमार एलोइस ने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा विदेश राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, यूपीए अध्यक्ष, विपक्ष के नेता तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ बैठकें कीं। यात्रा का मुख्य लक्ष्य मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को गहन और व्यापक बनाना तथा विशेषकर अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करना था। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार नीतियों के प्रति वर्तमान चुनौतियों पर विचारों का भी आदान-प्रदान किया गया। राजकुमार एलोइस ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को भी देखा। उन्हेंने मुम्बई की भी यात्रा की।

लिथुआनिया

12-18 नवम्बर, 2010 तक संसद के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लिथुआनिया के 3-सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से भारत और लिथुआनिया के बीच संबंध और सुदृढ़ हुए। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश राज्य मंत्री तथा विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ बैठकें कीं। लोक राजनय प्रभाग ने प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। संसद सदस्यों और मंत्रियों से मुलाकात करने के अलावा प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ऊर्जा संसाधन संस्थान, पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा आगरा का भ्रमण किया। भारतीय कंपनियों के साथ व्यापारिक अवसरों और संबंधों का पता लगाने के लिए लिथुआनिया के संसद सदस्यों के साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी था।

मेसेडोनिया

भारत और मेसेडोनिया के बीच दूसरा विदेश कार्यालय परामर्श 15 सितम्बर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री विवेक काटजू, सचिव (पश्चिम) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि मेसेडोनिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री जोरान पैट्रोव, उपविदेश मंत्री द्वारा किया गया। दोनो पक्षों ने सहमति प्रकट की कि द्विपक्षीय व्यापार का स्तर इसकी क्षमता से कम है तथा व्यापार और आर्थिक संबंधों को संवर्द्धित करने के उपायों का पता लगाने पर सहमति प्रकट की। इस पर भी सहमति हुई कि वार्ता के अंतर्गत विभिन्न करारों को शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

माल्टा

सचिव (नौवहन) के नेतृत्व में 2-सदस्यीय भारतीय नौवहन प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए जुलाई 2010 में माल्टा की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने माल्टा परिवहन केंद्र सहित विभिन्न नौवहन सुविधाओं का अवलोकन किया।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कर परिहार तथा मौद्रिक अपवंचन रोकथाम संबंधी एक करार पर 2010 में सफलतापूर्वक बातचीत की गई तथा इस पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

मोलडोवा

मोलडोवा में संकटपूर्ण बाढ़ के परिणामस्वरूप आपदा न्यूनीकरण कार्य हेतु मोलडोवा गणराज्य की सरकार को भारत सरकार ने 1,00,000 अमरीकी डालर (एक लाख अमरीकी डालर) की सहायता प्रदान की। मोलडोवा के मीडिया में इस सहायता को व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया।

मोलडोवा ने दूर संवेदी, बैंकिंग तथा लेखा परीक्षा तथा लेखा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए आईटीईसी स्लाटों की अपनी उपयोगिता को विस्तृत किया। मोलडोवा के राजनयिक ने विदेशी राजनयिकों हेतु 49वें व्यावसयिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

मोन्टेनेगरो

यूगोस्लाविया के सोशलिस्ट फेडरेल गणराज्य, जिसका मोन्टेनेगरो संघटक गणराज्य था, के दिनों से मोन्टेनेगरो के साथ भारत के संबंध परम्परागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। मोन्टेनेगरो का समवर्ती प्रत्यापन बेलग्रेड से वियना में हो गया तथा आस्ट्रिया के भारतीय राजदूत ने अपना प्रत्यय-पत्र 6 अक्तूबर, 2010 को पोडगोरिका में प्रस्तुत किया।

भारत ने अपने तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत मोन्टेनेगरो को शामिल किया है तथा मोन्टेनेगरो के दो अधिकारियों ने इस वर्ष दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है।

नार्वे

मंत्रालययी और अधिकारी स्तर, दोनों पर वर्ष के दौरान भारत और नार्वे के बीच व्यापक वार्तालाप निरंतर बना रहा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा भू विज्ञान राज्य मंत्री, श्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 5-9 जून, 2010 तक नार्वे की यात्रा की। नार्वे के अनुसंधान और उच्च शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा करने के अलावा उन्होंने स्वालबर्ड में भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री का निरीक्षण किया तथा ग्लोबल सीड वाल्ट और स्वालबर्ड विश्वविद्यालय की यात्रा की। उन्होंने 8 जून, 2010

को लिलेस्ट्रोम में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुव वर्ष सम्मेलन में भी भाग लिया तथा प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय चर्चा आयोजित की। डॉ. सी. पी. जोशी, पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने 13-15 सितम्बर, 2010 तक नार्वे में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान स्थानीय शासन संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा स्थानीय शासन पर संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक आयोजित की गई।

नार्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री, श्री ट्रोन्ड गिसके ने बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 अक्तूबर-1 नवम्बर 2010 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा सहित राज्य मंत्री (रक्षा) के साथ चर्चा की। यात्रा के दौरान सामाजिक सुरक्षा संबंधी एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री एरिक सोलेहम, नार्वे के पर्यावरण और विकास सहयोग मंत्री ने 'भारतीय सामाजिक लोकतंत्रः एकीकृत बाजार, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय' पर 10वें इंदिरा गांधी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19-21 नवम्बर, 2010 तक दिल्ली की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने श्री फारुख अब्दुल्ला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री जयराम रमेश, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन से मुलाकात की।

संस्कृति पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 12 मई, 2010 को ओसलो में आयोजित की गई, जिसके दौरान वर्ष 2010-2015 हेतु सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। श्री विजय शर्मा, सचिव (पर्यावरण और वन) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 मई, 2010 को ओसलो जलवायु और वन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नार्वे की यात्रा की। श्रीमती सुजाता राव, सचिव (स्वास्थ्य) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नार्वे-भारत साझेदारी पहल की संयुक्त संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 2-6 जून, 2010 तक नार्वे की यात्रा की।

पोलैंड

प्रधानमंत्री डोनाल्ड रसक ने 6-8 सितम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात की तथा प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के साथ चर्चा की। उनकी यात्रा भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान 2010-2013 के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए।

श्री आर.के. सिंह, सचिव (रक्षा उत्पादन) ने सैनिक सहयोग पर पांचवें भारत-पोलिश संयुक्त कार्य समूह में भाग लेने क लिए 7-9 अप्रैल, 2010 तक पोलैंड की यात्रा की। पोलैंड के लैंड फोर्सेज कमांडर मेजर जनरल बिगन्यू ग्लोएनका ने दोनों सशस्त्र बलों के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए 22-25 नवम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की।

पोलैंड के संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत मंत्री, श्री बोगडान ड्रोजेवेस्की ने भारत में मनाए जा रहे 'चोपियान 2010 इंडिया' में भाग लेने के लिए 23-24 नवम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की।

रोमानिया

विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर ने 9-10 अप्रैल, 2010 तक रोमानिया की यात्रा की तथा रोमानिया के विदेश मंत्री, श्री टेओडोर बाकोन्शची तथा रोमानियाई संसद के स्पीकर (अध्यक्ष) से मुलाकात की। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की गई। राज्य मंत्री के साथ भारतीय व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल था तथा उन्होंने बुखारेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंड्रस्ट्री में रोमानिया-भारत व्यापार फोरम का उद्घाटन किया।

9-16 मई, 2010 तक 15 अधिकारियों सहित राष्ट्रीय रक्षा कालेज (एनडीसी) प्रतिनिधिमंडल ने एनडीसी के बाह्य देशों की यात्रा के भाग के रूप में रोमानिया की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने रोमानिया के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की यात्रा की।

इकोनॉमी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री बोरबेली कारोली के नेतृत्व में एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव के साथ वार्ता हेतु 18-22 नवम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की।

सर्बिया

11 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में भारत-सर्बिया विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर आयोजित किया गया, जिसके दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। चर्चा में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को भी शामिल किया गया।

सुप्रसिद्ध नृत्यांगना श्रीमती रंजना गौहर के नेतृत्व में 10-सदस्यीय ओड़ीसी नृत्य दल ने सितम्बर 2010 में सर्बिया की यात्रा की तथा बेलग्रेड और कई अन्य सर्बियाई शहरों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

स्लोवाकिया

कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंड्रस्ट्री के 32-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2010 में स्लोवाकिया की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने स्लोवाक निवेश और व्यापार एजेंसी सहित स्लोवाक चैम्बर आफ कॉमर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

स्लोवेनिया

लगातार दूसरे वर्ष राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने 30-31 अगस्त, 2010 को लेड स्ट्रटेजिक फोरम में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अगले दशक की वैश्विक चुनौतियों पर एक प्रस्तुतिकरण पेश किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान स्लोवेनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर 8 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। स्लोवेनिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री ड्रेगोलजुबा बेनसिना, स्टेट सेक्रेटरी, विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। वार्ता क्षेत्रीय विषयों के अलावा द्विपक्षीय संबंधों विशेषकर आर्थिक संबंधों के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित थी। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत-स्लोवेनिया संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक 2 नवम्बर, 2010 को आयोजित की गई तथा अभी तक कुल 12 संयुक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई हैं।

ल्युबियाना दूतावास ने 14 अप्रैल, 2010 को भारत-स्लोवेनिया व्यापारिक साझेदारी पर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारत स्लोवेनिया व्यापारिक संबंधों पर एक पुस्तिका भी जारी की गई। 11 भारतीय कंपनियों ने 6-13 सितम्बर, 2010 को सेलजे में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया।

स्लोवेनिया के उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटरी, डॉ. जोजसेफ ग्योरकोस की यात्रा के दौरान आईसीपीई स्थित भारतीय लोक सेवकों के लिए अनुसंधान, परामर्श तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए 7 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में उद्यम प्रोत्साहन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीपीई) तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईसीपीई की शासी परिषद का 50वां सत्र 9 नवम्बर, 2010 को आयोजित किया गया। श्री भास्कर चटर्जी, सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार तथा आईसीपीई की शासी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 7-9 नवम्बर, 2010 को ल्युबियाना की यात्रा की।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त शांति संदेश वाहक शहर सलोवेंज ग्रेडेक नगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई तथा इस अवसर पर गांधीजी की आत्मकथा का स्लोवेनियाई अनुवाद जारी किया गया।

स्वीडन

नवम्बर 2009 में स्वीडिश प्रधानमंत्री फ्रेडरिक रिइनफैल्ड की यात्रा द्वारा सृजित संवेग द्विपक्षीय यात्राओं के सक्रिय विनिमय के साथ 2010 के दौरान भी बना रहा। जल संसाधन राज्य मंत्री विनसेंट पाला ने 5-11 सितम्बर, 2010 को 'विश्व जल सप्ताह' में भाग लेने के लिए बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन की यात्रा की। स्वीडन की उद्यम और ऊर्जा मंत्री सुश्री मॉड औलोफसन ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27-31 अक्तूबर, 2010 तक भारत की यात्रा की। स्वीडिश संसद के निमंत्रण पर चार भारतीय संसद सदस्यों के समूह ने मई 2010 में स्टॉकहोम की यात्रा की।

सरकारी स्तर पर काफी यात्राओं का विनिमय हुआ और भारत के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर 2010 में स्टॉकहोम की यात्रा की तथा वर्ष 2010-2012 के लिए सहयोग संबंधी प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्य अंग अंतरिक्ष निगम लिमिटेड को स्टॉकहोम में 29 अप्रैल, 2010 को ग्लोब फोरम द्वारा प्रतिष्ठित 'सतत् अनुसंधान पुरस्कार, 2010' प्रदान किया गया। स्वीडन के सामाजिक कार्य और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्टेट सेक्रेटरी सुश्री केरिन जॉनसन ने 29-30 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली की यात्रा की तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री और राज्य मंत्री दोनों से मुलाकात की।

पर्यावरण संबंधी संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक 1 दिसम्बर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त कार्य समूह की प्रथम बैठक भी 14-16 दिसम्बर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर 19 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारतीय अध्ययन के बारे में पीठ की स्थापना करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली और लुंड विश्वविद्यालय, स्वीडन के बीच एक अन्य समझौता ज्ञापन पर 22 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। स्वीडन में भारतीय कला, संगीत, नृत्य और साहित्य से संबंधित फिल्मों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों को दर्शाने वाले एक तीन महीने लंबे सांस्कृतिक समारोह का 1 अक्तूबर, 2010 को स्टॉकहोम में उदघाटन किया गया।

साफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनियों के राष्ट्रीय संघ नैसकॉम के प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक अवसरों का पता लगाने के लिए मई 2010 में स्टॉकहोम और गोथेनबर्ग की यात्रा की। जनवरी 2011 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इंवेस्टर्स बैठक में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी के लिए 2-8 सितम्बर, 2010 तक गुजरात राज्य सरकार के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने स्टॉकहोम की यात्रा की।

स्विटजरलैंड

वर्ष का मुख्य आकर्षण 30 अगस्त, 2010 को स्विस विदेश मंत्री, माइकेलिन कालमे-रे की भारत की सरकारी यात्रा थी। विदेश मंत्री के साथ उनकी चर्चा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों सहित वित्त, पर्यावरण, प्रवासन, आर्थिक नीति और विज्ञान के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय विषयों पर केंद्रित थी। उन्होंने वित्त मंत्री और पर्यावरण व वन मंत्री से भी मुलाकात की। उनकी यात्रा के दौरान आय पर करों के क्षेत्र में दोहरे कराधान करार (डीटीए) में संशोधन करने वाले प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। संशोधित डीटीए में ओईसीडी मानक के अनुसार सूचना के आदान-प्रदान संबंधी प्रावधान शामिल हैं। स्विस विदेश मंत्री ने बंगलौर में स्विस महाकौंसलावास खोलने की भी घोषणा की, जो उच्च शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

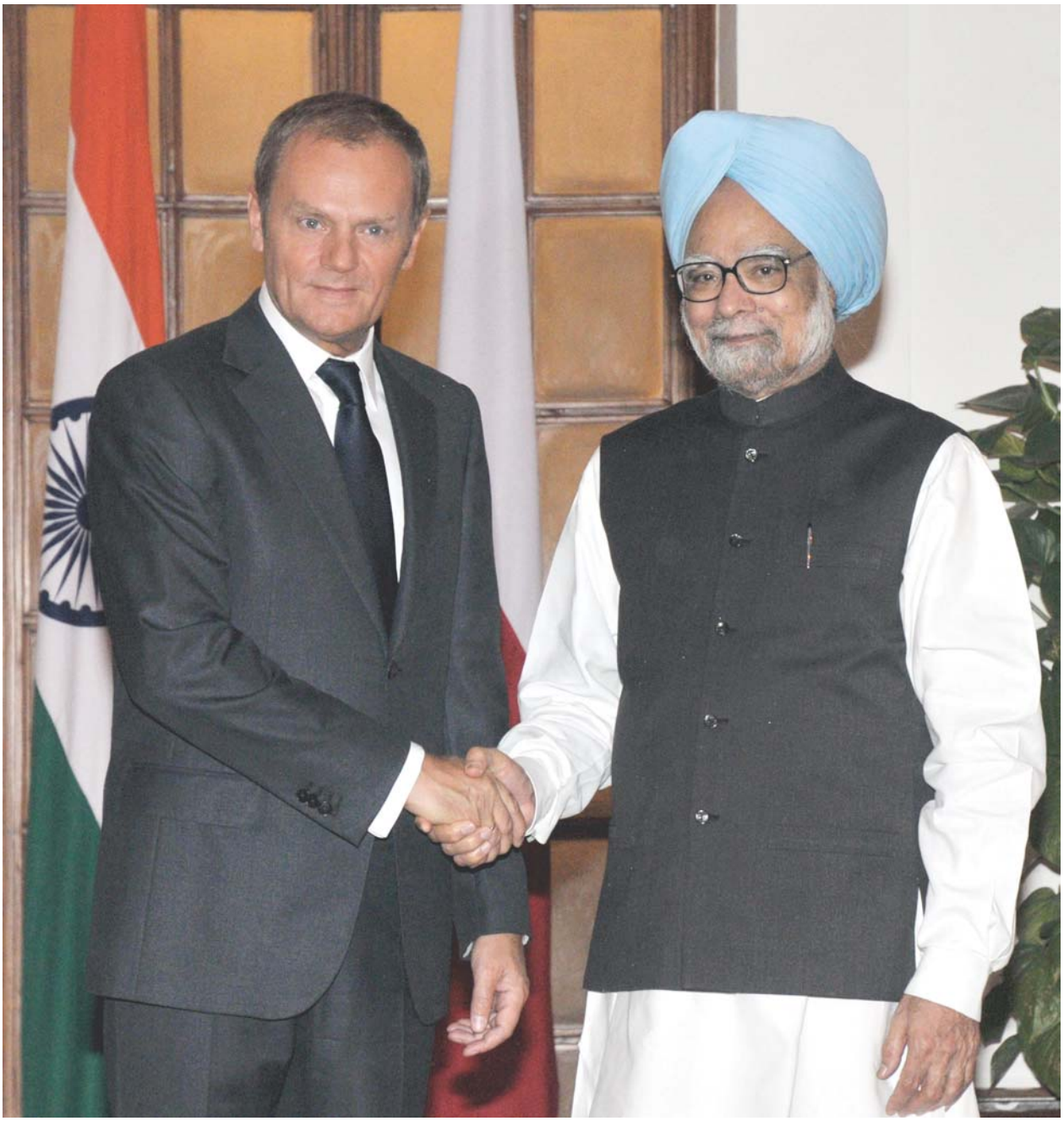

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 7 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली में पोलैंड के प्रधान मंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ।

संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में एक 18-सदस्यीय भारतीय संसदीय सदभावना प्रतिनिधिमंडल ने 1-4 अप्रैल, 2010 तक स्विटजरलैंड की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल में संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री श्री वी. नारायणसामी, 12 संसद सदस्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के 4 अधिकारी शामिल थे।

श्रीमती मीरा कुमार, अध्यक्ष लोक सभा, के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 16 और 17 जुलाई, 2010 को बर्न में संसद की महिला अध्यक्षों की आईपीयू छठी वार्षिक बैठक तथा 19-21 जुलाई, 2010 तक जिनेवा में संसद के अध्यक्षों के आईपीयू सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15-21 जुलाई, 2010 को स्विटजरलैंड की यात्रा की। जिनेवा सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष के साथ एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल था।

भारत-स्विस संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 12वां दौर 1 अक्तूबर, 2010 को ज्यूरिख में आयोजित किया गया। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सहित द्विपक्षीय आर्थिक तथा वाणिज्यिक हितों की व्यापक परिधि के विषयों, बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग, प्रवासन और वीजा के क्षेत्र से संबंधित मामलों, भारत-एफ्टा व्यापार तथा निवेश करार पर बातचीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग, डब्ल्यूटीओ दोहा राउंड तथा बाजार पहुंच से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। दिनांक 17-19 अगस्त तक नई दिल्ली में तथा 11-12 नवम्बर, 2010 तक जिनेवा में वर्ष के दौरान भारत-एफ्टा व्यापार तथा निवेश करार हेतु बातचीत का क्रमशः 5वां तथा 6ठा दौर आयोजित किया गया।

तुर्की

भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर और प्रगति हुई तथा वर्ष के दौरान विभिन्न उच्च स्तरीय राजनैतिक यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ। तुर्की के कृषि मंत्री मेहदी एकर ने 17-19 जून, 2010 तक दिल्ली की यात्रा की तथा कृषि मंत्री श्री शरद पवार से मुलाकात की। यात्रा के दौरान वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 हेतु भारत और तुर्की के बीच कृषि की वार्षिक योजना को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। मुक्त व्यापार करार स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तुर्की-भारत संयुक्त अध्ययन समूह की दूसरी बैठक 13-14 मई, 2010 को अंकारा में आयोजित की गई। कर्नाटक सरकार के वस्त्र, युवा कार्य तथा खेल मंत्री श्री गुलहाट्टी डी. शेखर के नेतृत्व में एक सात-सदस्यीय निवेश संवर्धन प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक में वस्त्र उद्योग पर रोड-शो की मेजबानी करने के लिए 17-20 मई, 2010 तक इस्तानबुल की यात्रा की। दिनांक 2-4 नवम्बर, 2010 तक इस्तानबुल में आयोजित अफगानिस्तान संबंधी चौथे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

अगस्त-सितम्बर 2010 में 79वें इजमीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी का लाभ लेने के लिए, सीईएस देशों में संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और संसाधन भेजने के लिए भारतीय और तुर्की व्यापारियों के लिए मंच उपलब्ध करवाने हेतु 24-25 अगस्त, 2010 तक भारत-तुर्की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडीपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस) व्यापारिक फोरम आयोजित किया गया। 15 प्रमुख भारतीय कंपनियों के साथ इजमीर मेले में भारतीय पैवेलियन सबसे बड़ा था।

श्री हरि मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में आईसीसीआर-प्रायोजित सांसकृतिक दल ने 18-20 मई, 2010 तक मध्य तुर्की में एरसियस विश्वविद्यालय, केयसेरी में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अन्य आईसीसीआर प्रायोजित 14-सदस्यीय भंगड़ा लोक नृत्य दल ने सितम्बर 2010 में तुर्की में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जैसलमेर यैलो नामक सार्क कलाकारों द्वारा आधुनिक कला की एक प्रदर्शनी सितम्बर-अक्तूबर 2010 में अंकारा में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित की गई। भारतीय सेना के मोटर साइकिल अभियान ने अगस्त 2010 में तुर्की की यात्रा की तथा गलीपोली स्थित प्रथम विश्व-युद्ध के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सशस्त्र बलों के कैडेटस के 22-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीआईएसएम विश्व सेना खेलों में भाग लेने के लिए 17-24 अक्तूबर, 2010 तक अंकारा की यात्रा की।

तुर्की के युद्धपोत टीसीजी गेलीबोलू ने पत्तन यात्रा के लिए 8-11 अप्रैल, 2010 तक मुम्बई की यात्रा की। इस्तांनबुल में नौसेना प्रमुख एडमिरल निर्मल वर्मा के पारगमन विराम के दौरान तुर्की के नौसेना प्रशिक्षण तथा शिक्षण कमांड के कमांडर ने उनसे मुलाकात की तथा जून 2011 में तुर्की के चार नौसैनिक जहाजों की भारत में पत्तन यात्रा का प्रस्ताव किया।

तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव ने एनएसए के साथ बातचीत के लिए 21 जनवरी, 2011 को भारत की यात्रा की। फरवरी 2010 के पहले पखवाड़े में अंकारा में विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित होने की संभावना है।

पश्चिम यूरोप

बेल्जियम

भारत के प्रधानमंत्री ने 9-11 दिसंबर, 2010 तक बेल्जियम की यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने बेल्जियम के प्रधानमंत्री वाइवेस लेटरमे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई की यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह प्रथम द्विपक्षीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान, विशेषकर दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों में भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों की समग्र परिधि की समीक्षा की गई। यात्रा के दौरान भारत और बेल्जियम के अग्रणी उद्यमियों की भागीदारी के साथ 'ब्रिलियेंट इंडिया' नामक भारत-बेल्जियम व्यापारिक बैठक भी आयोजित की गई।

पूर्व में वर्ष के दौरान, भारत के उपराष्ट्रपति ने 3-5 अक्तूबर, 2010 तक आयोजित एशिया-यूरोप बैठक-8 शिखर सम्मेलन में भारतीय

10 दिसंबर, 2010 को ब्रसेल्स, बेल्जियम में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हरमन वॉन रोम्पी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जोस मैनुअल बरासो के साथ।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 6 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोजी के साथ मुलाकात करते हुए।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में ब्रुसेल्स की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने एएसईएम-8 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों के लिए राजा द्वारा दिए गए भोज में किंग एल्बर्ट-II, बेल्जियम के राजा के साथ संक्षिप्त वार्तालाप किया। उन्होंने प्रधानमंत्री वाइवेस लेटरमे के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक भी की।

बेल्जियम पक्ष की तरफ से क्राउन प्रिंस फिलिप ने 20-27 मार्च, 2010 तक भारत की यात्रा की, उन्होंने बेल्जियम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की 160 बेल्जियम कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित 350 सदस्यीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व किया। यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और संवर्धित करने पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री, जहाजरानी मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा लोक सभा में विपक्ष के नेता से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, भारत और बेल्जियम के बीच आर्थिक संबंधों में वृद्धि करने के लिए लगभग 30 व्यापारिक समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर हीरा क्षेत्र का निरंतर प्रभुत्व बना रहा, हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से व्यापार समूह को वैविध्यपूर्ण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2009 में द्विपक्षीय व्यापार टर्नओवर यूरो 7.1 बिलियन था, जोकि 2008 के टर्नओवर यूरो 8.8 बिलियन की तुलना में कम था। तथापि, जनवरी-अगस्त, 2010 की अवधि हेतु उपलब्ध आंकड़े 60.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दर्शाते हैं, जोकि 2009 में उसी अवधि के दौरान 3.479 बिलियन यूरो की तुलना में 5.57 बिलियन यूरो है।

सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में भारत ने एशिया-यूरोप बैठक-8 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 25 जून-10 अक्तूबर 2010 तक ब्रुसेल्स के बोजार में आयोजित 'ए पैसेज टू एशियाः 25 सेन्चुरीज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन एशिया एंड यूरोप' नामक प्रदर्शनी में भाग लिया। इसी अवसर पर, ब्रुसेल्स में बोजार प्रदर्शनी केंद्र स्थित सेंटर आफ फाइन आर्टस में 11 सितम्बर, 2010 को माधवी मुदगल के दल द्वारा 'अनन्या' नामक एक नृत्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

फ्रांस

फ्रांस के राष्ट्रपति, श्री निकोलस सरकोजी ने 4-7 दिसम्बर, 2010 तक भारत की कार्यकारी यात्रा की। फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सुश्री कार्ला सरकोजी तथा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें उनके मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग चैम्बर्स के प्रतिनिधि, व्यापारी और मीडिया के लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति सरकोजी ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता के व्यापक-परिधि के विषयों पर चर्चा की। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, नामतः परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में, अंतरिक्ष और फिल्म सह-निर्माण के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने 'भारत-फ्रांसः भविष्य के लिए साझेदारी' पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जोकि रक्षा, असैनिक परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, आर्थिक और व्यापार विनिमय, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, सतत् विकास, विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक सहयोग तथा सांस्कृतिक विनिमय के रणनीतिक क्षेत्रों में भविष्य के लिए सहयोग हेतु रोडमैप निर्धारित करता है। राष्ट्रपति सरकोजी ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत हेतु फ्रांस के समर्थन् को पुनः दोहराया। राष्ट्रपति सरकोजी की यात्रा ने इस महत्वपूर्ण पी-5 देश के साथ हमारी रणनीतिक भागीदारी की निरंतरता को सुनिश्चित किया।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सरकोजी ने पूर्व में अप्रैल 2010 में वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन तथा जून 2010 में टोरोंटो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात की थी।

एनएसए और फ्रेंच राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत-फ्रेंच रणनीतिक वार्ता 11 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश सचिव और उनके समकक्ष, फ्रेंच एमएफए में महासचिव श्री पियरै सैलाल के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 4 मई, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रक्षा सचिव और उनके फ्रेंच समकक्ष के बीच रक्षा सहयोग संबंधी उच्च समिति (एचसीडीसी) की बैठक 18-19 नवम्बर, 2010 को पेरिस में आयोजित की गई। जनरल एलरिक इरासटोरजा, फ्रेंच थल सेना प्रमुख ने 30 जनवरी-2 फरवरी 2011 तक भारत की यात्रा की।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री के नेतृत्व में एक 13-सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 28-31 मार्च, 2010 को फ्रांस की यात्रा की। श्री दयानिधि मारन, वस्त्र मंत्री ने भारतीय वस्त्र और परिधानों को प्रोत्साहित करने के लिए संगोष्ठी और बैठक हेतु 1-2 फरवरी, 2010 तक पेरिस की यात्रा की। श्री सुबोध कांत सहाय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने फ्रेंच निवेश को आमंत्रित करने तथा भारत में इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 2-5 फरवरी, 2010 तक पेरिस और क्विम्पर की यात्रा की। उन्होंने फ्रेंच कृषि मंत्री, श्री ब्रुनो ली मेयर और फ्रेंच विदेश व्यापार राज्य मंत्री, मैडम एनी-मैरी इड्राम के साथ भी बैठकें कीं। श्री मुरली देवड़ा, पैट्रोलियम मंत्री ने 10-11 मई, 2010 तक पेरिस की यात्रा की तथा उन्होंने ऊर्जा संबंधी विषयों पर चर्चा की। श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ओईसीडी एमसीएम और डब्ल्यूटीओ वार्ता के लिए 27-28 मई, 2010 तक पेरिस में थे। श्री विलासराव देशमुख, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने अलसटोम के साथ चर्चा करने के लिए 15-17 जून, 2010 तक यात्रा की। डॉ. इकबाल सिंह, पुदुचेरी के उपराज्यपाल ने ला-रोशेल शहर के साथ सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 16-21 जून, 2010 तक फ्रांस की यात्रा की। श्री आनंद शर्मा,

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत-फ्रेंच सीईओ फोरम में भाग लेने तथा संयुक्त समिति की बैठक के लिए 24-25 जून, 2010 तक पेरिस की यात्रा की, श्री श्रीकांत जेना, रसायन राज्य मंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग में वद्धि करने के लिए 28-30 जून, 2010 तक फ्रांस की यात्रा की। श्री सैम पित्रोदा, नवाचार संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार ने 'रेनकोनट्रेस इकोनोमिक्स डेस एक्स-एन-प्रोवेंस' नामक आर्थिक फोरम में भाग लेने के लिए 2-6 जुलाई, 2010 को फ्रांस की यात्रा की। विकसित अनुसंधान के प्रोत्साहन पर भारत-फ्रेंच फोरम का 24वां दौर पेरिस में 31 जनवरी, 2011 को आयोजित किया गया।

फ्रेंच पक्ष से श्री जीन-लुइस बोरलू, परिस्थिति विज्ञान, ऊर्जा तथा सतत् विकास मंत्री ने दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5-7 फरवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की। कृषि मंत्री ब्रुनो ली मेयरे ने 5-7 अक्तूबर, 2010 तक भारत की द्विपक्षीय यात्रा की।

यूरोपीय संघ के देशों के बीच भारत के व्यापारिक साझेदारों की सूची में फ्रांस का स्थान 5वां है (जर्मनी, यूके, बेल्जियम, और नीदरलैंड के पश्चात)। भारत-फ्रेंच व्यापार में 2009 में 21 प्रतिशत की गिरावट आई (2008 में यूरो 6.78 बिलियन की तुलना में 2009 में यूरो 5.36 बिलियन) 2010 के प्रथम दस महीनों में, 2009 के इसी अवधि में यूरो 4.42 बिलियन की तुलना में व्यापार लगभग 31 प्रतिशत बढ़कर यूरो 5.80 बिलियन हो गया है। इसी अवधि के दौरान भारत से निर्यात यूरो 2.39 बिलियन से 46 प्रतिशत बढ़कर यूरो 3.5 बिलियन हो गया तथा फ्रांस से आयात यूरो 2.04 बिलियन से 13 प्रतिशत बढ़कर यूरो 2.30 बिलियन हो गया। अनुमानतः यूरो 2.34 बिलियन के संचयी निवेश के साथ भारत में फ्रांस 9वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है (अप्रैल 2000-अगस्त 2010 की अवधि के दौरान यूरो 1.4 बिलियन अथवा 1.78 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश हुआ, जोकि कुल प्रवाह का 2 प्रतिशत था)।

आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-फ्रेंच संयुक्त समिति की बैठक 24-25 जून को पेरिस में आयोजित की गई। भारत-फ्रेंच सीईओ फोरम की दूसरी बैठक भी 24-25 जून, 2010 को पेरिस में आयोजित की गई।

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के लक्ष्य के अनुकरण में सड़क संबंधी जेडब्ल्यूजी का अगला दौर 5-6 जनवरी, 2011 तक पेरिस में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री कमलनाथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा किया गया।

जी-20 की फ्रेंच अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य समूह की बैठक 13 जनवरी, 2011 को आयोजित की गई, जिसके बाद 15-16 जनवरी, 2011 को जी-20 वित्त डिप्टीज की बैठक, दोनों पेरिस में आयोजित की गई। जी-20 शेरपास की बैठक 25-26 जनवरी, 2011 को पेरिस में आयोजित की गई तथा जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक भी पेरिस में 17-19 फरवरी, 2011 को आयोजित किए जाने की संभावना है।

'नमस्ते फ्रांस' नामक भारतीय सांस्कृतिक उत्सव की परिकल्पना और शुरुआत 14 अप्रैल, 2010 को की गई तथा जिसमें मल्लिका साराभाई और दर्पण अकादमी के कलाकारों के दल का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा पेरिस स्थित क्वाई ब्रेनले म्यूजियम में देशी भारतीय कला की प्रदर्शनी लगाई गई। 'नमस्ते फ्रांस' कला, संगीत, नृत्य, फैशन, पर्यटन, फिल्म और साहित्य तथा अपने परम्परागत और समकालीन रूपों, दोनों में व्यापारिक और शैक्षणिक सहित भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रस्तुतिकरण है।

जर्मनी

जर्मनी यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा यूरोपीय यूनियन बजट में इसका सबसे अधिक योगदान है। यूरोप में भारत का यह सबसे बड़ा तथा विश्व स्तर पर पांचवां व्यापारिक साझेदार है। भारत और जर्मनी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर परस्पर व्याप्त विचारों, परस्पर विश्वास और सहयोग पर आधारित घनिष्ठ संबंध निर्मित किए हैं। 2010 में जर्मनी ने जर्मन एकीकरण के 20 वर्षों का उत्सव मनाया। भारत और जर्मनी 2011 में राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा करेंगे। 2012 में भारत में 'जर्मनी वर्ष' तथा जर्मनी में 'भारत वर्ष' के साथ इस अवसर को मानने की तैयारी चल रही है।

दोनों पक्षों की कुछ उच्च स्तरीय यात्राओं के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध सतत् गति से बढ़ रहे हैं। वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण यात्राओं में फरवरी 2010 में जर्मन फेडरल राष्ट्रपति, डॉ. होर्स्ट कोहेलर की भारत की सरकारी यात्रा शामिल है। राष्ट्रपति कोहेलर ने राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की, जबकि विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने उनसे भेंट की। राष्ट्रपति कोहेलर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा मुम्बई में व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की तथा दारेवाडी, महाराष्ट्र में जल विभाजक विकास परियोजना का दौरा किया। राष्ट्रपति की यात्रा के पश्चात, औद्योगिक और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-जर्मन संयुक्त आयोग के 17वें सत्र की सहअध्यक्षता करने के लिए सितम्बर 2010 में जर्मन आर्थिक मंत्री रैनर ब्रुडेरले ने यात्रा की तथा 17-19 अक्तूबर, 2010 तक वाइस चांसलर तथा विदेश मंत्री डॉ. गुड्डो वेस्टरवेल ने यात्रा की। डॉ. वेस्टरवेल ने प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों ने 2011-2012 में भारत में जर्मनी का वर्ष तथा 2012-2013 में जर्मनी में भारत का वर्ष मनाने के लिए विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। इन दो वर्षों के दौरान ये समारोह भारत-जर्मन राजनयिक साझेदारी के 60 वर्षों के पूरा होने के उपलक्ष्य में हैं।

चांसलर मरकेल के निमंत्रण पर 11 दिसम्बर, 2010 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बर्लिन की यात्रा की। उन्होंने जर्मनी

फेडरल गणराज्य के राष्ट्रपति श्री क्रिश्चयन वुल्फ से मुलाकात की तथा चांसलर मरकेल से उनके कार्यालय में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने सिविल परमाणु क्षेत्र, रक्षा सहयोग में सहयोग की संभावना सहित विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक विषयों पर चर्चा की तथा 2012 तक द्विपक्षीय व्यापार में यूरो 20 बिलियन की वृद्धि करने के निर्णय को दोहराया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2011 में भारत की यात्रा करने के लिए चांसलर मरकेल को निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने हमारे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों की समग्र संभावना तक पहुंचने के उद्देश्य से जर्मन निर्यात नियंत्रण विनियमों में छूट की आवश्यकता पर भी बल दिया। दोनों नेताओं ने विस्तृत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटें सुरक्षित करने के प्रयासों सहित आगामी दो वर्षों के लिए यूएनएससी पर गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए अपनी रणनीतियों को समन्वित करने का भी निर्णय लिया।

जर्मनी से भारत की अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में, भारत में सरकारी के विपणन अभियान की शुरुआत करने के लिए 8-12 मार्च, 2010 तक नॉर्थ राइन वेस्टफालिया के जर्मन राज्य की आर्थिक कार्य और ऊर्जा मंत्री सुश्री क्रिस्टा थोबेन की यात्रा शामिल थी। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने विद्युत मंत्री, श्री सुशील कुमार शिंदे और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, डॉ. फारुख अब्दुल्ला से मुलाकात की। जर्मनी की फेडरल सरकार के स्टेट सेक्रेटरी गुर्ट म्युलर ने नई दिल्ली में कृषि संबंधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के लिए 1 सितम्बर, 2010 को भारत की यात्रा की तथा नवम्बर 2010 में जर्मन की कृषि मंत्री इलसे आयगनर ने भारत की यात्रा की। सुश्री आयगनर ने श्री सुबोध कांत सहाय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा प्रोफेसर के. वी. थामस, कृषि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री से मुलाकात की। अन्य महत्वपूर्ण जर्मन प्रतिनिधियों, जिन्होंने भारत की यात्रा की, उनमें शामिल हैं; लोवर सेक्सनी की जर्मन स्टेट के मुख्यमंत्री डेविड मैक एलिस्टर, जिन्होंने लोवर सेक्सनी के व्यापार और उद्योग, विज्ञान तथा मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 50-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 सितंबर से 3 अक्तूबर, 2010 तक चेन्नै, नई दिल्ली तथा पुणे के भारतीय शहरों की यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा से मुलाकात की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम), श्री आनन्द शर्मा ने 6-8 अक्तूबर, 2010 तक डुसलडोर्फ तथा बर्लिन की यात्रा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने डुसलडोर्फ स्थित मिशन का उद्घाटन किया तथा नार्थ राइन वेस्टफालिया के आर्थिक कार्य, ऊर्जा, भवन, आवास तथा परिवहन राज्य मंत्री, श्री हैरी वॉयगसबर्गर से मुलाकात की। बर्लिन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने फ्रानहोफर फोरम में 'भारत-जर्मन आर्थिक संबंधों के चालक के रूप में परिवर्तन' नामक फिक्की-फ्रानहोफर गोलमेज को संबोधित किया। उन्होंने एशिया ब्राउन बोवेरी (एबीबी) कंपनी द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की यात्रा भी की। इस यात्रा के दौरान (i) फ्रानहोफर सोसायटी, केंद्रीय निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) बैंगलुरु तथा सीआईआई, (ii) फिक्की तथा आईमुव के बीच तीन समझौता ज्ञापनों; और (iii) व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर फिक्की और बीआईबीबी के बीच सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। श्री दयानिधि मारन, वस्त्र मंत्री ने भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने के लिए 3-5 फरवरी, 2010 तक फ्रेंकफर्ट की यात्रा की। श्री प्रफुल पटेल, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने बर्लिन एयर शो तथा आईएटीए एजीएम बैठक में भाग लेने के लिए बर्लिन की यात्रा की। श्री श्रीकांत जेना, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने 30 जून-2 जुलाई 2010 तक जर्मनी में सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, पत्तन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने पत्तन परिचालन का अध्ययन करने संबंधी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 2 जुलाई, 2010 को हैम्बर्ग, जर्मनी की यात्रा की। एडमिरल निर्मल वर्मा, नौसेना प्रमुख ने 22-26 अगस्त, 2010 तक जर्मनी की यात्रा की। बर्लिन में उन्होंने रक्षा सचिव, जर्मन चांसलर के विदेश और सुरक्षा नीति सलाहकार तथा वाइस-एडमिरल एक्सल स्किमफ, जर्मन नौसेना प्रमुख से मुलाकात की। एडमिरल वर्मा ने एकर्नफोर्ड तथा हैम्बर्ग में कैल नामक नौसेना बेस की भी यात्रा की।

भारत से अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में, श्री अशोक चावला, वित्त सचिव और श्री आलोक शील, संयुक्त सचिव (एमआर) की यात्रा, जिन्होंने 19 मई, 2010 को जी-20 डिप्टीस की बैठक तथा 20 मई, 2010 को वित्तीय बाजार विनियम संबंधी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बर्लिन की यात्रा की शामिल थी। श्री बी. के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग ने 26-28 मई, 2010 तक लिपजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, 2010 में भाग लेने के लिए जर्मनी की यात्रा की। उन्होंने भवन, परिवहन और शहरी विकास फेडरेल मंत्री, श्री पीटर रामसौर तथा श्री जेक शार्ट, सचिव, आईटीएफ से मुलाकात की। श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जर्मनी के कॉरपोरेट कानूनों और विनियमों में विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए 28-31 मई, 2010 तक जर्मनी में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री अजय आचार्य, विशेष सचिव (डीपी) ने आईएलए, 2010 के लिए 8-12 जून, 2010 तक बर्लिन की यात्रा की। डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष ने नैरोबी में राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन के अंतर्गत अध्ययन भ्रमण के भाग के रूप में 21-23 सितम्बर, 2010 तक बर्लिन की यात्रा की।

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (भारत सरकार के प्रधान सचिव) के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल तथा सदस्य मैकेनिकल रेलवे बोर्ड (सचिव, भारत सरकार) ने डयूश्च बाहन द्वारा आयोजित यूरोपीय एशियाई रेल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितम्बर 2010 में बर्लिन की यात्रा की। बर्लिन में प्रतिनिधिमंडल ने महत्वपूर्ण रेलवे औद्योगिक मेले इनोट्रांस को देखने के अवसर

प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह 13 अप्रैल, 2010 को
वाशिंगटन में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक के दौरान जर्मनी की चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल के साथ।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री श्री डेविड कैमरून
29 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस सम्मेलन में।

का लाभ उठाया। श्री बी.एस. मीना, सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार ने 63वें आईएए वाणिज्यिक वाहन प्रदर्शनी के दौरान 24 सितम्बर को हैनोवर में 'भारत दिवस, 2010' में भाग लेने के लिए 23-25 सितम्बर, 2010 तक जर्मनी की यात्रा की।

भारत-जर्मन परामर्शी समूह की 19वीं बैठक 22-24 अक्तूबर, 2010 तक बर्लिन में आयोजित की गई।

पश्चिमी और मध्य यूरोप (फ्रांस और यूके के अलावा) के मिशन प्रमुखों हेतु मिशन प्रमुखों का सम्मेलन 22-23 जनवरी, 2011 तक बर्लिन में आयोजित किया गया।

आयरलैंड

भारत-आयरलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर विकसित होते रहे। चूंकि, भारत आयरलैंड की एशिया रणनीति में प्रमुख देश बना रहा, द्विपक्षीय संबंधों को अधिक अर्थपूर्ण और पारस्परिक लाभकारी व्यवस्था में संवर्द्धित करने का लक्षित दृष्टिकोण बना रहा। व्यापार और निवेश में वर्ष के दौरान प्रकट वृद्धि हुई। सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की बढ़ती संख्या तथा शैक्षिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षेत्रों में बढ़ते आदान-प्रदान ने दोनों देशों के बीच संवर्द्धित द्विपक्षीय पारस्परिक विचार-विमर्श में योगदान दिया है।

कारपोरेट कार्य तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने पश्चिमी आयरलैंड में अहाकिस्ता में समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए 22-26 जून, 2010 तक आयरलैंड की यात्रा की, जहां एयर इंडिया 'कनिष्का' दुर्घटना की 25वीं बरसी मनायी गई थी। यात्रा के दौरान, उन्होंने आयरिश विदेश मंत्री, श्री माइकेल मार्टिन से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने संबंधी पहल पर चर्चा की। उन्होंने कार्क और डबलिन में उद्यम, व्यापार और नवाचार आयरिश मंत्री, श्री बैटओ कैफे तथा आयरिश व्यापारियों से भी मुलाकात की तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने संबंधी विचारों का आदान-प्रदान किया।

मार्च 2010 में संचार, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन आयरिश मंत्री, श्री एमन इयान ने सेंट पैट्रिक दिवस समारोह के लिए मुम्बई और दिल्ली की यात्रा की। यात्रा के दौरान मंत्री, इयान ने दोनों शहरों में भारतीय व्यापार और उद्योग के व्यापक वर्ग के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। दिल्ली में उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की तथा प्रगाढ़ भारत-आयरलैंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंध विकसित करने की संभावना पर व्यापक चर्चा की। भारत में मंत्री की चर्चा में द्विपक्षीय सहयोग हेतु विश्वनीय क्षेत्रों के रूप में वित्त, इंटरनेट, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि क्षेत्र की पहचान की गई।

आयरलैंड में आर्थिक मंदी के बावजूद, वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में सतत वृद्धि देखी गई, वस्तुओं और सेवाओं में कुल टर्नओवर 1 बिलियन यूरो के स्तर को पार कर गया। सेवाओं के व्यापार में वस्तुओं के व्यापार की तुलना में 20 प्रतिशत तीव्र वृद्धि हुई। मई 2010 में वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक ने 308 मिलियन अमरीकी डालर पर एंगलो-अमरीकी समूह से आयरलैंड की सबसे बड़ी जिंक की खान खरीदी।

इटली

भारत-इटली विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर नई दिल्ली में 26 मार्च, 2010 को आयोजित किया गया। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की तथा बहुपक्षीय विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय यात्राओं में शामिल थी, रोम में 'भारत में आधारभूत संरचना अवसर' पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री कमलनाथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (14-15 दिसम्बर, 2010) की यात्रा; लेक कॉमो में पर्यटन पर इटेलियन राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए सुश्री कुमारी शैलजा, पर्यटन मंत्री (14-18 अक्तूबर, 2010) की यात्रा; रोम में प्रमुख अर्थव्यवस्था के फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए श्री जयराम रमेश, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (29 जून-1 जुलाई 2010) की यात्रा; और स्ट्रेसा में 2010 आईआईएफ डिशले सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग (30 जून-1 जुलाई, 2010) की यात्रा। श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने उच्च-स्तरीय फिक्की प्रतिनिधिमंडल के साथ 30 जनवरी-2 फरवरी 2011 तक रोम और मिलान की यात्रा की।

राज्य स्तर पर व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश (17-23 जून, 2010); श्री भास्कर जाधव, पत्तन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार (4-6 जून, 2010); श्री नरेन्द्र ब्रागता, बागवानी मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार (12-16 जुलाई, 2010) द्वारा किया गया।

21 जुलाई, 2010 को श्री एच.एम. पल्लमराजु, रक्षा राज्य मंत्री (आरआरएम) ने यूके में एयर शो के अवसर पर फार्नबोरो में रक्षा अवर सचिव श्री गाइडो क्रोसेटो से मुलाकात की।

राजदूत (सेवानिवृत्त) सतीन्द्र के लाम्बा, अफगानिस्तान पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए रोम (18 अक्तूबर, 2010) की यात्रा की।

इटली के पर्यावरण उपमंत्री, श्री रोबर्टो मेनिया ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन, 2010 में भाग लेने के लिए 27-29 अक्तूबर, 2010 तक भारत की यात्रा की।

लक्समबर्ग

वर्ष के दौरान, लोक सभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-13 जून, 2010 तक लक्समबर्ग की यात्रा की। यात्रा के

दौरान, अध्यक्ष ने अपने लक्समबर्ग के समकक्ष श्री लारेंट मोसर, लक्समबर्ग के चैम्बर आफ डिप्टीस के अध्यक्ष के साथ चर्चा करने के अलावा हेनरी, लक्समबर्ग के ग्रेंड डयूक, श्री जीन-क्लाड जंकर, प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रियों तथा अधिकारियों से मुलाकात की। अध्यक्ष ने दोनों देशों की संसदों के बीच पारस्परिक संबंधों को जारी रखने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत की यात्रा करने के लिए अपने समकक्ष को भी आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त, लक्समबर्ग के अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार मंत्री श्री जीनोट क्रेके ने आर्थिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 9-14 जनवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की।

द्विपक्षीय व्यापार टर्नओवर 2008 में यूरो 37 मिलियन से बढ़कर 2009 में यूरो 44 मिलियन हो गया। वर्ष के दौरान दोहरे कराधान के परिहार तथा आय और पूंजी पर करों के संबंध में मौद्रिक अपवंचन की रोकथाम संबंधी करार, जिसपर 2 जून, 2008 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, लक्समबर्ग हेतु 1 जनवरी, 2010 तथा भारत हेतु 1 अप्रैल, 2010 को लागू हो गया।

पुर्तगाल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-पुर्तगाल संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 1-3 जुलाई, 2010 को लिसबन में आयोजित की गई। 2010-2012 हेतु सहयोग संबंधी कार्यक्रम को बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया तथा उस पर हस्ताक्षर किए गए।

पुर्तगाल ने 2011-2012 के लिए गैर-स्थाई यूएनएससी सीट तथा एसीएबीक्यू तथा एफएटीएफ जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

वर्ष 2010 के दौरान भारत से पुर्तगाल की यात्रा करने वालों में शामिल थे; श्री दिगम्बर कामत, गोआ के मुख्यमंत्री, 4-6 अक्तूबर, 2010, श्री एलिक्से स्केवेरा, विद्युत और पर्यावरण मंत्री, गोआ सरकार 17-18 जून, 2010 तथा लोक सभा सदस्य, श्री एम. बी. राजेश, 20-24 मई, 2010।

पुर्तगाल से प्रोफेसर कार्लोस जोरिन्हो, ऊर्जा और नवाचार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने 27-29 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लिया।

सड़क परिवहन/राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई ने आधारभूत संरचना क्षेत्र से भारतीय कंपनियों सहित 25-28 मई, 2010 तक लिस्बन में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय सड़क फेडरेशन-विश्व बैठक में भाग लिया। भारतीय उद्योग परिसंघ, असम के 14-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने पुर्तगाल में व्यापार-सह-अध्ययन यात्रा की।

सांस्कृतिक क्षेत्र में पारस्परिक यात्रा में शामिल थी; डॉ. सोनल मानसिंह और उनके दल की यात्रा, जिन्होंने लिस्बन और मेदिरा में कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा भारतीय फुटबॉल टीम की यात्रा, जिन्होंने जुलाई और अगस्त 2010 में दो महीने के लिए पुर्तगाल में मैच खेले।

सैन मारिनो

सुश्री एनटोनेला मुलारोनी, विदेशी और राजनैतिक कार्य, दूरसंचार और परिवहन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सैन मारिनो ने 11-12 नवम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान सैन मारिनो की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

स्पेन

भारत और स्पेन के बीच राजनैतिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं तथा दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि करने तथा प्रगाढ़ बनाने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। विगत दो वर्षों में कई उच्च-स्तरीय संपर्क हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्पेन की प्रथम राजकीय यात्रा अप्रैल 2009 में हुई, जिसके पश्चात स्पेन के क्राउन प्रिंस की राजकीय यात्रा नवम्बर 2009 में हुई तथा इसमें इस वर्ष द्विपक्षीय विचार-विमर्श को गति मिली।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (एनआरई) मंत्री ने 18-22 मई, 2010 तक स्पेन की यात्रा की। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ (फिक्की) द्वारा समन्वित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 16-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल मंत्री के साथ था। एनआरई मंत्री ने अपने समकक्ष स्पेन के उद्योग, पर्यटन और व्यापार मंत्री, श्री मिगुएल सेबसटिएन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एनआरई मंत्री ने जेनेरा, नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार मेले की यात्रा की तथा सौर विद्युत संयंत्रों की यात्रा की। एनआरई मंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्पेनिश उद्योग के साथ भी विचार-विमर्श किया। फिक्की ने स्पेनिश सौर ऊर्जा सोलरटाइस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम) ने 20-21 जून, 2010 तक स्पेन की यात्रा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अपने समकक्ष स्पेन के उद्योग, पर्यटन और व्यापार मंत्री श्री सेबसाटिएन तथा द्वितीय उपप्रधानमंत्री तथा अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री, सुश्री एलेना सालगाडो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रमुख स्पेनिश कंपनियों के सीईओ के समूह को संबोधित किया।

भारत-स्पेन आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त आयोग (जेईसी) का 9वां सत्र 21 जून, 2010 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री की यात्रा के दौरान मैड्रिड में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा स्पेनिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री मिगुअल सेबसटिन, उद्योग पर्यटन तथा व्यापार मंत्री द्वारा किया गया। पहली बार जेईसी मंत्रालयी स्तर पर आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने

आपसी हितों के क्षेत्र तथा द्विपक्षीय निवेश और व्यापार में वृद्धि करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने होरासिस द्वारा आयोजित तथा कई स्पेनिश संस्थानों के साथ फिक्की द्वारा सहयोजित ग्लोबल इंडिया बिजनेस बैठक, 2010 के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने स्पेन के उद्योग, पर्यटन तथा व्यापार मंत्री के साथ बैठक का उदघाटन किया। अस्टुरियास के प्रिंस, स्पेनिश क्राउन प्रिंस ने बैठक में विशेष भाषण प्रस्तुत किया। प्रमुख भारतीय उद्योगों के 30 से अधिक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में वृद्धि करने तथा वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने संबंधी रणनीतियों पर चर्चा की गई।

असम, केरल और तमिलनाडु की विधान सभाओं के अध्यक्ष क्रमशः श्री टांका बहादुर राय, श्री के. राधाकृष्णन तथा श्री आर. अवुदयप्पन तथा असम की विधान सभा की उपाध्यक्ष सुश्री प्रणति फुकन के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-21 सितम्बर, 2010 तक स्पेन की यात्रा की। केरल और तमिलनाडु विधानसभाओं के अध्यक्षों ने 21 सितम्बर, 2010 तक टोलेडो की यात्रा की तथा कादिला-ला मोचा के प्रेसीडेंट ऑफ द कोर्टस (संसद) से मुलाकात की।

स्पेन के ऊर्जा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, श्री पैड्रो मारीन ने 25 अक्तूबर, 2010 को भारत की यात्रा की। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की तथा सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, से मुलाकात की। श्री मारीन ने 20 से अधिक स्पेनिश कंपनियों के साथ दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2010 में भी भाग लिया।

अप्रैल से सितम्बर 2010 की अवधि में भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.78 बिलियन अमरीकी डालर था। व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था। वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार ने विगत वर्ष हेतु उसी अवधि की तुलना में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है।

जनवरी 2009 में हस्ताक्षरित विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसरण में 2009-2010 की अवधि हेतु सहयोग का सहमत कार्यक्रम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत तथा विज्ञान और नवाचार मंत्रालय, स्पेन के बीच इस कार्यक्रम में दोनों पक्षों ने सहयोग हेतु 6 क्षेत्रों की पहचान की। इन 6 क्षेत्रों में 25 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, स्पेन तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, भारत के बीच सहयोग संरचना के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है। दोनों समाजों में आपसी समझ को मजबूत बनाने के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण, फिल्म शो व प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। एक दूसरे के इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए संगोष्ठियों एवं विद्वानों की गोष्ठियों जैसे शैक्षणिक प्रारूप तथा छात्रवृत्ति के प्रावधान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य समारोह में, मैड्रिड के राष्ट्रीय नृत्य सभागार में 16-21 जून, 2010 तक भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य का एक लघु उत्सव आयोजित किया गया था, जिसके दौरान वालोडोलिड नगर में अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण किए गए थे, स्पेन की महामान्या महारानी ने उदघाटन प्रस्तुतिकरण में भाग लिया। गायक श्री पी उन्निकृष्णन, पंडित धनंज्य कौल, श्री टी. एस. मणी तथा डॉ. सोनल मानसिंह ने भी प्रस्तुतिकरण किए थे।

भारत-स्पेन ट्रिब्यून का 5वां सत्र 14-15 अक्तूबर, 2010 तक मैड्रिड में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजदूत सुधीर देवरे, महानिदेशक, भारतीय विश्व कार्य परिषद ने लिया था तथा स्पेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री एलेना पिजनेरो, भूतपूर्व राजदूत, फोर्ड सीडी तथा केपीएमजी स्पेन के वर्तमान सहभागी ने किया। स्पेन के विज्ञान व नवाचार मंत्री, डॉ. क्रिस्टिना गारमेंडिया ने सत्र का उदघाटन किया। निम्नलिखित चार शीर्षकों अर्थात (I) 21वीं शताब्दी के लिए ऊर्जा रणनीति, (II) ज्ञान समाज (III) मुख्य वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनैतिक चुनौतियां; और (IV) सुरक्षा मामलों तथा आतंकवाद में सहयोग पर ट्रिब्यून की चर्चा आयोजित की गई थी।

नीदरलैंड

अक्तूबर 2010 में नई सरकार की स्थापना के बाद द्विपक्षीय संबंधों में और तेजी आई।

19 सितम्बर, 2009 को हेग में आयोजित 'प्रवासी भारतीय दिवस' यूरोप की सफलता के बाद भारतीय मंच के साथ आदान-प्रदान एक प्राथमिकता रही है।

भारत के साथ आदान-प्रदान तथा समकालीन भारत के बारे में अधिक से अधिक समझ व ज्ञान विकसित करने के संबंध में नीदरलैंड की इच्छा प्रदर्शित करने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लीडन विश्वविद्यालय में समकालीन भारतीय अध्ययन के लिए सर्वप्रथम दीर्घावधिक पीठ स्थापित करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) तथा लीडन विश्वविद्यालय के बीच 8 दिसम्बर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह पीठ सितम्बर 2011 तक पूरी तरह आरंभ हो जाएगी।

गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अलग से पूरे वर्ष के कार्यकलापों की सूची तैयार की गई है।

व्यापार व निवेश प्रतिनिधिमंडलों की कई यात्राओं तथा व्यापार समारोहों के आयोजन से व्यापार व वाणिज्यिक संबंधों की प्रगाढ़ता व महत्व प्रदर्शित होता है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री सचिन पायलट ने एमस्टर्डम में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी, 2010 पर वर्ल्ड कांग्रेस (डब्ल्यूसीआईटी-2010) में भाग लेने के लिए 26-27 मई, 2010 तक नीदरलैंड में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्री ने डयूश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्थानीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बरों के प्रतिनिधियों, ड्यूस कंपनियों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नीदरलैंड में स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थानीय प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके बाद, राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा प्रदाता कंपनी संघ (नैसस्कॉम) द्वारा प्रायोजित 9-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में प्रचालन स्थापित करने के अवसरों का पता लगाने के लिए 9-10 दिसम्बर, 2010 को नीदरलैंड की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने ड्यूस की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भावी संयुक्त उद्यमों तथा गठबंधनों पर वार्ता करने के अलावा भारतीय एवं ड्यूस की आईसीटी कंपनियों के कार्यपालकों के साथ नेटवर्किंग सत्र में विचार-विमर्श किया।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और एक सरकारी एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ 15-17 जून, 2010 तक नीदरलैंड की यात्रा की। उन्होंने प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने के अलावा, निवेशक बैठक और एमस्टर्डम में संगोष्ठी को संबोधित किया।

मेघालय के मुख्यमंत्री, श्री मुकुम संगमा के साथ उप मुख्यमंत्री, श्री रोवेल लिंग्दोह तथा विधानसभा के तीन सदस्यों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 27-30 जून, 2010 के दौरान नीदरलैंड की यात्रा की।

कई भारतीय कंपनियों ने 19-23 अगस्त, 2010 के दौरान आयोजित नीदरलैंड के सबसे बड़े समुद्री कार्यकलाप समारोह 'सेल एमस्टर्डडम' में भाग लिया तथा इसमें लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने भाग लिया।

नीदरलैंड भारत चैम्बर आफ कामर्स एडं ट्रेड (एनआईसीसीटी), केपीएमजी तथा आईएनजी ने संयुक्त रूप से 16 सितम्बर, 2010 को 'भारत ड्यूश व्यापार संबंधों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक' विषय पर नीदरलैंड-भारत व्यापार बैठक 2010 (एनआईबीएम-2010) आयोजित की। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न डच तथा भारतीय कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

डे इंडस्ट्रीली ग्रूट क्लब (आईजीसी) में भारतीय पीठ ने 12 अक्तूबर, 2010 को 'विश्व के लिए प्रयोगशालाः अनुसंधान और विकास में भारत की बढ़ती शक्ति' पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें नीदरलैंड के नैगम समुदाय ने व्यापक रूप से भाग लिया।

भारी उद्योग विभाग के सचिव, श्री बी. एस. मीणा ने भारी उद्योग एवं अवस्थापना के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 24-29 अक्तूबर, 2010 तक एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्षा, श्रीमती भूपेन्द्र प्रसाद ने 8 दिसम्बर, 2010 को रोटरडैम में आयोजित 'विश्व नदी मंच' पर संगोंष्ठी मे भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नीदरलैंड की यात्रा की।

विदेश कार्यालय विचार-विमर्श 21 जनवरी, 2011 को हेग में आयोजित किया गया था।

भारतीय श्रम व रोजगार मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने 10-11 मई, 2010 तक हेग में वैश्विक बाल श्रम सम्मेलन, 2010 तथा साथ ही डच के सामाजिक मामले एवं रोजगार मंत्री व योरोपीय आयोग द्वारा 12-14 दिसम्बर, 2010 तक लीडन में एएसईएम-श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में भाग लिया।

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी), नई दिल्ली से 17-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 16-21 मई, 2010 तक नीदरलैंड की यात्रा की। इस दल ने डच के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा आर्थिक कार्य मंत्री के साथ-साथ नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान (क्लिजलेडायल) के प्रमुख विचार केंद्र के साथ आदान-प्रदान किया।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे), स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए), निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन (एचसीसीएच) रासायनिक हथियार निषेध संबंधी संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) तथा वस्तुओं के लिए साझा निधि (सीएफसी) सहित हेग में स्थित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विभिन्न बैठकों में सक्रियता से भाग लिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईपीपी) में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का अनुरीक्षण करना भी जारी रखा।

भारत ने बहुपक्षीय मंच में मुख्य सफलता प्रदर्शित करते हुए 25 जून, 2010 को नीदरलैंड की मध्यस्थता में एम्सटर्डम में आयोजित एफएटीएफ की पूर्ण बैठक में वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) की पूर्ण सदस्यता ग्रहण की।

भारत ने वस्तुओं के लिए साझा निधि के एम्सटर्डम न्यायालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपनी वचनबद्धताओं के अनुसार सीएफसी के साथ अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। भारत ने 14-15 अक्तूबर, 2010 तक एम्सटर्डम में आयोजित सीएफसी के कार्यपालक बोर्ड की 50वीं बैठक में भाग लिया, जोकि 12-13 अक्तूबर, 2010 को आयोजित सीएफसी के तदर्थ कार्य समूह की बैठक के बाद आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निधि की भावी भूमिका व अधिदेश तथा इसके दीर्घ कालिक पोषण पर विचार करना था। उसके पश्चात भारत को वर्ष 2011 के लिए सीएफसी के शासी परिषद का अध्यक्ष चुना गया। भारत नए अध्यक्ष के रूप में सीएफसी की भावी भूमिका और अधिदेश के बारे में अन्य गर्वनरों के सहयोग से विचार-विमर्श करेगा।

युनाइटेड किंगडम

27-29 जुलाई, 2010 के दौरान यूके के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन द्वारा भारत की सरकारी यात्रा इस वर्ष की मुख्य विशेषता है। प्रधानमंत्री कैमरॉन के साथ उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप संयुक्त घोषणा 'भविष्य के लिए भारत-यूके संवर्धित सहभागिताएं' जारी की।

प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन के साथ भारत यात्रा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें 6 मंत्री शामिल थे (अर्थात् विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री विलियम हेग, राजकोष के चांसलर, जार्ज आसबार्न, व्यापार नवाचार एवं निपुणता मंत्री, डॉ. विंसी केबल, संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री, जर्मी हंट, विश्वविद्यालय एवं विज्ञान राज्य मंत्री, डेविड विलेट्ज, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्यमंत्री ग्रेगरी बार्कर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर पीटर रिकेट्स)। प्रधानमंत्री कैमरॉन ने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से मुलाकात की तथा विपक्ष के नेता के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने यूके के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कैमरॉन ने वाणिज्य एवं उद्योग मत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा अपने साथ आने वाले कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर डेवॉस पद्धति में सीएनबीसी द्वारा प्रसारित दूरदर्शन की सीधी प्रसारण चर्चा में भाग लिया। यूके के प्रधानमंत्री ने 29 जुलाई, 2010 को प्रधानमंत्री के साथ सीमित वार्ता की। उन्होंने बैंगलोर की यात्रा की थी। हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लि. के संयंत्र में 57 अतिरिक्त हॉक एडवांस जेट ट्रेनर के विनिर्माण के लिए हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लि., ब्रिटिश एयरोस्पेश इंजीनियरिंग (बीएई) सिस्टम तथा रोल्स रॉयस के बीच 700 मिलियन पाउंड के करार पर भी हस्ताक्षर किए थे। दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। प्रधानमंत्री कैमरॉन ने भारत को स्थाई सीट देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए यूके के समर्थन को भी दोहराया। इस यात्रा के दौरान रतन टाटा तथा स्टैण्डर्ड चार्टर के पीटर सैंड की सह-अध्यक्षता में एक नया भारत-यूके निजी क्षेत्र से मंच स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह करार ब्रिटिश इंडिया अवस्थापना समूह स्थापित करने के लिए था, जिसका नेतृत्व दोनों पक्षकारों द्वारा किया जाएगा तथा जिसमें निजी क्षेत्र से नवप्रवर्तनकारी सहभागिता को शामिल किया जाएगा। यूके-भारत शिक्षा एवं अनुसंधान की सफल पहल को 2011 के बाद अन्य पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया था।

नियमित यात्राओं के माध्यम से संसदीय संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाया गया। यूके संसद से भारत के सभी तीनों मित्र समूहों ने भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत की यात्रा की। भारत-ब्रिटिश सांसद मंच ने 11-15 अक्तूबर, 2010 तक यूके की यात्रा की।

भारत से मंत्री स्तर व वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर यूके की निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण यात्राएं हुई हैं।

- वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री, श्री ज्योतिरदित्य सिंधिया ने 6-8 अप्रैल, 2010 तक यूके की यात्रा की।
- केंद्रीय भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्र। श्री विलासराव देशमुख ने 18 जून, 2010 को भारत हैवी इलौक्ट्रिकल्स लि. तथा शेफफील्ड फोर्जमास्टर इंटरनेशनल लि. (एसएफफार्डसन) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए शेफील्ड, यूके की यात्रा की।
- रक्षा राज्य मंत्री श्री एम. एम. पल्लमराजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 जुलाई, 2010 तक यूके में फार्नबारो अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदर्शनी-2010 में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल में सचिव (डीपी) एवं एओपी-इन-सी एसएसी, भारतीय वायु सेना भी शामिल थे।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने लंदन की यात्रा की; सीआईआई सीईओए का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 27-29 जून, 2010 तक यूके की यात्रा की। उन्होंने यूके के प्रधानमंत्री, यूके के विदेश सचिव और व्यवसाय, नवाचार एवं कौशल मंत्री डॉ. विंस कैबल से मुलाकात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 8-9 अक्तूबर, 2010 तक लंदन पुनः यात्रा की तथा व्यवसाय, नवाचार और कौशल मंत्री के साथ 9 अक्तूबर, 2010 को द्विपक्षीय बैठक की।
- विधि एवं न्याय मंत्री, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली ने न्याय मंत्री, श्री केनिथ क्लार्क के निमंत्रण पर 5-9 जुलाई, 2010 तक यूके की यात्रा की।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, श्री कमलनाथ ने 27-29 सितम्बर, 2010 तक लंदन की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन एवं सड़क क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान उन्होंने यूके के परिवहन मंत्री श्री फिलिप हैमोंड के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
- पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री मुरली देवड़ा ने न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (एनईएलपीआईएक्स) के नवें दौर की वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 7-8 अक्तूबर, 2010 तक लंदन की यात्रा की।
- लोक सभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार ने 'आइजल ऑफ मैन' में आयोजित कांफ्रेंस आफ स्पीकर्स एंड प्रेजाइडिंग आफीसर्स आफ द कॉमनवेल्थ (सीएसपीओसी) की स्थाई समिति में भाग लेने के लिए 12-15 जनवरी, 2011 तक संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और एक राष्ट्र की संसद की दूसरे राष्ट्र की संसद से संवाद बढ़ाने एवं सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए 16-19 जनवरी, 2011 तक लंदन की यात्रा की।

- भारत-यूके रक्षा परामर्शदात्री समूह की 13वीं वार्षिक बैठक 11 जनवरी, 2011 को लंदन में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रक्षा सचिव, श्री प्रदीप कुमार और यूके पक्ष का नेतृत्व यूके रक्षा मंत्रालय की स्थाई उप मंत्री, सुश्री उर्सुला ब्रेनेन ने किया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई।
- भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और यूके के व्यवसाय मंत्री स्तरीय भारत-यूके संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) की 7वीं बैठक 19 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- भारत और यूके के बीच 13वीं गोलमेज बैठक 18-20 फरवरी, 2011 तक सूरजकुंड में आयोजित किए जाने की संभावना है।

वर्ष के दौरान यूके की ओर से मंत्रालय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण यात्राएं भी की गई।

प्रिंस चार्ल्स ओर डचेस आफ कोर्नवाल ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समरोह में महारानी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2-5 अक्तूबर, 2010 तक भारत की यात्रा की। अर्ल आफ बेसेक्स, जोकि राष्ट्रमंडल खेल के उप संरक्षक भी हैं, ने भी उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

यूके आप्रवासन, मंत्री श्री डेमियन ग्रीन ने 23-25 अगस्त, 2010 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने यूके की आप्रवासन नीति पर व्यापक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री, श्री व्यालर रवी, विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रणीत कौर, पंजाब के राज्यपाल, श्री शिवराज पाटिल और पंजाब के मुख्यमंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री एम. रामचंद्रन से मुलाकात की।

लंदन शहर के लार्ड मेयर, निक एन्स्टी के नेतृत्व में एक व्यवसाय शिष्टमंडल ने 29 अक्तूबर-1 नवम्बर 2010 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने यूके और भारत के बीच संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए मुंबई और दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पूंजी बाजार अवसंरचना-वित्त और बैंकिंग के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया गया।

यूके के विश्वविद्यालय एवं विज्ञान मंत्री, डेविड विल्लेट्स ने दिल्ली, बंगलौर और पुणे की एक सप्ताह की यात्रा करने के लिए 11 नवम्बर, 2010 को भारत की यात्रा की। दिल्ली में प्रवास के दौरान उन्होंने मानव संसाधन विकास, कृषि तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रियों एवं बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। श्री विल्लेट्स ने यूके-भारत शिक्षा मंच की सह अध्यक्षता की। इस यात्रा के दौरान यूकेआईई आरआई-।। की शुरुआत की गई।

यूके के रक्षा मंत्री, डॉ. लियम फॉक्स ने 22-23 नवम्बर, 2010 को दिल्ली की यात्रा की। यह 2005 से यूके के किसी कार्यकारी रक्षा मंत्री की प्रथम भारत यात्रा थी। डॉ. फॉक्स ने रक्षा मंत्री, श्री ए. के. एंटोनी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री, श्री एंड्रयू मिचेल ने 24-27 नवम्बर, 2010 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने वित्त मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बैठकें कीं।

यूके भारत का बड़ा व्यापार साझेदार है। 2009-2010 में भारत ने यूके में 6.228 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया और यूके की ओर से 4.423 बिलियन अमरीकी डालर का आयात हुआ।

सीमाथुरक मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में संशोधित समझौता ज्ञापन, जिस पर 9 नवम्बर, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे, को प्रचालनीय बना दिया गया है। उक्त समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नोडल संपर्क बिंदु स्थापित कर दिए गए हैं, ताकि सूचना के आदान-प्रदान और समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहायता को सुविधाजनक बनाया जा सके।

यूरोपीय संघ

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, जिनकी रणनीतिक साझेदारी साझे मूल्यों और कानून व्यवस्था, मानवाधिकार के लिए सम्मान और बुनियादी स्वतंत्रता पर आधारित है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बातचीत होती रही है, जिसमें सन् 2000 के बाद से हुई 11 शिखर बैठकें शामिल हैं। भारत-ईयू संयुक्त कार्य योजना जो 2005 में अपनाई गई थी और 2008 में जिसकी समीक्षा की गई थी, आज भी भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग का मानक बना हुआ है।

भारत ने यूरोपीय संघ के साथ प्रगाढ़ संबंध जारी रखे। यूरोपीय संघ सामान्य जीडीपी मायने में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक और उन्नत प्रौद्योगिकी, विशेषकर ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों के संबंध में, का भंडार है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और विदेशी निवेशों का महत्वपूर्ण स्रोत है। 2010 में लिस्बन संधि के कार्यान्वयन से यूरोपीय संघ को नया आयाम प्राप्त हुआ है, यूरोपीय संघ के भीतर समाकलन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है और यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद सहित ईयू संस्थानों की क्षमताओं में वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे यूरोपीय संघ का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्वाभाविक रूप से दोनों देशों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों के व्यापक पहलू के संबंध में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ता जाएगा।

कुल मिलाकर यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था से जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देशों की अर्थव्यवस्था सुधरी है। यूनानी संकट के प्रत्युत्तर में यूरोजोन सदस्य देशों ने अस्थाई उपाय के रूप में मई 2010 में यूरोपीय वित्तीय स्थिरीकरण सुविधा (ईएफएसएफ)

और यूरोपीय वित्तीय स्थिरीकरण तंत्र (ईएफएसएम) स्थापित किए हैं। यूरोपीय स्थिरीकरण तंत्र, (ईएसएम) नामक एक नया स्थाई तंत्र जो 2013 के मध्य में ईएफएसएफ की अवधि समाप्त होने पर इसका स्थान लेगा, पर नवम्बर 2010 में यूरोजोन वित्त मंत्रियों द्वारा सहमति हो गई थी तथा जिसे 16-17 दिसम्बर, 2010 को आयोजित यूरोपीय परिषद की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था। जैसाकि लिस्बन संधि में प्रावधान किया गया है, यूरोपीय संघ ने औपचारिक तौर पर 1 दिसम्बर, 2010 को यूरोपीय विदेशी कार्य सेवा (ईईएएस) भी प्रारंभ की है। ईईएएस के यूरोपीय सदस्य देशों के बीच विदेश नीति के बेहतर समन्वय में सहायता करने की उम्मीद है और इससे यूरोपीय संघ द्वारा विश्व स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने में आसानी होगी। विदेश कार्य और सुरक्षा नीति के ईयू उच्च प्रतिनिधि स्लेडी कैथेराइन एशटनऔरईयू व्यापार आयुक्त श्री कैरेल डी गुच्च ने शिखर बैठक में भाग लिया।

भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक

11वीं भारत-ईयू शिखर बैठक 10 दिसम्बर, 2010 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। यह लिस्बन संधि के लागू होने के बाद प्रथम शिखर बैठक थी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हरमन वान रोम्पी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, श्री जोस मैनुएल बरोसो ने यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया। यूरोपीय संघ की ओर से यह पहला अवसर था कि जब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने अध्यक्ष बरोसो के साथ बैठक की, जिससे लिस्बन संधि से हुए परिवर्तन परिलक्षित होते हैं।

इस शिखर बैठक में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों की समीक्षा की गई; 2011 के वसंत में एक महत्वाकांक्षी और संतुलित भारत-ईयू व्यापक व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए) संपन्न कराने के महत्व पर जोर दिया गया; सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का स्वागत किया गया; और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक संयुक्त घोषणा जारी की गई। इस शिखर बैठक के दौरान संस्कृति पर भारत-ईयू संयुक्त घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं द्वारा जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में 2011 में प्रस्तावित अगली भारत-ईयू शिखर बैठक में ऊर्जा, स्वच्छ विकास और जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2008 संयुक्त कार्य कार्यक्रम के परिणाम प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की गई। संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए शीघ्र भारत-ईयू करार करने; 2005 में प्रारंभ किए गए उपग्रह नौवहन संबंधी करार को शीघ्र अंतिम रूप देने; और नागरिक उड्डयन करार के शीघ्र कार्यान्वयन का भी आह्वान किया गया।

इस शिखर बैठक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जी-20, जलवायु परिवर्तन और निस्त्रीकरण समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इस शिखर बैठक के अवसर पर भारत-ईयू व्यवसाय शिखर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा और यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त, श्री कैरेल डी गुच्च ने भाग लिया।

यूरोपीय संसद

यूरोपीय संसद सितम्बर 2009 में औपचारिक रूप से गठित भारतीय शिष्टमंडल ने 25-30 अप्रैल, 2010 तक भारत की यात्रा की। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष ग्राहम वाटसन ने किया, जोकि यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य हैं और उन्होंने भारत के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से मुलाकात की।

भारत-ईयू मंत्रालयी और वरिष्ठ अधिकारी स्तर की बैठक

21वीं भारत-ईयू मंत्रालयी बैठक 22 जून, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री, श्री एस. एम. कृष्णा ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। लिस्बन संधि के लागू होने के बाद ईयू का नेतृत्व पहली बार इसके विदेश कार्य एवं सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि, सुश्री कैथेराइन एशटन ने किया। नेताओं ने भारत-ईयू रणनीतिक साझीदारी की समीक्षा की और साथ ही जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक वित्तीय संकट, निशस्त्रीकरण और ऊर्जा सुरक्षा सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

भारत और ईयू के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों (एओएम) का एक नियमित तंत्र भी है। 2010 में, भारत-ईयू वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 21 अक्तूबर, 2010 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई।

वार्ताएं

चौथी भारत-ईयू सुरक्षा वार्ता 8 जून, 2010 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने विचारों का आदान-प्रदान किया और सुरक्षा और इससे जुड़े मुद्दों पर सहयोग सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की।

सिविल सोसाइटियों के बीच विचार-विमर्श

आईसीडब्ल्यूए और सुरक्षा अध्ययन संबंधी यूरोपीय संघ संस्थान (ईयूआईएसएस) द्वारा संयुक्त रूप से गठित प्रभावी बहुपक्षवाद संबंधी दूसरे भारत-ईयू मंच की 11-12 अक्तूबर, 2010 को ब्रुसेल्स में बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों के सहभागियों ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन, जलदस्युता विरोधी कार्रवाई में सहयोग आदि सहित भारत-ईयू संबंधों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

व्यापार और निवेश

27 देशों के समूह के रूप में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है, जबकि भारत 2009 में यूरोपीय संघ का

9वां सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। 2008 के आंकड़ों की तुलना में 2009 में 13.5 प्रतिशत के घाटे से 52.9 बिलियन यूरो का कुल व्यापार हुआ। (भारतीय निर्यात-25.4 बिलियन यूरोः भारतीय आयात-27.5 बिलियन यूरो)। तथापि (जनवरी-जुलाई, 2010 की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ को भारतीय निर्यात में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ 18.8 बिलियन यूरो और आयात में 26 प्रतिशत वृद्धि के साथ 15.7 बिलियन यूरो तक पहुंचा । 2009 में, विभिन्न सेवा क्षेत्र में यूरोपीय संघ में कुल भारतीय निर्यात 7.5 बिलियन यूरो था, जबकि यूरोपीय संघ से कुल भारतीय आयात 8.8 बिलियन यूरो था।

2009 में 2.88 बिलियन यूरो की तुलना में 2008 में यूरोपीय संघ से भारत में एफडीआई अंतर्वाह 3.27 बिलियन था। एफडीआई के लिए यूरोपीय संघ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश हैः - जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फ्रांस। वर्ष 2008 में भारतीय निवेश में 3.69 बिलियन यूरो की तुलना में 2009 में 940 मिलियन यूरो की गिरावट भी देखी गई है।

महत्वपूर्ण यात्राएं

भारत और यूरोपीय संघ के बीच महत्वपूर्ण यात्राओं में प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह की यात्राएं शामिल हैं, जिन्होंने 9-11 दिसम्बर, 2010 तक आयोजित भारत-ईयू शिखर बैठक में भाग लेने के लिए उस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा भी शामिल थे। उपराष्ट्रपति, श्री मोहम्मद अंसारी ने एशिया-यूरोप बैठक और शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 3-5 अक्तूबर, 2010 तक ब्रुसेल्स की यात्रा की। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'ग्लोबल जॉब क्राइसिस से उबरने के संदर्भ में कौशल एवं रोजगार नीति पर संयुक्त घोषणा' विषयक चौथी ईयू-भारत बैठक और त्रिपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 5-9 जुलाई, 2010 तक ब्रुसेल्स की यात्रा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अपने ईयू समकक्षों के साथ बैठक करने के लिए 28-30 नवम्बर, 2010 तक ब्रुसेल्स की यात्रा की।

यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त कैरेल डी गुच्च ने 3-5 मार्च, 2010 तक भारत की यात्रा की और उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। जलवायु कार्य आयुक्त, कौनी हेडेगार्ड ने 7-9 अप्रैल, 2010 तक भारत की यात्रा की और उन्होंने पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री आदि के साथ बैठकें की। विदेश कार्य एवं सुरक्षा नीति की ईयू उच्च प्रतिनिधि, सुश्री कैथेरीन एशटन ने भारत-ईयू मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए 22-25 जून, 2010 तक भारत की यात्रा की।

■■

8 अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए)

वर्ष 2010 में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत के प्रधान मंत्री की नवंबर 2009 की वाशिंगटन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा घोषित वैश्विक सामरिक भागीदारी का संवर्धन और विस्तार करना जारी रखा।

इस वर्ष बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति होने के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा मिला तथा कुछ ऐसे करार और पहल किए गए, जो भारत-अमरीकी सामरिक भागीदारी को नए स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इस विस्तारित कार्यकलाप की झलक नवंबर 2010 में अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा और प्रथम मंत्रिस्तरीय भारत-अमरीका सामरिक वार्ता में मिली, जिसकी सहअध्यक्षता वाशिंगटन डीसी में जून 2010 में भारत के विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन द्वारा की गई थी। राजनैतिक, सामरिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर होने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त दोनों पक्षों ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, सुरक्षा तथा सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में भी सम्पर्कों का विस्तार करने की प्राथमिकता का संकेत दिया। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ओबामा ने अप्रैल 2010 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और जून 2010 में टोरंटो में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी अतिरिक्त समय में एक दूसरे से मुलाकात की।

इस वर्ष हुए उच्चस्तरीय आदान-प्रदानों में निम्नलिखित शामिल थे सितंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान अतिरिक्त समय में न्यूयार्क में विदेश मंत्री और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन की बैठक; अक्तूबर माह में वाशिंगटन डीसी में अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन के साथ वित्त मंत्री की मुलाकात; सितंबर माह में रक्षा मंत्री की वाशिंगटन डीसी की द्विपक्षीय यात्रा; सितंबर माह में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की वाशिंगटन डीसी की यात्रा; जून और सितंबर माह में मानव संसाधन विकास मंत्री की यात्रा; जून माह में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की यात्रा; जून माह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की यात्रा; जून माह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की यात्रा; सितंबर 2010 और जनवरी 2011 में वाशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठकें; जुलाई और दिसंबर 2010 में प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री एस. के. लाम्बा की यात्रा; और सितंबर 2010 तथा फरवरी 2011 में विदेश सचिव की यात्रा। संयुक्त राज्य अमरीका से भारत की यात्रा पर आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में शामिल हैं, वित्त मंत्री टिमोथी गीथनर (अप्रैल 2010), वाणिज्य मंत्री गैरी लॉक (नवंबर 2010 और फरवरी 2011); कृषि मंत्री विलसेक (नवंबर 2010 और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जुलाई 2010)।

इस वर्ष निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुईं: असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करार का कार्यान्वयन करने के लिए दोनों सरकारों द्वारा शेष प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना;विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के भारत के दावे के प्रति अमरीकी समर्थन के संबंध में राष्ट्रपति ओबामा की घोषणा; भारत के लिए निर्यात नियंत्रणों में ढील दिए जाने संबंधी अमरीकी निर्णय;चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (आस्ट्रेलिया समूह, वासनर व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था) में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए अमरीकी समर्थन की घोषणा; पूर्व एशिया वार्ता सहित विस्तारित सामरिक विचार-विमर्श; जुलाई 2010 में हस्ताक्षरित आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग संबंधी पहल; नई होमलैंड सुरक्षा वार्ता; मार्च 2010 में संपन्न कृषि एवं खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; अप्रैल 2010 में आरंभ की गई वित्तीय एवं आर्थिक भागीदारी; भारत में स्थापित किए जा रहे वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन; स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अनेक नई पहलकदमियां; और राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के दौरान लोकतंत्र एवं विकास के लिए नई अंतराष्ट्रीय भागीदारी का शुभारंभ।

प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति ओबामा ने नवंबर 2010 में नई दिल्ली में इस बात की पुष्टि की कि भारत-अमरीका सामरिक भागीदारी न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि 21वीं सदी में वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है।

राष्ट्रपति बराक ओबामा का दौरा

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमारे प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर 6-9 नवंबर, 2010 तक भारत का राजकीय दौरा किया। यह उनकी पहली यात्रा थी, जो नवंबर 2009 में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के उपरान्त हुई। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। प्रथम महिला मिशेल ओबामा और लगभग 200 अमरीकी व्यवसाइयों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आया था।

राष्ट्रपति ओबामा ने मुम्बई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ 6 नवंबर, 2010

7 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में पालम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर अमरीकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

से अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने सीआईआई-फिक्की-यूएसआईबीसी व्यावसायिक बैठकों को संबोधित किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं उद्यमियों से मुलाकात की और टाउन हॉल शैली की बैठकें की जिनमें युवाओं, शिक्षा, कृषि, ई-शासन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया।

8 नवंबर, को दिल्ली में उनके आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल थे, प्रधान मंत्री के साथ बैठक तथा पारस्परिक हित के वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत। दोनों नेताओं ने भारत-अमरीकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की बैठक की भी अध्यक्षता की और एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ओबामा ने संसद सदस्यों को संबोधित किया तथा माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विपक्ष की नेता और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा से भी मुलाकात की। यह यात्रा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर पारस्परिक समझबूझ को सुदृढ़ बनाने, हमारे द्विपक्षीय सहयोग को गतिशीलता प्रदान करने और सामरिक भागीदारी को नए स्तर तक उन्नयित करने के लिए एक दीर्घावधिक रूपरेखा का सृजन करने में सफल रही।

राष्ट्रपति ओबामा द्वारा विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के भारत के दावे के प्रति अमरीकी समर्थन की पुष्टि किया जाना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा जिससे दोनों सरकारों के इस साझे विश्वास की पुष्टि हुई कि न्यायसंगत और स्थाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी, विश्वसनीय और वैध संयुक्त राष्ट्र आवश्यक है।

अमरीका ने भारत को दोहरे उपयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के उपायों, इसरो और डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाले संगठनों को अमरीकी इकाई सूची से हटाने, अपने निर्यात नियंत्रण विनियमों में भारत के साथ सामंजस्य स्थापित करने, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, आस्ट्रेलिया समूह और वासनर व्यवस्था में भारत की सदस्यता का समर्थन करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

दोनों देशों ने अफगानिस्तान, पूर्व एशिया, मध्य एवं पश्चिम एशिया और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े घटनाक्रमों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारत द्वारा किए जा रहे योगदानों की सराहना की। दोनों देशों ने अफगान सरकार के परामर्श से क्षमता निर्माण, कृषि एवं महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त विकास परियोजनाओं पर कार्य करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

दोनों देशों ने अप्रसार तथा सार्वभौमिक और निष्पक्ष वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने तथा परमाणु आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र जिसकी स्थापना भारत में की जा रही है, में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया।

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने लोकतंत्र एवं विकास हेतु साझी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पहल का शुभारंभ किया जिसमें अफ्रीका सहित अन्य देशों में कृषि विकास एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का समर्थन करना शामिल है। आर्थिक सहयोग पर विशेष बल दिया गया जिसमें दोनों देश व्यापार बाधाओं एवं संरक्षणवादी उपायों को समाप्त करने तथा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने अनेक नई द्विपक्षीय पहलकदमियों की घोषणा की जिनमें शामिल हैं संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना पर करार/समझौता ज्ञापन; भारत में शिला गैस संसाधनें का दोहन और आकलन; ऊर्जा सहयोग कार्यक्रम का निर्माण; भारत में वैश्विक रोग पहचान केंद्र की स्थापना; तथा संवर्धित मानसून पूर्वानुमान जिससे वर्ष 2011 के मानसून से आरंभ करते हुए किसानों के लिए विस्तृत पूर्वानुमान संप्रेषित किए जाएंगे।

सामरिक वार्ता

जुलाई 2009 में दोनों सरकारों ने मंत्रिस्तरीय सामरिक वार्ता का शुभारंभ किए जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की जिसमें पारस्परिक हित की चार आधारशिलाओं अर्थात सामरिक सहयोग, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और विकास;अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि;विज्ञान और प्रौद्योगिकी; तथा स्वास्थ्य और नवाचार के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों और वार्ता तंत्र पर विशेष बल दिया जाएगा। व्यापक वार्ता रूपरेखा में द्विपक्षीय कार्यकलाप के 18 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

विदेश मंत्री तथा अमरीकी विदेश मंत्री ने 3 जून, 2010 को वाशिंगटन डीसी में पहली भारत-अमरीका सामरिक वार्ता की सहअध्यक्षता की। भारत सरकार के प्रतिनिधमंडल में हमारे संसाधन विकास मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विदेश सचिव, पर्यावरण सचिव, जैव प्रौद्योगिकी सचिव तथा विशेष सचिव (गृह) शामिल थे। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य मंत्री, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमरीकी एआईडी प्रशासक, राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार, उप मंत्री (ऊर्जा), नासा प्रशासक तथा वैश्विक मामलों के अंडर सेक्रेटरी शामिल थे। भारत के साथ अमरीकी संबंधों के प्रति व्यक्तिगत वचनबद्धता संप्रेषित करते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने इस अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लिया और कहा कि अमरीका भारत के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है और भारत ''हमारे सपनों के भविष्य के लिए अनिवार्य'' है।

श्रीमती क्लिंटन ने कहा कि अमरीका और भारत के बीच विस्तारित भागीदारी ओबामा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने भारत को एक विश्वसनीय और अपरिहार्य मित्र बताया। इस बातचीत से पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने, दोनों सरकारों द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए मध्यम अवधि की कार्ययोजना तैयार करने

30 अक्तूबर, 2010 को हनोई, वियतनाम में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन के साथ मुलाकात करते हुए।

और नवंबर 2010 में होने वाली राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा की योजना बनाने का अवसर मिला। अगली सामरिक वार्ता का आयोजन अप्रैल 2011 में नई दिल्ली में किया जाएगा।

राजनैतिक और सामरिक परामर्श

इस वर्ष दोनों पक्षों के बीच राजनैतिक एवं सामरिक परामर्श और भी गहन एवं विस्तारित हुए। भारत-अमरीका राजनैतिक कार्यकलापों में आपसी हित के सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों अर्थात भारत के तात्कालिक पड़ोस में स्थिरता और सुरक्षा की चुनौती, आतंकवाद के खतरे, नई और वर्तमान अप्रसार चुनौतियों, पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के घटनाक्रमों तथा वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति पर विशेष बल दिया गया। इस बातचीत से आपसी समझबूझ में वृद्धि हुई और अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों में समानता आई जिसके फलस्वरूप भारत-अमरीकी वैश्विक सामरिक भागीदारी और सुदृढ़ हुई।

भारत के प्रधान मंत्री राष्ट्रपति ओबामा ने एशिया में मुक्त, संतुलित और समावेशी रूपरेखा का विकास किए जाने के लिए इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने स्थिर, लोकतांत्रिक, समृद्ध और स्वतंत्र अफगानिस्तान को बढ़ावा देने के लिए परामर्श, सहयोग और समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेता पूर्व एशिया के घटनाक्रमों पर जारी सामरिक परामर्शों को गहन बनाने पर सहमत हुए और उन्होंने मध्य एवं पश्चिम एशिया सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक हित के अन्य सभी मुद्दों पर सामरिक विचार-विमर्श को विस्तारित और गहन बनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रों की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए हवाई, समुद्री, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपने साझे विजन का विकास करने हेतु अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए एक वार्ता तंत्र की शुरुआत की है। इस वार्ता तंत्र की पहली बैठक अक्तूबर 2010 में वाशिंगटन डीसी में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया।

भारत और अमरीका ने अपनी पारस्परिक समझबूझ को सुदृढ़ बनाया है और दोनों देश 21वीं सदी में अप्रसार एवं सार्वभौमिक तथा निष्पक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में किए जा रहे वैश्विक प्रयासों की अगुआई कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना हमारे कार्यकलापों का एक नया तत्व है जिससे आतंकवादियों द्वारा परमाणु हथियारों अथवा सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त करने के खतरों में कमी आएगी। दोनों पक्षों ने भारत में स्थापित किए जा रहे वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र में सहयोग करने हेतु नवंबर 2010 में एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया।

आतंकवाद का मुकाबला

दोनों सरकारों ने नियमित बातचीत, क्षमता निर्माण तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के जरिए आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग को सवंर्धित करना जारी रखा। इस वर्ष जुलाई 2010 में हस्ताक्षरित आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग संबंधी पहल (सीसीआई) और होमलैंड सुरक्षा वार्ता जैसी पहलकदमियां की गईं। आशा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध द्विपक्षीय संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक मार्च 2011 में नई दिल्ली में होगी जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने में जारी सहयोग की समीक्षा की जाएगी।

राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दोहराया कि लश्कर-ए-तैयबा सहित अन्य सभी आतंकी नेटवर्कों का सफाया किया जाना होगा और पाकिस्तान को मुम्बई आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं को दण्डित करना होगा। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अवसंरचनाओं और सुरक्षित आश्रय स्थलों का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों ने प्रचालनात्मक सहयोग को गहन बनाने, आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी प्रौद्योगिकी का अंतरण किए जाने, क्षमता निर्माण तथा आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को संरक्षित रखने पर अपनी सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर मौजूद आतंकी ठिकाने अस्वीकार्य हैं।

विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (राजनैतिक) ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच की पहली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसका आयोजन अमरीकी सरकार द्वारा विश्व स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला किए जाने हेतु किए जाने वाले प्रयासों के एक भाग के रूप में किया गया था।

5 नवंबर, 2010 को अमरीकी सरकार ने एलईटी के आजम चीमा (मुम्बई हमला, 2006 और 2008), हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (एलईटी), मुहम्मद मसूद, और अजहर अल्वी (जेईएम संस्थापक) को वित्त मंत्रालय की आतंकी सूची में शामिल कर दिया गया जिसके तहत अमरीकी नागरिकों के साथ उनके कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अमरीकी सरकार को अमरीकी क्षेत्राधिकार में उनकी संपत्तियों को फ्रीज करने हेतु समर्थ बना दिया गया।

अमरीकी प्राधिकारियों ने मुम्बई आतंकी हमलों की जांच के संदर्भ में भारतीय एजेंसियों को मई-जून 2010 में डेविड हेडली तक संपर्क मुहैया कराया जो अमरीका में कैद है।

अमरीकी होमलैंड सुरक्षा उपमंत्री सुश्री जेन हौल लूते ने दिल्ली में अप्रैल 2011 में हमारे गृह मंत्री और अमरीकी होमलैंड सुरक्षा मंत्री द्वारा आरंभ की जाने वाली पहली होमलैंड सुरक्षा वार्ता हेतु तैयारियों पर चर्चा करने के लिए 11-12 जनवरी, 2011 तक भारत का दौरा किया।

प्रतिरक्षा

नवंबर 2010 में राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के दौरान दोनों सरकारों ने सुरक्षा वार्ता, संयुक्त अभियानों तथा प्रतिरक्षा

उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने सहित अन्य तरीकों के जरिए रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

वर्ष 2010 के आरंभ में अमरीकी रक्षा मंत्री राबर्ट गेट्स की यात्रा के उपरान्त 27-28 सितंबर, 2010 को रक्षा मंत्री ने अमरीका का दौरा किया और वहां के रक्षा एवं विदेश मंत्री से विचार-विमर्श किया। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख एडमिरल माइकल मुलेन तथा रक्षा अंडर सेक्रेटरी सुश्री माइकल फ्लोर्नोय ने भारत में अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने के लिए भारत का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख तथा नौसेना प्रमुख ने क्रमशः मई 2010 और सितंबर 2010 में अमरीका का दौरा किया। मई 2010 में वाशिंगटन में आयोजित भारत-अमरीका रक्षा खरीद और उत्पादन समूह की बैठक से अमरीका से रक्षा सामानों की खरीद से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने का उपयोगी अवसर मिला। द्विपक्षीय रक्षा खरीद एवं उत्पादन समूह तथा रक्षा नीति समूह की अगली बैठकें 1-4 मार्च, 2011 तक वाशिंगटन डीसी में होंगी जिनकी अध्यक्षता क्रमशः रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और रक्षा सचिव द्वारा की जाएगी।

अक्तूबर-नवंबर 2010 में अलास्का में भारत और अमरीका की सेनाओं के द्वारा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किए गए जिसमें विदेश गई आज तक की भारतीय थल सेना की सबसे बड़ी टुकड़ी ने भाग लिया। दोनों देशों की नौसेनाओं ने गोवा तट पर 'मालाबार, 2010' नामक वार्षिक अभ्यास में भी भाग लिया।

हाल में अमरीका से चार बिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि की रक्षा खरीद की गई है। इस वर्ष अमरीका ने सी130जे परिवहन विमान की आपूर्ति शुरू कर दी है।

असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग

दोनों सरकारों ने अक्तूबर 2008 में हस्ताक्षरित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग से संबद्ध करार को कार्यान्वित करने के लिए शेष उपाय पूरे कर लिए। अगस्त 2010 में अपशिष्ट अमरीकी परमाणु ईंधन के पुनर्संसाधन हेतु व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं से संबद्ध करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत ने भी सितंबर 2010 में परमाणु असैन्य दायित्व विधेयक का अधिनियमन किया और 4 नवंबर, 2010 को पूरक मुआवजे से संबद्ध एक अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। अमरीकी प्रशासन ने भारतीय ऑपरेटरों के साथ बातचीत आरंभ करने के लिए अमरीकी कंपनियों को लाइसेंस जारी करने की दिशा में आवश्यक उपाय पूरे कर लिए। अमरीकी कंपनियों और भारत में ऑपरेटरों के बीच बातचीत आरंभ हो गई है।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा प्रभाविता क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने प्रोन्नत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी (पीएसीई) के जरिए भविष्य के लिए हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की जिसके तहत स्वच्छ एवं ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकियों, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, शिला गैस और स्मार्टग्रिडों के क्षेत्र अनुसंधान और इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस वर्ष ऊर्जा क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय पहलकदमियों में दोनों सरकारों की संयुक्त वित्तीय सहायता से संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना हेतु नवंबर 2010 में हस्ताक्षरित करार शामिल है जिसमें भवनों में सौर ऊर्जा, द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों और ऊर्जा प्रभाविता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नवंबर 2010 में हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोग कार्यक्रम की स्थापना से संबद्ध करार से ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। 30 सितंबर, 2010 को दोनों पक्षों ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण एवं ऊर्जा प्रभाविता प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण एवं नवाचार हेतु भागीदारी करारों पर हस्ताक्षर किए जिनका कार्यान्वयन पांच वर्षों की अवधि में किया जाएगा। नवंबर 2010 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, अमरीका भारत में शिला गैस के आकलन और दोहन में सहायता करेगा। अमरीकी राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला ने पूरे भारत के लिए सौर मानचित्रण और जीआईएस आंकड़ों के क्षेत्र में तकनीकी सहायता की है, जो अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

व्यापार और निवेश

सामानों और सेवाओं के व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि और संतुलन तथा दोनों ओर से निवेशों में हो रही वृद्धि भारत-अमरीकी आर्थिक संबंधों की विशेषता है। राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार बाधाओं और संरक्षणवादी उपायों में कमी लाने तथा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की जिससे कि व्यापार और निवेश की असीम क्षमताओं को पूर्णरूपेण प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रपति महोदय की यात्रा के दौरान ही अमरीकी कंपनियों के साथ कुल 15 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का कारोबार संपन्न किया गया।

दोनों सरकारों के पास द्विपक्षीय व्यापार पहुंच तथा व्यापार और निवेश से जुड़े अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए सुविकसित तंत्र विद्यमान हैं। हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि की सहअध्यक्षता में व्यापार नीति मंच की बैठक 20-21 सितंबर, 2010 को वाशिंगटन में हुई और आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी का शुभारंभ अप्रैल 2010 में नई दिल्ली में वित्त मंत्री और अमरीकी वित्त सचिव द्वारा किया गया। भारत-अमरीका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक दिसंबर 2010 में हुई।

भारत सरकार ने अमरीका में, खासकर सेवा क्षेत्र में विद्यमान संरक्षणवादी भावनाओं और कुशल कामगारों के लिए वीजा

शुल्क में वृद्धि किए जाने पर अपनी चिन्ताओं से अमरीकी सरकार को अवगत कराया जिसका भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

विदेश सचिव और अमरीकी वाणिज्य अंडर सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाले उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी) की पिछली बैठक मार्च 2010 में वाशिंगटन डीसी में हुई। इसकी अगली बैठक वर्ष 2011 के आरंभ में नई दिल्ली में होगी।

अमरीकी वाणिज्य मंत्री गैरी लाक के नेतृत्व में एक उच्च अधिकार प्राप्त व्यावसायिक मिशन ने 5-11 फरवरी, 2011 तक भारत का दौरा किया। यह मिशन नई दिल्ली, बंगलोर और मुम्बई भी गया। वाणिज्य मंत्री श्री लॉक ने बंगलोर में आयोजितय एयरो इंडिया प्रदर्शनी में भाग लिया और उन्होंने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ मुलाकात की।

अंतरिक्ष

दोनों सरकारों ने भावी चन्द्र मिशनों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों, मानव अंतरिक्ष उड़ानों और आंकड़ों के आदान-प्रदान में सहयोग करने के तौर तरीकों पर चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों सरकारें वर्ष 2011 के आरंभ में ही असैनिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक बुलाएंगी।

नवाचार

राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान दोनों सरकारों ने सूचना तक सम्पर्क को बढ़ावा देने और नागरिक कार्यकलापों में सक्रियता लाने, वैश्विक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और अन्य देशों के साथ विशेषज्ञता बांटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का उपयोग किए जाने के संबंध में द्विपक्षीय मुक्त सरकार संवाद का शुभारंभ किया। चुनाव प्रबंधन एवं ई-शासन के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता और अनुभवों का उपयोग रुचि रखने वाले अन्य देशों में इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को गहन बनाने के लिए सहकारी पहलकदमियों पर भी भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग की पहली बैठक के दौरान चर्चा की गई। इस बैठक की सहअध्यक्षता राज्य मंत्री पृथ्वी राज चौहान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रपति के सहायक एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक डा. जॉन पी. होल्ड्रेन द्वारा 24-25 जून, 2010 को वाशिंगटन में की गई थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी विज्ञान, जांच विश्लेषण, मॉडलिंग और पूर्वानुमान तथा इनसैट-3डी क्षेत्र में अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्तूबर 2010 में तीन कार्यान्यवन व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

14-16 सितंबर, 2010 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ तथा भारत में अमरीकी दूतावास द्वारा आयोजित एक 'नवाचार गोलमेज बैठक' में ई-शासन, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समावेशी नवाचार की पहचान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में की गई। लोक सूचना अवसंरचना एवं नवाचारों पर प्रधान मंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव डा. टी. रामासामी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (ह्वाइट हाउस) श्री अनीश चोपड़ा और नवाचारों के लिए विदेश मंत्री के सलाहकार श्री एलेक रोस ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया।

लोक सूचना अवंसरचना एवं नवाचारों पर प्रधान मंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा ने 21-22 जनवरी, 2011 तक वाशिंगटन में मुक्त सरकार पहल के संबंध में आयोजित तैयारी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बहुपक्षीय समूह में ऐसे अनेक देश शामिल हैं, जो मुक्त सरकारों के प्रति वचनबद्ध हैं। यह राष्ट्रपति ओबामा की पहल है, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए उनके संबोधन के बाद की गई।

नागर विमानन

नागर विमानन क्षेत्र भारत-अमरीका आर्थिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्र है। विमान तथा एयरोस्पेस उत्पाद अमरीका द्वारा भारत को किए गए जा रहे निर्यातों के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरे हैं। जुलाई 2010 में आयोजित नागर विमानन उपसमिति की दूसरी बैठक और सितंबर 2010 में आयोजित भारत-अमरीका हवाई अड्डा अवसंरचना कार्यदल की पहली बैठक के साथ ही इस संभावनाशील क्षेत्र में बातचीत की प्रक्रिया जारी रही।

कृषि

हरित क्रान्ति के दौरान दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग की ऐतिहासिक विरासत का उपयोग करते हुए दोनों सरकारें नई चिरहरित क्रान्ति के भाग के रूप में खाद्य सुरक्षा का विस्तार करने हेतु परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का विकास, परीक्षण और प्रतिवलन करने में मिलकर कार्य करने पर सहमत हुईं।

दोनों सरकारों ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर जारी सहयोग को और सक्रिय बनाने के लिए मार्च 2010 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आरंभिक 'कृषि संवाद' की शुरुआत सितंबर 2010 में की गई जिसकी सहअध्यक्षता विदेश सचिव तथा ऊर्जा, कृषि एवं आर्थिक मामलों से संबद्ध अमरीकी अंडर सेक्रेटरी द्वारा की गई। इस संवाद से तीन क्षेत्रों में सहयोग के प्रस्तावों पर चर्चा करने का मंच उपलब्ध हुआ। ये क्षेत्र हैं कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में रणनीतिक सहयोग; कृषि विस्तार, खेत से बाजार सम्पर्क;तथा मौसम एवं फसल पूर्वानुमान।

दोनों सरकारों ने नवंबर 2010 में संवर्धित मानसून पूर्वानुमान के लिए एक कार्यान्वयन करार संपन्न किया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2011 की वर्षा ऋतु से किसानों के लिए विस्तृत पूर्वानुमानों का संप्रेषण आरंभ हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत में मानसून के लिए मॉडल सिमुलेशन इत्यादि का समन्वयन करने के लिए एक 'मानसून डेस्क' की स्थापना की जाएगी।

वैश्विक मुद्दे

द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दा मंच से वैश्विक हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किए जाने तथा लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं सतत विकास जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं चलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस मंच की आठवीं बैठक की सहअध्यक्षता विदेश सचिव और लोकतंत्र एवं वैश्विक मामलों के अमरीकी उपमंत्री मैरियो ओटेरो द्वारा 16 सितंबर, 2010 को वाशिंगटन में की गई।

27 मई, 2010 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित दूसरे द्विपक्षीय महिला सशक्तीकरण संवाद में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण, स्वसहायता समूहों के लिए क्षमता निर्माण, सूक्ष्म-वित्त सहायता, महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या का समाधान, बाल शिक्षा एवं महिला-पुरुष बजटिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। दोनों सरकारें आर्थिक प्रयासों में अफगानिस्तान की अग्रणी महिलाओं की सहायता करने के तौर तरीकों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

स्वास्थ्य

भारत-अमरीका स्वास्थ्य पहल की दूसरी बैठक का आयोजन 24 जून, 2010 को वाशिंगटन में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद और अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मानव एवं स्वास्य सेवा सचिव कैथलीन सेबेलियस ने किया। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की और स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत कार्यकारी दलों का निर्माण किए जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की जिसमें सहयोग बढ़ाने और साझा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु दोनों सरकारों के संबंधित अंगों को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारत और रोग नियंत्रण केंद्र अमरीका के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया है जिसके अंतर्गत नई दिल्ली में वैश्विक रोग पहचान क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र का उद्देश्य देशांतरगामी एन्फ्लुंजा और अन्य उभरती बीमारियों के कारण स्वास्थ्य के समक्ष उत्पन्न खतरों के विरुद्ध तैयारी करना है।

शिक्षा सहयोग

शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 में लगभग 1,03,000 भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए अमरीकी विश्वविद्यालयों में नामांकन कराया था। मानव संसाधन विकास मंत्री ने दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जून और सितंबर 2010 में अमरीका का दौरा किया। भारत-अमरीका उच्च शिक्षा शिखर बैठक के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अमरीका के साथ सहयोग को नई गति मिलेगी। 2011 में आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। दोनों सरकारों ने सिंह-ओबामा 21वीं सदी ज्ञान पहल को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय सहित अन्य सभी उपाय किए हैं।

वर्ष, 2010 से प्रत्येक सरकार द्वारा 3.35 मिलियन अमरीकी डालर का संवर्धित अंशदान किए जाने के निर्णय के फलस्वरूप शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 में भारतीय और अमरीकी राष्ट्रिकों को लगभग 260 फुलब्राइट-नेहरू छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए गए।

दोनों सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक भागीदारी करार 'भारत-शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायता (आईएन-एसटीईपी)' पर हस्ताक्षर किए जिसका कार्यान्वयन पांच वर्ष की अवधि में किया जाएगा।

संस्कृति

दोनों देशों के लोगों के बीच जीवन्त सम्पर्कों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वर्ष 2011 में वाशिंगटन डीसी में ''भारत महोत्सव' का आयोजन करेगी जिसमें भारत की विविधतापूर्ण कला, संस्कृतिक, इतिहास, खानपान तथा पर्यटन तथा आर्थिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

कनाडा

वर्ष 2010 में भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नया संवेग मिला। व्यापार और निवेश, कृषि, ऊर्जा, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगकी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रगति और पारस्परिक हित के वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर संवर्धित समझबूझ प्रतिबिंबित हुई।

प्रधान मंत्री ने टोरंटो में आयोजित जी-20 शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में 27 जून, 2010 को कनाडा के प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अप्रैल 2010 में वाशिंगटन में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक तथा 12 नवंबर, 2010 में सियोल में आयोजित जी-20 शिखर बैठक के दौरान भी मुलाकात की थी।

इस वर्ष दोनों सरकारों ने जून 2010 में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए; सितंबर 2010 में व्यापार और निवेश पर पहली द्विपक्षीय वार्ता का शुभारंभ किया; नवंबर 2010 में व्यापक आर्थिक सहभागिता करार पर वार्ता शुरू की। सामाजिक सुरक्षा करार पर वार्ता पूरी की; और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार पर बातचीत को आगे बढ़ाया।

टोरंटो में प्रधान मंत्री जी का द्विपक्षीय कार्यक्रम

टोरंटो में 25-26 जून, 2010 को आयोजित जी-20 शिखर बैठक के उपरान्त प्रधान मंत्री ने 27-28 जून, 2010 तक टोरंटो में विभिन्न द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लिया। कनाडा के प्रधान मंत्री श्री हार्पर के साथ हुई बैठक के अतिरिक्त इस यात्रा के दौरान 27 जून को असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर करार संपन्न किया गया और निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग कोसुविधाजनक बनाने के लिए तीन समझौता ज्ञापन संपन्न किए गएः (1) खान

और भूविज्ञान संसाधन, (2) संस्कृति, और (3) उच्च शिक्षा। 28 जून, 2010 को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने सतत राजनैतिक कार्यकलापों और उच्चस्तरीय यात्राओं तथा नियमित द्विपक्षीय संवाद के प्रति दोनों नेताओं की वचनबद्धता की पुष्टि की। प्रधान मंत्री ने 28 जून, 2010 को वहां की संसद में भारतीय मूल के सदस्यों तथा प्रान्तीय संसदों के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने टोरंटो स्थित स्मारक में एयर इंडिया के विमान कनिष्क दुर्घटना की 25वीं बरसी पर इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

द्विपक्षीय व्यापार

प्रधान मंत्री श्री हार्पर की नवंबर 2009 की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों के भीतर 15 बिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने का निश्चय लिया था। वर्ष 2008 में द्विपक्षीय व्यापार 4.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था। जनवरी-अगस्त 2010 के दौरान 2.5 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जो पिछले वर्ष में इसी अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार व्यापक तौर पर संतुलित रहा और दोनों दिशाओं में सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। कनाडा को भारतीय निर्यात में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कनाडा से आयात में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण	जनवरी-अगस्त 2009	जनवरी-अगस्त 2010	औ बदलाव
भारत का कुल निर्यात	1158	1280	10.6औ
भारत का कुल आयात	1048	1249	19.2औ
कुल व्यापार	**2206**	**2529**	**14.64औ**

(स्रोतः स्टेटिस्टिक्स, कनाडा) आंकड़े वर्तमान दर पर हजार अमरीकी डालर में

व्यापार और निवेश पर संवाद को संस्थागत रूप देने के लिए व्यापार और निवेश में वार्षिक मंत्रिस्तरीय वार्ता का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा तथा कनाडा के व्यापार श्री पीटर वान लोन द्वारा 23 सितंबर, 2010 को ओटावा में किया गया। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, पर्यावरण, खनन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण, पर्यटन वित्तीय एवं अन्य सेवाओं, कृषि तथा अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। वार्षिक मंत्रिस्तरीय संवाद के अंतर्गत दोनों सरकारें सिद्धांत रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर कार्यकारी दलों की स्थापना करने पर सहमत हुईं जिसके अंतर्गत अवसंरचना, उर्जा एवं खनन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। दोनों मंत्रियों ने ओटावा में 24 सितंबर, 2010 को व्यावसायिक परिसंघों द्वारा आयोजित भारत-कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की।

व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) करार की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए नवंबर 2009 में दोनों सरकारों द्वारा गठित संयुक्त कार्यकारी दल ने मई 2009 में दोनों सरकारों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में सीईपीए से दोनों देशों को होने वाले लाभों को देखते हुए भारत-कनाडा सीईपीए के लिए आधिकारिक बातचीत आरंभ करने की अनुशंसा की गई थी। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सियोल में 12 नवंबर, 2010 को दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा की गई औपचारिक घोषणा के उपरान्त 18 नवंबर, 2010 को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कनाडा के व्यापार मंत्री द्वारा नई दिल्ली में सीईपीए पर आधिकारिक बातचीत का शुभारंभ किया गया। आधिकारिक वार्ताओं का पहला दौर मार्च 2011 में आयोजित किए जाने की आशा है।

18 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में भारत के अपर सचिव (वाणिज्य) और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहायक उप मंत्री की अध्यक्षता में वार्षिक व्यापार नीति परामर्शों के सातवें दौर से द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा करने और पारस्परिक लाभ के लिए इसे संवर्धित करने के तौर तरीकों का पता लगाने का उपयोगी अवसर मिला। दोनों देश निवेशों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु एक द्विपक्षीय करार पर भी बातचीत कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा करार को भी अंतिम रूप दिया गया है और इस पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाने की आशा है।

कृषि

कृषि उत्पाद अभी भी द्विपक्षीय व्यापार एक महत्वपूर्ण अंग है। अप्रैल-सितंबर 2010 के दौरान भारत से कनाडा को 69.68 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के कृषि पण्यों का निर्यात किया गया। इसी अवधि के दौरान भारत में कनाडा से 254.80 मिलियन अमरीकी डालर का कृषि आयात किया गया जिसमें मटर और दाल भी शामिल है। भारत सरकार मार्च 2011 तक भारत में आगमन बंदरगाह पर कनाडा से आयातित मटर और दालों के लिए धूम्रीकरण की अंतरिम व्यवस्था की है। भारत कनाडा के लिए मटर और दाल का सबसे बड़ा बाजार है और वर्ष 2009 में इन मदों का लगभग 533 मिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया। दालों से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल, जिसकी बैठक जुलाई 2010 में कनाडा में हुई के जरिए दोनों सरकारें धूम्रीकरण मुद्दे का दीर्घावधिक समाधान प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 1-8 सितंबर, 2010 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय की कनाडा यात्रा और 16-17 सितंबर, 2010 तक कनाडा के कृषि मंत्री श्री जेरी रिट्ज की भारत यात्रा के दौरान कृषि और पशुपालन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई।

ऊर्जा

27 जून, 2010 को टोरंटो में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में कनाडा के साथ एक सहयोग करार संपन्न किया गया। इस करार के अंतर्गत परमाणु रिएक्टरों की डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण, ऑपरेटिंग अनुभवों के बंटवारे तथा इनकी

12 नवंबर, 2010 को दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित जी-20 शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कनाडा के प्रधान मंत्री श्री स्टीफन हार्पर की मुलाकात।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 28 जून, 2010 को कनाडा, टोरंटो में कनाडा के सांसदों/विधान सभा सदस्यों के साथ समूहिक फोटो में।

डीकमीशनिंग, यूरेनियम की आपूर्ति, तीसरे देशों में परियोजनाओं, परमाणु ईंधन चक्र तथा परमाणु कचरा प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण; तथा परमाणु सुरक्षा, विकिरण सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा अनुप्रयोगों का विकास और उपयोग किए जाने में सहयोग को सुविधाजनक भी बनाया गया है। दावानुकूलित गुरुजल रिएक्टरों एवं कांडू (कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम) रिएक्टरों के संबंध में दोनों देशों की क्षमताओं के मद्दे नजर दोनों देशों के रूप में कार्य किए जाने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।

विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने ऊर्जा क्षेत्र में कनाडा के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए 15-21 सितंबर, 2010 तक कनाडा का दौरा किया। नवंबर 2009 में हस्ताक्षरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन के तहत 26-28 मई, 2010 को ओटावा में कनाडा-भारत ऊर्जा मंच की पहली बैठक हुई। इसके उपरान्त क्रमशः स्वच्छ कोयला, तेल और गैस, ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास; तथा विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा प्रभाविता क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के दो कार्यकारी दलों का गठन किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने अल्बर्टा में आयोजित वैश्विक पेट्रोलियम प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 8-10 जून, 2010 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रान्त का दौरा किया।

खनन

भारत और कनाडा में खनन और भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए जून 2010 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के जरिए गवेषण, भूरसायन और भूभौतिकी; भूपरिसंकट; भूविज्ञान सूचना एवं संबद्ध सूचनाओं;पर्यावरणीय भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोग करने; तथा दोनों देशों में खनन क्षेत्र में द्विपक्षीय निवेशों को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा का प्रावधान किया गया है। खान मंत्री श्री बी. के. हांडिक ने कनाडाई खनन उद्योग के संघों एवं अपने कनाडाई समकक्ष के साथ चर्चा करने के लिए 8-13 जुलाई, 2010 तक कनाडा का दौरान किया। खान मंत्रालय ने खनन एवं भूविज्ञान संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए ओंटारियो प्रान्त के साथ एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया। कनाडा-भारत प्रतिष्ठान ने 27-29 सितंबर, 2010 तक टोरंटो में कनाडा-भारत धातु एवं खनन मंच का आयोजन किया जिसमें सचिव (खान) तथा भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शिक्षा

जून 2010 में भारत और कनाडा ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया जिससे पाठ्चर्या विकास, शैक्षणिक विकास, छात्र एवं संकाय आदान-प्रदान तथा संयुक्त अनुसंधान सुविधाजनक बन सकेगा। दोनों सरकारें इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना करेंगी। कनाडा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री गैरी गुडईयर की 6-10 नवंबर, 2010 की भारत यात्रा और 8-13 नवंबर, 2010 तक प्रमुख कनाडाई विश्वविद्यालयों के 20 प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा में द्विपक्षीय उच्च शैक्षिक सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया।

हाल में कनाडा के संस्थानों ने कनाडाई विश्वविद्यालयों में स्नात्कोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के लिए चार मिलियन कनाडाई डालर मूल्य की छात्रवृत्तियों और पुरस्कारों की घोषणा की है। सितंबर 2010 में ओटावा में कार्लटन विश्वविद्यालय में नैनो विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, एयरो इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और नेटवर्क विषयों में अनुसंधान करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और नीति में कनाडा भारत उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इस विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन कार्यक्रम में एक भारत पीठ की स्थापना किए जाने के लिए टोरंटो विश्वविद्यालय के साथ मंशा प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

मानव संसाधन प्रबंधन एवं लोक प्रशासन क्षेत्र में वरिष्ठ लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग हेतु संघ लोक सेवा आयोग और कनाडा लोक सेवा आयोग के बीच शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

जुलाई 2010 में इसरो के व्यावसायिक विंग अंतरिक्ष निगम लिमिटेड ने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन का उपयोग करते हुए भारत से एक कनाडाई उपग्रह एनएलएस-6.1 एआईएसएसएटी-1 छोड़ा गया।

17 कनाडाई कंपनियों और अनुसंधान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जियोमैटिक्स, आपदा प्रबंधन और दूर संवेदन क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु 16-18 जनवरी तक आयोजित जियोस्पैटियल विश्व मंच में भाग लेने के लिए हैदराबाद का दौरा किया।

आतंकवाद

23 जून, 2010 को कनाडा में एयर इंडिया के विमान कनिष्क पर हुई बमबारी की 25वीं बरसी मनाई गई। प्रधान मंत्री श्री हार्पर ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और कनाडाई सुरक्षा एवं पुलिस एजेंसियों की संस्थागत असफलता तथा इसके उपरान्त पीड़ितों के परिवारों के साथ किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगी।

राष्ट्रमंडल खेल

कनाडा ने अक्तूबर 2010 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए 250 एथलीटों का एक दल भेजा था। राष्ट्रमंडल खेलों में कनाडा के खेल मंत्री श्री गैरी लुन ने कनाडा सरकार का प्रतिनिधत्व किया।

संस्कृति

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सितंबर 2010 में कनाडा की इन्विट कला की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

अन्य यात्राएं

इस वर्ष भारत और कनाडा के बीच अनेक मंत्रिस्तरीय दौरे हुए। कनाडा के वित्त मंत्री श्री जिम फ्लाहर्टी ने जारी आर्थिक सहयोग की समीक्षा करने के लिए 17-19 मई, 2010 तक भारत का दौरा किया। उप्रवासन, नागरिकता और बहुसंस्कृतिवाद मंत्री श्री जैसोन कैनी ने वीजा, उप्रवासन तथा संबंधित मसलों पर चर्चा करने के लिए 7-10 सितंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया। अल्बर्टा के प्रधान मंत्री श्री एड स्टेलमैक ने भारत तथा अल्बर्टा प्रान्त के बीच सहयोग को संवर्धित करने के उद्देश्य से 2-8 नवंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया। 17-19 नवंबर, 2010 तक भारत यात्रा पर आए कनाडाई सुरक्षा आसूचना सेवा के निदेशक श्री रिचर्ड फादेन के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में जारी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई।

संसदीय सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने और एक उभरती वैश्विक ताकत के रूप में भारत का अध्ययन करने के लिए पहल के अंतर्गत सिनेटर अनीत रैनल आंद्रेचुक के नेतृत्व में कनाडाई सीनेट की विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबद्ध स्थाई समिति के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 4-10 सितंबर, 2010 तक भारत का दौरा किया। कनाडाई न्यायाधीशों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी 30 अक्तूबर-1 नवंबर 2010 तक भारत का अध्ययन दौरा किया।

5 संसद सदस्यों सहित एक 69 सदस्यीय कनाडाई प्रतिनिधिमंडल ने 10-13 जनवरी, 2011 तक के लिए अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में भाग लिया।

क्यूबेक प्रान्त के आर्थिक विकास, नवाचार एवं गवेषण मंत्री श्री क्लिमेंट जिग्नेक भारत और क्यूबेक प्रान्त के बीच जारी सहयोग पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से 29 जनवरी-4 फरवरी तक मुम्बई और दिल्ली की यात्रा पर आने वाले हैं। आशा है कि वे कुछ केंद्रीय मंत्रियों और महाराष्ट्र के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।

कनाडा के मुख्य न्यायाधीश परम माननीय वेबर्ले मैकलेच्लिन 17वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5-8 फरवरी तक हैदराबाद की यात्रा पर आने वाले हैं।

आतंकवाद का मुकाबला, अवैध उप्रवासन, मानव तस्करी, हवाई अड्डा सुरक्षा तथा सीमा सुरक्षा जैसे सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए कनाडा के लोक सुरक्षा कैबिनेट मंत्री विक टोयव्स के 23-26 फरवरी तक नई दिल्ली की यात्रा पर आने की आशा है।

लैटिन अमरीका एवं कैरेबिया

अर्जेन्टीना

पिछले वर्ष अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति की यात्रा से सृजित गतिशीलता के आधार पर इस वर्ष हुई नियमित यात्राओं के कारण अर्जेन्टीना के साथ हमारे संबंध सक्रिय बने रहे। सितंबर 2010 में वियेना में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित करार पर हस्ताक्षर करके भारत और अर्जेन्टीना सामरिक भागीदारी का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अर्जेन्टीना की मई क्रान्ति के 200 वर्ष पूरा होने पर आयोजित समारोहों में भाग लेने के लिए 23-27 मई, 2010 तक विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर की अर्जेन्टीना यात्रा के दौरान उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री श्री तायना, उद्योग और पर्यटन मंत्री सुश्री देबोरा जिओरजी तथा ब्यूनस आयर्स के सीएम से मुलाकात की थी। अर्जेन्टीना के कृषि, मवेशी एवं मात्स्यिकी मंत्री श्री जुलियान एंद्रेज डोमिंगेज ने 2-3 अगस्त, 2010 तक भारत का सरकारी दौरा किया और उन्होंने कृषि मंत्री श्री शरद पवार तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुबोधकांत सहाय से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वर्तमान द्विपक्षीय सहयोग को और गहन बनाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। भारत के कृषि मंत्री ने 10-12 सितंबर तक अर्जेन्टीना का दौरा किया तदुपरांत पंजाब के उप प्रधान मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्रियों तथा अन्य व्यवसाइयों वाले एक विशाल प्रतिनिधि मंडल ने भी अर्जेन्टीना का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान अर्जेन्टीना के समकक्ष के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए 4 अक्तूबर, 2010 को ब्यूनस आयर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने समकक्ष उप विदेश मंत्री श्री अल्बर्टो डालोटो के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार-विनिमय किया। यात्रा के दौरान राजनयिक मिशन एवं कोंसली टेंडरों के पारिवारिक सदस्यों के लिए लाभकारी रोजगार पर एक करार संपन्न किया गया।

ब्यूनस आयर्स के गवर्नर श्री मारिसियो मारिसी 29 अप्रैल को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित चौथे भारत-एलएसी व्यावसायिक कांक्लेव में मुख्य अतिथि थे। द्विपक्षीय व्यापार में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली और भारत इस अवधि के दौरान अर्जेन्टेनियाई सोया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया। एस्सार ने अर्जेन्टीना की एक बीपीओ फर्म एक्शनलाइन का अधिग्रहण किया है जिसका अनुमानित राजस्व 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है और कर्मचारियों की संख्या 5,000 है। इस अधिग्रहण के साथ ही एस्सार लैटिन अमरीका में सबसे बड़ा भारतीय बीपीओ बन गया है।

अर्जेन्टीना के कोस्टगार्ड की स्थापना के 200 वर्षीय समारोह के अवसर पर भारतीय तटरक्षक से एडमिरल अनिल चोपड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 जून-2 जुलाई 2010 तक ब्यूनसआयर्स का दौरा किया।

तीसरे भारत महोत्सव का आयोजन अर्जेन्टीना मे 4-16 नवंबर, 2010 तक आयोजन किया गया। इस महोत्सव में नृत्य, फिल्म, कला प्रदर्शन, फोटो प्रदर्शनी, सेमिनार, खाद्य महोत्सव, साहित्यिक कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन किया गया।

बोलीविया

बोलीविया के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे। हालांकि इस अवधि के दौरान कोई बड़ी यात्रा नहीं हुई परन्तु हमारे आर्थिक कार्यकलाप सक्रिय हैं। जिंदल स्टील तथा बोलीविया सरकार की एक इकाई इंप्रेसा सिदेरुर्जिका डेल मुटुन (ईएसएम) ने अगस्त 2010 में राष्ट्रपति द्वारा जारी डिक्री द्वारा अल मुटुन लौह अयस्क भंडार और बोलीविया में इस्पात संयंत्र परियोजना का विकास कार्य दोबारा आरंभ कर दिया है। एक अनुमान के अनुसार जिंदल स्टील ने अल मुटुन में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया और जमीन उपलब्ध कराए जाने पर कम्पनी इसी इस्पात संयंत्र के नजदीक विद्युत उत्पादन इकाई की भी स्थापना करना चाह रही है। भारत ने 19-22 अप्रैल, 2010 तक बोलीविया में जलवायु परितर्वन और धरती माता के अधिकारों पर आयोजित वर्ल्ड पीपुल्स कांफ्रेंस में भाग लिया।

ब्राजील

आईबीएसए और ब्रिक शिखर सम्मेलनों के लिए 14-15 अप्रैल, 2010 तक हमारे प्रधान मंत्री की ब्रासीलिया यात्रा ब्राजील के साथ हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति लूला के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई जिसमें हमारे संबंधों के सभी पहलुओं और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय घटनाक्रमों पर बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने भारत-ब्राजील सामरिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाने की अपनी वचनबद्धता को नवीकृत किया जिसकी झलक इस यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में मिली। प्रधान मंत्री ने इब्सा और ब्रिक सदस्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। शिखर बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत-ब्राजील सामरिक संवाद और ब्रिक सदस्य देशों के साथ सामरिक वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत-ब्राजील सामरिक वार्ता और ब्रिक सदस्य देशों के साथ सामरिक वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 27-29 मई, 2010 तक रियो दि जनारियो, ब्राजील में आयोजित सभ्यताओं के संघ के तीसरे वैश्विक मंच ने ब्राजील का दौरा किया। अपने संबोधन में श्रीमती प्रनीत कौर ने भारत की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण सभ्यतामूलक एवं सांस्कृतिक विरासत की बात कही और मतभेद पैदा करने वाले मुद्दों की जगह विभिन्न सभ्यताओं के बीच विद्यमान समानता पर बल देने की आवश्यकता जताई। सचिव (पश्चिम) ने 1 सितंबर, 2010 को यात्रा पर आए ब्राजील के विदेश मंत्रालय के महासचिव (उप मंत्री) श्री एंटोनियो दि अगुआर के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने ब्राजील और भारत में वित्त सचिवों के स्तर पर द्विपक्षीय आर्थिक एवं वित्तीय संवाद तंत्र की स्थापना की है।

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने बेसिक देशों-ब्राजील दक्षिण अमरीका भारत और चीन की चौथी मंत्रिस्तरीय समन्वयन बैठक में भाग लिया। जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत इस बैठक का आयोजन 25-26 जुलाई, 2010 को रियो दि जनारियो में किया गया। सूचना एवं संचार राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीआईआई-लैटिन अमरीका कंक्लेव में भाग लेने 1-5 सितंबर, 2010 तक साओपालो और रियो दि जनारियो का दौरा किया जहां उन्होंने प्रमुख व्यवसाइयों से बातचीत की। ब्राजील के विकास, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उप मंत्री श्री इवान रामल्हो ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्री शरद पवार ने एक विशाल व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 8-10 सितंबर, 2010 तक ब्राजील का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के उपमुख्य मंत्री और कुछ राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल थे। उन्होंने ब्राजील के कृषि मंत्री श्री बैगनर रोसी के साथ मुलाकात की और कृषि उद्योग तथा कृषि अनुसंधान में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों से बातचीत की।

वायुसेना प्रमुख प्रदीप बसंत नायक ने 29 जून-2 जुलाई 2010 तक ब्राजील का दौरान किया और अपने समकक्ष तथा ब्राजील की अन्य रक्षा संस्थापनाओं के साथ बातचीत की। ब्राजील की नौसेना के चीफ एडमिरल जूलियो सोरेस डि मोउरा नेटो ने 9-11 अगस्त तक भारत का दौरा किया। संयुक्त रक्षा समिति की पहली बैठक 2010 25 अगस्त, 2010 तक नई दिल्ली में हुई।

चिली

चिली के नए राष्ट्रपति श्री सेबास्तियन पिनेरा ने मार्च 2010 में अपना कार्यभारत ग्रहण करने के तत्काल बाद भारत के साथ संबंधों को संवर्धित करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशों के बीच पारम्परिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। सूचना एवं संचार राज्य मंत्री ने एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ सितंबर 2010 में चिली का दौरा किया जहां उन्होंने अपने समकक्ष और चिली के व्यवसाइयों के साथ मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान कृषि क्षेत्र में सहयोग पर तीन प्रोतोकोल संपन्न किए गए। सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश कार्यालय परामर्शों के पांचवे दौर में भाग लेने के लिए 8 अक्तूबर, 2010 को चिली का दौरा किया। दोनों पक्षों ने राजनैतिक एवं आधिकारिक दौरों का आदान-प्रदान किए जाने के जरिए संबंधों को सुदृढ़ बनाने एवं वर्तमान करारों को कार्यान्वित करने पर अपनी सहमति जताई। चिली पक्ष ने भूकम्प राहत के लिए पांच मिलियन अमरीकी डालर की उदार सहायता दिए जाने पर भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। वहां की सीनेट के अध्यक्ष श्री जॉर्ज पिजारो सोतो के नेतृत्व में चिली के एक तीन सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 23-28 जनवरी, 2011 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात की और विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, संचार एवं सूचना राज्य मंत्री तथा विदेश मंत्रालय की स्थाई समिति से मुलाकात की।

उक्त अवधि के दौरान अनेक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों ने चिली का दौरा किया। नेस्कॉम के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने

अक्तूबर 2010 में, 24 सदस्यीय शिष्टमंडल ने अप्रैल 2010 में सेंटियागो में आयोजित खनन प्रदर्शनी (एक्स्पो मिन) 2010 में भाग लेने के लिए और राइट्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2010 में चिली का दौरा किया।

कोलम्बिया

कोलम्बिया के राष्ट्रपति श्री जुआन मैनुअल सैंटोस ने अगस्त 2010 में अपना कार्यभार संभाला और भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त की। इस अवधि के दौरान कुछ उच्चस्तरीय यात्राएं भी हुईं। कोलम्बिया के उपराष्ट्रपति फ्रांसिस्को सैंटोस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 23-28 अप्रैल, 2010 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा दिल्ली, मुम्बई और बंगलोर में विभिन्न भारतीय उद्यमियों से बातचीत की। शहरी विकास राज्य मंत्री प्रोफेसर सौगतरॉय के नेतृत्व में 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सतत शहरी परिवहन प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए 28 सितंबर-3 अक्तूबर 2010 तक बगोटा का अध्ययन दौरा किया। भारत ने मार्च 2010 में ओईसीडी द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग और क्षमता विकास पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रम से संबद्ध कार्यबल की बैठक में भी भाग लिया। कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों ने कार्टाजेना में 7-8 अप्रैल, 2010 तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच के लैटिन अमरीकी सम्मेलन में भाग लिया। ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद) के नेतृत्व 151 भारतीय कंपनियों के व्यावसायिक प्रतिनिधमंडल ने कोलम्बिया का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने कोलम्बियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की जिन्होंने भारतीय उद्यमियों से कोलम्बिया में निवेश करने का अनुरोध किया। जुलाई 2010 में भारत ने दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार (डीटीएए) पर बातीचीत समाप्त की। भारत ने कोलम्बिया के लिए आईटेक प्रशिक्षण स्लाट्स की संख्या को 35 से बढ़ाकर 45 करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

इक्वाडोर

हमारी चिरकालिक वचनबद्धता के रूप में इक्वाडोर को 8 लाख अमरीकी डालर मूल्य की दवाएं सौंपे जाने के साथ ही इक्वाडोर के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंधों को और बढ़ावा मिला। 28 भारतीय भेषज कम्पनियों के एक फार्मेक्सिल प्रतिनिधि मंडल ने व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए 23 अगस्त, 2010 को इक्वाडोर का दौरा किया। भारत द्वारा प्रदान किए गए पांच ध्रुव मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों ने 13 माह के दौरान इक्वाडोर में अपनी सेवा के 1,500 घंटे पूरे कर लिए, जिनके जरिए विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया गया और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवाजाही सुविधाजनक हुई।

मैक्सिको

सभी स्तरों पर यात्राओं का आदान-प्रदान किए जाने से मैक्सिको के साथ हमारी विशेष भागीदारी और संवर्धित हुई। 11 नवंबर, 2010 को प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति फिलिप काल्डेरोन ने जी-20 शिखर बैठक के दौरान मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। मैक्सिको की विदेश मंत्री सुश्री पैट्रीशिया स्पीनोसा कैंटिलियानो ने मैक्सिको के उपमंत्री के साथ 16-17 अगस्त, 2010 तक भारत का दौरा किया। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत यात्रा पर आए गणमान्य अतिथि के साथ बातचीत की जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय घटनाक्रमों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। उन्होंने प्रधान मंत्री और पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश से मुलाकात की। श्री रमेश के साथ उन्होंने नवंबर 2010 में कानकुन में आयोजित होने वाले कोप-16 शिखर सम्मेलन से पूर्व जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मैक्सिको की पर्यटन मंत्री श्री ग्लोरिया गुबेरा ने भारत का दौरा किया और पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा से मुलाकात की। 16 अगस्त, 2010 को हुई इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने भारत तथा मैक्सिको के बीच बेहतर हवाई सम्पर्क सुविधा और दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर बातचीत की। इससे पूर्व सीनेटर कार्लोस जिमिनेज मैकियास के नेतृत्व में मैक्सिको के 8 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 8-14 अगस्त, 2010 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने राज्य सभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष तथा विदेश और गृह मंत्रालय से संबद्ध स्थाई समितियों के सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर भारत और मैक्सिको के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली और मैक्सिको दोनों स्थानों में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।

वाणिज्य सचिव श्री राहुल खुल्लर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 21-24 अप्रैल, 2010 तक मैक्सिको सिटी में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से संबद्ध द्विपक्षीय उच्चस्तरीय समूह की दूसरी बैठक में भाग लिया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मैक्सिको सिटी में 11-14 जुलाई, 2010 तक आयोजित विदेश कार्यालय परामर्शों में भाग लिया और अपने समकक्ष उपमंत्री सुश्री मारिया डि लोर्डेस अरांडा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने राजनैतिक, आधिकारिक एवं आर्थिक संवाद एवं सहयोग को गहन बनाकर अपनी विशेषीकृत भागीदारी को और संवर्धित करने पर सहमति व्यक्त की। शहरी विकास राज्य मंत्री प्रोफेसर सौगत रे के नेतृत्व में एक बड़े भारतीय प्रतिनिधमंडल ने शहरी परिवहन प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए 4-6 अक्तूबर, 2010 तक मैक्सिको सिटी का दौरा किया।

कृषि मंत्री शरद पवार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 5-7 सितंबर, 2010 तक मैक्सिको का दौरा किया और कृषि अनुसंधान में सहयोग किए जाने के संदर्भ में मैक्सिको के कृषि मंत्री के साथ चर्चा की। इस यात्रा के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और मैक्सिको के राष्ट्रीय वानिकी, कृषि, खाद्य एवं मात्स्यिकी राष्ट्रीय संस्थान (आईएनआईएफएपी) के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया।

श्री पवार ने सीआईएमएमवाईटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं उन्नयन केंद्र का भी दौरा किया और भारत में सीआईएमएमवाईटी के प्रमुख क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना किए जाने के बारे में चर्चा की। इसे दक्षिण एशिया में बोरलॉग संस्थान कहा जाएगा। इस संदर्भ में भारत के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा सीआईएमएमवाईटी के बीच एक मंशा ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयराम रमेश ने 3-5 नवंबर, 2010 तक मैक्सिको में कोप-16 से पहले होने वाली बैठकों में भाग लिया और बाद में 29 नवंबर-11 दिसंबर 2010 तक कानकुन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधमंडल ने 4-22 अक्तूबर, 2010 तक मैक्सिको के गुवादालजारा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में आयोजित आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूर-संचार यूनियन) पूर्णाधिकारी सम्मेलन में भारतीय प्रतनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने 23-26 सितंबर, 2010 तक मैक्सिको सिटी में आयोजित अमेरिका के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले (एफआईटीए) में भी भाग लिया।

मैक्सिको सिटी में आईसीसीआर के गुरुदेव टैगोर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ हो जाने के साथ ही भारत-मैक्सिको सांस्कृतिक सम्पर्कों में एक नए अध्याय की शरुआत हुई। आईसीसीआर ने सर्वेंटीनो नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए 22 अक्तूबर-2 नवंबर 2010 तक सुश्री मंगला भट्टा के नेतृत्व में छः सदस्यीय कत्थक नृत्य मंडली को प्रायोजित किया। हिडाल्गो प्रान्त के तुला नगर पालिका में भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया। कोलोजियो डि मैक्सिको के एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन केंद्र में ओक्टावियो पाज भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना करने के लिए 21 जुलाई, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पराग्वे

राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के संयुक्त निमंत्रण पर 10-14 अप्रैल, 2010 तक पराग्वे की सीनेट के अध्यक्ष मिग्वेल कैरी जोसा के नेतृत्व में पहले संसदीय प्रतनिधिमंडल की भारत यात्रा से पराग्वे के साथ हमारे संबंधों को और बढ़ावा मिला। यात्रा पर आए 5 सदस्यीय बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सभा के सभापति और लोक सभा अध्यक्ष स्थाई समिति के सदस्यों से मुलाकात की। सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 7 अक्तूबर, 2010 को अशन्शियन में पहले द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्शों में भाग लिया। दोनों पक्षों ने राजनैतिक एवं सरकार स्तरीय सम्पर्कों को प्रोत्साहित करने सहित समग्र द्विपक्षीय सहयोग को ठोस बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। अशन्शियन में 11-19 नवंबर, 2010 तक आयोजित भारत महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय खान-पान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पेरू

नियमित द्विपक्षीय यात्राएं पेरू के साथ हमारे संबंधों की विशेषता हैं। सूचना एवं संचार राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2-6 सितंबर, 2010 तक पेरू का दौरा किया और द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के संबंध में पेरू के वाणिज्य और पर्यटन मंत्री से चर्चा की। उन्होंने लीमा में सीआईआई द्वारा आयोजित भारत लैटिन अमरीका व्यावसायिक कांक्लेव को संबोधित किया। भारत-पेरू व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीआईआई तथा लीमा वाणिज्य परिसंघ के बीच एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया गया।

पेरू के व्यापार और पर्यटन मंत्री श्री एडवर्डो फेरेओर्स ने 17 जनवरी, 2011 को भारत का दौरा किया और वाणिज्य मंत्री तथा पर्यटन राज्य मंत्री से मुलाकात की और सीआईआई उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने उत्तरोत्तर बढ़ते व्यापार और निवेश को देखते हुए बीआईपीपीए और डीटीएए संपन्न् किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

ऊरुग्वे

5 अक्तूबर, 2010 में मोंटवीडियो (स्पेनी उच्चारणः मोंटीवीडियो) में आयोजित प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श परामर्शों के साथ ही उरुग्वे के साथ पारम्परिक रूप से हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध और संवर्धित हुए। सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं खासकर व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा की।

वेनेजुएला

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम को राष्ट्रपति शावेज द्वारा कारबोबो तेल (वेनेजुएला की ओरीनोको पट्टी) का ठेका दिया जाना वेनेजुएला के साथ हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। इस कंसोर्टियम में भारतीय तेल निगम लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड, स्पेन की रेस्पोल तथा मलेशिया की पेट्रोनास शामिल है। 12 मई, 2010 को संयुक्त उपक्रम, पेट्रो कारबोबो एसए का सृजन किए जाने के लिए कराकास में हस्ताक्षर समारोह हुआ जिसमें राष्ट्रपति शावेज ने यह ठेका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा को दिया। सचिव (पश्चिम) ने भारत यात्रा पर आए एशिया-मध्य पूर्व तथा ओसीनिया के लिए विदेश मामलों के उपमंत्री श्री तेमिर पोरास पोंसेलियाल के साथ चर्चा की। श्री पोरस ने 11 सितंबर, 2010 को पुनः भारत का दौरा 5 मई, 2010 को किया।

मध्य अमेरिका

अल-सल्वाडोर, होंडुरास और निकारागुआ जैसे सभी मध्य अमरीकी देशों के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण हैं। हमारे संबंध न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि सीका (मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली) के जरिए भी सुदृढ़ हुए। अल सल्वाडोर और निकारागुआ की सरकारों के अनुरोध पर अल सल्वाडोर में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईटीआई) को 2011 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

बेलिज

बेलिज के खेल एवं शासन मंत्री श्री जॉन बिर्चमैन साल्दिवार ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान अक्तूबर 2010 में भारत का दौरा किया।

कोस्टारिका

कोस्टारिका के विदेश मंत्री श्री रेने कास्ट्रो सलाजर की 19-20 अक्तूबर, 2010 तक की भारत यात्रा से भारत-कोस्टारिका संबंधों को नई गति मिली। विदेश मंत्री ने यात्रा पर आए गणमान्य अतिथि के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की और कोस्टारिका की विकास गतिविधियों के लिए समर्थन और सहयोग का प्रस्ताव किया। यात्रा पर आए गणमान्य अतिथि ने भारत में कोस्टारिका के दूतावास का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश से मुलाकात की और सीआईआई में भारतीय व्यवसाइयों के साथ चर्चा की। सितंबर 2010 में पंजाब के उप मुख्य मंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल ने एक कृषि प्रतिनिधिमंडल के साथ संरक्षित कृषि फार्मों का अध्ययन करने के लिए कोस्टारिका का दौरा किया। भारत ने टोमस चक्रवात के पश्चात आपदा राहत के लिए कोस्टारिका सरकार को एक लाख अमरीकी डालर का नकद अंशदान दिया गया।

ग्वाटेमाला

ग्वाटेमाला में दिसम्बर 2009 में खोले गए मिशन में प्रथम भारतीय राजदूत श्री प्रवीन वर्मा ने सितम्बर 2010 में अपना कार्यभार सृहज किया।

पनामा

पनामा के आर्थिक और वित्त मंत्री श्री अल्बर्टो वलारीनो की 12 नवंबर, 2010 की यात्रा के साथ ही भारत और पनामा के मैत्रीपूर्ण संबंध और संवर्धित हुए। उन्होंने वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ मुलाकात की तथा नई दिल्ली में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक के दौरान अनेक व्यावसायिक प्रतिनिधियों और विचारकों के साथ चर्चा की। वित्त मंत्री के साथ हुई अपनी बैठक में श्री बलारीनो ने पनामा नहर का विस्तार किए जाने संबंधी पनामा सरकार की परियोजना से लाभ लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया। यह कार्य अगस्त 2014 तक पूर्ण होने की आशा है। वित्त मंत्री ने भारत-सीका संवाद के महत्व को रेखांकित किया जिसका पनामा भी सदस्य है।

मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली (स्पेनिशः सिस्टेमा डि ला इंटीग्रेश्योन सेंट्रो अमेरिकाना; सीका)

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 27 सितंबर, 2010 को न्यूयार्क में 65वें संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान भारत-सीका वार्ता की। उन्होंने सीका के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बेलिज के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 2010-2011 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने पर सीका सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री ने सीका देशों के लिए आईटेक स्लाट्स की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत-सीका व्यावसायिक मंच का गठन किए जाने का भी आह्वान किया।

कैरेबिया

कैरेबिया क्षेत्र के साथ भारत के घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। इस क्षेत्र में भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं जिनके साथ अपने संबंधों को हम पोषित करना चाहते हैं। कैरेबिया क्षेत्र के साथ हमारे संबंध यात्राओं के आदान-प्रदान तथा सभी स्तरों पर होने वाले कार्यकलापों के द्वारा संवर्धित हुए। इस अवधि के दौरान केरल की आठ सदस्यीय हिन्दुस्तानी कलारी संगम मंडली ने क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य का दौरा किया। भारत ने टोमस चक्रवात के कारण हुई तबाही के पश्चात आपदा राहत के लिए सेंट लूसिया को 5 लाख अमरीकी डालर का नकद अंशदान दिया। भारत ने भारतीय सहायता से सेंटविशेंट और ग्रेनेडाइंस में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने का अनुमोदन कर दिया। भारत के दो सदस्यीय सौर विशेषज्ञ दल ने बहामा में सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 18-25 जुलाई, 2010 तक बहामा का दौरा किया।

क्यूबा

भारत और क्यूबा ने राजनयिक संबंधों की स्थापना किए जाने की 50वीं (1960-2010) वर्षगांठ मनाई। वर्ष भर चलने वाले समारोहों में कार्यशालाओं, क्रिकेट टूर्नामेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चित्रकला प्रदर्शनियों सिम्फनी आर्केस्ट्रा तथा शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हवाना में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। क्यूबा के लघु उद्योग उप मंत्री महामहिम श्री एलोय डी ला कैरीडेड अल्वारेज मार्टीनेज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सितंबर 2010 में भारत का दौरा किया। भारत में विशेषकर बॉक्सिंग में क्यूबाई प्रशिक्षकों को नियुक्त करने से भारत-क्यूबा खेल संबंधों को भी बढ़ावा मिला।

मार्च 2010 में बायोकान लिमिटेड ने अपनी सहायक कम्पनी बायोकान एसए के जरिए क्यूबा के सीआईएमएबी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। भारत की एक अन्य प्रौद्योगिकी कम्पनी बीसीएमसी पावर सिस्टम्स को क्यूबा और वेनेजुएला के बीच सबमैरिन तार डालने के कार्य में अल्काटेल लुशेंट द्वारा बैकअप बिजली प्रदान करने के लिए छः करोड़ की संविदा दी गई जो कि 2011 के मध्य तक कार्यान्वित की जानी है।

गयाना

इस अवधि के दौरान गयाना के साथ हमारे पारम्परिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान सितंबर 2010 में न्यूयार्क में गयाना के राष्ट्रपति श्री भरत जगदेव से मुलाकात की। अपवहन

और सिंचाई के हैवी ड्यूटी कृषि पम्पों की खरीद हेतु गयाना को दी गई 4 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखलाओं का उपयोग करने के लिए एक करार संपन्न किया गया। पोत परिवहन मंत्रालय के एक उच्चस्तरीय तकनीकी प्रतिनिधिमंडल ने आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत गयाना में गहरे जल पत्तन के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन किया।

हैती

भारत ने हैती के पुनर्निर्माण के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन किया। जुलाई 2010 में पुंटाकाना में आयोजित हैती के भविष्य पर विश्व शिखर बैठक में भारत ने हैती सरकार की इच्छा के अनुसार राजधानी पोर्ट-आफ प्रिंस के मुख्य सरकारी भवनों में से एक का पुनर्निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत ने न्यूयार्क में आयोजित हैती के लिए अंतर्राष्ट्रीय दाता सम्मेल में तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष 5,00,000 अमरीकी डालर का अंशदान करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने कृषि विकास से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) द्वारा हैती को दिए गए ऋण को माफ करने के लिए एक मिलियन अमरीकी डालर का नगद अंशदान किया है।

हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन (मिनुस्ताह) के साथ संबद्ध दो भारतीय पुलिस इकाइयों (एफपीयू) के अतिरिक्त अक्तूबर 2010 में एक तीसरी टुकड़ी भी वहां पहुंच गई। इसके साथ ही हैती में भारतीय एफपीयू की कुल संख्या अब 460 हो गई है। एफपीयू ने अच्छा कार्य किया है जिसकी संयुक्त राष्ट्र और हैती सरकार द्वारा काफी सराहना हुई है।

जमैका

11 अगस्त, 2010 को भारत ने किंग्स्टन, जमैका में बुस्टामेंट बाल अस्पताल हेतु दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद किए जाने के लिए जमैका सरकार को 3,00,000 अमरीकी डालर की मानवीय सहायता दी। नवंबर, 2010 में भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण हुई तबाही के पश्चात आपदा राहत के लिए जमैका को 50,000 अमरीकी डालर का नकद अंशदान दिया।

सूरीनाम

नए राष्ट्रपति श्री देसी बोतेरेस, जिन्होंने मई 2010 में अपना कार्यभार संभाला, के शासन काल में द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। वे मेगा काम्बीनेशन पार्टी के हैं। सूरीनाम के सांसद श्री राशिद दोखी ने राष्ट्रपति बोतेरेस के विशेष दूत के रूप में अक्तूबर 2010 में भारत का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ एवं गहन बनाने के लिए भारतीय प्राधिकारियों के साथ अनेक उच्चस्तरीय बैठकें कीं।

ट्रिनिडाड एंड टोबैगो

ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्रथम महिला प्रधान मंत्री के रूप में श्रीमती कमला प्रसाद विशेसर द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नया संवेग मिला। ट्रिनिडाड एवं टोबैगो के पर्यटन मंत्री डा. रूपर्ट ग्रफिथ ने 11-12 जनवरी, 2011 तक भारत का दौरा किया। उनके साथ एक बीस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी आया जिसमें विभिन्न अधिकारी एवं निजी टूर ऑपरेटर शामिल थे। क्रिकेटर श्री ब्रायन लारा, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो पर्यटन के ब्रांड अम्बेसडर, भी इस शिष्टमंडल के भाग थे।

भारत-ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की भागीदारी से भारतीय निर्यात संघों के परिसंघ (एफआईईओ) के 35 सदस्यीय शिष्ट मंडल ने भारतीयों के आगमन दिवस के अवसर पर मकोया के उत्कृष्टता केंद्र में 21-31 मई, 2010 तक भारत-व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया। न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी (ट्रिनिडाड एंड टोबैगो) ने पोर्ट ऑफ स्पेन में अपने मुख्यालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है। 35 मिलियन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डालर की लागत से बनने वाला यह भवन दो वर्ष में पूरा हो जाएगा, जो कम्पनी के क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में भी कार्य करेगा।

बहुपक्षीय

अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (आईएडीबी)

अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (आईएडीबी) के अध्यक्ष श्री लुई अल्बर्टो मुरेनो ने मुख्य तौर पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में भाग लेने के लिए 15-16 नवंबर, 2010 तक नई दिल्ली का दौरा किया। श्री मोरेनो ने वित्त मंत्री, विदेश राज्य मंत्री प्रनीत कौर तथा वाणिज्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने अनुरोध किया कि भारत ऋण नहीं लेने वाले देश के रूप में आईएडीबी का सदस्य बनकर इस क्षेत्र की उत्तरोत्तर बढ़ती संभावनाओं का लाभ उठाए क्योंकि यहां भारत के हितों में भी वृद्धि हो रही है। यात्रा के दौरान एक विशेष रिपोर्ट 'इंडियाः लैटिन अमरीकाज नेक्स्ट विग थिंग' का लोकार्पण किया गया।

■■

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 9

संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 65वां सत्र

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड में सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में 21-30 सितम्बर, 2010 तक न्यूयॉर्क की यात्रा की। महासभा में 29 सितम्बर, 2010 को दिए अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने वैश्विक अधिशासन में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका की पुनः पुष्टि की और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि समसामयिक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से इसे और भी मुखर तथा संबलित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की आवाज मजबूत करना एक तात्कालिक जरूरत है ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक एवं प्रातिनिधिकारी संस्था बनाया जा सके। विदेश मंत्री ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रति भारत सरकार की बचनबद्धता को दोहराते हुए यह भी संकेत दिया कि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में प्रगति हासिल करने में भारत सरकार की ओर से क्या-क्या प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्त्री-पुरुष समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की नवनिर्मित संस्था 'यूएन वूमन' के लिए भारत की मजबूत बचनबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किए गए विशिष्ट समय-सीमा के भीतर सार्वभौमिक, भेदभाव रहित और सत्यापन करने योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने हेतु भारत की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकने वाली एक बहुपक्षीय, निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापन किए जाने योग्य विखंड्य सामग्री कटौती संधि (एफ.एम.सी.टी.) के लिए निरस्त्रीकरण सम्मेलन में वार्ता किए जाने के प्रति भारत की सतत् वचनबद्धता का भरोसा दिलाते हुए परमाणु विस्फोट परीक्षण पर स्वैच्छिक, एक-पक्षीय स्थगन कायम रखने की भारत की वचनबद्धता को दोहराया।

65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में आयोजित अनेक उच्च स्तरीय बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया जिनमें शामिल हैं - 22 सितंबर, 2010 को न्यूयॉर्क में आयोजित एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) की मंत्रिस्तरीय बैठक; 20-22 सितंबर, 2010 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक; निरस्त्रीकरण पर उच्च स्तरीय बैठक; जी-15 विदेश मंत्रियों की बैठक; सूडान पर उच्च स्तरीय बैठक; जी-4 मंत्रिस्तरीय बैठक; लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों के दीर्घकालिक विकास के लिए मॉरीशस रणनीति हेतु समीक्षा बैठक; फिलिस्तीन पर गुट निरपेक्ष आंदोलन (नैम) मंत्रिस्तरीय बैठक; एसआईसीए (मध्य अफ्रीकी एकीकरण व्यवस्था) के साथ बैठक; नैम समन्वयन ब्यूरो (नैम सीओबी) विदेश मंत्रियों की बैठक; राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक और सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक। वार्षिक जी-77 मंत्रिस्तरीय बैठक सहित अन्य उच्च स्तरीय बैठकों में अधिकारियों के स्तर पर हिस्सा लिया गया।

विदेश मंत्री ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया। इनमें गुयाना के राष्ट्रपति के साथ रात्रिभोज बैठक और बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री, अमरीका की विदेश मंत्री, यूके के विदेश सचिव और बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, सुडान तथा सियरा लेओना के विदेश मंत्रियों के साथ हुई बैठकें शामिल थीं।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रणीत कौर ने 18-22 अक्तूबर, 2010 तक न्यूयॉर्क की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती प्रणीत कौर ने 20 अक्तूबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण बैठक को आर्थिक, सामाजिक तथा उनसे जुड़े क्षेत्रों में प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों तथा शिखर बैठकों के निष्कर्षों के कार्यान्वयन के संबंध में संबोधित किया।

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने 25 सितम्बर, 2010 को मेक्सिको की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित जलवायु परिवर्तन पर मंत्रिस्तरीय परामर्श में हिस्सा लिया। उन्होंने 22 सितम्बर, 2010 को जैव-विविधता पर उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया और भाषण दिया।

18 संसद सदस्यों और एक पूर्व संसद सदस्य से मिलकर बने एक गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर-नवम्बर 2010 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए तीन बैचों में न्यूयॉर्क की यात्रा की। भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर संबंधी विशेष समिति की रिपोर्ट, संगठन की भूमिका को सुदृढ़ बनाए जाने, सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व और उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने, संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति को सुधारे जाने, संयुक्त राष्ट्र में न्याय के प्रशासन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त, महिलाओं के विकास, बाल अधिकारों को प्रोन्नत और संरक्षित किए जाने, निर्धनता उन्मूलन और अन्य विकास संबंधी मुद्दों; दीर्घकालिक विकास, मानवाधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण, शांतिरक्षा, शांति-निर्माण, निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय

आतंकवाद के उन्मूलन के उपायों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण बैठक और उसकी समितियों में अपना वक्तव्य दिया।

वर्ष 2011-2012 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का चयन

भारत को 1 जनवरी, 2011 से दो वर्षों की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। 12 अक्तूबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए चुनाव में भारत को 190 वैध मतों में से 187 मत मिले जो अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने गए पांच देशों के मिले मतों में सर्वाधिक थे। भारत लगभग दो दशक के अंतराल के बाद सुरक्षा परिषद में पुनः प्रवेश करेगा। भारत ने अभी तक सुरक्षा परिषद में छह कार्यकाल पूरे किए हैं; 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 और 1991-92।

सुरक्षा परिषद में अपने आगामी कार्यकाल के दौरान भारत की तत्कालीन प्राथमिकता अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और अफ्रीका सहित अपने निकट और विस्तारित पड़ोस में शांति और स्थिरता, अराजक तत्वों तक अभिकर्त्ताओं को सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोके जाने सहित आतंकवाद निरोध, और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा और शांति निर्माण प्रयास को सुदृढ़ किया जाना होगी। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अति आवश्यक ढ़ांचागत सुधार किए जाने के लिए काम करते रहने के प्रति भी वचनबद्ध हैं।

चौथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित करके 2 अक्तूबर, 2010 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष द्वारा की गई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने वक्तव्य में अहिंसा के सिद्धांत को 'मानवजाति के पास सबसे बड़े बल' के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दुर्भावना और संघर्ष पर विजय पाने और लोगों तथा राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मान और समझ की भावना स्थापित करने के लिए अहिंसा की ताकत का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। समारोह में श्री बीरद राजाराम याज्ञिक द्वारा प्रकाशित 'एमकेजी-इमेजिंग पीस, ट्रुथ एंड अहिंसा' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुधार

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अति आवश्यक ढांचागत सुधार लाने के लिए समान दृष्टिकोण वाले सदस्य राष्ट्रों के साथ अपना सहयोग जारी रखा। 2010 के प्रारम्भ में भारत को जी-4 तथा दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मूलपाठ-आधारित वार्ता कराने के अपने प्रयासों में सफलता मिली। 2010 में आयोजित वार्ताओं में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के एक बड़े बहुमत ने सुरक्षा परिषद में शीघ्र सुधार के लिए अपनी मंशा को प्रकट किया, जिसके तहत उन्होंने उसकी स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों की सदस्यता का विस्तार किए जाने तथा परिषद के कार्य के तरीकों में सुधार लाए जाने पर बल दिया।

भारत ने खासतौर से अप्रैल 2010 से तदर्थ कार्य समूह में आयोजित की गई महासभा पुनर्जीवीकरण पर चर्चा में सक्रिय हिस्सा लिया। भारत ने पुनर्जीवीकरण के लिए अनेक सुझाव देकर अग्रणी भूमिका निभायी, जिनमें से अनेक सुझावों को उस संकल्प में शामिल किया गया जिसे सितम्बर 2010 में संकल्प 64/301 (2010) के नाम से अंगीकार किया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 जुलाई, 2010 को स्त्री-पुरुष समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नवीन संयुक्त राष्ट्र संस्थान 'यूएन वूमन' के सृजन के लिए अनुमोदन प्रदान किया। भारत की विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रणीत कौर ने इस एतिहासिक संकल्प को अंगीकार किए जाने के समय महासभा को संबोधित किया।

आतंकवाद

आतंकवाद का दमन करने और आतंकी गतिविधियों को रोकने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी रही। इस संदर्भ में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ मसौदा व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) पर चर्चा में प्रगति और उसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। सीसीआईटी के मुद्दे पर छठी समिति की तदर्थ समिति द्वारा 12-16 अप्रैल, 2010 तक आयोजित बैठक और अक्तूबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति की बैठक में विचार किया गया। फ्रेंडस ऑफ चेयर ने अभिसमय के लिए संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

शांतिरक्षा

भारत संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा कार्यकलापों को सबसे बड़े और निरंतर योगदान करने वाले राष्ट्रों में से एक बना रहा। वर्ष 2010 में भारत 8,919 सैनिकों का योगदान करके तीसरा सबसे बड़ा सैनिकों का योगदान करने वाला राष्ट्र रहा, जिन्हें लेबनान (यूएनआईएफआईएल), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (मोनुस्को), सीरिया-इजराइल सीमा पर गोलान की पहाड़ियों (यूएनडीओएफ), लाइबेरिया (यूएनएमआईएल), सूडान (यूएनएमआईएस), कोट डी' आयवर (यूएनओसीआई), साइप्रस (यूएनएफआईवाईपी), पूर्व तिमोर (यूएनएमआईटी), और हैती (एमआईएनयूएसटीएएच) में 9 संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों में नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी भारतीय उपस्थिति कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन में 4,248 सैनिकों की थी। उसके बाद सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में 2,636 सैनिकों की थी।

शांति निर्माण

भारत ने 4 नवम्बर, 2010 को शांति निर्माण निधि में 2 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की, जिससे

शांति निर्माण निधि में इसका कुल योगदान दो गुना होकर 4 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि

भारत ने नवम्बर 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की। इस प्रकार भारत ने जुलाई 2005 में स्थापित निधि के लिए कुल 25 मिलियन अमरीकी डालर के योगदान की पेशकश से भी योगदान किया, जिससे वह अमरीका के बाद दूसरा सबसे अधिक योगदान करने वाला राष्ट्र बन गया। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि लोकतांत्रिक संस्थाओं को समन्वित और सुदृढ़ करने तथा लोकतांत्रिक अधिशासन को सहज बनाने के लिए सभ्य समाज को शामिल करके चलाई जाने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है।

मध्य पूर्व

भारत ने 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति और पूर्ण समिति में मध्य पूर्व मुद्दे पर विचार-विमर्श में संलग्नता जारी रखी। भारत के वक्तव्यों में फिलिस्तीन के लोगों को अपने न्याय संगत लक्ष्य को प्राप्त करने और गरिमा एवं आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करने के प्रयासों को अपना समर्थन प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को रेखांकित किया गया और साथ ही आतंक एवं हिंसा के सभी कृत्यों के प्रति अपना संकल्पबद्ध विरोध भी दोहराया गया। गाजा पट्टी में मानवीयता से जुड़ी चिंताओं को प्राथमिकता दिए जाने को बल देते हुए भारत ने फिलिस्तीन के भीतर सामग्रियों और व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों में पूरी तरह ढील दिए जाने का आह्वान किया। भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए कोक 1 मिलियन अमरीकी डालर का और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकार को संयुक्त बजटीय समर्थन के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान भी किया। इस वर्ष का बजटीय सहयोग इस वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री के बीच हुई चर्चा पर आधारित था।

प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने संदेश में फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक ऐसे सप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य और संयुक्त फिलिस्तीनी राष्ट्र के प्रति भारत के अटल समर्थन को दोहराया, जो पूर्वी जेरुसलम में अपनी राजधानी के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ शांतिपूर्वक रह सके, जैसा कि अरब शांति पहल, क्वार्टेट रोड मैप और संगत संयुक्त राष्ट्र संकल्पों में कहा गया है।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन

गुट निरपेक्ष आंदोलन (नैम)

नैम द्वारा 'गुट निरपेक्ष आंदोलन-पचास वर्षों की उपलब्धियां-हमारी भावी साझा दृष्टि' विषय पर 65वीं महासभा के दौरान 27 सितम्बर, 2010 को नैम के समन्वयन ब्यूरो की एक मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नैम की 50वीं वर्षगांठ के मुख्य समारोह के लिए आरंभिक कार्य तैयार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री ने कहा कि नैम का मार्गदर्शन एक नवीन, सुदूरदर्शी और संकेंद्रित विषय सूची द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्त के प्रबंधन, सतत् खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, निर्धनता उन्मूलन, भूख और विपन्नता को समूल अंत करने, जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी एवं संगठित अपराध का मुकाबला करने से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों को हल किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंदोलन को सार्वभौमिक और भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने और सभी तरह के परमाणु अस्त्रों से मुक्त विश्व का निर्माण करने के लिए प्रयासों में अपनी और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी आह्वान किया कि वैश्विक विकास कार्यसूची में अफ्रीका की प्रमुखता सुनिश्चित करने के लिए नैम सतत प्रयास करे।

राष्ट्रमंडल

भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है, जहां की आबादी इसकी कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत है। यह राष्ट्रमंडल के बजट का चौथा सबसे बड़ा योगदाता है। भारत राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग निधि (सीएफटीसी) द्वारा वित्त पोषित सबसे अधिक संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ भी प्रदान करता है और ब्रिटेन के बाद विकासशील राष्ट्रमंडल देशों को सहयोग प्रदान करने वाला राष्ट्र है।

3-14 अक्तूबर, 2010 तक नई दिल्ली में उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। 71 राष्ट्रमंडल राष्ट्रों और भूक्षेत्रों से लगभग 7,000 खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 101 पदक हासिल किए और राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे मजबूत प्रदर्शन किया और आस्ट्रेलिया के बाद दूसरे सर्वाधिक पदक जीतने वाले राष्ट्र के रूप में उभरा।

विदेश मंत्री ने 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 27 सितम्बर, 2010 को आयोजित राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया बैठक में अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने सर्वसम्मति निर्माण, अनौपचारिकता और सद्भावना पर आधारित राष्ट्रमंडल की विलक्षण कार्यशैली, किए गए उल्लेखनीय कार्यकलापों की प्रशंसा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रमंडल के समर्थन में भारत सरकार की पहलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

राष्ट्रमंडल महासचिव श्री कमलेश शर्मा ने राष्ट्रमंडल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए मार्च, अगस्त और अक्तूबर 2010 में भारत की यात्रा की।

कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल) के अध्यक्ष और सीईओ सर जॉन डेनियल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्माल स्टेट्स ऑफ कॉमनवेल्थ (वीयूएसएससी) परियोजना के लिए भारत के समर्थन पर चर्चा के लिए 18 नवम्बर, 2010 को भारत आए थे। वीयूएसएससी राष्ट्रमंडल के 32 छोटे राष्ट्रों/द्वीप राष्ट्रों को

आईसीटी के उपयोग और ई-लर्निंग फार्मेट में मानव संसाधन के प्रशिक्षण हेतु सीओएल द्वारा चलाई गई परियोजना है।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला ने 19-21 मई, 2010 को अकरा, घाना में आयोजित राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन निकाय (सीएनईएमबी) के प्रमुखों की पहली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 16 जुलाई, 2010 को लंदन में आयोजित सीएनईएमबी की बैठक में भी हिस्सा लिया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने 16 मई, 2010 को जेनेवा में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में चर्चा का मुख्य मुद्दा '2015 तक राष्ट्रमंडल तथा स्वास्थ्य एमडीजी' था। बैठक में 43 देशों से आए 293 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

लोकतंत्र समुदाय

वारसा में 2000 में इस संगठन की स्थापना की दसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2-4 जुलाई, 2010 को क्राको, पोलैंड में 'वैश्विक लोकतंत्र एजेंडा' पर लोकतंत्र समुदाय की एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 70 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 20 देशों की मंत्रिस्तरीय भागीदारी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकत्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। भारत की ओर से बैठक में सरकारी स्तर पर प्रतिनिधित्व किया गया।

सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैती पर सम्पर्क समूह

भारत संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती निरोध प्रयासों में सक्रिय भागीदारी करता रहा। जनवरी 2009 में स्थापित सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैती पर संपर्क समूह (सीजीपीसीएस) के संस्थापक सदस्य के रूप भारत ने नवम्बर, 2010 में न्यूयॉर्क में इस संपर्क समूह की पूर्ण बैठक और उसके चौथे कार्य समूहों में हिस्सा लिया। सीजीपीसीएस 45 देशों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बना एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

यूएनईएस प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र में भारत

वर्ष 2010 संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा रहा। भारत के सर्वाधिक मत प्राप्त करने के उपरांत 2011-2012 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना गया। कुल 190 मतों में 187 मत हासिल करने पर भारत को प्राप्त मदों की संख्या न केवल चुनाव में खड़े देशों में सबसे अधिक थी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के 98 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि यह कई वर्षों में सबसे बेहतर परिणाम भी रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उम्मीदवारी को इतना व्यापक समर्थन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को मिले व्यापक समर्थन की भी पुनः पुष्टि करता है। भारत ने 1 जनवरी, 2011 को जापान से सुरक्षा परिषद में एशियाई सीट का पदभार ग्रहण किया। भारत उन्नीस वर्षों के अंतराल के बाद सुरक्षा परिषद में प्रवेश करने जा रहा है।

भारत को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के चुनाव में भी आकर्षक सफलता हासिल हुई। भारतीय उम्मीदवार को एशिया से तीन पदों के लिए पांचवीं समिति में अत्यधिक महत्वपूर्ण चुनावी संघर्ष में सर्वाधिक मत हासिल हुए, जिसमें चीन, जापान और पाकिस्तान ने भी उम्मीदवारी की थी।

वर्ष 2010 में भारत स्त्री-पुरुष समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण ('यूएन वूमन') के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था सृजित करने में भी पूरी तरह संलग्न रहा और अग्रणी भूमिका निभाता रहा। भारत ने यूएन वूमन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण अंतिम वार्ता सत्रों की सहअध्यक्षता की और उसकी अंतिम अवस्थाओं में प्रक्रिया के भारत के निपुण नेतृत्व इसके तेजी से बढ़ते वैश्विक ओहदे और स्वीकार्यता को दर्शाते हैं। नवम्बर 2010 में भारत को इकोसोक द्वारा यूएन वूमन के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया था।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र के उच्चस्तरीय खंड में सरकारी भारतीय प्रतिनिधियों की अगुवाई में 21-30 सितम्बर, 2010 तक न्यूयॉर्क की यात्रा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए अपने भाषण में उन्होंने आह्वान किया कि समसामयिक वास्तविकताओं को अभिव्यक्त करने और उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वार्ताकारी, नीति निर्माता और प्रतिनिधित्वकारी निकाय के रूप में महासभा को वैश्विक राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक एजेंडे की स्थापना करनी चाहिए। इसे महासचिव की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों और संयुक्त राष्ट्र तथा ब्रेटन बुड्स संस्थाओं के बीच संबंध में अपने ओहदे को पुनः प्राप्त करना चाहिए।

विदेश मंत्री ने यूएन वूमन और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए भारत की मजबूत वचनबद्धता को दोहराया और आशा प्रकट की कि मानवाधिकार परिषद की आगामी समीक्षा में एक प्रभावी और भरोसेमंद तंत्र के रूप में परिषद की भूमिका के योगदान पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि जलवायु परिवर्तन संबंधी कष्टसाध्य संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय और उसके क्योटो प्रोतोकॉल और साथ ही तीन साल पहले बाली में तैयार किए गए उसके रोडमैप का अनुपालन किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्व के हजारों करोड़ निर्धन लोगों को बेहतर भविष्य की उनकी आकांक्षाओं, जिनमें छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्रों, सबसे कम विकसित देशों और अफ्रीकी देशों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी भिन्न-भिन्न क्षमताओं पर

गौर करना चाहिए। उन्होंने विकसित देशों का आह्वान किया कि उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को न केवल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने संबंधी अपनी अधिक महत्वाकांक्षी वचनबद्धताओं के अर्थ में बल्कि विकासशील देशों को उनके उपशमन और अनुकूलीकरण प्रयासों में मदद करने के अर्थ में भी पूरा करना चाहिए।

आम बहस की शुरुआत से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र में कई अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें 20-22 सितम्बर, 2010 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पर उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक, कार्यान्वयन हेतु मॉरीशस रणनीति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक और जैव विविधता पर अभिसमय संबंधी एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम शामिल थे। विदेश मंत्री ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्य और कार्यान्वयन हेतु मॉरीशस रणनीति की उच्च स्तरीय समीक्षा लक्ष्यबैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की, जबकि पर्यावरण और वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभाग) श्री जयराम रमेश ने जैव विविधता पर अभिसमय संबंधी उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रणीत कौर ने अक्तूबर 2010 में न्यूयॉर्क की यात्रा की और प्रमुख संयुक्त राष्ट्र शिखर बैठकों तथा सम्मेलनों के अनुवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

चुनाव

भारत के उम्मीदवार राजदूत चन्द्रशेखर दास गुप्ता को आर्थिक और सामाजिक परिषद को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी समिति (इकोसोक) के चुनाव में सर्वाधिक मत मिले और उन्हें 27 अप्रैल, 2010 को इसका सदस्य बनाया गया।

उनका चयन गैर-सरकारी संगठनों संबंधी समिति, एचआईवी/एड्स पर संयुक्त यूएन कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आयोग में भी सर्वसम्मति से किया गया।

संयुक्त राष्ट्र की पांचवीं (प्रशासनिक और बजटीय) समिति ने संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र लेखा परीक्षा सलाहकार समिति में एशियाई राष्ट्रों के समूह में हुई रिक्ति को भरने के लिए सर्वसम्मति से 5 नवम्बर, 2010 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय की नियुक्ति की सिफारिश की।

पांचवीं समिति ने भारत के स्थायी मिशन, न्यूयॉर्क में प्रथम सचिव श्रीमती नामग्या सी खाम्या को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों संबंधी 16 सदस्यों वाली सलाहकार समिति में एशियाई समूह के तीन पदों में से एक पर सर्वोच्च मत से चयन किया। शेष दो रिक्तियां जापान और चीन के उम्मीदवारों द्वारा भरी गई हैं।

आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दे

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

न्यूयॉर्क में 20-22 सितम्बर, 2010 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पर एक उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को 2015 तक पूरा किए जाने की भारत की सर्वोच्च राजनैतिक वचनबद्धता की जानकारी दी। उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक के दौरान 'लक्ष्य की ओर अग्रसरः सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट' शीर्षक से एक राजनैतिक घोषणा अंगीकार की गई।

आर्थिक और सामाजिक परिषद (इकोसोक)

आर्थिक और सामाजिक परिषद के 2010 यथेष्ट सत्र का आयोजन 28 जून-22 जुलाई 2010 तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेणीत कौर ने 28 जून-2 जुलाई, 2010 तक मंत्रिस्तरीय खंड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की और 'अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों तथा वचनबद्धताओं का कार्यान्वयन तथा स्त्री-पुरुष समानता एवं महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर वार्षिक मंत्रिस्तरीय समीक्षा को संबोधित किया। इस विषय पर एक मंत्रिस्तरीय घोषणा उच्च स्तरीय खंड की समाप्ति पर अंगीकार की गई।

विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन (वाइपो)

भारत ने वाइपो के साथ अपनी सर्जनात्मक संलग्नता जारी रखी और इसकी बौद्धिक सम्पत्ति और विकास, लिप्यतंरण और संबंधित अधिकार, ट्रेड मार्क, औद्योगिक अभिकल्पना और भौगोलिक संकेत पर स्थायी समितियों, परम्परागत ज्ञान, लोकगीत और आनुवंशी संसाधन संबंधी अंतर सरकारी समिति और प्रवर्तन संबंधी सलाहकार समिति की बैठकों में सक्रिय भागीदारी की। सचिव (डीआईपीपी) की अगुवाई में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से एक प्रतिनिधिमंडल ने 22-29 सितम्बर, 2010 तक जिनेवा में आयोजित वाइपो के सदस्य राष्ट्रों की सभाओं की बैठकों की 48वीं श्रंखला में हिस्सा लिया।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संबंधी आयोग (अंकटाड)

भारत ने अंकटाड की सभी बैठकों में हिस्सा लिया जिनमें व्यापार और विकास बोर्ड के सत्र और उद्यम विकास नीतियों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नयाचार में क्षमता निर्माण, विकास के लिए निवेश, ग्रामीण विकास तथा व्यापार के नियामक और संस्थागत पहलुओं पर विशेषज्ञ बैठकें भी शामिल थीं। 2010 में भारत ने स्वेच्छा से अंकटाड न्यास निधि में 15,000 अमरीकी डालर का योगदान किया, जो अंकटाड विशेषज्ञ बैठकों में विकासशील देशों से विशेषज्ञों की वित्तपोषण भागीदारी के रूप में था। भारत के प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष ने प्रतिबंधात्मक कारोबार के नियंत्रण हेतु बहुपक्षीयता आधारित स्वीकृत समतामूलक सिद्धांतों और नियमों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए 8-12 नवम्बर, 2010 तक आयोजित छठे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (आईटीयू)

इस वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (आईटीयू) से संबंधित एक प्रमुख कार्यकलाप 4-22 अक्तूबर, 2010 तक

गुआडालाजारा, मेक्सिको में आयोजित पूर्णाधिकारी सम्मेलन (पीपी10) था। भारत को आईटीयू के परिषद में पुनः चुना गया और भारत के नामिती श्री पी. के. गर्ग को भी रेडियो नियामक बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया। आईटीयू परिषद के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में दूरसंचार विभाग के उपमहानिदेशक (आईआर) श्री आर. एन. झा ने अप्रैल और जुलाई 2010 में परिषद से संबंधित बैठकों में हिस्सा लिया।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आईटीयू महासचिव तथा अन्य चुने हुए अधिकारियों के साथ आईटीयू के विभिन्न कार्यकलापों में भारत की स्थिति को बढ़ावा देने और समेकित करने के संबंध में बैठकें करने के लिए 10-11 जून, 2010 को जेनेवा की यात्रा की।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.)

भारत ने 17-21 मई, 2010 तक 63वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हिस्सा लिया। भारत ने जन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षोपाय करने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर जोर दिए जाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किए जाने, जरुरी दवाओं की पहुंच बढ़ाने और जन स्वास्थ्य चिंताओं को हल करने के लिए ट्रिप्स लोचनीयता के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की विश्व स्वास्थ्य संगठन मंच पर वकालत करना जारी रखा। भारत ने सामाजिक विकास में समानता सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य संबंधी सहस्राब्धि विकास लक्ष्यों को केंद्र बनाने को प्रोत्साहित किया।

भारत ने एक नए बहुप्रयोजन कार्यसमूह की स्थापना के माध्यम से विश्व महामारी प्रतिश्याय मोर्चाबंदी ढांचा (पीआईपीएफ) को अंतिम रूप दिए जाने में अपनी संलग्नता बनाए रखी। ए/एच1एन1 और प्रतिश्याय विश्व महामारी के संदर्भ में इस ढांचे का उपयोग बढ़ा है। भारत ने इस बात पर जोर देना जारी रखा कि लाभ-साझा करने तथा विश्व महामारी प्रतिश्याय सामग्री की पहुंच दोनों को ढांचे में समानता से हल किया जाना चाहिए ताकि सभी प्रभावित आबादियों को टीके और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। भारत विकासशील देशों में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैश्विक कार्य संहिता तैयार किए जाने को चल रही प्रक्रिया में संलग्न रहा। भारत ने गैर-संक्रमणीय बिमारियों पर वैश्विक रणनीति पर संकेंद्रण बनाए रखा और इन बीमारियों से लड़ रहे विकासशील देशों के दोहरे बोझ को कम किए जाने की जरुरत पर बल दिया जो संक्रमणीय बीमारियों के परम्परागत क्षेत्रों तथा गैर संक्रमणीय बिमारियों के उभरते बोझ दोनों से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने 6-10 सितंबर, 2010 तक बैंकाक में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया संबंधी डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति की 63वीं बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर बने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

विश्व वायुमंडलीय संगठन

मौसम सेवाओं संबंधी वैश्विक ढांचा (जीएफसीएस): मई-जून 2009 में जेनेवा में डब्ल्यू सीसी 3 घोषणा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उच्च स्तरीय कृत्यक बल की स्थापना के परिणाम स्वरूप विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस कृत्यक बल के विचारार्थ विषय को अंतिम रूप देने के लिए 11-12 जनवरी, 2010 तक एक अंतर्सरकारी बैठक का आयोजन किया। अंतर्सरकारी बैठक की रिपोर्ट में समान दृष्टिकोण वाले समूह (जिसका भारत एक सदस्य है) के सामान्य सिद्धांत शामिल किए गए जिनमें (क) मौसम सेवाओं संबंधी वैश्विक ढांचे की स्थापना और (ख) मौसम सेवाओं के पणधारियों को मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े एकत्र करके भेजे जाने में राष्ट्रीय सरकारों की केंद्रीय और निर्णायक भूमिका पर बल दिया गया। भारत ने समान दृष्टिकोण वाले समूह के भीतर विचार-विमर्शों का नेतृत्व करना और उच्च स्तरीय कृत्यक बल के कार्यकलापों की प्रगति का मानीटरण करना जारी रखा। भारत ने उच्च स्तरीय कृत्यक बल को सीएचएफ 10,00,000 के वचनबद्ध योगदान के शेष हिस्से के रूप में अगस्त 2010 में सीएचएफ 5,00,000 का योगदान किया। भारत ने प्रारुप रिपोर्ट पर अपनी राष्ट्रीय टिप्पणियां भी भेजी, जो अतिरिक्त तकनीकी ब्यौरों के साथ समान दृष्टिकोण वाले समूह के अनुरुप थीं। प्रारुप रिपोर्ट का उच्च स्तरीय कृत्यक बल द्वारा संशोधन किया जा रहा है, जोकि सभी सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त टिप्पणियों पर आधारित होगा। संशोधित रिपोर्ट 12 जनवरी, 2011 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी)

भारत ने यूएनईएससीएपी के 66वें वार्षिक सत्र में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन 13-19 मई, 2010 तक इन्चियोन, कोरिया गणराज्य में किया गया था। सत्र का विषय 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में चुनौतियों को हल करना; एक स्थिर और समर्थनकारी वित्तीय व्यवस्था को प्रोन्नत करना; हरित विकास अथवा पर्यावरण की दृष्टि से दीर्घकालिक आर्थिक विकास, जिसमें प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण के माध्यम से विकास भी शामिल है' था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व थाइलैंड में भारतीय राजदूत और ईएससीएपी में स्थायी प्रतिनिधि श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने किया।

संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)

भारत ने 12-19 अप्रैल, 2010 तक सैल्वाडोर, ब्राजील में आयोजित 12वें अपराध कांग्रेस में हिस्सा लिया। 12वें अपराध कांग्रेस का विषय 'वैश्विक चुनौतियों के लिए व्यापक रणनीतियांः अपराध की रोकथाम और दाण्डिक न्याय पद्धति तथा परिवर्तनशील विश्व में उनका विकास' था। भारत साइबर-अपराध, समुद्री डकैती आदि जैसे अपराध के नवीन और उभरते स्वरूपों के मुद्दे सहित कई मुद्दे उठाने में अग्रणी रहा।

गृह मंत्रालय में विशेश सचिव सुश्री अनीता चौधरी ने 17-22 मई, 2010 तक वियना, आस्ट्रिया में आयोजित अपराध की रोकथाम और दाण्डिक न्याय संबंधी आयोग (सीसीपीसीजे) की 19वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के राजदूत श्री दिनकर खुल्लर सीसीपीसीजे के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए। भारत ने अपराध से जुड़े मामलों पर अपनी स्थिति को जोर देकर स्पष्ट किया और अपराध के भिन्न-भिन्न स्वरूपों, खासतौर जो महिलाओं पर किए जाते हैं, को रोकने के लिए किए गए उपायों पर विशेष बल दिया। भारत ने बैठक के दौरान अंगीकार किए गए समुद्री डकैती का मुकाबला करने संबंधी संकल्प को रखने में अग्रणी भूमिका निभाई और उसका सहप्रायोजन भी किया। भारत ने अफगानिस्तान से अफीम और स्वापक द्रव्यों की तस्करी और अफगान स्वापक तस्करी मार्ग के प्रभावित देशों में उनके उपभोग और संबंधित समस्याओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से की गई पेरिस समझौता पहल की विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया। भारत ने पेरिस समझौता पहल को दिए गए अपने महत्व को ध्यान में रखते हुए इससे 2,00,000 अमरीकी डालर का योगदान किया।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ घनिष्ठ संलग्नता बनाए रखी। भारत से गए प्रतिनिधिमंडल ने 10-12 मई, 2010 को वियना में आयोजित औद्योगिक विकास बोर्ड के 37 सत्र की बैठकों में हिस्सा लिया। भारत ने यूएनआईडीओ से खासतौर पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के क्षेत्र में सेवाओं की सुपुर्दगी बढ़ाने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के महानिदेशक डॉ. कण्डेह के. युमकेल्ला ने 27-29 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन (डीआईआरसी, 2010) में हिस्सा लिया। उन्हें 28 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली स्थित टीईआरआई विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया।

पर्यावरण से जुड़े मुद्दे

जैव विविधता संबंधी अभिसमय

जैव विविधता संबंधी अभिसमय पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 22 सितंबर, 2010 को न्यूयॉर्क में किया गया। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयराम रमेश ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने जैव विविधता और जीव-विज्ञानी विविधता संबंधी अभिसमय को वैश्विक चर्चा के केंद्र पर रखे जाने पर बल दिया और आह्वान किया कि वैश्विक जीव विज्ञानी संसाधनों के संरक्षण के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर अंतर्सरकारी पैनल की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए।

अक्तूबर 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव ने जैव विविधता संबंधी अभिसमय के पक्षकारों के 10वें सम्मेलन (सीओपी10) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नगोया में आयोजित सीओपी-10 के दौरान पहुंच और लाभ साझा करने संबंधी नगोया प्रोतोकॉल को सफलतापूर्वक अंगीकार किया गया, जिसके द्वारा आनुवंशी स्रोतों के उत्पन्न लाभों को निष्पक्ष और समान रूप से साझा किए जाने हेतु एक ढांचा स्थापित किया गया है।

सतत **कालिक विकास संबंधी आयोग**

भारत ने सतत विकास संबंधी आयोग के कार्यों में सक्रिय भागीदारी की जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की भीतर एक उच्च स्तरीय आयोग है और जिसकी भूमिका एजेंडा 21 तथा जोहानसबर्ग कार्यान्वयन योजना (जेपीओआई) के कार्यान्वयन की समीक्षा और प्रोन्नयन करना है। सचिव (पर्यावरण) श्री विजय शर्मा ने 3-14 मई, 2010 को न्यूयॉर्क में आयोजित आयोग के 18वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। यह दो वर्षीय कार्यान्वयन चक्र का समीक्षा सत्र था और इसमें कचरा प्रबंधन, रसायन, परिवहन, खनन और उपभोग एवं उत्पादन के सतत पैटर्न पर विषय केंद्रित चर्चा की गई।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संबंधी सम्मेलन की प्रथम तैयारी समिति (जिसे रिओ 20 भी कहा गया है) की 17-19 मई, 2010 को आयोजित बैठक में भी हिस्सा लिया। तैयारी समिति की बैठक में रियो सम्मेलन के बाद की गई प्रगति और निष्कर्षों के कार्यान्वयन में शेष बचे कार्य, नवीन तथा उभरती चुनौतियों को हल करने और सतत विकास एवं निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में यूएनसीएसडी 2012 - हरित अर्थव्यवस्था हेतु विषय, तथा सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचा पर चर्चा की गई।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभिसमय की रूपरेखा

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में दिए अपने भाषण में विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया था कि कष्टसाध्य संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय और इसके क्योटो प्रोतोकॉल के नियमों और तीन साल पहले बाली में पेश किए गए रोडमैप का अनुपालन किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्व के हजारों करोड़ निर्धनों के बेहतर भविष्य की उनकी आकांक्षाओं- जिनमें छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्रों, अल्प विकसित देशों और अफ्रीकी देशों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी भिन्न-भिन्न क्षमताओं पर गौर करना चाहिए। उन्होंने विकसित देशों का आह्वान किया कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को न केवल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने संबंधी अपनी अधिक महत्वाकांक्षा वचनबद्धताओं के अर्थ में बल्कि विकासशील देशों को उनके उपशमन और अनुकूलीकरण प्रयासों में मदद करने के अर्थ मे भी पूरा करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 29 नवम्बर, 2010 से 11 दिसम्बर, 2010 तक कानकुन, मैक्सिको में आयोजित किया गया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन का सोलहवां सत्र (सीओपी-16) और क्योटो प्रोतोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में पक्षकारों के सम्मेलन का छठा सत्र (सीओपी/एमओपी-6) भी शामिल था। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयराम रमेश के नेतृत्व में एक बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में हिस्सा लिया।

कानकुन सम्मेलन से पहले वर्ष 2010 में तदर्थ कार्य समूहों के चार वार्ता सत्र आयोजित किए जा चुके थे। ये सत्र अप्रैल, मई-जून, और अगस्त 2010 में बोन, जर्मनी में और अक्तूबर में तियान्जिन, चीन में आयोजित किए गए थे। इन सभी बैठकों में सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया था।

कानकुन में हुए सम्मेलन के दौरान बाली कार्ययोजना और अभिसमय तथा क्योटो प्रोतोकॉल के अधीन दीर्घकालिक सहयोग कार्रवाई के दो ट्रैकों को शामिल करके कई निर्णय लिए गए। कानकुन करार की मुख्य-मुख्य बातों में विकसित तथा विकासशील देशों से समान प्रतिनिधित्व के साथ सीओपी के अधीन 'हरित जलवायु निधि' के गठन; संवर्धित वित्तीय और तकनीकी समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन हेतु एक 'कानकुन अनुकूलन ढांचा' की स्थापना; प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तातंरण के लिए एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति और जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र तथा नेटवर्क के साथ एक 'प्रौद्योगिकी तंत्र' की स्थापना; और प्रौद्योगिकीय एवं वित्तीय समर्थन के साथ विकासशील देशों में वन कटाई एवं वन अवक्रमण से उत्पन्न उत्सर्जन को रोकने (आईईडीडी) के संबंध में निर्णय शामिल थे।

वर्ष 2010 में भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य बैठकों में भी सक्रिय भागीदारी की। इनमें क्रमशः सितम्बर और नवम्बर 2010 में आयोजित आठवीं और नवीं नेताओं के प्रतिनिधियों की बैठकें और नवम्बर 2010 में मैक्सिको सिटी में मैक्सिकन मेजबानों द्वारा आयोजित सी ओडी पूर्व मंत्रिस्तरीय बैठक शामिल थी।

भारत ने भी नई दिल्ली में नवम्बर 2010 में एक जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित किया, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण पर कानकुन में लिए गए निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की गई।

बेसिक समूह के हिस्से के रूप में भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच कानकुन सम्मेलन के लिए पूरा सहयोग बना रहा और नई दिल्ली (जनवरी 2010), केपटाउन (अप्रैल 2010), रिओ (जुलाई 2010) तथा तिआन्जिन (अक्तूबर 2010) में बैठकें की गई।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अधिशासन पर मंत्रियों/उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के परामर्शी समूह की यूएनईपी की पहली बैठक 7-9 जुलाई को नैरोबी में आयोजित की गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अधिशासन पर मंत्रियों/उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के परामर्शी समूह की यूएनईपी की दूसरी बैठक 21-23 नवम्बर को एस्पो, हेल्सिंकी में आयोजित की गई। इन बैठकों में विचार-विमर्श के मुख्य विषय 'हरित अर्थव्यवस्था' और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अधिशासन का सुधार रहे। भारत ने कैलेण्डर वर्ष 2010 के दौरान जी-77 और चीन (नैरोबी चैप्टर) की अध्यक्षता भी की।

सामाजिक और मानवाधिकार के मुद्दे

भारत ने मानवाधिकारों और सामाजिक मुद्दों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संगठनों के कार्यकलापों में सर्जनात्मक ढंग से भागीदारी की जो विकासोन्मुख उद्देश्य और साथ ही अपनी सहनशीलता और मानवाधिकारों तथा मानवीय मूल्यों के सम्मान की ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए एक समदर्शी दृष्टिकोण अपनाने के प्रति भारत की वचनबद्धता दर्शाती है।

भारत ने मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट तथा वैश्विक स्वास्थ्य तथा विदेश नीति मुद्दों सहित विभिन्न कार्यसूची मदों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा पूर्ण सत्र में हुई चर्चा में सक्रिय भागीदारी की।

भारत ने अटलांटिक पार दास व्यापार को समाप्त किए जाने की 200वीं वर्षगांठ के आयोजन के अनुवर्तन' पर आयोजित बहस में भी हिस्सा लिया। इस संबंध में भारत ने दास प्रथा और अटलांटिक पार दास व्यापार के पीड़ितों के सम्मान में न्यूयॉर्क में स्थायी स्मारक के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास निधि को अप्रैल 2010 में 2,60,000 अमरीकी डालर का योगदान भी किया।

निःशक्त जनों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के राष्ट्र पक्षकारों की तीसरी बैठक

निःशक्त जनों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के राष्ट्र पक्षकारों की तृतीय बैठक 1-3 सितम्बर, 2010 तक आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती संगीता गैरोला ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान निःशक्त जनों के अधिकारों संबंधी समिति के बारह सदस्यों के चुनाव के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों पर तीन पैनल चर्चाएं आयोजित की गई, (क) समुदाय में समावेशन और निवास (सीआरपीडी का अनुच्छेद 19); (ख) समावेशन और शिक्षा का अधिकार (सीआरपीडी अनुच्छेद 24) और (ग) खतरे की स्थिति और मानवीय आपातकालिकताएं (सीआरपीडी का अनुच्छेद 11)।

महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग

महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग के 54वें सत्र का आयोजन 1-12 मार्च, 2010 तक किया गया। भारत 2009 से चार वर्षों के लिए आयोग का सदस्य है। वर्ष 2010 में बीजिंग घोषणा और

कार्रवाई मंच (बीडीपीए) की 15वीं वर्षगांठ है, इसलिए आयोग की बैठक का मुख्य विषय शेष बचे अवरोधों और नई चुनौतियों पर काबू करने की दृष्टि से बीडीपीए के कार्यान्वयन की समीक्षा था। एक संक्षिप्त घोषणा भी अंगीकार की गई। इसके अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर 7 संकल्प भी अंगीकार किए, जिनमें (क) फिलिस्तीन की महिलाओं की स्थिति और उनकी सहायता; (ख) बालिका और एचआईवी/एडस; (ग) बंधक बनाए गए महिलाओं और बच्चों की रिहाई, जिनमें सशस्त्र संघर्ष के उपरांत बंधक बनाए गए महिलाएं और बच्चे शामिल हैं; (घ) महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (ड़) महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा रोकी जा सकने योग्य मातृत्व मृत्यु और अस्वस्थता को समाप्त करना; (च) मौजूदा चार कार्यालयों को मिलाकर एक समन्वित संस्था का रूप दिया जाए और महिला-पुरुष समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्थन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, तथा (छ) महिलाओं के जननांगों को भेदने की प्रथा को समाप्त करना शामिल थे।

मानवाधिकार परिषद

2010 में तीन नियमित सत्रों के अतिरिक्त मानवाधिकार परिषद ने हैती में आपदा के उपरांत समुत्थान प्रक्रिया के प्रति मानवाधिकार दृष्टिकोण को प्रोन्नत करने के संबंध में एक विशेष सत्र का आयोजन किया। परिषद ने 48 देशों के लिए तीन सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा कार्य समूह सत्रों का भी आयोजन किया। सलाहकार समिति, सामाजिक मंच, अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दों पर मंच और स्वदेशी लोगों के अधिकारों संबंधी विशेषज्ञ तंत्र, विकास का अधिकार संबंधी कार्य समूहों और डरबन घोषणा तथा कार्रवाई कार्यक्रम के सत्रों का आयोजन किया गया। परिषद के समीक्षा संबंधी कार्य समूह के पहले सत्र और कई संबंधित अनौपचारिक बैठकों का आयोजन किया गया। परिषद ने शांतिपूर्ण सभा करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता और कानून तथा व्यवस्था में महिलाओं के साथ भेदभाव पर दो नए अधिदेश सृजित किए। भारत ने जून 2010 तक परिषद के सदस्य के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा किया और अब परिषद का प्रेक्षक है। मानवाधिकार परिषद में भारत की सहभागिता की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

- परिषद के अध्यक्ष द्वारा भारत के स्थायी प्रतिनिधि को परिषद की समीक्षा संबंधी कार्यसूची और कार्यक्रम के सहायक के रूप में मनोनीत किया गया।
- एशियाई समूह द्वारा भारत के स्थाई प्रतिनिधि को परामर्शी समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जो उनके चयन के लिए विशेष प्रक्रियाओं को तय करता है और उसने उसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता की।
- सीईडीए डब्ल्यू द्वारा नवम्बर 2010 में भारत की आपवादित रिपोर्ट की जांच की गई।
- एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट और डम्पिंग ऑफ टॉक्सिक एंड डैंजरस प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट के विशेष रिपोर्टर श्री ओके चुक्वू ओबिना इबियानू ने जनवरी 2010 में भारत की यात्रा की।
- मानवाधिकारों के संरक्षकों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टर सुश्री मार्गरेट सेकगया जनवरी 2011 में भारत की यात्रा करने वाली हैं।
- महत्वपूर्ण संधि मानीटरण निकायों और मानवाधिकार तंत्रों के सदस्यों के रूप में प्रतिष्ठित भारतीयों ने उत्कृष्ट सेवाएं करनी जारी रखी, जिनमें श्री पी. एन. भगवती (मानवाधिकार समिति के सदस्य), श्री दिलीप लाहिरी (नस्लभेद उन्मूलन समिति के सदस्य) और सुश्री इंदिरा जयसिंह (महिलाओं के साथ भेदभाव का उन्मूलन करने संबंधी समिति की सदस्य) शामिल थे।
- श्री चन्द्रशेखर दास गुप्ता को दूसरे कार्यकाल के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। श्री अरविंद ग्रोवर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्य मानक का उपभोग करने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के विशेष रिपोर्टर के रूप में अपने अधिदेश का निर्वाह करते रहे। श्री किशोर सिंह अगस्त 2010 में शिक्षा का अधिकार के विशेष रिपोर्टर नियुक्त किए गए।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के साथ संलग्नता की अपनी निरंतर वचनबद्धता (इसके बावजूद कि भारत ने शरणार्थियों संबंधी 1951 के भेदभाव पूर्ण अभिसमय और उसके 1967 के प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है) और सहनशीलता एवं अपनी भूमि पर हजारों शरणार्थियों को पनाह देने की अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण भारत ने उसकी सभी महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। कार्यकारी समिति के 61वें सत्र और संरक्षण चुनौतियों संबंधी उच्चायुक्त की वार्ता की चौथी बैठक में भारत की ओर से वक्तव्य दिए गए। भारत ने 2010 के लिए यूएनएचसीआर के कार्यकलापों पर मसौदा ओम्नीबस संकल्प, 2010 को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में स्वीडन का सक्रियता से समर्थन भी किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, शरणार्थियों, स्वदेश वापस जाने वालों और विस्थापतों तथा मानवीयता संबंधी प्रश्नों की रिपोर्ट पर कार्यसूची मद सं.61 के अधीन तीसरी समिति के पांचवें सत्र के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। सभी हस्तक्षेपों में भारत ने यूएन एचसीआर द्वारा अपने कोर अधिदेश पर उसके अभियानों, बजट और कार्मिकों को केंद्र पर रखे जाने, अपने अधिदेश को आपदा राहत कार्यकलापों की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करने के बजाए शरणार्थियों, राष्ट्रविहीन और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिए जाने के महत्व की बात को दोहराया। यूएनएचसीआर और भारत सरकार के

बीच तृतीय वार्षिक द्विपक्षीय परामर्श जेनेवा में मार्च/अप्रैल 2011 में होने की संभावना है।

प्रवासन

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम)

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रवासन के संबंध में आयोजित सभी बैठकों, अनौपचारिक परामर्शों और अंतर्सत्रीय कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। इन बैठकों में भारत ने सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के कोर अधिदेश को समर्थन देने में सहयोग प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की। भारत ने प्रवासन और विकास क बीच सहज जुड़ाव को पहचानने तथा प्रवासन के मुद्दे को मौजूदा कानून और व्यवस्था से जोड़कर देखने के बजाए अधिक व्यापक ढंग से देखे जाने के लिए सदस्य राष्ट्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के सचिवालय से आग्रह किया। वर्ष 2010 महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नवम्बर 2009 में 98वें परिषद सत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संघ के विदेशी लेखापरीक्षक के रूप में 2010-2012 तक तीन वर्षों के लिए चुने जाने के उपरांत) सितंबर 2010 में औपचारिक ढंग से अपना कार्यभार ग्रहण किया, जो नॉर्वे से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के विदेशी लेखा परीक्षक हुए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के महानिदेशक की 2011 में भारत यात्रा की संभावना है।

प्रवासन और विकास पर वैश्विक मंच (जीएफएमडी)

प्रवासन और विकास पर वैश्विक मंच की चौथी बैठक 10-12 नवम्बर, 2010 तक पूरतो वल्लार्ता, मैक्सिको में आयोजित किया गया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने किया। प्रवासन और विकास पर वैश्विक मंच की चौथी बैठक का विषय 'प्रवासन और मानव विकास के लिए भागीदारी, साझा सम्पन्नताः साझा जिम्मेदारी' था। हाल के वैश्विक वित्तीय संकट और इसके खासतौर पर प्रवासन और विकास परिणाम चर्चाओं और बहस के मुख्य विषय रहे। बांग्लादेश की अध्यक्षता में कोलम्बो प्रक्रिया की एक बैठक प्रवासन और विकास पर वैश्विक मंच के दौरान आयोजित की गई, जिसमें कोलम्बो प्रक्रिया की आगामी चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक, जिसका आयोजन ढाका में अप्रैल 2011 के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा, के लिए ठोस और संभारतंत्र से जुड़े मद्दें पर चर्चा की गई।

अंतर्संसदीय संघ (आईपीयू)

अंतर्संसदीय संघ के 2010 में तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। छठा महिला प्रवक्ता सम्मेलन बर्न में 16-18 जुलाई, 2010 तक आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सम्मेलन में महिलाओं को सशक्तिकरण, अनुभवों को साझा करने और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। संसद के अध्यक्षों का तीसरा विश्व सम्मेलन 19-21 जुलाई, 2010 को जेनेवा में आयोजित किया गया, जिसमें सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों द्वारा की गई प्रगति और संसदों द्वारा किए गए तत्संबंधी योगदानों की समीक्षा की गई। लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के उपसभापति ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधि ने अंतिम घोषणा (साझा हितों के लिए वैश्विक लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना) में आतंकवाद, और आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने के लिए एकजुटता दर्शाने और सामूहिक कार्यवाही की जरूरत को रेखांकित करने के लिए एक पैराग्राफ जोड़े जाने का प्रस्ताव किया।

वार्षिक 123वीं अंतर्संसदीय संघ सभा का आयोजन जेनेवा में 30 सितम्बर-6 अक्तूबर 2010 को किया गया। लोक सभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें राज्य सभा के उपसभापति तथा लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों के संसद सदस्य शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र और संसद के बीच सहयोग, निर्वाचन संबंधी हिंसा की रोकथाम और सत्ता का सहज हस्तांतरण सुनिश्चित करने, राजनैतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रवासन और विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादन और जनसंख्यिकीय परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त संसदीय मामले और जल संसाधन मंत्री की अगुवाई में एक भारतीय सद्भावना संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 3-4 अप्रैल, 2010 तक जेनेवा की यात्रा की।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

भारत ने 2-18 जून, 2010 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 99वें सत्र में हिस्सा लिया। भारत को सामाजिक और आर्थिक असमानता को हल करने के लिए अपनी विभिन्न राष्ट्रीय श्रमोन्मुख पहलों के लिए मान्यता मिली, इन पहलों के नाम हैं- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (एनआरईजीएस), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनएसडीवी), नई पेंशन स्कीम (एनपीएस)। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की चल रही सुधार प्रक्रिया में शामिल रहा, जो इसके अधिशासन तंत्र से संबंधित है, जिसके अंतर्गत शासी निकाय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भी सुधार किया जाना शामिल है।

यूनेस्को

कार्यकारी बोर्ड के 184वें सत्र का आयोजन 30 मार्च-15 अप्रैल, 2010 तक और 185वें सत्र का आयोजन 5-22 अक्तूबर, 2010 तक किया गया। मार्च/अप्रैल 2010 में आयोजित कार्यकारी बोर्ड सत्र में रवीन्द्र नाथ टैगोर, पाबलो नेरुदा और एइमे सीजेयर के योगदान को समन्वित ढंग से मनाए जाने के एक प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। कार्यकारी बोर्ड के 184वें सत्र में भारत के अनुरोध पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मुद्दे को खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया गया।

कार्यकारी बोर्ड के 185वें सत्र का आयोजन 5-22 अक्तूबर, 2010 को पेरिस में किया गया। पूर्ण सत्र में बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि डॉ. कर्ण सिंह के भाषण को काफी सराहना मिली, जिसमें उन्होंने महानिदेशक द्वारा प्रतिपादित की गई 'नवीन मानववाद ' को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और विज्ञान एवं समाज से संबंधित मुद्दों को संवर्धित संकेन्द्रण दिए जाने की अपील की ताकि प्रौद्योगिकीय उन्नति का आम जनता के लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। उन्होंने संस्कृति को विकास से जोड़ने में यूनेस्को द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका को भी रेखांकित किया। अब 'विकास के लिए संस्कृति' विषय को यूनेस्को में सभी कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों का केंद्रीय विषय बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

2009 में यूनेस्को महात्मा गांधी शांति और दीर्घगामी विकास के लिए शिक्षा संस्थान (एमजीआईईपी) को श्रेणी-। संस्थान के रूप में स्थापित किए जाने के लिए, लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान उद्देश्यों को परामर्श द्वारा तय किए जाने, संचालन और प्रशासन संबंधी ढांचे की पुष्टि किए जाने और शैक्षणिक कार्यकलापों के प्रमुख विषयों का निर्धारण करने की दृष्टि से इस संबंध में प्रगति की गई। प्रस्तावित संस्थान के ढांचे, स्टाफ और प्रबंधन को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित अन्य उपायों पर कार्रवाई चल रही है।

विश्व विरासत समिति का 34वां सत्र जून 2010 में ब्रासीलिया में आयोजित किया गया, जयपुर स्थित जंतर-मंतर को शिलालेख के लिए सूची पर अनुमोदित किया गया। इसके साथ सूची में शामिल सम्पत्तियों की कुल संख्या 28 हो गई है, जिसमें 5 राष्ट्रीय और 23 सांस्कृतिक सम्पत्तियां हैं।

भारत और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से 2011 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ को यादगार रूप से मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 12 मई, 2010 को मैसन डि ले इंडि सिटी यूनिवर्सिटी, पेरिस में किया गया।

14 सितम्बर, 2010 को मदर टेरेसा की जन्म सदी समारोह का आयोजन पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में यूनेस्को और भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

24-26 मार्च, 2010 तक यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) के अंतर्सरकारी परिषद के 27वें सत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री रघु मेनन को आईपीडीसी का नया अध्यक्ष चुना गया। भारत ने 30,000 अमरीकी डालर के वार्षिक योगदान के माध्यम से आईपीडीसी को उसके शुरुआत से अब तक 1.4 मिलियन डालर का योगदान किया है। भारत ने आईपीडीसी को इस वर्ष (2010-2011) उसके कार्यक्रमों के लिए 5,00,000 अमरीकी डालर का विशेष योगदान किया है।

यूनेस्को के मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन परिषद के 22वें सत्र का आयोजन 31 मई से 4 जून, 2010 तक यूनेस्को मुख्यालय में किया गया। परिषद ने जीव मंडल भंडार के विश्व नेटवर्क में ग्रेट निकोबार क्षेत्र को एक भंडार के रूप में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया। परिषद ने गौर किया कि प्रस्तावित जीवमंडल भंडार में उत्तर अंडमान से बाहर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक विस्तृत समीपस्थ वन्य क्षेत्र हैं और महसूस किया कि इसका जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए नामांकन किए जाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। परिषद ने भारतीय प्राधिकारियों को अपना नामांकन पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने प्रस्ताव में समुद्री और तटीय क्षेत्रों को भी शामिल करने के लिए कहा। नोरक्रेक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (मेघालय), सिमलीपाल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (ओडिसा) और पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (मध्यप्रदेश) को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया। भारत स्थित जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में नामांकित 15 स्थलों में से सात जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को अब जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है।

विधि और संधि प्रभाग

विधि और संधि प्रभाग के वर्ष, 2010 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप रहेः

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समाप्त करने के लिए उपायः वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीति के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रों से आग्रह किया कि जहां उचित हो आतंकवाद से संबंधित तथ्यों पर आधारित सूचनाओं के आदान-प्रदान में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि त्रुटिपूर्ण या अपुष्ट सूचनाओं का संचार न होने पाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रों से आगे आग्रह किया कि अपने भूक्षेत्र में रहने वाले ऐसे राष्ट्रिकों या व्यक्तियों का पूर्ण अभियोजन सुनिश्चित करें जो किन्हीं या सभी आतंकी गतिविधियां को वित्तपोषित या वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। जहां तक आतंकवाद पर तदर्थ समिति की बैठक का संबंध है, यह निर्णय लिया गया कि तदर्थ समिति की बैठक अप्रैल 2011 में आयोजित की जाएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी और वैश्विक आतंकवाद की व्यापक और समन्वित ढंग से हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय खंड की बैठक आयोजित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

इस वर्ष के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक (सीसीआईटी) के संबंध में की गई प्रगति पर 65वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों के विधिक सलाहकारों की अनौपचारिक बैठक में भी चर्चा की गई।

विधिक सलाहकारों की वार्षिक अनौपचारिक बैठक की भारत ने अध्यक्षता की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित मामलों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय के समीक्षा सम्मेलन के निष्कर्षों; विधिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के संधि खंड के कार्य-व्यापार और प्रक्रियाएं, और 15 अक्तूबर, 1999 के संकल्प 1267 (1999) के अनुसरण में स्थापित 'अलकायदा और तालिबान प्रतिबंध' से संबंधित सुरक्षा परिषद समितियों के कार्यों, खासतौर पर व्यक्तियों और संगठनों को सूची में शामिल करने और सूची से निकालने की प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। बैठक के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की अनिवार्य अधिकारिता बढ़ाने के संबंध में एक विशेष संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के विधिक सलाहकारों और अन्य विशेषज्ञों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने हिस्सा लिया था।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विशेष समितिः संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर और संगठन की भूमिका के सुदृढ़िकरण पर विशेष समिति विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जो निम्नलिखित से संबंधित हैं- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना; अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित कार्यों में लगी अन्य समितियों/निकायों के साथ खासतौर पर प्रतिबंधों से प्रतिकूलतः प्रभावित हुए बिना तृतीय राष्ट्रों को सहायता दिए जाने के संबंध में समन्वयन करना। विधि और संधि प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत मुद्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की। महासभा ने अपने कार्यों पर विशेष समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (ए/65/33) पर विचार करने के बाद संकल्प 65/31 अंगीकार किया। महासभा ने विशेष समिति से आग्रह किया है कि प्रतिबंध लागू किए जाने पर प्रभावित हुए तृतीय राष्ट्रों को सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत विषय पर प्राथमिकता से विचार किया जाना जारी रखा जाए और साथ ही भविष्य में कार्यान्वयन के लिए व्यापक तौर पर स्वीकार्य उपायों की पहचान करने के अपने कार्य तरीके में भी सुधार किया जाए। राष्ट्रों से कहा गया है कि वे सुरक्षा परिषद के कार्य व्यवहार सूचीपटल को अद्यतन करने और संयुक्त राष्ट्र के अंगों में कार्य व्यवहार संबंधी समूह कार्यों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए न्यास निधि में स्वैच्छिक योगदान करें। विगत वर्षों के दौरान भारत का दृष्टिकोण यह रहा है कि सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णयों के हिस्से के रूप में प्रतिबंध से प्रभावित हुए तृतीय राष्ट्रों की ओर प्रमुख जिम्मेदारी ग्रहण करें। भारत सुरक्षा परिषद के कार्य व्यवहार सूचीपटल और संयुक्त राष्ट्र के कार्यव्यवहार संबंधी संग्रह अंगों को अद्यतन/प्रकाशित किए जाने से संबंधित सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है।

महासागर और समुद्र के कानूनः संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 65वें सत्र में दो संकल्प, 65/37 और 65/38 अंगीकार किए जो 'महासागर और समुद्र के कानून' एवं विस्तृत मत्स्य भंडार और अत्यधिक भ्रमणशील मत्स्य भंडार के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित 10 दिसम्बर, 1982 के समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और संबंधित लिखतों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 1995 करार सहित 'दीर्घकालिक मात्स्यिकी' की कार्यसूची मदों से संबंधित थे। यह प्रभाग इन संकल्पों को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान उत्पन्न हुए विभिन्न विधिक मुद्दों पर सलाह प्रदान करने में सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है।

भारत ने मई 2009 में समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 के प्रावधानों के तहत विस्तारित महाद्वीपीय समुद्रतट के संबंध में अपना पहला आंशिक दावा महाद्वीपीय समुद्रतट की सीमा संबंधी आयोग (सीएलसीएस) के समक्ष प्रस्तुत किया। अगस्त 2009 में भारत ने सीएलसीएस के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण की, जिसमें इसने अपने अनुरोध का परिचय कराया और उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से व्याख्या की, और साथ ही अपने अनुरोध के संबंध में वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने एवं उनका विश्लेषण करने में प्रयुक्त तरीकों और उपकरणों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की।

समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के राष्ट्र पक्षकारों की 20वीं बैठक न्यूयॉर्क में 14-18 जून, 2010 तक आयोजित की गई। भारत इस अभिसमय का एक राष्ट्र पक्षकार है और इसने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में प्रशासनिक और बजटीय मामलों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आरएसए) की रिपोर्ट और सीएलसीएस से संबंधित मामलों एवं आयोग पर कार्य के दबाव सहित समुद्र के कानून संबंधी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) के कार्य संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

विधि और संधि प्रभाग ने न्यूयॉर्क में 30 अगस्त-3 सितम्बर 2010 तक आयोजित 'सामाजिक आर्थिक पहलुओं सहित समुद्री पर्यावरण के संबंध में वैश्विक रिपोर्टिंग और राष्ट्र के मूल्यांकन हेतु नियमित प्रक्रिया' के कार्यान्वयन हेतु तौर-तरीके निर्धारित करने संबंधी तदर्थ कार्यसमूह की बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नियमित प्रक्रिया के प्रथम चक्र के उद्देश्य और विस्तार को केंद्र पर रखा गया ताकि लक्ष्य श्रोताओं के लिए उनके उपयोग और महत्व को सुनिश्चित किया जा सके।

एएएलसीओ

प्रभाग ने जुलाई 2010 में दारएस सलाम, तंजानिया में आयोजित एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन (एएएलसीओ) के वार्षिक सत्र में हिस्सा लिया। एएएलसीओ अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के बीच सहयोग और परामर्श को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया निकाय है। प्रभाग ने एएएलसीओ द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया, जिनमें निम्नलिखित विषयों पर आयोजित बैठकें/सम्मेलन भी थेः - '21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय कानून की चुनौतियों; 'मानव तस्करी रोकने के संबंध में कार्यशाला', 'उत्प्रवासियों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय (आईसीसी) के कानून की समीक्षा के संबंध में सम्मेलन। प्रभाग ने सदस्य राष्ट्रों से आए सहभागियों के लिए एएएलसीओ द्वारा

आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए रिसॉर्स व्यक्तियों की व्यवस्था की।

अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय (आईसीसी)

विधि और संधि प्रभाग ने 31 मई-11 जून 2010 तक कम्पाला, उगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय के रोम संविधि के समीक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया।

समीक्षा सम्मेलन में मुख्यतः 'आक्रमण के अपराध' की परिभाषा, आक्रमण के अपराध पर विचार के लिए न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की शर्तें और परिभाषा को अंगीकार करने वाले रोम कानून के संशोधनों को प्रभावी करने की प्रक्रिया को केंद्र बनाया गया। सम्मेलन में न्यायालय, शांति और न्याय, और पीड़ित एवं प्रभावित हुए समुदायों पर रोक कानून का प्रभाव के बीच समन्वयन बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

समीक्षा सम्मेलन ने रोम संविधि में एक नए प्रावधान को शामिल करने पर विचार किया, जो विष अथवा विषैले हथियारों, विषैली अथवा अन्य गैसों के प्रयोग अथवा ऐसी बुलेटों के प्रयोग, जो मानव के शरीर में आसानी से फैल जाएं, को गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में युद्ध अपराध बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के दौरान ऐसे हथियारों के प्रयोग को रोम संविधि के अंतर्गत एक युद्ध अपराध पहले ही बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, समीक्षा सम्मेलन में यह भी सहमति हुई कि कुछ समय के लिए राष्ट्र पक्षकारों के अपने स्वयं के राष्ट्रिकों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के संबंध में सात वर्षों के लिए न्यायालय की अधिकारिता से छूट का विकल्प चुन सकने संबंधी प्रावधान पर विचार न किया जाए और इस प्रावधान की राष्ट्र पक्षकारों की सभा द्वारा 2015 में समीक्षा की जाएगी।

सोमालिया के समुद्री तट के पास समुद्री डकैती के संबंध में संपर्क समूह

इस प्रभाग ने सोमालिया के समुद्री तट के पास समुद्री डकैती के संबंध में संपर्क समूह के विधिक मुद्दों संबंधी कार्य समूह-II में हिस्सा लेना जारी रखा। इस कार्य समूह ने सोमालिया के समुद्री तट के पास समुद्री डकैतों से उत्पन्न विधिक चुनौतियों संबंधी सूचना के निरंतर आदान-प्रदान, संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन के लिए अतिरिक्त तंत्र स्थापित करने की संभावना की जांच, 'विधिक टूल बाक्स' विकसित करने जिसमें उन कदमों की जांच सूची हो, जिन्हें राष्ट्र यह सुनिश्चित करने के लिए उठा सकते हैं कि संदिग्ध समुद्री डकैतों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए उनके पास क्या-क्या बातें होनी चाहिए, बाधा सामग्रियों की सूची और अंतर्राष्ट्रीय न्याय निधि के विचारार्थ विषय जैसे सौंपे गए कार्य पूरे कर लिए हैं। कार्य समूह अभियोजन के अंतर्राष्ट्रीय विधिक आधारों का संकलन करने और साक्ष्य संबंधी मानकों पर व्यापक ढांचा विकसित करने, 'शिप राइडर' करारों, और संदिग्ध समुद्री डकैतों तथा सशस्त्र लुटेरों के हस्तान्तरण की शर्तों पर एक समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने के कार्य में भी संलग्न रहा। कार्य समूह समुद्री डकैती के अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों की जांच भी कर रहा है।

यूएनसीआईटीआरएएल

प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनी संबंधी आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल), उसके क्रमशः दिवाला कानून, सुरक्षा हितों और ऑनलाइन विवाद समाधान संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक वियना, आस्ट्रिया में 13-17 दिसम्बर, 2010 तक आयोजित की गई। कार्यसमूह को ई-कॉमर्स विवादों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र तैयार करने के परम्परागत तरीके समय लेने वाले और खर्चीले हैं, तथा ई-कामर्स सीमा पार विवादों को अनुकूल बनाया जाए, और शीघ्र एवं कम खर्चीले समाधान की व्यवस्था की जाए, जिसमें इतनी लागत, समय या बोझ न हो जो उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ की तुलना में अत्यधिक हो।

वित्तीय कार्रवाई कृत्यक बल (एफएटीएफ): सदस्यता के लिए भारत के आवेदन को अनुमोदित किया गया और भारत जून 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया।

विधि और संधि प्रभाग ने एफएटीएफ मूल्यांकन दल की बैठकों में हिस्सा लिया, जिसमें एफएटीएफ मानकों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन के संबंध में खासतौर से प्रत्यर्पण और आतंकियों की वित्तीय व्यवस्था और धन की तस्करी रोकने के लिए परस्पर विधिक सहायता के संबंध में हमारे विधिक और संस्थागत तंत्रों, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जांच की गई और उन पर चर्चा की गई।

पर्यावरण से संबंधित कानून

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित कई करारों, वन्यजीवन अनुसंधान संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों; समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ विकास तंत्र की जांच की।

प्रभाग ने कुआलालम्पुर, मलेशिया में 8-12 फरवरी, 2010 तक आयोजित जैव-सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोतोकॉल (अनुच्छेद 27) के संदर्भ में देयता ओर क्षतिपूर्ति संबंधित 'अध्यक्षों के मित्रों के समूह' की द्वितीय बैठक में हिस्सा लिया। कुआलालम्पुर, मलेशिया में 15-19 जून, 2010 तक आयोजित जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोतोकॉल के संदर्भ में देयता और क्षतिपूर्ति से संबंधित 'अध्यक्षों' के मित्रों के समूह' की तृतीय बैठक में भी हिस्सा लिया। जीवविज्ञानी विविधता संबंधी अभिसमय (सीबीडी) की सीओपी-10 के साथ जैव सुरक्षा पर कोर्टेजेना प्रोतोकॉल की सीओपी/एमओपी-5 का आयोजन 10-15 अक्तूबर, 2010 को नगोया में किया गया था। इस बैठक में जीवित संशोधित जीवों से उत्पन्न क्षति के लिए देयता और क्षतिपूर्ति संबंधी नागोया-कुआलालम्पुर प्रोतोकॉल को अंगीकार किया गया।

उत्पत्ति मूलक संसाधनों के उपयोग व लाभ को साझा करने के संबंध में विधि एवं संधि प्रभाग ने 20-28 मार्च, 2010 को काली, कोलम्बिया में आयोजित उपयोग व लाभ को साझा करने के संबंध में तदर्थ बहु-प्रयोज्य कार्यदल की 9वीं बैठक; 10-16 जुलाई, 2010 को मांट्रियल, कनाडा में उपयोग व लाभ को साझा करने के संबंध में तदर्थ बहु-प्रयोज्य कार्यदल की पुर्नआयोजित 9वीं बैठक सहित 17-21 सितंबर, 2010 को उपयोग व लाभ साझा करने के संबंध में अंतर-क्षेत्रीय वार्ता समूह की बैठक तथा 6-16 अक्तूबर, 2010 को नागोया, जापान में उपयोग व लाभ साझा करने के संबंध में 16 अक्तूबर, 2010 को आयोजित कार्यचालन समूह की एक दिवसीय बैठक में भाग लिया। सीओपी 10 से सीबीडी तक उत्पत्तिमूलक संसाधनों के उपयोग के संबंध में नागोया प्रोतोकोल पारित किया गया था।

प्रभाग ने 7-8 सितम्बर, 2010 तक हनोई, वियतनाम में आयोजित जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोतोकॉल संबंधी एशियाई क्षेत्रीय तैयारी कार्यशाला में प्रतिनिधित्व किया और 9-12 मार्च, 2010 तक ब्राजीलिया, ब्राजील में आयोजित एबीएस पर सुदृढ़ मानसिकता वाले अति-विविध देशों (एलएमएमसी) की विशेषज्ञ-सह-मंत्रिस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया।

प्रभाग ने देयता और क्षतिपूर्ति संबंधी सहअध्यक्षों के मित्रों के समूह की चौथी बैठक (6-8 अक्तूबर), जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोतोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी-एमओपी-5) की पांचवीं बैठक (11-15 अक्तूबर) में भी प्रतिनिधित्व किया।

अंटार्कटिका

पुंटा डेल एस्टे, उरुग्वे में 3-7 मई, 2010 तक आयोजित तैंतीसवीं अंटार्कटिका संधि परामर्शी समिति बैठक (एटीसीएम) की विधिक और संस्थागत समूह की बैठक में हिस्सा लिया।

तम्बाकू प्रोतोकॉल

14-21 मार्च, 2010 तक जेनेवा में आयोजित तम्बाकू उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रोतोकॉल संबंधी अंतर्सरकारी वार्ताकारी निकाय (आईएनबी-4) के चौथे सत्र में हिस्सा लिया।

जल संसाधन

विधि और संधि प्रभाग ने सिंधु जल संधि के अधीन स्थापित स्थाई सिंधु आयोग की बैठकों में हिस्सा लिया। प्रभाग सिंधु जल संधि के अधीन गठित माध्यस्थम न्यायालय के समक्ष भारत की स्थिति का समन्वयन और प्रस्तुतिकरण करने में भी सक्रियता से संलग्न है। सिंधु जल संधि भारत द्वारा निर्माण की जा रही किशनगंगा पनविद्युत परियोजना का आरेख के प्रति अपने उद्देश्यों के संबंध में पाकिस्तान द्वारा शुरु की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप की गई थी।

प्रभाग ने ब्रह्मपुत्र जल के उपयोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून के पहलुओं और चीन द्वारा एकतरफा ब्रह्मपुत्र जल की धारा मोड़ने के प्रयास से संबंधित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जिसे अंतिम रूप दिए जाने में संयुक्त सचिव (एलएंडटी) संयोजक रहे। प्रभाग ने आंध्र प्रदेश में निर्मित पन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में प्रथम प्रयोग के अधिकारों संबंधी आंतरिक कानूनी मुद्दों पर जानकारी भी प्रदान की।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

विधि और संधि प्रभाग ने 30 अगस्त-10 सितम्बर 2010 तक बीजिंग में आयोजित उड्डयन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन राजनयिक सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की। सम्मेलन में नागरिक उड्डयन के खिलाफ अविधिमान्य कार्यकलाप के दमन हेतु अभिसमय (मॉट्रियाल अभिसमय, 1971) और विमान की अविधिमान्य जब्ती को रोकने संबंधी अभिसमय (द हेग अभिसमय, 1970) में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की गई और उन्हें अंगीकार किया गया। प्रस्तावित संशोधन में, वास्तव में, आतंकवाद-निरोधी और प्रसार-निरोधी दोनों तरह के लक्ष्यों को बढ़ाने का विचार परिलक्षित होता है। प्रस्ताव है कि ऐसे विभिन्न कार्यों को शामिल किया जाए, जिन्हें राष्ट्रों को अपने घरेलू कानूनों के अंतर्गत दंडनीय बनाना होगा। इनमें नागरिक विमान का उपयोग हथियार के रूप में करना; नागरिक विमान का उपयोग अविधिमान्य ढंग से जैविक, रासायनिक ओर नाभिकीय सामग्रियों को बिखेरने के लिए करना; जैविक, रासायनिक और नाभिकीय सामग्रियों का उपयोग करके नागरिक उड्डयन पर हमला करना, इन कृत्यों को रोकने की धमकी देना; और ऐसे कार्यों में योगदान करने वाले कार्यों जैसे उकसाना, भागीदारी, संगठित करना, सुपुर्दगी आदि जैसे कार्य शामिल होंगे जो अभिसमय के अंतर्गत प्रतिषिद्ध होंगे और इस तरह दंडनीय अपराध होंगे।

प्रभाग ने विभिन्न बहुपक्षीय-द्विपक्षीय वार्ताओं में सक्रियता से भागीदारी की, जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न अभिसमयों और करारों को अंगीकार किया गया, जिनमें शामिल हैं- आईसीएओ राजनयिक सम्मेलन, जिसके परिणामस्वरूप बीजिंग अभिसमय और मांट्रियाल प्रोतोकॉल को सितम्बर 2010 में अंगीकार करके अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के साथ अविधिमान्य हस्तक्षेप रोका गया।

मुक्त व्यापार करार

मलेशिया और जापान के साथ मुक्त व्यापार करार के लिए वार्ता पूरी हो चुकी है और आसियान, व्यापार वार्ता समिति की बैठक के लिए वार्ता चल रही है।

द्विपक्षीय निवेश करार

चालू वर्ष के दौरान, लिथुआनिया, लातविया, सेशेल्स और जिम्बाब्वे के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करारों (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया गया। लातविया, सेशेल्स, जिम्बाब्वे और चेक गणराज्य के साथ बीआईपीपीए के संबंध में अनुसमर्थन के दस्तावेजों को दिल्ली में आदान-प्रदान किया गया

ताकि करार को प्रभावी किया जा सके। अमेरिका के साथ समन्वेषी वार्ता पूरी हो चुकी है। स्लोवेनिया और चेक गणराज्य के साथ बीआईपीपीए वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं और अंतिम प्रारूप पर दोनों पक्षों द्वारा आद्यक्षर किए जा चुके हैं। हांगकोंग, वेनेजुएला, अजरवैजान, तंजानिया, क्यूबा और क्रोएशिया के साथ वार्ता चल रही है।

मंत्रिमंडलीय टिप्पणियाँ

विधि और संधि प्रभाग ने विभिन्न प्रारुप मंत्रिमंडलीय टिप्पणियों की जांच की और उनके संबंध में अपनी सहमति प्रदान की, जिनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं- बंकर तैल प्रदूषण क्षति के लिए सिविल देयता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 2001 (बंकर अभिसमय) के लिए सहमति; समुद्री जहाज पूरक भार जल और तलछट के नियंत्रण और प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (बीडब्ल्यूएम अभिसमय) 2004 के लिए सहमति; संकटमय और अनिष्टकारी सामग्रियों से उत्पन्न प्रदूषण की दुर्घटनाओं के लिए मोर्चाबंदी, प्रतिक्रिया और सहयोग संबंधी प्रोतोकॉल (एचएनएस प्रोतोकॉल) 2000 के लिए सहमति, समुद्रवर्ती दावों के लिए देयता की सीमा संबंधी अभिसमय (एलएलएमसी), 1976 के लिए 1996 के प्रोतोकॉल के लिए सहमति; समुद्री जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम संबंधी अभिसमय 1973/78 (एमएआरपीओएल 73/78) में अनुबंध (वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विनियम) जोड़ने हेतु 1997 प्रोतोकॉल के लिए सहमति; समुद्री जहाजों की सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से ग्राह्य रिसाइकिलिंग हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (हाँगकाँग अभिसमय, 2009) पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन; स्वच्छ विकास तंत्र करार; भारतीय वन अधिनियम, 1927 का संशोधन; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संशोधन; और प्रारूप बीज विधेयक, 2004। इसके अतिरिक्त चेक गणराज्य, ईरान इस्लामिक गणराज्य और नेपाल के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करारों (बीआईपीए) से संबंधित प्रारूप मंत्रिमंडलीय टिप्पणियों की जांच की गई और उन पर सहमति प्रदान की गई।

सामाजिक सुरक्षा करार

प्रभाग ने आस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडेन और पुर्तगाल जैसे विभिन्न देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों की वार्ता में सक्रिय भागीदारी की। इसने नीदरलैंड के साथ श्रमिक आवाजाही करार पर वार्ता में भी हिस्सेदारी की।

नालन्दा विश्वविद्यालय

विधिक और संधि प्रभाग ने नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने और उसे संसद में पुरःस्थापित किए जाने में भागीदारी की। प्रभाग ने भारत और नालन्दा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले मसौदा मुख्यालय करार पर भी अपनी सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विधेयक की संसद में पुरःस्थापित किया गया। चालू वर्ष के दौरान विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया और भारत के राष्ट्रपति की सहमति से नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 प्रभाव में आया। प्रभाग ने राजपत्र अधिसूचना जारी कराने में भी भागीदारी कीः पहले नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को प्रभावी करने में और दूसरे, नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख नियत करने में।

प्रत्यर्पण और अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहायता

विधि और संधि प्रभाग ने विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां, आपराधिक और सिविल मामलों में परस्पर विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में करार किए जाने संबंधी विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं में सहयोग प्रदान किया। इन सफल वार्ताओं के परिणामस्वरूप अजरबजान और इंडोनेशिया के साथ मिलकर प्रत्यर्पण संधियों के मूल पाठ को अंतिम रूप दिया गया। आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि पर अजरबजान, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ वार्ता की गई। इसके परिणामस्वरूप इंडोनेशिया और अजरबजान के साथ संधियों को अंतिम रूप दिया गया। सजा पाए व्यक्तियों के हस्तांतरण पर संधियां करने के लिए श्रीलंका और इटली के साथ भी वार्ताएं की गईं। दोनों संधियों के मूलपाठ को अंतिम रूप दिया गया। प्रभाग ने घरेलू और साथ ही विदेशी अधिकारिताओं से प्राप्त प्रत्यर्पण अनुरोधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अन्य अनुरोधों की भी जांच की और विधिक सलाह प्रदान की। प्रभाग ने लियान, फ्रांस और कैसाब्लांका, मोरोक्को में, क्रमशः 10-11 मई, 2010 और 22-24 सितम्बर, 2010 तक आयोजित खतरा नोटिस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ाने संबंधी कार्य समूह की बैठकों में हिस्सा लिया।

विविक्षा

प्रभाग द्वारा अनेक रक्षा सहयोग करारों, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी करारों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी करारों की वर्ष के दौरान विधिक्षा की गई। इनमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संबंधी करार, राष्ट्रपारीय संगठित अपराध और स्वापक द्रव्यों की तस्करी/नशीले पदार्थों की तस्करी; जल-विज्ञान आंकड़ों को साझा करने; गैस और ऊर्जा करार; जलवायु परिवर्तन संबंधी द्विपक्षीय करार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बाघ संरक्षण पर सेंट पीटसबर्ग घोषणा, पशु कल्याण पहलों पर सार्वभौमिक घोषणा, 2005, सुंदरवन का संरक्षण; लाभदायक रोजगार करार; जल सर्वेक्षण पर करार; सीमा शुल्क सहयोग करार, कार्बन ट्रेडिंग आदि शामिल हैं।

भारत ने वर्ष के दौरान विदेशों के साथ कई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों/करारों पर हस्ताक्षर किए तथा उनका अनुसमर्थन किया। विस्तृत सूची परिशिष्ट-। पर संलग्न है। वर्ष 2010 के दौरान जारी पूर्ण शक्तियों के दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-II पर है और वर्ष के दौरान जिन दस्तावेजों के अनुसमर्थ के संबंध में कार्रवाई की गई उनकी सूची परिशिष्ट-III। पर संलग्न है।

■■

10 निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामले

संयुक्त राष्ट्र महासभा

भारत ने वैश्विक, निष्पक्ष तथा सत्यापनीनय परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए अपना समर्थन जारी रखा। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 29 सितंबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में एक वक्तव्य में निर्धारित समय-सीमा में सार्वभौमिक एवं निष्पक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की बाध्यकारी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह एक ऐसा लक्ष्य है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1998 में महासभा में जोरदार वक्तव्य दिया था। उन्होंने सदस्य राज्यों तथा गैर-सरकारी समुदायों के बीच विचार-विमर्श और वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान भी किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य को सशक्त बनाया जा सके, जिसे परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई में बदला जा सकता है। उन्होंने नए खतरों की उत्पत्ति का उल्लेख भी किया, जिसमें आंतकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने का खतरा भी शामिल है।

महासभा की प्रथम समिति के सत्र के दौरान भारत ने वैश्विक व निष्पक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्राथमिकता को दोहराया। भारत ने यह कहा कि वैश्विक व निष्पक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक प्रतिबद्धता द्वारा प्रबलित चरणबद्ध प्रक्रिया तथा सहमति से निर्धारित बहुपक्षीय अवसंरचना की आवश्यकता है। भारत ने निरस्त्रीकरण व अप्रसार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य को सशक्त बनाने के लिए वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने का समर्थन किया।

भारत ने कहा कि 2006 में प्रस्तुत इस कार्यान्वयन दस्तावेज में राजीव गांधी कार्ययोजना, 1988 की भावना व विषयवस्तु शामिल है। परमाणु अस्त्रों के सम्पूर्ण उन्मूलन, सुरक्षा सिद्धांतों में परमाणु हथियारों के महत्व में कमी तथा परमाणु खतरे को कम करने के उपाय सहित ये प्रस्ताव प्रासंगिक बने रहे, जिनमें परमाणु हथियारों की पूर्व सूचना, परमाणु सम्पन्न राज्यों द्वारा 'परमाणु हथियारों का प्रथम उपयोग न करने' से संबंधित वचनबद्धता पर वार्ता, परमाणु अस्त्रों के उपयोग पर रोक लगाने से संबंधित अभिसमय पर वार्ता तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर परमाणु अस्त्रों के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए परमाणु अस्त्र अभिसमय पर वार्ता शामिल है।

हाल के वर्षों में भारत ने प्रथम समिति में तीन संकल्प प्रस्तुत किए। आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने के उपायों से संबंधित भारत के संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस संकल्प को दिए गए महत्व को दर्शाता है। यह संकल्प सर्वप्रथम 2002 में प्रस्तुत किया गया था। इस संकल्प में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से यह आह्वान किया गया था कि वे आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार तथा उनके प्रमोचन के साधन प्राप्त करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का अपना समर्थन दे। सदस्य देशों को इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सशक्त बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संवर्धित करने के लिए भी कहा गया था। इस वर्ष 74 देशों ने इस संकल्प को सह-प्रायोजित किया।

परमाणु हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने के अभिसमय से संबंधित भारत के संकल्प में किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के प्रयोग अथवा खतरे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर करार सम्पन्न करने के लिए वार्ता शुरू करने के लिए निरस्त्रीकरण सम्मेलन को किए गए अनुरोध को दोहराया गया है।

'परमाणु खतरे को कम करने' से संबंधित संकल्प में परमाणु हथियारों की तैनाती हटाने तथा परमाणु हथियारों को चौकसी की स्थिति से हटाने सहित परमाणु हथियारों के गैर-इरादतन व दुर्घटनावश प्रयोग के जोखिम को कम करने के लिए तात्कालिक उपायों तथा परमाणु सिद्धांतो की समीक्षा करने का भी आह्वान किया गया था। सदस्य राज्यों से यह आह्वान भी किया गया था कि वे परमाणु हथियारों के सभी पहलुओं का प्रसार रोकने तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन के उद्देश्य से परमाणु निरस्त्रीरकण को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक उपाय करें।

प्रथम समिति व महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका के संबंध में भारत द्वारा प्रस्तावित निर्णय के मसौदे को बिना मतदान के पारित कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग के सत्र 2010 की बैठक 29 मार्च-16 अप्रैल 2010 को न्यूयार्क में आयोजित की गई। आयोग ने परमाणु निरस्त्रीकरण व परमाणु हथियारों के अप्रसार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिफारिशों तथा चौथे निरस्त्रीकरण दशक के रूप में 2010 की मसौदा घोषणा के कारकों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। भारत ने आयोग के विचार-विमर्श में भाग लिया तथा इसके परिप्रेक्ष्य में आदान-प्रदान किया।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन

निरस्त्रीकरण सम्मेलन एक एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि विमर्शक निकाय है। वर्ष 2010 में सम्मेलन ने अपनी कार्यसूची मदों, कार्यों के कार्यक्रम, आयोजनों व प्रक्रियाओं तथा साथ ही अन्य मामलों पर 35 औपचारिक, 34 अनौपचारिक पूर्ण बैठकें कीं। तथापि, निरस्त्रीकरण सम्मेलन 2010 के सत्र के लिए अपने कार्यक्रम को पारित नहीं कर सका। भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में वार्ता तथा अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरा करने वाले बहुपक्षीय, निष्पक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से सत्यापनीय एफएमसीटी का समर्थन किया। इस संबंध में भारत की स्थिति इसके द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए बिना पूर्वाग्रह के दी गई उच्च प्राथमिकता है।

निरस्त्रीकरण पर उच्चस्तरीय समिति

विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के कार्य को पुर्नप्रबलित करने तथा बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा 24 सितंबर, 2010 को न्यूयार्क में संयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात पर निराशा व्यक्त की कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन को बहुपक्षीय संधियों पर वार्ता करने के उसके प्रमुख कार्य से रोका गया था। उन्होंने 2011 के प्रारंभ में अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एफएमसीटी वार्ता तत्काल शुरू करने के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया।

परमाणु सुरक्षा सम्मेलन

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से 13 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। 47 देशों तथा 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में परमाणु सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा परमाणु आतंकवाद के खतरे से निपटने के उद्देश्य से एक विज्ञप्ति तथा कार्ययोजना पारित की गई। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि परमाणु सुरक्षा आज एक सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने यह कहा कि परमाणु सामग्रियों की अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों व समूहों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि भारत आईएईए तथा इच्छुक विदेशी सहभागियों की अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के आधार पर परमाणु ऊर्जा सहभागिता के लिए वैश्विक केन्द्र स्थापित करेगा। इस केन्द्र में आधुनिक परमाणु ऊर्जा प्रणाली अध्ययन, परमाणु सुरक्षा, रेडिएशन सुरक्षा तथा स्वास्थ्य देखरेख, कृषि व खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रेडियोआइसोटोप्स तथा रेडिएशन प्रौद्योगिकी प्रयुक्त करने से संबंधित 4 अध्ययन केन्द्र शामिल होंगे।

पारम्परिक हथियार/कतिपय पारम्परिक हथियारों पर अभिसमय (सीसीडब्ल्यू)

भारत सशस्त्र संघर्ष कानून व अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों में मुख्य अभिसमय के रूप में सीसीडब्ल्यू के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने सीसीडब्ल्यू के सभी पांचों प्रोतोकोलों का अनुसमर्थन किया है और इसने प्रोतोकोल के प्रारूप पर वार्ताओं मे सक्रिय भागीदारी की है जिसमें मानवीय और सुरक्षा विचारों में संतुलन स्थापित किया गया है। वर्ष के दौरन युद्ध सामग्री कलस्टर पर प्रोतोकाल पर वार्ता करने के लिए जेनेवा में सरकारी विशेषज्ञ समूह (जीजीई) की 2 औपचारिक बैठकें आयोजित की गई थी।

नवंबर में आयोजित उच्च संविदाकारी पक्षों की बैठक में जीजीई के अधिदेश को 2011 तक बढ़ा दिया गया था। भारत ने युद्ध सामग्री क्लस्टर पर प्रोतोकाल के मसौदे पर विचार-विमर्श करने के लिए जीजीई द्वारा की गई प्रगति का स्वागत किया है।

भारत ने 24 नवंबर, 2010 को जेनेवा में आयोजित सीसीडब्लयू के संशोधित प्रोतोकाल II (बारुदी सुरंगो, शिकंजो तथा अन्य उपकरणों पर एपी II) के उच्च संविदाकारी पक्षों के 12वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष के दौरान बैठक के महत्वपूर्ण मामलों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) एपी-II का सार्वभौमिक, सीसीडब्लयू को प्रोतोकाल II के समाप्त करने की संभावना तथा पीड़ित सहायता के मामले शामिल है। भारत ने एपी II में शामिल अवधारणा का समर्थन किया तथा कार्मिक-रोधी बारुदी सुरंगों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। भारत ने 29 नवंबर-3 दिसंबर 2010 के दौरान जेनेवा में आयोजित कार्मिक-रोधी बारुदी सुरंगों संबंधी अभिसमय (ओटावा अभिसमय) में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

सीसीडब्ल्यू के प्रोतोकाल v (युद्ध के विस्फोटक अवशेष) के उच्च संविदाकारी पक्षों का चौथा वार्षिक सम्मेलन 22-23 नवंबर, 2010 को जेनेवा में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्रोतोकाल के सार्वभौमिकरण, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, जेनरिक निरोधात्मक उपायों, पीड़ित सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सहायता जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इससे पहले सीसीडब्ल्यू के प्रोतोकाल v के तीसरे सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में राजदूत हमीद अली राव, निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि, ने संयुक्त राष्ट्र सामान्य सत्र में यह रिपोर्ट दी थी कि प्रोतोकाल के उच्च संविदाकारी पक्षों की संख्या 2009 के 61 से बढ़कर 2010 में 69 हो गई थी।

शस्त्र व्यापार संधि

भारत ने जुलाई 2010 में न्यूयार्क में आयोजित अस्त्र व्यापार संधि पर 2012 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए प्रारम्भिक समिति की प्रथम बैठक में भाग लिया। भारत ने यह कहा कि अस्त्र व्यापार संधि के लिए चरणबद्ध, तथ्यात्मक, पारदर्शी तथा मतैक्य युक्त अवधारणा से सार्वभौमिक स्वीकार्य दस्तावेज की संभावना में वृद्धि होगी।

लघु अस्त्र व हल्के हथियार

भारत ने लघु अस्त्रों तथा हल्के हथियारों (एसएएलडब्ल्यू) के अवैध व्यापार के संबंध में 14-18 जून, 2010 को न्यूयार्क में

आयोजित संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राज्यों की चौथी द्विवार्षिक बैठक (बीएमएस-4) में भाग लिया। भारत ने लघु अस्त्रों व हल्के हथियारों के उत्पादन पर कड़े राष्ट्रीय नियंत्रण, उचित पहचान चिह्न, अवैध हथियारों का पता लगाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भंडारों के प्रभावशाली प्रबंधन, निर्यात नियंत्रण तथा उन्हें कड़ाई से लागू करने के संबंध में सदस्य राज्यों के वर्तमान दायित्वों, विशेष रूप से यूएनसीओए से उत्पन्न दायित्वों के पूर्ण व प्रभावशाली कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देना जारी रखा।

जैविक हथियारों पर अभिसमय

भारत सामूहिक विनाश के हर प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रथम बहुपक्षीय, निष्पक्ष संधि के रूप में जैविक हथियार अभिसमय (बीडब्ल्यूसी) को अत्यधिक महत्व देता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः अगस्त 2010 तथा दिसंबर 2010 में आयोजित बीडब्ल्यूसी विशेषज्ञ बैठक तथा पक्षकार राज्यों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस वर्ष की बैठक रोग निगरानी, जांच व निदान और लोक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं में सुधार सहित जैविक अथवा जहरीले हथियारों के कथित प्रयोग के मामले में किसी पक्षकार राज्य के अनुरोध पर संबद्ध संगठनों के साथ सहायता व समन्वय के प्रावधान पर सामान्य समझ व प्रभावशाली कार्रवाई के संवर्धन व चर्चा पर केन्द्रित थी। भारत 2011 में जेनेवा में आयोजित 7वें समीक्षा सम्मेलन में बीडब्ल्यूसी के कार्यान्वयन को सशक्त बनाने पर विचार करेगा।

रासायनिक हथियार अभिसमय

भारत ने हेग में रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा रासायनिक हथियार अभिसमय के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। भारत को ओसीसीडब्ल्यू के कार्यपालक परिषद के सदस्य के रूप में अन्य 2 वर्षों के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है, जिसमें इसने अप्रैल 1997 से अभिसमय लागू होने के पश्चात सतत रूप से प्रतिनिधित्व किया है।

भारत ने 29 नवंबर-3 दिसंबर 2010 तक हेग में आयोजित सीडब्ल्यूसी के पक्षकार राज्यों के 15वें सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने इस वर्ष के दौरान आयोजित ओसीसीडब्ल्यू की कार्यपालक परिषद के 60वे, 61वें व 62वें सत्र में भी भाग लिया। परिषद व सम्मेलन के विचार-विमर्श के दौरान भारत ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने में प्रगति, उद्योग सत्यापन, सहायता व सुरक्षा उपाय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम सहित रासायनिक हथियार अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपना परिदृश्य प्रस्तुत किया। भारत ने वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड, गोपनीयता आयोग तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों पर परामर्शी निकायों सहित संगठन के कई सहायक निकायों के सदस्य के रूप में भी योगदान दिया। भारत ने ओसीसीडब्ल्यू के अंतर्गत आयोजित विशेष आयोजनों अथवा कार्यक्रमों, विशेष रूप से रासायनिक हथियार नष्ट करने से संबंधित सुविधाओं की यात्राओं, अक्तूबर 2010 में हनोई में आयोजित सहायता व सुरक्षा पर एसिसटेक्स प्रयासों, रासायनों के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर सीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद XI पर कार्यशाला में भाग लिया तथा ओसीसीडब्ल्यू के एसोसिएट कार्यक्रम की मेजबानी भी की।

ओपीसीडब्ल्यू के महानिदेशक श्री अहमत अजोमकू ने 13-14 जनवरी, 2011 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान रासायनिक हथियार अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

आईएईए

भारत ने 20-24 सितंबर, 2010 को वियना में आयोजित आईएईए के वार्षिक आम सम्मेलन में भाग लिया। आम सम्मेलन में परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षोपायों, परमाणु ऊर्जा विषय पर कई संकल्प पारित किए। आम सम्मेलन के अवसर पर 23 सितंबर, 2010 को 'परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग' पर अर्जेंटीना के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार कैंसर थेरेपी के लिए आईएईए कार्यक्रम के अंतर्गत 2 रेडियोथेरेपी मशीनें (भाभाट्रान) भी दान करेगा, जिसमें से एक मशीन श्रीलंका व दूसरी मशीन नामीबिया को दान की जाएगी। भारत ने परमाणु विनाश पर पूरक प्रतिपूर्ति पर 27 अक्तूबर, 2010 को वियना में आयोजित अभिसयम पर भी हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक, श्री युकिया अमानो ने 16-19 जनवरी, 2011 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति

आईएसटीआरएसी (इसरो) के निदेशक शिव कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9-18 जून, 2010 को वियना में आयोजित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति के 53वें सत्र में भाग लिया। इस बैठक में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग से संबंधित कई मुद्दों, जैसे कि अंतरिक्ष से मलवा हटाने पर चर्चा की गई।

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)

आसियान क्षेत्रीय मंच एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजनैतिक सुरक्षा मामलों पर वार्ता, सहयोग व विश्वास निर्माण के लिए एक प्रमुख मंच है। अंतर्राष्ट्रीय अवधि, 2009-2010 के दौरान भारत व वियतनाम ने विश्वास निर्माण उपायों तथा उपचारात्मक राजनय पर एआरएफ अंतर-सत्रीय समर्थन समूह (एआरएफ-आईएसजी ऑन सीबीएमएस एण्ड पीडी) की सह अध्यक्षता की।

वाशिंगटन में 11 अप्रैल, 2010 को ब्लेयर हाउस में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और अमरीकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा की मुलाकात।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 13 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ।

विदेश राज्य मत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने 23 जुलाई, 2010 को हनोई में आयोजित एआरएफ की 7वीं मंत्रालयी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में उभरती क्षेत्रीय संरचना में एआरएफ के महत्व की पुनःपुष्टि की गई तथ एआरएफ प्रक्रिया में प्रेरक बल के रूप में आसियान की भूमिका का समर्थन किया गया। एआरएस लक्ष्य वक्तव्य, 2010 के कार्यान्वयन के लिए 'हनोई कार्ययोजना' पारित करना इस बैठक की मुख्य विशेषता रही है। एआरएफ की मंत्रालयी बैठक, 2009 में लक्ष्य विवरण पारित किया गया था। इस बैठक के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में मैत्री व सहयोग संधि संशोधित करने के लिए तीसरे प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की ओर से श्रीमती प्रनीत कौर ने इस प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने मलक्का तथा सिंगापुर जलमडरुमध्यों में नौवहन सुरक्षा तथा समुद्री पर्यावरण सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अधिकार क्षेत्र में बहुपक्षीय परियोजनाओं में भाग लिया तथा योगदान दिया।

एडीएमएम प्लस बैठक

रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटोनी ने 12-13 अक्तूबर, 2010 को हनोई में आयोजित आसियान + 8 रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम प्लस) प्रथम बैठक में भाग लिया। यह आसियान रक्षा मंत्रियों की वर्तमान वार्षिक संरचना में विस्तार का प्रतीक है, जिसे 2006 में 8 वार्ता सहभागियों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैण्ड, कोरिया गणराज्य, रूस तथा अमरीका को शामिल करने के लिए गठित किया गया था। इस बैठक में प्रभावशाली, कारगर, मुक्त तथा समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के मुख्य संघटक के रूप में एडीएमएमप्लस स्थापित करने के महत्व को मान्यता देने से संबंधित संयुक्त घोषणा पारित की गई थी, जिससे एडीएमएम साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए 8 'प्लस' देशों के साथ सहयोग कर सकेगा। इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वार्ता तथा विचार-विनिमय करने के लिए यह नई संरचना इस समूह के भीतर सभी देशों में भरोसे व विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तथा खुले व पारदर्शी सुरक्षा संरचना के निर्माण में सार्थक योगदान दे सकता है।

एशिया (सीआईसीए) में आदान-प्रदान तथा विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 जून, 2010 को इस्तानबुल, तुर्की में आयोजित आदान-प्रदान तथा विश्वास निर्माण उपायों पर तीसरे शीर्ष सम्मेलन में भाग लिया। सीआईसीए के 20 वर्तमान सदस्य देशों के नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वियतनाम और इराक सीआईसीए के नए सदस्यों के रूप में शामिल हुए, जबकि बांग्लादेश एक पर्यवेक्षक बन गया। तुर्की ने 2 वर्षों की अवधि के लिए कजाकिस्तान के स्थान पर सीआईसीए की अध्यक्षता ग्रहण की, जोकि इसके प्रारम्भ से ही सीआईसीए का अध्यक्ष था। सीआईसीए की तीसरी शीर्ष घोषणा में सामान्य रूप में विश्व समुदाय और विशेष रूप से एशिया के सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में सीआईसीए द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई। सदस्य राज्यों ने वार्ता के लिए तथा आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए मंच के रूप में सीआईसीए का विकास जारी रखने के लिए अपनी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि की। सदस्य राज्यों ने आतंकवाद की निंदा की तथा इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में की।

भारत ने 4-6 अक्तूबर, 2010 को अंकारा में आयोजित सीआईसीए के विशेष कार्य समूह व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया, जिसमें सदस्य राज्यों के बीच विश्वास निर्माण उपायों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। बहरीन सीआईसीए के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जबकि फिलीपींस पर्यवेक्षक बन गया।

अन्य मुद्दे

विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव तथा अमरीका के अस्त्र नियंत्रण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपमंत्री सुश्री एने तोशर के नेतृत्व में भारत-अमरीका सामरिक सुरक्षा वार्ता 17 सितंबर, 2010 को वाशिंगटन में आयोजित की गई। इस वार्ता में निरस्त्रीकरण व अप्रसार तथा भारत को उच्च प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए अमरीकी विनियमों को आसान बनाने के क्षेत्र में बहुपक्षीय घटनाक्रम तथा साझा हितों के विविध वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दे शामिल थे।

■■

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

11

इब्सा (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका)

इब्सा की परिकल्पना वर्ष 2003 में साझे मूल्यों एवं समान आकांक्षाओं वाले तीन महाद्वीपों के तीन सबसे बड़े लोकतांत्रिक और विकासशील देशों के बीच वार्ता मंच के रूप में की गई थी। यह तीनों देश और उनके लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा प्रदान करने के लिए एक संस्था के रूप में उभरा है। इब्सा की रूपरेखा के अन्तर्गत सहयोग के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर केन्द्रित होते हुए 16 क्षेत्रीय कार्यदल हैं। इब्सा न्यास कोष अन्य विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग का एक नूतन विचार है।

चतुर्थ इब्सा शिखर सम्मेलन ब्रासीलिया में 15 अप्रैल, 2010 को आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे। इब्सा के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधार, वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट और आतंकवाद सहित कई विषयों पर चर्चा की। नेताओं ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रतिनिधिक एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसमें तत्काल सुधार की मांग की। नेताओं ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गंभीर खतरा माना। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भारत में हुए आतंकी हमलों की निन्दा की और भारत के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की।

ब्रासीलिया घोषणा पत्र के अलावा, चतुर्थ इब्सा शिखर सम्मेलन में सामाजिक विकास रणनीति और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में कृषि सहयोग का भविष्य नामक दो दस्तावेज पारित किये गए। इस शिखर सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी दो समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये गए।

विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्त समय में न्यूयार्क में सितंबर 2010 में आयोजित इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन)

ब्रिक में चार प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश आते हैं, जो कि एक साथ विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.9 प्रतिशत तथा विश्व की जनसंख्या का 40 प्रतिशत और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) का लगभग 22 प्रतिशत है।

ब्रिक नेताओं की द्वितीय शिखर बैठक 15 अप्रैल, 2010 को ब्रासीलिया में आयोजित इब्सा शिखर सम्मेलन के पश्चात आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री ने किया। यह शिखर बैठक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का उसकी प्रबंधकीय संरचना सहित सुधार, जी-20 के अन्दर सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुधार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे सहित व्यापक मुद्दों पर केन्द्रित थी। इस शिखर बैठक के पश्चात संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। शिखर बैठक में ब्रिक के विकास बैंकों के बीच सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

शिखर बैठक के पूर्व सुरक्षा संबंधी ब्रिक उच्च प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा किया गया। द्वितीय ब्रिक शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में आयोजित अन्य कार्यक्रमों/ बैठकों में ब्रिक विकास बैंक बैठक (एम्जिम बैंक ने भाग लिया), ब्रिक सहयोगी बैठक भारतीय कृष्क उर्वरक सहकारी संघ (इफको) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लि. परिसंघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ इसमें सम्मिलित हुए और रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक एवं इब्सा व्यापार मंच की बैठक शामिल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने संयुक्त ब्रिक एवं इब्सा व्यापार मंच की बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में फिक्की, सीआईआई और एसौचेम के व्यापार एवं उद्योग प्रतिनिधि शामिल थे। द्वितीय ब्रिक शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में ब्राजील ने ब्रिक के बुद्धिजीवियों की एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जिसमें आरआईएस, आईसीआरआईईआर, आब्जर्बर रिसर्च फाउंडेशन और आईआईएम (अहमदाबाद) के विद्वानों ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्त समय में 21 सितंबर, 2010 को ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयार्क में आयोजित की गई। बैठक में हुई चर्चाओं में कृषि के क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, विकास बैंकों, प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकारियों इत्यादि के मुद्दे शामिल थे। न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

सेंट पीटर्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो, किंग्डाओ और मुम्बई के मेयरों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया। मुम्बई के नगर निगम आयुक्त ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

जून 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित प्रथम ब्रिक शिखर सम्मेलन में, जैसाकि प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया था, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने अगले दो वर्षों के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति और उसमें ब्रिक देशों की भूमिका पर एक संयुक्त ब्रिक अध्ययन संबंधी ब्रिक कार्यशाला 10-11 सितम्बर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की।

सुरक्षा पर ब्रिक उच्च प्रतिनिधियों की 5 अक्तूबर, 2010 को सोची, रूस में आयोजित तीसरी बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भाग लिया।

ब्रिक सांख्यिकीय प्राधिकारियों ने चीन में वर्ष 2011 में आयोजित तृतीय ब्रिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक सांख्यिकीय प्रकाशन का दूसरा अंक प्रकाशित करने के लिए उसकी समीक्षा और उसे अद्यतन करने के लिए 1-3 दिसंबर, 2010 तक रियो डी जेनेरियो में दूसरी बैठक आयोजित की।

जी-15 समूह

पंद्रह देशों के समूह (जी-15) की स्थापना सितम्बर 1989 में बेलग्रेड में आयोजित 9वें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। जी-15 के अधिदेश में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट और ठोस विचारों की पहचान करने और साझी सोच विकसित करने और साझी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से विश्व स्थिति की और विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की स्थिति की समीक्षा करना शामिल है।

जी-15 की 15 मई, 2010 की मंत्रिस्तरीय बैठक के पश्चात जी-15 देशों के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी ईरान द्वारा 17 मई, 2010 को की गई। इस शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट, विकासशील देशों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर और एमडीजी के मुद्दे शिखर सम्मेलन में चर्चा के केन्द्र बिन्दु थे। इस शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जी-15 की अध्यक्षता ईरान से श्रीलंका को सौंपी गई। प्रगति और वित्तीय स्थिति की समीक्षा का कार्य शुरू करने और इस समूह को पुनः सशक्त बनाने के लिए कार्योन्मुख सिफारिश करने के लिए संयुक्त विज्ञप्ति में वरिष्ठ अधिकारियों/वैयक्तिक प्रतिनिधियों वाला एक उच्चस्तरीय कार्य बल स्थापित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के पूर्व हुई जी-15 मंत्रिस्तरीय बैठक में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

आसियान/एएसईएम/एसीडी बिमस्टेक

8वीं भारत-आसियान शिखर बैठक और पांचवीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक 30 अक्तूबर, 2010 को हनोई, वियतनाम में आयोजित की गई। प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आसियान और भारत के नेताओं ने भारत-आसियान संबंधों में प्रगति का जायजा लिया और इन संबंधों को एक नई उचाईं तक ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आसियान सहयोग की नए पहलों की घोषणा की। भारत ने, अपने द्वारा शुरू की गई नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना में हुई प्रगति से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के नेताओं को अवगत कराया।

उप राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 4-5 अक्तबर, 2010 को ब्रसेल्स में आयोजित 8वीं एशिया-यूरोप शिखर बैठक में भाग लिया और अधिक प्रभावकारी वैश्विक आर्थिक शासन पद्धति, सतत विकास, आतंकवाद का मुकाबला और संगठित अपराध का सामना, संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में सुधार इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में भाग लिया।

डा. डी. पुरंडेश्वरी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 8-9 नवंबर, 2010 को तेहरान में आयोजित 9वीं एशिया सहयोग वार्ता में भाग लिया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 6-7 दिसंबर, 2010 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित तृतीय संयुक्त कार्य दल की बैठक (बिमस्टेक के स्थायी सचिवालय की स्थापना पर) और 22-23 नवंबर, 2010 को कैंडी, श्रीलंका में आयोजित तृतीय बिमस्टेक कृषि सहयोग पर विशेषज्ञ दल की बैठक में भाग लिया।

हिन्द महासागर परिधि-क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर-एआरसी)

हिन्द महासागर परिधि-क्षेत्रीय संघ की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। इसमें 18 देश अर्थात् आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, इंडोनिया, भारत, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोजांबिक, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। मिस्र, जापान, चीन, यू.के, और फ्रांस उसके पाँच वार्ता भागीदार हैं। 'खुला क्षेत्रवाद' इसका मार्गदर्शी सिद्धांत है और वह स्वैच्छिक आधार पर कार्य संचालन करता है और सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। आईओआर-एआरसी का शीर्ष निकाय मंत्रिपरिषद होता है।

हिन्द महासागर परिधि-क्षेत्रीय सहयोग संघ के मंत्रिपरिषद की 10वीं बैठक 5 अगस्त, 2010 को साना, यमन में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मानव संसाधन विकास राज्य मत्री डा. डी. पुरंडेश्वरी ने किया। बैठक के पश्चात साना विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार एवं निवेश का संवर्धन, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, और संचरणीय रोग और उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने जैसे क्षेत्रों में आईओआर-एआरसी सदस्य देशों के बीच और अधिक सहयोग पर बल दिया गया। मंत्रियों की परिषद ने अदन की खाड़ी और हिन्द महासागर के अन्य भागों में जल-दस्युता का मुकाबला करने की पहल के लिए समर्थन भी जताया। भारत हिन्द महासागर परिधि-क्षेत्रीय सहयोग संघ की अध्यक्षता वर्ष 2011 में ग्रहण करेगा।

■■

टोरंटो में आयोजित जी-20 शिखर बैठक के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह
27 जून, 2010 को जी-20 के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों के साथ समूहिक फोटोग्राफ में।

ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लूला डिसिल्वा, रूस के राष्ट्रपति श्री दिमित्री ए. मेदवेदेव,
भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और चीन के राष्ट्रपति श्री हू जिंताओ
15 अप्रैल, 2010 को ब्रासीलिया में आयोजित द्वितीय ब्रिक शिखर बैठक में हस्ताक्षर समारोह के दौरान।

12 सार्क

थिम्पु में 28-29 अप्रैल, 2010 को आयोजित 16वां सार्क शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना था, क्योंकि यह सार्क की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह भूटान द्वारा आयोजित पहला सार्क शिखर सम्मेलन भी था। यह शिखर सम्मेलन विगत हाल में सार्क द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को समेकित करने और उनमें तेजी लाने के लिए निर्णयों को लागू कराने में सफल रहा।

भूटान द्वारा यथा प्रस्तावित इस शिखर सम्मेलन का विषय 'जलवायु परिवर्तन' था। इस शिखर सम्मेलन में 'एक हरित एवं खुशहाल दक्षिण एशिया की ओर' नामक थिम्पु रजत जयंती घोषणापत्र और जलवायु परिवर्तन पर अलग से मंत्री स्तरीय वक्तव्य पारित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में दो करार और पर्यावरण पर एक अभिसमय और सेवाओं में व्यापार पर सार्क करार पर हस्ताक्षर किये गए। पर्यावरण पर सार्क अभिसमय से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होने की आशा है। सेवाओं में व्यापार संबंधी सार्क करार से क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होने और क्षेत्र में सेवा में व्यापार बढ़ने की भी आशा है, जिससे आर्थिक विकास के उद्देश्य में सहायता मिलेगी। सार्क विकास कोष (एसडीएफ) सचिवालय के स्थायी परिसर का भी थिम्पु में उदघाटन किया गया और सार्क विकास कोष (एसडीएफ) के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की औपचारिक रूप से नियुक्ति की गई।

शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने देशीय संसाधनों की स्थायी निधियों पर आधारित सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए 'दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय स्थायी निधि' की स्थापना करने और दक्षिण एशिया में जलवायु प्रवर्तन केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की। प्रधान मंत्री ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के लिए सार्क एलडीसी देशों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए 50 'सार्क-भारत रजत जयंती छात्तवृत्ति' का प्रावधान करने की भी घोषणा की। दक्षिण एशिया के भावी विकास पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए क्षेत्र के सुविख्यात लोगों वाला दक्षिण एशिया मंच स्थापित किया जाना, शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल था। यह सहमति हुई कि अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2011 में मालदीव करेगा।

तीसरे सार्क आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठक तीन वर्षों के अंतराल के बाद 26 जून, 2010 को इस्लामाबाद में संपन्न हुई। बैठक में आतंकवाद के विरूद्ध सहयोग पर इस्लामाबाद सार्क मंत्रिस्तरीय वक्तव्य पारित करना बैठक की उपलब्धि रही। बैठक में वीजा, सुरक्षा, आतंकवाद, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने, मादक दवाओं और स्वापकों इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि सार्क देशों के गृह मंत्रियों की चौथी बैठक वर्ष 2011 में भूटान में आयोजित की जाएगी।

जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक उष्मीकरण के मुद्दों को भी सक्रियतापूर्वक उठाया गया। अन्तर-सरकारी विशेषज्ञ दल की बैठक 16-17 अगस्त, 2010 को थिम्पु में संपन्न हुई और इसमें एक साझे सार्क दृष्टिकोण पर सहमति बनी, जिसे कि नवंबर 2010 के अंत में कानकुन में आयोजित सीओपी 16 में प्रस्तुत किया गया।

सार्क वित्त सचिवों की 22-23 अगस्त, 2010 को आयोजित चौथी बैठक के पश्चात 24 अगस्त, 2010 को थिम्पु, भूटान में सार्क वित्त मंत्रियों की चौंथी बैठक आयोजित हुई। बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात को दोहराया गया कि सार्क विकास कोष के अंतर्गत वित्तपोषित की जाने वाली क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय परियोजनाएं मांग-प्रायोजित होनी चाहिएं और ऐसी परियोजनाओं को संबंधित सार्क क्षेत्र तंत्रों के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में सेवाओं के व्यापार संबंधी सार्क करार का शीघ्रता से अनुसमर्थन किये जाने की भी मांग की गई। बैठक में, क्षेत्र में किसी भी अप्रत्याशित भावी वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभावों से बचने और तैयार रहने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने की सिफारिश की गई, जैसाकि पहले भी मंत्रिपरिषद के फरवरी 2009 में कोलंबो में आयोजित अपने 31वें सत्र में सहमति हुई थी।

दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय (एसएयू) ने जेएनयू परिसर (पुराने), नई दिल्ली स्थित अपने अस्थायी परिसर से 26 अगस्त, 2010 से कार्य करना शुरू कर दिया है। वर्तमान वर्ष के लिए सिर्फ दो पाठ्यक्रमों अर्थात् मास्टर ऑफ आर्ट्स (विकास की अर्थव्यवस्था) और एमसीए (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री) की शुरूआत की गई है। पहले वर्ष के दौरान बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25-25 छात्रों का नामांकन किया गया है। विश्वविद्यालय के वर्ष 2015 तक पूरी तरह से स्थापित हो जाने की संभावना है। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी अन्तर-सरकारी संचालन समिति की 7वीं बैठक 21-22 सितम्बर, 2010 तक नई दिल्ली में

थिम्पु, भूटान में आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 29 अप्रैल, 2010 को
प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अन्य सार्क देशों के राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 28 अप्रैल, 2010 को
थिम्पु, भूटान में आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

आयोजित हुई। बैठक में विश्वविद्यालय की शेष बची प्रक्रियाएं जिनमें उसके नियम, शैक्षणिक संरचना, विनियम और कार्य-व्यापार योजना शामिल हैं, पर चर्चा की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया।

सार्क की स्थापना के 25वें वर्ष के आयेजन के लिए विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 16-17 सितम्बर, 2010 को सार्क @ 25 पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता की। इसे इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर (आईआईसी) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा आयोजित किया गया था। विदेश मत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने उद्घाटन भाषण दिया। इसके सहभागियों में सार्क सदस्य देशों के अधिकारियों के साथ-साथ वहां के शिक्षाविद् शामिल थे। पिछले 25 वर्षों के दौरान सार्क में हुई प्रगति और संगठन द्वारा अभी भी सामना की जा रही मुख्य चुनौतियों पर चर्चा की गई।

28 सितंबर, 2010 को न्यूयार्क में सार्क मंत्रिपरिषद की परंपरागत अनौपचारिक बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र के दौरान अतिरिक्त समय में संपन्न हुई। सार्क के अध्यक्ष के रूप में भूटान द्वारा समन्वित इस बैठक में थिम्पु में आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। अन्तर-सत्र शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम को संशोधित करने पर भी इसमें सहमति हुई।

सार्क खाद्य बैंक की चौथी बैठक 27-28 अक्तूबर, 2010 को ढाका में आयोजित की गई। अन्य मुद्दों के साथ-साथ, बैठक में खाद्य बैंक को कार्यात्मक बनाने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई। यह सहमति हुई कि ऐसे भंडार-ग्रहों/गोदामों को अधिसूचित करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाए, जहां कि सदस्यों द्वारा खाद्यान्नों की संवर्धित अतिरिक्त मात्रा रखी जाए। यह भी सहमति हुई कि क्षेत्र में एक आधुनिक खाद्यान्न विश्लेषण प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं की उपलब्धता से खाद्य बैंक में रखी गई अतिरिक्त मात्रा से खाद्यान्नों के कारोबार को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बोर्ड की अगली बैठक में बोर्ड के विचारार्थ एक प्रस्ताव भारत द्वारा तैयार कर रखा जाए, जिसमें ऐसी किसी पहल के लिए सार्क विकास कोष से सहायता का पता लगाना शामिल हो।

थिम्पु में अप्रैल 2010 में 16वें सार्क शिखर सम्मेलन के पूर्व कार्यक्रम समिति के 38वें सत्र के दौरान, जैसाकि सहमति हुई थी, भारत ने 20-22 नवंबर, 2010 को सार्क सदस्य देशों के लोक सेवा आयोगों के प्रमुखों की पहली बैठक की मेजबानी की। बैठक में संबंधित देशों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों द्वारा अपनी भूमिका, कार्यों एवं उद्देश्यों पर पेपर पढ़े गए। उन्होंने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में कुल मिलाकर लोक सेवा आयोगों को सुदृढ़ करने की श्रेष्ठ रीतियों को साझा करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। यह सहमति हुई कि अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग अगली ऐसी बैठक तक, जिसकी वर्ष 2011 में पाकिस्तान द्वारा मेजबानी करने की पेशकश की गई है, केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेंगे।

22 नवंबर को अन्तर-सरकारी परिवहन दल की बैठक के पश्चात 23 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित सार्क परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी गई सार्क क्षेत्रीय बहु-विध परिवहन अध्ययन की सिफारिशों पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञ दल की दूसरी बैठक मोटर-वाहन और रेलवे पर दो प्रारूप करारों के पाठ पर आगे विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारंभ में बांग्लादेश से भारत होकर नेपाल तक एक कंटेनर ट्रेन चलाने को प्रदर्शित करने के लिए आगे बढ़ा जाए।

कानकून में 29 नवंबर-5 दिसंबर 2010 तक आयोजित सीओपी-16 के दौरान सार्क के अध्यक्ष के रूप में भूटान के अनुरोध पर और अन्य सार्क सदस्य देशों के समर्थन से सार्क को यूएनएफसीसीसी सचिवालय में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया।

सार्क पर्यटन मंत्रियों की तीसरी बैठक 12-13 जनवरी, 2011 को काठमांडू में संपन्न हुई। बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों द्वारा किये गए कार्यों पर बल दिया गया और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के अन्य उपायों पर चर्चा की गई।

सार्क, मंत्री परिषद का 33वां (अन्तर-शिखर सम्मेलन) सत्र 8-9 फरवरी, 2011 को भूटान में आयोजित किया गया। इससे पूर्व स्थायी समिति (विदेश सचिव स्तरीय) का 38वां सत्र आयोजित किया गया। इन बैठकों के दौरान 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के अलावा पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवहन, वित्त, शिक्षा, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आतंकवाद, विधिक मामले इत्यादि के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित सम्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें इन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा शामिल है।

■■

तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग तथा विकास भागीदारी 13

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटेक) कार्यक्रम, अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता (स्केप) और कोलंबो योजना के अंतर्गत तकनीकी सहयोग योजना (टीसीएस) को विकासशील विश्व के साथ भारत की विकास भागीदारी एवं सहयोग के महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया गया है। इन सहयोगी कार्यकलापों का उद्देश्य क्षमता निर्माण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी का अंतरण और अनुभवों को बाँटना रहा है। इन सहयोगी कार्यकलापों की उपयोगिता एवं सार्थकता इन कार्यक्रमों में सहभागियों की बढ़ती संख्या से झलकती है।

असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटेक) और अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता (स्केप) वर्ष 1964 में लघु पैमाने पर शुरू होकर आइटेक विगत वर्षों में काफी बड़ा रूप ले चुका है और आज अपने आपको सहयोग के विविध क्षेत्रों में प्रदर्शित करते हुए यह भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक और गतिशील भाग बन गया है। यह मांगपरक और उत्तर-उन्मुखी है। वर्तमान में 159 आइटेक/स्केप भागीदार देश हैं (**परिशिष्ट-IV** पर सूची संलग्न)। आइटेक और स्केप असैनिक तथा रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत में सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारी संख्या में भागीदारों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। आइटेक की वेबसाइट itec.mea.gov.in को और अधिक उपभोक्ता अनुकूल और आइटेक/स्केप सहभागियों की आवश्यकताओं के प्रति उसे आसान बनाने के लिए विशेष रूप से लक्ष्य किया गया है, ताकि वे पैनलबद्ध संस्थानों और अनुमोदित पाठ्यक्रमों से संबंधित विवरण प्राप्त कर सकें और फार्म इत्यादि डाउनलोड कर सकें। आइटेक/स्केप सहभागी देशों की सहभागी सरकारों के साथ-साथ पाठ्यक्रम में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों, दोनों के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में अंग्रेजी तथा पांच विदेशी भाषाओं में एक विवरणिका-आइटेक/स्केप पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण संस्थानों के वार्षिक संकलन प्रकाशित किए गए। मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में आयोजित वार्षिक 'आइटेक दिवस' समारोहों के जरिए पूर्व विद्यार्थियों के नेटवर्क को प्रोत्साहित किया गया। विकासशील विश्व में आइटेक ने एक ब्रांड नाम या एक लोकप्रिय छवि प्राप्त कर ली है।

वर्ष 2010-2011 के दौरान 159 विकासशील देशों को उनकी रूचि एवं लाभ के क्षेत्रों में आइटेक/स्केप के अन्तर्गत 5,500 असैनिक प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए। असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसके पैनल में 46 संस्थाएं हैं और इसके तहत कार्यरत व्यावसायिकों के लिए व्यापक आधार वाले एवं विभिन्न प्रकार के कौशलों एवं विषयों पर मुख्य रूप में लगभग 232 पाठ्यक्रम, मुख्यतया अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए। सबसे अधिक लोकप्रिय पाठ्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से सबंधित एवं अंग्रेजी भाषा के रहे। सरकारी अधिकारियों और अन्यों को वित्त एवं लेखा, लेखा-परीक्षण, बैंकिंग, शिक्षा, आयोजना एवं प्रशासन, संसदीय अध्ययन, अपराध रिकार्ड, वस्त्र, ग्रामीण विद्युतीकरण, उपकरण डिजाइन, नेत्र-विज्ञानी उपकरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए गए। इसके अलावा ग्रामीण विकास, एसएमई और उद्यमिता विकास से संबंधित सामान्य पाठ्यक्रमों ने भी कई सहभागियों का ध्यान आकर्षित किया। (विदेश मत्रालय के आइटेक एवं स्केप कार्यक्रम के अन्तर्गत असैनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थानों की सूची **परिशिष्ट-V** पर संलग्न है)।

आइटेक कार्यक्रम अनिवार्यतः द्विपक्षीय है। तथापि, विगत वर्षों में आइटेक कार्यकलापों के विषय क्षेत्र का विस्तार हुआ है और इसके दायरे में क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठन भी आए हैं। इन संगठनों और समूहों में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान), जी-15, बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक), मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी), अफ्रीकी संघ (एयू), एफ्रो-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ), पान-अफ्रीकी संसद, कैरेबियाई समुदाय (कारीकोम), राष्ट्रमंडल और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) शामिल हैं।

कुछ आइटेक/स्केप सहभागी देशों के विशेष अनुरोध पर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान नीचे दिए गए क्षेत्रों में निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रम संचालित किये गए (किए जाने हैं):

(i) इराक के तकनीशियनों के लिए 14 सितम्बर से 8 दिसंबर 2010 तक भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर में 'जयपुर फुट टेक्नोलॉजी' पर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

(ii) सौर ऊर्जा केन्द्र, गुड़गांव द्वरा 18 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2010 तक 'सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग' पर विशेष पाठ्यक्रम;

(iii) सी-डब्ल्यूईटी, चेन्नै द्वारा 18 अक्तूबर-3 नवंबर 2010 तक 'विंड टरबाइन टेक्नोलॉजी' पर विशेष पाठ्यक्रम;

(iv) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू द्वारा 25 अक्तूबर से 3 नवंबर 2010 तक 'जैव-ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम' नामक विशेष पाठ्यक्रम;

(v) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 15 नवंबर से 30 नवंबर 2010 तक व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ एवं मध्य क्रम के सरकारी अधिकारियों के लिए 'नीतिकारों एवं वार्ताकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम' नामक विशेष पाठ्यक्रम;

(vi) पोस्टल स्टॉफ कॉलेज, गाजियाबाद द्वारा 6 दिसंबर से 16 दिसंबर 2010 तक 'पोस्टमास्टरों एवं प्रबंधकों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम' नामक विशेष पाठ्यक्रम;

(vii) पोस्टल स्टॉफ कॉलेज, गाजियाबाद द्वारा 7 मार्च से 18 मार्च 2011 तक 'पोस्ट मास्टरों एवं प्रबंधकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम' नामक विशेष काठ्यक्रम;

(viii) नाईजीरिया के लोगों के लिए एनआईपीईआर, मोहाली द्वारा 7 फरवरी से 25 फरवरी 2011 तक 'औषध विनियामक उद्योग प्रतिनिधियों एवं प्रयोगशालाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम' नामक विशेष पाठ्यक्रम;

(ix) आईआईएफटी सेन्टर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज द्वारा डब्ल्यूटीओ में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के लिए 28 फरवरी से 4 मार्च 2011 तक 'ट्रेनिंग प्रोग्राम टु फेमिलियराइज ऑन दी पिट्फॉल्स एंड रिवार्ड्स ऑफ दी डब्ल्यूटीओ' नामक विशेष पाठ्यक्रम;

(x) भारत-अफ्रीका शिखर मंच में जैसाकि निर्णय लिया गया था, 'भोगौलिक सूचना प्रणाली' पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, हैदराबाद द्वारा 1 फरवरी से 2 मार्च 2011 तक विशेष पाठ्यक्रम;

(xi) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 14 मार्च से 25 मार्च 2010 तक व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ एवं मध्य क्रम के सरकारी अधिकारियों के लिए 'नीतिकारों एवं वार्ताकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम' नामक विशेष पाठ्यक्रम;

(ख) कोलंबो योजना के अंतर्गत तकनीकी सहयोग योजना (टीसीएस)

एशिया और प्रशांत में सहकारी एवं आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोलंबो योजना क्षेत्र के देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए वर्ष 1951 में स्थापित एक क्षेत्रीय अन्तर-सरकारी संगठन है। कोलंबो योजना की दक्षिण-दक्षिण तकनीकी सहयोग योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने कोलंबो योजना के हस्ताक्षकर्त्ता 18 देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तकनीकी सहयोग योजना (टीसीएस) की शुरूआत की है। कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग योजना को 1 अप्रैल, 2010 से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से विदेश मत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

वर्ष 2010-2011 के दौरान, कोलंबो योजना के सदस्य देशों के विद्वानों के लिए प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। इसमें कोलंबो योजना देशों के सहभागियों को आवंटित करने के लिए कोलंबो योजना सचिवालय को दिये गए 90 स्लॉट शामिल हैं। कोलंबो योजना के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के 39 संस्थानों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विद्वानों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, लेखा परीक्षा एवं लेखा, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर शिक्षा, संसदीय मामले, ग्रामीण विकास, वस्त्र, जल संसाधन, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनिरियरी, वित्तीय प्रबंधन, बीमा इत्यादि के क्षेत्र शामिल हैं।

इसके अलावा, कोलंबो योजना स्टॉफ कॉलेज (सीपीएससी), मनीला की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता कोलंबो योजना सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2010-2011 के दौरान सीपीएससी, मनीला ने भारत सरकार के वित्तीय अनुदान के अन्तर्गत अगस्त और नवंबर 2010 में आयोजित कार्यकलापों के साथ 'तकनीकी मानव संसाधन विकास-गरीबी उन्मूलन के लिए टीवीईटी कौशल के लिए एशिया-प्रशांत क्षमता-निर्माण परियोजना' नामक दो-वर्षीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रम की शुरूआत की। भूटान के साथ जहां तक हमारे क्रियाकलापों का संबंध है, भारत सरकार ने शैक्षिक वर्ष 2010-2011 से कोलंबो योजना व्याख्यानों की संख्या को 30 तक बढ़ाने के भूटान की शाही सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

रक्षा प्रशिक्षण

रक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ती रूचि का पता इस बात से चला कि रक्षा सेवा के तीनों स्कंधों अर्थात सेना, नौसेना और वायु सेना के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 800 अधिकारियों/प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन पाठ्यक्रमों का स्वरूप सामान्य एवं विशेषज्ञता का था और इनमें तीनों सेवाओं के युवा अधिकारियों के लिए फाउंडेशन पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, इलेक्ट्रानिक्स, यांत्रिकी अभियंत्रण, समुद्री जल-विज्ञान, विद्रोह का मुकाबला एवं जंगल-युद्ध कला शामिल थे। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा सेवा कॉलेज, वेलिंगटन के लिए निर्धारित संख्या से अधिक स्व-वित्तपोषण आधार पर उनमें भाग लिया। उत्तरोत्तर बढ़ते परस्पर संपर्कों से भारत में रक्षा प्रशिक्षण को विकासशील एवं विकसित देशों द्वारा दिये जाने वाले महत्व का पता चलता है।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

सरकारों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा-परीक्षा, कानून, विविध कृषि क्षेत्र, फार्माकोलॉजी, सांख्यिकी

एवं जनसंख्या विज्ञान, लोक प्रशासन, और वस्त्र के क्षेत्रों सहित असैनिक एवं रक्षा क्षेत्र के 38 विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किये गए थे। इथियोपिया, लाओस, लिसोथो, मंगोलिया, सेशेल्स और जांबिया द्वारा प्रशिक्षण एवं परामर्शी क्षमताओं में रक्षादलों की सेवाएं प्राप्त की गईं।

विकास सहभागिता एवं परियोजना सहयोग

वर्ष 2010-2011 के दौरान विशेष रूप से पुरातत्व संरक्षण, सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी तथा लघु एवं मंझोले उद्यमों के क्षेत्रों में कार्यान्वयन करने के लिए कई द्विपक्षीय परियोजनाएं शुरू की गईं। द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं में मुख्यतः आवश्यक भौतिक अवसंरचना स्थापित करने तथा क्षमता निर्माण पर बल दिया गया, ताकि इन परियोजनाओं का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

क्रियान्वयनधीन मुख्य परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **कंबोडियाः** ता प्रोह्म मंदिर के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्य संबंधी परियोजना के अंतर्गत, मंदिर के विभिन्न स्थलों पर भारतीय पूरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किये जा रहे पुनरूद्धार के कार्यों में और प्रगति हुई।

(ii) **लाओ पीडीआरः** वाट फु के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का संरक्षण एवं पुनरूद्धार संबंधी कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाना जारी है। लाओ पीडीआर में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के चरण-I के अंतर्गत लाओं के 30 छात्रों को प्रशिक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता अप्रैल 2010 में पूरी हो गई।

(iii) **अल सल्वाडोर तथा निकारागुआः** आईसीटी केन्द्रों में अतिरिक्त एक-वर्षीय प्रशिक्षण जून 2010 में शुरू हुआ।

(iv) **सीरियाः** दमिश्क में आईसीटी केन्द्र के अधिष्ठापन एवं चालूकरण का कार्य दिसंबर 2010 में पूरा हो गया और प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया है।

(v) **ग्रेनाडाः** आईसीटी केन्द्र स्थापित करने के लिए अक्तूबर 2010 में कार्यकारी एजेंसी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(vi) **बुरुंडी, कांगो जनवादी गणराज्य और फिजीः** आईसीटी केन्द्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

(vii) **वियतनामः** आईसीटी में एक अत्याधुनिक (एडवांस) संसाधन केन्द्र स्थापित करने संबंधी परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

(viii) **जिम्बाब्वेः** लघु एवं मझोले उद्यम के क्षेत्र में परियोजना वर्ष 2006 में शुरू हुई और यह समाप्ति के अंतिम चरण में है। जिम्बाब्वे के लोगों को कार्य-पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंतिम चरण का कार्य चल रहा है।

(ix) **इंडोनेशियाः** निर्माण क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने संबंधी परियोजना शुरू करने के लिए कार्यकारी एजेंसी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गए। अचेह, इंडोनेशिया में कार्य और परियोजना का कार्यान्वयन संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(x) **इक्वाडोर एवं डोमिनीकन रिपब्लिकः** आईसीटी केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

व्यवहार्यता अध्ययन

(i) बर्बिस, गुयाना में गहरा जल नदी बंदरगाह के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है और व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट गुयाना सरकार को भेज दी गई है।

(ii) माण्टेनिग्रो के विदेश मंत्रालय में एक सुरक्षित संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है और माण्टेनिग्रो सरकार को भेज दी गई है।

आपदा राहत के लिए सहायता

वर्ष 2010-2011 के दौरान, प्राक्रतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को भारत ने तत्काल मानवीय एवं आपदा राहत सहायता प्रदान की। बेनिन, चिली, गाम्बिया, जमैका, लाइबेरिया, मालदोवा, म्यांमा, नाइजर, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को नगद दान के रूप में राहत सहायता दी गई।

■■

14 निवेश और व्यापार संवर्धन

आर्थिक राजनय क्रमिक रूप से भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। तेजी से हो रहे वैश्वीकरण के साथ विदेशों में भारत के आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित रखना और बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गया है। विदेश मंत्रालय अपने विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से व्यापार एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के कार्य में सक्रियतापूर्वक लगा हुआ। वाणिज्यिक एवं आर्थिक मोर्चे पर प्रयासों का समान्वय करने और वाणिज्य मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी विभागों, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और आर्थिक कार्य विभाग और साथ ही निर्यात संवर्धन परिषद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए मंत्रालय में निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी) प्रभाग सृजित किया गया है।

भारतीय मिशन उभरते अवसरों का लाभ उठाने और विदेशी निवेशकों तक पहुंचने में उत्तरोतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे उद्योगों की पहलों के समर्थनकारी भी रहे हैं और वे वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और चैम्बर ऑफ कामर्स के साथ सहभागीतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। निवेशकों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरों को प्रोत्साहित किया जाता है और निवेश अनुकूल गंतत्व के रूप में भारत को प्रदर्शित कर विदेशी निवेशों का और अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। व्यापार से व्यापार के संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए भारत आने वाले और विदेश जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को शामिल करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

हमारे मिशनों को भारतीय उद्योगों की बढ़ती मांगों को कारगर ढंग से पूरा करने में मदद करने के लिए वर्ष 2010-2011 में बाजार सर्वेक्षण, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां क्रेता-विक्रेता सम्मेलन इत्यादि सहित बाजार के विस्तार संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए उन्हें 8.5 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई थी। सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने, स्थानीय नियमों एवं विनियमों के संबंध में सूचना एकत्र करने, क्षेत्र-विशेष संबंधी संगोष्ठी एवं सम्मेलन आयोजित करने, विवरणिका एवं प्रचार-सामग्री का मुद्रण करने इत्यादि के लिए बाजार का अध्ययन करने के लिए मिशन इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

वर्ष 2010-2011 के दौरान आईटीपी प्रभाग नीतिगत निविष्टियां एवं सूचना प्रदान करने वाली विभिन्न सरकारी एजेंसियों जिनमें, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मक परिषद, निवेश भारत इत्यादि शामिल हैं, के साथ संपर्क स्थापित करना जारी रखा। प्रभाग ने द्विपक्षीय नागर विमानन मामलों पर नागर विमानन मंत्रालय के साथ और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ भी कार्य किया है। फिक्की और सीआईआई जैसे व्यापार संवर्धन निकायों और उद्योग संगठनों को सुविधा, मिशनों के साथ संपर्क, प्रचार-प्रसार इत्यादि के रूप में उनके बाह्य कार्यकलापों में सहायता दी गई है। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 5-6 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल व्यापार मंच आयोजित करने के लिए सीआईआई को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस आयोजन में विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आईटीपी प्रभाग का 'भारत-गतिशील व्यवसाय सहभागीः निवेशक अनुकूल गंतव्य' नामक वार्षिक प्रकाशन के नवीनतक संस्करण को संभावित विदेशी निवेशकों एवं व्यवसायिकों में प्रचार-प्रसार करने और बाँटने के लिए विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और केन्द्रों में परिचालित किया गया है। यह प्रकाशन भारत की आर्थिक शक्ति और वर्तमान व्यापार माहौल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत में निवेश माहौल, कराधान, व्यापार संगठनों के रूप और व्यापार एवं लेखाकरण नीतियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने वाली 'डुइंग बिजनेस इन इंडिया' नामक एक पत्रिका भी सभी मिशनों/केन्द्रों को भेजी गई।

आईटीपी प्रभाग की वेबसाइट www.indiainbusiness.nic.in जिसमें भारत में वाणिज्यिक एवं निवेश अवसरों के बारे में व्यापक सूचना दी गई है, को और अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए उसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। यह वेबसाइट भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और व्यापार एवं निवेश के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और इसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों और व्यवसायियों को सूचना का एकल स्रोत प्रदान करना है। इस वेबसाइट पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित साप्ताहिक एवं मासिक अद्यतन जानकारी उपलब्ध है।

ऋण-श्रृंखलाएं

भारत सरकार अपनी राजनयिक रणनीति के भाग के रूप में अफ्रीका, लातीन अमरीका और एशिया के विकासशील देशों को भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अन्तर्गत रियायती ऋण-श्रृंखलाएं प्रदान करती है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये श्रृंखलाबद्ध ऋण उदार

ऋण के रूप में हैं, जिनसे ऋण प्राप्त करने वाले देशों को अपनी विकास परियोजनाएं शुरू करने में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया में श्रृंखलाबंद ऋण प्राप्तकर्ता देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करती है, जिससे भारत के प्रति अपार सद्भावना स्थापित होती है। इस ऋण-श्रृंखला से परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में भारत की क्षमता और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने और भारतीय मालों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद मिली है।

आईटीपी प्रभाग इन ऋण-श्रृंखलाओं के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय में नोडल प्रभाग है। यह गहनतापूर्वक मंत्रालय के अन्य टेरिटोरियल प्रभागों, भारतीय मिशनों, आर्थिक कार्य विभाग और एक्जिम बैंक के साथ मिल कर कार्य करता है, ताकि ऋण-श्रृंखला का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके।

ऋण-श्रृंखला प्रक्रिया में अधिक कार्यकुशलता और पारदर्शिता की शुरूआत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग और एक्जिम बैंक के परामर्श से जुलाई 2010 में ऋण-श्रृंखला संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। इन दिशानिर्देशों में अनुमोदन से पूर्व परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, ठेके दिये जाने के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली, विस्तृत अनुवीक्षण तंत्र और अन्य उपबंधों की आवश्यकता होती है।

आज की तिथि तक 56 विकासशील देशों को भारत सरकार द्वारा 7,642.91 मिलियन अमरीकी डालर की 136 ऋण-श्रृंखलाएं प्रदान की गई हैं। वर्ष 2010-2011 के दौरान 2,548.33 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 16 ऋण-श्रृंखलाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बांगलादेश को 1 बिलियन अमरीकी डालर, रेल परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 382.37 मिलियन अमरीकी डालर, अवसंरचना विकास के लिए नेपाल को 250 मिलियन अमरीकी डालर, पनबिजली परियोजनाओं के लिए डीआर कांगो को 210 मिलियन अमरीकी डालर, चीनी उद्योग के विकास के लिए इथोपिया को 213.31 मिलियन अमरीकी डालर, लाओ पीडीआर को विद्युत-उत्पादन परियोजनाओं के लिए 72.55 मिलियन अमरीकी डालर, केन्या को विद्युत पारेषण लाइन के लिए 61.6 मिलियन अमरीकी डालर और मॉरीशस को अपतटीय गश्ती पोत की खरीद के लिए 48.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-श्रृंखलाएं शामिल हैं। अन्य ऋण-प्राप्तकर्ता देशों में मलावी, मोजाम्बिक और कंबोडिया शामिल है।

इन ऋण-श्रृंखलाओं से व्यापार एवं निवेश का संवर्धन कर ऋण-प्राप्तकर्ता देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर काफी सकरात्मक प्रभाव पड़ा है। कई देशों में विद्युत-उत्पादन एवं पारेषण, ग्रामीण विद्युतीकरण, परिवहन, रेल, कृषि, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

ऋण-श्रृंखला के अन्तर्गत वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए विकासशील देशों को व्यवहार्यता अध्ययन करने में सहायता करने के लिए 5 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि से विकासशील देशों, जिनके पास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केन्द्रित परियोजनाओं की पहचान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है, को अपनी तकनीकी एवं वित्तीय सुसाध्यता स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी।

■■

15 ऊर्जा सुरक्षा

सितम्बर 2007 में ऊर्जा सुरक्षा यूनिट का गठन सबसे पहले विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए) के आई.टी.पी. प्रभाग के अंदर किया गया। ऊर्जा के आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2009 में ऊर्जा सुरक्षा यूनिट को एक समग्र प्रभाग के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में विदेश मंत्रालय के कार्य की रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैंः विदेशों में ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर स्थायी राजनयिक हस्तक्षेप करना; तेल, गैस एवं कोयला के साथ-साथ ऊर्जा के अन्य संसाधनों के लिए देश के आपूर्ति आधार को और विविधतापूर्ण बनाने के सरकारी प्रयासों में सहायता करना; ऊर्जा के नोडल मंत्रालयों के साथ विचार विनिमय करना; नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए गठबंधन एवं प्रौद्योगिकी अंतरण को सुविधाजनक बनाना; और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय नवाचारों तथा ज्ञान आधार में विस्तार की जानकारी रखना। ऊर्जा सुरक्षा के अतिरिक्त, संसाधन एवं खाद्य सुरक्षा को भी ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग के अधिदेश के अंतर्गत लाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ऊर्जा से संबंधित मुद्दों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है तथा इसी भावना से यह अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (इरेना), ऊर्जा दक्षता एवं सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी (आई.पी.ई.ई.सी.), नवीकरणीय ऊर्जा एवं दक्षता साझेदारी (आर.ई.ई.ई.पी.), अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आई ई एफ), और संयुक्त तेल डाटा पहल (जे.ओ.डी.आई.) में शामिल हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई.ई.ए) के साथ अपनी भागीदारी में वृद्धि की है। इन मंचों में अग्रणी भागीदारी ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग से प्रतिनिधित्व के साथ-साथ नोडल मंत्रालयों से है। इस प्रभाग ने आई.पी.ई.ई.सी. की नीति समिति की बैठक (नई दिल्ली, अक्टूबर 2010), आई.पी.ई.ई.सी. (वाशिंगटन डीसी, मई 2010), आई.ई.एफ. (कानकुन, मार्च 2010) और इरेना (आबूधाबी, अक्तूबर 2010) बैठक में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने 26 जनवरी, 2009 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) में भारत के शामिल होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मुख्यालय आबूधाभी में है। भारत सरकार में नोडल मंत्रालय नया एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। भारत ने 4 मई, 2010 को इरेना की संविधि की पुष्टि की, जो आगे चलकर 25 देशों द्वारा पुष्टि के बाद 8 जून, 2010 को प्रभावी हुई। आबूधाभी में भारत के राजदूत को इरेना में प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्यायित किया जाता है।

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा, जी-20, नाम, ब्रिक, असेम, इब्सा, पूर्वी एशियाई ऊर्जा मंत्री बैठक, सी.आई.सी.ए. और राष्ट्रमंडल जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए निविष्टियां प्रदान करने का कार्य जारी रखा। अन्य देशों के अलावा यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया एवं जर्मनी के साथ वार्षिक द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ता के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों एवं मंत्रालयों को भी निविष्टियां प्रदान की गईं।

ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए विदेश मंत्रालय में नोडल बिंदु के रूप में ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने ऊर्जा से जुड़े सभी मंत्रालयों के साथ घनिष्ट समन्वय बनाए रखा तथा ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर उनकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में सहायता प्रदान की। अक्तूबर 2010 में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2010 (डी.आई.आर.ई.सी.-2010) के आयोजन में नया एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सहायता की गई। इस प्रभाग ने ऊर्जा सुरक्षा पर अनौपचारिक कार्य समूह की आवधिक बैठकों के माध्यम से तेल एवं अवसंरचना से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य जारी रखा।

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने प्रस्तावित तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस पाइप लाइन के लिए तकनीकी कार्य समूह (टी.डब्ल्यू.जी.) तथा संचालन समिति की बैठकों में भाग लिया जिसकी वजह से 11 दिसम्बर, 2010 को आश्गाबाद में आयोजित तापी शिखर बैठक में अंततः तापी अंतर्सरकारी करार एवं रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर का मार्ग प्रशस्त हुआ।

■■

नीति आयोजना और अनुसंधान 16

नीति आयोजना और अनुसंधान प्रभाग की मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं विदेश नीत और वैश्विक कार्यों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं और अध्ययनों की प्रोसेसिंग करना; भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित विषयों को देखने वाले विचारकों, अनुसंधान निकायों, विश्वविद्यालयों आदि का डाटाबेस तैयार करना/उसको अद्यतन करना; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जा.सी.) तथा इससे संबद्ध विश्वविद्यालयों और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के साथ विचार विनियम करना तथा जब भी निर्देश हो मंत्री/राज्य मंत्री एवं विदेश सचिव के लिए भाषणों का मसौदा तैयार करना। इसके अतिरिक्त, नीति आयोजना और अनुसंधान प्रभाग, मंत्रिमंडल और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए महीने के महत्वपूर्ण घटनाक्रम का मासिक सार तैयार करता है और प्रेषित करता है। प्रभाग समयबद्ध तरीके से विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट संकलित, सम्पादित, मुद्रित तथा वितरित भी करता है। यह रिपोर्ट शेष विश्व के साथ भारत के संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण के सार संग्रह के रूप में काम करती है। यह प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित इंडिया के ''भारत और विदेश'' अध्याय के लिए सामग्री को समन्वित और संकलित भी करता है।

नीति आयोजना और अनुसंधान प्रभाग ने कोलकाता विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थापित विदेश नीति अध्ययन संस्थान की स्थापना का समन्वय व अनुवीक्षण किया है, जिसकी स्थापना विदेश मंत्रालय की वित्तीय सहायता से की गई है। इसके कार्यक्रमों में एम.फिल. पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पूर्वी एशिया व दक्षिण एशिया के देशों पर केंद्रित भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करना शामिल है।

नीति आयोजना एवं अनुसंधान प्रभाग के बजट के अंतर्गत वित्तीय सहायता से रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान (इडसा), नई दिल्ली 'भारत के पड़ोसीः अगले दो दशकों में चुनौतियां' शीर्षक से एक अनुसंधान परियोजना सम्पन्न कर रहा है।

संयुक्त सचिव (पी.पी.एंड.आर.) ने सितम्बर 2010 के दौरान भारत-चीन विदेश नीति परामर्श के चौथे दौर में भाग लेने के लिए बीजिंग जाने वाले भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

इस अवधि के दौरान नीति आयोजना व अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक/पूर्ण रूप से वित्त पोषित सेमिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों व अध्ययनों की सूची **परिशिष्ट-VI** में दी गई है।

नीति आयोजना और अनुसंधान प्रभाग स्थिति कक्ष व सीमा कक्ष के कार्य की भी देखरेख करता है। उनके सभी प्रशासनिक मुद्दों और वास्तविक कार्यों की देखरेख इस प्रभाग द्वारा की जाती है। यह प्रभाग हमारे देश में आने वाले विदेशी प्रकाशनों में भारत की बाह्य सीमाओं के सीमांकन की जांच करने के लिए उत्तरदायी है तथा इस मामले से संबंधित मंत्रालयों को अपनी सलाह भी प्रदान करता है। यह वर्ड सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों एवं अनुसंधान विद्वानों को भारतीय सर्वेक्षण के साथ उनके सरकारी कार्य में उपयोग के लिए मैप शीट की आपूर्ति का समन्वय करता है। यह प्रभाग मंत्रालय के पुराने रिकार्डों को देखने के लिए अनुसंधान विद्वानों के अनुरोधों से संबंधित कार्य भी करता है।

स्थिति कक्ष

स्थिति कक्ष मंत्रालय का बहुआयामी, बहु-सुविधायुक्त अधुनातन परिसर है। 2007 में स्थापित इस कक्ष में संचार की अपेक्षित संयोजकता तथा प्रदर्शन पैनल हैं जिनकी किसी नाजुक स्थिति से निपटने के लिए जरूरत होती है। मंत्रालय के संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ के रूप में अपनी प्राथमिक भूमिका के अलावा, टेलीफोन/वीडियो कांफ्रेंस समेत प्रस्तुतीकरण एवं सम्मेलन जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए सभी प्रभागों द्वारा इस परिसर का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है।

भूमिका

स्थिति कक्ष की भूमिका नीचे दी गई हैः

1 मिशनों के प्रमुखों के साथ सम्मेलन, प्रस्तुतीकरण, आवधिक ब्रीफिंग, और वीडियो/टेलीफोन कांफ्रेंस के आयोजन के लिए तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा अपेक्षित मानचित्रों एवं प्रतिबिंभों पर चर्चा के लिए भी अनेक सुविधाओं से युक्त परिसर के रूप में काम करना।

2 संकट के मामलों में संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ (नियंत्रण कक्ष) के रूप में काम करना।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान गतिविधियां

- **नियंत्रण कक्ष के रूप में स्थिति कक्षः लेह में भयंकर बाढ़ः** अगस्त 2010 में लेह में भयंकर बाढ़ से जिन मित्र विदेशी राष्ट्रों के राष्ट्रिक प्रभावित हुए थे उनके मिशनों को अबाध रूप से सूचना प्रदान करने/उनसे सूचना प्राप्त करने में सुविधा के लिए स्थिति कक्ष में 24 घंटे काम

करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इस नियंत्रण कक्ष ने 7 दिन (9-15 अगस्त, 2010) तक अबाध प्रचालन के लिए दिल्ली एवं श्रीनगर में स्थापित समान नियंत्रण कक्षों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य किया।

- **मिशनों में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा की स्थापना:** मंत्रालय में संचार के साथ एक नया आयाम जोड़ने संबंधी मंत्रालय के स्वप्न के अनुसरण में, चुनिंदा मिशनों में चरणबद्ध ढंग से वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के चरण 1 एवं चरण 2 के अंग के रूप में, 2009 में 13 मिशनों में यह सुविधा स्थापित की गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, चरण 3 एवं चरण 4 के कार्य में प्रगति हुई है। 2010 में 3 और मिशनों अर्थात थिम्पू, बैंकाक और सिंगापुर स्थित मिशनों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे वीडियों कांफ्रेंस की सुविधा से युक्त मिशनों की कुल संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इसके अतिरिक्त चरण 4 के कार्यान्वयन के अंग के रूप में, 6 और मिशनों के लिए तकनीकी संबाव्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं तथा निकट भविष्य में इन मिशनों में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा स्थापित की जाएगी।

- **मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा का प्रयोग:** इस अवधि के दौरान हमारे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंतःक्रियात्मक संचार के लिए स्थिति कक्ष में उपलब्ध वीडियो कांफ्रेस की सुविधा का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे अधिकारियों द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुल मिलाकर 18 वीडियो कांफ्रेंसों का आयोजन किया गया।

सीमा कक्ष

नीति आयोजना और अनुसंधान प्रभाग के अंग के रूप में स्थापित सीमा कक्ष के कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

1 भारतीय सर्वेक्षण के समन्वय से भारत की बाह्य सीमाओं के सभी पहलुओं की जांच करना तथा प्रकाशन के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित मैप शीटों की संवीक्षा करना।

2 क्षेत्रीय प्रभागों को सीमा संबंधी मामलों पर मानचित्र संबंधी सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना।

3 उपलब्ध मानचित्र संबंधी सामग्री/आधारिक मानचित्रों के एकत्रीकरण, मिलान और उनको डिजीटल बनाने में सहायता प्रदान करना।

4 सीमा स्तंबों की मरम्मत/अनुरक्षण तथा भारतीय बूभाग (डाटा बेस आदि का अनुरक्षण) में किसी अतिक्रमण संबंधी रिपोर्टों सहित संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्य के संबंध में भारतीय सर्वेक्षण व राज्य सरकारों के साथ संपर्क स्थापित करना।

5 समुद्री सीमा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से संबंधित सूचना के एकत्रीकरण और उसको डिजीटल बनाने तथा महाद्विपीय शेल्फ का रेखाचित्र बनाने में सहायता प्रदान करना।

6 विकास कार्यों के प्रयोजन के लिए, विभिन्न सरकारी व अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा अनुरोधित प्रतिबंधित मानचित्रों की रक्षा मंत्रालय के सहयोग से जांच करना।

7 नौसैनिक जल विज्ञान कार्यालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ संपर्क स्थापित करना।

8 भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में सभी मानचित्रों, दस्तावेजों और सूचना के आधान के रूप में कार्य करना।

9 विदेश पत्र-पत्रिकाओं और एटलसों में प्रकाशित गलत मानचित्रों की जांच करना तथा इन मानचित्रों को ठीक करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

सीमा कक्ष ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय बू-भाग तथा समुद्री सीमा पर विभिन्न आंतरिक/अंतर्मंत्रालयीन बैठकों में भाग लिया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा (जमीनी एवं समुद्री) के विभिन्न पहलुओं पर सभी भू-भागीय प्रभागों को मानचित्र संबंधी तथा तकनीकी निविष्टियां प्रदान की।

2 विभिन्न भू-भागीय प्रभागों द्वारा आयोजित अंतर्मंत्रालयीन बैठकों के लिए निविष्टियां प्रदान की।

3 सर्वेक्षण व मानचित्रण प्रवृत्ति व प्रौद्योगिकी की जानकारी के लिए भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सीमा कक्ष से संबद्ध किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यों के लिए भारतीय सर्वेक्षण का दौरा आयोजित किया गया।

4 बंग्लादेश में भारतीय इंक्लेव के मानचित्रण पर निविष्टियां प्रदान की।

5 संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भारत-बंग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सम्मेलनों/बैठकों पर मानचित्र संबंधी निविष्टियां प्रदान की।

6 भारत-बंग्लादेश सीमा पर जे भी डब्ल्यू जी बैठक के लिए निविष्टियां प्रदान की तथा इसमें भाग लिया।

7 भारत-बंग्लादेश समुद्री एवं जमीनी सीमाओं पर विधि एवं संधि प्रभाग को निविष्टियां प्रदान की।

8 डा.जी.सी.ई.आई, अहमदाबाद को कृष्णा-गोदावरी घाटी में क्षेत्रीय समुद्री जल की सीमाओं पर निविष्टियां प्रदान की।

9 इंटरनेट पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत की बाह्य सीमा के गलत चित्रण के बारे में नीति आयोजना एवं अनुसंधान प्रभाग को निविष्टियां प्रदान की।

10 राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त हिन्दी श्रृंखला के मानचित्रों की जांच।

11 भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानान्तर सीमा स्तम्भ के निर्माण एवं अनुरक्षण की आयोजना, निधियां जारी करना एवं मानिटरिंग।

12 सीमा स्तम्भों के अनुरक्षण/निर्माण के लिए सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ संपर्क।

13 भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत ओएसएम एवं डीएसएम मानचित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रमाणीकरण (44 मानचित्र पत्रक)।

14 भारत की बाह्य सीमा को शामिल करते हुए सीमा पट्टी मानचित्रों के लिए डाटा बेस को अंतिम रूप देना।

15 सीमा पट्टी मानचित्रों का अभिलेखागारीय अंकीयकरण।

16 भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शामिल करते हुए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्थलाकृति संबंधी मानचित्रों का अंकीय एवं हार्ड प्रति में अभिलेखीकरण।

■■

17 प्रोतोकोल

अप्रैल 2010-फरवरी 2011 तक की अवधि के दौरान राज्याध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष और विदेश मंत्री स्तरीय 45 व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की जबकि भारत से 24 व्यक्तियों ने विदेश की यात्रा की। इन यात्राओं की बड़ी संख्या, व्यापक भौगोलिक कवरेज तथा कार्यकलापों की गहनता से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विश्व के साथ भारत के व्यापक कार्यकलाप प्रतिबिंबित होते हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय रहा कि सभी पी-5 देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने जुलाई-दिसंबर 2010, अर्थात छह महीने की अवधि के भीतर ही भारत की यात्राएं की। वर्ष 2010 में पांच नए आवासीय मिशन खोले गए जिससे नई दिल्ली में इन मिशनों की कुल संख्या 145 हो गई। स्विटजरलैंड और न्यूजीलैंड द्वारा क्रमशः बेंगलुरु और मुम्बई में दो कोंसलावास खोले गए। इसके अतिरिक्त 14 देशों ने नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगालुरु और कोलकाता में नए मानद कोंसलावास भी खोले। इस वर्ष के दौरान विदेशी राजनयिक मिशनों द्वारा 148 नए पदों का सृजन किया गया।

अप्रैल 2010-फरवरी 2011 के दौरान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधान मंत्री स्तर पर हुई भारत की सरकारी/कार्यकारी यात्राएं

क्र.सं.	**गणमान्य अतिथि का नाम और ब्यौरा**	**तारीख**
1.	महामहिम श्री हामिद करजई, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति	26-30 अप्रैल, 2010
2.	महामहिम श्री गुरबांगुली बरदीमुहामेदोव, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति	24-26 मई, 2010
3.	महामहिम श्री जेम्स, एलिक्स मिशेल, सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति	1-3 जून, 2010
4.	महामहिम डा. जैकब जुमा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति	2-4 जून, 2010
5.	महामहिम श्री महिन्दा राजपक्षे, श्रीलंका लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति	8-11 जून, 2010
6.	महामहिम ले. जनरल मोमपती एस. मेराफहे, बोत्सवाना गणराज्य के उपराष्ट्रपति	15-19 जून, 2010
7.	महामहिम सीनियर जनरल थान शवे, म्यामां संघ की स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट कौंसिल के अध्यक्ष	25-29 जुलाई, 2010
8.	परम माननीय डेविड कैमरून, संसद सदस्य, युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री	27-29 जुलाई, 2010
9.	महामहिम श्री डोनाल्ड टस्क, पोलैंड गणराज्य के प्रधान मंत्री	6-8 सितंबर, 2010
10.	महामहिम श्री अर्मांडो एमिलो गुबुजा, मोजम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति	26 सितंबर-4 अक्तूबर 2010
11.	महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक, भूटान नरेश	5-7 अक्तूबर, 2010
12.	महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक, भूटान नरेश	20-29 अक्तूबर, 2010
13.	महामहिम ल्योन्छिन जिग्मी वाई थिनले, भूटान के प्रधान मंत्री	30 अक्तूबर-3 नवंबर 2010
14.	महामहिम श्री न्वाजी बिंगू-वा मुथारिका, मलावी के राष्ट्रपति; तथा श्रीमती मुथारिका	3-7 नवंबर, 2010
15.	माननीय बराक ओबामा, संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति	6-9 नवंबर, 2010
16.	महामहिम श्री रायला ए. ओडिंगा, कीनिया के प्रधान मंत्री	14-17 नवंबर, 2010
17.	लिचटेन्स्टिन के महामहिम वंशानुगत राजकुमार एलोइस और महामान्या राजकुमारी सोफी	14-20 नंवबर, 2010
18.	महामहिम डा. एच. सुसिलो बाम्बंग युधोयोनो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति; और मादाम एचजे एनी बाम्बंग युधोयोनो	24-26 जनवरी, 2011
19.	महामहिम डा. रामबरन यादव, नेपाल के राष्ट्रपति	27 जनवरी-5 फरवरी 2011

अप्रैल 2010-जनवरी 2011 के दौरान विदेश मंत्री स्तर पर हुई भारत की यात्राएं

क्र.सं.	गणमान्य अतिथि का नाम और ब्यौरा	तारीख
1.	महामहिम श्री कमलेश शर्मा, राष्ट्रमंडल महासचिव	27 मार्च-1 अप्रैल 2010
2.	महामहिम प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद, रियाद के गवर्नर	11-15 अप्रैल, 2010
3.	महामहिम श्री एलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के विदेश मंत्री	3-5 मई, 2010
4.	महामहिम डा. अली अब्दुस्सलाम त्रेकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष	3-5 मई, 2010
5.	महामान्या बैरोनेस कैथरीन एस्तोन, यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष	22-25 जून, 2010
6.	महामहिम डा. सैयद शम्शुद्दीन होसैनी, ईरान इस्लामी गणराज्य के आर्थिक एवं वित्तीय कार्य मंत्री	7-9 जुलाई, 2010
7.	महामहिम श्री कात्सूया ओकादा, जापान के विदेश मंत्री (दिल्ली में ट्रांजिट हाल्ट)	20 जुलाई, 2010
8.	महामान्या सुश्री हिलैरी रोधाम क्लिंटन, अमरीका की विदेश मंत्री (नई दिल्ली में तकनीकी हाल्ट)	20 जुलाई, 2010
9.	महामहिम श्री जार्ज येओ, सिंगापुर के विदेश मंत्री	31 जुलाई-4 अगस्त 2010
10.	महामान्या श्री पैट्रीशिया इस्पिनोसा कैंटेलानो, मैक्सिको की विदेशी मंत्री	15-17 अगस्त, 2010
11.	महामहिम डा. ममादोऊ टंगारा, गाम्बिया गणराज्य के विदेश मंत्री	16-22 अगस्त, 2010
12.	महामहिम श्री कात्सूया ओकादा, जापान के विदेश मंत्री	21-22 अगस्त, 2010
13.	महामहिम डा. जाल्मई रसूल, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री	24-26 अगस्त, 2010
14.	महामान्या श्रीमती मिशेलिन काल्मी-रे, संघीय काउंसलर, स्विटजरलैंड के संघीय विदेश विभाग की प्रमुख	29-31 अगस्त, 2010
15.	महामहिम श्री रेने कास्ट्रो, कोस्टारिका के विदेश मंत्री	19-20 अक्तूबर, 2010
16.	महामहिम श्री गुईदो वेस्टरविले, जर्मनी के विदेश मंत्री	17-19 अक्तूबर, 2010
17.	महामहिम श्री यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला, ओमान सल्तनत के विदेश मंत्री	20-22 अक्तूबर, 2010
18.	महामहिम श्री एडवर्ड नालबंदियान, आर्मेनिया गणराज्य के विदेश मंत्री	10-13 नवंबर, 2010
19.	महामहिम श्री सर्गेई इवानोव, रूसी परिसंघ की सरकार के उपाध्यक्ष	17-19 नवंबर, 2010
20.	महामहिम श्री सर्गेई वी. लावरोव, रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री	29 नवंबर, 2010
21.	महामहिम श्री हैलेमरियम डेस्लेन, इथोपिया के उप प्रधान मंत्री/ विदेश मंत्री	30 नवंबर से 5 दिसंबर 2010
22.	महामान्या सुश्री लेने इस्पर्सन, डेनमार्क की उप प्रधान मंत्री/विदेश मंत्री	14-16 दिसंबर, 2010

अप्रैल 2010-जनवरी 2011 के दौरान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधान मंत्री स्तरीय निजी/पारगमन यात्राएं

क्र.सं.	गणमान्य अतिथि का नाम और ब्यौरा	तारीख
1.	लेफ्टीनेंट जनरल एम. एस. मेराफहे, बोत्सवाना गणराज्य के उपराष्ट्रपति (चेन्नै में तकनीकी हाल्ट)	20 जुलाई, 2010
2.	महामहिम माहा वजिरालांगकोर्न, थाईलैंड के युवराज (मुम्बई में ठहराव)	25 जुलाई, 2010
3.	महामहिम माहा वजिरालांगकोर्न, थाईलैंड के युवराज (पारगमन) (मुम्बई)	13 अगस्त, 2010
4.	महामहिम श्री जैकब जुमा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति (पारगमन) (मुम्बई)	22 और 26 अगस्त 2010
5.	महामहिम श्री रैफेल कोरिया, इक्वाडोर गणराज्य के राष्ट्रपति (पारगमन)	5-11 सितंबर, 2010

6.	महामहिम श्री इवान गास्परोविच, स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति (पारगमन)	10 सितंबर, 2010
7.	महामहिम श्री पियरे न्कुरिंजिजा, बुरुंडी के राष्ट्रपति (निजी यात्रा)	13-19 सितंबर, 2010
8.	महामहिम श्री मार्कस स्टीफन, संसद सदस्य, नौरू के राष्ट्रपति; और मादाम अमांडा स्टीफन (सीडब्ल्यूजी)	1-5 अक्तूबर, 2010
9.	महामहिम प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स; और कैमिला, डचेज ऑफ कार्नवाल (सीडब्ल्यूजी)	2-5 अक्तूबर, 2010
10.	महामहिम श्री मुहम्मद नशीद, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति (सीडब्ल्यूजी)	2-5 अक्तूबर, 2010
11.	परम माननीय श्री आनंद सत्यानंद, न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ; और श्रीमती सुसान सत्यानंद (सीडब्ल्यूजी)	2-7 अक्तूबर, 2010
12.	मोनाको के महामहिम प्रिंस अल्बर्ट-II (सीडब्ल्यूजी)	3-5 अक्तूबर, 2010
13.	महामहिम श्री टुमास हैंड्रिक इल्विस, एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति (पारगमन)	4 अक्तूबर, 2010
14.	आर्कबिशप ऑफ केंटरबरी (निजी)	9-28 अक्तूबर, 2010
15.	महामहिम श्री मेलेस जेनावी, इथोपिया के प्रधान मंत्री (पारगमन) (कोलकाता)	10 और 13 नवंबर 2010
16.	महामहिम श्री महिन्दा राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति (सीडब्ल्यूजी)	12-14 अक्तूबर, 2010
17.	महामहिम माहा वजिरालांगकोर्न, थाईलैंड के युवराज (निजी)	13 नवंबर, 2010 (गया)
18.	परम माननीय श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, मारीशस गणराज्य के राष्ट्रपति (निजी)	14-28 नवंबर, 2010
19.	महामहिम सर आनंद सत्यानंद, न्यूजीलैंड गवर्नर जनरल	5-10 जनवरी, 2011
20.	महामहिम श्री ऐरेस बोनीफासियो बतिस्ता एली, मोजाम्बिक के प्रधान मंत्री; अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ	5-14 जनवरी, 2011
21.	महामहिम प्रो. गिल्बर्ट बुकेन्या, उगांडा के उपराष्ट्रपति	9-14 जनवरी, 2011
22.	महामहिम श्री बर्नार्ड मकूजा, रवांडा के प्रधान मंत्री	10-15 जनवरी, 2011

अप्रैल-दिसंबर 2010 के दौरान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राएं

क्र.सं.	**पदनाम और ब्यौरा**	**तारीख**
1.	प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका और ब्राजील की यात्रा	10-16 अप्रैल, 2010
2.	सार्क शिखर बैठक के लिए प्रधान मंत्री की भूटान यात्रा	28-30 अप्रैल, 2010
3.	राष्ट्रपति की चीन लोक गणराज्य की यात्रा	26-31 मई, 2010
4.	उप राष्ट्रपति की चेक गणराज्य और क्रोएशिया की यात्रा	6-12 जून, 2010
5.	जी-20 शिखर बैठक के लिए प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा	25-29 जून, 2010
6.	राष्ट्रपति की लाओस और कम्बोडिया की यात्रा	9-18 सितंबर, 2010
7.	उप राष्ट्रपति की ब्रसेल्स यात्रा	3-6 अक्तूबर, 2010
8.	प्रधान मंत्री की जापान, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा	24-30 अक्तूबर, 2010
9.	जी-20 शिखर बैठक के लिए प्रधान मंत्री की कोरिया गणराज्य की यात्रा	10-12 नवंबर, 2010
10.	राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया की यात्रा	21-29 नवंबर, 2010
11.	प्रधान मंत्री की बेल्जियम और जर्मनी की यात्रा	9-11 दिसंबर, 2010

अप्रैल 2010-फरवरी 2011 के दौरान विदेश मंत्री की विदेश यात्राएं

क्र.सं.	पदनाम और ब्यौरा	तारीख
1.	भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा	5-8 अप्रैल, 2010
2.	सार्क बैठक के लिए विदेश मंत्री की भूटान यात्रा	26-30 अप्रैल, 2010
3.	विदेश मंत्री की कजाकिस्तान यात्रा	11-13 मई, 2010
4.	जी-15 विदेश मंत्रियों की बैठक केक लिए विदेश मंत्री की तेहरान यात्रा	15-18 मई, 2010
5.	सामरिक वार्ता के लिए विदेश मंत्री की वाशिंगटन यात्रा	2-6 जून, 2010
6.	एससीओ शिखर बैठक के लिए विदेश मंत्री की ताशकंद यात्रा	10-11 जून, 2010
7.	विदेश मंत्री की सियोल यात्रा	16-19 जून, 2010
8.	विदेश मंत्री की मारीशस, मोजाम्बिक और सेशल्स की यात्रा	2-6 जुलाई, 2010
9.	विदेश मंत्री की पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की यात्रा	14-16 जुलाई, 2010
10.	विदेश मंत्री की अफगानिस्तान यात्रा	19-20 जुलाई, 2010
11.	संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के लिए विदेश मंत्री की न्यूयार्क (अमरीका) की यात्रा	21 सितंबर-2 अक्तूबर 2010
12.	विदेश मंत्री की सिंगापुर यात्रा	26-28 अक्तूबर, 2010
13.	आरआईसी बैठक के लिए विदेश मंत्री की चीन यात्रा	14-16 नवंबर, 2010
14.	विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा	25-28 नवंबर, 2010
15.	विदेश मंत्री की काबुल, अफगानिस्तान की यात्रा	8-9 जनवरी, 2011
16.	द्विपक्षीय बैठकों के लिए विदेश मंत्री की मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया की यात्रा	18-20 जनवरी, 2011
17.	विदेश मंत्री की थिम्पु, भूटान यात्रा	7-9 फरवरी, 2011

अप्रैल 2010 से जनवरी 2011 की अवधि के दौरान प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करने वाले विदेशी राजदूतों/उच्चायुक्तों की सूची

क्र.सं.	देश का नाम	मिशन प्रमुख का नाम	प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करने की तारीख
1.	अल्जीरिया	श्री मोहम्मद-हेसेने एचारिफ	8 अप्रैल, 2010
2.	बुरुंडी	श्री एलोविस रुबूका	8 अप्रैल, 2010
3.	जार्जिया	श्री जुराब कातचकात्विश्विली	8 अप्रैल, 2010
4.	लिथुवानिया	श्री पीट्रास सिमिलुनास	8 अप्रैल, 2010
5.	दक्षिण अफ्रीका	श्री हैरिस म्बुलेलो सिथिम्बिले मजेके	8 अप्रैल, 2010
6.	अल सल्वाडोर	डा. रुबेन आई जमोरा	30 जून, 2010
7.	फिलीपींस	श्री रोनाल्ड बी. अलारे	30 जून, 2010
8.	लाओ पीडीआर	श्री थोंगफान्ह श्याख्योम	30 जून, 2010
9.	कजाकिस्तान	श्री दोउलत ओ कुआनशेव	30 जून, 2010
10.	अफगानिस्तान	डा. नान्गुयालई तारजी	30 जून, 2010

11.	मोनाको (अनिवासी)	श्री मार्को पिसीनीनी	30 जून, 2010
12.	ग्वाटेमाला (अनिवासी)	श्री बायरोन इस्कोबेडो मर्नांडेज	30 जून, 2010
13.	मलावी	डा. श्रीमती क्रिसी च्वांजे मुघोघो	5 अगस्त, 2010
14.	चेक गणराज्य	श्री मिलोस्लाव स्तासेक	5 अगस्त, 2010
15.	रवांडा	श्री विलियम्स न्कुरिंजिजा	5 अगस्त, 2010
16.	निकारागुआ (अनिवासी)	श्री साउल अराना कास्टेलोन	5 अगस्त, 2010
17.	ट्यूनीशिया	श्री मोहम्मद एलियस बेन मारजोक	29 सितंबर, 2010
18.	एपोसटोलिक नन्सीएचर (होली सी)	आर्कविशप साल्वाटोर पेनाशियो	29 सितंबर, 2010
19.	वियतनाम	श्री न्यूजेन थान तान	29 सितंबर, 2010
20.	माली	श्री ओस्मान टांडिया	29 सितंबर, 2010
21.	चिली	श्री क्रिस्टियान बैरोस मेलेट	29 सितंबर, 2010
22.	बोस्निया एवं हर्जेगोविना	प्रो. डा. सीद एब्दिक	29 सितंबर, 2010
23.	सेनेगल	श्री अमादोऊ मोस्तफा दियोफ	29 सितंबर, 2010
24.	अल्बानिया	श्री फैतोस कर्सीकू	18 अक्तूबर, 2010
25.	डेनमार्क	श्री फ्रेडी स्वाने	18 अक्तूबर, 2010
26.	मिस्र	श्री खालिद एली एल्बाक्ली	18 अक्तूबर, 2010
27.	कोरिया गणराज्य	श्री किम जुंग केउन	18 अक्तूबर, 2010
28.	इराक	श्री अहमद तहसिन अहमद बरवारी	18 अक्तूबर, 2010
29.	बेनिन	श्री आंद्रेय सानरा	18 अक्तूबर, 2010
30.	इटली	श्री जियाकोमो सेनफेलिस डी मोंटफोर्टे	18 अक्तूबर, 2010
31.	उक्रेन	श्री ओलेकसांद्र शेवचेन्को	8 दिसंबर, 2010
32.	गाम्बिया	श्री डेम्बो एम. बादजी	8 दिसंबर, 2010
33.	यमन	सुश्री खदीजा रादमान मोहम्मद घेनम	8 दिसंबर, 2010
34.	कनाडा	श्री स्टेवाट बेक	8 दिसंबर, 2010
35.	लीबिया	डा. अली अब्द-अल-अजीज अल-असावी	8 दिसंबर, 2010
36.	नामीबिया	डा. सैमुअल म्बांबो	8 दिसंबर, 2010
37.	सैन मैरिनो (अनिवासी)	श्री लूसियो अमाती	8 दिसंबर, 2010
38.	एस्तोनिया (अनिवासी)	श्री पीप जाहिलो	8 दिसंबर, 2010

अप्रैल-जनवरी, 2011 की अवधि के दौरान भारत से जाने वाले मिशन प्रमुखों की सूची

क्र.सं.	**मिशन प्रमुख का नाम**	**देश का नाम**	**जाने की तारीख**
1.	महामहिम श्री अल्फोंसो सिल्वा	चिली	5 अप्रैल, 2010
2.	महामहिम श्री मोहम्मद घाली उमर	नाइजीरिया	26 अप्रैल, 2010

3.	महामहिम श्री लाय बोन्खम	लाओ पीडीआर	30 अप्रैल, 2010
4.	महामहिम श्री ओले लोंसमन पोल्सेन	डेन्मार्क	8 मई, 2010
5.	महामहिम श्री जोसफ कैरोन	कनाडा	11 जून, 2010
6.	महामहिम श्री मुस्तफा ए.एम. नोमन	यमन	8 जुलाई, 2010
7.	महामहिम श्री वू क्वांग डियेम	वियतनाम	30 जुलाई, 2010
8.	महामहिम श्री पंडित मनीदेव प्रसाद	ट्रिनिडाड एंड टोबैगो	31 जुलाई, 2010
9.	महामहिम श्री एस.के. वलूबिता	जाम्बिया	16 अगस्त, 2010
10.	महामहिम श्री पाइक योंग-सुन	कोरिया गणराज्य	27 अगस्त, 2010
11.	महामहिम श्री मोहम्मद हिगाजी	मिस्र	27 अगस्त, 2010
12.	महामहिम श्री मैतेन एन. कपेवाशा	नामीबिया	30 अगस्त, 2010
13.	महामहिम श्री रोबर्टो टोस्कानो	इटली	1 सितंबर, 2010
14.	महामहिम श्री बिलफ्रेड कनेली	माल्टा	3 सितंबर, 2010
15.	महामहिम श्री मोहम्मद अली दाहेर	जोर्डन	9 सितंबर, 2010
16.	महामहिम श्री लाबड़ी मोखारिक	मोरक्को	17 सितंबर, 2010
17.	महामहिम श्री रूपर्ट होल्बोरो	न्यूजीलैंड	10 दिसंबर, 2010
18.	महामहिम श्री लोन डी ला रीवा	स्पेन	18 दिसंबर, 2010
19.	महामहिम श्री कैल्विन ईयु	सिंगापुर	14 जनवरी, 2011
20.	महामहिम श्री लुई फिलिप कैस्ट्रो मेंडिस	पुर्तगाल	27 जनवरी, 2011

अप्रैल-नवंबर 2010 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देशों ने नई दिल्ली में अपने आवासी मिशन खोले

क्र.सं.	**देश का नाम**
1.	कोस्टारिका
2.	माली
3.	टोगो
4.	बेनिन
5.	जार्जिया

अप्रैल-नवंबर 2010 के दौरान भारत में अनुमोदित विदेशी प्रधान कोंसलावासों/मानद कोंसलावासों की सूची

प्रधान कोंसलावास

1.	स्विटजरलैंड	बैंगलुरु
2.	न्यूजीलैंड	मुम्बई

मानद कोंसलावास

1.	मंगोलिया	बैंगलुरु
2.	आइसलैंड	मुम्बई

3.	केप वर्डे	नई दिल्ली
4.	आयरलैंड	कोलकाता
5.	जार्डन	मुम्बई
6.	चाड	नई दिल्ली
7.	मोजाम्बिक	मुम्बई
8.	घाना	मुम्बई
9.	स्वीडन	मुम्बई
10.	पेरू	बैंगलुरु
11.	कोरिया	मुम्बई
12.	इंडोनेशिया	मुम्बई
13.	मेसेडोनिया	मुम्बई
14.	थाईलैंड	कोलकाता

अप्रैल-2010 से जनवरी 2011 तक भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/केंद्रों में नवसृजित पदों का माहवार ब्यौरा

क्र.सं.	**माह**	**सृजित पदों की संख्या**
1.	अप्रैल	49
2.	मई	17
3.	जून	12
4.	जुलाई	18
5.	अगस्त	17
6.	सितंबर	05
7.	अक्तूबर	11
8.	नवंबर	19
9.	दिसंबर	05
10.	जनवरी	05
	कुल	**158**

■■

कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं 18

पासपोर्ट कार्यालय

भारत वर्तमान में 37 पासपोर्ट कार्यालय और 15 पासपोर्ट संग्रह केन्द्र हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय सिविल उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मशीन-प्रिंटेड और मशीन-रीडेबल पासपोर्ट जारी करते हैं। पासपोर्ट आवेदनों को इलेक्ट्रानिक रूप में स्कैन एवं एकत्र किया जाता है।

पासपोर्टों की बढ़ती मांग

पिछले वर्षों के दौरान जारी किये जाने वाले पासपोर्टों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या में वृद्धि नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है।

	1979-80	1989-90	1999-00	2010
जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या (लाख में)	8.51 लाख	15.58 लाख	25.80 लाख	52.51 लाख
विगत अवधि की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता		83%	66%	104%

37 पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 2009 में जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या 50.28 लाख थी और 6.76 लाख विविध सेवाएं प्रदान की गई थीं। वर्ष 2010 के दौरान जारी किये गए पासपोर्टों की कुल संख्या 52.51 लाख थी। 2009 में कुल 610.10 करोड़ रूपऐ के राजस्व की तुलना में 2010 में सभी पासपोर्ट कार्यालयों से कुल 679.11 करोड़ रूपए का राजस्व सृजित किया गया।

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, जिसका अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1959 में गठन किया गया था, की कुल संख्या 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 2,697 थी। मंत्रालय ने संवर्ग के गठन, शीघ्र प्रौन्नति और प्रोडक्टीविटी-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरूआत से सीपीओ कार्मिकों की सेवा स्थितियों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाये हैं।

पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली

मंत्रालय जनता की आसानी एवं सुविधा के लिये पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल एवं त्वरित बनाने के लिए कई उपाय करता रहा है। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नवत परिभाषित किये गए हैं:

(क) जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और स्पीड पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकरण

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी सेवाओं को आवेदकों के लिए सुभल बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तर पर जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ (डीपीसीएस) खोले गए हैं जहां पर जिलाधीश/पुलिस अधीक्षक पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करते हैं, और जांच और पुलिस सत्यापन के बाद पासपोर्ट जारी करने के लिए सबंधित पासपोर्ट कार्यालय को आवेदन भेज देते हैं। 1,096 स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से भी पासपोर्ट आवेदन प्राप्त किये जाते हैं।

(ख) ऑनलाइन आवेदन

सभी पासपोर्ट कार्यालयों में ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने की शुरूआत की गई है। जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और स्पीड पोस्ट केन्द्रों को ऑनलाइन आवेदन फाइल करने एवं उसे पासपोर्ट कार्यालयों को आंकड़े हस्तांतरित करने की भी अनुमति दी गई है जिसमें शीघ्र पासपोर्ट जारी करने की सुविधा है।

(ग) तत्काल स्कीम

2010 के दौरान, नागरिकों को शीघ्रतापूर्वक पासपोर्ट जारी करने के लिए वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई तत्काल स्कीम के तहत भारत में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 6.72 लाख पासपोर्ट जारी किये गए।

(घ) पासपोर्ट अदालत

पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट आवेदकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवधिक रूप से पासपोर्ट अदालतें आयोजित करते रहे हैं। ये अदालतें पुराने मामलों का निस्तारण करने में काफी उपयोगी रही हैं। लंबित पड़े आवेदनों का निपटारा करने के अभियान में भाग के रूप में जनवरी, फरवरी और मार्च 2011 में पूरे भारत में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा विशेष अदालतें आयोजित की गईं।

(ड.) निष्पादन समीक्षा बैठकें/आरपीओ सम्मेलन

19 नवम्बर और 29 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में मंत्रालय द्वारा 37 पासपोर्ट कार्यालयों के साथ मिल कर निष्पादन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दक्षिण क्षेत्र के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के लिए पासपोर्ट अधिकारियों का सम्मेलन 26 दिसम्बर, 2010 को कोचि में आयोजित किया गया। दक्षिणी क्षेत्र के पासपोर्ट कार्यालयों के लिए 27 दिसम्बर, 2010 को कोच्ची में पासपोर्ट सेवा परियोजना पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

(च) लोक शिकायत निवारण तंत्र

सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाये गए हैं। आवेदकों की सहायता करने एवं साथ ही समस्याओं/शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सुविधा काउंटर एवं हेल्प डेस्क भी खोले गए हैं। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में सीपीवी प्रभाग में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी पासपोर्ट कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सीपी ग्राम वेबसाइट के माध्यम से लोक शिकायत निवारण तंत्र में भाग लेते हैं।

(छ) सूचना का अधिकारी अधिनियम (आरटीआई)

आवेदकों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। इस प्रभाग द्वारा कुल 943 आरटीआई आवेदनों एवं 426 अपीलों का निस्तारण किया गया।

(ज) वेबसाइट

1999 में स्थापित सीपीवी प्रभाग की वेबसाइट http://passport.gov.in को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है ताकि इसे अधिक उपयोग के अनुकूल बनाया जा सके। इसमें पासपोर्ट, स्टेटस इंक्वायरी के बारे में विस्तृत जानकारी होने के साथ-साथ इसका विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के साथ संपर्क है और इसमें डाउनलोडेबल फार्म भी हैं।

अवसंरचना

पूरे भारत में 37 पासपोर्ट कार्यालयों में से 19 सरकार/विदेश मंत्रालय के स्वामित्व वाले भवनों से प्रचालन कर रहे हैं और 18 किराये के भवनों से प्रचालन कर रहे हैं। आठ पासपोर्ट कार्यालय उनके अपने भवनों के निर्माण के लिए पहले से ही उपयुक्त प्लाट खरीद चुके हैं। 2010 के दौरान पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापतनम के लिए भवन पूरा कर लिया गया है। मुंबई में नये कार्यालय भवन का निर्माण 2010 में प्रारंभ किया गया।

नई परियोजनाएं

पासपोर्ट/वीजा जारी करने की प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसे अद्यतन करने की दृष्टि से मंत्रालय ने कई परियाजनाएं शुरू की हैं। ये निम्नलिखित हैं:

(क) पासपोर्टों की सेन्ट्रलाइज्ड प्रिंटिंग

विदेश स्थित 140 गैर-कम्प्यूटरीकृत मिशनों/केन्द्रों के संदर्भ में सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली में मशीन रीडेबल पासपोर्टों (एमआरपी) की सेन्ट्रलाइज्ड प्रिंटिंग के लिए परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के बाद वर्ष के दौरान मंत्रालय ने 92,203 पासपोर्ट जारी किये।

(ख) ई-पासपोर्ट जारी करना

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने 25 जून, 2008 को ई-पासपोर्ट, जिसे बायोमिट्रिक पासपार्ट के नाम से भी जाना जाता है, जारी करने की शुरूआत की एक प्रायोगिक परियोजना के भाग के रूप में सभी राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट अब ई-पासपोर्ट के रूप में जारी किया जा रहा है। इंडिया सेक्युरिटी प्रेस, नासिक द्वारा ई-पासपोर्टों के निर्माण के लिए इसकी प्रचालन प्रणाली सहित आईसीएओ कंप्लायंट इलेक्ट्रानिक कॉनटेक्टलेस इंलेज की खरीद के लिए वैश्विक पीक्यूबी आवेदनों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। संबंधित एजेंसियों से टेकनीकल एवं सेक्युरिटी क्लियरेंस मिल जाने के पश्चात ही ठेका देने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(ग) पासपोर्ट/वीजा कार्य की आउटसोर्सिंग

विदेश स्थित 56 भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने 31 दिसम्बर, 2010 तक पासपोर्ट/वीजा आवेदनों एवं इन्हें संग्रह करने का कार्य आउटसोर्स किया है।

(घ) पासपोर्ट सेवा परियोजना

सितम्बर 2007 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पासपोर्ट सेवा परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य समयबद्ध, पारदर्शी, अधिक अभिगम्य और विश्वसनीय रूप से नागरिकों को पासपोर्ट से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करना है।

इस परियोजना में पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसकेएस) स्थापित करने की योजना है जहां पर आवेदन फार्म की प्रारंभिक जांच, शुल्क प्राप्त करना, दस्तावेजों की स्कैनिंग, फोटो खींचना आदि जैसे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल निजी स्तर के कार्य सेवा प्रदाता टाटा कंसलटैंसी सर्विसेस लिमिटेड द्वारा निष्पादित किये जाएंगे। पासपोर्ट प्रदान करने जैसे संवेदनशील कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही निष्पादित कि जाएंगे। इस परियोजना द्वारा तीन महीने के भीतर पासपोर्ट जारी करने, और जहां पुलिस सत्यापन जरूरी हैं वहां पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो

जाने के पश्चात तीन दिन के भीतर पासपोर्ट जारी जारी किये जाने की उम्मीद है।

तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा एजेंसी (3 पीएए) द्वारा सख्त जांच और प्रायोगिक परीक्षण के पश्चात कर्नाटक में सभी चारों पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को 21 मई, 2010 को लोगों के लिए खोल दिया गया था। 28 मई, 2010 को विदेश मंत्री ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री की मौजूदगी में औपचारिक तौर पर परियोजना (4 पासपोर्ट सेवा केन्द्र) का उद्घाटन किया। 17 अगस्त, 2010 को आरपीओ, चंडीगढ़ के अंतर्गत 3 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में पीएसके प्रचालन में था। पासपोर्ट सेवा परियोजना के सभी सातों प्रायोगिक केन्द्र संतोषजनक ढ़ंग से कार्य करते रहे हैं। 31 दिसम्बर, 2010 को पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में कुल 2,60,420 आवेदन स्वीकार किये गए थे और 1,58,519 पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा परियोजना प्रणाली में भेजे दिए गए थे। बंगलोर और चंडीगढ़ में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राष्ट्रीय काल सेन्टर प्रचालित हैं। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा एजेंसी (3 पीएएए) (मानकीकरण, जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय-एसटीक्यूसी) ने जनवरी 2011 में प्रायोगिक चरण को प्रमाणित किया है। सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार 2011 के दौरान सभी शेष 70 पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थपित कर लिये जाने की संभावना है।

वीजा

(क) विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों द्वारा वीजा जारी किया जाना

पिछले वर्षों की तुलना में हमारे मिशनों एवं केन्द्रों द्वारा वीजा मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है जिसमें जारी करने वाली प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। अधिकांश मिशन और केन्द्र पूरे देश में वीजा या तो उसी दिन मंजूर करते हैं अथवा अधिकतर 48 घंटे के अंदर मंजूर करते हैं। विदेश स्थित 56 भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने 31 दिसम्बर, 2010 तक वीजा आवेदन संग्रहण कार्य को आउटसोर्स कर दिया है।

(ख) सीपीवी प्रभाग द्वारा वीजा जारी किया जाना

सीपीवी प्रभाग ने मार्च 2010 में विदेशी राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों को 7,026 वीजा जारी किये।

(ग) वीजा उन्मुक्ति करार

भारत ने 51 देशों के साथ वीजा उन्मुक्ति करार किये हैं जिनके तहत राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। 2009 में मिस्र और मैसेडोनिया के साथ जिन करारों पर हस्ताक्षर किये गए उन्हें 2010 में क्रियान्वित कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान सीरिया के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

कोंसली मामले

(क) एपोस्टिल अभिसमय परियोजना की शुरूआत

2010 के दौरान मंत्रालय द्वारा 3,15,146 व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक दस्तावेज और 3,04,301 वाणिज्यिक दस्तावेज अभिप्रमाणित किये गए थे। इसके अतिरिक्त विदेश में उपयोग हेतु 1,64,872 दस्तावेज सत्यापित किये गए।

(ख) प्रत्यर्पण मामले और विधिक सहायता

मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए एक विधिक एवं संस्थागत रूप रेखा प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय करारों पर चर्चा करने का सक्रियता से आग्रह करता रहा है। इन कोंसली करारों में प्रत्यर्पण, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता, सिविल सहायता और सजायाफता कैदियों का स्थानांतरण संबंधी संधियां शामिल हैं।

अजरबैजान सरकारी शिष्टमंडल ने प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि और सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि पर बातचीत करने के लिए जून 2010 में नई दिल्ली की यात्रा की। प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत करने के लिए एक भारतीय सरकारी शिष्टमंडल ने नवम्बर 2010 में इंडोनेशिया की यात्रा की और इडोनेशिया के सरकारी शिष्टमंडल ने दिसम्बर 2010 में नई दिल्ली की यात्रा की।

वर्ष के दौरान भारत से प्रत्यर्पण के लिए विदेशों से दस अनुरोध प्राप्त हुए थे और भारत ने प्रत्यर्पण के लिए विदेशों से दो अनुरोध किये।

■■

19 प्रशासन और स्थापना

विदेशों में कुल 176 भारतीय मिशन एवं केंद्र हैं। भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसरण में, जो विदेशों में भारत की राजनयिक मौजूदगी को अनिवार्य बनाते हैं, जाफना एवं हंबानटोटा (दोनों श्रीलंका में) में दो नए केंद्र खोले गए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ग्वाटेमाला शहर में भी मिशन खोला गया।

संसद, संसद सदस्यों से संबंधित मुद्दों तथा राजनीति के गणमान्य व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए मंत्रालय में एक नया संसद एवं अति विशिष्ट व्यक्ति (वीआईपी) प्रभाग सृजित किया गया। संसद एवं वीआईपी प्रभाग मंत्रालय में संसदीय कार्य, संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वसनों के कार्यान्वयन, संसद सदस्यों एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों आदि द्वारा विदेश मंत्री को संबोधित संचारों के प्रत्युत्तरों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत बनाने तथा नियमों, विनियमों एवं कार्यविधियों को सरल बनाने के लिए प्रयास जारी रहे। गृह अवकाश भाड़ा, प्रतिपूरक भत्तों को प्रभावित किए बिना भारत में 8 दिन तक प्रतिपूरक अवकाश बिताने की अनुमति तथा सामूहिक वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी के अंतर्गत बीमा की राशि ₹ 30 लाख से बढ़ाकर ₹ 50 लाख करके अनुदान के एक अतिरिक्त सेट की दृष्टि से भारत आधारित अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अफगानिस्तान में कार्यरत मिशनों/केंद्रों की आवश्यकताओं एवं जरूरतों को हल किया गया। कार्यविधियों का अनुसरण करते हुए, कार्मिकों से संबंधित मुद्दों को सहानुभूतिपूर्वक निपटाने के लिए हर समय प्रयास किए गए।

विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठकों के माध्यम से तथा संशोधित आश्वस्त आजीविका संवर्धन योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया गया।

समूह 'घ' के पदों को छोड़कर मंत्रालय में स्टाफ की कुल संख्या 3,459 है, जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट-VIII** की सारणी में दिया गया है। यह उन लोगों की संख्या है जो विदेशों में स्थित 176 भारतीय मिशनों एवं केंद्रों तथा मुख्यालय में तैनात हैं। ऊपर उल्लिखित संख्या में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय विदेश सेवा 'बी' (आईएफएस बी) तथा दुभाषिया एवं कानूनी तथा संधि (एलएंडटी) संवर्ग के अधिकारी भी शामिल हैं।

आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती समेत सीधी भर्ती (डीआर), विभागीय पदोन्नति (डीपी) तथा सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के माध्यम से 1 अप्रैल-30 नवम्बर 2010 तक मंत्रालय में विभिन्न समूहों में की गई भर्ती का ब्यौरा **परिशिष्ट-IX** में दिया गया है।

परिशिष्ट-X में दी गई सारणी मंत्रालय के अधिकारियों की विदेशी भाषाओं में दक्षता का ब्यौरा प्रदान करती है।

यह मंत्रालय अपने कार्मिकों के बीच लैंगिक समता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनौतीपूर्ण आबंटनों को हाथ में लेने के लिए महिला अधिकारियों को भी समान अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इस समय 18 महिला अधिकारी विदेशों में स्थित विभिन्न मिशनों एवं केंद्रों की प्रमुख हैं। 7 महिला अधिकारी सचिव स्तर पर, 4 महिला अधिकारी अपर सचिव स्तर पर, 26 महिला अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर पर तथा 15 महिला अधिकारी निदेशक स्तर पर हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र तथा इससे संबद्ध संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला अधिकारियों ने महत्वपूर्ण पदों को भी धारण किया है। कार्य स्थल पर महिला अधिकारियों की यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों से निपटने तथा राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं के साथ समन्वय एवं विचार विनिमय करने के लिए सचिव स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में मंत्रालय में यौन उत्पीड़न के विरूद्ध एक शिकायत समिति गठित की गई है।

विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने का सुनिश्चय करना तथा अपने कर्मचारियों में विकलांग व्यक्तियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व रखना मंत्रालय का एक प्रमुख उद्देश्य है।

स्थापना प्रभाग

पिछले वर्षों की तरह, कार्यविधियों को मुख्य धारा में लाने एवं सरल बनाने तथा मुख्यालयों एवं विदेशों में स्थित मिशनों एवं केंद्रों के अधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों को प्रक्रियागत करने की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए ताकि कार्यालय उपकरण, वाहन, फर्नीचर, फर्निशिंग, लेखन सामग्री, कलात्मक वस्तुओं एवं संबद्ध मदों की आपूर्ति एवं रखरखाव की दृष्टि से उनके कामकाज में सुविधा प्रदान की जा सके। बेहतर आवासीय आवास को किराए पर लेना सुकर बनाने के लिए अनेक मिशनों/केंद्रों के लिए किराए की अधिकतम सीमा को संशोधित किया गया तथा संपत्तियों को किराए पर लेने एवं अनुरक्षण संबंधी प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाया गया। मुख्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लाभार्थ, कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित विदेश मंत्रालय के छात्रावास तथा गोल मार्किट स्थित विदेश मंत्रालय

के नए छात्रावास में जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। निवासियों की सुविधा के लिए, इन छात्रावासों के साथ-साथ द्वारिका स्थित विदेश मंत्रालय के आवासीय परिसर में पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन प्रदान किए गए। विदेश मंत्रालय के चाणक्यपुरी स्थित आवासीय परिसर के लिए, नई एवं परिवर्धित एकीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाओं की व्यवस्था की गई तथा निवासियों को अधिक छाया एवं हरित आवरण उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त पेड़ लगाए गए। विशेष रूप से गर्मी के महीनों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए परिसरों में पानी के अतिरिक्त कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका से अनुरोध किया गया है।

उनके कार्य के कार्यात्मक एवं प्रशासनिक पक्षों को मुख्य धारा में लाने के लिए, निरीक्षकों के उच्च स्तरीय दलों ने अशगाबाद, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, ग्वांग्झू, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई, सोफिया तथा ताशकंद स्थित मिशनों/केंद्रों का निरीक्षण किया। पहले किए गए निरीक्षण की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी गई।

निमार्णाधीन नए जवाहर लाल नेहरू भवन के लिए, फर्नीचर, फर्निशिंग, आई सी टी सेवाएं, मशीनें एवं उपकरण तथा कलात्मक वस्तुएं अधिग्रहीत करने के लिए कार्य हाथ में लिया गया। घरदारी, बागवानी एवं लैंड स्केपिंग समेत मशीनरी एवं उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के साथ-साथ परिसरों के रखरखाव के लिए सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा खरीदे गए वाहनों के लिए राजनयिक डिस्काउंट, जिसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया, प्राप्त करने के लिए मैसर्स डेमलेर क्रिशलर एजी, जर्मनी के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। अनेक देशों के साथ भारत के बढ़ते विचार विनिमय के जरिए, परिवहन संबंधी परिवर्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछेक मिशनों के लिए अतिरिक्त वाहन संस्वीकृत किए गए। 25 प्रतिशत की कटौती, जो सितम्बर 2000 से लागू थी, को समाप्त करके विदेश सेवा पर यात्रा के लिए सितम्बर 2010 में दैनिक भत्ते की पूर्ण दरों को बहाल किया गया।

परियोजना प्रभाग

परियोजना प्रभाग विदेश मंत्रालय के कार्यालयों तथा कर्मचारियों के निवासों के प्रयोग के लिए भारत एवं विदेशों में भवनों के निर्माण तथा बनी बनाई संपत्तियों के क्रय के लिए जिम्मेदार है। विदेशों में स्थित केंद्रों के सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य भी परियोजना प्रभाग द्वारा संभाला जाता है। भारत सरकार विदेशों में स्थित 77 केंद्रों में 81 चांसरी भवनों, विदेशों में स्थित 93 केंद्रों में मिशन प्रमुखों के लिए आवासों तथा विदेशों में स्थित 47 केंद्रों में अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 636 आवासों का स्वामी है। इसके अलावा, सरकार 2 केंद्रों पर सांस्कृतिक केंद्रों तथा 1 केंद्र पर संपर्क कार्यालय का भी स्वामी है। इस समय प्रमुख जीर्णोद्धार/ पुनर्विकास परियोजनाओं समेत 53 निर्माण परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

मंत्रालय ने विदेशों में तथा भारत में संपत्तियों के निर्माण एवं बनी बनाई संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दोधारी रणनीति अपनाया है। मंत्रालय अधिक से अधिक केंद्रों पर बनी बनाई संपत्तियां अधिग्रहीत करने के लिए निरंतर एवं जीवंत प्रयास कर रहा है तथा इस संबंध में ऐसे केंद्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां किराएदारी के भुगतान पर व्यय अधिक होता है।

विदेशों में स्थित परियोजनाओं में, बुडापेस्ट, प्राग एवं बेरूत स्थित चांसरी एवं आवासों के लिए निर्माण एवं पुनर्विकास कार्य पूरा हो गया है। बीजिंग, ढाका, इस्लामाबाद, काबुल, काठमांडू और लंदन में चांसरी और/या आवासों के संबंध में बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। निर्माण पूर्व गतिविधियों की प्रगति के आधार पर, उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में अनेक निर्माण परियोजनाएं आरंभ होंगी। इनमें अबूजा, ब्रासिलिया, ताशकंद एवं वारसा स्थित निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

सिडनी, दुबई एवं पारामारिबो स्थित निवासों के लिए तथा हांगकांग स्थित चांसरी के लिए बनी बनाई संपत्तियां अधिग्रहीत की गई हैं। पेरिस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना तथा पेरिस में स्थित दूतावास द्वारा प्रयोग के लिए आवास के लिए बनी बनाई संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव प्रक्रियाकरण के उन्नत चरण पर हैं। ब्रुनेई में चांसरी एवं आवासों के निर्माण के लिए एक भूखण्ड अधिग्रहीत किया गया है। अल्जियर्स, हेलसिंकी, न्यूयार्क, रबात, रोम तथा वाशिंगटन में भूखण्ड/बनी बनाई संपत्तियों के क्रय के लिए अनेक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। ब्रुसेल्स, डब्लिन तथा लंदन में प्रमुख पुनर्विकास प्रस्ताव पूरा होने के नजदीक पहुंच रहे हैं। भारत एवं वियतनाम के बीच संपत्तियों का आदान-प्रदान अंतिम चरणों में है तथा दोनों सरकारों के मध्य समझौता ज्ञापन के अनुसार निकट भविष्य में वियतनाम के दूतावास के लिए नई दिल्ली में एक भूखण्ड के लिए चांसरी एवं दूतावास के आवास का आदान-प्रदान किया जाएगा।

भारत में, विदेश मंत्रालय के कार्यालयों के लिए जवाहर लाल नेहरू भवन का निर्माण पूरा होने के करीब पहुंच रहा है। केनिंग लेन पर ट्रांजिट आवास परियोजना तथा नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान परिसर का कार्य पूरा हो गया है।

2010-2011 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान में पूंजी परिव्यय के अंतर्गत ₹ 375 करोड़ का आंबटन किया गया है। अगले वित्त वर्ष में, विदेशों में चल रही एवं नई निर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ बनी बनाई संपत्तियों के क्रय के लिए ₹ 440 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

कल्याण प्रभाग

कल्याण प्रभाग मंत्रालय के सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य कल्याण से संबंधित कार्य देखता है।

1 शैक्षिक मामले

कल्याण प्रभाग ने केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विदेश मंत्रालय को आंबटित 60 सीटों के विरूद्ध केंद्रीय विद्यालयों में विदेश मंत्रालय के कार्मिकों के बच्चों के दाखिला में सुविधा प्रदान की है।

शैक्षिक वर्ष 2010-2011 के लिए, कल्याण प्रभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ विदेश मंत्रालय को आबंटित सीटों के विरूद्ध भारत में विभिन्न इंजीनियरिग कालेजों में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों एवं केंद्रों में कार्यरत भारत आधारित कार्मिकों के 49 बच्चों के दाखिला में भी सुविधा प्रदान की। इसी तरह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ विदेश मंत्रालय को आबंटित सीटों के विरूद्ध भारत में चिकित्सा कालेजों में तीन बच्चों को दाखिला कराया गया।

3 स्टाफ लाभ निधि

कल्याण प्रभाग मंत्रालय के अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों के अंशदान द्वारा वर्षों से निर्मित स्टाफ लाभ निधि चलाता है। मुख्य रूप से, विदेश मंत्रालय के स्टाफ के सदस्यों की मृत्यु के मामले में दाह संस्कार का खर्च वहन करने के लिए वित्तीय सहायता (₹ 15,000 प्रत्येक मृत्यु के मामले के लिए) देने के वास्ते इस निधि का प्रयोग किया जाता है। कल्याण प्रभाग की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय दंपत्ति संघ (ईएएसए) ने विदेश मंत्रालय के मृत कर्मचारियों के सात आश्रितों में से प्रत्येक को ₹ 70,000 की राशि का चेक प्रदान किया।

4 अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

जब भी किसी स्टाफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, कल्याण प्रभाग परिवार में बचे सदस्यों की वित्तीय स्थिति का जायजा लेता है तथा यह भी जांच करता है कि क्या मृत व्यक्ति की पत्नी/पति या कोई बच्चा समूह 'ग' या 'घ' के किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त है। परिवार की वित्तीय स्थिति के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की सूची कल्याण प्रभाग में रखी जाती है।

5 सहायता अनुदान

कल्याण प्रभाग मंनोरंजन की सुविधाओं एवं खेलकूद के लिए विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों तथा भारत में स्थित सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। यह प्रभाग अंतर-मंत्रालयी क्रीड़ा गतिविधियों की भी व्यवस्था करता है तथा उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

6 झंडा दिवस

कल्याण प्रभाग इन संगठनों के लिए निधियां जुटाने के निमित्त, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस तथा सशस्त्र बल झंडा दिवस जैसे विभिन्न झंडा दिवसों के आयोजन की व्यवस्था करता है।

7 कैंटीन

कल्याण प्रभाग विदेश मंत्रालय की विभागीय कैंटीनों (जो अकबर भवन, साउथ ब्लाक एवं पटियाला हाउस में स्थित हैं) के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

8 सामान्य

कल्याण प्रभाग उस समय विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों में विदेश मंत्रालय के कार्मिकों के बच्चों के दाखिला में सुविधा प्रदान करता है जब उनका मुख्यालय में स्थानांतरण होता है। यह प्रभाग गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, टेलीफोन/मोबाइल फोन कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस तथा इसी तरह की अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में उनकी सहायता करके विदेश मंत्रालय के स्थानांतरित कर्मचारियों को व्यवस्थित होने की प्रक्रिया में भी सहायता प्रदान करता है।

सतर्कता

- 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्याः 140
- 1 अप्रैल-28 दिसम्बर 2010 तक की अवधि के दौरान प्राप्त मामलों की संख्याः 27
- 28 दिसम्बर 2010 तक मामलों की कुल संख्याः (140+27=) 167;
- 28 दिसम्बर, 2010 तक औपचारिक दंड लगाकर बंद किए गए मामलों की संख्याः 23;
- 28 दिसम्बर, 2010 तक वीआरएस, मृत्यु आदि के कारण औपचारिक दंड लगाए बिना बंद किए गए मामलों की संख्याः 59
- 28 दिसम्बर, 2010 तक बंद किए गए मामलों की कुल संख्याः (23+59=) 82;
- 28 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की कुल संख्याः (167-82=) 85

25 अक्तूबर-1 नवम्बर 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। विदेशों में स्थित सभी मिशनों/केंद्रों तथा विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित शपथ ग्रहण की।

अभिलेखागार एवं रिकार्ड प्रबंधन प्रभाग

1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ अवधि के दौरान अभिलेखागार एवं रिकार्ड प्रबंधन प्रभाग ने रिकार्ड प्रबंधन के अपने अधिदेशित कार्य को पूरे अध्यवसाय से निभाया।

रिकार्ड प्रबंधन की निम्नलिखित गतिविधियों को संपन्न किया गयाः

1	रिकार्डों का अंकीयकरण	6695
2	रिकार्डों का विवर्गीकरण	4777
3	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को रिकार्डों का स्थानातंरण	2704
4	संबंधित प्रभागों के मूल्यांकन के दौरान नष्ट करने के लिए संदर्भित किए गए अभिचिन्हित रिकार्ड	1536

■■

सूचना का अधिकार तथा मुख्य लोक सूचना कार्यालय 20

1 अप्रैल-15 दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान मत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कुल 774 आवेदन प्राप्त हुए। ये आवेदन प्रशासन, व्यक्तिगत शिकायत, हजयात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, खाड़ी युद्ध मुआवजा, विदेश नीति तथा आर्थिक मुद्दों इत्यादि से संबंधित थे। इसी अवधि के दौरान इन आवेदनों में से 136 के लिए मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील आवेदन दायर किए गए। इसके अतिरिक्त, सीपीआईओ तथा मंत्रालय के नोडल अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सूचना आयोग में होने वाले सुनवाई में भी भाग लेते रहे हैं। सूचना का अधिकार, 2005 के उपबंधों का पूर्ण तथा समयपूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

■■

21 ई-गवर्नेंस एवं आई.टी. प्रभाग

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों एवं हमलों में बृद्धि के विश्वव्यापी परिदृश्य के मद्देनजर मुख्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रारूप आई टी सुरक्षा नीति के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। इन प्रशिक्षण सत्रों में तकरीबन 300 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आई टी सुरक्षा पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। अब 131 से अधिक मिशनों ने आई एम ए एस साफ्टवेयर का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिसने विदेशों में स्थित इन भारतीय मिशनों द्वारा लेखाओं की सूचना को मुख्य धारा में ला दिया है। ऐसी उम्मीद है कि शेष मिशन निकट भविष्य में इस साफ्टवेयर का उपयोग करने लगेंगे। वर्ष 2010-2011 के दौरान एच.सी.आई., क्वालालम्पुर में वीजा एवं पासपोर्ट सेवा के कार्य का बहिर्स्रोतन पूरा हो गया।

■■

समन्वय 22

समन्वय प्रभाग की तीन शाखाएं हैं अर्थात् संसद अनुभाग, समन्वय अनुभाग और शिक्षा अनुभाग।

संसद अनुभाग

समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय का संसद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु है; इन कार्यों में संसद के प्रश्न-उत्तर, आश्वासन, विदेश संबंधों पर बहस और दोनों सदनों के पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। यह प्रभाग विदेश मामलों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन भी करता है और विदेश मामलों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति तथा अन्य संसदीय समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय करता है।

समन्वय अनुभाग

समन्वय अनुभाग राज्यपालों, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा उपसभापति, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि द्वारा की जाने वाली विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करने के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, यात्रा के राजनैतिक एवं प्रकार्यात्मक औचित्य, की गई बैठकों और संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र की सिफारिश को ध्यान में रखने के बाद ही विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक अनापत्ति प्रदान की जाती है। अप्रैल से नवंबर 2010 के दौरान, समन्वय अनुभाग ने इन दौरों के लिए 2,253 राजनीतिक अनापत्तियां जारी की हैं।

अनुभाग विदेशी गैर-अनुसूचित उड़ानों तथा नौसैनिक जहाजों से यात्राओं के लिए राजनयिक अनापत्तियां प्रदान करने से संबंधित कार्यों को भी देखता है। चालू वर्ष के दौरान, प्रभाग ने विदेशी गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए 917 अनापत्तियां जारी कीं।

समन्वय अनुभाग ने विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भारतीय खिलाड़ियों और खेल-कूद टीमों की भागीदारी के लिए और विदेशी खिलाड़ियों/टीमों की भारत यात्रा के लिए बड़ी संख्या में अनुमोदन प्रदान करने की कार्रवाई की थी।

यह अनुभाग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत एमेच्योर डब्ल्यू/टी लाइसेंस प्रदान करने, विदेशों में स्थित भारत विदेश सांस्कृतिक मैत्री और सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान के वास्ते अनापत्ति देने के अनुरोधों की भी जांच करता है।

समन्वय अनुभाग विदेशी राष्ट्रिकों को पद्म अवार्ड प्रदान करने से संबंधित कार्यों का समन्वय करता है। समन्वय अनुभाग विदेश स्थित भारतीय मिशनों/कंद्रों से नामांकन प्राप्त करता है और मंत्रालय की सिफारिशों से गृह मंत्रालय को अवगत कराता है।

समन्वय प्रभाग द्वारा मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई), सदभावना दिवस (20 अगस्त) और कौमी एकता सप्ताह/दिवस (19-25 नवंबर) भी मनाया गया; मुख्यालय में और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों, दोनों स्थानों पर अधिकारियों को शपथ दिलाई गयी।

शिक्षा अनुभाग

शिक्षा अनुभाग इस मंत्रालय को क्रमशः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित सीटों पर स्व-वित्तपोषित विदेशी छात्र योजना के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस/बीई/बी.फार्मेसी और भारत की विभिन्न संस्थाओं से डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 63 मित्र, पड़ोसी एवं विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करता है। शिक्षा अनुभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं और शोध पाठ्यक्रमों में चयनात्मक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप सहित इंजीनियरी, चिकित्सा, प्रबंधन, अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं परा-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान करने की भी कार्रवाई की गई।

शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 के लिए शिक्षा अनुभाग ने एमबीबीएस/बीडीएस और बीई/बी फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्रमशः 95 और 104 आवेदन प्राप्त किए और उन पर कार्रवाई की। इसके अलावा, 2010 (जनवरी-नवंबर) के दौरान भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 989 विदेशी आवेदकों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान की गई।

■■

23 विदेश प्रचार

भारत आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों की प्रेस कवरेज

भारत आने वाले राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों (एचओएस/जी) के साथ आने वाले विदेशी मीडिया के प्रतिनिधिमंडलों तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधान मंत्री के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले भारतीय मीडिया के प्रतिनिधिमंडलों को संभारतंत्रीय एवं संपर्क सहायता प्रदान करने की दृष्टि से प्रेस सुविधा कार्य इस प्रभाग की गतिविधियों का एक प्रमुख अंग है। वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत की सशक्त भागीदारी में उच्च स्तरीय दौरों की श्रृंखला के साथ एक उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला। उनमें से उल्लेखनीय थेः यूएसए, आरओके, आइसलैंड, जर्मनी, तुर्की, फिलीस्तीन, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका एवं मोजाम्बिक के राष्ट्रपतियों का दौरा; भूटान के नरेश, बेल्जियम के राजकुमार का दौरा; यूके, बांगलादेश, चीन, मलेशिया, पोलैंड एवं भूटान के प्रधान मंत्रियों और बहरीन, नार्वे, आस्ट्रेलिया अर्मेनिया, मैक्सिको, गाम्बिया, जापान, अफगानिस्तान एवं ओमान के विदेश मंत्रियों का दौरा। विदेश प्रचार प्रभाग ने भारत आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त प्रेस सम्मेलनों की व्यवस्था की तथा इन दौरों के उपयुक्त कवरेज के लिए भारत में आधारित अतिथि मीडिया एवं विदेशी मीडिया की सहायता की।

भारत के गणमान्य लोगों के विदेश दौरों की प्रेस कवरेज

इस प्रभाग द्वारा दौरों का उपयुक्त मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले मीडिया के लिए सभी संभारतंत्रीय व्यवस्थाएं की गईं जिसमें पूर्णतः सुसज्जित मीडिया केंद्रों की स्थापना एवं प्रचालन, मीडिया ब्रीफिंग एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान राष्ट्रपति के चीन, लाओ पीडीआर, कम्बोडिया, संयुक्त अरब अमीरात एवं सीरिया के उनके दौरे पर, उपराष्ट्रपति के चेक गणराज्य, क्रोएशिया एवं बेल्जियम के दौरे पर, प्रधान मंत्री के यूएसए, ब्राजील, भूटान, कनाडा, जापान, मलेशिया, वियतनाम, आर ओ के (दक्षिण कोरिया), बेल्जियम एवं जर्मनी के दौरे पर तथा विदेश मंत्री के पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, जापान, मोजाम्बिक, मारीशस, कुवैत, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के दौरे पर मीडिया का प्रतिनिधिमंडल उनके साथ गया।

सरकारी प्रवक्ता का कार्यालय

सरकारी प्रवक्ता के कार्यालय ने भारत की विदेश नीति के संचालन से संबंधित रोजमर्रा के घटनाक्रमों पर सूचना के प्रसार के लिए केंद्र के रूप में काम किया। इस कार्यालय ने प्रमुख घटनाक्रमों पर नियमित ब्रीफिंग का आयोजन करके पूरे वर्ष के दौरान भारतीय एवं विदेशी मीडिया के साथ संपर्क स्थापित किया जिनका भारत की विदेश नीति, आवक एवं जावक उच्च स्तरीय दौरों तथा रोजमर्रा के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से सरोकार था। वर्ष के दौरान (नवम्बर 2010 तक), इस प्रभाग द्वारा विभिन्न मुद्दों पर 80 प्रेस विज्ञप्ति, 68 प्रेस वार्ता, 76 संयुक्त प्रेस वक्तव्य तथा 74 मीडिया एडवाइजरी जारी की गई।

इसके अलावा, मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को पृष्ठभूमि संबंधी ब्रीफिंग उपलब्ध कराकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण एवं परिपेक्ष्य का संप्रेषण करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के साथ प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव तथा अन्य गणमान्य लोगों के साक्षात्कार की व्यवस्था की गई। इन साक्षात्कारों की प्रतिलिपियों को शीघ्रता से मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया।

विदेश मंत्रालय की नई वेबसाइट

विदेश मंत्रालय की पूर्णतः पुनःअभिकल्पित वेबसाइट लांच की गई। यह वेबसाइट देखने एवं महसूस करने में बिल्कुल नई है, प्रयोक्ता अनुकूल है, तथा इसका उद्देश्य विश्व को आधुनिक भारत का चेहरा प्रदर्शित करना है। विदेश मंत्रालय की नव गठित वेबसाइट का औपचारिक उद्घाटन दिसम्बर 2010 में विदेश सचिव द्वारा किया गया। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने इस प्रभाग द्वारा सूचना के प्रसार के लिए एक उपयोगी माध्यम के रूप में काम करना जारी रखा। प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री एवं विदेश सचिव द्वारा विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाषण/साक्षात्कार/वक्तव्य तथा सरकारी प्रवक्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति एवं वार्ता के साथ वेबसाइट के वक्तव्य खंड को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। इस वेबसाइट को भारत के अंदर एवं बाहर भी बड़े पैमाने पर अक्सेस किया जाता है, तथा इसमें विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों तथा विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटों के हाइपर लिंक हैं।

हिन्दी, ऊर्दू एवं अरबी वेबसाइट

वेबसाइट के हिन्दी खंड को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। आम जनता के साथ-साथ भारतीय मीडिया के प्रतिनिधि

भी हिन्दी वेबसाइट की सराहना कर रहे हैं। विदेश प्रचार प्रभाग ने अब एएनआई के साथ वेबसाइट के ऊर्दू एवं अरबी में अनुवाद की भी व्यवस्था की है। इन साइटों को भारत में एवं हमारे पड़ोसी देशों में ऊर्दू मीडिया के साथ-साथ अरबी भाषी देशों द्वारा बड़े पैमाने पर अक्सेस किया जाता है।

विदेश प्रचार प्रभाग का सूचना पट

इस प्रभाग ने विदेशों में स्थित मिशनों/केंद्रों को भारत के विभिन्न पहलुओं पर व्यावसायिक रूप से लिखित फीचर लेख उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सूचना पट का उपयोग करना जारी रखा। हमारे मिशनों/केंद्रों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों से रूचि के निबंधों को भी दैनिक आधार पर सूचना पट पर अपलोड किया गया।

नई पहलः विदेश मंत्रालय का वेब पोर्टल

विदेश प्रचार प्रभाग विदेशों में स्थित मिशनों एवं केंद्रों की वेबसाइटों समेत विदेश मंत्रालय की सभी वेबसाइटों के लिए एक सामान्य टेम्पलेट (होम पेज) रखने के उद्देश्य से अब एक एकीकृत एम ई ए वेब पोर्टल विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। विकास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपर सचिव (एडी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। निविदाओं के लिए आमंत्रण जारी किया गया है तथा कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भारत-अफ्रीका सम्पर्क वेबसाइट

विदेश प्रचार प्रभाग और आईएएनएस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत-अफ्रीका सम्पर्क वेबसाइट भारत एवं अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। इस वेबसाइट पर विकास सहयोग पर विशेष बल के साथ भारत एवं अफ्रीका पर समाचार, लेख एवं आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस वेबसाइट को www.indiaafricaconnect.in पर अक्सेस किया जा सकता है तथा इसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

भारत में आधारित विदेशी मीडिया को संभारतंत्रीय सहायता

भारत में आधारित 300 से अधिक विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों को रूचि के विभिन्न मुद्दों पर संगत सूचनाओं के प्रावधान के साथ-साथ प्रत्यय दस्तावेजों, वीजा एवं निवास परमिट में सहायता के माध्यम से आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे अबाध रूप से काम कर सकें। वर्ष के दौरान इन पत्रकारों को वीजा विस्तार और/या प्रत्यायन की सुविधाएं प्रदान की गईं।

विदेशी पत्रकारों द्वारा परिचय यात्राएं

विदेशी पत्रकारों द्वारा भारत की परिचय यात्राएं भारत के विभिन्न आयामों से उनको अवगत कराने के लिए इस प्रभाग के प्रयासों का एक प्रमुख हिस्सा है। यह भारत की राजनीति, विदेश नीति की प्राथमिकताओं, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रत्यक्ष जानकारी के माध्यम से बेहतर समझ प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाती है। विदेश प्रचार प्रभाग ने भारत में महत्वपूर्ण संस्थाओं एवं उत्कृष्टता केंद्रों के ऐसे अनेक दौरों का आयोजन किया। मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, व्यावसायिक प्रतिनिधियों तथा भारतीय मीडिया समेत राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकों का भी आयोजन किया गया। भारत के पड़ोसी देशों पर विशेष बल के साथ अब तक 100 से अधिक विदेशी पत्रकारों की मेजबानी की गई है। इनमें चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मध्य एशियाई देशों, जापान एवं कोरिया तथा एंग्लोफोन अफ्रीकी देशों के वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, नेपाल, तथा सार्क एवं आसियान देशों के महिला पत्रकार शामिल थे। वर्ष के दौरान पूर्वी एशियाई देशों, इब्सा, एवं ब्रिक देशों से ऐसे और दौरों की संभावना है।

प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन एवं विशेष कार्यक्रम

विदेश प्रचार प्रभाग पड़ोसी देशों से मीडिया के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य घटनाओं का भी आयोजन करता है। संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों की सिफारिशों के आधार पर, विदेश प्रचार प्रभाग ने 30 अफगानी पत्रकारों (15 प्रिंट, 10 श्रव्य दृश्य, और 5 रेडियो) के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में एक टेलर मेड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। आई आई एम सी (भारतीय जन संचार संस्थान) में म्यांमार के 25 पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, अतिथि पत्रकारों ने वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों एवं भारतीय मीडिया के साथ मुलाकात की तथा ऐतिहासिक स्थलों एवं उत्कृष्टता के केंद्रों का भी दौरा किया। यह प्रभाग आपसी समझ बढ़ाने एवं सूचना अंतराल को पाटने के लिए चुनिंदा अफ्रीकी देशों में संवाददाताओं के नियोजन के लिए पी टी आई एवं आई ए एन एस को सहायता भी प्रदान कर रहा है।

वृत्त चित्र एवं फिल्में

इस प्रभाग के कार्य का एक प्रमुख क्षेत्र विदेशी श्रव्य दृश्य एजेंसियों द्वारा निर्मित वृत्त चित्रों की प्रोसेसिंग करना एवं मंजूरी प्रदान करना है। अप्रैल से नवम्बर 2010 की अवधि के दौरान पर्यटन, वन्य जीव एवं आर्थिक गतिविधि समेत विभिन्न विषयों पर विदेशी निर्माण गृहों एवं अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों से भारत में वृत्त चित्रों की शूटिंग के लिए 210 से अधिक प्रस्तावों को प्रोसेस किया गया एवं अनुमोदित किया गया।

प्रशासन/गृह व्यवस्था

कार्य करने के सामान्य परिवेश में सुधार करने तथा सौंदर्य की दृष्टि से कार्यालय स्थान के मनोहारी स्वरूप में वृद्धि करने के लिए इस प्रभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हरे बरे पौधों के साथ-साथ चुनिंदा ऐतिहासिक चित्रों के प्रदर्शन ने इस क्षेत्र को और भी प्रदर्शनीय एवं आकर्षक बना दिया है।

■■

24 लोक राजनय

विदेश मंत्रालय (एमईए) के लोक राजनय (पीडी) प्रभाग का गठन 2006 में हुआ। इस प्रभाग के अधिदेश में अन्य बातों के साथ प्रिंट एवं श्रव्य दृश्य सामग्री तैयार करना शामिल है जो अधिक प्रभावी ढंग से भारत के विविध पक्षों को परिलक्षित करने में हमारे मिशनों को समर्थ बनाते हैं। यह प्रभाग व्यापक श्रेणी की आउटरिच गतिविधियों का भी आयोजन करता है जिनका उद्देश्य भारत के अंदर एवं बाहर भी भारत एवं इसकी विदेश नीति से संबंधित चिंताओं के प्रति अधिक समझ पैदा करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रभाग हमारी चिंताओं से संबंधित विषयों पर सेमिनार, सम्मेलन एवं विशेष परियोजनाएं आयोजित करने के लिए प्रमुख घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, विचार केंद्रों, अनुसंधान संगठनों एवं वाणिज्य चेम्बर तथा निजी संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग विभिन्न देशों एवं संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी भी करता है ताकि उनको भारत का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जा सके। विशिष्ट आउटरिच गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आउटारीच कार्यकलाप

आगन्तुकों की मेजबानी

प्रमुख निर्णयकर्ताओं एवं प्रभाव उत्पन्न करने वालों को भारत की बेहतर समझ प्रदान करने के उद्देश्य से हम अपने आगन्तुक कार्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं। एक विशिष्ट मेन्यू में शामिल हैं - अनेक सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) या फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) जैसे प्रमुख वाणिज्य चेम्बर में अर्थव्यस्था पर ब्रीफिंग, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (इडसा), प्रेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान (ओ आर एफ) जैसे विचार केंद्रों में विचार विनिमय सत्र, जो भारत के पड़ोसी देशों में सुरक्षा के माहौल की व्याख्या करते हैं तथा दिल्ली के बाहर किसी बड़े शहर का दौरा। सामान्यतया संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के दौरे का आयोजन उस समय किया जाता है जब संसद चल रहा होता है ताकि आगंतुक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को काम करते हुए देख सकें। आगंतुकों द्वारा व्यक्त की गई रूचि के आधार पर जलवायु परिवर्तन, कृषि, लघु उद्योग, सूक्ष्म वित्त, इलेक्ट्रानिक अभिशासन, या टेली मेडिसीन जैसे विषयों को भी शामिल किया जाता है। लोक राजनय प्रभाग द्वारा जिन आगंतुकों की मेजबानी की गई उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- एशियाई सिनेमा के संवर्धन के लिए नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18-22 अगस्त, 2010 तक प्रख्यात फिल्म पत्रकारों एवं आलोचकों के 7-सदस्यीय दल का दौरा;
- 22-28 अगस्त, 2010 तक कम्बोडिया की राष्ट्रीय सभा से बहुदलीय संसदीय शिष्टमंडल का दौरा;
- 11-16 सितम्बर, 2010 तक जर्मन विदेशी संबंध परिषद के अनुसंधान संस्थान (डीजीएपी) के निदेशक डा. ईबरहार्ड सेंडसिनेदर ओट्टो - वोल्फ का दौरा;
- 26 सितम्बर-2 अक्तूबर 2010 तक भारतीय संसद के शिष्टमंडल का सात-सदस्यीय यूनाइटेड किंगडम लिबरल लोकतांत्रिक मैत्री दौरा;
- 13-18 नवम्बर, 2010 तक संसद के उपाध्यक्ष श्री एल्गिस कसेटा के नेतृत्व में लिथुवानिया के 4 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल का दौरा;
- 21-27 सितम्बर, 2010 तक युवा संविधान सभा (सीए) के सदस्यों के 11-सदस्यीय नेपाली संसदीय शिष्टमंडल का दौरा;
- 28 नवम्बर-5 दिसम्बर 2010 तक आस्ट्रेलिया के 7 सदस्यीय युवा राजनीतिक नेताओं का दौरा; और
- पीबीडी 2011 (प्रवासी भारतीय दिवस 2011) के सिलसिले में 6-10 जनवरी, 2011 की अवधि के दौरान 27 पी आई ओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) पत्रकारों का दौरा। सम्मेलन के दौरान पत्रकारों ने कार्यशालाओं एवं सत्रों में भाग लिया तथा उनको एक दिन की यात्रा के लिए आगरा भी ले जाया गया।
- 23-29 जनवरी, 2011 तक न्यूयार्क से कैरीकॉम (कैरेबियाई समुदाय) देशों के स्थायी प्रतिनिधियों (पीआर) के 14-सदस्यीय शिष्टमंडल का दौरा। यात्रा के दौरान, इस शिष्टमंडल ने विदेश मंत्री (ईएएम) तथा पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश से भेंट की। सचिव (पश्चिम) तथा महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (डीजी, आईसीसीआर) ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। इस शिष्टमंडल ने मुम्बई एवं आगरा का दौरा भी किया।
- यूएस कांग्रेस स्टाफ से बना एक 7-सदस्यीय शिष्टमंडल 19-27 फरवरी, 2011 तक भारत के दौरे पर आएगा तथा एक अन्य समूह भी 19-27 मार्च, 2011 तक बैक-

टू-बैक दौरे पर आएगा। इन दौरों के दौरान, ऐसी संभावना है कि ये शिष्टमंडल पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कामकाज देखने वाले विचार केंद्रों एवं संस्थाओं के साथ बैठकों का आयोजन करने के अलावा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी भेंट करेंगे।

- 'भावी कार्यक्रम के लिए अगुआ' के अंग के रूप में अफ्रीकी देशों के 22 संसद सदस्य मार्च 2011 में भारत के दौरे पर आएंगे।

विदेशों के दौरे

लोक राजनय प्रभाग के उद्देश्यों से तालमेल रखने वाले कार्यक्रमों के लिए इस प्रभाग ने अनेक विदेशी दौरों के लिए भी सहायता प्रदान की है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- 26-27 अप्रैल, 2010 को हैफा विश्वविद्यालय के एशियाई अध्ययन विभाग के 9वें वार्षिक सम्मेलन के अंग के रूप में डांडी मार्च के 80 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित महात्मा गांधी पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए प्रो. रामचन्द्र गुहा का इजराइल का दौरा;
- 6-11 दिसम्बर, 2010 तक ओकाजाकी संस्थान, टोकियो के साथ विचार विनिमय के लिए भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान (यूएसआई) के निदेशक के नेतृत्व में 4 सदस्यीय शिष्टमंडल का जापान दौरा;
- 16 नवम्बर, 2010 को ब्यूनस आयर्स में एक व्यावसायिक सम्मेलन में बोलने के लिए सी आई आई के पूर्व मुख्य सलाहकार श्री तरूण दास का दौरा; और
- लंदन और बर्मिघम में 29 नवम्बर, 2010 को सीआईआई, यू के द्वारा आयोजित समावेशी विकास पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए योजना आयोग में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कार्यक्रम के प्रमुख डा. मिहिर शाह (सदस्य, योजना आयोग) और स्व नियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राहुल बरकातकी का दौरा।

सेमिनार/द्विपक्षीय वार्ता/सम्मेलन/पुस्तक प्रदर्शनी/फिल्मों की स्क्रीनिंग/फिल्म महोत्सव

- 8-10 अप्रैल, 2010 तक शिलांग में 'फ्राम लैंड लॉक्ड टू लैंड लिंक्ड: नार्थ ईस्ट इंडिया इन बिम्स्टेक' शीर्षक से दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया।
- इंडोनेशिया गंणतंत्र के विदेश मंत्रालय, आसियान सचिवालय, जकार्ता तथा उडायन विश्वविद्यालय, बाली के साथ मिलकर 3-5 मई, 2010 तक जकार्ता और बाली में आउटरिच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई;
- 24-25 मई, 2010 को सियोल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईई आर) द्वारा आयोजित 9वां वार्षिक भारत - कोरिया वार्ता;
- 'सीमा पारीय व्यापार एवं वाणिज्य में सुविधा प्रदान करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के साथ संपर्क की भूमिका' पर संगोष्ठी जिसे 31 जुलाई, 2010 को गुवाहाटी में 'उद्योग शिक्षाविद व्याख्यान माला' के उनके कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय वाणिज्य चेम्बर, कोलकाता द्वारा आयोजित किया गया;
- 10 सितम्बर, 2010 को 'बंगलौर-चेन्नई-वियतनाम- हांगकांग वाणिज्यिक कोरीडोर' पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन;
- 17 सितम्बर' 2010 को 'भारत एवं बेलारूस की महान सांस्कृतिक विरासत' पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन जो रोयरिच संधि, मिन्स्क की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित था;
- 17-21 सितम्बर, 2010 तक ताराग्राम यात्रा 2010 - 'हरी भरी अर्थव्यवस्थाओं की दिशा में - लोगों एवं हमारे ग्रह के लिए परिमाणनीय समाधान' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन;
- खाड़ी अनुसंधान वेंद्र, दुबई के साथ मिलकर 16-17 अक्तूबर, 2010 को रियाद में भारत-खाड़ी साझेदारी परियोजना की तीसरी बैठक;
- अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, गोवा में 22-25 नवम्बर, 2010 तक 'दक्षिण एशिया में मीडिया में महिलाएं: विकास में साझेदार' पर 7वीं वार्षिक दक्षिण एशियाई मीडिया शिखर बैठक 2010;
- ईरान की प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक तेहरान पुस्तक मेले में भागीदारी;
- 23वां तूरीन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जिसमें भारत 'अतिथि देश' था;
- 3 नवम्बर, 2010 को राजीव कुमार और संतोष कुमार द्वारा लिखित पुस्तक 'राष्ट्र के हित में: भारत के लिए एक सामरिक विदेश नीति' का विमोचन;
- 2010 में इस प्रभाग द्वारा प्रायोजित भारत के आर्थिक उत्थान पर 24 मिनट के वृत्त चित्र को जनवरी 2011 में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा चलाए जा रहे भारतीय समावेशी अभियान के अंग के रूप में डावोस में विश्व आर्थिक मंच में दिखाया गया;
- 2010 में इस प्रभाग द्वारा प्रायोजित भारत में ब्लाइंड क्रिकेट पर 'यह क्रिकेट है, नहीं!!! शीर्षक से 30 मिनट के एक वृत्त चित्र को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 8 फरवरी 2010 को फिल्म महोत्सव 'परसिस्टेंस रेजिस्टेंस 2011' के अंग के रूप में दिखाया गया;
- लोक राजनय प्रभाग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ, यूके के साथ मिलकर भारत मीडिया केंद्र, वेस्टमिनिस्टर विश्वविद्यालय, लंदन में 18 फरवरी, 2011 को 'उभरती

मृदु शक्ति के रूप में भारत' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संयुक्त सचिव (पीडी) ने 19 फरवरी, 2011 को आक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को संबोधित भी किया;

- 4-6 मार्च, 2011 तक वाराणसी में भारत-नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। नेपाल से 15 प्रतिनिधि तथा भारत से भी इतने ही प्रतिनिधि सेमिनार में भाग लेंगे;
- भारतीय विश्व मामले परिषद और लोक राजनय प्रभाग के साथ मिलकर मार्च 2011 में नई दिल्ली में यूएनएससी सुधार पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा;
- भारतीय दूतावास, ब्रासिलिया ने हिन्दी, तमिल, मलयालम तथा बंग्ला भाषाओं में समकालीन भारतीय फिल्मों पर दो फिल्म महोत्सवों का आयोजन किया। महोत्सव के दौरान कुल मिलाकर 31 फिल्में दिखाई गईं - 19 फिल्में रायो डि जेनेरियो में तथा 12 फिल्में ब्रासिलिया में।

इस प्रभाग ने फिल्म महोत्सवों के आयोजन में अनेक भारतीय मिशनों/केंद्रों की सहायता की जैसे कि अल्जीयर्स, ब्रासिलिया, साओपोलो, मैक्सिको शहर, क्वालालम्पुर तथा अनेक अन्य राजधानियों में।

अनेक मिशनों एवं केंद्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। कार्यक्रमों में व्याख्यान, सेमिनार, सम्मेलन, फोटो प्रदर्शनी, फिल्म महोत्सव, स्कूली बच्चों के लिए वाद द्व विवाद प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक शो शामिल थे।

इस प्रभाग ने पैनल चर्चा के साथ निम्नलिखित वृत्त चित्रों का भी प्रदर्शन किया:

- 1 अक्तूबर, 2010 को श्रीमती अर्पणा श्रीवास्तव रेड्डी द्वारा हमसायेः दो राष्ट्र, दो पड़ोसी। पैनल में विशेष सचिव (पीडी) तथा अफगानिस्तान के राजदूत शामिल थे;
- 11 अक्तूबर, 2010 को श्री रश्मि लूथरा द्वारा 'इमर्जिंग टाइजः इंडिया एंड सेंट्रल एशिया'। पैनल में सचिव (पूर्व) तथा भारत - सीआईएस चेम्बर ऑफ कॉमर्स की महासचिव डा. ज्योत्सना चौधरी शामिल थे;
- 28 अक्तूबर, 2010 को श्रीमती ज्योत्सना सूद द्वारा 'गॉड्स चूजन वन'। पैनल में संसद सदस्य श्री ऑस्कर फर्नांडीज, दिल्ली के आर्चबिशप डा. विन्सेंट माइकल कोंसीसाओ तथा फ्रांस के राजदूत महामहिम श्री जेरोम बोनाफोंट शामिल थे;
- 30 नवम्बर' 2010 को श्रीमती कामना प्रसाद द्वारा निर्मित 'उर्दू एंड मॉडर्न इंडिया'। पैनल में कारपोरेट मामले एवं अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद तथा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री अशोक वाजपेयी शामिल थे;
- ब्रासिलिया में इब्सा शिखर बैठक में वृत्त चित्र 'इब्साः ए पीपुल्स प्रोजेक्ट' के संक्षिप्त संस्करण को दिखाया गया।

विशिष्ट व्याख्यान माला

विदेश मंत्रालय की विशिष्ट व्याख्यान माला के अंतर्गत इस प्रभाग ने विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में व्याख्यानों का आयोजन किया है जिन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से बहुत उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर मिला है। अप्रैल 2010 से अब तक दिए गए व्याख्यानों की सूची नीचे दी गई है:

इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है तथा त्रिपुरा विश्वविद्यालय, महाराजा कालेज (कोचीन), रावेनशा विश्वविद्यालय (कटक), केरल विश्वविद्यालय, एच एस गौड़ विश्वविद्यालय (सागर), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (रोहतक), कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर) आदि समेत पूरे देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं।

श्रव्य दृश्य प्रचार

प्रभाग ने भारत के विविध पक्षों को परिलक्षित करने वाले निम्नलिखित वृत्त चित्रों को पूरा किया:

- **एनीमेयर - ए डिजीटल स्टोरी:** एक्सप्लोर्स इंडिया ड्रामैटिक इंट्री इन्टु दि पल्सेटिंग अरेना ऑफ एनिमेशन, ब्रिगिंग आउट दि स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल एक्यूमेन ऑफ दि की प्लेयर्स।
- **बांडिंग विद अफ्रीका:** एक्सप्लोर्स दि एवर ग्रोइंग रिलेशन्स ऑफ इंडिया विद कांटिनेंटल अफ्रीका।
- **मार्शल ट्रेडिसन्स ऑफ दि इंडियन आर्मी:** यह दर्शाता है कि आधुनिकीकरण की अपरिहार्य प्रक्रिया से सेना कैसे तालमेल बिठाने का प्रयास करती है तथा अपनी अनोखी एवं विशिष्ट परंपराओं को बनाए रखने की प्रचुर प्रतिबद्धता के साथ आधुनिक युद्धकला की चुनौतियों को दर्शाता है।
- **उर्दू एंड मार्डन इंडिया (उर्दू):** आधुनिक भारत में उर्दू भाषा की प्रगति को चित्रित करता है।
- ए परफेक्ट ब्लेंडः दार्जिलिंग चाय पर एक फिल्म
- **हमसाए - टू नेशन्स, टू नाइवर्स:** भारत एवं अफगानिस्तान यानी दो प्रचीन संस्कृतियों की कहानी जो मैत्री के असंख्य धागों के माध्यम से एक दूसरे से बंधे हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
- **इंडिया बाई च्वाइस:** विदेशी हमेशा से आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की ओर आकृष्ट होते रहे हैं, परंतु आज भारत की तेजी से उत्थान कर रही अर्थव्यवस्था यहां स्थाई निवास स्थापित करने के लिए प्रवासियों को आकर्षित कर रही है।

अप्रैल 2010 से आगे दिए गए व्याख्यानों की सूची

क्र.	तिथि	विश्वविद्यालय	वक्ता	विषय
1	23 अप्रैल, 2010	हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय	राजदूत श्री के. वी. राजन	एशियाई शताब्दी के लिए दक्षिण एशियाई विकास एवं निहितार्थ
2	1 मई, 2010	सिक्किम विश्वविद्यालय	राजदूत श्री राजीव सीकरी	भारत की पूरब की ओर देखो नीति
3	13 मई, 2010	मणिपुर विश्वविद्यालय	राजदूत श्री राजीव भाटिया	भारत के साथ साझेदारी के माध्यम से अफ्रीका की चुनौतियों का समाधान
4	16 जुलाई, 2010	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	राजदूत श्री आर. एम. अम्यंकर	भारत और पश्चिम एशिया
5	23 अगस्त, 2010	बंगलौर विश्वविद्यालय	राजदूत श्री सी. दासगुप्ता	भारत का जलवायु परिवर्तन संबंधी राजनय
6	25 अगस्त, 2010	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	राजदूत श्री एस. टी. देवारे	भारत की पूरब की ओर देखो नीति
7	27 अगस्त, 2010	तेजपुर विश्वविद्यालय	राजदूत श्री एस. टी. देवारे	भारत की पूरब की ओर देखो नीति
8	30 अगस्त, 2010	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	राजदूत श्री एस. टी. देवारे	भारत की पूरब की ओर देखो नीति
9	30 अगस्त, 2010	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद	राजदूत श्री एस. टी. देवारे	भारत की पूरब की ओर देखो नीति
10	6 सितम्बर, 2010	रांची विश्वविद्यालय	राजदूत श्री एच. एच. एस. विश्वनाथन	उपद्रवग्रस्त अफ्रीका के लिए संभवनाएं एवं चुनौतियां
11	7 सितम्बर, 2010	केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय	राजदूत श्री एच. एच. एस. विश्वनाथन	उपद्रवग्रस्त अफ्रीका के साथ भारत की संलिप्तता
12	13 सितम्बर, 2010	जाधवपुर विश्वविद्यालय	राजदूत श्री आर. सेन	भारत की चिंताओं एवं प्राथमिकताओं से अमेरिकी हित समूहों को अवगत करानाः विदेश में एक सार्वजनिक राजनयिक कवायद
13	14 सितम्बर, 2010	कलकत्ता विश्वविद्यालय	राजदूत श्री आर. सेन	भारत-रूस संबंधों का विकास
14	28 सितम्बर, 2010	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	राजदूत श्री बी. बालाकृष्णन	भारत के विदेशी संबंधों में प्रौद्योगिकी की भूमिका
15	5 अक्तूबर, 2010	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	राजदूत श्री किशन एस. राणा	भारत की विदेश नीतिः नागरिक आयाम
16	22 अक्तूबर, 2010	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	राजदूत श्री के. सिबल	भारत-पाक संबंध
17	24 अक्तूबर, 2010	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	राजदूत श्री स्वश्वान सिंह	यूएन संगठनों की भूमिका एवं कार्यकरण
18	26 अक्तूबर, 2010	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	राजदूत श्री जी. पार्थसारथी	भारत-पाक संबंध
19	7 दिसम्बर, 2010	जामिया मिलिया इस्लामिया	राजदूत श्री रोनेन सेन	भारत-यूएस संबंधः राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के पश्चात
20	10 दिसम्बर, 2010	बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	श्रीमती विजया लता रेड्डी	भारत की पूरब की ओर देखो नीति

- **लव सांग ऑफ दि वर्ल्ड (ए फिल्म ऑन दि बॉउल्स ऑफ बंगाल):** दि स्टोरी ऑफ दि बॉउल्स, ए कल्ट ऑफ ट्रेवलिंग मिंस्ट्रेल्स हू आर रिचिंग आउट टू दि वर्ड एंड विनिंग इट ओवर विद दियर सिम्पलीसिटी एंड इंट्रीग्रिटी ऑफ परपज, थ्रो दियर सोलफुल म्यूजिक।

- **इन दि सीजन ऑफ ब्लू स्टॉर्म:** मुस्लिम महिलाओं एवं उनकी उपलब्धियों के मुकाबले में समकालीन भारतीय समाज की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

- **गॉड्स चूजन वन:** कैप्चर्स दि जर्नी ऑफ ऐन ऑर्डिनरी नन फ्राम बारनगांनम, ए स्मॉल टाउन इन केरला, एचीविंग दि एक्ट्राआर्डिनरीः दि कैनोनाइजेशन ऑफ दि फस्ट इंडियन कैथोलिक ओमन, सिस्टर एल्फोंसा, ऐज ए सेंट, भाई दि वेटिकन।

- **रिसर्जेंट मानस:** कैप्चर्स न्यू डेवलपमेन्ट्स इन दि मानस नेशनल पार्क इन वेस्टर्न आसाम, ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिन्स 1992।

- **फुटस्टेप इन्टु फ्यूचर:** फोकसेस ऑन डिफरेंट फेसेट्स ऑफ ए म्यूच्युअली बेनीफिसियल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रसिया दैट हैज स्पैन्ड जेनेरेशन्स।

- **इंडिय एम्पावर्ड:** भारत के विद्युत क्षेत्र पर एक वृत्त चित्र।

- **ऑन दि विंग्स ऑफ करेज:** ऐन एक्टेंसिवली रिसर्च्ड फिल्स ऑफ कैटेक्लास्मिक इवेंट्स शोकेसिंग दि रूट्स ऑफ कॉनफिल्क्ट्स इन दि मॉर्डन इवाल्विंग ह्यूमन सोसाइटीज।

- **दि पाथब्रेकर्स III:** ए सीरीज टू पुट स्पेशल फोकस ऑन दोज रेयर इंडिविजुअल्स, हू, थ्रो शियर ग्रिट, डिटर्मीनेशन, एंड कमिटमेंट, हैव सक्सिडेड इन रिवर्सिंग नियर इम्पॉसिबल प्रोब्लम्स, एंड शेकेन सोसाइटी आउट ऑफ इट्स एपैथी।

- **वाइब्रेंट कलर्स:** ट्रेसेस दि जेनेसिस ऑफ इंडियाज पब्लिशिंग इंडस्ट्री, स्टार्टिंग दि जर्नी इन ऐनसिएंट एंड मीडिवल टाइम्स, ट्रेवलिंग थ्रो दि कोलोनियल पीरियड एंड दि फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर एराइविंग ऐट दि प्रजेंट जंक्चर।

- **ए पीपुल्स प्रोजेक्ट (इब्सा पर एक फिल्म):** लोगों के सामूहिक लाभ के लिए दक्षिण - दक्षिण सहयोग के नए मॉडल को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका की सरकारों की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

- **इमर्जिंग टाईज; इंडिया - सेंट्रल एशिया इकॉनामिक रिलेशन्स:** सदियों से मध्य एशिया के चार देशों एवं भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संपर्कों की लंबी परंपरा को प्रतिबिंबित करता है।

- **ए ला कार्टे! (फूड इन दि फास्ट लेन):** फोकसेस ऑन दि वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रीट फूड इन इंडिया... ए वेराइटी दैट रिफ्लैक्ट्स रिमार्केबल इनोवेशन।

इनमें से कई फिल्मों को अनेक प्रारूपों में तैयार किया गया है, ताकि उनको न केवल विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाया जा सके अपितु मीडिया के अन्य नए चैनलों पर भी दिखाया जा सके। 20 फिल्मों को पहले ही यू-ट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है।

इसके अलावा, इस प्रभाग ने साहित्य, भारतीय विवाह, जयपुरी पैर, नरेगा, ई-गवर्नेंस पहल, साड़ी, ब्लाइंड क्रिकेट एवं भारतीय वास्तुशिल्प जैसे विविध किस्म के विषयों पर चालू वर्ष में 20 वृत्त चित्र प्रायोजित किया है। हमने अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ मिलकर भी 3 वृत्त चित्रों को प्रायोजित किया है अर्थात राष्ट्रीय संस्कृति निधि से श्री आमोल पालेकर द्वारा किशोरी अमोलकर पर वृत्त चित्र, एम ओ आई ए के साथ श्री सिद्धार्थ काक द्वारा भारतीय डायसपोरा पर 10 भागों वाली एक श्रृंखला, और डिस्कवरी चैनल के साथ स्वर्ण मंदिर पर एक फिल्म। इस प्रभाग ने वृत्त चित्रों को हाई डिफिनिशन प्रारूप में अंतरित करने तथा अनेक भाषाओं में डब करने का भी सजग प्रयास किया है। इन फिल्मों के लिए व्यापक स्तर पर दर्शक तैयार करने के प्रयास के अंग के रूप में, पीडी प्रभाग ने दूरदर्शन के साथ एक विशेष समझौता किया है। इस प्रभाग द्वारा निर्मित 90 वृत्त चित्रों को अक्टूबर 2010 से डी डी - इंडिया पर दिखाया भी जा रहा है।

अपने वृत्त चित्रों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने मैसर्स सारेगामा और एक गैर-सरकारी संगठन मैजिक लैन्टर्न फाउंडेशन के साथ गैर-अनन्य वितरण करार किया है।

टैगोर का 150वां जन्मदिन मनाने के लिए प्रभाग मैसर्स सारेगामा के साथ मिलकर टैगोर की कृतियों का एक अनुकूलित सेट निकाल रहा है। इस सेट में समालोचनात्मक रूप से प्रशंसित फिल्म 'ए स्टोरी ऑफ गीतांजलि', जिसे प्रभाग द्वारा 2008 में तैयार किया गया, गीतांजलि के गानों से युक्त एक श्रव्य सीडी, तथा टैगोर पर लेख, रोचक कहानियों से युक्त एक बहुभाषी पुस्तिका (स्पेनिश, पुर्तगीज, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी) शामिल होंगी।

प्रिंट प्रचार

इस प्रभाग ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं:

- ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा एक पुस्तक जिसका शीर्षक है 'जलवायु परिवर्तन का सरलीकरण';

- श्रीमती राधा रैना द्वारा एक कॉफी टेबल पुस्तक जिसका शीर्षक है 'भारत और कजाकिस्तान - दूरस्थ अतीत से प्रतिध्वनियां'; और

- एक कॉफी टेबल पुस्तक जिसका शीर्षक है 'कुछ पुराना

कुछ नया - रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मदिन के लिए श्रद्धांजलि': प्रकाशक - मार्ग पब्लिकेशन्स।

भारत के विभिन्न आयामों पर 4 नई कॉफी टेबल पुस्तकें प्रायोजित की गई हैं और गुजराती, पंजाबी, तमिल एवं तेलुगू में क्षेत्रीय भाषा पुस्तकों के उपयुक्त सेटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि हमारे मिशन भारतीय डायसपोरा तक हमारे आउटरिच प्रयासों के लिए इनका उपयोग कर सकें।

इस प्रभाग ने 'दि आटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी' का स्लोवेनियन में अनुवाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुस्तक 'ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' का बुल्गेरियन में अनुवाद और टैगोर की कृतियों का सर्बियन में अनुवाद प्रकाशित करने की पहलों का समर्थन किया है। भारत की 14 विभिन्न भाषाओं के 30 कवियों की 50 समकालीन कविताओं के संग्रह से युक्त एक पुस्तक के जर्मन में अनुवाद एवं प्रकाशन के लिए 3000 यूरो की राशि संस्वीकृत की गई।

भारत संदर्श पत्रिका

विदेश मंत्रालय के फ्लैगशिप प्रकाशन के लिए अधिक विविध अंतर्वस्तु एवं आकर्षक प्रारूप सृजित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। प्रभाग ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मदिन के अवसर पर भारत संदर्श पत्रिका का विशेषांक निकालने की पहल की। इस अंक को निकालने के लिए प्रभाग ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ घनिष्ट साझेदारी स्थापित की। इस अंक को 17 प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। भारत संदर्श पत्रिका को अधिक पेशेवर आयाम प्रदान करने के विचार से, जनवरी 2011 से इसका प्रकाशन एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

6 भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, रसियन एवं अरबी में पहली बार 2005-2006 में प्रकाशित कॉफी टेबल पुस्तक 'टाइमलेस स्प्लेंडर' की 15,000 प्रतियां मुद्रित करने एवं अपडेट करने का कार्य प्रभाग द्वारा मैसर्स मीडिया ट्रांस एशिया को सौंपा गया है।

विदेश मंत्रालय की फ्लैगशिप पत्रिका 'भारत संदर्श पत्रिका' को आनलाइन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2010 के आखिरी अंक को राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी के साथ मिलकर निकाला गया तथा यह आधुनिक एवं समकालीन कला के बारे में है तथा इसे भारतीय कला शिखर बैठक एवं जयपुर साहित्य महोत्सव में वितरित किया गया।

अंकीय राजनय

लोक राजनय प्रभाग ने एक सक्रिय अंकीय राजनय दृष्टिकोण शुरू किया है जिसका उद्देश्य तीन स्पष्ट लक्ष्यों के साथ वेब 2.0 उपकरणों द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं का दोहन करना है:

- इंटरनेट सेवी युवा पीढ़ी के साथ जुड़ना।
- ट्वीटर, यूट्यूब, फेसबुक, लॉगस्पाट और इसी तरह के अन्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत सशक्त, कम खर्चीले संचार चैनलों का उपयोग करना।
- फीडबैक प्राप्त करने तथा विचार विनिमय मंच सृजित करने के लिए इन चैनलों का उपयोग करना जो नागरिकों के साथ हमारे संबंधों को सुधारते हैं।

लोक राजनय प्रभाग ने इनमें से प्रत्येक चैनल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है तथा एक वेबसाइट (www.indiandiplomacy.in) भी शुरू किया है जो वेब 2.0 प्लेटफार्म पर आधारित है। आम जनता से प्राप्त प्रत्युत्तर अत्यन्त सकारात्मक है तथा इसके ट्वीटर में पहले ही 4,000 से अधिक अनुयायी हो चुके हैं। यूट्यूब पर वृत्त चित्रों के संक्षिप्त संस्करणों को डाला गया है तथा विदेशों में स्थित मिशनों की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्रदान करने एवं साझा करने के लिए फेसबुक पर एक अंत:क्रियात्मक स्थान सृजित किया गया है। इन पहलों ने हाल में इंडिया ई-गवर्नेंस 2.0 अवार्ड 2010 के माध्यम से पहचान प्राप्त की है, जहां लोक राजनय प्रभाग ने सरकार में सामाजिक मीडिया के सबसे नवाचारी उपयोग के लिए अवार्ड प्राप्त किया।

लोक राजनय प्रभाग के फेसबुक पृष्ठ पर 'भारत संदर्श पत्रिका के मित्र' और 'आई टी ई सी के मित्र' समूह सृजित किए जा रहे हैं।

भारत ब्रांड का निर्माण

लोक राजनय प्रभाग ने विदेशों में भारत ब्रांड के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की है। इस दिशा में प्रमुख पहलों में से कुछ इस प्रकार हैं: 12-14 नवम्बर, 2010 तक केरल में आयोजित पहले हे साहित्य महोत्सव के लिए सहायता; 'भारत में परिवर्तन का भविष्य' अभियान के लिए सहायता जो डिजाइन, व्यवसाय योजना, फोटोग्राफी, निबन्ध लेखन एवं अन्य प्रतियोगिताओं की श्रृंखला के माध्यम से विश्व के 18 प्रमुख विश्वविद्यालय परिसरों में भारत के बारे में जागरूकता सृजित करने का प्रयास है; और जनवरी 2011 में डाबोस में विश्व आर्थिक मंच की शिखर बैठक के दौरान 'India.Inclusive@Davos' विषय पर एक प्रमुख ब्रांड अभियान के लिए सी आई आई के साथ साझेदारी।

लोक राजनय प्रभाग की वेबसाइट आईटीईसी तथा अन्य सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे विश्व में भारत की विकास साझेदारियों के उदाहरण सृजित करने का सजग प्रयास करती है। भारत की मृदु शक्ति की वैश्विक पहुंच एवं प्रभाव को परिलक्षित करने एवं उजागर करने के लिए इसी तरह का एक और प्रयास भी किया जा रहा है। इसके वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने तथा हमारे लोक राजनय संबंधी प्रयासों के लिए इसे एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए दूरदर्शन के साथ सक्रिय वार्ता चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध समुदाय का सृजन

इस प्रभाग ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्वानों एवं विशेषज्ञों का एक राष्ट्रव्यापी डाटा बेस सृजित किया है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और जे ए आई आर के साथ साझेदारी में किया गया है। एक बंद गूगल मेल समूह सृजित किया गया है जहां इन विद्वानों ने एक दूसरे के साथ विचार विनिमय किया है तथा लोक राजनय प्रभाग के साथ संबंध स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्वानों पर अब तक के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

लोक राजनय को गति प्रदान करना

इस प्रभाग ने लोक राजनय के क्षेत्र तथा विदेश नीति में इसके बढ़ते महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक तरह की गतिविधियां शुरू की है। 'सूचना के युग में लोक राजनय' पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 10-11 दिसम्बर, 2010 को आयोजित किया गया जो भारत में आयोजित अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। विदेश सचिव द्वारा बीज भाषण दिया गया, जिन्होंने अतिथि प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोज भी दिया। संयुक्त सचिव (पीडी) ने इडसा एवं ओ आर एफ जैसे विभिन्न विचार केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में इस विषय पर व्याख्यान भी दिया है। लोक राजनय के लिए प्रभाग की महत्वाकांक्षी योजना के मद्देनजर, इसने एक अलग लोगो का भी सृजन किया है जिसका इसके सभी उत्पादों एवं प्रभाग द्वारा समर्थित कार्यक्रमों में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रभाग के लिए एक विशिष्ट पहचान सृजित करने की दिशा में चल रहे प्रयासों में यह एक प्रमुख मील पत्थर है।

■■

विदेश सेवा संस्थान 25

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण

विदेश सेवा संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक आईएफएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। परिवीक्षाधीन अधिकारी विदेश सेवा संस्थान में एकवर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करते हैं ताकि वे व्यापक श्रेणी के कार्यों को सम्पन्न करने में समर्थ हो सकें जिनकी मुख्यालय में तथा विदेशों में स्थित मिशनों एवं केन्द्रों में उनके व्यावसायिक करियर के दौरान उनसे सम्पन्न करने की अपेक्षा होती है।

अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद 2008 बैच के आईएफएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने जुलाई-अगस्त 2010 में विदेशों में अपनी भाषा तैनाती आरम्भ की। इस बैच के लिए विदाई समारोह का आयोजन 14 जून, 2010 को किया गया। सुश्री एन सुभाषिनी को सर्वश्रेष्ठ परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिए विमल सान्याल स्वर्ण पदक के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ प्रबंध लेखन के लिए विमल सान्याल रजत पदक के लिए चुना गया। विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव द्वारा उनको पदक प्रदान किए गए, जो विदाई समारोह में मुख्य अतिथि थीं।

2009 बैच के आई एफ एस के 24 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने जनवरी 2011 में भारतीय सेवा संस्थान में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण व्याख्यानों के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं से संबद्धता के माध्यम से संचालित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, रक्षा एवं सुरक्षा, आर्थिक राजनय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सांस्कृतिक राजनय, भारत की विरासत, पर्यावरणीय एवं जलवायु राजनय, ऊर्जा सुरक्षा आदि जैसे अनगिनत विषयों पर माड्यूल शामिल थे। विदेश नीति के परम्परागत विषयों के अलावा, इस सेवा में प्रवेश करने वाले युवा अधिकारियों को समकालीन सामाजिक विकास के मुद्दों, अल्पसंख्यक अधिकार एवं समस्याएं, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार के मुद्दों आदि पर संक्षिप्त जानकारी भी प्रदान की गई। परिवीक्षाधीन अधिकारियों में प्रभावी संचार कौशल विकसित करने तथा चिंतन की क्षमता सृजित करने के निमित्त समूह चर्चा, मामला अध्ययन, एवं विशिष्ट मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण भी शुरू किया गया।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भारतीय थल सेना और वायु सेना के साथ संबद्धता पर भेजा गया तथा मुम्बई में पश्चिमी नौसेना कमान के दौरे पर भी भेजा गया। सितम्बर 2010 में अपने मुम्बई दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), एक्जिम बैंक, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) समेत अग्रणी वित्तीय संस्थाओं के विशेषज्ञों के साथ विचार विनिमय में भी भाग लिया।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के कामकाज की जानकारी प्राप्त करने तथा भारत के सन्निकट पड़ोसियों के बारे में अपने ज्ञान में बृद्धि करने के निमित्त अप्रैल-मई 2010 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने तीन समूहों में काठमांडू (नेपाल), माले (मालदीव) और रंगून (म्यांमार) का दौरा किया।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली में 7 सप्ताह के एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि प्रबंधन एवं आर्थिक मुद्दों में उनके कौशलों का विकास हो सके।

परिवीक्षाधीन आधिकारी अक्तूबर 2010 में 'भारत दर्शन' दौरे पर गए ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत तथा आर्थिक एवं पर्यटन क्षमता से परिचित हो सकें। नवम्बर 2010 में जिला प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने निम्नतम स्तर पर प्रशासन तथा ग्रामीण समुदायों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में जानने का अवसर प्राप्त किया। अपना एफ एस आई प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारतीय विदेश सेवा के 2009 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने जनवरी 2011 में मंत्रालय में अपना डेस्क अटैचमेंट शुरू किया।

2010 बैच के भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने दिसम्बर 2010 में संस्थान ज्वाइन किया तथा उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ हो गया है।

मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण

मई 2010 में 1992 बैच के निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए ईमेल आधारित मध्यावधिक करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हुआ। 1993 बैच के आई एफ एस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के अंतिम चरण पर है तथा 1994 बैच के आई एफ एस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में एक विस्तृत मोनोग्राफ लिखने के अलावा भारत की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा एवं क्षेत्रीय मुद्दों के चार माड्यूलों पर असाइंमेंट शामिल होता है।

मंत्रालय के अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार पर एक दिवसीय माड्यूल 11 फरवरी, 2011 को आयोजित किया जा रहा है।

मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों के लिए 2 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 20-30 अप्रैल तथा 4-15 अक्तूबर, 2010 तक संचालित किए गए जिसके दौरान प्रतिभागियों को संचार कौशल एवं विदेशों में स्थित मिशनों के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों ने एकीकृत मिशन लेखाकरण साफ्टवेयर (आईएमएएस) में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों के लिए एक अन्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 14-21 मार्च, 2011 तक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

मंत्रालय के सहायकों एवं लिपिकों के लिए बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बीपीसी) 26 जुलाई-3 अगस्त 2010 तक संचालित किया गया। प्रतिभागियों को मिशन से संबद्ध विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय के सहायकों एवं लिपिकों के लिए एकीकृत मिशन लेखाकरण साफ्टवेयर (आईएमएएस) पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दो एकीकृत मिशन लेखाकरण साफ्टवेयर (आईएमएएस) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ सहायकों एवं लिपिकों के लिए एक अन्य बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बीपीसी) 7 फरवरी-2 मार्च 2011 तक आयोजित किया जाएगा।

अन्य मंत्रालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ संबंधों का संवर्धन

विदेश सेवा संस्थान द्वारा 5-9 अप्रैल 2010 तक 'भारत की विदेश नीति में मुख्य धाराएं' पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की ओर से 5वां ऊर्ध्वाधर विचार विनिमय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में संयुक्त रूप से आई ए एस, आई पी एस, आई एफ एस तथा रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

11-12 अक्टूबर, 2009 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के 11वें सम्मेलन में संयुक्त सचिवों में से एक ने विदेश सेवा संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

विदेशी राजनयिकों के लिए कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान ने पूरे विश्व के विभिन्न देशों के साथ मैत्री एवं सहयोग का सेतु निर्मित करने के अपने प्रयासों के तहत विदेशी राजनयिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का कार्य जारी रखा।

आईओआर-एआरसी सदस्य देशों के राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम 28 अप्रैल-11 मई 2010 तक आयोजित किया गया। आईओआर-एआरसी से 13 राजनयिकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। आसियान देशों के राजनयिकों के लिए 18 अगस्त-16 सितम्बर 2010 तक एक विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें 7 आसियान देशों से 31 राजनयिकों ने भाग लिया। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को दिल्ली एवं दिल्ली के आसपास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक महत्व के विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया। उन्होंने आगरा, बोधगया एवं बंगलौर का भी दौरा किया। अफगानिस्तान के राजनयिकों के लिए 7वां विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नवम्बर- दिसम्बर 2010 में आयोजित किया गया जिसमें 18 राजनयिकों ने भाग लिया।

विदेश सेवा संस्थान ने प्रशांत द्वीपसमूह के देशों के राजनयिकों के लिए 10-14 जनवरी, 2010 तक फिजी में एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया। इस पाठ्यक्रम में 10 देशों के 14 राजनयिकों ने भाग लिया।

विदेशी राजनयिकों के लिए 50वां व्यावसायिक पाठ्यक्रम विदेश सेवा संस्थान में 5 जनवरी-4 फरवरी 2011 तक आयोजित किया जा रहा है। 37 देशों के 38 राजनयिक 50वें पीसीएफडी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रमंडल के देशों के राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम 7-11 मार्च, 2011 तक आयोजित किया जा रहा है।

विदेशों में स्थित समकक्ष संस्थानों के साथ सहलग्नताएं

विदेश सेवा संस्थान तथा दक्षिण अफ्रीका की राजनय अकादमी के भीच सहयोग की संस्थानिक रूपरेखा प्रदान करने वाले एक समझौता ज्ञापन पर 4 जून, 2010 को हस्ताक्षर किया गया। अगस्त 2010 में विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विदेशों में गाम्बियावासी मामले मंत्री डा. मामाडोऊ टंगरा के नेतृत्व में गाम्बिया के एक 5-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश सेवा संस्थान के संकायाध्यक्ष से मुलाकात की। सितम्बर 2010 में सिविल सेवा चयन एवं विदेश में प्रशिक्षण बोर्ड (सीएसएसटीबी) के अध्यक्ष श्री यू क्याव थू के नेतृत्व में म्यांमार के एक प्रतिनिधिमंडल ने विदेश सेवा संस्थान का दौरा किया। इथोपिया के उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री महामहिम श्री आटो हलेमारियम डेसालेगन के नेतृत्व में इथोपिया के एक 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिसम्बर 2010 में विदेश सेवा संस्थान के संकायाध्यक्ष से मुलाकात की।

राजनयिक प्रशिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय मंच की 38वीं बैठक में भाग लेने के लिए विदेश सेवा संस्थान के संकायाध्यक्ष ने 27-29 सितम्बर, 2010 तक माल्टा का दौरा किया। वार्षिक बैठक में राजनयिक अकादमियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थानों के संकायाध्यक्ष एवं निदेशक भाग लेते हैं।

■■

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार

26

मंत्रालय के पास मिशनों/केंद्रों को शामिल करके विदेशों में हिंदी के प्रचार के लिए एक सुसंगठित कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत हिंदी शिक्षण सामग्री (पाठ्य पुस्तकें, साहित्य एवं बच्चों की पुस्तकों, हिंदी पत्रिकाएं, कम्प्यूटर पर हिंदी सीखने के लिए साफ्टवेयर, हिंदी सीखने की सीडी और शब्दकोश सहित) शैक्षणिक संस्थानों को आपूर्ति की जाती है। मंत्रालय विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से हिंदी से संबंधित कार्यकलापों के लिए विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता भी प्रदान करता है। वर्ष 2010-2011 के दौरान विदेश स्थित लगभग 70 मिशनों/केंद्रों को हिंदी पुस्तकें, पाठ्य सामग्री व साफ्टवेयर भेजे गए। विदेश स्थित लगभग 100 मिशनों/पोस्टों को हिंदी पत्रिकाओं की आपूर्ति की गई। 4 मिशनों/केंद्रों को विदेशों में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए विविध अनुदान भी स्वीकृत किए गए।

एक द्विपक्षीय करार के तहत, हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार करने के लिए मॉरीशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गयी है। सचिवालय के कार्यकलापों को विदेश मंत्रालय तथा मॉरीशस सरकार के इसके मॉरीशियाई समकक्ष द्वारा समन्वित किया जाता है।

मंत्रालय केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य का समन्वय करता है। प्रतिवर्ष विदेशी छात्रों को 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2010-2011 के दौरान 82 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देता रहा है। द्विपक्षीय संधियों, करारों, समझौता-ज्ञापनों, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, संसद प्रश्न जैसे दस्तावेज तथा संसद के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अल्प सूचना पर यूनजीए जाने वाले आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के चार सदस्यों (जो कि सांसद थे) के भाषणों का ऑनलाइन हिंदी अनुवाद किया गया।

राजभाषा के रूप में हिंदी में प्रशिक्षण मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग है। वर्ष के दौरान ऐसे चार कार्यक्रम आयोजित किए गए। लगभग 200 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

मंत्रालय ने मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा व हिंदी दिवस का आयोजन किया। पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण व आलेखन, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, हिंदी प्रश्नोत्तरी तथा हिंदी कविता पाठ जैसी प्रतियोगताएं आयोजित की गई थीं। इस बार मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी। हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह साउथ ब्लॉक के समिति रूम में आयोजित किया गया तथा समारोह की मुख्य अतिथि विदेश सचिव, श्रीमती निरुपमा राव थी।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन से संबंधित सलाह देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित की गयी हैं। तदनुसार, विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन विदेश मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है।

'कौटिल्य पुरस्कार योजना' के तहत विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर, हिंदी लेखकों की उनकी मौलिक रचना के लिए सम्मानित करता है। वर्ष के दौरान, कौटिल्य पुरस्कार से संबंधित समिति की सिफारिशों पर डॉ. विक्रम सिंह को उनकी पुस्तक (भारत में राजनीतिक चिंतन की परंपरा) के लिए कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने 5 अक्तूबर, 2010 को साउथ ब्लॉक के समिति कक्ष में आयोजित हिंदी दिवस, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, के अवसर पर डॉ. विक्रम सिंह को ₹ 60,000 की राशि का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह तथा एक शॉल से सम्मानित किया।

हिंदी पखवाड़ा, 2010 के अवसर पर हमारे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के साथ मिशनों ने हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी लेखन प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। विदेश स्थित 36 मिशनों/केंद्रों को इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए थे।

हिंदी अनुभाग ने मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की। प्रतिभागियों को सरकार की राजभाषा नीति व हिंदी में टिप्पण व आलेखन जैसे विषयों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी गयी था। अंतिम दिन सह-भागियों को हिंदी पुस्तकें भी वितरित की गईं।

प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विदेश स्थित हमारे सभी मिशन/केंद्रों के साथ-साथ मुख्यालय में भी 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है।

विदेश स्थित 40 मिशनों/केंद्रों को 10 जनवरी, 2011 को विश्व हिंदी दिवस आयोजित करने के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए। 10 जनवरी, 2011 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के अनुदेश जारी किए गए।

वर्ष 2010-2011 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जायजा लेने के लिए पुणे, तिरुवनंतपुरम तथा कोच्चि स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का दौरा किया। इन यात्राओं से संबंधित कार्य का समन्वय मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान, हिंदी अनुभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग की प्रगति का आकलन करने के लिए मंत्रालय के 25 अनुभागों तथा चंडीगढ़, शिमला और हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया। इन कार्यालयों के कर्मचारियों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

■■

विदेश सचिव, श्रीमती निरुपमा राव 10 जनवरी, 2011 को
विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में पुरस्कार विजेताओं के साथ।

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा 27 अगस्त, 2010 को
नई दिल्ली में मिशन प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

27 तीसरा मिशन प्रमुख (एचओएम) सम्मेलन

तीसरा भारतीय मिशन प्रमुख (एच ओ एम) सम्मेलन नई दिल्ली में 27-29 अगस्त, 2010 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूरे विश्व से 119 उच्चायुक्तों एवं राजदूतों ने भाग लिया। विदेश मंत्री श्री एस एम कृष्णा ने 27 अगस्त, 2010 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, आई सी सी आर के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सम्मेलन को संबोधित किया। मिशन प्रमुखों ने भारत के राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

मिशन प्रमुखों ने विदेश नीति से जुड़े मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करते हुए विचार विनिमय के अनेक सत्रों में भाग लिया, जिसमें सन्निकट एवं विस्तारित पड़ोस में घटनाक्रम, प्रमुख राष्ट्रों एवं क्षेत्रों के साथ संबंध तथा भारत के लिए महत्व रखने वाले क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। सीआईआई एवं फिक्की द्वारा आयोजित सत्रों के दौरान मिशन प्रमुखों ने व्यावसाय एवं उद्योग जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ भी वार्तालाप किया, जिसमें श्री गुरचरण दास तथा सुश्री इंदरा नुई शामिल हैं।

■■

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

28

भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक समझ स्थापित करने, सुदृढ़ करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। जैसा कि संस्था ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में भागीदारी करना;
- दूसरे देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना;
- अन्य देशों और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देना और उन्हें सुदृढ़ करना।
- संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित और विकसित करना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिषद ने निरंतर कार्य किया है।

परिषद के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

भारत सरकार और अन्य अभिकरणों की ओर से विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृति योजनाओं का प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का कल्याण, भारतीय नृत्य एवं संगीत सीखने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, पारस्परिक आधार पर प्रदर्शनियों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं परिसंवादों का आयोजन एवं उनमें भाग लेना, विदेशों में मुख्य सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेना, विदेशों में 'भारत महोत्सव' का आयोजन करना, मंचीय कलाकारों की मंडलियों का आदान-प्रदान, विदेशों में मंचीय कलाकारों द्वारा व्याख्यान-प्रदर्शन का आयोजन; विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विदेशों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया जाता है और आगंतुकों का विदेश कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विदेशों में व्याख्यान देना, पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण करने, दृश्य-श्रव्य सामग्री, कला-वस्तुएं तथा संगीत यंत्र मुहैया कराने के लिए विशेषज्ञ भेजे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार हेतु सचिवालय उपलब्ध कराना, वार्षिक मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन करना, मौलाना आजाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना, भारत तथा विदेशों में वितरण के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को बनाए रखना, एक समृद्ध पुस्तकालय और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पांडुलिपियों का रख-रखाव और दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल बनाना।

क्षेत्रीय कार्यालय

परिषद के 15 क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नै, कटक, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पुणे, शिलांग, तिरूवनन्तपुरम और वाराणसी में कार्य कर रहे हैं। गोवा में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और महानिदेशक द्वारा गोवा सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री की उपस्थिति में 23 नवंबर, 2010 को किया गया। अहमदाबाद, पटना, श्रीनगर और भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की प्रक्रिया भी चल रही है।

क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकलापों में स्थानीय निकायों/संगठनों के साथ समन्वय करना और परिषद की छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी छात्रों को सहायता प्रदान करना शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालय भारत आने वाले और विदेश जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडलों और परिषद के विशिष्ट विजिटरों को संभारतंत्तीय सुविधाएं प्रदान भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भा.सां.सं.परि. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यकलापों की संख्या को बढ़ाना और भारत के भिन्न-भिन्न भागों में आईसीसीआर के आउटरीय को भी बढ़ाने पर अब अधिक बल दिया गया है।

क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठकः विदेशी छात्रों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और विदेशी छात्रों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शुरू किये गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों की एक बैठक 8 सितम्बर, 2010 को आजाद भवन, आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली में आहूत की गई थी। सभी अनुभाग के प्रमुख भी मुख्यालय में उपस्थित थे।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रः परिषद वर्तमान में विदेशों में 25 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र संचालित कर रहा है, जो आबुधाबी (यूएई), अल्माटी (कजास्तान), बैंकाक (थाइलैंड), बीजिंग (चीन), बर्लिन (जर्मनी), काहिरा (मिस्र), कोलंबो (श्रीलंका), ढाका (बंगलादेश), डरबन एवं जोहान्सबर्ग (दोनों दक्षिण अफ्रीका में), दुशांबे (ताजिकिस्तान), जार्जटाउन (गुयाना), जकार्ता (इंडोनेशिया), काबुल (अफगानिस्तान), काठमांडू (नेपाल), क्वालालम्पुर (मलेशिया), लंदन (यू.के.), मेक्सिको सिटी (मेक्सिको), मास्को

(रूसी परिसंघ), पारामारिबो (सूरीनाम), पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद एवं टोबैगो), पोर्ट लुई (मॉरीशस), सुवा (फिजी), ताशकंद (उज्बेकिस्तान) और टोक्यो (जापान) के साथ-साथ बाली (इंडोनेशिया), लाउटोका (फिजी) और थिम्पु (भूटान) में तीन उप-केन्द्र स्थित हैं। भा.सां.सं.परि. के अध्यक्ष डा. कर्ण सिंह द्वारा सितम्बर 2010 में थिम्पु में आयोजित एक समारोह में नेहरू-वांगचुक सांस्कृतिक केन्द्र का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अपने अध्ययन-पीठ कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशों में समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता और सराहना को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के साथ भारतीय प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों को विभिन्न प्रतिष्ठित एवं प्रख्यात विदेशी विश्वविद्यालयों में भा.सां.सं.परि. द्वारा दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक अध्ययन-पीठों में प्रतिनियुक्त किया गया है।

विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार कार्यक्रम और परिषद की स्वयं की 'विस्तार योजना' के अंतर्गत ये अध्ययन-पीठ स्थापित किये गए हैं। दीर्घकालिक अध्ययन-पीठ एक-वर्षीय अवधि अथवा उससे अधिक के लिए स्थापित किये जाते हैं। अल्पकालिक अवधि की अध्ययन पीठ तीन से छह माह की होती है। शिक्षण के अलावा, प्रतिनियुक्त प्राध्यापक अनुसंधान मार्गनिर्देशन, संगोष्ठी समन्वयन, प्रकाशन जैसे अन्य शैक्षिक कार्यकलापों और अन्य संस्थानों में वक्ता के रूप में कार्य करते हैं। भा.सां.सं.परि. के विदेशों में 65 अध्ययन पीठ हैं। इन 65 अध्ययन-पीठों में से 42 अध्ययन पीठ वित्तीय वर्ष 2009-2010 तक विद्यमान थे। वित्तीय वर्ष 2010-2011 (30 नवंबर, 2010 तक) में भा.सां.सं.परि. ने 23 अतिरिक्त पीठ स्थापित किये।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 (30 नवंबर, 2010 तक) में स्थापित नई अध्ययन पीठ चीन में (दो अध्ययन पीठ, भारतीय अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान प्रत्येक में एक), कनाडा में (2 अध्ययन पीठ, भारतीय इतिहास और समाज विज्ञान प्रत्येक में एक), यू.के. (2 अध्ययन पीठ, आद्युनिक भारतीय इतिहास और समाज विज्ञान प्रत्येक में एक), कंबोडिया (संस्कृत और बौद्ध अध्ययन), इंडोनेशिया (संस्कृत), मॉरीशस (संस्कृति एवं भारतीय दर्शनशास्त्र), इटली (भारतीय अर्थशास्त्र), नेपाल (संस्कृति विज्ञान), न्यूजीलैंड (भारतीय राजनीति), स्वीडन (भारतीय इतिहास), नीदरलैंड (समकालीन भारतीय अध्ययन), मेक्सिको (भारतीय अध्ययन), आयरलैंड (इक्यूमेनिक्स), जापान (समकालीन भारतीय अध्ययन), जर्मनी (5 अध्ययन पीठ, पर्यावरण नीति, समाज-विज्ञान, साहित्यिक/मीडिया/संस्कृति अध्ययन, विधि एवं राजनीति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन) और दक्षिण अफ्रीका (समाज विज्ञान) में अवस्थित है।

भा.सां.स.परि. ने जापान में अपना दूसरा अध्ययन पीठ स्थापित करने के लिए रयूकोकु विश्वविद्यालय, क्योटो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भा.सां.सं.परि. ने तीन नए अध्ययन पीठ स्थापित करने के लिए इटली, इंडोनेशिया और नेपाल के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

शिक्षा वृत्ति कार्यक्रम

भारत और पूरे विश्व में भारत की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत के प्रति विद्वानों में गहरी रूचि को ध्यान में रखते हुए परिषद् द्वारा शिक्षा वृत्ति कार्यक्रम के विचार को संकल्पनाबद्ध किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा सावधानीपूर्वक चयनित विद्वानों को 30 शिक्षावृतियां प्रदान की जाएंगी, जिनके पास भारत से संबंधित विषयों पर अच्छी संख्या में प्रकाशन एवं शोध अध्ययन के साथ एक सुदृढ़ एवं प्रभावकारी शैक्षणिक पहचान हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित फेलो को 3,000 अमरीकी डालर प्रतिमाह की शिक्षावृत्ति मिलती है और उनके द्वारा वांछित किसी भारतीय विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी मंच या गैर-सरकारी संगठन से संबद्धता प्राप्त होती है। भारत में प्रवास के दौरान फेलो छात्रों, शिक्षण संकाय, फेलो और लेखकों के साथ विचार-विमर्श भी करते हैं और परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न संवादों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्याख्यानमालाओं में भाग लेते हैं।

आज की तिथि तक इस योजना के अंतर्गत 26 फेलो का चयन किया गया है, जिनमें से छह फेलो, न्यूजीलैंद्व हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, जांबिया, मंगोलिया और नीदरलैंड प्रत्येक से एक-एक फेलो भारत आए और विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षावृत्ति की अवधि पूरा कर लौट गए। बुलगारिया, जर्मनी, मंगोलिया, ग्रीस, उज्बेकिस्तान, नीदरलैंड, कजाकिस्तान, जापान, आयरलैंड, मेक्सिको, म्यांमा और ईरान से 12 फेलो विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में अपने शोध कार्य में लगे हैं और आने वाले माह में त्रिनिदाद एंड टुबैगो, फिजी, वियतनाम, लाओ पीडीआर, इटली, आस्ट्रेलिया, हंगरी और नेपाल से आठ और फेलो अपनी फेलोशिप आरंभ करने के लिए आने वाले हैं।

सम्मेलन एवं संगोष्ठियां

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे बुद्धिजीवियों, विचार-निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों के आयोजन में सहयोग किया है। इनमें शामिल हैं (क) दक्षिण कोरिया (10-11 मई, 2010) तथा सिंगापुर में (24-25 मई, 2010) को बौद्ध सम्मेलन, और (ख) चेक गणराज्य (17-19 जून, 2010) तथा इंडोनिशिया (11-16 अक्तूबर, 2010) में भारत-विद्या से संबंधित सम्मेलन। इन सम्मेलनों में भारत, मेजबान देश और मेजबान देश के पड़ोसी देशों से बौद्ध अध्ययन और भारत-विद्या के विद्वानों ने भाग लिया। इन सम्मेलनों से अच्छी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। इन प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहित होकर परिषद विदेशों में भारत-विद्या और बौद्ध अध्ययन पर और सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है। भारत में परिषद ने मेक्सिको राजदूतावास

के सहयोग से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की वर्षगांठ के समारोह पर एक सम्मेलन आयोजित किया।

परिषद ने भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन में जे.एन.यू., दिल्ली विश्वविद्यालय और आईआईएएस (शिमला) जैसे प्रख्यात संस्थानों और विभिन्न संगठनों की भी सहायता की जिनमें कई प्रमुख भारतीय और विदेशी विद्वानों ने भाग लिया और उर्दू एवं फारसी भाषाओं सहित सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विषयों पर सम्मेलन/संगोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने में विभिन्न विश्वविद्यालयों को सहयोग दिया। भा.सां.सं.परि. द्वारा सहायता प्राप्त प्रमुख विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय और एमजी विश्वविद्यालय (कोट्टायम) थे।

परिषद ने 28-29 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में पारस्परिक सांस्कृतिक वार्तालाप पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। परिषद द्वारा दस्तकारी हाट के सहयोग से आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में 3-17 जनवरी, 2011 तक की अवधि के दौरान दिल्ली हाट में आयोजित संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमा, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के महिला शिल्पकारों को परिषद एक मंच पर लाया। भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच बौद्धवाद के बंधन को संवर्धित करने की अपनी नीति के भाग के रूप में परिषद ने 3-4 दिसंबर, 2010 को कंबोडिया में एक बौद्ध सम्मेलन भी आयोजित किया।

मध्य जनवरी 2011 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अंत तक की अवधि के दौरान परिषद् विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित करने में सहयोग कर रहा है। मार्च, 2011 के मध्य में एक बौद्ध सम्मेलन श्रीलंका में भी आयोजित किया जाना निर्धारित है।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को छात्रवृति एवं कल्याण

भा.सां.सं.परिषद की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है विदेशी छात्रों को डॉक्टोरल, स्नातकोत्तर, स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के साथ-साथ इंजीनियरी, फार्मेसी, व्यवसाय प्रबंधन और लेखाशास्त्र जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करना है। भा.सां.सं.परि. द्वारा प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत में इस समय लगभग 4,700 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। अप्रैल-नवंबर 2010 तक की अवधि के दौरान परिषद ने अफगानी छात्रों के लिए 675 छात्रवृत्तियां और अफ्रीकी छात्रवृत्ति योजना सहित 2,350 नई छात्रवृतियां दी हैं, जिनमें से 1379 विदेशी छात्रों ने भारत में अपने-अपने संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश ले लिया है।

परिषद विदेशी छात्रों के लिए नियमित रूप से 'शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन शिविर' और 'अध्ययन दौरे' आयोजित करता है।

दिसंबर 2010 से जनवरी 2011 के मध्य तक की अवधि के दौरान परिषद ने विदेशी छात्रों के लिए भारतवर्ष के विभिन्न भागों में 14 शीतकालीन शिविर आयोजित किये।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुरोध पर 10-11 जनवरी, 2011 को आजाद भवन, आईसीसीआर में विभिन्न देशों से भारतीय मूल के 35 विदेशी अतिथि विद्वानों के लिए एक परिचय पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, नृत्य, चलचित्र, कला एवं पुरातत्व पर व्याख्यान और पॉवर-प्वाएंट प्रस्तुति के साथ-साथ नई दिल्ली में लाल किला और हुमाँयू का मकबरा के दौरे शामिल थे।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में नए आए छात्रों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय (ओ) और दिल्ली विश्वविद्यालय/जे.एन.यू. के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकारों के ब्रीफिंग और स्पिक-मैके के प्रतिनिधियों द्वारा व्याख्यान और एक कत्थक नृत्यांगना सुश्री नवीना ज़फा का व्याख्यान प्रस्तुति शामिल थे।

भा.सां.सं.परि. के 60वें वर्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और भा.सां.सं.परि. के संस्थापक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद की 122वीं जयंती के स्मरणोत्सव पर, परिषद ने आईजीएनसीए, नई दिल्ली में 12 नवंबर, 2010 को 'संस्कृति के माध्यम से मैत्री' नामक 18वां अंतर्राष्ट्रीय छात्र सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 18 देशों के विदेशी छात्र समुदाय ने अपने संबंधित देशों की संस्कृति के प्रतिनिधि पहलू को दर्शाते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। भा.सां.सं.परि. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने और विदेश स्थित कुछ भारतीय मिशनों ने भी इस उत्सव को मनाया।

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) के अनुरोध पर परिषद द्वारा 2010 बैच के भा.वि.से. के परिवीक्षार्थियों के लिए 21-25 मार्च, 2011 तक एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्याख्यान/व्याख्यान-सह-प्रदर्शनों, पॉवर-प्वाएंट प्रस्तुति और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूचि के स्थलों के दर्शन/दौरे शामिल थे। भारतीय कला एवं संस्कृति पर व्याख्यान सुविख्यात सांस्कृतिक विद्वानों द्वारा दिए गए।

भारत आने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

भा.सां.सं.परि., भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विदेशी मंचीय कलाकरों के भारत-दौरे आयोजित करती है। इन मंडलियों की मेजबानी द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत और साथ ही विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सिफारिशों और भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों और सांस्कृतिक केन्द्रों से प्राप्त अनुरोधों पर की जाती है। अप्रैल 2010-जनवरी 2011 की अवधि के दौरान परिषद ने मिस्र, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस, जर्मनी, मॉरीशस, थाइलैंड, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, ताइवान, यू.के., अफगानिस्तान, कोलंबिया, नेपाल, बोत्सवाना, पोलैंड, टर्की, ब्राजील, मेक्सिको, इक्वाडोर और

अल्जीरिया की 31 विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों के दौरों की मेजबानी की। परिषद ने दिल्ली में ठुमरी उत्सव एवं मल्हार उत्सव आयोजित करने सहित 54 विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।

परिषद ने दक्षिण एशियाई बैंड उत्सव और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव जैसे दो बड़े उत्सवों का भी आयोजन किया जिनमें आस्ट्रिया, इटली, यू.के., मेक्सिको, जापान, स्पेन, बेलारूस, मिस्र, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के सहभागियों ने दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद और चंडीगढ़ में प्रस्तुति दी। इसके अलावा, नौवें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर ऋतु-संहार मंडली की नृत्य-प्रस्तुति सहित भारतीय कलाकारों द्वारा 7 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में छह विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गए।

परिषद ने 11 भूटानी कलाकारों की मेजबानी की ताकि वे भारत में 1 दिसंबर 2010-31 जनवरी 2011 तक 'धर्म परियोजना' के अंतर्गत कांस्य ढ़लाई और गढ़ाई के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकें।

प्रकाशन

परिषद का अपना एक महत्वाकांछी प्रकाशन कार्यक्रम है, जिसमें वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। परिषद ने पांच भिन्न-भिन्न भाषाओं में पांच पत्रिकाएं नामतः 'भारतीय क्षितिज' और 'अफ्रीका त्रैमासिक' (दोनों अंग्रेजी भाषा की त्रैमासिक पत्रिका), 'पेपेल्स डि ला इंडिया' (स्पेनिश भाषा की द्विवार्षिक पत्रिका), 'रेनकांट्रे एवेक ले इंडे' (फ्रेंच भाषा की द्विवार्षिक पत्रिका) और 'थकाफट-उल-हिंद' (अरबी भाषा की त्रैमासिक पत्रिका) प्रकाशित की है। भा.सां.सं.परि. की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'भारत के मौलाना' नामक उसके प्रकाशन (चार खंडों में) का पुनर्मुद्रण किया गया।

आवक्ष प्रतिमाएं एवं प्रदर्शनियां

वर्ष के दौरान दो आवक्ष प्रतिमाएं और 23 प्रदर्शनियां प्रायोजित की गई। 32 देश नामतः स्लोवेनिया, मॉरीशस, अलजीरिया, टर्की, ईरान, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, दक्षिण कोरिया, सीरिया, गुयाना, फ्रांस, अर्जेंटिना, श्रीलंका, ताइवान, थाइलैंड, ट्यूनीशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, स्वीडन, इटली, मिस्र, जर्मनी, इंडोनेशिया, चीन, स्पेन, भूटान, म्यांमा, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, रूस, आर्मेनिया और यू.के. इसके लाभकारी देश रहे।

विदेशों में प्रस्तुति देने हेतु कलाकारों/प्रदर्शनियों को प्रायोजित किया गयाः

वर्ष के दौरान 16 भिन्न-भिन्न कलाकार और प्रदर्शनियाँ प्रायोजित किये गए।

आजाद भवन कला दीर्घा, आईसीसीआर, नई दिल्ली में 'क्षितिज श्रृंखला' के अंतर्गत स्थानीय प्रदर्शनियां;

वर्ष के दौरान 37 प्रदर्शनियां प्रायोजित की गईं।

विदेश से आने वाली प्रदर्शनियां

वर्ष के दौरान विदेश से आयी दो प्रदर्शनियां लगाई गई।

विदेश जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

अप्रैल, 2010 जनवरी, 2011 के दौरान भा.सां.सं.परि. द्वारा 85 सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित किये गए।

भा.सां.सं.परि. द्वारा मार्च 2011 तक 33 अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित किये जाने की आशा है।

भारत महोत्सव

परिषद द्वारा भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक समझ को बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने के अपने प्रयास के भाग के रूप में निम्नलिखित उत्सव आयोजित किये गएः

परिषद की उत्सव इकाई द्वारा 30-सदस्यीय रतन थियाम मंडली तथा तीन सदस्यीय निमाई दास बाउल मंडली की प्रस्तुति के साथ बीजिंग में 4 अप्रैल, 2010 को चीन में शुरू हुए भारत महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया गया। यह उत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत प्रस्तुतियों पर आधारित था और इसमें भारत के भिन्न-भिन्न भागों से 21 मंचीय कलामंडलियों ने भाग लिया। यह उत्सव भा.सां.सं.परि. द्वारा आयोजित चेंगदु में कलाक्षेत्र की 30-सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्यमंडली की प्रस्तुति के साथ चीन में भारत उत्सव का समापन समारोह अक्तूबर 2010 में संपन्न हुआ।

परिषद ने फ्रांस में 'नमस्ते फ्रांस' के नाम से भारत उत्सव आयोजित किया। अप्रैल 2010 में हुए उद्घाटन समारोह में श्रीमती मल्लिका साराभाई के नेतृत्व में एक 20-सदस्यीय दर्पण अकादमी मंडली द्वारा लोक एवं जनजातीय नृत्यों की उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। यह मई 2011 तक जारी रहेगा।

परिषद ने दो नृत्य मंडलियों श्रीमती कुमकुम मोहन्ती के नेतृत्व में एक 10-सदस्यीय ओडिसी नृत्य मंडली और श्रीमती मारियानेला के नेतृत्व में एक 12-सदस्यीय गोयनशिन नोकेट्राम मंडली को अर्जेंटिना में भारत उत्सव के लिए 4-14 नवंबर, 2010 तक प्रायोजित किया।

विदेश का दौरा कार्यक्रम

परिषद द्वारा भारतीय बुद्धिजीवियों, विद्वानों, शिक्षाविदों और कलाकारों के विदेश दौरे को प्रायोजित किया जाता है, ताकि वे विदेश में संगोष्ठियों, गोष्ठियों, अध्ययन दौरों और सम्मेलनों में भाग ले सकें।

अप्रैल-नवंबर 2010 तक की अवधि के दौरान, परिषद द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में 44 प्रख्यात विद्वानों के दौरे प्रायोजित किए गए।

प्रतिष्ठित आगन्तुक कार्यक्रम

भारत और दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने और उसे मजबूत बनाने के अपने प्रयास के भाग के रूप में परिषद द्वारा अपने प्रतिष्ठित आगन्तुक कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य देशों से विशिष्ट जनों और विद्वानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और कलाकारों की भारत यात्राओं को भी सुलभ बनाया जाता है। अवधि के दौरान परिषद द्वारा त्रिनिदाद व टोबैगो, कनाडा, कंबोडिया, अमरीका, मेक्सिको, अजरबैजान, सूरीनाम, जाम्बिया, वियतनाम, स्वीडन, पोलैंड, सिंगापुर, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे भिन्न-भिन्न देशों से 15 प्रतिष्ठित आगंतुकों की मेजबानी की।

मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यान

लार्ड मेघनाद देसाई 'वैश्वीकरण एवं सर्वदेशीय संस्कृति' विषय पर 12 नवंबर, 2010 को तीन मूर्ति सभागार, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली में मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यान, 2010 दिया। भा.सां.सं.परि. के अध्यक्ष, डा. कर्ण सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

हिन्दी से संबंधित कार्यकलाप

हिन्दी के विद्वानों, लेखकों और पाठकों के बीच त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका 'गगनाँचल' की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भा.सां.सं.परि. ने 2010 से इस पत्रिका को त्रैमासिक से द्विमासिक कर दिया है। वह इसके प्रकाशन की संख्या को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 करने पर भी विचार कर रहा है। भा.सां.सं.परि. द्वारा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर प्रतिष्ठान को एक हिन्दी संगोष्ठी आयोजित करने के लिए मई 2010 में 1,00,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। भा.सां.सं.परि. ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक हास्य कवि सम्मेलन भी आयोजित किया। भा.सां.स.परि. ने राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त न्यास को 50,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की और अगस्त 2010 में राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त पुरस्कार स्थापित किया। भा.सां.सं.परि. हिन्दी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विदेश स्थित अपने भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को शब्दकोषों और भारतीय संस्कृति पर हिन्दी पुस्तकें नियमित रूप से भेज रहा है। यूरोप में अगस्त, 2010 में आयोजित 'हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता' के विजेताओं के भारतीय दौरे सां.सां.सं.परि. द्वारा प्रायोजित किए गए। हिन्दी का प्रसार करने के लिए भा.सां.सं.परि. प्रत्येक वर्ष यू.के. के विभिन्न शहरों में कवियों के दल भेजता है। इस वर्ष अगस्त 2010 में भी कवियों के एक दल को लंदन भेजा गया। संगोष्ठी में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि शिष्टमंडल भेजा। सां.सां.सं.परि. ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान में नवंबर 2010 में आयोजित हिन्दी संगोष्ठी-सह-कार्यशाला में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि शिष्टमंडल भेजा। भा.सां.सं.परि. ने तमिलनाडु हिन्दी साहित्य अकादमी को नवंबर 2010 में एक हिन्दी संगोष्ठी आयोजित करने के लिए 2,00,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। भा.सां.सं.परि. ने टोक्यो और ओसाका, जापान में नवंबर 2010 में आयोजित हिन्दी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि शिष्टमंडल भेजा।

■■

29 भारतीय विश्व कार्य परिषद

1 अप्रैल 2010-9 जनवरी 2011 तक की अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद द्वारा आयोजित और नियोजित किए गए कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1)	व्याख्यान	15
2)	संगोष्ठियां	09
3)	द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ताएं	14
4)	समूह चर्चाएं/पृष्ठभूमि सार	03
5)	अन्य कार्यक्रम (पुस्तक विमोचन/ फिल्म प्रदर्शन आदि)	03
	कुल	**44**

कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1 भारत एवं चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'भारत एवं चीनः लोक राजनय, समझ पैदा करना' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिव शंकर मेनन द्वारा बीज भाषण (2 अप्रैल, 2010)।

2 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के महासचिव डा. शील कांत शर्मा द्वारा 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रवादः संभावनाएं एवं चुनौतियां' विषय पर व्याख्यान (14 सितम्बर, 2010)।

3 बेलारूस गणराज्य के प्रथम उप प्रधान मंत्री श्री व्लादिमीर आई. सेमाक्षो द्वारा व्याख्यान (25 अक्तूबर, 2010)।

4 'भारत और जीसीसी देश, ईरान एवं इराकः उभरते सुरक्षा संदर्श' विषय पर आईसीडब्ल्यूए एएएस एशियाई संबंध सम्मेलन 2010।

उप राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी द्वारा उद्घाटन भाषण तथा विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव द्वारा समापन भाषण (20-21 नवम्बर, 2010)।

6 "इथोपिया–भारत संबंध" विषय पर इथोपिया के उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री श्री हेलमेरियम देसालेगन द्वारा व्याख्यान। (1 दिसम्बर, 2010)

6 'बदलती विश्व व्यवस्था में भारत एवं पोलैंड' विषय पर आईसीडब्ल्यूए-पीआईएसएम संगोष्ठी (पोलिश अंतर्राष्ट्रीय मामले संस्थान के साथ मिलकर, जिसके साथ भारतीय विश्व कार्य परिषद का एक समझौता ज्ञापन है) (7 दिसम्बर, 2010)।

7 'विकसित हो रही विश्व व्यवस्थाः भारत - रूस संदर्श' पर आईसीडब्ल्यूए-एमजीआईएमओ सम्मेलन (मास्को राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान (एमजीआईएमओ) के साथ मिलकर) (9-10 दिसम्बर, 2010)।

8 'अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप पर पुनर्विचार' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (मौलाना आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता (एमएकेएआईएएस) के साथ मिलकर) (6-7 जनवरी, 2011)।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सूची **परिशिष्ट-XV** के रूप में संलग्न है। भारत के अंदर विश्वविद्यालयों एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले केंद्रों के साथ आउटरिच कार्यक्रमः

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विदेश नीति अध्ययन संस्थान के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया।

भारत के बाहर विश्वविद्यालयों एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले केंद्रों के साथ आउटारीच कार्यक्रमः

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए निम्नलिखित के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किएः

1 इथोपियाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास संस्थान (ईआईआईपीडी)।

2 तुर्की गणराज्य के विदेश मंत्रालय का सामरिक अनुसंधान केंद्र।

3 कोरिया गणराज्य का विदेशी मामले एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान (आईएफएएनएस)।

4 नेपाल विश्व कार्य परिषद, एनसीडब्ल्यूए बिल्डिंग, हरिहर भवन, पुलचौक, काठमांडू।

भारतीय विश्व कार्य परिषद में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरेः

1. लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स के निदेशक श्री हावर्ड डेविस (8 अप्रैल, 2010)
2. फिनलैंड के विदेश मंत्री श्री अलक्जेंडर स्टब (3 मई, 2010)
3. उक्रेन के उप विदेश मंत्री श्री विक्टर माइको (22 सितम्बर, 2010)
4. बेलारूस गणराज्य के प्रथम उप प्रधान मंत्री श्री व्लादिमीर आई. सेमाक्षो (25 अक्टूबर, 2010)
5. अर्मेनिया गणराज्य के विदेश मंत्री श्री एडवर्ड नलबांडियन (11 नवम्बर, 2010)
6. डा. राबिन निब्लेट, निदेशक, शाही अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान, घाटम हाउस, लंदन (16 नवम्बर, 2010)
7. इथोपिया के उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री श्री हेलमरियम देसालेगन (1 दिसम्बर, 2010)
8. चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधान मंत्री श्री वेन जियाबाओ (16 दिसम्बर, 2010)

अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप

भारतीय विश्व कार्य परिषद ने अपनी अनुसंधान गतिविधियों को सुदृढ़ करना जारी रखा। अनुसंधान अध्येताओं ने चीन, जापान, नेपाल, फारस की खाड़ी तथा रूस/ सीएआर में राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक रूझानों एवं घटनाक्रमों के अध्ययन एवं अनुसंधान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अनुसंधान अध्येताओं ने भारत एवं विदेशों में आयोजित सम्मेलनों में सक्रियता से भाग लिया जहां उन्होंने पेपर प्रस्तुत किया। उन्होंने मुद्दा सारांश, नीति सारांश एव दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया जिन्हें भारतीय विश्व कार्य परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इन गतिविधियों ने शैक्षिक नेटवर्किंग, बहु-विषयक अनुसंधान में सिनर्जी तथा भारतीय विश्व कार्य परिषद की अनुसंधान क्षमता एवं रूपरेखा का विस्तार करने में योगदान किया है।

1 दिसम्बर 2010-9 जनवरी 2011 की अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद के अनुसंधान अध्येताओं ने भारत एवं विदेशों में आयोजित निम्नलिखित सम्मेलनों में भाग लिया जहां उन्होंने पेपर प्रस्तुत किएः

1. 7 दिसम्बर, 2010 को आईसीडब्ल्यूए-पीआईएसएम सम्मेलन (नई दिल्ली)
2. भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए), नई दिल्ली तथा मास्को राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान (एमजीआईएमओ), मास्को द्वारा 9-10 दिसम्बर, 2010 को 'विकसित हो रही विश्व व्यवस्थाः भारत रूस संदर्श' (नई दिल्ली)
3. 14 दिसम्बर, 2010 को 'भारत जापान संबंध' पर जापानी राष्ट्रीय मौलिक संस्थान की सुश्री याशिको सकुराई के नेतृत्व में जापान के 8 सदस्यीय समूह के साथ विचार विनिमय (नई दिल्ली)
4. 6-7 जनवरी, 2011 को आईसीडब्ल्यूए एमएकेएआईएएस द्वारा 'अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप पर पुनर्विचार' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (नई दिल्ली)
5. 9-10 दिसम्बर, 2010 को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित 'दक्षिण एशिया में सुरक्षा चुनौतियांः उभरते सिद्धांत एवं रणनीतियां' पर सम्मेलन (जयपुर)
6. 10 दिसम्बर, 2010 को दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुरद्वारा 'चीन का उत्थान एवं दक्षिण एशिया में उभरते सुरक्षा मुद्दे' विषय पर सम्मेलन (जयपुर)

भारतीय विश्व कार्य परिषद ने अनुसंधान प्रकाशन निकालने के लिए दो प्रख्यात विद्वानों/पूर्व प्रैक्टिशनर्स को भारतीय विश्व कार्य परिषद में नियुक्त किया है। उन्हें अनुसंधान अनुदान प्रदान किया गया है तथा उनसे 12 महीने में अपने अनुसंधान परिणाम जमा करने की अपेक्षा होती है। ये परियोजनाएं पुस्तकों/मोनोग्राफ में परिणत होंगी।

दिल्ली के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों एवं विचार केंद्रों तक पहुंचने के अपने प्रयास में भारतीय विश्व कार्य परिषद ने मझोले एवं छोटे आकार के कस्बों में स्थित अनेक विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक संबंध स्थापित किया है। साथ ही परिषद के निदेशानुसार, भारतीय विश्व कार्य परिषद डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा जयपुर विश्वविद्यालय, जयपुर के साथ सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। नागपुर विश्वविद्यालय, वारंगल विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, शिलांग विश्वविद्यालय तथा त्रिपुरा विश्वविद्यालय के साथ संबंध विकसित करने के लिए भी इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं। भारतीय विश्व कार्य परिषद ने अपने आउटरिच कार्यक्रम पर सलाह देने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरंजन दास की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया है। भारतीय विश्व कार्य परिषद ने दिल्ली के बाहर के अनेक विश्वविद्यालयों एवं विचार केंद्रों को अपनी ई-मेल नेटवर्क प्रणाली में भी लाया है।

भारतीय विश्व कार्य परिषद की वेबसाइट अब काम कर रही है तथा भारतीय विश्व कार्य परिषद के प्रकाशनों, कार्यक्रमों एवं घोषणाओं को शामिल करने के लिए इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

इस अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद की पत्रिका 'भारत तिमाही' (आईक्यू) को नियमित रूप से प्रकाशित किया गया। अक्टूबर-दिसम्बर 2009, जनवरी-मार्च 2010 एवं अप्रैल जून 2010 के अंक क्रमशः 9 जून, 2010, 28 जुलाई, 2010

और 28 अक्तूबर, 2010 को निकाले गए। इसके अलावा, भारतीय विश्व कार्य परिषद ने 16 अप्रैल 2010 को 'भारत रूस रणनीतिक साझेदारी' शीर्षक से एक प्रकाशन निकाला है जिसका संपादन श्री निवेदिता दास कुण्डू ने किया है।

भारतीय विश्व कार्य परिषद ने अप्रैल से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग परिषद (सीएससीएपी) संबद्ध निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लियाः

1. क्वालालम्पुर में 10 जून, 2010 से आयोजित संचालन समिति की 33वीं बैठक एवं 23वीं एशिया प्रशांत गोलमेज बैठक जिसमें राजदूत किशन एस. रैना, अध्यक्ष (सीएससीएपी भारत) ने भाग लिया।

2. 3-4 जुलाई, 2010 को सिंगापुर में आयोजित सीपीडब्ल्यूएमडी (व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार पर रोक) पर सीएससीएपी अध्ययन समूह की बैठक जिसमें राजदूत दिलीप लहरी (सेवानिवृत्त) ने भाग लिया।

3. मेट्रो मलीना, फिलीपीन्स में 21-22 सितम्बर, 2010 को आयोजित होने के लिए निर्धारित आर 2 पी पर सीएससीएपी का एसजीएम, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार ने भाग लिया।

4. मेट्रो मलीना में 21-22 नवम्बर, 2010 को आयोजित सीएससीएपी की 34वीं संचालन समिति बैठक जिसमें राजदूत लीला के. पोनप्पा, अध्यक्ष सीएससीएपी भारत ने भाग लिया।

5. हो ची मिन्ह शहर में 16-17 दिसम्बर, 2010 को आयोजित सीपीडब्ल्यूएमडी पर सीएससीएपी अध्ययन समूह की बैठक जिसमें राजदूत दिलीप लहरी (सेवानिवृत्त) ने भाग लिया।

भारतीय विश्व कार्य परिषद का पुस्तकालय

भारतीय विश्व कार्य परिषद के पुस्तकालय ने पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा यूएन एवं ईयू दस्तावेजों के सम्पूर्ण संग्रह के स्वचालन के जरिए भविष्य की दिशा में ऊंची छलांग लगायी है। आरएफआईडी की अधुनातन प्रौद्योगिकी का प्रयोग सप्रू हाउस के वर्षों पुराने पुस्तकालय को अगले स्तर पर ले गया है जो आज की जरूरतों के काफी अनुरूप है। प्रवेश एवं निकास बिंदु पर आरएफआईडी गेट पुस्तकालय के संसाधनों की सुरक्षा करने में सहायता करते हैं तथा सूची प्रबंधक पुस्तकालय के सूची प्रबंधन में सहायता करता है। यह पुस्तकालय के स्टॉक का नियमित रूप से सत्यापन करने में काफी मददगार होगा। अब संग्रह ओपीएसी (ऑन लाइन सार्वजनिक पहुंच कैटलॉग) के माध्यम से तलाशी योग्य हो गया है और इस प्रकार सूचनाओं के पूर्ण इलेक्ट्रानिक प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रबंधन एवं पुस्तकालय दल की ऊर्जा अब दुर्लभ पुस्तकों, समाचारपत्रों के जिल्दबंद खंडों तथा प्रेस की कतरनों की अंकीय अंतर्वस्तु सृजित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में इस पुस्तकालय के समृद्ध एवं अनूठे संसाधनों को सुव्यवस्थित करने एवं परिरक्षित करने में काफी मददगार होगी जो विश्व मामलों के क्षेत्र में भारत एवं दुनियाभर के अनुसंधानकर्ताओं एवं विशेषज्ञों के लिए बहुत उपयोगी होगा। भारत तिमाही के संपूर्ण संग्रह (1945-2008) का अंकीयकरण किया गया है तथा उन्हें वेबसाइट पर पलटा जा सकता है। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन के दस्तावेज उपलब्ध हैं जिन्हें भविष्य के लिए अंकीय रूप से परिरक्षित किया गया है। पुस्तकालय की सदस्यता खूब तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही इसका राजस्व सृजन भी बढ़ रहा है। मात्र ₹ 0.59 लाख के अर्जन से शुरूआत करने वाले पुस्तकालय का राजस्व आज वित्त वर्ष 2009-2010 के अंत में ₹ 8.90 लाख तक पहुंच गया है। दिसम्बर 2010 में सदस्यता 713 तक पहुंच गयी तथा आज भी इसमें वृद्धि हो रही है तथा राजस्व ₹ 8,61,500 के अंक को छू लिया है। पुस्तकालय का परिवेश आकर्षक एवं मनोहारी दिखता है तथा इसका रंगढंग काफी सुंदर हो गया है। सीटों की संख्या बढ़ कर 250 हो गयी है, जो अभी भी बढ़ती जा रही है। सजावट अब आकर्षक हो गई है तथा रोमन ब्लाइंड एवं नयी आरामदेह कुर्सियां एवं मेज लगे हैं। वातावरण सहज एवं पढ़ाई करने के लिए अनुकूल है। पुस्तकालय अब हर किसी को समान रूप से आकर्षित कर रहा है। पुस्तकालय का प्रयोग करने वाले अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि इसकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। सप्रू हाउस पुस्तकालय अब अनेक मानिंद संस्थाओं एवं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकायों अर्थात इफला, डेलनेट एवं आइजलिक का सदस्य है। हमारे अनुसंधान संकाय एवं अनुसंधान छात्रों के लिए सूचनाएं मंगाने या सामग्री उधार लेने के लिए इन सदस्यताओं का अभीष्ठ रूप से प्रयोग किया जाता है। हमारी उपलब्धियों की एक अन्य विशेषता डेलनेट के यूनियन कैटलॉग पर हमारे पुस्तकालय के संग्रह की दर्शनीयता है। इन दिनों कुछ प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा हमारी उपस्थिति महसूस की जाती है क्योंकि हम अमेरिकी केंद्र, ब्रिटिश परिषद, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, एनएमएमएल (तीन मूर्ति), केंद्रीय सचिवालय, डेलनेट, तथा विभिन्न अन्य ख्यातिप्राप्त पुस्तकालयों से पूछताछ प्राप्त करते हैं। प्रतिष्ठित अखबारों के मीडिया कर्मी सूचना के लिए पुस्तकालय का दौरा कर रहे हैं। संग्रह में भारी संख्या में पुस्तकें जोड़ी जा रही हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों एवं विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों पर पुस्तकें, अफ्रीका, दक्षिण एशिया एवं मध्य, पूर्व एवं पश्चिम एशिया से संबंधित पुस्तकें, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण एवं ग्लोबल वार्मिंग पर पुस्तकें। नई पुस्तकों की अभिवृद्धि तथा नई इलेक्ट्रानिक पत्रिकाओं के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के संग्रह में वृद्धि की जा रही है। जेएसटीओआर (अभिलेखागारीय अंतर्वस्तु के साथ पत्रिकाओं का एक ऑन लाइन डाटाबेस) तथा एसएजीई, टेलर एंड फ्रांसिस एवं इसी तरह की अन्य प्रिंट एवं ऑन लाइन पत्रिकाओं का सब्सक्रिप्शन अनुसंधानकर्ताओं को काफी सहायता प्रदान करेगा। हमारे राजनयिकों द्वारा लिखित

पुस्तकों का एक संग्रह 'राजनय की विरासत' शीर्षक से पुस्तकालय में सृजित किया जा रहा है। इस संग्रह को हमारी वेबसाइट पर भी हाइलाइट किया जाता है। नई पुस्तकों के नामों की सूची में अभिवृद्धि हमारी वेबसाइट की एक नियमित विशेषता है जो ऐसी पुस्तकों के बारे में सूचना प्रदान करती है जिन्हें पुस्तकालय के संग्रह में हाल में शामिल किया गया है। हम अपने पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के बारे में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं को सूचनाएं परिचालित करेंगे। प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के प्रोफेसरों एवं अनुसंधान विद्वानों ने समान रूप से पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं प्रेस कतरनों का संदर्भ ग्रहण किया है। प्रमुख सरकारी अधिकारी पुस्तकालय की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं तथा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जो इस बात का द्योतक है कि हमारे पुस्तकालय की लोकप्रियता बढ़ रही है। हम अपने पुस्तकालय कर्मियों के कौशलों को भी स्तरोन्नत कर रहे हैं। उन्हें गहन प्रशिक्षण एवं सम्मेलनों के लिए नियमित रूप से भेजा जाता है ताकि वे अद्यतन रूझानों एवं प्रौद्योगिकी से अवगत रहें। भारतीय विश्व कार्य परिषद के पुस्तकालय में हाल में एक गहन एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पुस्तकालय की संपूर्ण टीम ने कंप्यूटरों का प्रयोग करके पुस्तकालय के नेमी कार्यों को निपटाने के लिए पुस्तकालय साफ्टवेयर का प्रयोग करने की जानकारी प्राप्त की। पुस्तकालय वेब-ओपीएसी पूरे विश्व में सप्रू हाउस की विरासत के बारे में सूचनाओं के प्रसार में भारतीय विश्व कार्य परिषद के पुस्तकालय में एक नई शुरूआत होगी। सभी ब्यौरों को अंतिम रूप दे दिया गया तथा डब्ल्यूईबी ओपीएसी शीघ्र ही भारतीय विश्व कार्य परिषद की वेबसाइट पर क्रियाशील होगा जो विदेशी नीति के अनुसंधानकर्ताओं एवं प्रैक्टिशनर्स को अध्ययन के उनके संबंधित क्षेत्रों में संसाधन ढूढ़ने में सरलता प्रदान करेगा। वेब-ओपीएसी हमारे संग्रह की झलक प्रदान करेगा तथा हमारी समृद्ध विरासत को अधिक दर्शनीय बनाएगा। स्टैक हाल एवं पुस्तकालय में निर्देशक संकेत पुस्तकालय में पाठक की यात्रा को सरल बनाते हैं क्योंकि विषय के संबंधित स्थान पर पहुंचने में पाठक की सहायता के लिए बे गाइड पर विषय एवं उसके स्थान का उल्लेख होता है।

■■

30 विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

पर्यवलोकन

अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में स्थापित एक विचार केन्द्र है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और विकासात्मक सहयोग में विशेषज्ञता प्राप्त है। आरआईएस को समय-समय पर सौंपे जाने वाली क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय सहयोग व्यवस्थाओं सहित बहुपक्षीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामलों पर भारत सरकार के एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। आरआईएस को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के विचार केंद्रों में प्रभावशाली नीतिगत वार्ता एवं क्षमता-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है।

अनुसंधान और सूचना प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत अनुसंधान आयोजित करता है और भारत सरकार को महत्वपूर्ण वार्ताओं के लिए और बैठकों के लिए तैयारी करने के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान और सूचना प्रणाली की कार्य योजना का केन्द्र बिंदु दक्षिण-दक्षिण सहयोग का संवर्धन करना और विकासशील देशों को विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय वार्ता करने में सहायता प्रदान करना रहा है। आरआईएस ने अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न गुट-निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठकों, पूर्वी एशियाई शिखर बैठकों, सार्क सम्मेलन, इब्सा शिखर बैठक, बिमस्टेक शिखर बैठक, अंकटाड मंत्री स्तरीय सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है। अनुसंधान और सूचना प्रणाली विभिन्न क्षेत्रीय पहलों की ट्रैक-II प्रक्रिया, जिसमें सेप्टा का ट्रैक-II अध्ययन समूह सम्मिलित है, में सलग्न है। भिन्न-भिन्न देशों के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार निष्पादित करने और वार्ता प्रक्रिया के दौरान आरआईएस ने भारत सरकार को विश्लेषणात्मक सहायता भी प्रदान की है। एशिया के शीर्ष नीति विचार केंद्रों के साथ एक एशियाई आर्थिक समुदाय के लिए संगठन नीतिगत वार्ता कर रहा है। अनुसंधान और सूचना प्रणाली भारत और अन्य देशों दोनों में स्थित नीतिगत विचार केंद्रों के अपने गहन नेटवर्क के जरिए अंतर्राष्ट्रीय-आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत समरूपता को सुदृढ़ करने की इच्छा रखता है।

वर्ष 2010-2011 के दौरान अनुसंधान और सूचना प्रणाली के मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं-

सरकार को अनुसंधान व नीतिगत निविष्टियां प्रदान करना

आरआईएस विशेष रूप से अपने सहभागी देशों के साथ भारत के आर्थिक तालमेल के संदर्भ में नीति तैयार करने में सहयोग के लिए अनुसंधान अध्ययन आयोजित किया है। आरआईएस द्वारा प्रदत्त कुछ विशिष्ट निविष्टियों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- **भारत-आसियानः** एमई प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के लिए वर्ष 2010-2015 के लिए भारत-आसियान कार्य योजना पर नोट तैयार किया गया। सीयेम रीप, कंबोडिया में 30 जनू-1 जुलाई 2010 के दौरान आयोजित 12वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (सोम) के लिए एमईआर प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को इनपुट्स प्रदान की गई।

- **कनाडा संयुक्त अध्ययन दलः** भारत-कनाडा संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) रिपोर्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के लिए भारत-कनाडा सेवा व्यापार से संबंधित अध्याय का मसौदा तैयार किया गया।

- **जी-20 मुद्देः** आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए जी-20 प्रक्रिया के कुछ पहलुओं पर नोट तैयार किया गया। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के लिए जी-20 की उत्पत्ति एवं कार्य पर दस्तावेज तैयार किया गया।

- **डब्ल्यूटीओ वार्ताः** आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए दोहा दौरः महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित वार्ता पर दस्तावेज तैयार किया गया।

नीतिगत वार्ता, सम्मेलन एवं संगोष्ठियां

वर्ष 2010-2011 के दौरान आरआईएस ने विकासशील देशों के बीच बुद्धिजीवी वार्ता का प्रसार करने के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए कई नीतिगत वार्ताएं, सम्मेलन और संगोष्ठियां एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस अवधि के दौरान आयोजित कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं-

थिंक टैंक्स के बिम्सटेक नेटवर्क **की प्रथम बैठकः** आरआईएस ने विदेश मत्रालय के सहयोग से 18-19 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में बिम्सटेक थिंक टैंक्स के संबंध में एक दो दिवसीय विचार-विमर्श का आयोजन किया। श्रीमती विजय लता रेड्डी, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया।

राजदूत फारूक सुभान, बांग्लादेश उद्यम संस्थान; महामहिम श्री यू. की. थीन, असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी, श्रीमती कुंजुंग लामु, ग्रॉस नेशनल हैपीनेस आयोग; डा. सूरत होरा चैकुल, चुलालो कोर्न विश्वविद्यालय, थाइलैण्ड; और श्री भरत प्रसाद पोखरेल, सीईडीए, नेपाल ने बैठक विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता की।

बैठक में निम्नलिखित विषयों- व्यापार और निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, कृषि तथा प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय समाकलन- नीति निर्माताओं के लिए सीख पर कार्यशालाः आरआईएस ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र, जादवपुर विश्वविद्यालय और अतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर भारतीय अनुसंधान परिषद के सहयोग से 11-12 मार्च, 2010 को आईआईएफटी, नई दिल्ली में व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय समाकलनः नीति निर्माताओं के लिए सीख पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय समाकलन पर इस कार्यशाला के आयोजकों में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अधुनातन अनुसंधान कार्यों का प्रचार-प्रसार करना था। इसने व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय समाकलन और व्यापार सुविधा नीतियों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान और विचार-विमर्श के लिए एक मंच भी प्रदान किया।

इस कार्यशाला की कार्यसूची में अतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क और क्षेत्रीय व्यापार करारों पर चर्चा; आटोमोटिव सेक्टर का अध्ययन; समुचित विकास करने सबंधी व्यापार नीतियां; कृषि सामग्री का व्यापार और समुचित विकास; व्यापार लागत, व्यापार सुविधा उपाय और उभरते नीतिगत एवं अनुसंधान मामलों तथा उन उभरते मुद्दों को शामिल किया गया जिनका व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय समाकलन के संबंध में नीति-निर्माताओं के लिए महत्व है।

भारत में एफडीआई से संबंधित संकल्पना, परिभाषा और आंकड़ा संबंधी मुद्दों पर संगोष्ठीः आरआईएस और औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी), नई दिल्ली ने 16 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में भारत में एफडीआई से संबंधित संकल्पना, परिभाषा और आंकड़ों संबंधी मुद्दों पर संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी की पृष्ठभूमि दस्तावेज डा. के. एस. चलपति राव, प्रोफेसर, आईएसआईडी और डा. विश्वजीत धर, डीजी, आरआईएस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। इस संगोष्ठी में प्रमुख रूप से भाग लेने वालों में प्रा. एस. आर. हाशिम और प्रो. एस. के. गोयल, आईएसआईडी, प्रो. सुनंदा सेन, आईसीएसएसआर नेशनल फेलो, प्रो. सी. पी. चन्द्रशेखर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, डा. सुतानु सिन्हा, इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और श्री ए. पी. गौड़, आरबीआई, मुंबई शामिल थे। आरआईएस की ओर से श्री रेजी के. जासेफ ने दस्तावेज प्रस्तुत किया।

उभरती अर्थव्यवस्था में व्यापार एवं जलवायु परिवर्तन पर अनौपचारिक वार्ताः आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थाई विकास केंद्र (आईसीटीएसडी) जेनेवा के सहयोग से संयुक्त रूप से उभरती अर्थव्यवस्था में व्यापार और जलवायु परिवर्तन प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी और बौधिक संपदा अधिकार आयाम पर 30-31 मार्च, 2010 के दौरान नई दिल्ली में एक दो दिवसीय अनौपचारिक वार्ता का आयोजन किया।

श्री जयराम रमेश, पर्यावरण एवं वन राज्य मत्री, भारत ने मुख्य भाषण पढ़ा और श्री राजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव (यूएनईएस), विदेश मंत्रालय, भारत इसके संचालक थे। राजदूत चन्द्रशेखर दासगुप्ता, गणमान्य व्यक्तियों, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) ने यूएनएफसीसीसी वार्ता में विकासशील देशों के परिदृश्य पर चर्चा की। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें प्रतिस्पर्धा और सीमा उपायों तथा प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण शामिल थे।

इस वार्ता में प्रमुख रूप से भाग लेने वालों में डा. जोयेल युदकेन, हाई रोड स्ट्रेटेजीज एलएलसी; श्री क्रिस्टोफर बेलमैन, आईसीटीएसडी; सुश्री डिंग वै, वाणिज्य मंत्री, चीन; श्री मुकुल सानवाल, साउथ सेंटर, जेनेवा; श्री अहमद अब्देल लतीफ, आईसीटीएसडी श्री रीने वोसेंजर, आईसीटीएसडी, श्री पेडरो टेरा, ब्राजील दूतावास; डा. एम. मणि, विश्व बैंक; श्री सूर्य पी. सेठी, पूर्व प्रधान सलाहकार, योजना आयोग; और श्री सर्जियो सी. त्रिनडाड, अंतर्राष्ट्रीय ईंधन प्रौद्योगिकी शामिल थे। आरआईएस की ओर से डा. विश्वजीत धर, डीजी, डा. एस. के. मोहंती, सीनियर फेलो, डा. सचिन चतुर्वेदी, सीनियर फेलो और डा. कृष्णा रवि श्रीनिवास, एसोसिएट फेलो ने प्रतिनिधित्व किया।

क्षेत्रीय आर्थिक एवं व्यापार संभवना पर आरआईएस - एडीबी गोलमेज वार्ताः आरआईएस और एडीबी ने 29 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय आर्थिक और व्यापार संभावना पर संयुक्त रूप से गोलमेज वार्ता की। श्री रजत एम. नाग, महा प्रबंध निदेशक, एडीबी और डा. श्रीनिवास मधुर, वरिष्ठ निदेशक, ओआरईआई-एडीबी ने क्षेत्रीय आर्थिक संभावना पर प्रस्तुतिकरण दिया। आरआईएस की ओर से डा. बिश्वजीत धर ने वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापार संभावना पर प्रस्तुतिकरण दिया। डा. प्रणब सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर प्रस्तुतिकरण दिया।

एशिया में सतत विकास और बढ़ते समाकलन पर आरआईएस-एडीबीआई सम्मेलनः आरआईएस और एडीबीआई ने संयुक्त रूप से 15 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली में एशिया में विकास और बढ़ते समाकलन पर सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयः एशिया में आर्थिक समाकलन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना और सतत विकास का संतुलन शामिल थे।

इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में डा. मसाहिरो कवई, एडीबी संस्थान; डा. सुमन बेरी, एनसीएईआर; श्री के. पी. कृष्णन, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार; डा. आलोक शील, वित्त मंत्रालय; डा. एम. गोविंदा राव, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान; श्री के.टी. चाको, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान; डा. पार्था मुखोपाध्याय, सीपीआर; और डा. शशांक भिडे, एनसीएईआर शामिल थे।

सार्क @ 25 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः आरआईएस और भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और सार्क सचिवालय के सहयोग से 16-17 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली में सार्क @ 25 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

डा. कपिला वात्स्यायन, संसद सदस्य, आजीवन न्यासी, आईआईसी और अध्यक्ष, आईआईसी एशिया प्रोजेक्ट ने प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता की और अध्यक्षीय भाषण दिया। श्री श्याम सरन, उपाध्यक्ष, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री एस. एम. कृष्णा, विदेश मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया। डा. शील कांत शर्मा, महासचिव, सार्क ने विशेष भाषण दिया।

दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यसूची में 25 वर्ष पश्चात सार्क से संबंधित विषयों; ट्रेड इन गुड्सः प्रोग्रेस एण्ड इंपेडिमेंट्स; ट्रेड इन सर्विसेजः वर्तमान स्थिति, संभावनाएं एवं चुनौतियां; वास्तविक संपर्क सुदृढ़ करना; ऊर्जा संपर्क सुनिश्चित करने और सार्क के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए कदमों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

प्रोफेसर मुचकुंद दूबे, अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद और उपाध्यक्ष, आरआईएस रिसर्च एडवाइजरी; डा. रहमान सोभान, नीति वार्ता केन्द्र, ढाका, बांग्लादेश; प्रोफेसर जी. के. चड्ढा, सीईओ, सार्क यूनीवर्सिटी; डा. के. एल. थापर, एशियाई परिवहन विकास संस्थान; श्री जे.सी. शर्मा, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय; और डा. सुमन केलेगमा, नीति अध्ययन संस्थान, कोलंबो, श्रीलंका ने इस सम्मेलन के भिन्न-भिन्न सत्रों की अध्यक्षता की।

सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में बोलने वाले प्रख्यात वक्ताओं में डा. श्रीधर के खत्री, दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्र, काठमांडू, नेपाल; डा. उत्तम देब, नीति वार्ता केन्द्र, ढाका, बांगलादेश; फैक उमर, सतत विकास नीति केन्द्र, इस्लामाबाद, पाकिस्तान; श्री अहमद सालिह, पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, मालदीव; डा. रोहन समाराजीवा, एलआईआरएनई एशिया, कोलंबो, श्रीलंका; श्री अरविंद मेहता, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार; डा. मोहम्मद रहमतुल्लाह, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग, ढाका, बांग्लादेश; श्री मोहम्मद हसन सोरोश युसुफजई, विदेश मंत्रालय, काबुल, अफगानिस्तान; डा. एम.पी. लामा, सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम; श्री रिनजिन दोर्जी, थिम्पु; आइशा पाशा, इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, बीकॉन हाउस नेशलन यूनीवर्सिटी लाहौर; अकमल हुसैन, बीकॉन हाउस नेशनल यूनीवर्सिटी, लाहौर; श्री पवन कपूर, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार शामिल थे।

आरआईएस संकाय सदस्यों, जिन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए उनमें डा. बिश्वजीत धर, डीजी, डा. राम उपेन्द्र दास, सीनियर फेलो और डा. प्रबीर डे, फेलो शामिल थे। कई व्यक्तियों ने इस सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग लिया और खुली चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जलवायु परिवर्तन - उभरते मुद्दों पर सेमिनारः आरआईएस और भारत व्यापार प्रोन्नति संगठन (आईटीपीओ) ने 16 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जलवायु परिवर्तनः उभरते मुद्दों' पर एक संयुक्त सेमिनार आयोजित की। डा. बिश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस ने इस विषय पर भाषण दिया। इस सेमिनार में पर्यावरणीय वस्तुओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बाजार पहुंच; और वैश्विक कार्बन बाजार और भारत से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सत्र आयोजित किये गए। वक्ताओं में- डा. अपर्णा साहनी, जेएनयू; श्री के. एम. गोपाकुमार, टीडब्ल्यूएन; श्री बिशाल थापा, आईसीएफ; श्री आर. के. सेठी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; और डा. कौशिक रंजन बंदोपाध्याय, सीनियर फेलो, एआईटीडी शामिल थे। आरआईएस की ओर से डा. एस. के. मोहंती, सीनियर फेलो और डा. राम उपेन्द्र दास, सीनियर फेलो द्वारा प्रस्तुतिकरण दिए गए।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- 15 नवंबर-10 दिसंबर 2010 के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग मुद्दों (जीआरईसीआई) पर आरआईएस/ईआरआईए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आसियान देशों के राजनयिकों के लिए व्यापार एवं आर्थिक सहयोगः वैश्विक एवं क्षेत्रीय संभावना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 3 सितंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- अर्थशास्त्र विभाग, बोगर कृषि विश्वविद्यालय, बोगर, इण्डोनेशिया की मेजबानी में 23-27 अगस्त, 2010 को व्यापार अनुसंधानः ग्रेविटी मॉडलिंग पर आर्टनेट/आरआईएस क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से विदेशी राजनयिकों के लिए आरआईएस द्वारा 10 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में व्यापार और आर्थिक सहयोगः वैश्विक एवं क्षेत्रीय संभावना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- आईटीईसी/एससीएएपी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत 14 फरवरी-11 मार्च 2011 के दौरान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईआईडीपी) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

आरआईएस प्रकाशन

आरआईएस ने चार नीतिगत संक्षिप्त सार प्रकाशित किए; नौ चर्चा पत्र; दक्षिण एशिया आर्थिक जरनल के दो अंक; एशियन जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास समीक्षा का एक अंक; न्यू एशिया मॉनीटर के दो अंक; और आरआईएस डायरी का एक अंक प्रकाशित किए गए। आरआईएस प्रकाशनों को इसकी वेबसाइट- http://www.ris.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

बजट

आरआईएस को विदेश मंत्रालय से वर्ष 2010-2011 के दौरान 5.35 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्राप्त हुई।

■■

पुस्तकालय

31

मंत्रालय के पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकें, समृद्ध स्रोत सामग्री और मानचित्रों का विशाल संग्रहण, माइक्रोफिल्में एवं सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। यह नीति नियोजन और शोध की सहायता के लिए आधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित है। पुस्तकालय लगभग 450 पत्रिकाओं, जर्नलों (ऑनलाइन जर्नलों एवं डेटाबेस सहित) और अखबारों की खरीददारी/प्राप्ति और रखरखाव करता है।

पुस्तकालय के पास एक आंतरिक कंप्यूटर प्रणाली है, जिसमें एक सर्वर और 12 पीसी टर्मिनल हैं। इस प्रणाली में हिन्दी में भी डाटा की एंट्री और पुनः प्राप्ति कार्य किया जाता है। पुस्तकालय में विदेशी मामलों एवं वर्तमान मामलों पर सीडी-रोम डाटाबेस है। पुस्तकालय के पीसी में सीडी-राइटर और लेजर प्रिंटर भी लगे हैं। पुस्तकालय में एक स्कैनर, एक माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिशे प्रिंटर, और फोटोकापियर भी है।

पुस्तकालय समिति पुस्तकों के क्रय और जर्नलों/आवधिक पत्रिकाओं को मंगवाने के साथ-साथ पुस्तकालयों के क्रिया-कलापों का प्रबंधन करती है। अप्रैल 2010 में पुस्तकालय समिति का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष संयुक्त सचिव (पीपी एंड आर) हैं, प्रादेशिक प्रभागों के तीन निदेशक सदस्य हैं और निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) इसके सदस्य सचिव हैं।

पुस्तकालय प्रबंधन के समस्त पहलुओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत पुस्तकालय साफ्टवेयर पैकेज ''लिबसिस'' तैयार कराकर समस्त प्रलेखन ग्रंथ संबंधी सेवाओं एवं पुस्तकालय के अन्य कार्यों एवं सेवाओं को कम्पयूटरीकृत कर दिया गया है। लिबसिस में मार्क के साथ-साथ नॉन-मार्क फार्मेट का प्रयोग किया जाता है और यह बूलियन आपरेटरों के प्रयोग से शब्द आधारित फ्री टैक्स्ट सर्चिंग की सहायता करता है। यह डाटाबेस को अद्यतन करने से पहले इनपुट डाटा का ऑनलाइन सत्यापन भी करता है। पटियाला हाऊस स्थित विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय के समस्त पीसी में इंटरानेट के माध्यम से समस्त पुस्तकों, मानचित्रों, दस्तावेजों एवं पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली पत्रिकाओं से चुने गए लेखों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। पुस्तकालय की जानकारी www.mealib.nic.in नामक विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइट पर भी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तकालय में प्राप्त समस्त नए दस्तावेजों अर्थात् पुस्तकों, मानचित्रों, माइक्रोफिल्मों, पत्रिकाओं से चुने गए लेखों को विदेशी मामले संबंधी फेयर्स डाटाबेस में नियमित रूप से संग्रहित किया जाता है। इस डाटाबेस और सीडी-रोम डाटाबेसों का प्रयोग करके पुस्तकालय वर्तमान जागरूकता सेवा और ग्रंथ सूची एवं निर्देशिका सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय नियमित तौर पर निम्नलिखित जारी करता हैः

विदेशी मामलों से संबंधित प्रलेखन बुलेटिन (एफएडीबी): अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संबंधित विषयों पर चुनिंदा लेखों की एक सूची।

हाल ही में हुए परिवर्धनः पुस्तकालय में पुस्तकों/प्रकाशनों की विस्तृत सूची शामिल की गई।

घटनाक्रमः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण समाचार मदें।

पुस्तकालय नियमित रूप से दैनिक नया क्रोनिकल पुस्तक सतर्कता और लेख सतर्कता सेवा प्रदान करता है, जो मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों में सभी विदेश सेवा अधिकारियों को ग्रुप ई-मेल आईडी के जरिए भेजे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त-पुस्तकालय में नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और केन्द्रों में उपयोगकर्ताओं के लिए 'ई.आई.यू. ऑनलाइन डाटाबेस/सर्विसेज', 'डाटा मानीटर से एम.बी.आई.सी.', 'बिजनेस मानीटर इंटरनेशनल', 'केसिंग्स वर्ल्ड न्यूज आरकाइव', 'न्यूजपेपर डायरेक्ट' और 'जे.एस.टी.ओ.आर.' आदि की सुविधा है। ये ऑनलाइन डेटाबेस और पत्र-पत्रिकाएं प्रयोक्ता नाम तथा पासवर्ड के जरिए इंटरनेट पर सुलभ हो सकती हैं। ऐसे नामों की एक सूची मुख्यालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों में भी परिचालित की गई है तथा यह विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइटः www.mealib.nic.in पर उपलब्ध है।

एनआईसी के सहयोग से पुस्तकालय ने विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1948 से 1998-99 तक) तथा विदेश मंत्रालय के अभिलेख (1995 से 1999 (अगस्त)) के सीडी रोम रूपांतर का एक पूरा पाठ निकाला है। सीडी संबंधी सूचना किसी भी दिए हुए शब्द या शब्द युग्म पर बुलियन खोज सहित संयुक्त खोज के जरिए पुनः प्राप्त की जा सकती है। यह सीडी रोम रूपांतर 1 जनवरी, 2000 को उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किया गया। पटियाला हाऊस, नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में संदर्भ हेतु इस सीडी का उपयोग किया जा सकता है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय संबंधी अभिलेखों के पश्च-रूपांतरण एवं बार-कोडिंग की परियोजना। इस अवधि के दौरान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

पुस्तकालय दिल्ली स्थित विभिन्न संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन कर रहे छात्रों को समय–समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

निदेशक एवं एएलआईओ ने सदस्य के रूप में आईएफएलए समिति की बैठकों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आईएफएलए और एसएलए सहित विभिन्न व्यावसायिक संगठनों और एसोसिएशनों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लिया।

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार श्रेणी-V पुस्तकालय के रूप में वर्गीकरण हेतु अपेक्षाएं पूरी करता है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइट एचटीटीपीः//एमईए लिब.निक.इन को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

शोधकर्ताओं सहित पुस्तकालय प्रयोक्ताओं का सीडी-रोम डेटाबेस तथा विदेश मामलों संबंधी सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली (एमएआईआरएस) सहित पुस्तकालय तथा इसके डेटाबेस का लाभ उठाने के लिए स्वागत है। शोधकर्ताओं सहित सभी पुस्तकालय प्रयोक्ताओं के लिए फोटोग्राफी और कंप्यूटर प्रिंट सुविधाएं उपलब्ध हैं।

■■

परिशिष्ट

परिशिष्ट ।

वर्ष 2010 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत की गयी संधियां/अभिसमय/करार

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
(क)	**बहुपक्षीय**			
1.	सेवाओं में व्यापार संबंधी सार्क करार (एसएटीआईएस)	29.4.2010	3.9.2010	
2.	अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (आईआरईएनए) का विधान	17.3.2009	22.3.2010	
3.	पर्यावरण पर सहयोग संबंधी सार्क अभिसमय	29.4.2010	5.10.2010	
4.	नाभिकीय क्षति संबंधी पूरक अभिसमय पर हस्ताक्षर	27.10.2010		
5.	तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन पर तुर्कमेनिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अंतर-सरकारी करार।	11.12.2010		
6.	तुर्कमेनिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच गैस पाइप लाइन ढांचा करार।	11.12.2010		
(ख)	**द्विपक्षीय**			
1.	**अंगोला** तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के लिए भारत गणराज्य सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अंगोला गणराज्य सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	1.11.2010		
2.	**अर्जेंटीना गणराज्य** नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और अर्जेंटीना गणराज्य की सरकार के बीच करार।	23.9.2010		
3.	कूटनीतिक मिशन या कौंसिली पोस्ट के पारिवारिक सदस्यों के लाभकारी व्यवसाय पर भारत गणराज्य की सरकार और अर्जेंटीना गणराज्य की सरकार के बीच करार।	4.10.2010		
4.	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के कृषि, पशुधन और मत्स्यपालन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	11.9.2010		
5.	**ऑस्ट्रेलिया** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और आस्ट्रेलिया सरकार के संसाधन, ऊर्जा एवं पर्यटन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन।	5.2.2010		
6.	**ऑस्ट्रिया** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और ऑस्ट्रिया गणराज्य के कृषि, वन्य पर्यावरण और जल प्रबंध मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	13.9.2010		

परिशिष्ट ।

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
7.	**बांग्लादेश** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध दवाओं के व्यापार पर रोक लगाने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	11.1.2010	10.2.2010	
8.	आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	11.1.2010	10.2.2010	
9.	दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	11.1.2010	9.8.2010	
10.	**भूटान** मांगदेच्छु जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच करार।	30.4.2010		
11.	पुनातसांगच्छू-II जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच करार।	30.4.2010		
12.	**बोस्निया एवं हर्जेगोविना** भारत गणराज्य की सरकार और बोस्निया एवं हर्जेगोविना की मंत्रिपरिषद के बीच हवाई सेवाओं के लिए करार।	21.5.2010		
13.	**बोत्सवाना** विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और बोत्सवाना गणराज्य की सरकार के बीच करार।	17.6.2010		
14.	लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और बोत्सवाना गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	17.6.2010		
15.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और बोत्सवाना गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	9.1.2010		
16.	**मध्य अफ्रीकी गणराज्य** मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईटीआई) की स्थापना के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	16.3.2010		
17.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और मध्य अफ्रीकी गणराज्य के विदेश कार्य क्षेत्रीय एकीकृत और फ्रांकोफोन मंत्रालय के बीच परामर्शों के लिए प्रोतोकॉल।	3.9.2010		
18.	भारत गणराज्य की सरकार और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	3.9.2010		
19.	**कनाडा** सांस्कृतिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार के संस्कृति मंत्रालय और कनाडायाई हैरिटेज विभाग के बीच समझौता ज्ञापन।	27.6.2010		
20.	नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कनाडा की सरकार के बीच करार।	27.6.2010		

परिशिष्ट ।

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
21.	उच्च शिक्षा में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और कनाडा की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	27.6.2010		
22.	पृथ्वी विज्ञान और खनन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य के खान मंत्रालय और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन।	27.6.2010		
23.	भूविज्ञान और खनिज स्रोतों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य के खान मंत्रालय और कनाडा के औन्टारियो प्रांत के उत्तरी विकास, खान और वन्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	8.7.2010		
24.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और कांगो गणराज्य के विदेश कार्य और सहयोग मंत्रालय के बीच परामर्शों के लिए प्रोतोकॉल।	17.3.2010		
25.	निवेशों के परस्पर संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	13.4.2010	30.4.2010	
26.	**चीन** भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच सीधा सुरक्षित दूरभाष संपर्क स्थापित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	7.4.2010		
27.	सिविल सेवाओं, कार्मिक प्रबंध और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के मानव संसाधन एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	27.5.2010		
28.	खेलकूद में सहयोग पर भारत गणराज्य के युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के खेलकूद सामान्य प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन।	27.5.2010		
29.	दोनों देशों के एअरलाइन कर्मचारियों हेतु वीजा आवेदन औपचारिकताओं को व्यवस्थित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	27.5.2010		
30.	भारतीय रिजर्व बैंक और चीन बैंकिंग विनियमन आयोग के बीच समझौता ज्ञापन।	16.12.2010		
31.	भारत के निर्यात-आयात बैंक और चीन विकास बैंक निगम के बीच समझौता ज्ञापन।	16.12.2010		
32.	बाढ़ के मौसम में लैंगकिन यांगबो/ सतलुज नदी के संबंध में चीन द्वारा भारत को जल संबंधी सूचना देने की व्यवस्था के बारे में भारत गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	16.12.2010		
33.	मीडिया आदान-प्रदान पर भारत गणराज्य की सरकार के विदेश मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य की सरकार के राष्ट्रीय परिषद सूचना कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।	16.12.2010		
34.	हरित प्रौद्योगिकी पर भारत गणराज्य की सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	16.12.2010		

परिशिष्ट ।

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
35.	वर्ष 2010-2012 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदानों के कार्यक्रम।	16.12.2010		
36.	**क्रोशिया** स्वास्थ्य और दवाओ के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और क्रोशिया गणराज्य की सरकार के बीच करार।	9.6.2010		
37.	**चैक गणराज्य** प्रेग में 11 अक्तूबर, 1996 को हस्ताक्षरित निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य और चैक गणराज्य के बीच करार में संशोधन के लिए भारत गणराज्य और चैक गणराज्य के बीच प्रोतोकॉल।	10.6.2010	2.8.2010	
38.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और चैक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	9.6.2010	20.8.2010	
39.	आर्थिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और चैक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	9.6.2010		
40.	सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रबंधों के कार्यान्वयन पर भारत गणराज्य की सरकार और चैक गणराज्य की सरकार के बीच प्रशासनिक प्रबंध।	9.6.2010		
41.	**चाड** भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चाड गणराज्य के विदेश कार्य अफ्रीकी एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकॉल।	6.9.2010		
42.	**डेनमार्क** सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और डेनमार्क साम्राज्य के बीच करार।	17.2.2010	14.6.2010	
43.	**डोमिनिकन गणराज्य** डोमिनिकन गणराज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईटीआई) की स्थापना के लिए भारत गणराज्य की सरकार और डोमिनिकन गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	23.1.2010		
44.	**यूरोपीय समुदाय** वैज्ञानिक और प्रौद्योगीकीय सहयोग संबंधी करार के नवीकरण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और यूरोपीय समुदाय के बीच करार।	13.11.2010	7.5.2010	
45.	**यूरोपीय आयोग** संस्कृति पर यूरोपीय आयोग और भारत सरकार के बीच संयुक्त करार	10.12.2010		
46.	**फिनलैंड** आर्थिक सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैंड गणराज्य की सरकार के बीच करार।	26.3.2010	7.6.2010	
47.	सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फिनलैंड के परिवहन एवं संचार मंत्रालय के बीच करार।	19.1.2010		

परिशिष्ट I

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
48.	**फ्रांस** नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच सहयोग करार।	13.9.2008	12.1.2010	
49.	**जॉर्जिया** व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जॉर्जिया की सरकार के बीच सहयोग करार।	30.3.2010		
50.	संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जॉर्जिया की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार।	30.3.2010		
51.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और जॉर्जिया की सरकार के बीच करार।	30.3.2010		
52.	**गाम्बिया** भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और गाम्बिया गणराज्य के विदेश कार्य, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रवासी गैम्बियाई मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकॉल।	19.8.2010		
53.	**ईरान इस्लामिक गणराज्य** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ईरान इस्लामिक गणराज्य के विद्युत मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	9.7.2010		
54.	भारत गणराज्य की सरकार और ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार के बीच हवाई सेवाओं के लिए करार।	9.7.2010		
55.	**आइसलैंड** भारत गणराज्य की सरकार और आइसलैंड की सरकार के बीच हवाई सेवाओं के लिए करार।	14.1.2010		
56.	**जापान** जापान-भारत ऊर्जा संवाद की चौथी बैठक के अवसर पर जापान के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय और भारत के योजना आयोग के बीच संयुक्त वक्तव्य।	30.4.2010		
57.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इलौक्ट्रोनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर के सशक्तीकरण हेतु परियोजना के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण और भारत सरकार के बीच अनुदान करार।	26.6.2010		
58.	अगले दशक में भारत-जापान रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के लिए संयुक्त वक्तव्य दृष्टिकोण।	25.10.2010		
59.	वीजा प्रक्रियाओं के सरलीकारण पर भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	25.10.2010		
60.	भारत गणराज्य और जापान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार संपन्न करने पर भारत गणराज्य और जापान के नेताओं के बीच संयुक्त घोषणा।	25.10.2010		

परिशिष्ट I

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
61.	**कोरिया** वर्ष 2010-2012 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत गणराज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच सहयोग कार्यक्रम।	25.1.2010		
62.	बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कोरिया अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन।	25.1.2010		
63.	सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग पर भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) और कोरिया गणराज्य के ज्ञान, अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	25.1.2010		
64.	दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारतीय गणराज्य की सरकार और कोरियाई गणराज्य की सरकार के बीच करार।	25.1.2010	9.8.2010	
65.	लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के लघु एवं मध्यम व्यापार प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन।	18.6.2010		
66.	सूचना सुरक्षा में सहयोग पर भारत गणराज्य के इंडियन कम्प्यूटर इर्मेजेंसी रैसपॉंस टीम (सीईआरपी-आईएम) (सूचना प्रौद्योगकी विभाग) और कोरिया गणराज्य के कोरिया कम्प्यूटर इर्मेजेंसी रैसपॉंस टीम कॉर्डीनेशन सेंटर (केआरसीईआरटी/सीसी), (कोरिया इंटरनेट एंड सीक्योरिटी एजेंसी) के बीच समझौता ज्ञापन।	20.7.2010		
67.	अनुसंधान एवं विकास सहयोग के संबंध में भारत के रक्षा मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	3.9.2010		
68.	भारत गणराज्य की भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और कोरिया गणराज्य के विदेश कार्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान (आईएफएएनएस) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	18.6.2010		
69.	**लातविया** निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लातविया गणराज्य की सरकार के बीच करार।	18.2.2010	5.3.2010	
70.	**लाइबेरिया** भारत गणराज्य की सरकार और लाइबेरिया गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	5.7.2010		
71.	**लक्समबर्ग** सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और ग्रांड डची ऑफ लक्समबर्ग के बीच करार।	30.9.2009	15.6.2010	
72.	**मलावी** भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और और मलावी गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्शों के लिए प्रोतोकॉल।	8.1.2010		

परिशिष्ट I

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
73.	खनिज संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	3.11.2010		
74.	भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच सामान्य सहयोग करार।	3.11.2010		
75.	ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	3.11.2010		
76.	स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	3.11.2010		
77.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	8.1.2010		
78.	**मलेशिया** भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि।	20.1.2010	27.9.2010	
79.	सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	27.10.2010		
80.	**मोजाम्बिक** खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	30.9.2010		
81.	आय पर कर के संबंध में कर-अपवंचन रोकने के लिए और दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच करार।	30.9.2010		
82.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और मोजाम्बिक गणराज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	30.9.2010		
83.	**मॉरीशस** सूचना सुरक्षा में सहयोग पर भारत गणराज्य के मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) और मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रीय कम्प्यूटर बोर्ड (एनसीबी) के बीच समझौता ज्ञापन।	3.7.2010		
84.	भारत गणराज्य के नेशनल इनफोरमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (एनआईसीएसआई) और मॉरीशस गणराज्य के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय(एमआईसीटी) के बीच समझौता ज्ञापन।	16.3.2010		
85.	**मंगोलिया** मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल के सचिवालय और लोक सभा सचिवालय, भारत के बीच सहयोग पर प्रोतोकॉल।	28.6.2010		
86.	**म्यांमा** आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य और म्यांमा संघ के बीच संधि।	27.7.2010	25.8.2010	

परिशिष्ट I

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
87.	सूचना सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमा संघ की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	27.7.2010		
88.	**नेपाल** हवाई सेवाओं के लिए भारत गणराज्य की सरकार और नेपाल की सरकार के बीच करार।	16.2.2010		
89.	हेतौदा, जिला मकवानपुर, नेपाल में नेपाल-भारत मैत्री पॉलिटेक्नीक की स्थापना के लिए भारत की सरकार और नेपाल की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	16.2.2010		
90.	वीरगंज, पारसा में वीरगंज सब- मैट्रोपॉलिटन सिटी आफिस के लिए नेपाल-भारत मैत्री सभा गृह के निर्माण के लिए भारत की सरकार और नेपाल की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	16.2.2010		
91.	भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ पांच सीमा केंद्रों पर रेलवे ढांचे के विकास के संबंध में भारत की सरकार और नेपाल की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	16.2.2010		
92.	नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क ढांचे को मजबूत बनाने के संबंध में भारत की सरकार और नेपाल की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	15.1.2010		
93.	खुमुल्तार, ललितपुर, नेपाल में नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी के परिसर में नेपाल-भारत मैत्री विज्ञान शिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिसर (एनसीएसएम) नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन।	11.5.2010		
94.	**नीदरलैंड** सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और नीदरलैंड साम्राज्य के बीच करार।	22.10.2009	15.6.2010	
95.	**नार्वे** मत्स्य-पालन मुद्दों पर सहयोग के लिए कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य-पालन विभाग, भारत सरकार और नार्वे के मत्स्य-पालन एवं तटीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	2.3.2010		
96.	स्थानीय सुशासन पर परस्पर सहयोग के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत गणराज्य और नार्वे साम्राज्य के स्थानीय सरकार एवं क्षेत्रीय विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	15.9.2010		
97.	**पेरु** वर्ष 2010-12 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार (डीएसटी) और पेरु गणराज्य की सरकार (सीओएनसीवाईटीईसी) के बीच प्रोतोकॉल।	22.1.2010		
98.	**रूसी संघ** भारत गणराज्य को आपूर्ति किए जाने वाले रूसी हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए बिक्री-पश्च सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच करार।	7.12.2009	12.2.2010	

परिशिष्ट I

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
99.	सैन्य तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में बौद्धिक संपत्ति अधिकारों (आईपीआर) की परस्पर सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच करार।	6.12.2005	19.2.2010	
100.	शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच करार।	12.3.2010		
101.	तेल एवं गैस के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच करार।	21.12.2010		
102.	**रवांडा** स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और रवांडा गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	21.12.2010		
103.	सऊदी अरब बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और सऊदी अरब गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किंग अब्दुल अजीज सीटी के बीच समझौता ज्ञापन।	28.2.2010		
104.	सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के बीच समाचार सहयोग पर करार।	28.2.2010		
105.	सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग पर सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यटिंग (सी-डैक), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत गणराज्य और सऊदी अरब गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किंग अब्दुल अजीज सीटी के बीच समझौता ज्ञापन।	28.2.2010		
106.	सांस्कृतिक सहयोग पर सऊदी अरब साम्राज्य के संस्कृति एवं सूचना मंत्रालय और भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	28.2.2010		
107.	सऊदी अरब साम्राज्य और भारत गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि।	28.2.2010		
108.	दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच करार।	28.2.2010	4.11.2010	
109.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार के बीच करार।	28.2.2010	9.11.2010	
110.	सऊदी अरब साम्राज्य और भारत गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि।	3.11.2010	4.11.2010	
111.	**सेशल्स** निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सेशल्स गणराज्य की सरकार के बीच करार।	2.6.2010	25.6.2010	
112.	**दक्षिण अफ्रीका** परस्पर सहयोग के लिए भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग की कूटनीतिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन।	4.6.2010		
113.	हवाई सेवाओं के लिए भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच करार।	4.6.2010		

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
114.	कृषि सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच करार।	4.6.2010		
115.	**श्रीलंका** दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार।	9.6.2010	27.9.2010	
116.	आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता पर भारत गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच संधि।	9.6.2010	30.6.2010	
117.	स्विस परिसंघःसामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच करार।	3.9.2010	7.7.2010	
118.	**स्वीडन** भारत-स्वीडन नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और उद्यम, ऊर्जा एवं संचार मंत्रालय, स्वीडन के बीच समझौता ज्ञापन।	19.4.2010		
119.	सीरियाई अरब गणराज्यःव्यापार सुविधा और प्रक्रिया उपाय पर सहयोग के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य और व्यापार एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय सीरियाई अरब गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन।	10.6.2010		
120.	उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	5.10.2010		
121.	सीरियाई अरब गणराज्य के रेडियो और दूरदर्शन के लिए सामान्य संगठन और भारत गणराज्य के प्रसार भारती (ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) के बीच समझौता ज्ञापन।	27.11.2010		
122.	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और सीरियाई न्यूज एजेंसी (एसएएनए) के बीच समझौता ज्ञापन।	27.11.2010		
123.	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा की छूट पर भारत गणराज्य की सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के बीच करार।	10.6.2010		
124.	वर्ष 2010-13 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग का कार्यपालक कार्यक्रम।	27.11.2010		
125.	**ताजिकिस्तान** कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और ताजिकिस्तान गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	7.10.2010		
126.	**तुर्कमेनिस्तान** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और तुर्कमेनिस्तान की सरकार के बीच करार।	25.5.2010	20.8.2010	

परिशिष्ट I

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
127.	**यूएसए** कृषि सहयोग एवं खाद्य सुरक्षा पर भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	16.3.2010		
128.	भारत-अमरीका आतंकवादरोधी सहयोग प्रयास।	23.7.2010		
129.	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और अमरीका के विदेश विभाग के बीच शेल गैस स्रोतों पर समझौता ज्ञापन।	6.11.2010		
130.	अमरीका-भारत ऊर्जा सहयोग कार्यक्रम की स्थापना के लिए भारत गणराज्य के योजना आयोग और अमरीका के वाणिज्य विभाग तथा अमीरकी व्यापार एवं विकास एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।	6.11.2010		
131.	संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास केंद्र पर सहयोग के लिए भारत के योजना आयोग और अमरीका के ऊर्जा विभाग के बीच करार।	4.11.2010		
132.	**जिम्बाब्वे** निवेशों के संवर्धनऔर परस्पर सुरक्षा के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार के बीच करार।	10.9.1999	4.10.2010	

परिशिष्ट II

1 जनवरी, 2010 से दिसंबर 2010 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज

क्रम सं	अभिसमय/संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
1.	आर्थिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैण्ड गणराज्य की सरकार के बीच करार	11.01.2010
2.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और डेनमार्क साम्राज्य के बीच करार	16.02.2010
3.	निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लातविया गणराज्य की सरकार के बीच करार	17.02.2010
4.	मत्स्य उद्योग के मुद्दों पर सहयोग के लिए कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार और नार्वे के मत्स्य पालन एवं तटीय कार्य मत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	25.02.2010
5.	संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जार्जिया की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार	29.03.2010
6.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जार्जिया की सरकार के बीच करार	29.03.2010
7.	व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग संबंधी अंतर-सरकारी आयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और जार्जिया सरकार के बीच करार	29.03.2010
8.	निवेशों के परस्पर संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच करार	13.04.2010
9.	स्थानीय सुशासन पर परस्पर सहयोग के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत गणराज्य और स्थानीय सरकार एवं क्षेत्रीय विकास मंत्रालय, नार्वे साम्राज्य के बीच समझौता ज्ञापन	30.04.2010
10.	आर्थिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार के बीच करार	03.06.2010
11.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार के बीच करार	03.06.2010
12.	स्वास्थ्य और औषध के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और क्रोएशिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	03.06.2010
13.	सूचना सुरक्षा में सहयोग पर इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम को-ओर्डिनेशन सेंटर (केआरसीईआरटी/सीसी), (कोरिया इंटरनेट एंड सिक्युरिटी एजेंसी), कोरिया गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन।	20.07.2010
14.	एपीटीए (आप्टा) सहभागी देशों के बीच व्यापार सुविधाओं पर ढांचागत करार; एपीटीए (आप्टा) सहभागी देशों के बीच सेवाओं में व्यापार के संवर्धन और उदारीकरण पर ढांचागत करार और एपीटीए (आपटा) सहभागी देशों के बीच निवेशों के संवर्धन, सुरक्षा और उदारीकरण पर ढांचागत करार।	23.08.2010
15.	नई दिल्ली में 2 नवंबर, 1994 को हस्ताक्षरित प्रोतोकॉल और नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2000 को हस्ताक्षरित पूरक प्रोतोकॉल द्वारा यथासंशोधित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्विस परिसंघ के बीच प्रोतोकॉल संशोधन करार।	27.08.2010
16.	नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और अर्जेंटीना गणराज्य की सरकार के बीच करार	20.09.2010

परिशिष्ट II

क्रम सं	अभिसमय/संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
17.	करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बरमुडा के बीच करार	28.09.2010
18.	आय पर कर के संबंध में कर-अपवंचन और दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोतोकॉल	30.09.2010
19.	आईबीएसए सीईटीआई की स्थापना के लिए राजस्व विभाग (राजस्व सचिव द्वारा यथाप्रतिनिधित्व) और संघीय राजस्व सचिवालय, ब्राजील (संघीय राजस्व के सचिव द्वारा यथा प्रतिनिधित्व) और दक्षिण अफ्रीका राजस्व सेवा (दक्षिण अफ्रीका राजस्व सेवा के आयुक्त द्वारा यथा प्रतिनिधित्व) के बीच समझौता ज्ञापन	04.10.2010
20.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच करार	15.10.2010
21.	भारत गणराज्य और नार्वे साम्राज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा पर करार	25.10.2010
22.	नाभिकीय क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति हेतु अभिसमय	26.10.2010
23.	निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लिथुआनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	2.11.2010
24.	तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन पर तुर्कमेनिस्तान सरकार, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अंतर-सरकारी करार	11.12.2010

परिशिष्ट III

1 जनवरी, 2010 से दिसंबर, 2010 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज

क्र.सं.	अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज	अनुसमर्थन जारी करने की तारीख
1.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और ग्रांड डची ऑफ लक्जमबर्ग के बीच करार	11.01.2010
2.	नाबिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास पर भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच सहयोग करार	12.01.2010
3.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और नीदरलैण्ड साम्राज्य के बीच करार	12.01.2010
4.	आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार	10.02.2010
5.	अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध दवाओं के व्यापार को रोकने पर भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार	10.02.2010
6.	भारत गणराज्य को आपूर्ति किए गए रशियन हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए ब्रिकी - पश्च सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच करार लागू होने की तारीख	12.02.2010 19.02.2010
7.	सैन्य तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआरएस) की परस्पर सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच करार	19.02.2010
8.	माल व्यापार करार और उसके अनुबंधों सहित; विवाद समाधान तंत्र पर करार, ढांचा करार संशोधन के लिए प्रोतोकॉल और माल व्यापार करार के अनुच्छेद 4 पर सहमति के संबंध में भारत गणराज्य और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग	02.02.2010
9.	निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लातविया गणराज्य की सरकार के बीच करार	05.03.2010
10.	अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (ईरना) के विधान	22.03.2010
11.	निवेशों के परस्पर संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच करार	13.04.2010
12.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग संबंधी करार के नवीकरण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और यूरोपीय समुदाय के बीच करार	07.05.2010
13.	आर्थिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैण्ड गणराज्य की सरकार के बीच करार	07.06.2010
14.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और डेनमार्क साम्राज्य के बीच करार	14.06.2010
15.	निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सेशल्स गणराज्य की सरकार के बीच करार	25.06.2010
16.	आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता पर भारत सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच संधि	30.06.2010

परिशिष्ट III

क्रम सं	अभिसमय/संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
17.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच करार	07.07.2010
18.	दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच करार	09.08.2010
19.	दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	09.08.2010
20.	निवेशों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए भारत गणराज्य और चेक गणराज्य के बीच करार के संशोधन पर भारत गणराज्य और चेक गणराज्य के बीच करार	02.08.2010
21.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और तुर्कमेनिस्तान की सरकार के बीच करार	20.08.2010
22.	सामाजिक सुरक्षा पर भारत गणराज्य और चेक गणराज्य के बीच करार	20.08.2010
23.	आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य और म्यामां संघ के बीच संधि	25.08.2010
24.	सेवाओं में व्यापार पर सार्क करार (एसएटीआईएस)	03.09.2010
25.	दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार	27.09.2010
26.	भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	27.09.2010
27.	दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच करार	28.09.2010
28.	निवेशों के संवर्धन और परस्पर सुरक्षा के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार के बीच करार	04.10.2010
29.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार के बीच करार	09.11.2010

परिशिष्ट IV

आइटेक भागीदार देशों की सूची

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
1.	अफगानिस्तान	41.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
2.	अलबानिया	42.	जीबोती
3.	अलजीरिया	43.	डोमिनिकन गणराज्य
4.	अंगोला	44.	पूर्व तिमोर
5.	अंग्यूला	45.	इक्वाडोर
6.	एंटिगुआ और बारबुडा	46.	मिस्र
7.	अर्जेंटीना	47.	एलसल्वाडोर
8.	आर्मेनिया	48.	बूमध्यवर्ती गिनी
9.	अजरबैजान	49.	इरिट्रिया
10.	बहामास	50.	इस्टोनिया
11.	बहरीन	51.	इथिओपिया
12.	बांग्लादेश	52.	फिजी
13.	बारबाडोस	53.	गैबोन
14.	बेलारुस	54.	गाम्बिया
15.	बेलीज	55.	जॉर्जिया
16.	बेनिन	56.	घाना
17.	भूटान	57.	ग्रेनाडा
18.	बोलिविया	58.	ग्वाटेमाला
19.	बोस्निया एवं हर्जेगोविना	59.	गिनी
20.	बोत्सवाना	60.	गिनी बिस्साउ
21.	ब्राजील	61.	गुयाना
22.	ब्रुनेई	62.	हैती
23.	बुलगारिया	63.	होंडुरास
24.	बुरकिना फासो	64.	हंगरी
25.	बुरुंडी	65.	इंडोनेशिया
26.	कम्बोडिया	66.	ईरान
27.	कैमरुन	67.	इराक
28.	केप वरडे द्वीप	68.	आइवरी कोस्ट
29.	कैमेन द्वीप	69.	जमैका
30.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	70.	जॉर्डन
31.	चाड	71.	कजाखस्तान
32.	चिली	72.	केन्या
33.	कोलम्बिया	73.	किरीबाती
34.	डोमिनिका राष्ट्रमण्डल	74.	कोरिया (डी पी आर के)
35.	कॉमोरोस	75.	किर्गिस्तान
36.	कुक आइलैंड	76.	लॉओस
37.	कोस्टा रिका	77.	लातविया
38.	क्रोसिया	78.	लेबनान
39.	क्यूबा	79.	लेसेथो
40.	चेक गणराज्य	80.	लाईबेरिया

परिशिष्ट IV

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
81.	लीबिया	121.	रवान्डा
82.	लिथुआनिया	122.	समोआ
83.	मैसिडोनिया	123.	सेनेगल
84.	मैडागास्कर	124.	सर्बिया
85.	मलावी	125.	सेशल्स
86.	मलेशिया	126.	सियरा लियोन
87.	मालदीव	127.	सिंगापुर
88.	माली	128.	स्लोवाक गणराज्य
89.	मार्शल द्वीप	129.	सोलोमान द्वीप
90.	मॉरीतानिया	130.	दक्षिण अफ्रीका
91.	मॉरीशस	131.	श्रीलंका
92.	मैक्सिको	132.	सेंट किटस तथा नेविस
93.	माइक्रोनेशिया	133.	सेंट लुसिया
94.	मोलडोवा	134.	सेंट विंसेंट तथा ग्रेनाडाइन्स
95.	मंगोलिया	135.	सूडान
96.	मानटिनिग्रो	136.	सूरीनाम
97.	मांटसेराट	137.	स्वाजीलैंड
98.	मोरक्को	138.	सीरिया
99.	मोजाम्बिक	139.	ताजिकिस्तान
100.	म्यामां	140.	तंजानिया
101.	नामीबिया	141.	थाइलैंड
102.	नौरू	142.	टोगो
103.	नेपाल	143.	टोंगा
104.	निकारागुआ	144.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो
105.	नाइजर	145.	टयूनीसिया
106.	नाइजीरिया	146.	तुर्की
107.	ओमान	147.	तुर्कमेनिस्तान
108.	पलावु	148.	तुर्क एवं कैकोस द्वीप
109.	फिलीस्तीन	149.	तुवालु
110.	पनामा	150.	यूगांडा
111.	पापुआ न्यू गिनी	151.	यूक्रेन
112.	परागुवे	152.	उरुग्वे
113.	पेरू	153.	उज्बेकिस्तान
114.	फिलीपीन्स	154.	वानुआतू
115.	पोलैंड	155.	वेनेजुएला
116.	कतर	156.	वियतनाम
117.	कांगो गणराज्य	157.	यमन
118.	साओ तोमे गणराज्य	158.	जाम्बिया
119.	रोमानिया	159.	जिम्बाब्वे
120.	रूस		

परिशिष्ट V

पैनल में शामिल आइटेक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	शहर
1.	सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान	नई दिल्ली
2.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रणाली लेखा परीक्षा केन्द्र सूचना प्रौद्योगिक, दूर संचार और अंग्रेजी पाठ्यक्रम	नोएडा
3.	अपटेक लिमिटेड	नई दिल्ली
4.	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग	मोहाली
5.	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग	नोएडा
6.	दूरसंचार प्रौद्योगिकी व प्रभंधन उत्कृष्टता केन्द्र	मुम्भई
7.	सी.एम.सी. लिमिटेड	नई दिल्ली
8.	एन.आई.आई.टी. लिमिटेड	नई दिल्ली
9.	अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	हैदराभाद
10.	यू.टी.एल. प्रौद्योगिकी लिमिटेडप्रभंध पाठ्यक्रम	भैंगलूर
11.	भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज	हैदराभाद
12.	अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
13.	भारतीय प्रभंधन संस्थान	अहमदाभाद
14.	अंतर्राष्ट्रीय प्रभंधन संस्थान	नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय भैंक प्रभंधन संस्थानएसएमई/ग्रामीण विकास पाठ्यक्रम	पुणे
16.	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान	अहमदाभाद
17.	राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान	नोएडा
18.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम संस्थान	हैदराभाद
19.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थानविशेष पाठ्यक्रम	हैदराभाद
20.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण भ्यूरो	नई दिल्ली
21.	मानव पुनर्वास प्रभंधन संस्थान	नई दिल्ली
22.	भारतीय जनसंचार संस्थान	नई दिल्ली
23.	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र	कोलकाता
24.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड भ्यूरो	नई दिल्ली
25.	राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (भारतीय मानक भ्यूरो)	नोएडा
26.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान	चेन्नई
27.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासनिक विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
28.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	नई दिल्ली
29.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थानतकनीकी पाठ्यक्रम	नोएडा
30.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण संस्थान	फरीदाभाद
31.	केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान	हैदराभाद
32.	केन्द्रीय औजार अभिकल्प संस्थान	हैदराभाद
33.	केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन	नई दिल्ली
34.	द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	केरल
35.	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान	हैदराभाद
36.	भारतीय उत्पाद प्रभंधन संस्थान	उड़ीसा

परिशिष्ट V

क्र. सं.	संस्थान का नाम	शहर
37.	भारतीय सूदुर संवेदन संस्थान	देहरादून
38.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	
	(क) वैकल्पिक जल ऊर्जा	
	(ख) जल विज्ञान विभाग	
	(ग) जल संसाधन विकास एवं प्रभंध विभाग	रूड़की
39.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	एस.ए.एस. नगर, पंजाभ
40.	राइटस (केवल रेलवे कार्मिकों के लिए पाठ्यकम)	गुड़गांव
41.	दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघपर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा पाठ्यक्रम	कोयम्भतूर
42.	दी भेयरफूट कॉलेज	तिलोनिया, राजस्थान
43.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र	चेन्नै
44.	भारतीय विज्ञान संस्थान	भंगलौर
45.	सौर ऊर्जा केन्द्र	गुड़गांव
46.	टेरी (ऊर्जा अनुसंधान संस्थान)	नई दिल्ली

परिशिष्ट VI

2010-11 की अवधि के दौरान नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्त पोषित की गई संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित/आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठियां/अध्ययन परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभाथा
1.	पाक अधिकृत कश्मीर पर अनुसंधान परियोजना (**5** वर्ष)	रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली
2.	नेपाल पर संगोष्ठी	एशिया केन्द्र, बेंगलुरु
3.	कलकता विश्वविद्यालय परिसर, अलीपुर में विदेश नीति अध्ययन संस्थान की स्थापना (आवर्ती अनुदान)	कलकता विश्वविद्यालय, कोलकाता
4.	'अबू-रैहान-अल-बरूनी और वर्तमान विश्व में उनकी प्रासंगिकता' पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
5.	'भारत के पड़ोसी देशः अगले दो दशकों में चुनौतियां' शीर्षक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली
6.	'परमाणु निरस्त्रीकरणः मानव सुरक्षा हेतु वैश्विक उपाय' पर संगोष्ठी	विद्या प्रसारक मंडल, मुम्बई
7.	'शांति, सामाजिक समावेशन और सतत विकास के लिए शिक्षाः एक प्रतिमान विपथन की ओर विषय पर उच्च शिक्षा' (आईसीएमजीयू-2010) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल
8.	चीन संबंधी अध्ययन पर तीसरी राष्ट्रीय कार्यशाला	जादवपुर विश्वविद्यालय के साथ चीन अध्ययन संस्थान (आईसीएस)

परिशिष्ट VII

1 जनवरी से 30 नवंबर 2010 तक प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदन पत्रों और तत्काल योजना सहित जारी किए गए पासपोर्टों, विविध आवेदन पत्रों की संख्या और प्रदत्त सेवाएं एवं राजस्व (तत्काल योजना के तहत राजस्व सहित) और पासपोर्ट कार्यालयों के व्यय संबंधी आंकड़े को दर्शाने वाला विवरण।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/ पासपोर्ट कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त हुए विविध आवेदनों पत्रों की संख्या	दी गई विविध सेवाएं	तत्काल सेवा के तहत जारी पासपोर्टों की संख्या	तत्काल सेवा के तहत प्राप्त राजस्व	कुल राजस्व	कुल व्यय
अहमदाबाद	301972	300409	13894	14147	15635	20073000	318708937	50658839
अमृतसर	82238	84472	14202	13679	2879	4875000	96731525	#
बंगलौर	325430	296212	28238	26925	62907	117207100	407015766	48957295
बरेली	65512	58828	10437	10061	2647	4218000	73960571	21462764
भोपाल	85479	89126	3071	3047	14464	18753000	103813772	14826446
बुवनेश्वर	44955	44417	5283	5236	15590	38348500	71390615	8185425
चंडीगढ़	239665	233911	27157	26808	12547	32082200	271483130	43516013
चेन्नै	226696	230058	36131	32012	89690	224678300	299776547	36836012
कोयम्बतूर	77811	74923	3032	3005	20359	52910900	109541005	11453464
देहरादून	49978	44655	3967	3663	3666	6856600	56923525	7500994
दिल्ली	318480	281154	27010	25991	61972	153055300	556240874	52572425
गाजियाबाद	128544	116697	10311	9379	9023	18094300	133331335	17559583
गुवाहाटी	54620	44737	6221	5424	7568	19040200	63627600	12426575
हैदराबाद	402545	330749	52354	46534	69625	189625900	526043637	67158507
जयपुर	179752	174934	29981	29835	20512	51038800	223499980	28411263
जालंधर	122582	125225	28854	27636	1839	3333900	155059044	55274911
जम्मू	24953	21158	3665	3369	135	194500	27850651	9666473
कोचीन	239138	236591	43929	43035	41705	102227000	312561000	52757892
कोलकाता	292825	253456	32132	28167	13291	3299600	294137465	34271260
कोझिकोड	193275	191869	29514	29160	28787	43786000	241144934	39024497
लखनऊ	328971	325236	69740	66977	14099	21690500	404182510	56417912
मदुरै	119419	120812	17947	17805	4362	10384900	133888148	26725889
मल्लापुरम	154508	150753	29847	29847	17533	26622500	196625807	26954279
मुंबई	310530	296031	20393	19734	22253	35606500	354016976	81911245
नागपुर	75689	66494	2409	2310	6882	8709000	83820883	7544723
पणजी	33755	33687	6566	6316	1789	2685000	42602671	6350962
पटना	138186	170921	32464	30044	6016	9863000	162779950	29769345
पुणे	144157	129514	6766	6779	16968	25827500	170048100	15517079
रायपुर	29593	26821	906	898	4540	11690000	35986700	3419518
रांची	44814	44816	6736	6700	10911	16529500	45982783	8365320
शिमला	25438	25524	2470	2487	2426	526000	30936318	4743020
श्रीनगर	33842	39021	1650	1466	519	763500	41218894	9436286
सूरत	94186	91051	10544	9889	1727	2238000	97544700	14933191
ठाणे	175729	164372	8447	8325	10248	16508500	192386400	30319084
तिरुवनंतपुरम	139234	142005	34423	32969	35661	54748500	206206994	26842166
त्रिची	120421	118251	21279	21148	11189	16383500	152125108	26979346
विशाखापट्टनम	77166	72554	29115	25417	10748	16700500	97916590	12236073
जोड़	**5502088**	**5251444**	**711085**	**676224**	**672712**	**1381175000**	**6791111445**	**1000986076**

पासपोर्ट कार्यालय जालंधर द्वारा किया गया

परिशिष्ट VIII

वर्ष 2010-11 के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में संवर्ग संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय के बजट से प्रदान किए गए पद और संवर्ग बाह्य पद इत्यादि शामिल हैं)।

क्रम सं.	काडर/पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रुप I	5	28	33
2	ग्रुप II	6	40	46
3	ग्रुप III	38	123	161
4	ग्रुप IV	44	121	165
5	कनिष्ठ प्रशा. संवर्ग/वरिष्ठ वेतनमान	70	164	234
6	(i) कनिष्ठ वेतनमान	10	25	35
	(ii) परिवीक्षार्थी आरक्षित	62	-	62
	(iii) छुट्टी आरक्षित	15	-	15
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	19	-	19
	(v) प्रशिक्षण आरक्षित	7	-	7
	कुल जोड़	**276**	**501**	**777**
भा.वि.से.(ख)				
7	(i) ग्रेड I	84	122	206
	(ii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	6	-	6
8	(i) एकीकृत ग्रेड II & III	149	242	391
	(ii) अवकाश आरक्षित	30	-	30
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	16	-	16
	(iv) प्रशिक्षण आरक्षित	25	-	25
9	(i) ग्रेड IV	176	421	597
	(ii) अवकाश आरक्षित	60	-	60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	55	-	55
10	(i) ग्रेड V/VI	142	103	245
	(ii) अवकाश आरक्षित	60	-	60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	14	-	14
11	(i) साइफर संवर्ग के ग्रेड II	39	147	186
	(ii) अवकाश आरक्षित	24	-	24
12	(i) आशुलिपिक संवर्ग	125	513	638
	(ii) अवकाश आरक्षित	47	-	47
	(iii) प्राशिक्षण आरक्षित (हिन्दी)	10	-	10
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	12	-	12
13	दुभाषिया संवर्ग	7	26	33
14	एल एंड टी संवर्ग	23	1	24
	योग	**1104**	**1578**	**2682**
	कुल योग	**1380**	**2079**	**3459**

परिशिष्ट IX

विदेश मंत्रालय में अप्रैल 2010 से नवम्बर 2010 तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ की गई भर्ती संबंधी आंकड़े।

समूह	रिक्तियों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			अनारक्षित
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
समूह क	6	-	-	-	6
समूह क (बाह्य संवर्ग)	2	-	-	-	2
समूह ख	93	13	7	8	65
समूह ग	9	2	-	1	6
कुल	**110**	**15**	**7**	**9**	**79**

परिशिष्ट X

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्या

भाषा	अधिकारियों की संख्या	भाषा	अधिकारियों की संख्या
अरबी	96	किसवाहिली	5
बहासा इंडोनेशिया	10	कोरियाई	3
बहासा मलेशिया	2	नेपाली	3
बर्मी	2	फारसी	20
चीनी	62	पुर्तगाली	20
डच	1	रसियन	81
फ्रेंच	68	सर्बो-क्रोशियन	2
जर्मन	28	सिंहली	1
हिब्रू	4	स्पेनिस	61
इटालियन	3	तुर्किश	6
जापानी	23	यूक्रेनियन	1
कज़ाक	1	वियतनामी	2

परिशिष्ट XI

वर्ष 2010-2011 (ब.अ.) में बजट आबंटन 6375.00 करोड़ रुपए है, जोकि वर्ष 2009-2010 के बजट अनुमान 6293.00 करोड़ रुपए की तुलना में 1.30 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010-2011 के लिए संशोधित अनुमान 7120.00 करोड़ रुपए है, जोकि बजट अनुमान 2010-2011 की तुलना में 11.69 प्रतिशत अधिक है।

विदेश मंत्रालय का वास्तविक व्यय, 2005-2006 से 2010-2011

वर्ष	वास्तविक (करोड़ रुपये में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर
2005-2006	4089.67	8.88
2006-2007	3949.68	-3.42
2007-2008	4572.39	15.77
2008-2009	6630.73	45.02
2009-2010	6290.77	-5.13
2010-2011 (ब.अ.)	6375.00	1.34
2010-2011 (सं.अ.)	7120.00	11.69

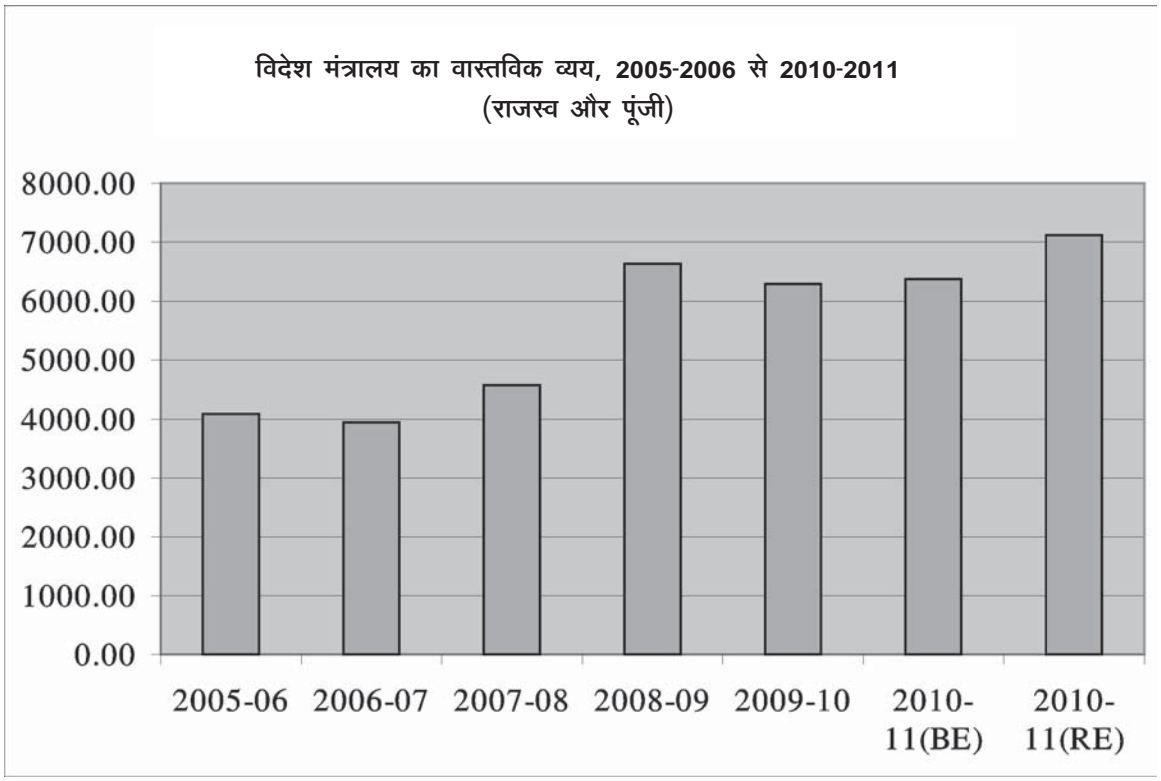

परिशिष्ट XII

क्षेत्र	आभंटन (करोड़ रुपये में)
विदेश मंत्रालय सचिवालय	236.11
राजदूतावास और मिशन	1313.60
पासपोर्ट और उत्प्रवासन	380.41
विशेष राजनयिक व्यय	1300.01
संस्थानों को अनुदान	180.42
तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2445.35
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	202.57
पूंजीगत परिव्यय	400.00
विदेशी सरकारों को ऋण और अग्रिम	472.00
अन्य	189.53
कुल	7120.00

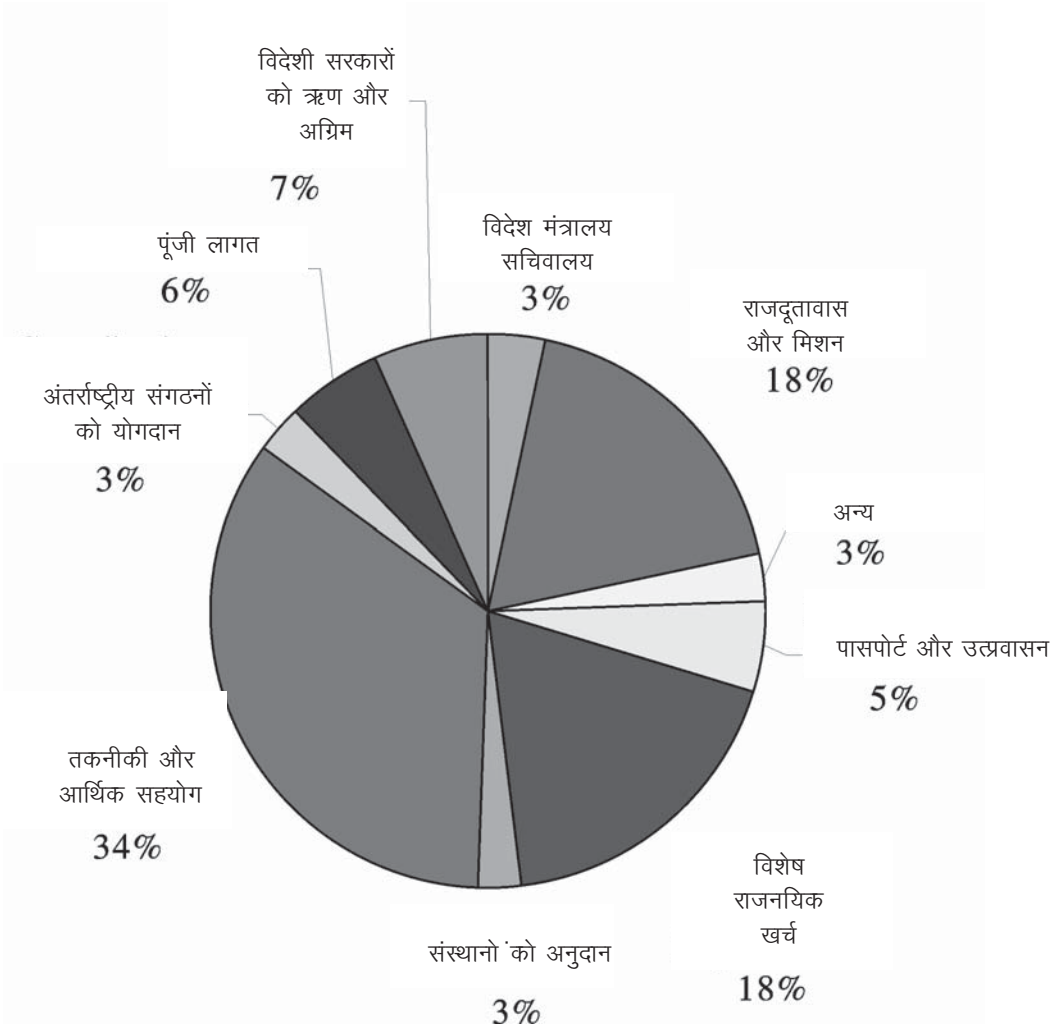

परिशिष्ट XII

1 भारत सरकार ने विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए भूटान सरकार को ऋण दिया है। वर्ष 2010-2011 के दौरान दिया गया ऋण 430.44 करोड़ रुपये रहा है।

2 विदेश मंत्रालय का बजट अनिवार्यतः गैर-योजनागत बजट है। तथापि, **1996-97** से मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक योजनागत बजट शीर्ष स्थापित किया गया है। योजनागत बजट भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि भूटान, अफगानिस्तान तथा म्यामां की कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए है। भूटान की कुछ अन्य परियोजनाएं, जो योजनागत बजट शीर्ष से वित्तपोषित की जा रही हैं - पुनात्सांगछू जल विद्युत परियोजना **I** व **II**, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना और डुंगसुंग सीमेंट संयंत्र परियोजना का निर्माण। अफगानिस्तान के काबुल से पुल-ए-खुमरी में दोहरी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के अतिरिक्त संघटकों के तौर पर अफगानिस्तान में डोसी एवं चरीकार में दो उप- केन्द्रों का भी निर्माण होगा। योजनागत आबंटन से म्यामां में कलादान बहुविध परिवहन परियोजना तथा भारत में स्थापित किया जा रहा प्रस्तावित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविधालय भी वित्तपोषित किए जा रहे हैं।

3 विदेश मंत्रालय के मुख्यालय का वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान संशोधित बजट अनुमान 236.11 करोड़ रुपये है, जो मंत्रालय के कुल बजट 7120.00 करोड़ का लगभग 3 प्रतिशत है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों के लिए संशोधित बजट अनुमान 1313.60 करोड़ रुपए पूंजीगत है, जो कि मंत्रालय के कुल राजस्व बजट का लगभग 18 प्रतिशत है।

4 पासपोर्ट तथा वीजा शुल्क और अन्य प्राप्तियों के रूप में विदेश मंत्रालय का राजस्व 31 दिसंबर, 2010 तक के लिए 1733 करोड़ रुपए रहा है। पासपोर्ट शुल्क 659 करोड़ रुपये और वीजा शुल्क 928 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राप्तियां 146 करोड़ रुपये हैं।

परिशिष्ट XIII

भारत के तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के मुख्य गंतव्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-2011 में भारत के तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के प्रधान लाभार्थी संशोधित अनुमान, 2010-2011 में निम्नलिखित हैं

निम्नलिखित देशों को सहायता और ऋण	**(करोड़ रुपये में)**	**भारत के कुल सहायता और ऋण बजट का प्रतिशत**
भूटान	1723.00	59.06
अफगानिस्तान	310.00	10.63
नेपाल	150.00	5.14
अफ्रीकी देश	150.00	5.14
श्रीलंका	90.00	3.08
म्यामां	90.00	3.08
यूरेशियाई देश	30.00	1.03
बांग्लादेश	3.00	0.10
मालदीव	11.00	0.38
लैटिन अमरीकी देश	4.00	0.14
अन्य	356.35	12.21
कुल	**2917.35**	**100.00**

परिशिष्ट XIV

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लम्बित लेखा परीक्षा पैरा की स्थिति

क्रम सं.	वर्ष	पैरा/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिस पर कि गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी लेखा परीक्षा के पुनर्निरीक्षण के बाद पी.ए.सी. को जमा कराई गई	पैरा/पी.ए. रिपोर्टों का विस्तृत विवरण जिन पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजी गई। की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियों की संख्या	भेजी गई की गई कार्रवाई संबंधी लेकिन अवलोकन के बाद वापस हुई और लेखा परीक्षा उनकी मंत्रालय द्वारा दुबारा वापिसी की प्रतिक्षा कर रहा है।	की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम पुनर्निरक्षण हुआ लेकिन मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को जमा नहीं करवाई गई
1.	2003	-	-	-	1
2.	2004	-	-	1	-
3.	2005	-	-	2	-
4.	2006	-	-	3	1
5.	2007	-	-	5	5
6.	2008-09	-	-	2	2
7.	2009	-	-	3	2
8.	2010-11	-	8	-	-
	कुल	-	**8**	16	11

परिशिष्ट XV

आई.सी.डब्ल्यू.ए. - संगोष्ठियां/सम्मेलन/व्याख्यान/बैठकेः अप्रैल 2010- जनवरी 2011

दिनांक	कार्यक्रम
व्याख्यान	
8 अप्रैल, 2010	सर हॉवर्ड डेविस, निदेशक, लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स द्वारा 'यूरोप, द लोस्ट कॉन्टिनेन्ट' पर प्रथम के.आर.नारायणन व्याख्यान अध्यक्षताः श्री सलमान खुर्शिद, कॉरपोरेट कार्य और अल्प संख्यक कार्य राज्य मंत्री (लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स के सहयोग से)
19 अप्रैल, 2010	'9/11 के बाद खाड़ी और अरब देश' पर श्री मोहम्मद जेसम अल-सागर, अध्यक्ष, अरब और अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिषद द्वारा व्याख्यान
3 मई, 2010	'जांएटस एट क्रॉसरोड्स-लिस्बन संधि के बाद भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी के लिए संभावनाए' पर श्री एलेक्जेंडर स्टब, विदेश मंत्री फिनलैंड द्वारा व्याख्यान
26 मई, 2010	'भारत-अफ्रीका संबंध' पर 'अफ्रीका दिवस' व्याख्यान
17 अगस्त, 2010	'एशिया-प्रशांत क्षेत्र और इस क्षेत्र में भारत-आस्ट्रेलिया सहयोग संबंधी परिदृश्य' पर श्री पीटर वर्गीज, भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त द्वारा व्याख्यान
14 सितम्बर, 2010	'दक्षिण एशिया क्षेत्रवादः संभावनाए और चुनौतियां' पर श्री शील कांत शर्मा, महासचिव, दक्षिण एसियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ(सार्क) द्वारा व्याख्यान अध्यक्षताः श्री एम. रसगोत्रा, भूतपूर्व विदेश सचिव
25 अक्तूबर, 2010	'समकालीन बेलारूसःव्यापार सहयोग और भागीदारी के लिए अवसर' पर श्री व्लादिमीर आई. सेमश्को, बेलारूस गणराज्य के प्रथम उप प्रधान मंत्री द्वारा व्याख्यान। अध्यक्षताः श्री वी.के. ग्रोवर, राजदूत
11 नवम्बर, 2010	'अर्मेनिया और उसके पड़ौसी देशः नई सक्रियता के लिए संभवनाएं' पर श्री एडवर्ड नलबंडियान, अर्मेनिया गणराज्य के विदेश मंत्री द्वारा व्याख्यान अध्यक्षताः श्री सुधीर टी. देवरे, महानिदेशक, आई.सी.डब्ल्यू.ए.
16 नवम्बर, 2010	'विश्व में भारत के संदर्भ में यू.के. और यूरोपीयन परिदृश्य' पर डॉ. रोबिन निब्लेट, निदेशक, रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल चाथम हाऊस, लंदन द्वारा व्याख्यान अध्यक्षताः डॉ. आबिद हुसैन
22 नवम्बर, 2010	'अनिश्चित दक्षिण-पूर्व एशिया में गरीबी और खाद्य सुरक्षा' पर डॉ. अरीस अनन्ता, वरिष्ठ अनुसंधान कर्ता, दक्षिण-पूर्व एशिया अध्ययन संस्थान, सिंगापुर द्वारा व्याख्यान अध्यक्षताः प्रो. अलख एन. शर्मा, निदेशक, मानव विकास संस्थान
23 नवम्बर, 2010	'जर्मनी और भारत-साझा चुनौतियों का समाधान करने में भागीदार' पर श्री थॉमस मटूसेक, जर्मनी संघीय गणराज्य के राजदूत द्वारा परिचर्चा अध्यक्षताः श्री एस.के. लाम्बा, राजदूत
24 नवम्बर, 2010	'म्यामां की नजर में विश्व-इन चुनावों का क्या अर्थ है?' पर डॉ. मैरी लाल(दक्षिण एशिया विशेषज्ञ), शिक्षा संस्थान, लंदन विश्वविद्यालय और चाथम हाऊस द्वारा व्याख्यान अध्यक्षताः श्री रवि भूतलिंगम, मुख्य कार्यपालक, मानस एडवायजरी (चीन अध्ययन संस्थान के सहयोग से)
1 दिसम्बर, 2010	'इथोपिया-भारत संबंध' पर श्री हेलमेरियम देसलग्न, विदेश मामलों के उप प्रधान मंत्री, इथोपिया द्वारा व्याख्यान अध्यक्षताः श्री किशन एस. राणा, राजदूत
16 दिसम्बर, 2010	चीन लोक गणराज्य की राज्य परिषद के अध्यक्ष, श्री वेन जियाबाओ द्वारा संबोधन अध्यक्षताः श्री एस.एम.कृष्णा, विदेश मंत्री
5 जनवरी, 2011	'भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच दीर्घ ऐतिहासिक संपर्कः हिंदू धर्म के आगमन से आज के तबलिज तक' पर डॉ. फरीस अहमद-नूर, समकालीन इस्लामिक कार्यक्रम पर वरिष्ठ कर्ता, एस. राजारत्नम अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, नान्यांग टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर द्वारा व्याख्यान। अध्यक्षताः प्रो. वीना सीकरी, फोर्ड फाऊंडेशन चेयर, जामिया मिलिया इस्लामिया
20 जनवरी, 2011	'21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत-पाकिस्तान संबंधों का विकास', पर श्री खुर्शीद कसूरी, पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री द्वारा व्याख्यान। अध्यक्षताः श्री मणिशंकर अय्यर, संसद सदस्य(राज्य सभा)
संगोष्ठी/सम्मेलन	
1 अप्रैल, 2010	'भारत और चीनः लोक राजनय, सहमति बनाने, भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ का आयोजन' बीज व्याख्यानः श्री शिवशंकर मेनन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (विदेश मंत्रालय के पूर्व-एशिया प्रभाग और चीन अध्ययन संस्थान, दिल्ली के सहयोग से)
17 मई, 2010	'अफगानिस्तानः आगे की दिशा में' पर आई.सी.डब्ल्यू.ए.-आई.डी.एस.ए. संयुक्त सम्मेलन
25 सितम्बर, 2010	'उभरते हुए भारत-अमरीका रणनीतिक संबंधः लागत, लाभ विश्लेषण' पर एशिया केन्द्र, बेंगलुरू के सहयोग से संयुक्त संगोष्ठी स्थानः बेंगलुरू
30 सितम्बर, 2010	'भारत-वियतनाम रणनीतिक भागीदारीः विस्तारित सहयोग का पता लगाना' पर एक- दिवसीय कार्यशाला

परिशिष्ट XV

दिनांक	कार्यक्रम
17 नवम्बर, 2010	'वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म का पुनरूत्थान और संस्कृति पर इसका संभावित प्रभाव' पर सम्मेलन आई.सी.डब्ल्यू.ए., चीन-भारत अध्ययन संस्थान, जीनान विश्वविद्यालय, ग्वांग्झू और बौद्ध धर्म अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित
20-21 नवम्बर, 2010	'भारत और जी.सी.सी. देश, ईरान और इराकः उभरता हुआ सुरक्षा परिदृश्य' पर आई.सी.डब्ल्यू.ए.-ए.ए.एस. एशियाई संबंध सम्मेलन, 2010 उद्घाटन संबोधनः श्री एम.हामीद. अन्सारी, उपराष्ट्रपति द्वारा समापन संबोधनः श्रीमती निरूपमा राव, विदेश सचिव द्वारा (एशोसिएशन ऑफ एशिया स्कॉलर(ए.ए.एस.), नई दिल्ली के सहयोग से)
7 दिसम्बर, 2010	'बदलती हुई विश्व व्यवस्था में भारत और पोलैंड' पर आई.सी.डब्ल्यू.ए.-पी.आई.एस.एम. संगोष्ठी (पोलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के सहयोग से, जिसके साथ आई.सी.डब्ल्यू.ए. का समझौता ज्ञापन है)
9-10 दिसम्बर, 2010	'विकसित होती हुई विश्व व्यवस्थाः भारत-रूस परिदृश्य' पर आई.सी.डब्ल्यू.ए.-एम.जी.आई.एम.ओ. सम्मेलन (मास्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स के सहयोग से)
6-7 जनवरी, 2011	'अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप पर पुर्नविचार' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के सहयोग से)
12 जनवरी, 2011	'भारत को जानिए कार्यक्रम' पर उभरते हुए भारत में लोकतंत्र और राजनय पर कार्यशाला (प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से)
28 जनवरी, 2011	फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकता दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन वक्ताः श्री अदली हासन शाबन सादेक, भारत में फिलिस्तीन राष्ट्र के राजदूत डॉ. अहमद सलेम सलेह अल-वहिशी, मुख्य प्रतिनिधि, अरब राष्ट्र मिशन लीग अध्यक्षता/संक्षिप्त टिप्पणीः सचिव(पूर्व) या सचिव(पश्चिम), विदेश मंत्रालय
22 जनवरी, 2011	'नेपाल में सांविधानिक संकट' पर संयुक्त संगोष्ठी स्थानः मुजफ्फरपुर, बिहार (भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सहयोग से)
चरण -I 22-23 जनवरी, 2011	काठमांडू में दक्षिण एशिया विचार मंच का वार्षिक सम्मेलन, शांति और विवाद अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित। आई.सी.डब्ल्यू.ए. के आमंत्रितों की भागीदारी।
द्विपक्षीय वार्ताएं	
20 अप्रैल, 2010	सार्क देशों की महिला पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ परस्पर सत्र अध्यक्षताःश्रीमती शशी उबान त्रिपाठी, भूतपूर्व राजदूत और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
26-30 जून, 2010	टी.ए.एस. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अनुसार, ताजिक विज्ञान अकादमी के साथ भारत-ताजिक संबंधों में सामान्य गतिशीलता पर वार्ता के लिए दुशांबे को पांच सदस्यीय आई.सी.डब्ल्यू.ए. प्रतिनिधि मंडल स्थानः दुशांबे
2 जूलाई, 2010	पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्तालाप अध्यक्षताः श्री सतीश चन्द्र, राजदूत
23 अगस्त, 2010	सी.आई.एस. देशों से वरिष्ठ पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्तालाप
22 सितम्बर, 2010	श्री विक्टर मेयको, उप विदेश मंत्री, युक्रेन के साथ वार्तालाप अध्यक्षताः श्री वी.बी. सोनी, राजदूत
11-12 अक्तूबर, 2010	द्वितीय आई.सी.डब्ल्यू.ए. ई.यू.आई.एस.एस. मंच की बैठक स्थानः ब्रुसेल्श
14-15 अक्तूबर, 2010	पांचवां भारत-स्पेन वार्तालाप मंच स्थान- मैड्रिड
21-22 अक्तूबर, 2010	'लोकतंत्र, विविधता और विकास' पर भारत-मैक्सिको द्वि-राष्ट्रीय संगोष्ठी मैक्सिको-भारत राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का आयोजन
11 नवम्बर, 2010	रवान्डा से पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्तालाप अध्यक्षताः प्रो. सुरेश कुमार, अध्यक्ष, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
23 नवम्बर, 2010	'नेपाल और भारत में लोकतांत्रिक और सांविधानिक घटनाक्रम' पर नेपाल से युवा संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गोलमेज सम्मेलन
1 दिसम्बर, 2010	'21वीं शताब्दी के दूसरें दशक में भारत और चीन' पर गोलमेज परिचर्चा आरंभकर्ताः डॉ. अल्का आचार्य श्री विनोद सी. खन्ना, राजदूत प्रो. मनोरंजन मोहन्ती (चीन अध्ययन संस्थान के सहयोग से)
14 दिसम्बर, 2010	'भारत-जापान संबंधों' पर जापान फोर नेशनल फंडामेंटल्स, टोकियो(जे.आई.एन.एफ.) से सूश्री योशिका सकुराय के नेतृत्व में जापान से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्तालाप
14 दिसम्बर, 2010	'अफ्रीका में भारत द्वारा सहयोग' पर श्री अलेक्स वाइनस ओबीई, निदेशक, क्षेत्रीय एवं सुरक्षा अध्ययन, अध्यक्ष अफ्रीका कार्यक्रम और डॉ. गैरथ प्राइस, कार्यवाहक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अनुसंधान कर्ता, एशिया कार्यक्रम, चाथम हाऊस, लंदन के साथ वार्तालाप।

परिशिष्ट XV

क्रम सं दिनांक	कार्यक्रम
21 दिसम्बर, 2010	सेन्टर फोर वियतनामी और साउथ-ईस्ट स्टडीज, समाज विज्ञान और मानविकी विश्वविद्यालय(वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हो ची मिन्ह शहर) से प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्तालाप
11 जनवरी, 2011	पूर्वी यूरोपिय देशों से संपादकों/पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्तालाप द्वाराः विदेश मंत्रालय का एक्स.पी. प्रभाग
समूह चर्चाएं/पृष्ठभूमि सार	
9 जुलाई, 2010	'बांग्लादेश-भारत संबंधः प्रधान मंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के छः महीने बाद' पर गोलमेज सम्मेलन अध्यक्षताः श्री मुचकुन्द दुबे, राजदूत
21 अगस्त, 2010	'रूस और अमरीका-रूस संबंधों पर प्रभाव' पर भारत में अमरीका के भूतपूर्व राजदूत श्री फ्रैंक जी. वाईजनर और किसिंजर एसोसिएटश में वरिष्ठ निदेशक, डॉ. थामस ग्राह्म के साथ गोलमेज सम्मेलन अध्यक्षताः श्री कमल सिब्बल, भूतपूर्व विदेश सचिव
6 सितम्बर, 2010	'दक्षिण चीन सागर में वर्तमान घटनाक्रम' पर गोलमेज सम्मेलन वक्ताः श्री टी.सी.ए. रंगाचारी, राजदूत रियर एडमिरल श्री राजा मेनन डॉ. विजय सखुजा कंमाडर शिशिर उपाध्याय (नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से)
पुस्तक विमोचन	
18 अगस्त, 2010	'उपनिवेशवाद और भारतीय अर्थव्यवस्था' नामक पुस्तक का प्रो. अमी बागची, निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान, कोलकाता द्वारा विमोचन (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के सहयोग से)
20 सितम्बर, 2010	श्री तालमीज अहमद की पुस्तक 'चिल्ड्रन ऑफ अब्राह्म एट वॉर क्लैस ऑफ मेशियानिक मिलिट्रीज्म' का श्री मणि शंकर अय्यर, संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा विमोचन
4 नवम्बर, 2010	'आर्मीग विदाऊट एमिंगःइंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन' नामक पुस्तक का विमोचन (लेखकः श्री स्टीफन पी. कोहेन और श्री सुनील दास) वक्ताः श्री जसवंत सिंह, संसद सदस्य; श्री के.एस. वाजपेयी, प्रसिद्ध राजनयिक तथा स्तंभकार; और श्री स्टीफन पी. कोहेन
12 फरवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 के बीच किए जाने वाले कार्यकलाप	
12 फरवरी, 2011	'सार्क में सहयोग सशक्तिकरणःगैर-परम्परागत सुरक्षा आशंकाओं के संदर्भ में' पर संयुक्त संगोष्ठी स्थानः राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सहयोग से)
19 फरवरी, 2011	'क्या हिन्द महासागर, भारतीय नहीं रहा? वर्तमान वास्तविकताएं, भारत के लिए चुनौतियां और अवसर' पर एशिया केन्द्र, बंगलौर के सहयोग से संयुक्त संगोष्ठी स्थानः बंगलौर
मध्य फरवरी, 2011	अफ्रीकी अध्ययन संघ, भारत के सहयोग से अफ्रो-एशियन सम्मेलन
3-4 मार्च, 2011	दिल्ली संवाद-3, भारत-एशिया सहयोग के पहले 20 वर्षों से आगे-विदेश मंत्रालय के सहयोग से आई.सी.डब्ल्यू.ए., फिक्की और आई.एस.ई.ए.एस., सिंगापुर द्वारा आयोजित स्थानः नई दिल्ली
फरवरी-मार्च, 2011	आई.सी.डब्ल्यू.ए. के सहयोग से विदेशों के साथ मैत्री संघ, नई दिल्ली द्वारा 'जी-20 और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग' पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन

परिशिष्ट XVI

आरआईएस

आरआईएस प्रकाशन

नीति पक्षसार

#48 बीआरआईसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग

#47 दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा को चुनौतियां

#46 अनाज आधारित ऐथनॉयल की खोजः अनाजों के लिए प्रतिस्पर्धा की पुनः जांच-परीक्षण

#45 भारत में जीवाश्म ईंधन आर्थिक सहायता सुधारः चुनौतियों का समाधान

विचार-विमर्श संबंधी कागजात

#169 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक और भारत का खाद्य निर्यात ग्रेविटी मॉडल यूजिंग थ्री डाइमेंशनल डाटा पर आधारित विश्लेषण, राजेश मेहता द्वारा।

#168 प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और नए कर्ताः प्रतिफलों और विनियमों पर चर्चा, सचिन चतुर्वेदी द्वारा।

#167 खाद्य-पोषण-ईंधन त्रिकोणः खाद्यान्न उपयोग प्रतिस्पर्धा के लिए अनाज-आधारित ऐथनॉयल के निहितार्थ, अरिंदम बैनर्जी द्वारा।

#166 वैश्विक वित्तीय संकटः भारत में व्यापारिक और औद्योगिक पुनर्गठन संबंधी निहितार्थ, प्रबीर डे और चिरंजीव नियोगी द्वारा

#165 क्या व्यापारिक खुलापन और वित्तीय विकास पूरक हैं? राम उपेन्द्र दास और मीनाक्षी ऋषि द्वारा

#164 क्या व्यापारिक वृद्धि के लिए सुशासन आवश्यक है? एशिया से अनुभवजन्य प्रमाण, प्रबीर डे द्वारा।

#163 क्षेत्रीय व्यापार करारों के अधीन उदगम के नियम, राम उपेन्द्र दास द्वारा।

#162 विश्व व्यापार संगठन में भौगोलिक संकेतः एक असमाप्त कार्यसूची, कस्तूरी दास द्वारा।

#161 भारत-नेपाल व्यापार संधि में संशोधन और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत बनाने के लिए इसके निहितार्थः इंदिरा नाथ मुखर्जी द्वारा।

पत्रिकाएं

1 दक्षिण एशिया आर्थिक पत्रिका, खंडः 11, सं. 1 मार्च, 2010

2 दक्षिण एशिया आर्थिक पत्रिका खंडः 1, सं. 2, दिसंबर, 2009

3 एशियाई जैव प्रौद्योगिकी तथा विकास समीक्षा, खंडः 12, सं.1 मार्च, 2010

4 न्यू एशिया मॉनिटर, खंडः 7, सं.2 और 3 जुलाई, 2010

5 न्यू एशिया मॉनिटर, खंडः 6, सं.9, खंडः 7, सं. 1 जनवरी, 2010

न्यूजलेटर

आर.आई.एस. डायरी खंड 7, सं. 3-4 और खंड 8, सं. 1 जनवरी, 2010

संक्षिप्तियाँ

आल्को	एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन
एबीएस	एक्सेस एण्ड बेनेफिट शेयरिंग
एसीएबीक्यू	प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों पर यूएन परामर्शी समिति
एसीडी	एशिया सहयोग वार्ता
एडीएमएम	आसियान रक्षा मंत्री बैठक
एएनडीआई	कोलंबियाई उद्यम संघ (एसोसिएशन नेशनल डी इम्प्रेसारियो डी कोलंबिया)
एएमएम	आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय मंच
आसियान	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन
एएसईएम	एशिया यूरोप बैठक
एसोचैम	एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
एयू	अफ्रीकी सघ
एडब्ल्यूजी	एड-हॉक वर्किंग ग्रुप
आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक
बार्क	भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र
बिमस्टेक	बहु-पक्षीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
बीआईपीपीए	द्विपक्षीय निवेश रक्षा एवं संवर्द्धन करार
ब्रिक	ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन
बीडब्ल्यूसी	जैविक हथियार अभिसमय
सीएएनडीयू	कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम
केपेक्सिल	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद
सीबीडी	जैविक विविधता अभिसमय
सीसीआईटी	अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय
सीसीपीसीजे	अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक न्याय आयोग
सीडी	निरस्त्रीकरण सम्मेलन
सी-डैक	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग
सीका	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीईडीएडब्ल्यू	महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम पर करार
सीईपी	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी करार
सीईटीआई	सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र
सीआईसीए	एशिया में कार्यकलाप एवं विश्वासोत्पादक उपाय
सीआईसीए	एशिया में कार्यकलाप एवं विश्वासोत्पादक उपाय
सीएलसीएस	महाद्वीपीय मग्नतट की सीमाओं पर आयोग
चोगम	राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक
सीआईसी	केन्द्रीय सूचना आयोग
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएस	स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल
कोमेसा	पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार
कॉरपट	समन्वित गश्ती
सीओएससी	चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
सीपीआईओ	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीवी	कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा
सीआरआरआईडी	ग्रामीण और औद्योगिक विकास शोध केन्द्र
सीएससीएपी	एशिया प्रशांत सुरक्षा सहयोग परिषद
सीएसडी	व्यापक सुरक्षा वार्ता
सीएसडब्ल्यू	महिलाओं की स्थिति पर आयोग
सीटीसीएन	जलवायु तकनीक केन्द्र और नेटवर्क
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान
डीएसएससी	रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज
डीटीएसी	दोहरा कराधान परिहार अभिसमय
ईएसी	पूर्व अफ्रीकी समुदाय
ईएएस	पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन
इकोवास	पश्चिम अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय
इकोसोक	आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद
ईएफटीए	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईआईएल	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ईएमएम	पूर्व एशिया मंत्री बैठक
ईयू	यूरोपीय संघ
एक्जिम	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ

संक्षिप्तियाँ

एफएटीएफ	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग
फिक्की	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ
एफआईपीबी	विदेश कार्यालय परामर्श
एफएमसीटी	विखण्डनीय पदार्थ नियंत्रण संधि
एफओसी	विदेश कार्यालय परामर्श
एफआईटीए	अंतराष्ट्रीय अमरीकी पर्यटन मेला
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
गेल	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
जी-15	ग्रुप-15
जीएफसीएस	जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक रूपरेखा
जीएफएमडी	उत्प्रवासन एवं विकास पर वैश्विक मंच
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जीएसटी	सामान एवं सेवा कर
एचएएल	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड
एचआईवी/एड्स	ह्यूमन ईम्यनो वायरस/एक्वयर्ड इम्यूनो डिफिसिएंसी सिण्ड्रोम
एचएलजी	उच्च स्तरीय ग्रपु
आईएईए	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
आईएटीटी	अंतर एजेंसी कार्य दल
आईएडीबी	अंतर-अमरीकी विकास बैंक
आईएएफएस	भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
आईबीएफ	भारतीय व्यवसाय मंच
आईबीईएफ	इंडियन ब्रैंड इक्विटी मंच
इब्सा	भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच
आईसीएओ	अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईसीडब्ल्यूए	भारतीय मामलों की विश्व परिषद
आईडीएसए	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय
आईआईबीएफ	भारतीय बैंकिंग एवं विश्व संस्थान
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
आईआईएफटी	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएफसी	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अभिसमय
आईआईटी	भारतीय तकनीकी संस्थान
आईसीसी	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएनजी	अंतर-क्षेत्रीय वार्ता समूह
आईएनएस	भारतीय नौसैनिक पोत
आईएनएसटीसी	अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा
आईएनटीओएसएआई	इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रिम ऑडिट इन्सटीट्यूशंस
आईओएम	अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन संगठन
आईओएनएस	इन्स्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइसेंज
आईओआर-एआरसी	हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ
आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
आईपीयू	अंतर-संसदीय संघ
आईआरईएनए	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी
आईएससीएस	अंतर-राज्यीय सचिवालय परिषद
आईटीईसी	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग
आईटीएलओएस	समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण
आईटीयू	अंतर्राष्ट्रीय टेलेकम्युनिकेशन संघ
जेईसी	आर्थिक सहयोग की संयुक्त आयोग
जेडब्लयूजी	संयुक्त कार्यकारी दल
एलडीसी	अल्प विकसित देश
एलएलएमसी	समुद्री दावों के लिए देयता
एलएमएमसी	समान विचारों वाले मेगा विविध देश
एलएनजी	द्रवित प्राकृतिक गैस
एलओसी	ऋण श्रंखला
एमडीजी	मिलेनियम विकास लक्ष्य
मेकॉन	मेटालुरजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड
मर्कोसुर	दक्षिणी शंकु देश बाजार
एमएफएन	अत्यंत अनुकूल राष्ट्र
एमओयू	समझौता ज्ञापन
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन परिसंघ लिमिटेड

संक्षिप्तियाँ

नाम	गुट-निरपेक्ष आन्दोलन
नासा	नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
नास्कॉम	राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ
नाटो	उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
एनडीआईसी	राष्ट्रीय विकास एवं नवाचार समिति
एनईएलपी	नई दोहन लाइसेंसिंग नीति
नेपाड	अफ्रीकी विकास के लिए नई भागीदारी
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनपीटी	परमाणु अप्रसार संधि
एनएससी	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
एनएसजी	नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह
ओसीआई	भारतीय मूल के विदेशी नागरिक
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
ओपीसीडब्ल्यू	रसायनिक हथियारों की रोकथाम के लिए संगठन
ओवीएल	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
पीबीएफ	शांति-निर्माण कोष
पीडीआईएल	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
पीएफडी	मंच पश्चात वार्ता
फार्म एक्जिल	भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात प्रोत्साहन परिषद
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईसी	क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय
राइट्स	रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस
आरटीआई	सूचना का अधिकार
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एसएडीसी	दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय
साफ्ता	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार
एसएयू	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय
एसबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
एससीएएपी	अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेवा	स्व-नियोजित महिला संघ
एचईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसआईसीए	मध्य अमरीकी एकीकरण व्यवस्था
एमएमई	लघु एवं मझोले उद्यम
एसटीपीआई	भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीम-9	टेक्नो-इकोनॉमिक अप्रोच फार अफ्रीका इंडिया मूवमेंट
टेकेस	टेक्नोलाजियन केहीटा मिस्केस
टेरी	टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
यूएनसीओपीयूओएस	बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समिति
अंकटाड	व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनईएससीएपी	एशिया व प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
आरएएल	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएनआईएफ आईएल	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल
यूएनएमआईएन	नेपाल में संयुक्त राष्ट्र मिशन
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
यूपीआर	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
वीएसएनएल	विदेश संचार निगम लिमिटेड
डब्ल्यूईएफ	विश्व आर्थिक मंच
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन